

॥ ५५५॥

इमजैसी का कच्चा चिट्ठा

कुलदीप नय्यर

हिन्दी रूपान्तर

भानस कश्यप



राधाकृष्ण

Originally published by-
VIKAS PUBLISHING HOUSE PVT LTD
 5, Ansari Road, New Delhi 110002 (India)
 in the English language under the title
THE JUDGEMENT : Inside Story of the Emergency in India

हिन्दी में प्रकाशित किया गया
 भद्रेश्वरी मूल का निर्माण

©
 कुलदीप नय्यर, नई दिल्ली
 1977

हिन्दी अनुवाद

©
 राधाकृष्ण, नई दिल्ली
 1977

प्रथम हिन्दी संस्करण जुलाई 1977
 तृतीय आवृत्ति अगस्त, 1977

मूल्य

पेपरबैक संस्करण 18 रुपये
 सजिल्द संस्करण 24 रुपये

भावरेण सज्जा सुकुमार शर्कर

प्रकाशक

राधाकृष्ण

2 भंसारी रोड, नरियागज
 नई दिल्ली 110002

मुद्रक हरजीत भाट्ट प्रेस, दिल्ली 110006

यह पुस्तक

भारत की जनता को समर्पित है
जिसमे यह फैसला करने की शक्ति थी
और जिसने यह फैसला किया ।

भूमिका

25 जून 1975 को राधी रात के समय अचानक टेलीफोन की घंटी बजी और मेरी आँख खुल गयी। उधर से कोई भोपाल से बात कर रहा था। वहाँ सड़कों पर पुलिस ही-पुलिस दिखायी दे रही थी। वह चाहता था कि मैं पता लगाकर बताऊँ कि ऐसा क्यों है? मैंने अलसाये हुए स्वर में कहा कि अच्छा पता लगाऊँगा और टेलीफोन रख दिया। टेलीफोन रखते ही फिर घंटी बजी। इस बार जालधर के एक अखबार से टेलीफोन आया था और उधर से जो आदमी बोल रहा था उसने बताया कि पुलिस ने प्रेस पर कब्जा कर लिया था और उस दिन के सारे अखबार जब्त कर लिये थे। इसके बाद मेरे अपने दफ्तर से टेलीफोन आया कि बहादुरशाह जफर भाग पर सारे अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गयी है और गैर सरकारी सूत्रों का कहना था कि वह 'जल्दी' लौटकर आने वाली नहीं है।

सब पूछिये तो मैंने इन घटनाओं के बीच आपस में कोई सम्बन्ध नहीं देखा। मैंने सोचा कि नोकरशाही एक बार फिर अपने हथकड़े भाजमा रही है। कई महीने पहले बस ड्राइवरो की हड़ताल के मौके पर दिल्ली के अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गयी थी, दस घंटे बाद बिजली आयी थी। शायद सरकार नहीं चाहती थी कि जयप्रकाश की 25 जून वाली उस मीटिंग की खबर अखबारों में छपे जिसमें उन्होंने सत्याग्रह का नारा दिया था।

इतने में इरफान खाँ का टेलीफोन आया, जो उन दिनों जयप्रकाश के शुरू किये हुए साप्ताहिक अखबार एवरीमस में काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्हें खबर मिली थी कि जयप्रकाश, मोरारजी और चन्द्रशेखर सहित बहुत-से नेता गिरफ्तार कर लिये गये हैं। इसके कुछ ही घंटे बाद इमजेंसी और सेंसरशिप लागू होने का ऐलान आया, सारे राष्ट्र को जंजीरो में जकड़ दिया गया था और उसकी खबर बन्द कर दी गयी थी।

किसी भी अखबारवाले को किसी भी दूसरी बात से इतनी निराशा नहीं होती जितनी कि इस बात से कि उसे ऐसी खबरें जमा करनी पड़ें जिनके बारे में वह जानता हो कि वे छप नहीं सकती। जल्द ही यह बात जाहिर हो गयी कि इमजेंसी का हमला 'कामयाब' हो गया था और ऐसा लगता था कि जनतंत्र को अब ऐसी रात का सामना करना पड़ेगा जिसका कोई अन्त नहीं होगा। लेकिन

सुबह की उम्मीद कितनी ही धुँधली बयो न रही हो, जब मैं हमजैसी लागू किये जाने की वजहों का पता लगाने निकला तो मेरे मन में हर बात को दज करते जाने और किसी दिन कितना लिखने का विचार उठा। जानकारी जमा करना बहुत कठिन काम था।

ऐसा खोफ छाया हुआ था, चारों तरफ इतनी दहशत थी कि शायद ही कोई जबान खोलता हो। कुछ बातों की पूता तो मुझे चला लेकिन 26 जुलाई को मैं गिरफ्तार कर लिया गया। सात हफ्ते बाद जब मुझे रिहा कर दिया गया तब मैंने फिर से इसका सिरा पकड़ा।

चुनावों का ऐलान होने के साथ ही 18 जनवरी को, हमजैसी में डील पढ़ने के बाद भी बहुत छोड़ ही लोग थे जो मुझसे बात करने की तयार थे। लेकिन चुनावों के बाद हर चीज बदल गयी और मैंने सजय गांधी, धार० के० धवन, एच० धार० गोखले, चंद्रजीत यादव, रुखसाना मुल्ताना, बेगम भाबिदा प्रहमद और पुलिस के और दूसरे विभागों के चौकी के अफसरों से बात की। इन सभी लोगों ने कहा कि किसी बात के साथ उनका नाम न जोड़ा जाये और मैंने अपना वायदा पूरी तरह निभाया है। लेकिन इन सभी लोगों ने बहुत खलबल मचाई की और हमजैसी की कहानी का लगभग सारा ताना बाना मैंने इन्हीं लोगों की बातों की बुनियाद पर बना है। मैंने कम-से कम छ बार श्रीमती गांधी से इंटरव्यू लेने की कोशिश की लेकिन वह राजी नहीं हुई।

हमजैसी के दौरान दो बार मैंने लगभग पूरे देश का दौरा किया—एक बार प्रक्टिकर नवम्बर 1975 में और फिर 1976 के मध्य में। इन यात्राओं के दौरान मैं बहुत से लोगों से मिला और मैंने बहुत सी सामग्री भी जमा की। मैंने कुछ मण्डरप्रारण्ड प्रकाशन भी जमा किये जो बहुमत के उन उन्नीस महीनों के दौरान छापे गये थे।

मैं यह दावा नहीं करता कि हमजैसी के बारे में किसी बात इस कितान में है। एक बात तो यह कि यह इतनी लम्बी कहानी है कि एक लाख शब्दों में पूरी बयान नहीं की जा सकती, दूसरे, हमजैसी हटने के बाद जो बहुत-से आरोप लगाये गये हैं, और जो बहुत-सी भ्रमों का फल है उनको मैं पूरी तरह छानबीन नहीं कर पाया हूँ और हमजैसी के दौरान बहुत से लोगों की कार्रवाई करतूतों पर राजी नहीं जो पढ़ा पढ़ा हुआ है उसे भी मैं नहीं चीर सका हूँ। लेकिन इस किताब में जो कुछ भी दिया गया है उसकी सच्चाई के बारे में अच्छी तरह छानबीन कर ली गयी है।

मैं जानता हूँ कि कुछ बातें जो मैंने चुनकर लिखी हैं वे इनमें से कुछ लोगों की अच्छी-मही-जगगी और मुमकिन है कि वे उनका खण्डन भी कर दें। मैं उनसे कोई भेगडा नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो यदमाओं को सच्चाई के साथ बयान कर देने का अपना काम किया है, मुझे किसी से डर नहीं है। अपनी योग्यता भर मैंने बीजों को उनके सस्ती रूप से बयान कर देने की कोशिश की है।

अपनी यात्राओं और लोगों से बातचीत के दौरान मैंने एक बात यह देखी है कि लगभग हर आदमी कितना ही सहमा हुआ बयो न रहा हो पर निरंकुश शासन को स्वीकार किसी ने नहीं किया था। लोगो में डर था, जो कुछ उनसे कहा जाता था वे वैसा ही करते भी थे, पर उन्होंने इस शासन को कभी स्वीकार नहीं किया। लोगो के मन में यह डर किसने बिठाया था और इसकी क्या वजह है कि सरकार के अंदर और दूसरी जगहों में भी लगभग किसी ने भी इस दबाव का मुकाबला करने की कोशिश नहीं की ? इन सवालों के बारे में खुली बहस होनी चाहिए।

—कुलदीप नय्यर



क्रम

डिप्टेटरशिप की छोर	13
घोर अथकार	64
छुरग का छोर	108
फैसला	158
परिशिष्ट	
1 भारत	189
2 सेंसरशिप की मार्गदर्शिकाएँ	197
अनुक्रमणिका	215

डिक्टेटरशिप की ओर

प्रधानमंत्री की कोठी के एक छोटे-से भिरे कमरे में दो टेलीप्रिंटर लगातौर सड़खड़ा रहे थे और शब्दों की एक अविश्राम धारा उड़ते जा रहे थे। सुबह के वक़्त, जब काम ज्यादा नहीं होता, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया (पी० टी० आई०) और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इण्डिया (यू० एन० आई०) के दफ्तर रात की भांसी हुई खबरों को निबटा रहे थे। घामतीर पर बाई, इन मशीनों की ओर झुककर भी नहीं देखता था, कम से कम दिन में इतनी जल्दी तो नहीं ही देखता था।

लेकिन 12 जून 1975 को श्रीमती इन्दिरा गांधी के सबसे सौनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, नेहरून के कुण्ड, अप्पर शेपन, धबराये हुए एक मशीन से दूसरी मशीन के बीच चक्कर लगा रहे थे। कमरे में डरावना सनाटा छाया हुआ था, जिसे टेलीप्रिंटरों की टेलीफोन का शोर भी नहीं ब्रेक पा रहा था।

बहुत बड़ी खबर मानेवाली थी और नैपत बड़ी जेबनों से उसकी इतजार कर रहे थे। उस दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा 1971 में लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री के चुने जाने के खिलाफ राजनारायण की दायर की हुई याचिका पर अपना फैसला सुनानेवाले थे। लगभग 10 बजनेवाले थे और कुछ ही घंटे पहले इलाहाबाद टेलीफोन बरने पर पता चला था कि जज साहब अभी अपने घर से नहीं निकले थे।

— दोपत ने सोचा, सिन्हा साहब भी मजबूत भादमी हैं। हर भादमी की एक ज़िमत होती है, लेकिन सिन्हा साहब की शायद नहीं थी। उन्हें ने कोई सल्लिब दिया जा सकता था और न ही उनसे दबाव डालकर कोई काम कराया जा सकता था।

श्रीमती गांधी के अपने प्रा त उत्तर प्रदेश के एक ससद सदस्य ने इलाहाबाद जाकर बातों-बातों में सिन्हा साहब से इसका जिक्र किया था कि क्या 500,000 रु० में उनका काम खल जायेगा। सिन्हा साहब ने कोई जवाब नहीं दिया था। बाद में उनके एक साथी जज ने उनसे कहा था कि मुझे उम्मीद है कि फसले के बाद आपको तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जायेगा। सिन्हा साहब ने बस उन्हें निरस्कार भरी नज़रों से देखा था।

फसले को टलवाने की कोशिश भी ज़ाकर साबित हुई थी। गृह मंत्रालय के ज्वाइट सेक्रेटरी प्रेम प्रकाश नैयर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से देहरादून में मिले थे और उनके सामने यह सुझाव रखा था कि अगर फैसला प्रधानमंत्री के अपनी विदेश-यात्रा पूरी कर लेने तक के लिए टाल दिया जाय तो अच्छा हो—फैसला खिलाफ होने पर ऐसी हालत में बड़ी परेशानी होगी।

चीफ जस्टिस साहब ने यह प्रार्थना सिन्हा साहब तक पहुँचा दी। जेज इतना नाराज हुए कि उन्होंने औरन भद्रालत के रजिस्ट्रार को टेलीफोन किया ऐनान कर देन को कहा कि 12 जून को फैसला सुनाया जायेगा। सिन्हा

भासक कांग्रेस पार्टी के साथ इतनी रिश्तायत की थी कि उन्होंने 8 जून को गुजरात विधान सभा के चुनाव से पहले फसला चुनाव की तारीख नहीं रखी थी ताकि चुनाव के नतीजों पर उसका प्रसर न पड़े।

फसला क्या होगा इसका पता जब साहब और उनके स्टेनोग्राफर के प्रलाप किसी को भी न था, न शेपन को और न किसी और को। खुफिया विभाग के लोग भी कुछ पता नहीं लगा सके थे। उसके कुछ लोग सिनहा साहब के स्टेनोग्राफर नेगीराम निगम को बहला फुसलाकर भेद लेने के लिए नई दिल्ली से इलाहाबाद तक गये थे। मगर वह भी अपने साहब के ही सचि में डसा हुआ लगता था। घमकियों से भी कोई काम नहीं निकला। और 11 जून की रात से वह और उसकी पत्नी अपने घर से 'लापता' थे। उनके कोई बच्चा था नहीं और खुफिया विभाग के लोग जब वहाँ पहुँचे तो घर में बिलकुल सनाटा था।

प्रधानमंत्री के सेनेटैरियट के लिए उम्मीद की केवल एक किरण यह थी कि सिनहा साहब की धार्मिक प्रवृत्ति को जानते हुए उनके घर के बाहर जो एक साधु तैनात किया गया था उसने बताया था कि "सब-कुछ ठीक हो जायेगा।" भय गुप्त-धरो के साथ वह भी कई दिन से सिनहा साहब की कोठी की चारदीवारी के बाहर बटा हुआ था। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं हो सकता था कि सिनहा साहब ने अपने स्टेनोग्राफर को क्या लिखवाया है। फसले का प्रमत्ती हिस्सा सिनहा साहब के सामने 11 जून को ही टाहप किया गया था, और घायद सिनहा साहब ने उसी वक्त अपने स्टेनोग्राफर को 'लापता' हो जाने के लिए कह दिया था।

सिनहा साहब जिन नतीजों पर पहुँचे थे वे उन्होंने बिलकुल अपने ही तक रखे थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान भी यह पता लगाना मुश्किल था कि उनका भुकाव किस तरफ है। मगर वह एक पल से दो सवाल पूछते थे तो इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि दूसरे पक्ष से भी उत्तरे ही सवाल पूछें। सुनवाई में चार साल लगे थे, और जब वह 23 मई, 1975 को खत्म हुई थी उसके बाद से न वह अपने घर से बाहर निकले थे और न ही उन्होंने किसी का टेलीफोन उठाकर सुना था।

रोपन ने एक बार फिर अपनी घड़ी देखी। टेलिप्रिटर लगातार इधर-उधर की शब्दों लड़खड़ाये जा रहे थे, जिनका कोई महत्व नहीं था। रोपन ने एक बार फिर घड़ी देखी। दस बजने में पाँच मिनट रह गये थे। सिनहा साहब वक्त के बहुत पाबन्द थे। वह भय जरूर हाईकोर्ट पहुँच गये होंगे। हाँ, वह पहुँच गये थे। जब साहब दुबले पतले धारीर थे, पचपन वय के आदमी थे। वह अपनी मोटर पर घर से सीधे प्रदालत भागे थे। जसे ही वह कमरा नं० 24 में अपनी कुर्सी पर आकर बठे, एक पैदावार ने, जो बड़े सलीबों के साथ-मुण्डे कपड़े पहन हुए था, मन्त्रालय भरी हुई प्रदालत में ऐलान किया, "साहबान, मुनिय जब जब साहब राजनारायण की चुनाव याचिका पर अपना फसला सुनाये तो कोई सती न बजाये।"

सिनहा साहब ने सामने 258 पेज का फसला रखा था। उन्होंने कहा, "इस मुकदमे में जो सबाम उठाये गये हैं उनके बारे में मैं जिन नतीजों पर पहुँचा हूँ गिफ्त बही मैं पदवार सुनाऊँगा।"

इसके बाद उन्होंने कहा "याचिका मजूर की जाती है। एक सण तब बिल ठुग मनाटा लाया रहा और फिर प्रधान न्यायाधीश की सहमति गृह मंत्री की ओर।" सामने टेलीफोन की तरफ सपने और गुप्तचर अपने अपने दानों की ओर। रोपन ने दस बजकर दो मिनट पर यू० एन० आई० ने टेलिप्रिटर की घड़ी सुनी और प्रधान न्यायाधीश नगर उम पर बिजली के बंदी की तरह छपी हुई लखर

पर पड़ी। श्रीमती गांधी का चुनाव रह। शेषन ने कागज मशीन पर से फाड़ा और उस कमरे की तरफ लपके जहाँ श्रीमती गांधी बंठी हुई थी। कमरे के बाहर ही उनकी मुठ-भेड़ उनके बड़े बेटे राजीव से हो गयी, जो इण्डियन एयर लाइंस में पाइलट है। उन्होंने खबर उसे सुनायी।

राजीव ने जाकर अपनी माँ को बताया, “उन लोगों ने आपका चुनाव रह कर दिया है।”

श्रीमती गांधी ने खबर सुनकर कोई तूफान खड़ा नहीं किया। उन्हें शायद कुछ राहत ही मिली कि इन्तज़ार से तो छुटकारा मिला।

कल सारा दिन वह सोच में डूबी रही थी। उनकी मुसीबत इस बात से और बढ़ गयी थी कि उनके धनिष्ठ मित्र दुर्गाप्रसाद धर का, जो पहले उनके मन्त्रिमण्डल में मंत्री थे और बाद में राजदूत होकर मास्को चले गये थे, देहान्त हो गया था लेकिन उस दिन सुबह वह ज्यादा खुश दिखायी दे रही थी।

इतने में एक और खबर आयी कि उहे छ साल के लिए कोई निर्वाचित पद संभालने से रोक दिया गया है। इस खबर से वह कुछ परेशान हुई और ऐसा लगा कि वह अपने भावों का छिपाने की कोशिश कर रही हैं। धीरे-धीरे चलकर वह बैठक में गयी।

सिनहा साहब ने उहे चुनाव में दो भ्रष्ट आचरणों का अपराधी ठहराया था। पहला यह था कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सेक्रेटरिस्ट के आफिसर, प्रॉन स्पेशल इयूटी यशपाल कपूर को “चुनाव में अपनी जीत की सम्भावनाएँ बढ़ाने” के लिए इस्तेमाल किया था। सरकारी नौकर होने की हैसियत से उन्हें इस काम के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाना चाहिये था। सिनहा साहब ने कहा कि यशपाल कपूर ने हालाँकि श्रीमती गांधी के चुनाव का प्रचार 7 जनवरी 1971 को शुरू किया था और अपनी नौकरी से इस्तीफा 13 जनवरी को जाकर दिया था, लेकिन वह 25 जनवरी तक सरकारी नौकरी पर बने हुए थे। जज साहब के अनुसार श्रीमती गांधी ने “अपने उम्मीदवार होने का ऐलान” 29 दिसम्बर 1970 को कर दिया था, जब उन्होंने नई दिल्ली में एक प्रेस कांफ़ेंस में भाषण देते हुए चुनाव में लड़े होने के अपने फैसले का ऐलान किया था।

दूसरी अनुचित बात यह थी कि श्रीमती गांधी ने वे मंच बनाने के लिए, जिन पर लड़े होकर उन्होंने चुनाव की मीटिंगों में भाषण दिये थे, उत्तर प्रदेश के सरकारी अफसरों की मदद ली थी। साउंडस्पीकरों का और उनके लिए बिजली का इन्तज़ाम भी इन अफसरों ने ही किया था।

राजनारायण 1,00,000 से अधिक वोटों से हारे थे, इन अनुचित आचरणों का चुनाव के नतीजे पर कोई खास असर नहीं पड़ा होगा। प्रधानमंत्री के चुनाव को रह कर देने को उचित ठहराने के लिए ये बहुत ही कमज़ोर आधार थे। लगभग बिल्कुल वसी ही बात थी कि सड़क पर आयाजाही के किसी कानून को तोड़ने के अपराध में प्रधानमंत्री का चुनाव रह कर दिया जाये।

लेकिन कानून तो कानून होता है और यह बिल्कुल साफ़ था कि अगर कोई उम्मीदवार “चुनाव में अपने जीतने की सम्भावना को बढ़ाने के लिए” किसी सरकारी नौकर से मदद लेगा तो यह भ्रष्ट आचरण माना जायेगा। सिनहा साहब ने खुद अपने फैसले में कहा कि उनके लिए कोई और चारा ही नहीं रह गया था। प्रधानमंत्री के लिए कानून में अलग से कुछ नहीं कहा गया था और वह इसके प्रस्ताव कोई और फैसला दे ही नहीं सकते थे। इस कानून को तोड़ने की सज़ा भी तय कर दी गयी थी और जज का अपनी तरफ़ से उसमें हेर फेर करने का कोई अधिकार नहीं था।

1. 1. 1. प्रधानमंत्री की कोठी पर जो लोग सबसे पहले पहुँचे थे, वे सामंतों पर बहुत प्रसन्नचित रहनेवाले पवित्र बवाल के मुख्यमंत्री, सिद्धार्थशंकर रे और कांग्रेस के गोल-मटोल अध्यक्ष देवकान्त शर्मा। उनके चेहरे पर विस्मय छाया हुआ था लेकिन जब श्रीमती गांधी ने कहा कि मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा तो दोनों चुप रहे।

2. 2. जैसे जैसे खबर फैली, मंत्री और दूसरे लोग घबराये हुए—। सुफंदरजग रोह पर ताता बाँधकर भान लगे। बैठक सचासच भरी हुई थी। कांग्रेस की एक जनरल सेक्रेटरी श्रीमती पूरबी मुखर्जी आयी और भाते ही फफक-फफककर रोने लगीं। यों तो वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे मंत्री ऐसा सगता था किसी का शोक मनाने प्राये हैं, लेकिन वे भी समझ रहे थे कि पूरबी मुखर्जी ने अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कुछ छरुत से किया था। श्रीमती गांधी ने कुछ झुल्लाकर उनसे अपने ऊपर झट्ट रखने को कहा। प्रधानमंत्री का चेहरा उतरा हुआ, पर शांत था, वह जानती थी कि उनके पास अब इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा ही नहीं रह गया है।

3. 3. किसी ने सुझाव दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपनी कर सकती है। लेकिन उससे बचन लगेगा। अभी सिद्धार्थशंकर रे, जो प्रधानमंत्री के सबसे निकट होने का दावा करते थे, और कानूतमत्री हरि रामचंद्र गोखले के बीच बहस हो-ही रही थी कि इतने में टेलिफोन पर एक और खबर आयी कि सिनहा साहब ने अपने फँसले की तामील की बीस दिन तक हथियार रखने की सफ शुब्दी में मजबूरी दे दी है। शातावरण बदल गया, सभने सन्तोष की साँस ली, गोखले ने पक्का पता करने के लिए इलाहाबाद टेलीफोन किया। बात सच थी। श्रीमती गांधी ने जिए फौरन इस्तीफा देना खट्टी नहीं था।

4. 4. लेकिन इस बवाल बाल ही बचाव हो गया था। सिनहा साहब ने फसले की तामील की हथियार रखने की धर्ती लगभग नामजूर ही कर दी थी, क्योंकि उससे एक दिन पहले खुफिया विभाग के लोगों ने उनके स्टेशनफार् को, जिस तरह परेशान किया था उस तरह वह बहुत झुल्लाये हुए थे। लेकिन श्रीमती गांधी ने बकील बी० एन० खर ने, जिन्हें फसला सुनाये जाने के मुकिल से बारह घंटे पहले हवाई जहाज से श्रीनगर से इलाहाबाद पहुँचाया गया था, सिनहा साहब का समझाया कि मुजिल ने उनके स्टेशनफार् के साथ जो कुछ भी किया उसमें उनके मुवकिल का कोई दोष नहीं है। सिनहा साहब से बात मान ली।

5. 5. फँसले पर घमेल की स्थिति रखने के पक्ष में सारे साहब की दलील यह थी कि नया ता चुनने में कुछ समय लगेगा और अगर प्रधानमंत्री से तुरत अपना पद छोड़ देने को कहा गया तो सारे देश का प्रशासन अस्त-व्यस्त हो जायेगा।

6. 6. प्रधानमंत्री की कोठी अब तक मंत्रियों व्यापारियों बड़े बड़े सरकारी अफसरों और सुधामदियों से बचासच भर चुकी थी। सिनहा साहब को बुरा भला कहा जा रहा था। साथ ही इस ज्ञात पर शतों भी था कि उन्होंने अपने फसले पर समल स्थगित कर दिया था। अब उस वकालत को बचाने के लिए कुछ समय मिल गया था जिसकी छाया में अब तक इन लोगों को धरण मिली हुई थी, वैसे ही जैसे उनके पिता के जमाने में भी यज्ञोप वकालत की छाया में जनपते रहे थे।

7. 7. एकद की इस घड़ी में राजीव अपनी माँ के पास था। पर श्रीमती गांधी का फँसला था।

8. 8. अभी घंटे का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकानीन जन कृष घायर को टेलीफोन किया पर उन्होंने बात करने से इंकार कर दिया।

दूमरा बेटा सजय अपने मारुति¹ के कारखाने में था, जो 'जनता' मोटर बनाने के लिए लगाया गया था। इस सारी गड़बड़ी में किसी को उसे खबर भेजने का ध्यान ही नहीं आया था, हालांकि इधर कुछ दिनों से अपनी माँ को उन कम्युनिस्टों से बचाने के लिए, जिनसे उस नफरत थी, उसने राजनीति में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, उसका भाई राजीव राजनीति में कोई हिस्सा नहीं लेता था।

जब सजय अपनी विलायती मोटर पर दोपहर के समय घर लौटा तो बाहर उस एक भीड़ दिखायी दी। वह समझ गया कि क्या हुआ होगा और वह सीधा अपनी माँ के पास गया। उसने कहा कुछ नहीं पर उसे दखत ही माँ का चेहरा खिल उठा। सजय अभी भट्टाई में वप का था पर माँ अपने अनुभव में जानती थी कि उसकी सलाह कितनी 'तजुबेकार' लगेगी जसी होती थी।

श्रीमती गांधी ने कमरा बंद करके अपने परिवारवाला के साथ सलाह मचाविरा किया कि क्या करना चाहिए। उनके दोनों बेटे, राजीव और सजय इसके खिलाफ थे कि वह 5 छ दिन के लिए भी इस्तीफा दें। सजय ने यह बात ज्यादा जोर देकर कही। उसने उन्हें वही बात बतायी जो वह खुद पहले से जानती थी—विपक्ष के लोगों से ज्यादा उह खुद अपनी पार्टी के लोगों के ऊँचे होमला से डरना चाहिए।

इसके बाद वह अपने घर की सामान रखन की काठरी में चली गयी। जब भी किसी संकट का सामना होता था वह ऐसा ही करती थी। यही उनका शरण स्थल था जहाँ उन्हें सांजन का समय और अवसर मिलता था।

उह बहुत सी बातों के बारे में सोचना था। अगर मैं अभी इस्तीफा दे दूँ और मुश्रीम काट में बरी होने के बाद फिर वापस आ जाऊँ तो मेरे उन आलोचकों का मुँह बंद हो जायेगा, जो यह आरोप लगाते हैं कि मैं हर कीमत पर कुर्सी से चिपकी रहना चाहती हूँ। लेकिन अगर मुश्रीम काट में भी इनाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का सही ठहराया तो मुझे हमेशा के लिए अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और एक और बलक ऊपर से लगा रहेगा।

उह भ्रमाना नहीं था कि जो अपील वह दायर करेगी उस पर अन्तलत का रवैया क्या होगा। अबस पहले भी जिन सदस्यों का चुनाव हाईकोर्ट से रह हो गया था या पाबन्दी लगा दी गयी थी, उह भी सदन में बैठने की इजाजत दे दी गयी थी, लेकिन उह बोट में बहस में हिस्सा लेना या भत्ता पान का अधिकार नहीं हाता था। अगर अन्तलत ने कुछ गलत लगाकर फैसला उनके पक्ष में दिया तो ?

उनके सलाहकारों ने संविधान की 88वीं धारा का आसरा लगा रखा था, जिसमें कहा गया था कि 'कोर्ट देन का अधिकार' न हात पर भी किसी भी मंत्री या एटार्नी जनरल का दावा ही सदन में बोलने और बहस में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। स्वयंसेवादा किसी भी ढंग का हो पर अदालत यह अधिकार किसी भी मंत्री से नहीं छीन सकती थी।

अगर मैं इस्तीफा दे दूँ तो सारी दुनिया में मेरी बाह बाह होगी, एक सच्चे जनवादी की हैसियत से मेरी साख इतनी बढ़ जायेगी कि अबकी जब चुनाव होगा तो एक बार फिर 1971 की तरह सत्ता मेरे हाथ में आ जायेगी। लेकिन अगर मुश्रीम कोर्ट ने मुझ पर छ साल के लिए चुनाव न लड़ने की पाबन्दी लगा दी तो ? इतना समय तो बहुत हाता है—सत्ते समय में तो लोग मेरा किया हुआ सारा अच्छा काम जायेंगे, और खुद मेरी पार्टी के अंदर के और उसके बाहर के सत्ता के लालची

का मेरे गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने का काफी मौका मिल जायेगा।

सजय ही उनका भ्रमेला महारा था। उन्हें पूरा भरोसा था कि इस घाटे वक्त में वही उनके काम आयेगा। बहा जाना है कि 1971 के चुनाव में चुनाव जीतनेवाला यह नाग उत्ती का दिया हुआ था, 'वह कहते हैं 'इन्दिरा हटाओ', लेकिन मैं कहती हूँ 'गरीबी हटाओ'।' लेकिन अब मिफ नारा गढ़ लेने में काम नहीं चलनेवाला था। वह जानता था कि उसकी माँ आसानी से हार माननेवाली नहीं थी। लेकिन इस समय तो वह यही करने जा रही थी। ऐसा किसी हालत में नहीं होने दिया जायेगा। मुझे जनता का समयन जुटाना होगा। न सिर्फ माँ को यकीन दिलाने के लिए कि देश को उनकी जरूरत है, बल्कि उनके दुश्मनों को दूर रखने के लिए भी।

सजय ने दून स्कूल में अपनी पढाई बीच में ही छोड़ दी थी और फिर इंग्लैंड में रोल्स रायस के कारखाने में अप्रेंटिस मेकनिक रहा था। राजनीति में अपने पाँव जमाने के लिए उसे क्या कुछ न करना पड़ा था। धन और सत्ता दोनों से उसे बहुत लगाव था और अब ये दोनों ही चीजें उसे मिलना शुरू हो गयी थी।

उसके खास मददगार थे 35 वर्षीय राजेन्द्रकुमार धवन, जो प्रधानमंत्री के सफ्टवेयर में एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी थे। अब से कोई दस बारह साल पहले तक वह रेलवे में 450 रु० महीने पर मलक थे। धवन के पाम इस समय जो कुछ था वह सजय की बदौलत था, दोनों बहुत गहरे दोस्त थे और कितने ही हुगामों में दोनों साथ थे। श्रीमती गांधी का कोई भी काम पड़ता तो सबसे पहले उन्हीं का सीपा जाता। कुछ लोग तो उन्हें दूसरा एम० एम० मथाई भी कहते थे, जो नेहरू के स्टेनोग्राफर थे और उनके अप्पर में एक सबसे प्रभावशाली घादमी बन गये थे।

सजय इस तुच्छ सरकारी अफसर के सहारे सारी सरकार की मशीनरी को अपने इशारे पर नचाता था, या बात इसका उल्टी थी? धवन के हाथ में इतनी ताकत थी कि किसी भी छोटे भाटे मंत्री या बड़े से बड़े अफसर को तो वह चुटकिया में उड़ा सकता था, वह जो कुछ कहता था उसे प्रधानमंत्री का कहा हुआ समझा जाता था। एक बार उसने एक मंत्री को इस बात पर बहुत सताया कि उसने प्रधानमंत्री के सफ्टवेयर को किसी महत्वपूर्ण सवाल के बारे में याद दिलाने के लिए दूसरा पत्र भेज दिया था।

सजय के एक और बहुत गहरे दोस्त थे हानाकि वह उम्र में उससे बहुत बड़े थे। वह थे 52 वर्षीय बसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री जहाँ वह इस तरह शासन करते थे माना वह उनकी जागीर हो। उनको उचित अनुचित सही गलत की कोई परवाह नहीं थी। उह इससे कोई सरोकार नहीं था कि काम किन तरीकों से किया जाय बस अपना मतलब पूरा होना चाहिए। एक फटीचर वकील से तरक्की करके वह दम वप से भी कम में मुख्यमंत्री बन बैठे थे और इससे भी आगे बढ़ने की तमना रखते थे। उहान ही सजय को मार्गति के कारखाने के लिए कौटियों के मोल 290 एकड़ जमीन दे दी थी और यह कीमत चुकाने के लिए सरकारी वज ऊपर से दिलवा लिया था। इसके बदले में सजय ने उह प्रधानमंत्री के दरबारे-खास में पहुँचा दिया था। माँ और बेटे दोनों को उन पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वह हर वक्त उनके कानों पर हाजिर रहते थे, सही या गलत कोई भी काम दे दो पूरा कर देते थे।

श्रीमती गांधी इसी त्रिमूर्ति के बीच घिरी हुई थी। और उह इन पर सोलह घान भरोसा भी था। सरकार में पार्टी में और आमतौर पर सारी राजनीति में यन्ही लोग उनकी तरफ से सब-कुछ करते थे। वह जानती थी कि ये लोग कभी-कभी घाछे हपकड़े भी इस्तेमाल करते थे लेकिन दम में ता कोई शक नहीं था कि वे काम पूरा कर

देते थे। उन्होंने इन लोगों को मनमानी छूट दे रखी थी क्योंकि इससे उनके कदम और मजबूत होने थे।

एक और आदमी था जो आठ वक्ता में काम आता था। वह थे कांग्रेस के अध्यक्ष देवकान्त बरूआ। उन्हें लोग दरबारी मसखरा कहते थे और वह हरदम श्रीमती गांधी के गुण गाया करते थे। श्रीमती गांधी ही उन्हें असम राज्य की राजनीति से निकालकर लायी थी और उन्हें पहले बिहार का गवर्नर, फिर अपने मंत्रिमण्डल का मंत्री और अन्त में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया था। अब वह उनका सहारा ले सकती थी।

श्रीमती गांधी उन्हें अपने पति की रोज़ गांधी के एक दोस्त की हैसियत से जानती थी। पति और पत्नी के बीच, जो दोनों ही अपने हठ के पक्के थे, आयेदिन जो झगड़े उठ खड़े होते थे उनमें बरूआ ने अक्सर बीच में पड़कर सुलह ममभीता कराया था। बरूआ का दक्षिणपंथी कम्युनिस्टों के साथ भी मेल जोल रह चुका था क्योंकि उससे उनको एक विचारधारा की चमक दमक मिल गयी थी, जिसका एक पिछड़े हुए देश में बहुत अच्छा असर पड़ता है। यह बात सजय का पसंद नहीं थी। वह उन्हें तिरस्कार से 'कॉमी' (कम्युनिस्ट का सक्षिप्त रूप) कहता था, लेकिन जब दाना ही का विपक्ष की ओर से खतरे का सामना करना पड़ा तो बरूआ और सजय कम से कम उस वक्त तो साथ आ ही गये।

जल्द ही वे दोनों सारी दुनिया के सामने यह साबित करने में जुट गये कि एक जज कुछ भी कहता रहे पर जनता का इसमें जरा भी शक नहीं था कि श्रीमती गांधी उसकी चुनौती हुईं नहीं थी और रह गयीं। उन्होंने पहला कदम यह उठाया कि उनकी लोकप्रियता को 'साबित करने' के लिए भीड़ें जुटाना शुरू किया। यह तमाशा वे पहले भी कई बार कर चुके थे। जबदस्ती टुकें जमा करके गांधी में भेजी गयी कि लोगों को अपने नेता के साथ बफ़ागारी का सबूत देने के लिये। सफ़दरजंग रोड पर श्रीमती गांधी की कोठी पर लायें। सरकारी (दिल्ली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की) बसें लोगों की भीड़ को भुपन लाने के लिए धड़ल्ले के साथ इस्तमाल की गयी। यह दूसरी बात है कि इन मीटिंगों के बाद लोगों को भुपन वापस लाने का कोई बंदोबस्त नहीं था और उन्हें पदल ही रगड़ते हुए घर वापस जाना पड़ा।

प्रधानमंत्री की कोठी से घबन ने आस पास के राज्यों, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को ऐसी ही मीटिंगें कराने के लिए टेलीफोन किया। उन्हें भीड़ें जुटाने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी लगा देने का बहुत अनुभव था। जुलाई 1969 में वे यह कर चुके थे, जब श्रीमती गांधी न 'प्रगतिशील' रूप धारण करने के लिए भारत के चौदह बड़े बच्चों के राष्ट्रीयकरण का फैसला किया था, साथ ही अब वह यह भी दिखाना चाहती थी कि कांग्रेस में उनके प्रतिद्वंद्वी 7-वर्षीय मोरारजी देसाई दक्षिणपंथी हैं क्योंकि वह वक्ता पर सिर्फ सामाजिक नियंत्रण लागू करना चाहते थे।

देसाई दो बार प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर चुके थे। एक बार 1966 में, जब श्रीमती गांधी से पहलेवाले प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री का ताकद में देहान्त हो गया था, और दुबारा 1967 में जब कांग्रेस उस समय की लोकसभा की 520 सीटों में से केवल 285 सीटें जीत पायी थी और किसी तरह बड़ी मुश्किल से उसने सत्ता अपने हाथ में सभाल रखी थी।

घबन ने जनता का समयन जुटाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी क्योंकि यशपाल कपूर जो इन बातों का ज़्यादा तजुर्गा रखते थे, इन दिनों नज़र से गिर गये। लोग उन्हें इस बात के लिए बहुत बुरा मता कह रहे थे कि उन्होंने की

श्रीमती गांधी मुसीबत में फँसी और उन पर चुनाव में भ्रष्ट आचरण का आरोप लगा। लेकिन धन यशपाल कपूर की वहुन के बेट थे और उन्होंने अपने मामा से बहुत-कुछ सीखा था। यशपाल कपूर भी रक्त से राजा बन थे। एक मामूली स्टेनोग्राफर से बढ़कर वह राज्यसभा के सदस्य बन गये थे, और इससे भी बड़ी बात यह थी कि वह श्रीमती गांधी के राजनीतिक सलाहकार और मुखबिर थे। कपूर हवा बंधन में बहुत माहिर थे जब भी श्रीमती गांधी की जनता में अपनी सास ऊँची करत व लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ी थी तो यशपाल कपूर बहुत काम धाम्ये थे। वह जानते थे कि किस मोके पर बीन-सी डोरी खींची जाये।

कुछ दिन तक वह रुठे हुए अपने घर पर ही पड़े रह। उनसे कह दिया गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फँसल में खुश उनका चर्चा खास तौर पर किया गया है इसलिए वह जनता की नजरो के सामने न आयें। बाद में उन्हें फिर वापस बुला लिया गया। यह नारा उन्होंने ही गढ़ा था कि 'देश की नेता इन्दिरा गांधी। बरफ़ा न यह कहकर कि 'इन्दिरा ही भारत हैं उसमें चार चाँद लगा दिये। बरफ़ा न यह सोचा भी नहीं था कि इसकी वजह से बहुत उलभन पैदा हो जायगी क्योंकि यह नारा उस समय से बहुत मिलता जुलता था जो नाज़ी नौजवानों को दिलायी जाती थी 'एडाल्ट हिटलर ही जमनी है और जमनी एडोल्फ हिटलर है।'

मुस्यमन्त्रियों को लोगो को बसो में भर भरकर श्रीमती गांधी की काठी के बाहरवाले चौराह पर भेजने में बहुत समय नहीं लगा। 1969 में जब बी० बी० गिरि भारत के राष्ट्रपति चने गये थे उसी दिन से वहाँ इस तरह के जलस-जुलूसों के लिए एक बना-बनाया मंच मौजूद था। उस समय श्रीमती गांधी ने इस पद के लिए खुद कांग्रेस के उम्मीदवार सजीव रेड्डी का विरोध किया था और उस समय भी प्रतिक्रिया और प्रगति की लड़ाई में उनके प्रति अपने समर्थन का सबूत देने के लिए भी 'जुटाई गयी थी।

जाहिर है, जनता के लिए राजनीति की सीधे सादे शब्दा में पेश करना जरूरी था। विचारधारा, या विचारधारा को मानने का दावा करने का अपना अलग महत्व था। कांग्रेस बहुत धरसे से 'जनवाद' और 'समाजवादी सिद्धांतों का दम भरती आयी थी, और इसी वजह से वह उस 'समाजवादी सिद्धांतों का दम भरती थी जो कि सोशलिस्ट पार्टी की योजना का हिस्सा था। उस समय प्रतिक्रियावादी' की टक्कर पर प्रगतिशील शब्द का बहुत चलन था। श्रीमती गांधी प्रगतिशील थी और सोशलिस्ट राजनारायण प्रतिक्रियावादी थे, और वह जान भी जिसने कुछ प्रतिक्रियावादी कानूनों का सहारा लेकर अपना फसला सुनाया था।

फँसला तो जल्द ही एक भायी गयी बात हो गया। श्रीमती गांधी ने यह जता दिया कि वह अपनी गद्दी छोड़नेवाली नहीं हैं क्योंकि जनता के विश्वास के सहारे वह गरीबी हटान और एक नया समाज बनाने के लिए काम करती रहेगी। कांग्रेस व छात्र संगठन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ न जो बाद में सजय गांधी का मना युवक कांग्रेस में मिलीन हो गया बहा श्रीमती गांधी भारत व कराडा द बुचल लोग भार शोषित जनता की नेता हैं, 'याय और बरावरी की बुनियाद पर समाज का बदलकर समाजवादी ढंग का बना दन के संघर्ष में वह उनका नेतृत्व कर रही हैं। उसन उनके खिलाफ हाइकोर्ट व फसल व वारे में एक शत्रु भी नहीं बहा।

श्रीमती गांधी के लिए समर्थन की यह नुमाइश इतनी भाड़ी थी कि कांग्रेस व कुछ ससद सदस्यों ने जनता की बहुलानवाल इन जलस-जुलूस पर नाक भी लिकाड़ी। लेकिन श्रीमती गांधी का एक ही जवाब था यह सब-कुछ अपने आप हो रहा है।

देग में से ठो-साहूकारों के पाँचों सगठनों ने घोर बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने भी श्रीमती गांधी के समयन में अपनी भावाज उठायी। उनके 'समाजवादी ढंग के' रवैये के बावजूद ये लोग जानते थे कि अपनी धन-सम्पत्ति और अपने विशेषाधिकारों को बचाये रखने के लिए उन्हीं का सहारा लेना सबसे अच्छा है। उनकी नीतियाँ उन समाजवादी नीतियों से तो कहीं अच्छी थी जिन्हें लागू करने का विपक्ष के बहुत से लोग दावा करते थे। उनकी पीठ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी हाथ था, जिसने अपने 13 जून के प्रस्ताव में कहा था, "दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादो तथाकथित नैतिक आधारों पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे के लिए छात्रों से जो शोर मचवा रहे हैं, उसमें उनके खतरनाक राजनीतिक उद्देश्य छिप नहीं रह सकते।" पार्टी जिसका रवैया सोवियत समयक था, यह उम्मीद करती थी कि वह कांग्रेस के कंधों पर बैठकर कम्युनिस्ट राज्यसत्ता के दरवाजे तक पहुँच जायेगी।

श्रीमती गांधी ने अपना विश्वास व्यक्त करने में जामिया मिलिया इस्लामिया और भारतीय दलित वगैरह सच जैसी सस्थाएँ भी पीछे नहीं रही। कई वर्षों से वह और उनके पिता धर्म निरपेक्ष समाज बनाने की कोशिश करते आये थे। ये लोग विपक्ष पर कसे भरोसा कर सकते थे, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक सच का ससदीय सगठन जनसच शामिल था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक सच एक हिंदू सगठन था जो हिंदू सस्कृति के आधार पर, या जिसे उसके संचालक भारतीय सस्कृति कहते थे, एक अनुशासनबद्ध समाज बनाने में विश्वास रखता था।

इस बात के बारे में तो किसी की कोई शक नहीं था कि अगर श्रीमती गांधी का वेटा उनके लिए किराये की भीड़ें न भी जुटाता तब भी उन्हें बहुत व्यापक समयन प्राप्त था। विपक्ष भले ही यह कहता रहे कि असल सवाल यह है कि एक अपराधी प्रधानमंत्री को अपने पद पर बने रहना चाहिए या नहीं और उन लोगों के खिलाफ जनता की चेतावनी देता रहे जो एक अदासती पसले को सड़को पर चुनौती देकर देश के जनवादी ढाँचे को तहस नहस कर देने पर तुले हुए थे। लेकिन उनकी भावाज श्रीमती गांधी की जयजयकार के नारा में लगभग बिल्कुल डबकर रह गयी।

कुछ मीजवान सोशलिस्टों ने असबत्ता जवाबी प्रदर्शन करने की कोशिश की। जब उनमें से कुछ लोग प्रधानमंत्री की कोठी के बाहर पुलिस का घेरा तोड़कर अंदर चले गए और 'इन्दिरा गांधी, इस्तीफा दे' के नार लगाने लगे तो सच गांधी की छास मददगार लम्बे बंद और खूबसूरत नाक-नकने वाली अशिका सोनी ने भपटकर एक लडके को थप्पड़ मार दिया। 35-वर्षीया अशिका सोनी, जो आगे चलकर युवक कांग्रेस की प्रेसिडेंट बननेवाली थी, यह साबित कर रही थी कि वह किसी से पीछे रहनेवाली औरत नहीं है। यह देखकर पुलिस को भी फौरन जोस आ गया, विरोध का स्वर उठानेवालों को बुरी तरह पीटा गया और उनमें से कुछ गिरफ्तार किये गये।

लेकिन इस सब विपक्ष ने हिम्मत नहीं हारी। साबित-समयक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर, जो श्रीमती गांधी का इसलिए साथ देती थी कि वह समझती थी कि उनका भुकाव इस की तरफ है विपक्ष की सभी पार्टियों ने ऐलान कर दिया कि वे उन्हें अपना प्रधानमंत्री नहीं मानती। उन्होंने उन पर इस बात के लिए धार किया कि हाईकोर्ट के पसले में अपराधी ठहरा दिये जाने के बाद भी वह गद्दी से नहीं हटेंगे।

उन सबके लिए—पुराने नेताओं की कांग्रेस पार्टी, हिंदू राष्ट्रवादी किसानों के हितों के समयक भारतीय सावदत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में

निकली हुई माफ़सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्टो के लिए—इलाहाबाद हाई-कोर्ट का फैसला मुँहमांगा बरदान था। वे बर्द बातो के लिए—अप्टाचार, जनवाणी परम्परावादी की तनिक भी परवाह न करने डिक्टेटरशिप की और बदन की प्रवृत्ति आदि के लिए—श्रीमती गांधी पर बार बार हमले कर चुके थे, लेकिन कोई भी तरकीब काम नहीं करती थी।

जो काम वे बरसों में नहीं कर पाय थे वह अब अदानत के फसले में उनकी तरफ से कर दिया था। उन्होंने श्रीमती गांधी के इस्तीफे की माँग की और राष्ट्रपति भवन के सामने घरना दिया हालाँकि राष्ट्रपति उन दिना न मीर गय हूए थे। उन्होंने कहा कि वे श्रीमती गांधी के खिलाफ और भी कानूनी कारवाइयाँ करेंगे और उन्होंने विभिन्न राज्या में अपनी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को इन्दिरा विरोधी मीटिंग और प्रदर्शनों की मुहिम तेज कर देने का आदेश दे दिया।

विपक्ष की सब पार्टियों को मिलाकर भी सदन में उनके साठ सदस्य भी नहीं थे। लेकिन अब उनका पलड़ा भारी था। उन्होंने नतिकता और उचित आचरण का मवाल उठाया और जयप्रकाश नारायण को जो महात्मा गांधी के बाद राष्ट्र के अन्तरात्मा के रखवाले माने जाते थे सदैव भिजवाया कि आकर हमारा नेतृत्व कीजिये।

वह अपने लिए जयप्रकाश से अच्छा कोई नेता चुन ही नहीं सकते थे हालाँकि 1974 में वह जयप्रकाश नारायण को निराश कर चुके थे क्योंकि उन्होंने उनकी यह सलाह नहीं मानी थी कि वे सब एक ही पार्टी में मिलकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ें। जयप्रकाश गांधीवादी थे और अंग्रेजों के खिलाफ 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के हारो रक्त चुके थे। वह हमेशा दबे कुचले और हर चीज से दचित उन बहुमत देश-वासियों की तरफ से आवाज उठाते रहे थे जिनकी अपनी कोई आवाज नहीं थी। एक लम्बे अरसे के दौरान वह सावजनिक जीवन में साफ सुथरेपन और ईमानदारी का प्रतीक बन गये थे। उन्होंने अपने बिहार राज्य में सावजनिक जीवन में बढ़ते हुए अप्टाचार के खिलाफ जो आन्दोलन शुरू किया था वह धीरे धीरे ठंडा पड़ गया था। वह आन्दोलन राज्य विधानसभा को मग कराने जसे मामूली लक्ष्य में घिरकर रह गया था और उसने उन उच्चतर नतिक लक्ष्या का भुला दिया था जिन्हें जयप्रकाश नारायण पूरा करना चाहते थे—एक ऐसा सच्चा जनवादी ढाँचा बनान की आवश्यकता, जो जनता की जरूरतों को पूरा करने के उपाय कर सके और राजनीति को अवमरवाद से छटकारा दिलाता। लेकिन बिहार आन्दोलन के दौरान जो पड़ लगाया गया था उसमें दो बप बाद फल लगे।

अब से पहले जयप्रकाश श्रीमती गांधी में इस बात पर भगडा करते रहे थे कि उन्होंने अप्टाचार को बढ़ावा दिया और समाजवाद के लक्ष्य के साथ गद्दारी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फसले में उन्हें नतिक पुनस्तथान की सार्वजनिक जीवन के मानदंडों का स्तर ऊँचा उठाने की सजाई फिर शुरू करन का सुनहरा अवसर दिखायी दिया।

बहुत अरस तक उनके और श्रीमती गांधी के बीच चाचा भतीजी जमे सम्बन्ध रहे थे और वह उह इटु कहते थे। लेकिन कई वर्षों से, खास तौर पर पिछले दो वर्षों से वे दोनों एक दूसरे में दूर होत गये थे। वह श्रीमती गांधी को सारे अप्टाचार की जड समझत थे और उनकी राय थी कि श्रीमती गांधी न बुनियादी आदर्शों को नष्ट कर दिया है। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फसले के बाद उन्होंने कहा कि श्रीमती गांधी का प्रधानमंत्री बन रहन का कोई अधिकार नहीं है। उह फौरन पद में हट जाना चाहिए। उनका गद्दी से चिपके रहना 'सावजनिक जीवन में गिप्टता और जन-

वाणी प्राचरण के सरासर खिलाफ' था।

श्रीमती गांधी जानती थी कि जयप्रकाश की ताकत से इकार नहीं किया जा सकता। जब वह 1 नवम्बर 1974 को उनसे मिले थे—इस मुलाकात का बंदोबस्त दुर्गाप्रसाद घर ने कराया था—तो श्रीमती गांधी इस बात पर राजी हो गयी थी कि अगर वह कोई और माँग न रखें तो बिहार की विधानसभा भंग कर दी जायेगी। जयप्रकाश इसके लिए राजी नहीं हुए।

जयप्रकाश नारायण को 17 जून को विपक्ष की पार्टियों का एक फौरी सन्देश मिला कि वह फौरन दिल्ली आकर उनकी विशाल रली की अगुवाई करें। लेकिन उन्होंने इकार कर दिया। वह उसके पक्ष में थे कि श्रीमती गांधी ने जा अपील दायर की थी उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद ही कोई तड़ाई छेड़ी जाय।

जयप्रकाश अच्छी तरह जानते थे कि अगर विपक्ष की पार्टियाँ मिलकर एक हो जायें तो उनकी ताकत बेहद बढ़ जायेगी। गुजरात विधानसभा के चुनाव में जनता मोर्चे की सफलता इस बात का काफी सबूत था, जहाँ उसने 182 सदस्यों के सदन में 87 सीटें जीती थी, और छ निदलीय सदस्यों के आकर मिल जाय स जनता पार्टी की पूरा बहुमत मिल गया था। कांग्रेस को सिर्फ 74 सीटें मिली थी, जबकि 1972 के चुनाव में, जब विपक्ष की पार्टियों में कोई एका नहीं था, उसने 140 सीटें जीती थी।

इस चुनाव से पहले वहाँ जयप्रकाश की 'सम्पूर्ण जाति' की पहली मुहिम चल चुकी थी। जयप्रकाश गुजरात जसा आ दोलन सारे देश में छेड़ना चाहते थे। मौका बहुत अच्छा था लेकिन पहले वह यह सुन लेना चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का श्रीमती गांधी की अपील के बारे में क्या कहना है। उन्हें उम्मीद थी कि कानून की परम्पराओं को देखते हुए देश का सर्वोच्च यामालय जस्टिस सिन्हा के फसले को सही ठहराने के मलावा और कुछ कर ही नहीं सकता।

श्रीमती गांधी भी इतजार कर रही थी और उन्हें भी यही उम्मीद थी कि म्दालत कानून का अक्षरशः पालन करने के बजाय उसकी असली भावना के अनुसार फैसला देगी।

अब चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर विपक्ष की सभी पार्टियों ने उन्हें प्रधान मंत्री न मानने का ऐलान कर दिया था इसलिए उनके लिए मुसीबतों ही मुसीबतों का सामना था। सदन की बैठक में वह किस मुँह से जायेंगी।

मा ही उन्हें सदन सदस्य तुलमोहन राम को दिये गये इपाट परमिट के बार में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सी० बी० आई०) की रिपोर्ट के सिलसिले में सदन में काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। तुलमोहन राम रेल मंत्री ललितनारायण मिश्र के साथ आदमी थे, और इसमें पहले कि यह परमिट जारी करने की जिम्मेदारी किसी के खिलाफ साबित की जा सकती, 3 जनवरी 1975 को ललितनारायण मिश्र की हत्या कर दी गयी थी।

एक बार मोरारजी देसाई न घमकी दी थी कि सी० बी० आई० की रिपोर्ट सबके सामने पेश करने की विपक्ष की एकमत माँग अगर पूरी न की गयी तो वह सदन में सत्याग्रह कर देंगे। श्रीमती गांधी ने स्पीकर गुरदयालसिंह दित्ता से बहुत अकड़कर माँग की थी कि मोरारजी देसाई को इस बात पर सदन में बाहर निकाल दिया जाये। बाद में वह स्पीकर के इस फैसले पर बहुत झुझलायी कि वह और मोरारजी उनसे उनके चर में मिलें। उन्हें यह अपमान इसलिए चुपचाप सह लेना पड़ा कि जब स्पीकर ने सुना कि उन्हें उनका यह फैसला अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और

श्रीमती गांधी को उह समझा बुझाकर राजी करना पडा कि वह अपने पत्र पर बने रह।

इस तरह की गद्दी अपवाह भी उठ रही थी कि ललितनारायण मिश्र को मरवा देने में उनका हाथ था। यह सच है कि इपोट साइसेंस कांड में उनका हाथ होने की सम्भावना के बारे में जो ले देहो रही थी उसकी वजह से उन्होंने उनसे इस्तीफा देने को ज़रूर कहा था। पर उह इस बात पर पछतावा हो रहा था और वह अपने आपकी अपराधी ममझ रही थी कि ललितनारायण मिश्र को उनका साथ देने की कीमत अपने प्राणों में चुकानी पनी थी। सजय और धवन न रल भवन में मिश्रजी के दफ्तर पर सील लगवा दी लेकिन इसी वजह यह थी कि उन्होंने वहाँ मारति के बारे में कुछ कागजात जमा कर रहे थे और वे लोग नहीं चाहत थे कि वे कागजात किसी दूसरे के हाथ में पड़ें। श्रीमती गांधी को भी इस बात का पता चला लेकिन अभी तक चूकि उन्होंने कभी मारति के मामले में दखल नहीं दिया था इसलिए अब भी उन्होंने इसकी कोई ज़रूरत नहीं समझी।

यह मामला भी ससद में उठेगा। श्रीमती गांधी ने ससद का जुलाई प्रगस्त अधिवेशन टलवा देने की बात भी सोची। अगर इपोट साइसेंस कांड पर बहस के दौरान विपक्ष में सत्तन की कोई कारवाई नहीं चलने दी थी, तो इलाहाबाद के फसले के बाद तो उसका बर्ताव और भी बुरा होगा। और यह नहीं कहा जा सकता था कि कामचलाऊ प्रधानमंत्री का इन दबावा के सामने क्या रवया होगा।

अपने पद पर बने रहने से उह घटनाक्रम की अपन हिसाब से मांड सबने का थोड़ा बहुत तो मौका मिलेगा। वह किसी हालत में इस्तीफा दे ही नहीं सकती थी। लेकिन दूसरों का इसका पता नहीं चलने देना चाहिए। लोग उन पर यह धुबहा करें कि वह हर हालत में अपनी गद्दी से चिपकी रहना चाहती है। इससे तो कहीं अच्छा होगा कि वह यह जताये कि दूसरा के समझाने बुझाने पर ही वह इसके लिए राजी हुई है। शायद उनका जवाब पहले से जानते हुए भी उन्होंने अपन मंत्रिमण्डल के पुराने अनुभवों साधिया जगजीवनराम, गणवतराव चट्टाण और स्वर्णसिंह से पूछा कि क्या मरी अपील पर सुप्रीम कोर्ट का फसला आन तक भरे लिए अपने पद पर बने रहना मुनासिब होगा। तीनों ही ने कहा कि अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो गजब हो जायगा। लेकिन ऐसा कहने के लिए उन सबकी वजह अलग अलग थी।

जगजीवनराम ने कहा कि उह प्रदानती कारवाई का सिलसिला पूरा हो जाने तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन उह अनेशा था कि सुप्रीम कोर्ट कुछ शर्तों के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के फसले की स्थगित रखने की मजूरी दया क्योंकि ऐसे मामले में अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कभी बिना किसी शर्त के इस तरह की मजूरी नहीं वकन होग। उन्होंने मुझसे उही निना कहा था "हम सुप्रीम कोर्ट के फसले तक बड़ी आसानी से इंतजार कर सकते हैं।"

पिछल कुछ वर्षों के दौरान श्रीमती गांधी के साथ जगजीवनराम के सम्बन्ध गिगडन गये थे। यहाँ तक कि इधर कुछ दिनों में बड़े बड़े सवाल को कौन कहे, छाट छोटे सवाल पर भी उनमें सलाह नहीं ली जा रही थी। श्रीमती गांधी हमेशा से जानती थी कि पार्टी में वह उनके सबसे बड़े प्रतिद्वन्द्वियों में से थे और 1969 में जाकिर हुसैन के मरने के बाद उन्होंने यही सोचकर उह राष्ट्रपति के पद के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने का सुझाव रखा था कि शायद वह उस ऊंचे पद के लाभ का जायेंगे। उह मंत्रिमण्डल में रखने के मुकाबले इस सजावटी पत्र पर रखने में

कोई खतरा नहीं था।

यह सच है कि श्रीमती गांधी ने उन्हें इस बात के लिए माफ कर दिया था कि वह दस साल तक इनकम टैक्स देना भूल गये थे। लेकिन जगजीवनराम यह समझते थे कि उन्होंने मोरारजी के खिलाफ उनका साथ देकर यह कज चुका दिया है, हालांकि 1963 में उनके पिता जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के पुनर्गठन के नाम पर कामराज योजना में जब जगजीवनराम और मोरारजी दोनों को मंत्रिमण्डल से निराला दिया था तो दोनों राजनीति के निर्जन वन में साथ साथ भटकते रह गये। वह बहुत चालाक और भट्ठावादी आदमी थे और श्रीमती गांधी इस बात को जानती थी। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ हुआ तो विद्रोह का जोखिम उठाये बिना ही प्रधानमंत्री का ताज अपने घास ही उन्हें पहना दिया जायेगा। जाहिर है कि ऐसी हालत में जगजीवनराम को फैसले तक इन्तजार कर देने में तकलीफ ही क्या हो सकती थी।

बह्मण के लिए जब तक श्रीमती गांधी बनी हुई थी तभी तक वह भी बने हुए थे। उनकी तमना बस यही थी कि उनके बाद दूसरे नम्बर पर बह्मि माने जायें। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में इस भरोसे पर कि उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जायगा उन्होंने कांग्रेस के पुराने सूरमाओं के साथ वोट दिया था लेकिन जब पुराने नेताओं की मण्डली ने सौदेबाजी शुरू कर दी तो वह फिर श्रीमती गांधी के साथ आ गये। इसलिए विपक्ष वालों के बीच उनकी साख बहुत गिर चुकी थी। जयप्रकाश नारायण के साफ शब्दों में यह कह देने के बाद कि प्रधानमंत्री के पद पर उनके मुकाबले में वह जगजीवनराम को ज्यादा पसन्द करेंगे उन्हें अब श्रीमती गांधी का साथ छोड़ने में कोई फायदा नहीं था।

स्वर्णसिंह की साख यह थी कि उनसे किसी का कोई भगडा नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने एक खास आदमी से उन्होंने मुना कि अगर उन्होंने कभी भी थोड़ा दिन के लिए भी अपने पद से इस्तीफा दिया तो अंतरिम काल में वह उन्हीं को प्रधानमंत्री बनायेंगी तो उनकी उममें भी जाग उठी वह समझते थे कि वह खुद ही इस्तीफा दे देंगी और हालांकि उन्होंने उनको ऐसा न करने की सलाह दी, लेकिन साथ ही यह भी जता दिया कि अगर वह इस्तीफा दे भी दें तब भी कोई हज नहीं है।

श्रीमती गांधी के बानूनी मलाहकार खासतौर पर सिद्धांतशक्ति के और गोखले भी (जिन्होंने इलाहाबाद में उनके मुकदमे को चौपट करके रख दिया था) उनके इस्तीफा देने के खिलाफ थे। उनकी दलील यह थी कि सुप्रीम कोर्ट 'दशकों की खुश बरन' की कोशिश नहीं करेगा जैसा कि इलाहाबाद के जज ने किया था और इसलिए उन्हें फसले का इंतजार करना चाहिए। कुछ धीर लगाये, जिनका कानून से कोई मतलब नहीं था, यह समझाया कि जिन अपराधों के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है वे सिर्फ तकनीकी अपराध हैं।

इस बात से तसल्ली तो बहुत मिली लेकिन देश में बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनकी समझ में यह बात नहीं आयी कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में यह कहा गया है कि कुछ अपराध तकनीकी होते हैं और कुछ ठोस अपराध होते हैं। 1951 में दो तरह के अपराध हुआ करते थे—मामूली और सगीन। चुनाव रद्द सिर्फ सगीन अपराधों की बुनियाद पर किये जाते थे। लेकिन 1956 में नेहरू के खमाने में चुनाव के

1 कांग्रेस के पुराने नेताओं की मण्डली में जिस विद्रोह के बहा जाया था बह्मण से कहा कि वह चुनाव तक के लिए मोरारजी को प्रधानमंत्री बन जाने दें जो 1972 में होनेवाले थे।

2 जयप्रकाश नारायण ने यह बात मुझको 1974 में अजमेर के लिए एक इंटरव्यू के दौरान बतायी।

वाननो मे हेर फेर करके उह आसान बना दिया गया। जिन अपराधों को भ्रष्ट आचरण माना गया था उनकी सूची वाट छांटकर बहुत छोटी कर दी गयी थी। लेकिन सरकारी नौकरो को चुनाव के काम के लिए इस्तमाल करना अब भी अपराध माना गया था। राज्यों के कई मंत्री और ससद के सदस्य और विधायक इसी बुनियाद पर अपनी सीटें खो चुके थे। जब श्रीमती गांधी के मंत्रिमण्डल के आंध्र प्रदेश के मंत्री चेन्ना रेड्डी को चुनाव में भ्रष्टाचार के तरीके अपनाने का अपराध ठहराया गया था तो उन्होंने खुद उनसे इस्तीफा देने को कहा था।

इसी उमूल पर चलकर तो उह भी इस्तीफा दे देना चाहिए था। वह पार्टी के नेताओं से सलाह माशविरा करती रही और इन लोगो ने समझा कि यह उनके दुर्नियुक्तन की निशानी है। वे लोग खुद अपने अपने राज्यों के ससद-सदस्यों से सलाह माशविरा करने लगे।

सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग चन्द्रजीत यादव के घर पर हुई, जो केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में एक राज्यमंत्री थे और कुछ कम्युनिस्ट विचार रखते थे। बरमा ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की। कांग्रेस के केवल कुछ गिन चुने भरोसा के नेताओं को इस मीटिंग में बुलाया गया था। उनमें प्रणव मुखर्जी भी थे, जो उस समय बहुत ही छोटे मंत्री थे। इन लोगो ने इस सवाल पर विचार किया कि अगर श्रीमती गांधी को कुछ दिन के लिए भी अपना पद छोड़ना पड़े तो उनकी जगह प्रधानमंत्री बिसको बनाया जाये।

दो में से एक को चुना था—जगजीवनराम या स्वर्णसिंह। स्वादातर लोग स्वर्णसिंह के पक्ष में थे क्योंकि उनके बारे में यह समझा जाता था कि उनसे किसी तरह का खतरा नहीं है और उनसे-को भी कहा जायेगा वही करेंगे। लेकिन जगजीवनराम मंत्रिमण्डल के सबसे पुराने सदस्य थे और उनको इस तरह रास्ते से हटा देने का मतलब यही था कि इन लोगों के मन में जो यह डर था कि अगर सुप्रीम काट न श्रीमती गांधी को बरी भी कर दिया तो भी जगजीवनराम पर यह भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह उनके लिए फिर गद्दी खाली कर देंगे, वह डर खुलेआम सबके सामने जाहिर हो जाता। इन लोगों की सम्झ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाये। इस मौके पर जगजीवनराम ने जिस तरह श्रीमती गांधी का साथ दिया था उससे तो इन लोगो का यही लगा कि शायद श्रीमती गांधी को भी उन पर भरोसा करने में कोई सकोच नहीं होता। और अगर उनको नजरअंदाज किया गया और उन्होंने विद्रोह कर दिया तो शायद पार्टी टूट जाय। ये लोग कोई फसला नहीं कर सके। प्रणव ने मुझे बताया कि अगर सिद्धांशानुसार के केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में होते तो भी वे उही को अन्तरिम प्रधानमंत्री बना दिया जाता। शायद जगजीवनराम के लिए भी उनसे टक्कर लेना मुश्किल होता।

लेकिन यह बारी अटक्लवाजी थी। श्रीमती गांधी अभी अपने पद पर बनी हुई थी और जब तब वह अपने पद पर थी तब तब इस बात का पूरा यकीन था कि उह वही भरपूर समयन मिलता रहगा जो हमेशा मिलता रहा था।

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के गत्रियों मुख्यमंत्रिया और राज्य के मंत्रियों से पूछा गया कि वे श्रीमती गांधी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट करते हुए एक क्षण पर दस्तखत करें। चूकि परभेदवरनाम हवस² मसविदा बहुत अच्छा तयार करना जात थे इसलिए इस क्षण

1 मंत्रिमण्डल के अध्यक्षों बनने से पहले वह केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में शिक्षामंत्री थे।

2 हकसर किता उमान में प्रधानमंत्री के सबसे पहले कर्मचारी थे लेकिन बाद में जब उन्होंने उनकी यह समझने का बौद्धिक को कि वह सत्य और गणपान कपूर को खदावा न दें तो उह दूध, मन्त्रियों की तरह निराल कैंका गया और योजना आयोग का डिप्टी चेयरमन बना दिया गया।

को शब्दों में पिरोने का काम उही को सौंपा गया। 1969 में जब कांग्रेस के दो टुकड़े हो गये थे उसके दौरान दूसरे पक्ष को भेजे गये लगभग सभी पत्रों का मसविदा उन्होंने ही तैयार किया था। हक्सर के मसविदे में डके छुपे ढंग से अदालतों की भी आलोचना की गयी थी लेकिन इसे बदल दिया गया क्योंकि जजा को नाराज कराने से कोई फायदा नहीं था जबकि सुप्रीम कोर्ट में श्रीमती गांधी की अपील की सुनवाई होना अभी बाकी थी। लेकिन उनके मसविदे का जो अमली हिस्सा था वह ज्यों का त्यों रहन दिया गया "श्रीमती गांधी अब भी प्रधानमंत्री हैं। हम अच्छी तरह सोच विचार करके इस पक्षके नतीजे पर पहुँचे हैं कि देश की अखण्डता, स्थायित्व और प्रगति के लिए उनका गति-ज्ञान नेतृत्व नितांत आवश्यक है।"

इस बयान पर दस्तखत करने के लिए होड़ लग गयी, क्योंकि इस वफादारी का पट्टा समझा जाने लगा था। सजय अपनी माँ को बराबर बताता रहता था कि किस-किसने अब तक दस्तखत कर दिये हैं। और भला ऐसा कौन था जिसने दस्तखत न किये हों? अखबारों में इन नामों की जो सूची छपी वह बराबर बढ़ती ही जा रही थी।

उड़ीसा की मुख्यमंत्री श्रीमती नंदिनी सरपथी उस पर दस्तखत करने के लिए भुवनेश्वर से दिल्ली रात को कुछ देर से पहुँची और इस बात पर हठ करने लगी कि अगले दिन सुबह के अखबारों में दस्तखत करनेवाला की जो सूची छप उसमें उनका नाम भी शामिल रहे। सरकार के सूचना कार्यालय के सफसरी ने सम्पादकों को टीलीफोन करके इसका पक्का बन्दोबस्त करा दिया। इस बात का बहुत महत्व था कि सब लोग जान लें कि कौन कौन श्रीमती गांधी का वफादार है। एक मंत्री जिहान प्रधान मंत्री की कोठी से बार बार टेलीफोन किये जाने पर भी दस्तखत करने में देर की वह थे स्वर्णसिंह। वह अपने दिमाग से किसी तरह यह बात नहीं निकाल पा रहे थे कि अगर श्रीमती गांधी इस्तीफा दे दें तो वह अंतरिम प्रधानमंत्री बन जायेंगे। और कई महीने बाद उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी।

इस बीच बाहरों और करबों में राज्या की सरकारों और पार्टियों ने अपने-अपने खर्चों से लाखों लोगों के प्रदर्शन संगठित किये थे, जो सबको पर नारे लगात फिरत थे कि 'हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते।' इसमें यह मतलब भी छिपा हुआ था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला दिया तो वे सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं मानेंगे। श्रीमती गांधी और उनके लोग हर सूरत के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे, अगर कोई अदालत किसी चुनाव के बारे में, खासतौर पर प्रधानमंत्री के चुनाव के बारे में, 'तकनीकी मुद्दों की बुनियाद पर फैसला दे दे तो वह पत्थर की लकीर नहीं हो जाता—जनता अपनी जो मर्जी जाहिर कर दे उसके बारे में तो कोई भी अदालत फैसला नहीं सुना सकती।

श्रीमती गांधी को एक ऐसी जगह से भी समर्थन मिल गया जहाँ से उन्होंने इसकी कोई उम्मीद भी नहीं की थी। टी० स्वामीनाथन पहले उनके कबिनेट सेनेटरी रह चुके थे। पहले तो उनकी नौकरी की मियाद बढा दी गयी थी और बाद में उन्हें श्रीमती गांधी ने चीफ एसेशन कमिशनर नियुक्त कर दिया था। उन्होंने ऐलान किया कि उन्हें इस बात का अधिकार था कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री सहित, किसी निर्वाचित पद पर हो और उसे किसी भी वजह से इसके लिए अयोग्य ठहरा दिया जाये तो वह अयोग्यता के इस प्रादेन का रद्द कर सकते हैं। नियमों में यही कहा गया था, हालाँकि उनसे पहले वाले चीफ एसेशन कमिशनर इन वमा न 1971 के चुनाव के बारे में अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि एसेशन कमिशनर को इस तरह के मनमाने अधिकार नहीं होने चाहिये।

इस बात की पहले से ही काफी चेतावनी दे दी गयी थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को झटल मान लेना जरूरी नहीं है। फिर भी श्रीमती गांधी इस बुनियाद पर अदालत में घाने वाली लड़ाई की तरफ लापरवाही नहीं बरत रही थी।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी परबों के लिए बम्बई के माने हुए वकील नानी ए० पालकीवाला से सम्पर्क किया। पालकीवाला को उस वक़्त प्रतिक्रिया बादी कहा गया था जब उन्होंने भेदभाव की बुनियाद पर चौदह भारतीय बका का राष्ट्रीयकरण अदालतों से रद्द करवा दिया था और पुराने देसी रजवाड़ों का गुजारा बन्द कर दिए जाने के बारे में इस दलील की बुनियाद पर गवा उठाया था कि गुजारा चूक जायदाद का हिस्सा है और जायदाद की सविधान में बुनियादी अधिकार माना गया है इसलिए गुजारा बन्द नहीं किया जा सकता।¹ लेकिन वक़्त पढ़ने पर श्रीमती गांधी के बुलाने पर पालकीवाला जो देश के सबसे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान टाटा के एक मीनिंगर डायरेक्टर भी थे, हवाई जहाज से दिल्ली पहुँचे। उन्होंने श्रीमती गांधी से कहा कि मैं मुकदमा जिता सकता हूँ। लेकिन उनका अपने पद पर बने रहना जनवाद की कसौटी पर वहाँ तक खरा उतरता था? लेकिन अब उन्हें किसी को भी यह बताने में कोई झिझक नहीं रह गयी थी कि उन्होंने अपने पद पर बने रहने का फसला कर लिया है और वह थोड़े दिनों के लिए भी अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

उन्हें कोई पक्का फैसला बरना ही था क्योंकि उन्हें इस्तीफा देने पर राजी कराने के लिए दबाव बढ़ता ही जा रहा था। और यह दबाव विपक्ष की ओर से ही डाला जा रहा हो ऐसी बात नहीं थी। खुफिया विभाग ने यह सूचना दी थी कि कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य भी यह चाहते थे कि जब तक 'बादल छट न जायें' मतलब यह कि जब तक वह सुप्रीम कोर्ट से बरी न हो जायें तब तक के लिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये। पुराने सोशलिस्टों का एक छोटा सा अपना धुन का पक्का गिरोह जिसे युवा-तुक कहा जाता था इस मुहिम में आगे आगे था। श्रीमती गांधी जानती थी कि ये लोग क्या कर सकते हैं। एक बार उन्होंने मोरारजी देसाई को नीचा दिखाने के लिए इन लोगों का सहारा लिया था। उन्होंने सरकारी फाइलें युवा तुक चन्द्रशेखर की यह साबित करने के लिए दिलवा दी थी कि अपने बैठे काति देसाई की करतूतों में मोरारजी की 'रजाम' भी शामिल है। काति देसाई ने अपना जीवन एक बीमा एजेंट की हैसियत से शुरू किया था और अब एक मालदार व्यापारी बन बठा था।

यह बात सभी जानते थे कि प्रधानमंत्री की हैसियत में श्रीमती गांधी न जा कुछ किया था उससे युवा तुक खुश नहीं थे। कुछ समय से वह इन लोगों का दबावर रखने की कोशिश कर रही थी। हालाँकि वह चन्द्रशेखर के कांग्रेस बकिंग कमेटी में चुने जाने में रुकावट डालने में सफल नहीं हो पायी थी लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति से कहकर एक और युवा तुक मोहन धारिया को मन्त्रिमण्डल से इसलिए निकलवा दिया था कि उन्होंने उनसे जयप्रकाश नारायण के साथ बातचीत शुरू करने के लिए कहा था।

और अब धारिया उनका इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उनका सुझाव था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट उन्हें बरी न कर दे तब तक के लिए उन्हें अपना पद छोड़कर जगजीवनराम या स्वर्णमिह को प्रधानमंत्री बना देना चाहिये। दूसरे युवा तुक भी उनके साथ थे और श्रीमती गांधी का डर था कि यह मांग तेजी के साथ बढ़ती ही जायगी।

1 गोमरनाथ बरनाम बकाब राज्य बोले मुकदमे में यह फसला दिया गया था कि मूल अधिकारों पर जो अनुविचार करने का अधिकार नहीं है।

खुफिया रिपोर्टों में बताया गया था कि युवा तुर्कों का जगजीवनराम से लगा-तार सम्पर्क था और वह विद्रोह की भाग भडका रह थे। जगजीवनराम ने लगभग बिलकुल खुले तौर पर कहना शुरू कर दिया था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदालत के फैसले को कोई साधारण बात नहीं समझा जाना चाहिये।

वह गिनतिया के खेल में भी हिस्सा लेने लगे थे और यह हिसाब लगाने लगे थे कि अगर मैं विद्रोह कर दू तो कितने लोग मेरा साथ देंगे। लेकिन उन्होंने देखा कि उनका साथ देनेवालों की मख्या काफी नहीं थी।

श्रीमती गांधी दाँव पेंच खूब जाननी थी। उन्होंने इस सुभाव का चर्चा करवा दिया कि अगर मैं अपना पद छोड़ने का फैसला करूँ भी तो अगला प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार मुझी को रहना चाहिये। जसा कि उन्हें अन्देश था इस सुभाव को किसी ने शुरू से ही नहीं माना—जगजीवनराम और चट्टाण दोनों इसके विलाफ थे।

जगजीवनराम खून का घूट पीकर रह गये जब उन्हें यह मालूम हुआ कि बहुत थोड़े भरसे के लिए जब श्रीमती गांधी डावाडाल थी तो उनके दिमाग में कमला पनि त्रिपाठी का नाम था, जिन्हें वह उत्तर प्रदेश से केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में 'कामचलाऊ प्रधानमंत्री' की हैसियत से लायी थी।

इसके बारे में जगजीवनराम ने यह रचैया अपनाया कि "हम लोग इस बात पर त्रिपाठीजी का समर्थन करने को तयार हैं कि वह श्रीमती गांधी का फिर वापस न मान दें।"

थोड़े दिन के लिए जिसे प्रधानमंत्री बनाया जाय अगर वह अपनी वफागारी से फिर सकता है तो वह आसानी से जाच बिठाने के लिए भी तैयार हो सकता है और श्रीमती गांधी बहुत भरसे से जाच का विरोध करती रहीं थी। जाँच से उनकी साख को ऐसा धक्का पहुँचता कि उनके लिए दुबारा संभव सकना मुश्किल हो जाता। उनकी एक दुखती रग तो उनके बेटे का मोटर का कारनामा मारति ही था।

दूसरी दुखती रग थी मुकद्दम की सुनवाई के दौरान 'दिल का दौरा' पड़ जाने से¹ वन्तम सोहराब नागरवाला की मौत। नागरवाला पेंशनयापता फौजी अफसर थे और कहा जाता था कि उन्होंने प्रधानमंत्री और उनके सेक्रेटरी हुकसर की घावाज की नकल करके नई दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की तिजोरियों से साठ लाख रुपये निकलवा लिये थे। (बक के बड़े खजांची बदप्रकाश जिन्होंने इसकी इजाजत दी थी, नौकरी छोड़ने के बाद कांग्रेस में चले गये थे।)

श्रीमती गांधी अगर जगजीवनराम पर भरोसा नहीं करती थी तो इसकी बजह थी। उन्हें यो भी युवा तुर्कों से टक्कर नेनी पड़ रही थी। पार्टी के अन्दर जाड़ तोड़ और तिकड़मो का बाजार इतना गम होता जा रहा था कि उनके लिए यह जरूरी हो गया था कि सदन में उनके भरोसे के लोग हों। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों का दिल्ली में तलब किया कि वे अपने अपने राज्यों के मजदूर मजदूरों पर 'निग्रहण' करें। यह चाहनी थी कि कांग्रेस समदीय दल जिसकी मीटिंग उनके भगविर से 18 नून व लिय तय की गयी थी उन्हें अपना भरपूर समर्थन दे। निद्रायनकर ने और आंध्र प्रदेश में राज्यमन्त्रा के सदस्य बी० बी० गजु का इस काम पर तैनात किया गया। उनकी हिम्मत दी गयी कि जो प्रस्ताव वे तयार करें उस पर जगजीवनराम से पक्की हमी करा लें।

1 एक डॉक्टर ने जिसका नागरवाला के शव की जाँच में कुछ सम्पर्क था मुझे बताया कि का दौरा पडने के बिना बनावग तरिका से भी पैदा किये जा सकते हैं।

इन लोगो पर पूरा भरोसा किया जा सकता था कि वे इस काम में कोई कसर उठा न रखेंगे। कांग्रेस ससदीय दल के भरपूर समर्थन का ऐसा सबूत मिल जाने के बाद राष्ट्रपति के लिए विपक्ष की उनको वखास्त कर देने की माँग को रद्द कर देना आसान हो जायेगा। संविधान यह कहता था कि जब तक बहुमत दल को उन पर विश्वास रहे तब तक वह प्रधानमंत्री बनी रह सकती थी।

जिस समय इलाहाबाद हाइकोर्ट का फैसला आया था उस समय राष्ट्रपति पल्लवर्द्धन श्री अहमद खान गये हुए थे। जब उन्होंने फमला सुना तो वह उसी दिन लौट आना चाहते थे लेकिन श्रीमती गांधी ने उन्हें टेलीफोन करके ऐसा करने से रोक दिया। अगले तीन दिन तक वह लगातार उनसे पूछते रहे कि वह वापस लौट आये या नहीं लेकिन वह नहीं चाहती थी कि वह बचन से रहल अपने दोरे पर स वापस आ जायें कि वही लोग इसका कोई गहरा मतलब न लगाने लें और यह न सोचने लें कि राष्ट्रपति उनका इस्तीफा लेने के लिए जल्दी वापस आ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के बाहर विपक्ष के लोग यही माँग लेकर घरना दिये बैठे थे।

16 जून को उनके दिल्ली वापस पहुँचने के थोड़ी ही देर बाद श्रीमती गांधी उनसे मिली। बहुत ही थोड़ी देर की मुलाकात थी, पंद्रह मिनट से भी कम लगे हागे, जिसके दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के सिलसिले में क्या तयारियाँ की जा रही हैं।

उसी दिन बाद में कम्युनिस्टों को छोड़कर विपक्ष के दूसरे नेताओं के साथ राष्ट्रपति का मुलाकात ज्यादा लम्बी रही। इन लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि आप श्रीमती गांधी को अपना पद छोड़ देने का हुक्म दें। राष्ट्रपति अहमद ने जाहिर यही किया कि वह इस सुभाव पर विचार कर रहे हैं—वह यह नहीं चाहते थे कि ऐसा लग कि वह किसी का पक्ष ले रहे हैं, वह इस कलक को भी धो डालना चाहते थे कि वह श्रीमती गांधी के लिए सिर्फ खड की एक मुहर हैं। उन्होंने पहले तो उनसे कहा कि यह सा देख लें कि कांग्रेस ससदीय दल की मीटिंग में क्या नतीजा निकलना है। लेकिन तब उन्होंने महसूस किया कि शायद उन्होंने गलत बात कह दी है और मुमकिन है कि इसका यह मतलब लगाया जाय कि वह किसी गम्भी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसका उनको गुमान भी नहीं था। उन्होंने फौरन अपनी बात बदल दी और कहा कि उनका मतलब यह था कि वे लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जान तक इंतजार कर लें। उनके प्रेस सेक्रेटरी ने यह सफाई देते हुए एक बयान भी जारी कर दिया ताकि अखबारों का कोई गलतफहमी न रह जाय।

राष्ट्रपति से मिलने के बाद विपक्ष के लोगो ने राष्ट्रपति भवन के सामने स अपना धरना उठा लिया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने श्रीमती गांधी को पद छोड़ने पर मजबूर करने के लिए अपनी मुहिम और तेज करने का भी फैसला किया। उनमें से कई लोगो ने कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के साथ सम्पर्क स्थापित करने की बात भी सोची कि कम-से-कम उनसे यह अपील तो की जाये कि वे प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा बनाये रखें। माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उस प्रतिनिधिमण्डल में शामिल नहीं थी जो राष्ट्रपति से मिलने गया था लेकिन उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का छोड़ कर विपक्ष की बाकी सभी पार्टियों की इस माँग का पूरा समर्थन किया कि श्रीमती गांधी अपनी कुर्सी छोड़ दें।

श्रीमती गांधी के इस्तीफे की माँग करने के लिए राष्ट्रपति से विपक्ष के लोगो की मुलाकात पर वह सबसे ज्यादा चिढ़ गयी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 1962 में गान्धी के हाथों भारत की हार के बाद जब उनके पिता की साख रसालत पहुँच

गयी थी, तब भी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की माँग करने के लिए विपक्षवाले एक साथ राष्ट्रपति से नहीं मिले थे।

वह महसूस करने लगी थी कि वह चारों ओर से घिर गयी है। उन्हे सबसे बड़ी चिंता विपक्ष की वजह से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी की वजह से थी, जिसमें असंतोष उबल रहा था। ज्यादातर सदस्य यह महसूस कर रहे थे कि अगर वह नतीजा बनी रही तो उनके लिए फरवरी 1976 में होनेवाला अगला चुनाव लड़ना नामुमकिन हो जायेगा। जगजीवनराम और युवा तुलु ज्यादा से ज्यादा ससद-सदस्यों के साथ सम्पर्क स्थापित कर रहे थे, और उनके सामने यह दलील रख रहे थे कि अदावाती फैसलों की मर्यादा बनाय रखने के लिए श्रीमती गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह ऐसी दलील थी जिसे समझने में आम लोगो को भले ही कोई कठिनाई होती पर विधायकों और ससद सदस्यों को नहीं।

इस खोचातानी का उन पर असर पड़ने लगा था। बात रात पर अब उन्हें गुस्सा भाने लगा था। अब उनके भाषण भी गुस्से से भरे होते थे। 'मेरे खिलाफ तरह-तरह के झूठे इल्जाम लगाये जात हैं, झूठी बातें कही जाती हैं मुझे बदनाम करने के लिए उल्टी सीधी सोहमतेँ लगायी जाती हैं लेकिन मैं मर कुछ बर्दान्त करती रही हूँ।' इस तरह की बातें वह उन मीटिंगों में कहती थी जो उनके समर्थन के लिए जुटायी जाती थी।

उन्होंने जस्टिस सिन्हा से भी लाहा लिया। खुलेआम उन्होंने कहा कि यशपाल कपूर 14 जनवरी के बाद से सरकारी नौकर नहीं रह गये थे और उसी तारीख से उन्होंने तनख्वाह लेना भी बंद कर दिया था। (मिनहा साहब ने कहा था कि यशपाल कपूर 25 जनवरी तक सरकारी नौकर की हैसियत से काम करते रहें थे), और यह कि प्रधानमंत्री की मीटिंगों के लिए सरकारी भवन से मच बनवाने का चलन उनके पिता के जमाने में भी था।

अपने भाषणों में वह अक्सर 1971 की बंगला दस की लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का चर्चा भी ले आती थी, उस वक़्त उनके सबसे कट्टर विरोधी जनसमूह में भी कहा था कि वह कांग्रेस पार्टी की नहीं बल्कि भारत की नेता है वह पार्टियों और विचारधाराओं से परे है।

वह अपने हर भाषण में विपक्षी दला पर हमला करने लगी और पहले की तरह ही सरकार की नीतियों की हर खराबी के लिए उन्हें दाय देने लगी, ये लोग गद्दार थे। वह कहती थी कि विपक्षवाले ही प्रगति के रास्ते का रोड़ा हैं। अब वह कहने लगी कि 'स्वार्थी लोगो की तरफ से डाली जाने वाली बाधाओं के बावजूद समाजवाद कामयाबियाँ हासिल करता रहेगा।

विपक्ष की ओर उनके पिता का जो रवया रहा था उसमें और उनके रवये में जमीन आसमान का फ़र्क था। विपक्ष के बहुत से लोगो का वह तिन मान थे जब राष्ट्रीय महत्त्व के सवाल पर उनसे सलाह ली जाती थी और खाने की समस्या या राष्ट्रीय एकता की समस्या में सम्बंध रखनेवाले कार्यक्रमों में उनका महयोग माँगा जाता था। अब उन्हें मिए कांग्रेस पार्टी के फैसला की सूचना देने के लिए बुलाया जाता था। वे जानते थे कि ससद में उनकी सख्या बहुत थोड़ी थी। लेकिन ऐसा तो नेहरू के जमाने में भी था और इसके बावजूद उनसे सलाह ली जाती थी और उनकी बात सुनी जाती थी। नेहरू न उन्हें कभी यह महसूस नहीं हान दिया कि इन लोगो को उन पर या उनकी सरकार पर उँगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। वह विरोध करने के अधिकार को बढ़ावा देते थे और समन्वय लाकतंत्र में विपक्ष के लिए जो भूमिका तब

की गयी है उसे अच्छी तरह समझते थे।

श्रीमती गांधी के लिए विपक्ष बस एन रोडा था। उन्होंने विपक्ष पर इल्जाम लगाया कि वह हमेशा अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश का सारा काम-काज ठप्प कर देने की कोशिश करता रहता था और इस सिलसिले में उन्होंने 1974 की रेलवे हड़ताल को मिसाल दी। रेलवे के कुल 13,50,000 नियमित कर्मचारियों में से, जिनमें से 3 50 000 रोजाना मजदूरी पर काम करते थे, लगभग 65 प्रतिशत ने हड़ताल में हिस्सा लिया था, लेकिन सरकार ने उन्हें कुचलने के लिए ऐसे भीषण दमन का सहारा लिया जैसा इससे पहले कभी नहीं देखा गया था—कितने ही लोग मौखिकता से बर्खास्त कर दिये गये, कितने ही नजरबंद कर दिये गये, हड़ताल करनेवाला के परिवारों को रेलवे के बचावों से निकाल दिया गया रेलवे की सस्ते अनाज की दुकानों को माल दना बन्द कर दिया गया और मजदूरों की वस्तुओं का पानी बिजली काट दिया गया।

वह इस बात की चर्चा करते नहीं मकनी थी कि चारों तरफ धराजवला और राजनीतिक तिकड़मवाजी फैलती जा रही है। यह सच है कि कुछ यूनिवर्सिटियों में गड़बड़ी मची हुई थी और कारखानों में इससे पहले कभी काम का इतना मुकसान नहीं हुआ था।

विपक्ष यह समझता था कि वह डिक्टेटर बनना चाहती हैं और इसलिए उनके पाँच उल्लाहता जरूरी हैं। जयप्रकाश ने अपना हमला और तेज कर दिया था और वह केंद्रीय सरकार की लोकतंत्र की आड़ में डिक्टेटरशिप के ढाँचे पर उतार लायी गयी एक औरत की हवामत कहने लगे थे। दबी जबान से उनकी पार्टी के कई लोग भी अब इसी तरह की दलीलें देने लगे थे।

और सबसे बड़ी बात यह थी कि कानूनी राय भी कुछ बहुत होमला बहान वाली नहीं थी। कानून के अच्छे से अच्छे जानकारों ने उनकी बताया था कि हद-से हद वह इसकी उम्मीद कर सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ घातों के साथ हाईकोर्ट के फैसले को स्थगित कर दे, हालाँकि वे समझते थे कि 'प्रतिम फैसले' में उन्हें बरी कर दिया जायगा। अगर हाईकोर्ट का फैसला कुछ घातों के साथ स्थगित किया गया तो उसमें उनकी सालों की जो भटका लगेगा उनके बाद क्या वह दृढ़मत कर पायेंगी?

जसा कि उन्होंने एक सम्पादक से कहा 'राजनीति का सभालना' या ही मुश्किल हो गया है। बाहर से विपक्ष के दबाव—जयप्रकाश का मुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जमा हान लगी थी—और खुद अपनी पार्टी के अन्दर सुलगती हुई विद्रोह की आग की वजह से उनका मन न तरह-तरह की आँकड़ा उठने लगे।

फसले और उसके बाद की घटनाओं के बारे में अपने-आपसे न जो सुविधाएँ थी और जो सपना छोपा उससे उनका अदमा और बढ़ता गया। वह साबित नगे कि अपने-आपसे न न कभी उनकी कठिनायियों का ठीक से समझा है और न ही उनकी काम याविया को। 'ई दिल्ली के एक दैनिक समाचार ने ता उनका और उनके परिवार वालों का विराधिया को इत्याक से म हाथ बताया था। उन्हें पूरा यकीन था कि अपने बारा को उनसे बर था, एक बार उन्होंने सम्पादकों को बताया कि उन्होंने ता मय बार पटना ही छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें मालूम था कि कौन-सा सरकार क्या निगमा।

अन्यथावाला के बारे में उनकी राय अच्छी नहीं थी। वह जानती थी कि 'सरोज' आ सक्ता है। सच तो यह है कि उन्हें सनितनारायण मिश्र ने बताया कि कि तरह उन्होंने दिल्ली, नवद पमा और गूट का अपना देकर कितने ही

पत्रकारों को, खास तौर पर नई दिल्ली के पत्रकारों को, अपनी तरफ़ मिला रखा था। उनके कहने पर उनके अपने सेक्रेटेरियट ने भी कितनी ही बार उनके आलोचकों पर हमला करने के लिए 'प्रगतिशील' पत्रकारों को इस्तेमाल किया था। वह जानती थी कि पत्रकार ही नयो, अखबारा के मालिक भी खरीद जा सकते थे। लेकिन अब ऐसा लगता था कि इन सब लोगो ने उनके खिलाफ़ गिरोहबन्दी कर रखी थी।

उनका धीरज टूटने लगा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे चारों तरफ़ से दुश्मनो ने उन्हें घेर लिया हो। ऐसा लगता था कि उनके बेटे सजय और उसकी टाली को छोड़कर, जिसमें धवन भी शामिल थे, बाकी सब लाग उनको गिरा देने के लिए कसर बाँध चुके हैं।

चारों तरफ़ बचनी और हलचल बढ़ती जा रही थी, 'गरीबी हटाओ' के उनके नारे स जनता के रहन-सहन में कोई सुधार नहीं हुआ था। 1950-51 और 1965-66 के बीच बीसमें तीन फीसदी प्रतिवध से कुछ ही ज्यादा बढ़ी थी। लेकिन उनके शासन-काल में क्रीमों कीमत से पन्द्रह फीसदी की रफ़्तार से बढ़ी थी। अब उनके खिलाफ़ लोग जितना ख़ुलकर बोलने लगे थे उतना इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था।

उन्होंने महसूस किया कि हालत जिस तरह बिगड़ती जा रही है वह उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। यही वह वक़्त था जब उन्होंने उन लोगों का मुह बन्द करने के लिए, जो कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों जगह उनकी बुराईयाँ गिनाने लगें थे, कुछ सदन कदम उठाने की बात सोची। विपक्ष जनमत का अपने पक्ष में कर सकता था। लगभग सभी पार्टियाँ मिलकर एक हो गयी थी और कांग्रेस पार्टी के अन्दर से टूट जाने का ख़तरा था।

उन्हें विपक्ष के बारे में 'कुछ करना होगा' जिसकी ताक़त सदन में उनकी अपनी पार्टी के छोटे हिस्से के बराबर भी नहीं थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि जब भी उन्होंने कोई कारवाई करने का फसला किया तो उसे पूरा करने में दर नहीं लगेगी, क्योंकि उन्होंने सारी ताक़त प्रधानमंत्री के सेक्रेटेरियट के हाथों में समेट रखी थी।

यह सिलसिला उनसे पहलेवाले प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के ज़माने में ही शुरू हो चुका था। उनके सेक्रेटरी एल० के० भा० का हर चीज़ में दख़ल रहता था और उन्हें लोग सुपर सेक्रेटरी कहने लगे थे। श्रीमती गांधी के सिविल सविनयान्तरण सेक्रेटरी पी० एन० हकसर तो भा० से भी दो कदम आगे बढ़ गए थे और उन्होंने पूरी व्यवस्था को इस तरह संगठित किया था कि हर चीज़ प्रधानमंत्री के सेक्रेटेरियट के चारों ओर ही घूमती थी। उसकी मजूरी के बिना कोई डिप्टी मन्त्ररी तक नहीं नियुक्त किया जा सकता था। उन्होंने अलग ही एक मनी-मन्त्रालय बना ली थी। इस सेक्रेटेरियट के हर अफसर का एक एक क्षेत्र की लगभग पूरी ज़िम्मेदारी सौंप दी गयी थी—चाह वह आर्थिक क्षेत्र हो या विदेशों से सम्बन्ध रखना हो या विज्ञान का क्षेत्र हो। सभी मन्त्रालय इन्हीं लोगों से आदेश लेकर काम करते थे। लेकिन हकसर की सबसे बड़ी दन यह थी कि उन्होंने इस ढाँचे पर राजनीतिक रंग चढ़ा दिया था। आजादी के बाद देश के इतिहास में पहली बार सरकार की मशीनरी का राजनीतिक कामा के लिए, ख़रूरत पड़ने पर कांग्रेस पार्टी के कामों के लिए, इस्तेमाल किया जाने लगा था। कुछ वर्षों बाद उन्हें अपने इस दिन के किये पर पछताना पड़ा।

श्रीमती गांधी ने इस मशीनरी को उन लोगों पर नियन्त्रण रखने की ताक़त दी जो 'भुरक्षा प्रदान कर सकते थे। केन्द्र में उनके पास बॉर्डर सिक्कोरिटी फ़ोर्स (बी० एस० एफ०), सेट्रल रिजर्व पुलिस (सी० आर० पी०), सेट्रल इन्डस्ट्रियल सिक्कोरिटी फ़ोर्स (सी० आई० एस० एफ०) और होमगार्ड के लगभग 700 000 पुलिसवाले थे।

इन टुकड़ियों का विभिन्न राज्यों की पुलिस से (जिसकी संख्या 8 00,000 बतायी जाती थी) और हथियारबंद फौज से, जिसमें लगभग 10,00 000 सिपाही थे, कोई सम्बंध नहीं था।

उनको ऐसा लगा कि विपक्ष हृद तक जाने की तयारी कर रहा है, उनको अपनी पार्टी के घेरे के और बाहर के दुश्मन अब बह्र बनने की कोशिश कर रहे थे जो वह राजनीतिक लड़ाई में नहीं कर पाये थे—उन्हें हटाने के लिए वे एक 'ग्रंडियल' जज के फैसले का सहारा लेने जा रहे थे। जल्द ही पढ़ने पर वह भी हृद तक जा सकती हैं।

सजय का इसके बारे में कोई शक नहीं था और उसने अपनी माँ को यह बात भी दिया। और जब वह हाईकोर्ट के फैसले के बाद सत्ता और उचित प्राचरण की सीखातानी में पड़ी हुई थी तब उसी में उन्हें फंसला करम में मदद दी थी और उसके बाद से वही उनका खास सलाहकार बन गया था। और उसी ने उनके सामने यह बात साबित कर दी थी कि देश का और देश की जनता को उनकी जल्द ही।

सजय दिन रात उनके मन में यही बात बिठाता रहता था कि आप अपने विरोधियों के साथ जल्द से ज्यादा नरमी बरतती हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने में निष्कर्षी हैं। आपके वक्त में काम आनेवाले उसके दोस्त बसिलाल का भी यही कहना था जिन्होंने अपने विरोधियों को पिटाकर, हवालात में बंद करवाकर या पुलिस से तंग करवाकर हरियाणा में विपक्ष की आवाज बिलकुल बंद कर दी थी। बसिलाल ने कहा, "मैं होता तो इन सबको जेल में डलवा देता। वहनजी आप इन लोगों को मेरे हवाले कर दीजिये, मैं एक एक को ठीक कर दूंगा। आप जल्द से ज्यादा मुरब्बत और दाराफत से काम लेती हैं।" उन्होंने अपने हरियाणा राज्य में यह बात साबित कर दी थी कि लोग इज्जत उसी की करते हैं जिसमें ताकत हा, जो काम पूरा करके दिखा सके।

लगभग सभी मुख्यमंत्री श्रीमती गांधी को यह चेतावनी द चुके थे कि उन्हें 'कुछ' करना होगा, नहीं तो घटनाओं की लहर उन्हें अपनी सपेट में ले लगी। उन्होंने यह मामला सजय पर छोड़ दिया। वही उन्हें दबाव के आगे न झुकने के लिए पूरा सहारा दे रहा था। जिस वक्त उनके पक्के से पक्के समयको के पांव भी लड़खड़ाते दिखायी दे रहे थे उस वक्त उसी ने उनको इस्तीफा न देने की सलाह दी थी।

जैसा कि बाद में सजय ने अपने एक दोस्त का बताया, 15 जून को उसी 'हालात को ठीक करने के लिए कोई योजना' बनाने का काम शुरू किया। उसका मसूदा यह था कि राजनीतिक स्तर पर और सरकारी स्तर पर सरकार का ढाँचा बदल दिया जाये। उसे काम करने का लौकतांत्रिक तरीका पसंद नहीं था। न ही उसमें कायदे कानून की गम्भीर जवाबदारी कारवाई को वर्णित करने का धीरज था। यह वक्त चाहता था, और वक्त तभी में निश्चयता जा रहा था।

सबसे पहला काम उसने यह किया कि अपने कमरे में दो 'शुक्रिया टेलीफोन' लगावा दिया। ये टेलीफोन सिर्फ मंत्रियों और चोटी के अफसरों के यहाँ लगाये जा सकते थे, लेकिन सभी लोग जानते थे कि उसका हक प्रधानमंत्री का है और इसलिए यह काम फौरन कर दिया गया। अब वह किसी को भी उसके सफ़ेरी की माफ़त टेलीफोन करने का जना भोव नये बिना सीधे टेलीफोन कर सकता था।

उसके विभाग में इस बात की पहले में कोई योजना नहीं थी कि वह क्या करना चाहता है। लेकिन उस पूरा यकीन था कि हर विरोधी को या तो खरीद जा है या तोड़ा जा सकता है। इसमें किसी तरह की मुरब्बत नज़ा की जानी

चाहिए। जसा कि एक बार उसने पश्चिम जर्मनी के किसी अखबार से इंटर्व्यू के दौरान कहा था, वह डिक्टेटरशिप को पसंद करता था लेकिन 'हिटलर जसी नहीं'। एक बार अगर लोगो के मन में डर बिठा दिया जाये तो वे या तो हुकम मानना सीख जायेंगे या कम से-कम अपनी जवान नहीं खालेंगे। सजय चाहता था कि जो हुकम दिया जाये उसे लोग मानें और इसके लिए वह ओछे से ओछे हथकड़े को भी बुरा नह समझता था।

युरू में योजना सिर्फ अखबारों पर लगाय लगाने और विपक्ष के कुछ नेताओं और महत्वपूर्ण लोगो का मुंह बंद कर देने की थी। इस तरह 'भ्रानुशासन' का पक्का बन्दोबस्त हो जायेगा और सब लोग ठीक रास्ते पर आ जायेंगे। अखबार ऐसी कोई बात नहीं छाप पायेंगे जो सरकार को बुरी लगे और विपक्ष के लोग ऐसी बात नहीं कह पायेंगे जो 'नापसंद' हो।

अखबारों का मुंह बंद करना जरूरी था। जैसा कि श्रीमती गांधी और सजय दोनों ही अक्सर अपने परिवार के दूसरे लोगो को कहा करते थे, उनके विरोधियों को आसमान पर चढ़ा देने और सरकार के खिलाफ 'अविश्वास का वातावरण' पैदा करने का सारा दोष अखबारों का था। लेकिन अखबार भी विपक्षवादी दोनों ही मिट्टी के शेर थे और उन्हें आसानी से बाबू में बिया जा सकता था।

सजय ने जब अपना मासुति का कारखाना लगाया था उसी दिन से वह अखबारों से खुश नहीं था। अखबारवालों ने इस कारखाने के बारे में और तब उनके बारे में हद से ज्यादा लिखा था—जूरत में ज्यादा ऐसी बातें जो उस अच्छी नहीं लगी थी, हालांकि उसने सम्पादकों को अपना कारखाना निखान का खुद ही बन्दोबस्त किया था।

इसकी ज्यादातर जिम्मेदारी उसने मूखनामत्री इन्द्रकुमार गुजराल के मध्य में दी थी। उसका कहना था कि गुजराल की पत्रकारिता में दोस्ती है लेकिन वह उनमें कभी सरकार के पक्ष में कोई बात नहीं लिखवा पाये। यह उसकी ज्यादाती थी। 1969 में जब चौन्ह बकों का कारोबार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था उसके बाद से गुजराल न ही श्रीमती गांधी की घूम बांधकर उन्हें आसमान पर चढ़ा दिया था और उनके पैर मजबूत करने के लिए सरकारी रेडियो और टेलिविजन और प्रकाशकों का पूरी तरह इस्तमाल किया था। उन्होंने अखबारों पर भी नबाव डाला था, आमतौर पर इन्हें देकर छोट और बमबोरे अखबारों पर—दल भर में सबसे अधिक इन्हें देकर ही देती थी इसलिए उसका पाग दूसरों को अपने पक्ष में रखने के लिए दल को बहुत कुछ था। लेकिन दत्तात्रेय हार्डिकोट के फमले के बाद ऐसा लगता था कि गुजराल का जोग कुछ ठंडा पड़ गया था।

मजय के मामिया घन और बसोतान को भी गुजराल और अखबारों दाना ही में चिड़ थी। घन यह दलील देते थे कि गुजराल न पत्रकारों को बहुत मर पर चढ़ा गया है और उन्हें उनकी अमली हैमियत बना दी जानी चाहिए। बसोतान ने उ ह बताया कि यही मंड के टिबून अखबारों को सरकारी इन्हें देना ब करके और ज गाडियां ब अखबार लकर हरियाणा आनी थी या उ मजय में हार गुजरती थी उनका पुनिम में चनान करवाना किम तरह उन्होंने उसे सीपा कर दिया था।

लेकिन एक छोट से राज्य में एक अखबार के मिताप जो कुछ किया गया था क्या यही मारे दल में अखबारों को बाबू में रखने के लिए किया जा सकता था? मजय

के दोस्त कुलदीप नारंग¹ ने उसे एक छोटी सी किताब दी जिसमें फिलीपाइस के सेंसरशिप के नियम दिये हुए थे और इस बात का भी पूरा ब्योरा दिया गया था कि इन नियमों को वहाँ लागू करने के लिए क्या बदोबस्त किया गया था। नारंग को महसूसमी नई दिल्ली में भ्रमरीकी दूतावास के अपने कुछ दोस्तों से मिली थी।

जयप्रकाश नारायण और दूसरे लोगों के खिलाफ कारबाई की योजना तो बहुत पहले जनवरी में ही बना ली गयी थी। मुझे इसका पता प्रधानमंत्री के सेक्रेटेरियट के एक सदस्य से चला था। उसने कहा था कि 'कब्जा करने' की कुछ तरकीबों के बारे में सोच विचार हुआ है। बस यहाँ-वहाँ से कुछ बिखरी बिखरी बातें ही वह पकड़ सका था, और हालाँकि उसे पूरा ब्योरा नहीं मालूम था, उनमें जयप्रकाश की गिरफ्तारी और भार० एस० एस० पर पाबंदी शामिल थी।

तब मैं सम्वाददाता नहीं था, दफ्तर में बैठकर काम करता था, इसलिए मैंने यह खबर जनसभ के दैनिक महरलैड गौर इंडियन एक्सप्रेस को भिजवा दी। महरलैड में खबर इस तरह छपी

नई दिल्ली, 30 जनवरी—भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक सभ पर पाबंदी लगा देने का फैसला कर लिया है।² उसने श्री जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करने का भी फैसला किया है।

उम्मीद की जाती है कि भार० एस० एस० पर पाबंदी 2-3 फरवरी की रात का बग़ायी जायगी और जयप्रकाश को 3 फरवरी को पटना में हवाई जहाज में उतरने ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

श्री गफूर (बिहार के मुख्यमंत्री) ने जब यह कहा था कि 'मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ', तो वह सिर्फ प्रधानमंत्री के फैसले का ऐलान कर रहे थे।

मैं दोनों फैसले इसी हफ्ते कैबिनेट की राजनीतिक मामलात की कमिटी में लिये गये।

इस प्राइवेंस का मतविदा तयार करने में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री सिद्धाचरकर ने भी हाथ बँटाया है—जा 1969 में प्रधानमंत्री के लिए प्राची रात को भेजे जानेवाले सन्देशों का मतविदा भी तैयार करते थे।

इस प्राइवेंस में कई बार फलाया गया यह झूठ फिर दोहराया गया है कि भार० एस० एस० एवं खुफिया संगठन है जो ग्रहिसा में विश्वास नहीं रखता। और उससे श्री एल० एन० मिश्रा की हरया की जिम्मेदारी हिंसा के उस वातावरण पर रखी गयी है जो भार० एस० एस० ने और जे० पी० के आन्दोलन ने पैदा किया है।

इंडियन एक्सप्रेस ने जे० पी० की गिरफ्तारी के बारे में इससे धसावा और कुछ नहीं कहा कि इसकी सम्भावना है, लेकिन बाकी खबर छाप दी।

नई दिल्ली, 30 जनवरी—यहाँ के राजनीतिक क्षेत्रों में ऐसा समझा जाता है कि जल्द ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक सभ पर पाबंदी लगाने के बारे में एक प्राइवेंस जारी किया जानवाला है।

1. उसी की ग़ाभी में सभ्य एक बार सेक्रेट सचिवों के होस्टल के बाहर पकड़ा गया था और मार्लैड में उसे हथामा था।

2. सिद्धाचरकर ने म धामती गोपी को 8 जनवरी को एक पत्र लिखकर उनसे प्राइवेंस जारी करवा भार० एस० एस० पर पाबंदी लगाने को कहा था।

इस दिशा में अटकलवाजी बिहार के मुख्यमंत्री श्री अब्दुल गफूर के इस बयान से शुरू हुई, जो उन्होंने बुधवार को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया था कि बिहार में श्री जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की रोकथाम के लिए बड़ी कारवाई की जानेवाली है।

याद रहे कि श्री गफूर ने इस बात से भी इकार नहीं किया था कि श्री नारायण गिरफ्तार किये जा सकते हैं। यह भी समझा जाता है कि सर्वोदय नेता की गिरफ्तारी इस हफ्ते के आखिर में या अगले हफ्ते के शुरू में हो सकती है।

आर० एस० एस० पर पाबंदी लगाने के बाद इस संगठन के खास खास नेता भी गिरफ्तार कर लिए जायेंगे। गिरफ्तार किये जानेवाले लोगों की सूची कई दर्जन तक पहुँच सकती है।

जनसभ से श्रीमती गांधी को जो नफरत थी उसे सभी जानते थे। जब उसने मार्च 1974 में दिल्ली में एक प्रदर्शन करने की योजना बनायी थी तो उन्होंने दिल्ली पुलिस के इम्पक्टर जनरल को उन लोगों के नाम दिये जिन्हें वह चाहती थी कि वे गिरफ्तार कर लिए जायें। अधिकारी यह महसूस करते थे कि हालत ऐसी नहीं है कि ऐसा कदम उठाया जाय लेकिन उनका हुक्म था। बाद में उन्होंने दिल्ली प्रशासन के चीफ को अफसरो को बदल दिया। और यही वह वक्त था जब सजय और धवन ने ऐसे अफसरो को जो उनके कफादार रहे दिल्ली में तैनात करवा दिया।

जनवरी में जो मसूब बनाम गये थे वे मजबूत के धब बहुत काम आये, जो 'हर चीज को काबू में रखने' की तरकीबें सोच रहा था। श्रीमती गांधी, जिन्होंने हर कदम पर सलाह ली जाती थी, जयप्रकाश और मोरारजी देसाई को शुरू ही में गिरफ्तार कर लेने के पक्ष में नहीं थी। लेकिन बाद में बात उनकी समझ में आ गयी—उनके जैसे नेताओं को उपद्रव भड़काने के लिए खुला छाड़ रखना खतरनाक साबित हो सकता था।

इन तैयारियाँ में 55वर्षीय राज्यमंत्री भोम मेहता भी हाथ बँटा रहे थे। हालांकि गृह मंत्रालय में वह दूसरे नम्बर पर थे लेकिन असली ताकत उन्हीं के हाथ में थी क्योंकि वहाँ यह थी कि वह प्रधानमंत्री के करीब हैं। उन्हें कई बार 'होम मेहता' के नाम से भी पुकारा जाता था। सविधान से हटकर जो भी काम करवाना होता था उसके लिए मजबूत उन्हीं को इस्तमाल करता था।

धवन की भोम मेहता फूटी आँखों नहीं सुहाते थे क्योंकि उनकी सजय तक सीधी पहुँच थी। लेकिन यह निजी पसन्द और नापसन्द का वक्त नहीं था, सब लोग मिनकर काम करते रहे। धवन बहुत बुनियादी हैसियत रखते थे क्योंकि श्रीमती गांधी अफसरो को ही नहीं बल्कि मंत्रियों तक को उन्हीं के जरिये आदेश भिजवाती थी। धवन जो कुछ कह देते थे उनके बारे में यह समझा जाता था कि प्रधानमंत्री यही चाहती हैं।

बसिलाल का प्रधानमंत्री के साथ बराबर सम्पर्क रहता था। उनसे 18 जून की मीटिंग के लिए दिल्ली में जमा राज्या के मुख्यमंत्रियों से खचा करने के लिए कहा कि कोई बड़ी कारवाई की जाने वाली है। बसिलाल ने सिद्धाथगढ़ पर और सत्यधी से बात करने से इकार कर दिया क्योंकि वह उन्हें कम्युनिस्ट बसिलाल और सजय दाता ही उन्हें नापसन्द करते थे, इसलिए श्रीमती। बताने की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले ली।

जाहिर में उन्हें यह नहीं बताना था कि क्या कारवाई की जा

लेकिन हर राज्य में भरोसे के अफसरों को यह बताया जा रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिये। दिल्ली में, जहाँ विपक्ष के ज्यादातर नेता मौजूद थे यह काम बिशनचंद को सौंपा गया। वह आई० सी० एस० से रिटायर हो गये थे और उस वक़्त दिल्ली के सेपिटमेंट गवर्नर थे। सज्ज का उन पर यह बहुत बड़ा एहसान था कि उसी ने उनको इतने ऊँचे पद पर पहुँचा दिया था। उनके साथ और नवीन चावला के साथ सज्ज का सीधा सम्पर्क था। नवीन दून स्कूल में उमने साथ पढ़ चुका था और इस वक़्त सेपिटमेंट गवर्नर का स्पेशल असिस्टेंट था।

उस वक़्त तक इमर्जेंसी की कोई बात नहीं थी बस इतना सुनने में आता था कि अखबारों के खिलाफ और विपक्षवालों के खिलाफ 'कोई कार्रवाई' होन वाली है। इस पर कोई चर्चा नहीं करता था कि यह कार्रवाई क्या होगी। कानून और संविधान की दृष्टि से इसके नतीजे क्या हों सकते हैं इसका लेखा-जोखा अभी करना बाकी था। लेकिन इरादा पक्का था, इस सचट से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूँढना ही था।

कार्रवाई की तारीख़ भी अभी तय होनी थी। लेकिन श्रीमती गांधी के दिमाग़ में यह बात साफ़ थी कि जो कुछ भी करना हो वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के कमरे के खिलाफ़ स्ट्रेट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो अर्जें द रखी हैं, उसका फँसला हो जाने के बाद ही किया जाये। उनके बकील धनकाशकालीन जज जस्टिस बी० भार० कृष्ण भट्टर¹ के सामने अपील दायर करने की तैयारियाँ कर रहे थे, जिनके बारे में श्रीमती गांधी समझती थी कि 'विचारधारा की हद्द तक वह उनकी तरफ़ हैं।

उपर उनका बेटा और उसकी टोली लडाई का नक्शा बनाने में लगे हुए थे, और इधर श्रीमती गांधी पार्टी का भरपूर समयन जुटाने का मुहिम में लगी हुई थी। और ऐसा लगता था कि उनको कामयाबी मिल रही है। मिट्ठापशकर और राजू 'समर्थन प्रस्ताव' लेकर जगजीवनराम के पास गये थे और यह सुझाव रखा था कि वही उसे पेश करें। प्रस्ताव में श्रीमती गांधी में पार्टी का 'पूरा भरोसा और विश्वास' एक बार फिर दोहराया गया था और यह यकीन जाहिर किया गया था कि 'प्रधान-मंत्री की हैमियत से उनके लगातार नतुत्व के बिना राष्ट्र का काम ही नहीं चल सकता।' जगजीवनराम ने प्रस्ताव के असबिदे में कोई खास हेर फेर नहीं किया, सब ता यह है कि उन्होंने राजू को शाबाशी दी और कहा कि तुमने कांग्रेस को बचा लिया' है।

श्रीमती गांधी ने भी जगजीवनराम के पास यह सन्देश भिजवाया कि वह इस बात का पक्का बताना चाहें कि युवा तुक प्रस्ताव के बिनाफ़ कुछ न बोलें। युवा तुक ने जगजीवनराम का बताना लिया था कि वे प्रस्ताव का समयन करने की तयार हैं, शान बस इतनी है कि उसका वह अन्तिम मान्य निबाल दिया जाय जिसमें कहा गया था कि "प्रधानमंत्री की हैमियत में उनके लगातार नतुत्व के बिना राष्ट्र का काम ही नहीं चल सकता।" उन तागा ने इस हिस्से पर कोई एतराज नहीं किया कि 'श्रीमती गांधी नव उत्थान के मध्य पर धाम बढ़त हुए भारत के और जनता की उमंगों की प्रतीक हैं। इस समय अन्तर्जमीनी की अण्डा काशेम का और राष्ट्र को उनके नतुत्व और भाग-अन की उम्मीद है। लेकिन वे हम वहाँ जान का मानने के लिए तयार नहीं हैं कि उनके बिना काम ही नहीं चल सकता।

1 भारत के प्रमुख जोज़ जस्टिस एम० एस० साहरो ने 1972 में भट्टर का विपुलित का विरोध इस बनिदान पर किया था कि भट्टर कम्यूनिस्ट थे।

जगजीवनराम उन सबकी इस सामूहिक राय को तो नहीं बदलवा सके, लेकिन अलबत्ता इस बात पर राजी कर लिया कि व मीटिंग में आयें ही नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने यह सवाल उठाया तो बदमजगी होगी। युवा तुकों के न हाने पर कुछ लोगो का माथा तो ठनका और कुछ कानाफूसी भी हुई, लेकिन 516 सदस्यों वाले संसदीय दल पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, उसने तो वही किया जो उस करना था। उसने एकमत होकर श्रीमती गांधी का समर्थन किया। अपने अपने राज्यों के सदसद-सदस्यों पर कड़ी नज़र रखनेवाले मुख्यमंत्री दूर खड़े तालियाँ बजाते रहे। जगजीवनराम ने प्रस्ताव पेश किया, लेकिन उन्होंने श्रीमती गांधी के गुण गिनाने से ज्यादा इस बात की चर्चा की कि सरकार और अदालतों के बीच तालमेल रहना चाहिए। चह्वाण ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए जो भाषण दिया उसने यह कमी पूरी कर दी, उन्होंने श्रीमती गांधी की तारीफ़ न सिर्फ इस बात के लिए की कि उन्होंने 1971 की लड़ाई में देश का नेतृत्व करके उसे विजय की मंजिल तक पहुँचाया बल्कि इस बात के लिए भी कि इस लड़ाई के बाद जो आर्थिक संकट आया उससे भी देश को उन्होंने ही उबार।

जसा कि पहले से तय था, श्रीमती गांधी पार्टी की मीटिंग में इस तरह आयी जैसे कोई रानी सलामी लेने आयी हो, और वह बस बहुत थोड़ी देर ही वहीं ठहरी। उन्होंने अपने भाषण में जो कुछ कहा उसमें कोई नयी बात नहीं थी—यही कि मौजूदा संकट के बादल काफी दिन से घिर रहे थे और यह उनके खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ 'बई ताक'ों के गठजोड़ का नतीजा था और यह कि वह अपनी सारी ताकत जनता से हामिल करती हैं।

जब प्रस्ताव को सभी ने एकमत होकर पास कर दिया तो मीटिंग के अध्यक्ष बरमा ने सुझाव दिया कि सब लोग श्रीमती गांधी के कमरे में चलें जो संसद के सेंट्रल हाल के पास ही था जहाँ कांग्रेस के संसद सदस्य जमा हुए थे, जगजीवनराम ने यह कहकर कि श्रीमती गांधी अपने घर जा चुकी हैं इस सुझाव को वहीं दफन कर दिया। वह समझौतेवाजी के रास्ते पर काफी आगे जा चुके थे, सब तो यह है कि वह ज़रूरत से ज्यादा समझौतेवाजी कर चुके थे और इसके बाद वह खुशामद की खुली नुमाइश नहीं करना चाहते थे।

प्रस्ताव पास हो जाने के बाद इस सवाल में कोई दम ही नहीं रह गया कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला कुछ शर्तों के साथ देगा या बिना किसी शर्त के। सभी का खयाल यह मालूम होता था कि चाहे जो कुछ हो जायें, वह अपनी जगह बने रहना चाहियें। अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें संसद की बहुसंख्ये में बोट देने या हिस्सा लेने की इजाजत न भी दे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री तो वह तब भी रह्यो।

श्रीमती गांधी के चोटों के कानूनी और राजनीतिक सलाहकार इस बात पर सोच विचार कर रहे थे कि अगर फैसले में उन पर यह पाबन्दी लगा दी गयी कि छ साल तक वे किसी ऐसे पद पर नहीं रह सकती जिनके लिए चुनाव जीतना ज़रूरी हो, तो ज़रूरत पड़न पर इस रुकावट को कस दूर किया जा सकता है। उन लोगो ने ऐसा कानून पास करवा देने की बात भी सोची कि एक छान्त तारीख तक मिसाल के तौर पर 1 जुलाई 1975 तक, जितने भी मेम्बरा पर इस तरह की पाबन्ती लगायी गयी हो उन सब पर से उस हटा लिया जाय। एक बार पढ़ने भी इस तरह का ब्रदम उठान की बात मोची गयी थी ताकि मध्य प्रदेश के डी० पी० मिश्रा और घाघर प्रदेश के चेना रेड्डी पद पर रह सकें, लेकिन फिर उस पर अमल नहीं किया गया।

एक सुझाव यह भी था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले का मानवर, जिसमें उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था, वह ज़रूरत पड़ने पर रायवरेली से दुबारा

पुनाब लठ सवती हैं।

लेकिन प्रजीव बात है कि जब भी इस तरह का कोई सुभाव श्रीमती गांधी के सामने रखा जाता था तो वह उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लिखाती थी। ऐसा लगता था कि वह अपने ही खयाल में डबी हुई हैं। कुछ तो वह सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रपीत की तैयारियों में लगी हुई थी लेकिन ज्यादातर उनका दिमाग उन बातों में उलझा रहता था जिनकी योजना बनाने में सजय और उसकी टोली जुटी हुई थी।

गैर-कम्युनिस्ट विपक्ष ने श्रीमती गांधी के इस्तीफा की मांग उठाने का फैसला किया। उन्होंने 21 और 22 जन को जनता मोर्चे में शामिल पार्टियों की कार्यकारिणी समितियों की एक मिली जुली बैठक बुलायी और श्रीमती गांधी को हटाने के लिए सार देहा में प्रान्दोलन देखने की योजना बनायी। जयप्रकाश ने सदन में भेजा कि वह मोर्चे की बातचीत में और विद्या-रैली में हिस्सा लेंगे। राजनारायण ने समझा घुमाकर जयप्रकाश को इस बात पर राजी कर लिया था कि कोई कारवाई शुरू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना जरूरी नहीं है।

विपक्ष ने सदन का मानसून (मध्य जुलाई) अधिवेशन बुलाये जाने पर भी जोर दिया और अपनी यह मांग स्वीकार के सामने रखी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता पहले ही इसके खिलाफ फसला कर चुके थे क्योंकि सदन की बैठक से उनके लिए परेशानियाँ ही इसके खिलाफ फसला कर चुके थे क्योंकि सदन की बैठक से उनके लिए परेशानियाँ पैदा हो सकती थी। उनकी दलील यह थी कि संविधान में इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा गया है कि दो अधिवेशनों के बीच छ महीने से ज्यादा का बक्त नहीं होना चाहिए। स्वीकार का मालूम था कि श्रीमती गांधी क्या चाहती हैं और इसलिए वह सदन का अधिवेशन बुलाने पर राजी नहीं हुए।

भगर सजय और उसकी टोली का बस चलता तो सदन की बैठक कभी होती ही नहीं क्योंकि उनके लिए यह बक्त की बर्बादी थी मिसाल के लिए पिछली ही बैठक के दौरान सिफ मुलामोहन राम के मामले पर बहस होती रही थी। और भगर साल का ज्यादातर हिस्सा सदन के सवाल का जवाब तयार करने में ही निकल जाये तो सरकार काम कब करे? उन्होंने इस बकार काम की राक थाम करने के बारे में सोचा।

कुछ इसी तरह के विचार एक बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ भुकाव रखने वाले कांग्रेसी मंत्री चंद्रजीत यादव ने भी जाहिर किये थे। नई दिल्ली से कांग्रेसी सदन-सदस्य गणिभूषण ने भी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के समयक से कुछ इसी तरह की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वह लिमिटेड डिक्टेटरशिप (सीमित डिक्टेटरशिप) के पक्ष में थे। बाद में जब उन्हें अपनी इस बात की याद दिलायी गयी तो उन्होंने कहा, 'लेकिन मैं लिमिटेड की बात नहीं थी, प्राइवेट लिमिटेड की नहीं।'

अब तक श्रीमती गांधी का खयाल बदल चुका था। इसाहाबाज वाले फसले के बाग उनके घर जो एक हिचकिचाहट ला गयी थी वह अब दूर हो गयी थी। सब तो यह है कि अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि वह फसला उन्हें हटाने के लिए दूर तक फलाये गये जान का ही एक हिस्सा था। किसी ने उनको बताया था कि जस्टिस सिनहा का मुकाम जनसभ की तरफ था।

सजय और उसकी टोली को अपनी कामयाबी का पूरा भरोसा था। छोटी स-छापी चोरे की वान में भी श्रीमती गांधी ने सिफ उनके साथ थी बल्कि उनकी कारवाई के लिए हर चीज लगभग थिम्बुन तयार थी। हर राज्य में विपक्ष के उन नेताओं की मुचियाँ नैपार की जा रही थी जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था और फिनीपाइस जखी समरणिप लागू करने की रती गती बात तय कर ली गयी थी।

'कारवाई' का वक्त भी तय हो चुका था—सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के अगले दिन। तैयारियों की रफ्तार और तेज कर दी गयी, आदेशों को पूरा करने का बन्दोबस्त कील काँटे से दुस्त कर लिया गया। ज़रूरत के वक्त जिन अफसरों पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता था, उन्हें ज्यादा से ज्यादा तादाद में बुनियादी महत्व की जगहों पर तनात किया जा रहा था।

गृह मंत्रालय के सेक्रेटरी निमल कुमार मुखर्जी को हटा देने का फैसला किया गया क्योंकि वह 'ज़रूरत से ज्यादा कानूनी' आदमी थे। राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी सुंदरलाल खराना को उनकी जगह लाया गया। उनके बारे में यह समझा जाता था कि उन्हें आसानी से मनचाही दिशा में मोड़ा जा सकता है। इसके बाद से किसका कहाँ तैनात करना है इसका फैसला अबले एक आदमी धवन के हाथ में छोड़ दिया गया था। बहुत दिन से उनकी यह शिकायत थी कि सरकार में भ्रष्टासी छाये हुए है, वह चाहत थे कि उत्तर भारत के लोगों का, खासतौर पर पंजाबियों का पलड़ा भारी रहे।

खुफिया विभाग के कर्त्ता धर्त्ता ए० जयराम को हटाकर कही और भेज दिया गया। उनकी जगह भरने के लिए पंजाब पुलिस के इन्स्पेक्टर जनरल शिवनाथ माथुर को चुना गया—पहले उन्हें एडीशनल डायरेक्टर बनाया गया और फिर डायरेक्टर। जयराम बहरहाल इस मामले में तो निकम्मे साबित हुए ही थे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सुनाये जाने से पहले वह इसकी भतक भी नहीं पा सके थे कि फसना क्या होगा।

बसीलाल ने ज्यादातर मुख्यमंत्रियों से बात कर ली थी और वे विपक्ष के लोगों के खिलाफ और अखबारों के खिलाफ कारवाई करने के लिए हर तरह से तैयार थे। सिद्धाथशकर रं और नदिनी सत्यजी से खुद भीमती गांधी ने बात की थी। सिद्धार्थ-शकर ने कामयाब वकील रह चुके थे, वह सिर्फ यह जानना चाहते थे कि ये दोनों कदम किस कानून के तहत उठाये जायेंगे। यह पूरी तरह से कदम उठाये जान के पक्ष में थे, लेकिन वह यह नहीं चाहते थे कि श्रीमती गांधी कानून के रास्ते से भटक जायें। श्रीमती गांधी का भुकाव खुद सविधान की हदों के अंदर रहकर काम करने की तरफ था और इसलिए उन्होंने सिद्धार्थशकर रं से कहा कि वह इसका तरीका सोच लें और कलकत्ता से उन्हें टेलीफोन कर दें।

खुफिया विभाग ने खबर दी कि विपक्ष आन्दोलन छेड़ने के लिए तैयार हो रहा है जिसमें हजारों लोग जुलूस बनाकर उनकी बौटी तक जायेंगे और उसे घेर लेने की कोशिश करेंगे। वे रेल की पटरियों पर बैठ जायेंगे और ट्रैनो को नहीं चलने देंगे। आवासों को काम नहीं करने दिया जायेगा। सरकारी दफ्तरो में कोई काम नहीं होना दिया जायेगा। कोशिश यह थी कि सारा नाम कान ठप्प कर दिया जाये।

यह इस बात का सबूत था बस सबूत की कोई ज़रूरत नहीं थी कि सज्ज ठीक हो रहा था कि विपक्ष का एक ही मकसद था—श्रीमती गांधी को हटवा देना। अब उनका पूरा दारोमदार अपने बटे और उसकी योजनाओं पर था। उन्हें पूरा भरोसा था कि वह उन्हें इस सबूत से उबारने के लिए कोई-न-कोई तरीका ढूँढ़ निकालेगा। वह देखती थी कि वह दिन में अठारह अठारह घंटे काम करना था।

नई दिल्ली में 20 जून को श्रीमती गांधी के समर्थन में सरकारी बन्दोबस्त से जुटायी गयी रैली में श्रीमती गांधी ने कहा कि वह अपनी आखिरी साँस तक जिस हैसियत से हो सवा जनता की सेवा करती रहूँगी। उन्होंने यह भी कहा कि सब उनका परिवार की परम्परा रही है।

सुली मीटिंग में पहली बार उन्होंने अपने परिवार की चर्चा की थी। उनके

परिवार के लोग मच पर ही मौजूद थे—सजय, राजीव और उसकी इटलियन बीवी सानिया।

श्रीमती गांधी ने कहा कि बड़ी बड़ी ताकतें न सिर्फ उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा देने के लिए, बल्कि उन्हें जान से मरवा देने तक के लिए एंडी चोटी का ज़ोर लगा रही थी और अपने इस मसूचे को पूरा करने के लिए उन्होंने बड़ी दूर-दूर तक जाल फेंका था।

चरघा इन्दिरा गांधी की हवा बाँधने का अपना पुराना काम कर रहे थे। उन्होंने वहीं जोड़-जाड़कर तैयार किया एक उदू का घेर पड़ा

इन्दिरा, तेरे मुँह की जय, तेरी शाम की जय,
तेरे काम की जय, तेरे नाम की जय।

रली बहुत कामयाब रही। जैसा कि श्रीमती गांधी ने कहा, 'इतनी बड़ी रैली दुनिया में कभी नहीं हुई थी।' लेकिन वह टेलीविजन पर नहीं दिखायी गयी थी क्योंकि वह पार्टी की रैली थी, सरकारी रैली नहीं थी। और इसकी वजह से गुजराल का अपना मन्त्रालय से हाथ धोना पड़ा। सजय की गुजराल से भड़प हो गयी और गुजराल ने भुम्भनाकर उससे कह दिया, मैं तुम्हारी माँ का मंत्री हूँ तुम्हारा नहीं।

पब्लिक मीटिंग से उठकर तेरह मुख्यमंत्री सीधे राष्ट्रपति भवन पहुँचे जहाँ उन्होंने एक बार फिर श्रीमती गांधी पर उनको पूरा भरोसा होने की बात दोहरायी और एक पेज का ममोरंडम राष्ट्रपति को दिया जिसमें कहा गया था कि श्रीमती गांधी के इस्तीफा देने से न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष राज्यों में भी हालत हाँबाहाल हो जायगी।

अगले दिन 23 जून को सोमवार के दिन उनमें से कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद थे जब जस्टिस ब्रिज्म अय्यर ने श्रीमती गांधी की अपील की सुनवाई की। उनकी अर्जी में 'श्रीमती गांधी जिस पद पर थी उस दलते हुए' 'बिना किसी शर्त के बिलकुल दो टूक' स्टे ऑर्डर की माँग की गयी थी। दलील यह दी गयी थी कि जब तक अपील का फसला न हो जाये तब तक राष्ट्र के हित में यही युनासिब है कि बतमान स्थिति में कोई हेर फेर न किया जाय।"

जस्टिस अय्यर ने दोनों पक्षों की दलीलें दो दिन तक सुनी और वह इस नतीजे पर पहुँचे कि श्रीमती गांधी को 'बुनाव म किसी मगीन गडबडी' का अपराधी नहीं ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं लेकिन उन्हें लोक-सभा में तब तक बाट देने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के फसल के खिलाफ उनकी अपील को निबटा न दे।

स्टे ऑर्डर कुछ शर्तों के साथ दिया गया था। लेकिन उन पर ससद को बहुसा में हिस्सा न लेने की कोई पाबन्दी नहीं लगायी गयी थी। फिर भी जस्टिस अय्यर ने ससद का ध्यान इस बात की ओर दिलाया था कि 'कानून ज़ोर होने पर भी अमानता की नज़र में कानून ही रहता है लेकिन उसमें कानून बनानेवाले चौकस और मुस्तद लागों की शर्तें खल जानी चाहिये।'

सरकार ने समाचार एजेंसियाँ स मह बन्दोबस्त कर लिया रेडियो और टेली विजन तो उनके कण्ठों में थे ही, कि फसल का वहीं पहलू उभारा जाय जिसमें उनके मतलब की बात कही गयी थी। इसका मतलब यह था कि श्रीमती गांधी के प्रधानमंत्री बने रहने पर कोई पाबन्दी नहीं थी।

तब तक जयप्रकाश भी ठिली पहुँच चुके थे। विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट से टक्कर नाना नहीं चाहते थे। उन्होंने फसल का स्वागत तो किया लेकिन एक बयान में

यह भी कहा कि "श्रीमती गांधी की साख बिलबुल उठ चुकी है, उनकी सदस्यता सीमित हो गयी है और वोट देने का अधिकार उनसे छिन चुका है। ऐसी हालत में वह किस तरह प्रधानमंत्री रह सकती हैं?" उन लोगों ने श्रीमती गांधी को इस्तीफा देने पर मजबूर करने के लिए सारे देश में आंदोलन छेड़ने के अपने पक्के इरादे को एक बार फिर दोहराया।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस वक्त गर कम्युनिस्ट विपक्ष के साथ शामिल तो नहीं हुई लेकिन उसका रवैया भी बहुत-कुछ ऐसा ही था—चूँकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीमती गांधी को 'भ्रूठा साबित कर दिया है इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उनका समर्थन करती रही। पार्टी के केन्द्रीय सचिव-मण्डल ने कहा कि उन्हें 'वक्षिणपथी प्रतिक्रियावादियों की धौंस' के भागे हथियार नहीं डालना चाहिए और प्रधानमंत्री के पद पर बने रहना चाहिए।

जस्टिस अय्यर के फसले से जगजीवनराम के मसूबों पर पानी फिर गया। उन्हें उम्मीद थी कि स्टेट-ऑर्डर कुछ दलों के साथ दिया जायेगा, और अदालत के फसले में यह बात साफ-साफ नहीं कही जायेगी कि वह प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं। बहरहाल उन्होंने अपनी चाल चलने में देर कर दी थी और जिस तरह बरफ़ा और दूसरे लोगों ने एक नैतिक सवाल को राजनीतिक सवाल बना दिया था, उसके बाद तो स्टेट ऑर्डर की कोई हैसियत ही नहीं रह गयी थी।

अब जगजीवनराम भी केन्द्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और दूसरे लोगों से सूर में सूर मिलाने लगे। एक बयान में और एक प्रस्ताव में इन लोगों ने कहा था कि श्रीमती गांधी के प्रधानमंत्री की हैसियत से काम करते रहने में कोई रुकावट नहीं थी। जगजीवनराम इससे भी एक कदम आगे बढ़ गये—उन्होंने कहा यह सिर्फ एक कानूनी मसला है, इसमें किसी नैतिक या राजनीतिक सवाल का दखल नहीं है। नैतिकता श्रीमती गांधी के पक्ष में थी।

कांग्रेस पार्टी के संसदीय बोर्ड की भी मीटिंग हुई और उसने पूरे राष्ट्र को चेतावनी दी कि 'हो सकता है कि कुछ गिरोह और कुछ लोग अपने स्वायत्त के लिए जनता को गुमराह करने और हालात का फायदा उठाने की कागिश करते रहें।'

जिन लोगों में पार्टी के बाक़ी लोगों की तरह इस मामले में उतना ज़ोर नहीं था उनमें मुवा तुक भी थे—चन्द्रशेखर मोहन धारिया, रामधन, कृष्णकांत और श्रीमती सहमीका। तम्मा—और इनके अलावा कुछ और लोग भी। उन्होंने अपनी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए अलग एक मीटिंग की। ताकत तो बहुत नहीं थी, उनका साथ देनेवाला के नाम उगलियों पर गिन जा सकत थे।

चन्द्रशेखर और कृष्णकांत दाना ही ने मुझे बताया, ऐसे लग तीस-卅 ज़्यादा नहीं रहे होंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ आ जाने का वादा किया था।

इलाहाबाद वाले फसले के बाद इंदिरा के पक्ष में एक मुहिम चलाने का निरा कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह जनवादी आदर्शों का सम्मान करने का दिखावा करना भी छोड़ दिया था उससे मुवा तुक बहुत दुखी थे। उन्हें सबम ज़्यादा निराशा जगजीवनराम से हुई थी, जो यह वायदा करने के बाद कि वह उनके साथ हैं, मदान छोड़कर भाग खड़े हुए थे।

श्रीमती गांधी के खय की उन्हें परवार नहीं थी क्योंकि वे पार्टी की तरफ़ से उनके खिलाफ़ अनुशासन की कारवाई निय जान के लिए तैयार थे। उन्होंने इस बात

को कभी छिपाने की कोशिश नहीं की थी कि वे जयप्रकाश को बहुत सराहत थे। चन्द्रशेखर श्रीमती गांधी से कितनी ही बार कह चुके थे कि वह जयप्रकाश से मिल लें और राजनीति की गंदगी दूर करने के लिए उनका सहयोग लें। 24 जून को चन्द्रशेखर ने जयप्रकाश को रात के खाने पर बुलाया। खुफिया विभाग वाली ने खबर दी थी कि भस्ती ससद-सदस्य युवा तुकों के ढंग से सोचते थे। लेकिन उस दिन दावत में सिर्फ बीस लोग आये थे।

सजय को और उसकी टोली को इस बात की तनिक भी चिंता नहीं थी कि युवा तुकों के बीच क्या हो रहा है, परवाह तो उन्हें, सच पूछा जाये तो, इसकी भी नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। वे अब अपनी योजना को पूरा करने के लिए सारे बलपुजों को ठीक कर रहे थे। सिद्धांतशंकर रे ने उनके लिए पूरा ब्योरा तैयार कर दिया था कि क्या-क्या करना है।

दो ही दिन पहले उन्होंने श्रीमती गांधी को कलकत्ता से टेलीफोन करके बताया था कि अगर 'कुछ करना' है तो उसका एक ही तरीका है कि 'भीतरी' इमर्जेंसी का ऐलान कर दिया जाय। (बाहरी इमर्जेंसी तो बंगलादेश की लड़ाई शुरू होने के वक्त दिसम्बर 1971 से ही लागू थी।) उन्होंने बताया था कि संविधान की धारा 352 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया था कि अगर देश के अंदर उपद्रव हो रहा हो तो वह इमर्जेंसी लागू कर सकता है। इस तरह सरकार को मनचाहे अधिकार मिल जायेंगे।

श्रीमती गांधी ने उनसे फौरन दिल्ली आ जाने को कहा। उनके लिए कलकत्ता से अचानक चले आने में कोई कठिनाई नहीं थी। एक मंत्रीक मशहूर था कि उनका सामान हमेशा बंधा तयार रहता था और दिल्ली का हवाई जहाज का टिकट हमेशा उनकी जेब में रहता था। जब से वह केन्द्रीय मंत्रिमण्डल छोड़कर मुख्यमंत्री बन थे तब से हर हफ्ते औसतन दो बार वह प्रधान मंत्री से सलाह मशविरा करने दिल्ली जाते रहे थे।

नई दिल्ली में 24 जून को अपनी बातचीत के दौरान सिद्धांतशंकर रे अपने इस विचार पर ही जोर देते रहे। प्रधानमंत्री की कोठी से जल्दी जल्दी मसद की लाइब्रेरी से संविधान की एक कॉपी भगवाई गयी। भगवारी और श्रीमती गांधी ने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए 'कुछ करने' की जो एक धूमिल-सी योजना थी उसकी अब न सिर्फ एक ठोस शक्ल उभर आयी थी बल्कि उसको संविधान का सहारा भी मिल गया था—जिस कार्रवाई की योजना तानाशाही कायम करने के लिए बनायी गयी थी उस पर परदा डालने के लिए एक वकील ने 'भीतरी इमर्जेंसी' की आठ दूध निकाली थी।

प्रधानमंत्री के सेक्रेटोरियट ने इमर्जेंसी लागू करने के लिए एक नाट पढ़ने से ही तैयार कर रखा था। यह अचानक सफट आ पढ़ने पर काम आनेवाली उन योजनाओं में से एक थी जो हमेशा तयार रखी जाती थी। इमर्जेंसी के अधिकारों के तहत केन्द्रीय सरकार राज्या को कोई भी हिदायत दे सकती थी संविधान की 19वीं धारा¹

1. संविधान की 19वीं धारा के अनुसार सब नागरिकों को वाक-स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्य का शांतिपूर्वक और निराश्रय सम्मेलन का सत्या या सत्य बनाने का भारत रा-य-सत्तर् में सशक्त पक्षाध संचरण का भारत रा-य-सत्तर् के किसी भाग में निवास करने और बग जाने का संपाति के धर्जन धारण और ज्वन का तथा कोई मृति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा।

को स्थगित कर सकती थी या सभी मूल अधिकारों को स्थगित कर सकती थी, प्रदालता या हुक्म दिया जा सकता था कि वे इन अधिकारों को लागू करवाने के उद्देश्य से दायर किये गये मुकद्दमे की सुनवाई न करें, इत्यादि। इसजैसी म के द्रीय सरकार के अधिकारों की कोई सीमा नहीं थी।

अनसर ऐसा लगता था कि श्रीमती गांधी को इस बात की ज्यादा चिन्ता रहती थी कि कोई चीज बाहर से देखने में कभी लगती है, इस बात की उतनी नहीं कि उसका असली सार क्या है। उन्होंने सन्तोष की साँस ली, इसजैसी की घोषणा करना कोई ऐसा काम नहीं होया जो संविधान के खिलाफ हो।

उनका रवया नेहरू के रवये से कितना अलग था। 1962 में जब चीनियों के खिलाफ हमारे पैर उखड़ जाने की वजह से सारा देश उनके खिलाफ होता जा रहा था, तो उस समय के रक्षामंत्री कृष्ण मेनन ने भीतरी इसजैसी लागू कर देने का सुझाव रखा था। नेहरू ने इस मानने से इस बुनियाद पर इकार कर दिया था कि इससे जनवादी परम्पराओं को धक्का पहुँचेगा।

अब क्या इसजैसी लागू करने का फैसला कर लिया गया था इसलिए गोखले को उसे ब्राजूनी जामा पहनाने के लिए बुलाया गया। लेकिन यह बात उनकी भी नहीं भासूम थी कि वह किस तारीख से लागू की जायगी।

इस कारवाई के लिए 25 जून की राती रात का वक्त तय किया गया था। यह सोचा गया था कि तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जायगा।

बुनियादी बात यह थी कि किसी को बाना-कान खबर न हो। श्रीमती गांधी, सजय, धवन, बसीलाल, प्रोम महता, विशनचंद और अब सिद्धाशकर रे को छोड़ कर किसी को भी पता नहीं था कि जल्द ही वह कारवाई होने वाली है, हालाँकि सबको लोगों के पास आदेश भेजे जान लगे थे कि उन्हें क्या काम करना है। ज्यादातर ये आदेश गिरफ्तारियों के बारे में थे।

बरमा ताड़ गये थे कि कोई खिचड़ी पक रही है। उन्हें 24 जून को इसजैसी के बारे में बताया गया। वह चाहते थे कि इस बार के असर को नरम करने के लिए कुछ 'प्रगतिशील कदम उठाये जायें, और इसके लिए उन्होंने चीनी की और कपड़े की मिलों के राष्ट्रीयकरण का सुझाव रखा। उन्होंने दलील यह दी कि 1969 में वकी के राष्ट्रीयकरण से किस तरह राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें कांग्रेस के सरकारी उम्मीदवार को हारने में मदद मिली थी। लेकिन सजय ने जो निजी कारोबार में पक्का विश्वास रखता था इस सुझाव को ठुकरा दिया।

बरमा ने एक और सुझाव रखा—बरोज़गार लागू को गुजारा देने का सुझाव। सजय ने यह कहकर कि इसमें पैसा बहुत लगेगा, इस सुझाव को भी ठुकरा दिया। कहा जाता था कि दो करोड़ से ज्यादा लोग बेरोज़गार थे।

ब्रह्मानंद रेड्डी को 25 जून को यह भेद की बात बतायी गयी। लेकिन उन्हें यह फिर भी नहीं बताया गया कि किन किन लोगों को गिरफ्तार किया जान वाला है, और उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की। कुछ घरसे से उन्होंने अपनी जान बचाये रखने के लिए, अपने ही गृह मंत्रालय में हाँ में हाँ मिलाकर समय काटते रहना सीख लिया था।

विपक्ष को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि क्या होने वाला है। शायद मालदार मार्क्सवादी ज्योतिषय बसु का तौर निशाने के सबसे पास जाकर लगा था जब उन्होंने खुलेआम यह कहा था कि श्रीमती गांधी संविधान को ही रद्द कर देने की बात सोच रही हैं—प्रधानमंत्री के यहाँ से किसी से उन्हें यह भनक मिली थी

कि कोई मरुत रुदम उठाया जाने वाला है। ज्योतिमय बसु ने अपने मकान की खिडकियों में लोहे के सीखचे लगवा लिये थे। बीजू पटनायक को भी, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री रह चुके थे और भारतीय लोकदल के एक नेता थे, मन-ही-मन ऐसा लग रहा था कि इस तरह की कोई योजना बनायी जा रही है, और उन्होंने अपना यह अदेशा जाहिर भी किया था। लेकिन विपक्ष में किसी ने इन लोगों की बातों का यकीन नहीं किया था। इन सुझावों की बात सोची भी नहीं जा सकती थी, इसलिए उन पर यकीन करना भी मुश्किल था।

बहरहाल, विपक्ष के नेता 25 जून की रैली की तैयारियों में लगे हुए थे। जयप्रकाश के दिल्ली देर से पहुँचने की वजह से, जिन्हें अब प्यार से 'लोकनायक' कहा जाने लगा था, यह रैली एक दिन के लिए टल गयी थी।

यह दिल्ली की एक सबसे बड़ी रैली थी, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितनी श्रीमती गांधी की थी, और श्रीमती गांधी के समयक इस बात के लिए अपनी पीठ ठोक रहे थे। लेकिन जो लोग जयप्रकाश की रैली में भागे थे वे खुद वहाँ पहुँचे थे, उन्हें लाने के लिए सरकार की तरफ से किराये की सारियों का इन्तजाम नहीं किया गया था, वह भाड़े की भीड़ नहीं थी। एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री को गद्दी से चिपके रहने पर बहुत खरी खरी बातें सुनायी, कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि वह डिक्टेटर की तरह काम कर रही हैं। उन्होंने यह बात साफ कर दी कि वे उनकी एक नहीं चलते दौंगे।

जयप्रकाश ने पाँच आदमियों की एक लोक-संघ समिति बनाने का ऐलान किया, जिसके चैयरमैन मोरारजी देसाई थे और जनसंघ के छोटी के नेता नानाजी देशमुख सेक्रेटरी थे, जिसे श्रीमती गांधी को इस्तीफा देने पर मजबूर करने के लिए 29 जून से सारे देश में आंदोलन छेड़ने का काम सौंपा गया। अहिंसा का रास्ता अपनाकर हड़तालें सत्याग्रह और प्रदर्शन करने का कार्यक्रम बनाया गया था।

जयप्रकाश ने वहाँ पर मौजूद भीड़ से हाथ उठाकर यह बताने को कहा कि देश में नैतिक आंशों के फिर से कायम करने के लिए वे ज़रूरत पड़ने पर जेल जाने को तैयार हैं। सचने अपने अपने हाथ उठा दिये। ताज़ुब की बात है कि चौबीस ही घंट बाद जेल जाना तो दूर रहा, इनमें से ज्यादातर लोगों ने कोई आवाज भी नहीं उठायी जब आवाज उठाना जरूरी था। जयप्रकाश ने पुलिस और फौज के लोगों से भी अपील की कि, जसा कि उनकी बापदे कानून की किताब में लिखा है वे किसी भी गर कानूनी हुक्म को मानने से इन्कार कर दें।

अनोखा व्यंग्य था कि 1930 के आसपास के दिनों में खुद कांग्रेस यही बात कहा करती थी। श्रीमती गांधी के दादा मोतीलाल नेहरू ने ही कांग्रेस पार्टी को यह प्रस्ताव रखने के लिए तैयार किया था जिसमें पुलिस में कटा गया था कि वह गर कानूनी हुक्म मानने से इन्कार कर दें। जिन लोगों को इस प्रस्ताव के पक्ष छपवाकर घाटने के लिए सजा दी गयी थी, उनकी अपील उस वक़्त इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली थी। ब्रिटिश राज्य के जजों ने फसला दिया था कि पुलिस स गर कानूनी हुक्म न मानने के लिए कहना कोई गलत बात नहीं है।

लेकिन श्रीमती गांधी, मजबूत और उनके समयका के लिए पुलिस और फौज से जयप्रकाश की यह अपील प्रचार का सबसे अच्छा हथियार था। अब वे वह सबक थे कि वह फौज में गडबडी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, यह एक ऐसी बात थी जिस परभावत फैलाने की सजा दी जा सकती थी। लेकिन यह तो बस एक कहाना था। इस रस्ती में बहुत पहले ही मैं सज्ज

गांधी और उनके भरोसे के लोग घातक वार करने की तैयारी कर रहे थे। जैसे जैसे गांधी रात का वक्त करीब आता गया, वैसे-वैसे प्रधानमंत्री की कोठी में हलचल भी बढ़ती गयी। सभी राज्यों को आदेश भेज दिये गये थे, और बहुत से लोग यह जानना चाहते थे कि उन्हें अखबारों पर सेंसर लागू कर देने और श्रीमती गांधी के विरोधियों को पकड़ लेने के अलावा क्या और भी कुछ करना है। दिल्ली में और दूसरी जगहों पर जो नेता गिरफ्तार किये जाने वाले थे उनकी फेहरिस्तें तैयार थी और वे श्रीमती गांधी का दिखाना भी दी गयी थी। ये फेहरिस्तें तैयार करने में एक खुफिया विभाग, जिसने बहुत मदद की थी वह था रिसच एंड एनालिसिस विंग (शोध तथा विश्लेषण विभाग) जिसे संक्षेप में 'ग' कहा जाता था।

रा की स्थापना विदेशों में भारत की जासूसी में सुधार करने के लिए 1962 में उस वक्त की गयी थी जब चीनिया के खिलाफ हमारी लड़ाई खरम होने वाली थी, क्योंकि चीनियों के खिलाफ लड़ाई के दौरान हमारी जासूसी बहुत निकम्मी साबित हुई थी। शुरू शुरू में बीजू पटनायक ने भी इस काम में हाथ बँटाया था, क्योंकि उनके बारे में यह मशहूर था कि वह "दुश्मन की पाँता के पीछे घुसकर काम कर चुके हैं।" कई माल पहले जब इण्डोनेशिया पर डच लोगों का शासन था उस वक्त वह वहाँ के राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता सुकार्नो को छुड़ाकर लाने के लिए खुद उड़कर हवाई जहाज जकार्ता में गये थे।

रा सीधे प्रधानमंत्री के सेक्रेटेरियट की निगरानी में काम करता था। श्रीमती गांधी पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने इसे देश के अन्दर राजनीतिक जासूसी के लिए इस्तमाल किया था। इसका गठान और इसमें काम करने वाले लोग उसकी सबसे बड़ी खूबी थे, उन्हें इस बुनियाद पर चुना जाता था कि वे या तो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे रह चुके थे, या भरोसे के किसी ऊँचे सरकारी अफसर या पुलिस के अफसर से उनकी रिश्तेदारी थी। रा ने सरकार का विरोध करने वाला, कांग्रेस पार्टी के अन्दर आलोचना करने वाला, व्यापारियों, सरकारी अफसरों और पत्रकारों के बारे में पूरा ख़्याल अपने महा जमा कर रखा था। विरोधियों की फेहरिस्त तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं था, रा के पास सबकी फाइलें तैयार थी।

इस सवाल पर भी विचार कर लेना जरूरी था कि गिरफ्तारी किस कानून के तहत की जाये। आन्तरिक सुरक्षा कानून (मीसा) में अभी साल ही भर पहले कुछ हेर-फेर करके सरकार को इस बात का अधिकार दे दिया गया था कि वह मजदूरों के सामने जुम लगाय बिना किसी भी आदमी की गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। लेकिन जब यह कानून पास किया गया था उस वक्त सरकार ने सदन में विपक्ष को यह विश्वास दिलाया था कि मीसा को राजनीतिक विरोधियों को नज़रबंद करने के लिए इस्तमाल नहीं किया जायेगा।

वसीलाल चाहते थे कि दिल्ली में जिन नेताओं की गिरफ्तार किया जाय उन्हें हरियाणा में नज़रबंद किया जाय। उन्होंने श्रीमती गांधी को बताया 'मैंने रोहतक में एक बहुत बड़ा आधुनिक जेल बनवाया है।'

श्रीमती गांधी न थल-सेना के प्रधान सनापति जनरल रैना को दौरे पर सवापम बुला लिया। यह सिर्फ इसलिए किया गया था कि वही कोई ऐसी-वैसी बात न हो जाय।

इस वक्त तक दिल्ली पुलिस के चोटी के अफसरों को यह पता लग चुका था कि जयप्रकाश नारायण मोरारजी सगठन कांग्रेस के प्रेसीडेंट अशोक मेहता और जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण अडवाणी जैसे लोग भी गिरफ्तार

किये जाने वाले हैं।

किस कानून के तहत ? चूंकि उह इमजेंसी के बारे में कुछ पता नहीं था इसलिए उन्होंने यह मालूम करने की कोशिश की कि उन्हें किस तरह गिरफ्तार किया जाये। उनमें कहा गया कि भारतीय दण्ड-संहिता (आई० पी० सी०) की दफा 107 में। लेकिन इस दफा में तो आवागमन पकड़े जाते थे। जयप्रकाश और मोरारजी को इस दफा में कैसे गिरफ्तार किया जा सकता था ?

दिल्ली के नामों की फेहरिस्त अभी किशनचंद की मदद से तयार की जा रही थी। जब पुलिस ने गिरफ्तारी के वारण्ट माये ता दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर सुशील कुमार इस बात पर अडगये कि पहले उह नाम बताये जायें। जब धवन को यह बात बतायी गया तो वह आपसे बाहर हो गये और उहान सुशील कुमार का चुपचाप बात मान लेते पर मजबूर कर दिया। उन्होंने साद वारण्ट पर दस्तखत कर दिये। पी० एस० भिडर, जो 'भरोमे के' पुलिस अफसर थे और हरियाणा से स्पेशल (खुफिया) ब्रांच में लाये गये थे, ज़रूरत में हिसाब से हर वारण्ट में नाम भरत जात थे।

राज्या में मुख्यमंत्रियों को मालूम था कि क्या होने वाला है। वे अपने अपने पुलिस के इस्पेक्टर जनरल और चीफ सेक्रेटारियों के साथ बैठे गिरफ्तार किये जानेवालों के नाम पत्र कर रहे थे। हालांकि बुनियाली तैयारियां की शुर्घात उसी वक़्त से हो गयी थी जब 20 जून के लगभग मुख्यमंत्री दिल्ली में लौटे थे लेकिन तब तक नक्शा कुछ बुंधना था, उस वक़्त यह सोचा गया था कि कुछ ही लोगों को पकड़कर उनका मुह बंद करने के लिए कुछ दिन तक जेल में रखना होगा।

जब भी मुख्यमंत्रियों का कोई दुविधा होती थी तो वे प्रधानमंत्री की कोठी पर टेलीफोन करते थे, जिस 'पराना' या 'महल' कहा जाता था। उसर से उनके सवालों का जवाब धवन देते थे। कुछ मुख्यमंत्री अभी तक यह बात ठीक से नहीं समझ पाये थे कि जब पहले से ही इमजेंसी लागू है तो फिर इस नई इमजेंसी की क्या ज़रूरत है। धवन ने उनको दाना का पत्र समझाया।

उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में पुलिस के हैडक्वार्टर में एक० आई० आर० (पहली सूचना की रिपोर्ट) का एक नमूना तैयार करके धान धाने भिजवा दिया गया ताकि काइला का पट सरन के लिए हाथ में कुछ रहे। ऐसा केवल सावधानी बरतने के लिए किया गया था, हालांकि यह सभी जानते थे कि भीमा के बंदियों का कोई बजह बताये बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता है।

मिठायाशंकर रे अबले मुख्यमंत्री थे जो दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और यही से टेलीफोन पर बलकत्ता में अपने अफसरों को आदेश भेजते रहते थे। वह एक इसलिए गये थे कि श्रीमती गांधी चाहता थी कि जब वह राष्ट्रपति के पास इमजेंसी की घोषणा पर दस्तखत कराने जायें ता वह उनके साथ रहें।

ऐन वक़्त में लगभग चार घंटे पत्ने मिठायाशंकर रे और श्रीमती गांधी राष्ट्रपति भवन गये। मिठाया बाबू को यह समझाने में कि भीतर इमजेंसी में क्या-क्या होगा लगभग पतालीस मिनट लग गये। राष्ट्रपति बहुत ज़दी ही उसका मतलब समझ गये। वह भी बकासत कर चुके थे। इसके बलावा उन्हें अपने यहाँ काम करनेवाले एक एसिस्टेंट के० एल० धवन से, जो प्रधानमंत्री के यहाँ काम करनेवाले धवन के भाई थे, कुछ कुछ भनक मिल गयी थी कि क्या करने की कानिफ की जा रने है।

मानाकारी करने की बात उन्होंने साची तब नहीं। उनके ऊपर श्रीमती गांधी के इनने बड़े एहसान का बाध था कि उह दग के इस सबसे ऊँच पत्र पर पहुँचा दिया। राष्ट्रपति श्रीमती गांधी के बहुत निबट रह चुके थे तास तौर पर 1969 के बाद

मे जब उन्होंने घोर जगजीवनराम ने मिलकर उस वक्त के कांग्रेस के अध्यक्ष एस० निजलिगप्पा को पत्र लिखकर इस बात पर एतराज किया था कि वह राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस के सरकारी उम्मीदवार सजीव रेड्डी के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए जनसमूह घोर दक्षिणपंथी स्वतंत्र पार्टी के पास जा रहे थे। राष्ट्रपति भ्रमद को याद था कि किस तरह उन लोगों ने, श्रीमती गांधी के नेतृत्व में, रेड्डी को हटाकर कांग्रेस के चोटी के नेताओं के गुट को, जिसे सिडीकैट कहा जाता था, नीचा दिखाया था।

इमजैसा की घोषणा पर राष्ट्रपति ने उसके लागू होने से पंद्रह मिनट पहले 25 जून को रात के 11 बजकर 45 मिनट पर दस्तखत किया। प्रधानमंत्री की कोठी वाले घबरे साहब उसका मसविदा लेकर भागे थे। उस दिन राष्ट्रपति भवन में काम करनेवाला कोई भी अफसर सुबह सात बजे से पहले सोने नहीं गया। इस घोषणा में कहा गया था "घातकिक उपद्रवों के कारण भारत की सुरक्षा के लिए सकट उत्पन्न हो गया है जिसके कारण गम्भीर आपात स्थिति मौजूद है।" उसमें सरकार को प्रत्यक्ष आरोप पर संमरणिप लागू कर देने, नागरिक अधिकार लागू करवाने के बारे में प्रदालतों में मुकदमे खड़ा करने, प्रादि के अधिकार द दिए गये थे।

बहुन कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कि कई साल पहले जर्मनी में हुआ था। हिटलर ने प्रेसीडेंट हिडेनब्रग पर दबाव डालकर 'जनता और राज्यसत्ता की रक्षा के लिए' एक अध्यादेश पर दस्तखत करा लिये थे जिसके अनुसार सविधान की वे धाराएँ कुछ समय के लिए रद्द कर दी गयीं जिनमें व्यक्ति और नागरिक स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गयी थी।

अब श्रीमती गांधी के हाथ में विपक्ष से और प्रखबारा से निबटने के लिए, जो उनकी कानूनी हैसियत को मानने से इकार करत थे, सारी ताकत आ गयी थी। अब उनके पास कानूना में मनमानी कतरम्योत करने की सारी ताकत थी, नियमों और परम्पराओं को बदलने की सारी ताकत थी। वह देग, जो अगस्त 1947 में अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के बाद से जनवाद के रास्त पर धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता आया था—पश्चिमी देशों की उस तमाम नुकताओं की बावजूद कि यह प्रणाली भारत के लिए ठीक है भी कि नहीं—वही अब डिक्टेटरशिप जैसी व्यवस्था कायम हो गयी थी।

श्रीमती गांधी ने एक बार कहा था कि वह चाहती हैं कि इतिहास में उनका नाम एक ताकतवर हस्ती की हैसियत से लिया जाय, "कुछ नेपोलियन या हिटलर की तरह क्योंकि उन्हें हमेशा याद रखा जायगा।

उनके पिता न लगभग चालीस साल पहले जो कुछ अपने बारे में लिखा था वह आज बेगी के बारे में भी सच साबित होन लगा था एक जरा से मोड़ में जवाहरलाल चोटी की धाल से चलनेवाले जनवाद का सारा ताम भाम दूर फेंककर डिक्टेटर बन सकते हैं। वह जनवाद और समाजवाद की भाषा और उसके बारे में भले ही इस्तेमाल करत रहें, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसी भाषा के सहारे फासिज्म किस तरह पनपा और बाद में उसने उसे बेकार काठ कबाड की तरह फेंक दिया। उनकी काम करवाने की, जो भी चीज उन्हें आपसन्द हो उसका सफाया कर देने की

1. पूरी जानकारी के लिए मेरी किताब 'इंडिया द डिक्टल इयर्स' पढ़िये। विकास दिल्ली 1971।

2. नेहरू न कलकत्ते की पत्रिका 'माइन रिभ्यू' के 5 अक्टूबर 1937 के अंक में 'राष्ट्रपति जवाहरलाल की जय के शीर्षक से एक गुमनाम लेख प्रकाशित करवाया था।

और नये सिरे से चीजों को बनाने की जो धुन उनमें है, वह जनवाद की धीमी चाल को शायद ही बर्दाश्त कर सके। वह मले ही भूखी अपने पास रख लें, लेकिन उसे भी वह अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़कर ही नम सेंगे। ग्राम हालात के उमाने में वह बस एक मुस्तैद और कामयाब अफसर से ज्यादा कुछ नहीं हूँ, लेकिन इकलावी दौर में सीज़र बनने का लालच हमेशा सामने रहेगा, और क्या यह मुमकिन नहीं है कि जवाहरलाल अपने आपको सीज़र समझने लगे ?”

जो भी नेहरू को जानता है वह यह भी जानता होगा कि वह ऐसा नहीं कर सकते थे। और जो भी उनकी बेटी को जानता है वह यह भी जानता होगा कि वह अपने का सिर्फ सीज़र समझकर ही सतोष कर लेनेवाली नहीं थी। उस रात इस नाटक में उनका बेटा परदे के पीछे खड़ा उन्हें बता रहा था कि उन्हें बबू क्या कहना है और कब क्या बोलना है।

उस रात प्रधानमंत्री के घर पर कोई सोया नहीं। राष्ट्रपति भवन से लौटकर श्रीमती गांधी ने मुबहू छ बजे कबिनेट की मीटिंग बुलाने का फैसला किया। उस वक़्त तक उन्हें मालूम हो चुका था कि जयप्रकाश मोरारजी और सकंटा दूसरे लोगों की गिरफ्तारिया योजना के अनुसार चल रही हैं।

यह कारवाई अचानक बड़ी तेज़ी से और बड़ी बरहमी के साथ की गयी थी और उसमें वे मारी बातें मौजूद थी जो सत्ता पर ख़बदस्ती बख़्शा कर लेने में होती हैं।

दिल्ली में विपक्ष के नेताओं को रात के ड़ाई और तीन बजे के बीच जगाकर गिरफ्तारी के बारे में दिखाये गये और उन्हें पकड़कर एक थान में ले जाया गया। फसा धम्य है कि यह थाना ससद भवन से बहुत दूर नहीं था। उन्हें भीमा में नज़रबन्द कर दिया गया उम्मी कानून के तहत जिसमें स्मगलरो को नज़रबन्द किया गया था।

जो लोग गिरफ्तार किये गये थे उनमें दक्षिणपथ के जनसंघ से लेकर वामपथ की माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तक सभी पार्टियों के साथ थे। विपक्ष की एक ही पार्टी जिस हाथ नहीं लगाया गया था वह थी मास्को समर्थक कम्युनिस्ट पार्टी जो कांग्रेस का साथ देती रही थी।

जिस वक़्त जयप्रकाश का गिरफ्तार किया गया तो “हाने सस्कृत का यह श्लोक पढ़ा बिनाशकाल विपरीत बुद्धि। दो ही दिन पहले मोरारजी दसाई ने इन्हीं के एक पत्रकार के इस सुझाव को मानने से इकार कर दिया था कि वह गिरफ्तार किये जा सकते हैं। उन्होंने कहा था, “वह ऐसा कभी नहीं करेंगी। ऐसा करने से पहले वह आत्महत्या कर लेंगी।” मोरारजी और जयप्रकाश का दिल्ली के पास ही सोना के डाक बैगने में ले जाया गया। लेकिन दोनों को अलग अलग कमरा में रखा गया, जिनके बीच कोई आने-जाने का रास्ता भी नहीं था।

दिल्ली के ज्यादातर भयवाक नहीं निकल सका कि आधी रात से पहन ही उनके प्रेसों की बिजली काट दी गयी थी, सरकारी तौर पर सफाई यह दी गयी कि बिजलीघर में कुछ गड़बड़ी पन हो गयी है। नई दिल्ली में स्टेटमन और हिंदुस्तान टाइम्स निकले क्याकि उनका बिजनी दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन से नहीं बल्कि नई दिल्ली की म्युनिसिपल कमटी से मिलती थी और धनधारा की बिजली काट दन का हुक्म सिर्फ दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन को भेजा गया था। पंजाब और मध्य प्रदेश में भी छापेखानों की बिजली काट दी गयी, लेकिन दूसरी जगहों के शहरों में

निकले। 26 जून को मुबहू देन के अन्तर की हालत के बारे में धनधारा में लिखने पर संसरशिष लागू कर दी गयी। सारी तबरे जांच-पड़ताल के लिए

सरकार के पास भेजनी पड़ती थी।

जिस वक्त तक मंत्री लोग कबिनेट की मीटिंग के लिए। सफदरजंग रोड पर पहुँचे, उस वक्त तक जितने लोगों के नाम गिरफ्तारी की फेहरिस्तों में थे वे लगभग सभी पकड़े जा चुके थे। सरकार ने अखबारों को इन लोगों की संख्या 676 बतायी, कबिनेट के मंत्रियों का यह भी नहीं बताया गया। इमर्जेंसी की घोषणा उनके सामने घटना हो जाने के बाद मजबूरी के लिए रख दी गयी। सभी लोग चुप रहे। जगजीवन-राम प्रौर चह्वाण बस अपने सामनेवाली दीवार को सँतक रहे। चारों तरफ एक तनाव था।

कुछ देर बाद स्वर्णसिंह बोले। उन्होंने पूछा कि क्या इमर्जेंसी सचमुच जरूरी थी? उन्होंने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा और न ही श्रीमती गांधी ने कुछ कहा। इसके बाद सिर्फ इस पर थोड़ी देर चर्चा हुई कि संविधान की धृष्टि से इमर्जेंसी का क्या मतलब है।

लेकिन कबिनेट की मीटिंग तो महज खानापूरी थी। यह रस्म पूरी हो जाने के बाद श्रीमती गांधी ने रेडियो पर अपने भाषण की तयारी शुरू कर दी, जिसका मसविदा सुबह चार बजे ही तैयार हो गया था। कुछ अंग्रेजी शब्दों के हिंदी शब्द न मिलने की वजह से उसे अन्तिम रूप देने में कुछ देर हुई थी।

हिंदुस्तान टाइम्स और स्टेट्समैन ने अपने दिन सुबह भी अखबार छापने की याजना बनायी थी। 11 बजे सुबह हिंदुस्तान टाइम्स तो निकलकर सड़का पर बिकने लगा लेकिन स्टेट्समैन में राटरी मशीन चलन ही वाली थी कि टेलिप्रिटर पर एक जरूरी खबर आयी जिसमें गिरफ्तारियाँ और देश के अंदर की हालत के बारे में सारी खबरें और टीका टिप्पणियों को पहले सेंसर में मजूर करा खन का ऐलान किया गया था। सारी खबरें जाँच पड़ताल के लिए सरकार के पास भेजना जरूरी था। जल्दी-जल्दी राटरी खबायी गयी। स्टेट्समैन ने अपने अखबार के पेज प्रूफ मजबूरी के लिए शास्त्री भवन में प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (पी० आई० बी०) के दफ्तर भिजवा दिये। लेकिन जब तक गिरफ्तार किये गये नेताओं के नाम आटकर और उनकी तस्वीरों पर काटन का निशान लगाकर ये प्रूफ वापस आये तब तक दफ्तर की बिजली कट चुकी थी। सप्लीमेंट नहीं छप सका, बस पत्र प्रूफ ऐतिहासिक दस्तावेज बनकर रह गये।

और जब यह खबर फैली कि हिंदुस्तान टाइम्स तो बिक रहा है, तो हाकरों से जल्दी जल्दी सारी बची हुई बापिंग वापस करने का कहा गया ताकि उनके विलाफ कोई कानूनी कारवाई न हो।

जनसंघ का अखबार मंदरलड अवेला अखबार था जिसने सप्लीमेंट निकाला। बाद में उसके प्रेस पर ताला डाल दिया गया।

उस दिन सुबह रेडियो पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में श्रीमती गांधी ने कहा कि सरकार को मजबूर होकर कुछ कदम उठाने पड़े हैं, क्योंकि "जब से मैंने जनतंत्र की खातिर भारत के आम नर-नारियाँ के हित में कुछ प्रगतिशील कदम उठाने शुरू किये हैं तभी मे एक बहुत गहरी और व्यापक साजिश की जा रही है।" उन्होंने कहा कि इस साजिश का मकसद जनतंत्र का काम ही न करने देना है। जनता की बाकामदा चुनी हुई सरकारों को काम नहीं करने दिया गया है और कहीं कहीं तो विधायकों को इन्सीफा देने पर मजबूर करने के लिए जोर जबदस्ती भी की गयी है ताकि कानूनी तौर पर चुनी गयी विधानसभाओं को भंग किया जा सके।" उन्होंने ललितनारायण मिश्र की हत्या का भी हवाला दिया, और यह इशारा किया कि उसमें विषम का हाथ है।

इतनी बहादुरी की बातें करने के बाद भी उनका डर दूर नहीं हुआ। जैसा कि बाद में उन्होंने किसी से कहा, “मुझे मालूम नहीं था कि जनता पर इसका क्या असर हुआ होगा।”

लोग हक्का-बक्का रह गये, उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि इमजसी का—श्रीमती गांधी के नादिरशाही फरमान का—मतलब क्या है। धीरे-धीरे उनकी समझ में आने लगा कि जो जनतांत्रिक व्यवस्था पच्चीस साल से काम कर रही थी उसको ग्रहण लग गया है। वे सोचते थे कि क्या अब हमेशा ऐसा ही रहेगा?

आकाशवाणी और टेलीविजन पर श्रीमती गांधी के ये शब्द बार-बार दोहराये जाते थे “अब हमें साधारण काम काज में बाधा डालने के लिए सारे देश में कानून और व्यवस्था का चुनौती देने वाले नये कायन्त्रमों का पता चलता है। कोई भी सरकार, जो सरकार कह जान का दावा करती है, इस बात को चुपचाप बर्दाश्त करके देश के स्वामित्व को खतरे में कैसे पड़ने दे सकती है?”

इमजसी का एक फायदा जरूर था कि जरूरी चीजों की कीमतों में ठहराव आ गया था। स्कूलों में, दूकानों पर दूना और बसों में अनुशासन का असर दिखायी देने लगा था, नई दिल्ली की सड़क पर तो गायें और भिसारी भी अब नहीं दिखायी देते थे।

लेकिन श्रीमती गांधी ने यह नहीं बताया कि यह सारी कारबाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही क्यों की जा रही थी, कारखानों में और स्कूल कालजा में ग्राम कानूनों की मदद से अनुशासन क्या नहीं लागू किया जा सकता था, और राष्ट्र में जो और भी बहुत सी बुराइयाँ थी उन्हें भी इन कानूनों की मदद से क्या नहीं दूर किया जा सकता था।

इसकी वजह बता पाना मुश्किल भी था। शायद श्रीमती गांधी ने सोचा कि इसकी कोशिश करना भी बेकार है। वह जानती थी कि उनकी साख बहुत गिर चुकी है। ललितनारायण मिश्र की एक शोक-सभा में उन्होंने कहा, अगर कोई मरी भी हत्या कर दे तब भी यही कहा जायेगा कि यह काम मैंने खुद करवाया है।”

कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया वसा पहले कभी नहीं हुआ था। लगभग सात लाख लोगों ने जैसा सख्त कदम था—‘पुलिस का राज’ तो था ही। सारे देश को अचानक एक धक्का सा लगा, ऐसा लगा मानो सबकी चेतना अचानक सुन हो गयी हो। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना सख्त कदम उठाया जायगा, किसी की समझ में यह भी नहीं आया कि इसके नतीजे क्या-क्या होंगे। बिलकुल ‘जुमेराती कल्लेग्राम’ था। लोग में पहली प्रतिक्रिया यह हुई कि श्रीमती गांधी की इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, वह बचकर निकलन नहीं पायेंगे।

खुद उनकी अपनी पार्टी के ज्यादातर लोग उतने ही हक्का-बक्का थे जितने कि दूसरे लोग। और सबसे पहले वही दुम दवाकर भाग खड़े हुए। 1966 में गद्दी संभालने के बाद में श्रीमती गांधी ने सत्ता का जो मोनार खड़ा किया था उस देखकर सब साग पर पर काँपने लग थे। अब तो जो वह कह दें वही कानून था और कोई भी नहीं कर सकता था। क्विंट के मंत्रियाँ और मुख्यमंत्रियाँ में लकर छाट-न छाट एक्जीक्यूटिव कौंग्रेस तक सभी अपने पद पर तभी तक रह सकते थे जब तक वह चाहें। जिस किसी ने भी सर उठान की काँग्रेस की उमे उठान हटा दिया। जा बच गये उस में ज्यादातर की राजनीतिक जिम्मे उन्हीं के दम में थी। किसी बात के बिनाप आवाज उठाना इनके बस का नहीं था।

श्रीमती गांधी की चुनौती की ही आत्मीय दमकत थी—चुहाण और जगजीवन-

राम। लेकिन दोनों मिलकर कोई काम नहीं कर सकते थे क्योंकि दोनों ही प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। और जब तक जान बच जाने की उम्मीद न होती तब तक वे उनसे टक्कर लेकर अपनी मौजूदा स्थिति को भी खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं थे। और उस वक्त उन्हें इसकी रस्ती भर भी उम्मीद नहीं दिखायी दे रही थी।

श्रीमती गांधी जानती थी कि उन्हें किन किन लोगों पर नज़र रखनी है। और उन्होंने नज़र रखी भी पूरी तरह।

जब मैं 26 जून को चह्माण और जगजीवनराम से मिलने उनके घर गया तो मैंने देखा कि खुफिया पुलिसवाले उनसे मिलने आनवालों की मोटरों के नम्बर और उनके नाम लिख रहे हैं। चह्माण तो डर के भारे मुझसे मिले भी नहीं और जगजीवनराम मिले भी तो एक मिनट के लिए और वह धबराये हुए दिखायी दे रहे थे। जगजीवनराम ने मुझसे बस इतना कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिये जाने का अदेश है। यह वान उ होने बड़ी सावधानी से टेलीफोन का रिसीवर नीचे उतारकर कही। वह जानते थे कि उनके टेलीफोन पर जो भी बात की जाती है वह बीच में सुनी जाती है और वह समझते थे कि अब उसमें यह बारीकी और पैदा कर दी गयी थी कि जब रिसीवर टेलीफोन पर रखा रहता था तब कमरे में होनेवाली सारी बातचीत दूसरी तरफ सुनायी देती थी।

प्रधानमंत्री की कोठी पर 26 जून की रात को विजय का जो वातावरण था उसके बारे में शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। सभी को इस बात पर सतोष था कि सारी कारवाई बिना किसी तबलीफ के पूरी हो गयी। किसी ने कभी विरोध करने की कोशिश भी नहीं की। अगर छुटपुट कुछ घटनाएँ हुई भी तो उन पर जल्दी ही काबू पा लिया गया। मजदूर नेता जाज फर्नांडीज, जनसंघ के नानाजी देशमुख और सुब्रह्मण्यम स्वामी और इक्का दुवका और लोगों को छोड़कर जो 'मडरप्राउड' चले गये थे, सभी खास खास लोग गिरफ्तार कर लिये गये थे। (नानाजी को तो किसी ने टेलीफोन कर दिया था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आ रही है और वह बच निकले थे)।

सजय ने अपनी माँ से कहा, 'मैं आपसे कहता था कि कुछ भी नहीं होगा।' बसिलाल ने कहा कि जसा कि वह पहले से ही जानते थे कही कुत्ता तक नहीं भौंका। इलाहाबाद में जस्टिस सिनहा को 'ठीक कर देने' के लिए कहला दिया गया था। अब पुलिस उनके पीछे परछाई की तरह लगी रहती थी। उनकी सारी पिछली करसूती की छानबीन की जा रही थी और उनके रिश्तेदारों को सताया जा रहा था।

गुजरात को 28 जून को योजना मंत्रालय में भेज दिया गया और उनकी जगह विद्याचरण शुक्ला ने संभाली। उन्होंने स्वर दी कि संसदशिप का बदोबस्त बड़ी तेजी से ठीक होता जा रहा है। धवन को यह खुशी थी कि दिल्ली में संसदशिप का कोई मतनब ही नहीं है। एक बार उन्होंने दिल्ली के भ्रष्टवारी के दफ्तरो की बिजली बटवा दी थी तो उनका सारा काम-काज तब तक ठप रहा था जब तक कि उन्होंने दुबारा बिजली चालू कर देने का हुक्म नहीं दिया था।

श्रीमती गांधी धबरायी हुई थी। यह सोचती थी कि अभी इतनी जल्दी यह नहीं कहा जा सकता कि सब ठीक ठाक है, लेकिन हर मुख्यमंत्री ने यही रिपोर्ट भेजी थी कि 'स्थिति पूरी तरह डाबू में है।'

दिल्ली की सड़कों पर डर छाया हुआ था। जनसंघ के स्वयंसेवक छोटी-छोटी टोलियों में गिरफ्तार हो रहे थे, और कुछ दूसरी छोटी-मोटी घटनाएँ भी हुईं। लेकिन बाहर से देखने में जिंदगी पहले की तरह ही चल रही थी। स्टेटसमन ने कमाल के

फोटोफाफर रघुराय की मीची हुई एक फोटो छापी थी, जिसमें सब-कुछ कह दिया गया था। उसमें दिखाया गया था कि एक आदमी दो बच्चा का साइकिल पर बिठाये ले जा रहा है पीछे पीछे एक औरत पैदल चल रही है और चारों ओर बीसिया पुलिस-वाले हैं। तस्वीर के नीचे लिखा था 'चांदनी चौक' में जिन्दगी पहले की तरह ठीक से चल रही है। (सेंसर के दफ्तर में जो आदमी था उसने तस्वीर को 'पाम' कर दिया—अगले दिन उस बदलकर किसी दूसरी जगह भेज दिया गया।)

मीसा के घोंडर के साइक्लोस्टाइन बिबे हुए पार्मों से उत्तर प्रदेश में कई मजिस्ट्रेटों को बड़ी आसानी हो गयी। उन्होंने खाली पार्मों पर दस्तखत कर दिये और बाकी कारवाई पुलिस पर छोड़ दी। सुफिया पुलिस की पुरानी रिपोर्टों की मदद से तैयार की गयी फेहरिस्तों के हिसाब में गिरफ्तारियाँ होती रही। फिर इसमें ताजजुब ही क्या है कि आगरा में पुलिस ने एक घर पर ऐसे आदमी को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा जो 1968 में मर चुका था।

अखबारों का गला घाटा जा रहा था। जनसभ के हिंदी के अखबार साप्ताहिक पाण्डवजन्म दैनिक सदन भारत और मासिक राष्ट्रधम बंद करवा दिये गये। पुलिस की एक टुकड़ी तलाशी के चारट या उचित अधिकारी की आज्ञा के बिना ही इन अखबारों के दफ्तर में घुस आयी, उसने खूबदस्ती प्रेस में काम करनेवाला को धक्का देकर बाहर निकाल दिया और प्रेस पर ताला डाल दिया ताकि इनमें से कोई अखबार छप न सके। इन अखबारों के प्रकाशक राष्ट्रधम प्रकाशन को सनसक में कोई वकील तक नहीं मिल सका। वकील डरत थे, जो भी उनकी परबी के लिए तयार होता उस भारत सुरक्षा कानून में पकड़कर बंद कर दिया जाता।

धुलू में पंजाब में अकालिया के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की गयी। उम्मीद थी कि ये जनसभ के खिलाफ सरकार का 'साथ देंगे,' क्योंकि सिक्ख हिन्दू सवाल पर दोनों में अन्तर्द्वन्द्व हो गयी थी। लेकिन सरकार यह भूल गयी थी कि दोनों में जा भी मतभेद रहे हों वे पिछले कुछ वर्षों के दौरान दूर हो गये थे। जयप्रकाश के लुधियाना जान पर, जहाँ अकालियों ने उनके लिए पाँच लाख आदमियों की मीटिंग जुटायी थी, ये लोग विपक्ष के उपाग करीब आ गये थे। बहरहाल, सरकार की नादिरशाही का पतला जनसभ की छेड़छाड़ से ज्यादा सगी था।

पंजाब के अखबारों पर, जो सार-सारे जालघर से निकलते थे पुलिस का हमला बहुत बरहम था। ट्रेन के वक्त के हिसाब से उर्दू और पंजाबी के ज्यादातर अखबार आधी रात तक छप जाते थे। पुलिस ने रात को देर से निकलनेवाले एडीशन समेत सभी एडीशनों की सारी कॉपीयाँ नष्ट करवा दी। पंजाब की पुलिस बड़ीगढ़ में ट्रिब्यून के दफ्तर भेजी गयी। जातिर है इसके लिए नई दिल्ली में हुकम धाया होगा क्योंकि सभ क्षेत्र होने के कारण बड़ीगढ़ में घुसने के लिए पुलिस की केन्द्रीय सरकार में इजाजत लनी पड़ती है। चीफ कमिशनर ने इस पर एतराज किया। बाद में घबरे ने इस मामले को अपने ढंग से निबटा दिया।

हरियाणा में ता किसी को भी मीसा या बी० आई० धार० में गिरफ्तार कर लेना वहाँ के शासकों के लिए मन बहलाने का आम तरीका था। किसी को भी पकड़ लेने के लिए वह बंटा हा या छोटा, दोस्त हा या दुश्मन किसी बहाने की जरूरत नहीं होती थी। इमर्जेंसी लागू होते ही विपक्ष के नेताओं और वामकर्त्ताओं की आम घर-पकड़ के अलावा एक हजार से ज्यादा आदमी किसी-न किसी बहाने पकड़ लिए गये थे। जेल में राजनीतिक कैदियों के साथ चौर-आकुषा जैसा बरताव किया जाता था।

दस मर में सबसे पहले महाराष्ट्र हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन ने श्रीमती

गांधी के नादिरशाही शासन की निन्दा की। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के प्रेसीडेंट राम जेठमलानी ने उनकी तुलना मुसोलिनी और हिटलर से की, हालांकि वह यह भी दलील देते रहे थे कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में स्टे-ऑर्डर दे दिया है इसलिए उसका सम्मान किया जाना चाहिए।

कई दूसरे राज्यों के बार एसोसिएशन ने भी ऐसा ही किया लेकिन न जाने क्या पश्चिम बंगाल बार एसोसिएशन ने चुप्पी साध रखी थी।

गुजरात में समुक्त मोर्चे की सरकार होन की वजह से वह राज्य इमर्जेंसी के प्रकोप में बच गया। मुख्यमंत्री बाबूभाई पटेल रडियो पर बोलना चाहत थे। केन्द्रीय सरकार ने उनको इसका मौका देना स इन्कार कर दिया। यह इमर्जेंसी के साथ उनकी पहली झड़प थी। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को आदेश भेजा था कि जनसभ के और दूसरे राजनीतिक नेताओं का गिरफ्तार कर लिया जाये। बाबूभाई ने पहले तो इस आदेश का मानने में इन्कार कर दिया और बाद में जब उन्होंने उनको गिरफ्तार किया भी तो डी० आई० ए० का सहारा लेकर, जिसमें गिरफ्तार किया गया आदमी जमानत पर छूट सकता है, जबकि मोसा में गिरफ्तार किये जानेवाले को कानून इस बात की इजाजत नहीं देता।

बाबूभाई ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह इस बात का पक्का सबूत रखते हैं कि नागरिक स्वतंत्रताओं में किसी तरह की बाधा न पड़ने पाये और यह भी कि वह मीटिंगों और जुलूसों पर पाबंदी नहीं लगायेंगे।

सार राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, बड़े शहरों में ज्यादा हो रहे थे। नागरिकों के बाले बिहने लगाने अपने घरों पर काले झण्डे फहराने और अपने दरवाजा पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखवाने के लिए बढ़ावा दिया गया, जिसमें मानव अधिकारों पर जोर दिया गया है।

जन प्रदर्शनों में खुप जुलूस, छात्रों के जुलूस, भूख हड़तालें और सांख्यिक स्थानों में भरने शामिल थे। धीरे धीरे सार देश में भीमती गांधी के गैंगडो आलोचकों ने इस राज्य में आकर धारण ली।

अगर विपक्ष की सरकार उनकी रक्षा करने के लिए न होनी तो नवनिर्माण समिति के छात्र नेताओं का गायद बनी मुमीवती का सामना करना पड़ता। 1974 में जब उस समय के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल ने अध्यापकों के उम्मीदवारों को, जो उस समय गुजरात में नवनिर्माण आंदोलनों की जान थे, हरबाकर अपने उम्मीदवार ईश्वरभाई पटेल को गुजरात यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनवा दिया था तो इन्हीं छात्र नेताओं ने उनसे भद्रिमण्डल का तहना उन्ट दिया था।

गुजरात सरकार सेंसरशिप के पक्ष में रही थी और उसने राज्य के सूचना विभाग के डायरेक्टर को चीफ सेंसर नियुक्त नहीं होने दिया जमा कि दूसरे राज्यों में हुआ था। प्रहमताबाद के कॉलेज अध्यापकों ने धात्तलन छेड़ दिया और विधानसभा में पूरे दिन इस सबाल पर बहस हुई। यह बात ठीक ठीक मालूम नहीं है सभी है कि नया सूचना विभाग के डायरेक्टर ने सरकार की मलाह से एगा दिया, लेकिन उन्होंने अलवारवाला में कहा कि उस दिन की विधानसभा की बारवाई न एगे।

कुछ दिन बाद केन्द्रीय सरकार ने स्थानीय प्रेम इनफार्मेशन ब्यूरो (पी० आई० बी०) के प्रधान अधिकारी को चीफ सेंसर बना दिया। वे अगवारों को के खबरें छापने से तो नहीं राकत थे जिनमें राज्य-सरकार को परशानी हानी भक्ति इमर्जेंसी या केन्द्रीय सरकार के बारे में सारी खबरों को बड़ी मुम्तदी से दबा दत थे।

तमिलनाडु में भी अगवारों पर सेंसरशिप लागू करने का विरोध किया।

द्रविड मुन्नेत्र कळगम (डी० एम० के०) की सरकार ने, जिसके मुख्यमंत्री करुणानिधि दे, खुली बगावत की नीति नहीं अपनायी और यह ऐलान किया कि वह केन्द्रीय सरकार के उही आदेशों को पूरा करेगी जो 'हमें मंजूर हों'। और सरकारी तौर पर, डी० एम० के० इमर्जेंसी के बिलकुल खिलाफ थी।

पश्चिम बंगाल में, मंत्रियों से लेकर मामूली कांस्टेबल तक सभी ने इमर्जेंसी में मिले हुए अधिकारों की आड़ लेकर अपने सारे, निजी और राजनीतिक, पुराने हिसाब निकास लिये। अमृत बाजार पत्रिका के दो पत्रकार और विचार धोप और बहन सेनगुप्ता, जिन्होंने मुख्यमंत्री की आलोचना की थी, गिरफ्तार कर लिए गये। धोप ने बंगला की एक छोटी सी किताब कालिका में 'राजनीति' आधार पर मुख्यमंत्री की आलोचना की थी लेकिन सेनगुप्ता का हमला निजी बातों के बारे में था। उन दोनों को मौसा में गिरफ्तार कर लेने का हुक्म दिया गया था। धोप को तो आसानी से गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन सेनगुप्ता बलकत्ता छोड़कर भाग गया और दिल्ली में काफी अरसे तक मजबूत के संरक्षण में रहा, जिससे पता चलता है कि श्रीमती गांधी के बैठे और मुख्यमंत्री के सम्बंध कितने खराब थे। लेकिन आखिरकार पुलिस ने सेनगुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया और जेल में उनके साथ बहुत बुरा बरताव किया गया, खासतौर पर इसलिए कि मुख्यमंत्री इस बात पर बहुत नाराज थे कि उसने उन पर कुछ निजी बातों को लेकर हमला किया था।

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता अशोक दासगुप्ता को अपनी रीमार माँ को देखने के लिए हथकड़ी पहनाकर बार घंटे की पैरोल पर ले जाया गया। उन्होंने बहुत कहा कि मैं राजनीतिक कदी हूँ और मेरी माँ को मुझे हथकड़ी पहने देखकर बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। ऐसा लगता है ऊपर से यह सब हिदायत दे दी गयी थी कि इमर्जेंसी में पकड़े गये कदियों को जब भी बाहर ले जाया जाये तो उनके हथकड़ी जरूर ढाली जाये। काफी आन्दोलन के बाद राजनीतिक कदियों को जो रिमायटें मिली थी, वे इमर्जेंसी के दौरान वापस ले ली गयी थी।

जिला अधिकारियों की ओर से आइवेट बसों के मालिकों को भाड़ा बढ़ा देने की जो इजाजत दी गयी थी उसके खिलाफ आवाज उठाने के अपराध में संगठन कांग्रेस के नेता राजकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिजली तथा सिंचाई मंत्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी बद अपने मालदा जिले में मौसा मंत्री के नाम से मशहूर थे। जिस किसी से भी वह नाराज हो जाते थे उसे मौसा में पकड़वा देना की धमकी देते थे।

अखबारों पर सेंसरशिप को पार्टी के और निजी कामों के लिए भी इस्तेमाल किया गया। ऐसी कितनी ही मिसालें हैं जब कांग्रेस के नेताओं के बयान भी सिर्फ इसलिए नहीं छपने दिये गये कि सूचना मंत्री सुब्रत मुखर्जी उन्हें नहीं छपने देना चाहते थे। सेंसर करनेवाला का साफ साफ बता दिया गया था कि मंत्री के ग्रुप के खिलाफ कोई खबर न छपने दी जाय।

विहार में, इमर्जेंसी के दौर में कितने ही तानाशाह उभर आये। वह जो वह देत थे वही कानून हा जाता था। कुछ तानाशाह बिलकुल ठगों की तरह रहते थे उनमें से कुछ ने अपनी रबरलियों के लिए सफ़्ट हाउसों और डाक बंगलों में कमरे रिजर्व करा रखे थे। जिला में जिला मजिस्ट्रेटों से भी ज्यादा उनका सिक्का चलता था। उनका हुक्म बिलकुल मुख्यमंत्री के हुक्म जैसा समझा जाता था और सरकारी अफसरों के लिए कायदे कानून के हिसाब से काम करने की कोई गंजाइश ही नहीं रह गयी थी।

हर कायदे कानून को शासक गुट का काम बनाने के लिए या तानाशाही के निजी हितों को पूरा करने के लिए मनचाहे ढंग से तोड़-भरोड़ लिया जाता था। भूमि-सुधारों का गहरा भस्तर उही जमींदारों पर पड़ता था जिनके बारे में यह शक होता था कि उनका झुकाव विपक्ष की ओर या कांग्रेस के दूसरे गुट की ओर है।

सरकार का प्रचारतंत्र मुख्यमंत्री की हवा बाँधने के लिए पूरा जोर लगाकर काम कर रहा था। सेंसरवाले ऐसी कोई बात छपने ही नहीं देते थे जिसमें उनकी प्रलोचना की गयी हो। सेंसरशिप का मतलब था कि ऐसी कोई खबर न छपने दी जाये जिससे सरकार को या कांग्रेस के शासक गुट को किसी परेशानी का सामना करना पड़े। पूर्णिया और मुंगेर जिलों के दंगों की खबर न बिहार में छपी और न कहीं और ही। भागलपुर जेल में नज़रबन्द कैदियों पर गोली चलाये जाने की खबर भी नहीं छपी, ये लोग उन बुनियादी सुविधाओं की माँग कर रहे थे जो जेल के कायदा की किताब में दर्ज हैं। बन्दूक के धनी पुलिसवालों और वॉर्डरों ने एक दजन से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया।

सारे देश के भ्रष्ट और गैर-जनतांत्रिक शासन के खिलाफ जब स एक प्रादोलन खड़ा करने के लिए जयप्रकाश ने इस राज्य को चुना था। जिस सम्पूर्ण क्रांति को फैलाने का जयप्रकाश ने बीड़ा उठाया था उसकी बुनियाद छात्र सभ्य समितियों और जन सभ्य समितियों के माध्यम से काम करने वाली युवा शक्ति और जन-शक्ति पर, और गाँवों से शुरू करके प्रशासन के हर स्तर पर कायम की गयी जनता सरकारों पर थी। इन हकाइयों के पीछे राष्ट्रीय प्रशासन की कोई समानांतर व्यवस्था कायम करने का कोई इरादा नहीं था बल्कि उनका काम सिर्फ सरकार की व्यवस्था पर निगरानी रखना था।

बिहार हो या गुजरात या दिल्ली सारे भारत में एक ही जसा नक्शा था, बबर शक्ति का प्रदर्शन और जहाँ कोई रत्ती भर भी सर उठाने की कोशिश करे उसे बरहमी से कुचल देना। हर जगह पुलिस ने विरोधियों को मीसा या डी० आई० आर० में वारंट जारी करके या वारंट के बिना ही पकड़ा। (भड़वाणी को गिरफ्तारी के नौ घंटे बाद गिरफ्तारी का आदेश दिलाया गया था।)

निरोधियों की बड़े पमाने पर गिरफ्तारी और भ्रष्टाचारों का गला घोट देने की जो योजना बनायी गयी थी, उसे बड़ी मुस्तदी से और बड़ी तेजी के साथ पूरा कर लिया गया। एक बूद भी खून बहाये बिना सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया गया था।

सारे देश में लोग घाघुघ पकड़े जा रहे थे। गिरफ्तारी के वारंट पर इसके भलावा और कुछ नहीं लिखा होता था कि 'प्रमुख प्रान्तीय को जनहित में' गिरफ्तार किया जा रहा है। उन पर न तो कानूनी कोई अपराध करने का आरोप लगाया जाता था और न ही उन पर कोई मुकदमा चलाया जाता था। ज्यादातर राज्यों में एक० आई० आर० (प्रथम सूचना रिपोर्ट) का, जिसकी बुनियाद पर गिरफ्तारी की वारंवाई शुरू की जाती है एक बेंचा-टका नमूना तैयार करके साइक्लोस्टाइल करा लिया गया था और उसकी कॉपियाँ हर जिले के थानों को भिजवा दी गयी थी कि जहाँ जरूरत पड़े उन्हें भर लिया जाये।

इसी तरह विदेशी पत्रकारों के देश से बाहर निकालने के आदेश भी सब पहले से टाइप करके तैयार रखे गये थे। सदन टाइम्स के पीटर हेजेल्हस्ट जिन्होंने बंगला-देश के सकट के दिनों में 'पाकिस्तानी सरकार के अत्याचारों के बारे में सारी दुनिया को बताने में सिलसिले में बहुत काम किया था, 'यूबोव' के लोरेन जॉन्स और के प्रखवार डेसी टेलीग्राफ के पीटर गिल उन पत्रकारों में से थे जिन्हें विदेश में

वे ज्वाइट सेक्रेटरी एस० एस० सिंधू के दस्तखत से यह आदेश मिला, जिसमें 'राष्ट्र-पति के नाम में' यह लिखा गया था कि वे भव भारत में नहीं रह सकते, उन्हें चौबीस घंटे के अन्दर देश के बाहर निकाल दिया जायगा और उसके बाद वे भारत में कदम न रखें। जॉर्जिस ने लिखा था, 'फ्रान्स के स्पेन से नेवर माफ़ो के चीन तक सारी दुनिया में दस साल तक खबरें जमा करने के दौरान मैंने कभी इतनी कड़ी और इतनी दूर-दूर तक फली हुई सेंसरशिप नहीं देखी।'

इन सभी लोगों को देश से बाहर निकालने के लिए एक ही ढंग अपनाया गया—पुलिस दरवाजे पर खटखटाती थी, आदेश उन्हें देती थी, उनके कागज़ों की तलाशी लेती थी और घंटे भर में वे बाहर निकाल दिये जाते थे।

विदेशों में साग पत्रकारों के इस तरह निकाले जाने पर दंग रह गये, हालाँकि उनमें से बहुतों ने यह कहकर अपने को समझा लिया कि भारत में जनता तो कभी रहा नहीं और ब्रिटिश ससदीय प्रणाली भारतीय स्वभाव से मेल नहीं खाती। उनका खयाल बहुत ऊँचाई से बात करने का था लेकिन बिना मुकदमा चलाये इतने बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारियों और भ्रमबारी का इस तरह गला घोट दिये जाने पर उन्हें सचमुच चिंता थी।

अगर देश के अन्दर सब-कुछ उसी ढंग से हुआ था जैसा सोचा गया था, तो विदेशों की प्रतिक्रिया का भी पहले से आँदा था। जैसा कि पहले ही सोचा गया था, श्रीमती गांधी ने जो कुछ किया था उस पर पश्चिमी देश हक्का-बक्का रह गये। बाप ने जो कुछ बनाया था उसे बटी ने मिटा दिया था।

लेकिन बाहर के किसी देश की सरकार ने सरकारी तौर पर कुछ भी नहीं कहा। उनका कहना था कि यह एक घरेलू मामला था। भारत सरकार ने उनके इस रवैये को बहुत पसंद किया हालाँकि पश्चिमी देशों के अखबार, कुछ लोग और सस्यार्थ, जो कड़ी आलोचना कर रही थी, उस पर उसे काफी गुस्सा था।

जाहिर है कि उनके अपने देश के अन्दर जो दबाव डाला गया उसी की वजह से अमरीका के प्रेमीडेंट फोर्ड ने भारत जाने का विचार अनिश्चित काल के लिए छोड़ दिया। अमरीका में भारत के राजदूत त्रिलोकीनाथ कौल ने इसकी वजह यह बतायी कि फोर्ड पर काम का इतना बोझ है कि वह समय नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन अमरीकी अधिकारियों ने यह मानते हुए कि वह बहुत काम में फँसे हुए हैं साथ ही यह भी कहा कि भारत की डाँवाडोल राजनीतिक स्थिति को देखते हुए इस यात्रा का विचार छोड़ देने का फसला किया गया था।

बाद में फोर्ड ने खुद कहा, मैं समझता हूँ कि यह सचमुच बड़े दुख की बात है कि 60 करोड़ लोग सच यह चीज छिन गयी है जो लगभग पिछले तीस साल से उनके पास थी। मैं समझता हूँ कि कुछ समय बाद के जनतांत्रिक तरीक़े फिर लौट आयेंगे, जिस रूप में कि हम उन्हें अमरीका में जानते हैं।" इस बात से कि उन्होंने यह बात चीन जान से पौरन पहले कही थी, सरकार को एक मोका हाथ लग गया। अक्सर्ड और नादिरशाही मिठाज के मुहम्मद युनुस ने, जिन्हें प्रधानमंत्री का विशेष दूत बना दिया गया था, विदेशी पत्रकारों से कहा कि इस बात पर बड़ी हँसी भाती है कि फोर्ड ने यह राय एक कम्युनिस्ट देश की यात्रा पर जाने से पहले जाहिर की।

काशिगटन में इडियस फार डेमोक्रेसी के नाम से एक सम्मेलन बनाया गया और 30 जून को भारतीय दूतावास के सामने एक प्रदर्शन किया गया। कार्यकारी राजदूत मोनसांल्वेज़ ने 1200 हिंदुस्तानियों के दस्तखत के साथ दी गयी एक प्रार्थना सेने से इबार कर दिया और उल्टे इन लोगों को पाकिस्तानी और चीनी एजेंट कहा।

अमरीकी ट्रेड यूनियन ए० एफ० एल०-सी० आई० थो० ने कहा, "भारत एक पुलिस राज्य बन गया है जिसमें जनतंत्र को कुचल दिया गया है।" उसने अमरीका की सरकार से अनुरोध किया कि जब तक वहाँ की जनता के लिए फिर से जनतंत्र की स्थापना न हो जाये तब तब के लिए वह भारत सरकार को कोई भी मदद न दे।

इंग्लैंड का, जिसके भारत के साथ भावुकता के सम्बन्ध बने हुए हैं, बहुत धक्का लगा। अखिरकार भारत ने जो रास्ता अपनाया था वह ब्रिटिश सत्तवीय प्रणाली का रास्ता था। अखबारों की स्वतंत्रता की हत्या को वहाँ और भी गहराई में महसूस किया गया। ब्रिटिश सरकार का विरोध प्रकट करने के लिए प्रिंस चार्ल्स की भारत की यात्रा रद्द कर दी गयी। बी० बी० सी० जिसका नई दिल्ली का दफ्तर पहले भी एक बार बन्द करवा दिया गया था, अब पहले से ज्यादा खबरें देने लगा और भारत में उपादातर लोगों को, जेलों के अन्दर भी, इमर्जेंसी के पूरे दौर में अपने देश की खबरें बी० बी० सी० के जरिये ही मिलती थी। बाद में उसके मिलनसार सम्वाददाता माक टेल्ली को एक बार फिर यह देश छोड़ना पड़ा क्योंकि भारत सरकार इस पर भड़ी हुई थी कि बी० बी० सी० भारत से जो खबरें भेजे उन पर पहले सेंसर की मजूरी ले।

लेकिन सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में राय इंदिरा गांधी के पक्ष में थी। आवाज को इमर्जेंसी के अन्धे नतीजे भी दिखायी देने लगे। इस अवसर पर ने लिला, "अधिकारियों ने दक्षिणपंथी पार्टियों के नेताओं की जो गिरफ्तारियाँ की हैं उनको जनतांत्रिक शक्तियाँ सही समझती हैं, और मॉरिशस लागू हो जाना मध्य इजारेदारों के अखबारों को सरकार के खिलाफ मुहिम चलाने और लोगों को भड़काने का मौका नहीं मिलेगा।"

चीन ने भी आलोचना की, जैसा कि वह हमेशा से करता आया था, लेकिन इमर्जेंसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए नहीं बल्कि भारत सरकार को बर्नाम कराने के लिए।

चुनाव में बजा तरीके अपनाने पर श्रीमती गांधी के अदालत में दोषी ठहराये जाने पर जुल्फिकार अली भट्टो ने सन्तोष प्रकट किया। बाद में उन्होंने एक मसबार को बताया, "उपमहाद्वीप के दूसरे हिस्से की स्थिति हाल की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि इस बाईबोल इलाके में पाकिस्तान ही के पाव मजबूती से जमे हुए हैं।"

श्रीमती गांधी ने पश्चिमी देशों के खिलाफ उनका नाम लेकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका गुस्सा साफ जाहिर था। उन्होंने कहा कि इन देशों ने पहले ही से भारत के खिलाफ एक खराब राय बना रखी है। किसी देश का नाम लिये बिना उन्होंने पश्चिमी तापतो और पश्चिमी देशों के अखबारों को बहुत सताड़ा कि एक तरफ तो वे गर जनतांत्रिक सरकारों को सहारा देते हैं और दूसरी तरफ "जनतंत्र की शिक्षा देने की कोशिश करते हैं।" उन्होंने घुमा फिराकर अमरीका पर अक्षरों का इल्जाम लगाया कि वह बातें तो जनतंत्र की बरता है लेकिन सैटिन अमरीका में और दूसरी जगहों में वह तरह तरह की डिक्टेटरी हकूमतों को लगातार सहारा देता रहता है। श्रीमती गांधी ने पश्चिमी देशों की सरकारों और उनके अखबारों की चर्चा इस तरह एक साथ की मानो वे एक ही चीज हों और यह आरोप लगाया कि विदेशी ताकतें भारत के 'अइरपाउंड' आन्दोलनों को बढ़ावा दे रही हैं।

उन्होंने कितनी ही बार कहा कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे थे वे वही देश थे जिन्होंने पाकिस्तान में याह्या खान की फौजी हुकूमत का और बंगला देश के दमन का समर्थन किया था। आज यही देश चीन के करीब आने के लिए एक-दूसरे से होठ कर रहे थे। "इन लोगों को चाहिए कि हमें उपदेश देने के बजाय अपने गिरेबान

मे मुंह डालकर देखें।”

उन विदेशी भ्रष्टाचारों को, जिनमें आलोचना करनेवाली खबरें छपती थी, भ्रान्त हो नहीं दिया जाता था। जब से शुक्ला सूचना मंत्री बने थे तब से सेंसरशिप और कड़ी हो गयी थी।

भ्रष्टाचारों के लिए हिदायतें जारी कर दी गयी थी और किसी भी भारतीय या विदेशी भ्रष्टाचार में अफवाह छापने, आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने और कोई भी ऐसा लेख छापने पर जिससे सरकार के खिलाफ विरोध की भावना उभरने का खतरा हो, बिलकुल पाबन्दी लगा दी गयी थी। ऐसे सभी कार्टून, फोटो और विज्ञापन, जिन पर सेंसर के कानून लागू हो सकते हैं सेंसर के लिए भेजना जरूरी ठहराया गया।

समाचार एजेंसियों के दफ्तरों में अक्सर तैनात कर दिये गये थे ताकि वे आपत्तिजनक चीजों को वही जगह पर काट दें। विदेशी समाचार एजेंसियाँ जो भेजती थी उनकी भी छानबीन की जाती थी और अगर उनमें सोवियत संघ जैसे 'मित्र देशों' के खिलाफ भी कोई बात होती थी तो उस वही दबा दिया जाता था। जयप्रकाश के एवरीमन, राज पनाईय के प्रतिपक्ष, और पीनू मोन्नी के भाष्य ऑफ द नेशन को अपना प्रकाशन बन्द कर देना पड़ा। जनसंघ के मंदरलड और आयनाइजर पर पाबन्दी लगा दी गयी और उनके दफ्तरों पर ताला लगा दिया गया।

शुक्ला न सजय को पूरा यकीन दिलाया था कि वह पत्रकारों को ठीक कर देंगे जबकि गुजराल यह काम नहीं कर पाये थे। उन्होंने दिल्ली के सम्पादकों की एक मीटिंग करके उनसे साफ साफ कह दिया कि सरकार 'कोई बेहूदगी' बर्नास्त नहीं करेगी, वह जमकर शासन करेगी।

उन्होंने मुझे बताया कि किसी सम्पादकीय में, किसी लेख में या किसी भी जगह खास जगह छोड़ना भी (जो अंग्रेजों के जमाने में सेंसरशिप के खिलाफ विरोध प्रकट करने का भारतीय भ्रष्टाचारों का एक आम तरीका था) बग़ावत समझा जायगा, उन्होंने सम्पादकों को गिरफ्तार कर देने की भी धमकी दी। सब लोग यह सुनकर दग रड़ गये लेकिन किसी ने इसके खिलाफ कुछ कहा नहीं। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सेंसरशिप को उचित बताया और सरकार की तारीफ के ऐसे पुनर्वाचे कि अगर शुक्ला की जगह कोई दूसरा होता तो खुद शरमा जाता।

भ्रष्टाचारवाला ने लिए सिफ डंडा था, कोई सालाब भी नहीं दिया जाता था। और इस डंडे को अच्छी तरह इस्तेमाल करने का पक्का बन्दोबस्त करने के लिए शुक्ला इण्डियन पुलिस सर्विस ने के० एन० प्रसाद को अपने मंत्रालय में ले लाया, यही उनका दाहिना हाथ था डंडा चलानेवाला हाथ था। उन्होंने एक अनोखा तरीका यह निकाला था कि वह टेलीफोन पर सेंसर को घाटे-देते थे और सेंसरवाले अक्सर को टेलीफोन कर देते थे।

लेकिन 29 जून को सेंसरशिप लागू किये जाने के खिलाफ अपनी धावाज उठाने के लिए प्रेस क्लब में सभासक्त सभी पत्रकार जमा हुए जिनमें कुछ सम्पादक भी थे और उन्होंने सरकार में आपत्ति की कि सेंसरशिप उठा ली जाय। उन्होंने जामशेर ने हिंदू समाचार के जगतनारायण और दिल्ली के मंदरलड ए० एम० धार० मसकानी की रिहाई की माँग की। मैंने इस प्रस्ताव की नज़रें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सूचना

मन्त्री के पास भेज दी।¹

विदेशी पत्रकारों को उनकी भेजी हुई खबरों के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता लेकिन उन्हें देश से निकाल बाहर किया जा सकता था। सबसे पहले जो निकाले गए वह थे चांसिंगटन पोस्ट के लीविस एम० साइमस, जिन्होंने एक लंबा लिखा था 'सत्य गांधी और उसकी माँ'। उसमें और बाता के अलावा यह भी लिखा था, 'भारत के लिए गम्भीर संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें अपने मंत्रिमण्डल के निवृत्ततम सहयोगियों पर भी भरोसा नहीं रह गया है बड़े-बड़े राजनीतिक फैसले करने के लिए अपने छोटे बेटे की मदद का सहारा लेने लगी हैं। परिवार के एक मित्र जो बड़े महीने पहले सत्य और श्रीमती गांधी के साथ खाने की दावत में शरीक हुए थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद देखा कि बेटे ने छ बार माँ के मुँह पर तमाचे मारे। वह कुछ भी न कर सकी। इस मित्र ने कहा, 'वह चुपचाप खड़ी तमाचे खाती रही। उसके डर के मारे उनका दम निकलता है।'

सत्य ही उनकी तरफ से हर बात का फसला करता था। पार्टी में या सरकार में उसकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन दोनों जगह वही 'चौधरी' था। देश में सारा प्रशासन-तंत्र उसके इशारे पर नाचता था। प्रधानमंत्री की कोठी से वह कैबिनेट के मंत्रियों मुख्यमंत्रियों और ऊँचे-ऊँचे सरकारी अफसरों को हुक्म देता था और वे चुपचाप उसका हुक्म बजा लाते थे। अक्सर तो ऐसा भी होता था कि जब वे श्रीमती गांधी के पास किसी सवाल पर बात करने जाते थे तो वह खुद कह देती थी, सत्य से बात कर लीजिये। और तब वह खुद अपनी तरफ से उन्हें आदेश देता था।

लेकिन सत्य लगभग हमेशा ही उन्हें बता देता था कि वह क्या कर रहा है और उन्हें क्या आदेश दिये हैं। इमर्जेंसी के शुरू शुरू के दिनों में सत्य और उनके कारिंदे—बसीलाल, भोम मेहता, धुन्ना और धवन—प्रधानमंत्री की कोठी पर दिन भर का लेखा-जोखा करने के लिए जमा होत थे। तब तक एक और आदमी इस टोली में शामिल हो गया था—यूनूस। वह कोठी में मँडराते तो पहले ही दिन से रहे थे लेकिन कुछ प्ररस तब उन्हें इस दीवाने-खास में घुसने की इजाजत नहीं थी। नेहरू परिवार के साथ उनका बहुत पुराना सम्बन्ध रहा था और नेहरू न ही उन्हें राजदूत चुना था। उनकी राय में श्रीमती गांधी की सारी मुसीबतों की जड़ हकसर थे।

इस 'इमर्जेंसी कौंसिल की मीटिंग' में, जिनमें श्रीमती गांधी भी हिस्सा लेती थी, खुफिया विभाग की रिपोर्टों, 'रा' के अनुमानों फोन पर मुख्यमंत्रियों से धवन की जमा की हुई खबरा पर चर्चा होती थी। विदेश संचार सेवा के जरिये विदेशी सवाद दाता जो ख़तरें भेजते थे उनकी नकलें भी उनके सामने रहती थी।

यही यह तय किया जाता था किस मंत्रालय या किस राज्य को, और किस अफसर के पास, क्या आदेश भेजे जायेंगे। बिलकुल वही नक्शा होता था जैसे लड़ाई के दौरान अलग अलग मार्चों पर फौजी कारवाई का फैसला किया जा रहा हो और हालाँकि श्रीमती गांधी बहा मीजुद रहती थी लेकिन सारी कारवाई की बागडोर सत्य के हाथ में रहती थी।

धवन और भोम मेहता में अक्सर तनावनी रहती थी, क्योंकि प्रधानमंत्री के पमनल असिस्टेंट भोम मेहता की जागीर में जाकर शिक्का मार लाते थे। धवन अक्सर

1 इसकी और अधिक जानकारी के लिए मेरी अगली पुस्तक 'जेल' में की प्रतीक्षा करें।

2 सत्य की शांति उन्हीं के घर पर हुई थी और श्रीमती गांधी का पूरा परिवार उन्हें बड़ा चाचा कहता था।

दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर किशनचंद और दिल्ली पुलिस के डी० आई० जी० मिडर के जरिये खुद अपनी मर्जी से भी कई काम करवा लेते थे। मिडर को अपनी बारी से पहले ही तरक्की देकर इम प्रोहदे पर पहुँचा दिया गया था, जिस पर प्रोम मेहता और गह मन्नालय के सेक्रेटरी खुराना बहुत खोके हुए थे। दोनों गुटों में हमेशा टनी रहती थी खासतौर पर दिल्ली में होनेवाली कारवाइयों के सवाल पर। उनके झगड़े भी सच्य ही निबटाता था और उन्हें उनके काम मौपता था।

श्रीमती गांधी का अपने बेटे और उसके कारिन्दों पर पूरा भरोसा था। उसे वह काम का धनी समझती थी, जिसने उन्हें उस वक्त बचा लिया था जब उनके परिवार लडखड़ा गया था। सजय का काम अपने नाना की तरह सिर्फ दूसरों को बचाना नहीं था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसे क्या बनना है, वह जानता था भविष्य उसी का है। श्रीमती गांधी इस बात के लिए पूरी तरह राजी थी कि वह फैमले करे—और बड़े बड़े सचालों के गारे में ही नहीं, अप्सरो की नियुक्ति और बदली, जो लोग बफादार थे उनका तरक्की और जो नहीं थे उनको सजा—इन सब बातों का फैसला सजय के ही हाथ में था। कभी-कभी किसी बुनियादी महत्व की जगह पर किसी अप्सर की नियुक्ति से पहले सजय उसकी इण्टरव्यू लेता था। ऐसा लगता है कि वह कई ऐसे लोगो को, जो बहुत लम्बे भरसे तब उसकी माँ की सेवा कर चुके थे धुबहे की नजर में देखता था, खासतौर पर कश्मीरियों, दक्षिण भारत के लोगो और पूरब के लोगो को।

सजय उत्तर के लोगो को, खासतौर पर पंजाबियों को ज्यादा पसन्द करता था। वह जानता था कि ये लोग उसके लिए जान तक दे देने को—या कम से कम दूसरी की जान न लेने को—हमेशा तैयार रहेंगे। जैसे-जैसे दिन बीतते गये कश्मीरी गिराह, जो उसकी माँ के जमाने में छाया हुआ था, धीरे-धीरे पंजाबी गिराह में बदलता गया। लेकिन अब वह सिर्फ गिराह नहीं था ठगो का गिराह था।

उसकी माँना उन लोगो की मदद में पूरी की गयी थी जिन पर वह इस बात के लिए पूरा भरोसा कर सकता था कि वे 'इमजेंसी की कारवाई' की मशीन के सारे बलपूर्वक अपनी अपनी जगह पर ठीक से फिट कर देंगे, राष्ट्रपति के दस्तखत में फरमाज जारी कराके सारे पंच बस दिये गये। अपने मूल अधिकारों की रक्षा कराने के भारतीय नागरिकों और विदेशियों के सारे अधिकार छीन लिये गये। एक और करमान की मदद में मोसा का कानून और सम्म बना दिया गया जो लोग नजरबन्ध किए जाते थे उन्हें या अगलतों को उनकी नजरबन्दी की वजह बताये बिना ही जेल में बन्द रखा जा सकता था। इसकी अपनी भी किसी अगलत में नहीं की जा सकती थी।

श्रीमती गांधी का दावा था कि वह हर काम सविधान की सीमाओं में रहकर कर रही हैं और वह अपनी हर कारवाई को उचित ठहराने के लिए जनमत की बचान की दुहाई देती थी। 'नासन कितना ही नादिरशाही क्या न हो जनमत का खिाया तो याकी रखना ही था। जसा कि आज पाब्ले ने कहा था, लगभग सभी लोग यह महसूस करते हैं कि जब हम किसी देश को जनतांत्रिक करते हैं तो हम उसकी प्रणाली करते हैं नतीजा यह होता है कि हर तरह के शासन में डिक्टेटर दावा यनी करता है कि उसका शासन जनमत है।

पल्लवाग पर मॉरगिन लागू कर दन मून अधिकांग को ताक पर रग दन और मकान सागा को मुहदमा पलाय बिना जेम में ठग देने के बाद बेवन पाब्ले की उम निराशी भाषा 'मूम्पीक' (नयी बानी) में ही, जिनम मुद मन्नालय को नाति मन्नालय कहा जाता था श्रीमती गांधी यह कह सकती थी कि भारत अब भी एक

इंटरनेशनल प्रेस इन्स्टीच्यूट ने श्रीमती गांधी से सेंसरशिप हटा लेने का अनुरोध किया, क्योंकि वह 'दुनिया की नज़रो में भारत के नाम पर एक कलक ही साबित हो सकती है।'

सोशलिस्ट इंटरनेशनल ने 15 जुलाई को जयप्रकाश से जहाँ वह नज़रबंद थे वही मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमण्डल भेजने का फैसला किया जिसमें विन्नी ग्राट, जो पश्चिम जर्मनी के चासलर रह चुके थे, और ब्रायरलड के डाक तार भत्री कोनार क्रू और ब्रायन भी शामिल थे। लेकिन भारत सरकार ने यह कहकर उन्हें इजाजत देने से इकार कर दिया कि 'यह भारत के आदरही मामलात में सरामर हस्तक्षेप' होगा। सोशलिस्ट इंटरनेशनल ने इसके जवाब में कहा, अब सभी सोशलिस्ट यह महसूस करते होंगे कि भारत में जो कुछ हो रहा है वह उनके लिए निजी मीर पर एक दु खद बात है।'

पश्चिमी देशों में सरकारी राय यह थी कि भारत में जनतन्त्र हमेशा के लिए खत्म हो गया है और यह बात कितनी ही सबलीफदेह क्यों न हो, श्रीमती गांधी को नाराज करने में तो अच्छा यही है कि इस सच्चाई को मान लिया जाये। अमरीका के विदेशमंत्री हेनरी किस्सिंजर ने विदेश विभाग में इस सवाल पर बहस की और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि अब भारत सरकार से निबटना ज्यादा आसान होगा। इस मीटिंग में उनके एक सहयोगी ने कहा कि श्रीमती गांधी की नीति अब ज्यादा व्यावहारिक होगी। किस्सिंजर ने कहा, 'तुम्हारा मतलब है बिकाऊ।' किसी ने डिक्टटर का भी जिक्र किया।

शायद उस वक़्त भी वह यह मानने को तयार नहीं थी कि वह डिक्टटर है, और अगर कोई उन्हें डिक्टटर कहता था तो वह इस अपना अपमान समझती थी। और देश में बहुत से लोग ऐसे थे जो यह यकीन ही नहीं कर सकते थे कि नहरू की बेटी डिक्टटर बन सकती है उन्हें पूरा यकीन था कि एक असाधारण स्थिति से निबटने के लिए उन्होंने असाधारण अधिकार अपने हाथ में ले लिये हैं। यह दूर कुछ दिन में बीत जायेगा।

लेकिन कम-कम अब आदमी ऐसा था जिम्मेदार शब्दों में कहा था कि वह किधर जा रही हैं। वह जानता था कि श्रीमती गांधी जनवादी नहीं हैं और उसने यह बात कह भी दी थी। और इसी अपराध में वह जेल में बंद था।

368
— शीमोने

२१ धीर अधिकार

‘मेरा हमेशा से यह विश्वास रहा है कि श्रीमती गांधी की जनतंत्र में कोई भास्था नहीं है, कि वह अपने स्वभाव और अपने विश्वास से डिक्टेटर हैं।’ ये शब्द जयप्रकाश नारायण ने जेल में अपनी डायरी में 22 जुलाई को लिखे थे।

इससे एक ही दिन पहले उन्होंने इसी आशय का एक लम्बा पत्र श्रीमती गांधी को लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था

“राष्ट्र के निर्माताओं ने, जिसमें तुम्हारे उदात्त पिता भी शामिल थे जो नीचे डाली थी उन्हें मेहरबानी करके नष्ट न करो। तुमने जो रास्ता अपनाया है उस पर भगड़े और मुसीबत के झलावा और कुछ नहीं है। तुम्हें उत्तराधिकार में एक महान् परम्परा उदात्त आदर्श और एक काम करता हुआ जनतंत्र मिला है। अपने पीछे इन सबके टूटे हुए खण्डहर न छोड़ जाना। इन सब चीजों को फिर से जुटाकर बमाने में बहुत समय लग जायेगा। इसे फिर से जुटाकर खड़ा कर दिया जायेगा, इसमें तो मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है। जिस जनता ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से टक्कर ली है और उसे नीचा दिखाया है वह निरबुशता के क्लक और अपमान को हमेशा के लिए स्वीकार नहीं कर सकती। मनुष्य की आत्मा कभी परास्त नहीं हो सकती, उसे चाहे जितनी बुरी तरह क्यों न कुचला जाये। अपनी निजी डिक्टेटरशिप कायम करके तुमने उसे बहुत गहरा दफन कर दिया है। लेकिन वह अपनी कब्र से फिर उठेगी। इस तक मे वह धीरे धीरे उभर रही है।

“तुमने सामाजिक जनतंत्र की बात की है। इन शब्दों से मन में कितनी सुन्दर कल्पना उभरती है। लेकिन तुमने खुद पूर्वी और मध्यवर्ती यूरोप में देखा है कि वास्तविकता कितनी कुरूप है। नगी तानाशाही और भ्रत में चलकर रूस का प्रभुत्व। मेहरबानी करके दया करके भारत को उस अमानक दुर्भाग्य की धार मत ढकेलो।’

गिरफ्तारी के बाद जयप्रकाश को पहले सोना ले जाया गया और फिर दिल्ली की गैल इण्डिया मेडिकल इन्स्टीच्यूट में लाया गया, क्योंकि वह बीमार थे। जल्द ही यह बात साफ तौर पर समझ में आ गयी कि उन्हें लम्बे घरसे तब अस्पताल में रखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन दिल्ली इसके लिए मनुसिब जगह नहीं थी, वह हमेशा से अफवाहों का शहर रहा है और अब भी था। यह भेद कौन नहीं जानता था कि जयप्रकाश गैल इण्डिया मेडिकल इन्स्टीच्यूट में है बाहर मदान में उत्सुक लोग की टोलियाँ जमा होने लगी थी।

उन्हें कहीं और ले जाना जरूरी था। उन्हें नजरबंद रखने के लिए चंडीगढ़ की पोस्ट-ग्रेजुएट इन्स्टीच्यूट को चुना गया। बसोलाल ने पहरेदारी के लिए कुछ चुने हुए पुलिसवालों का बन्दोबस्त कर दिया। जयप्रकाश को भाग निकलने का मौका नहीं दिया जा सकता था, जिस तरह वह 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान जेल से भाग निकले थे।

Handwritten musical score on 11 staves. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and clefs, written in a cursive style. The score is organized into systems, with some staves containing multiple lines of notation. The handwriting is dense and characteristic of 18th or 19th-century musical manuscripts.

- 7) खेती के काम की कम से कम मजदूरी की दर पर फिर से विचार।
 - 8) पचास लाख हेक्टेयर नयी जमीन पर सिंचाई का बल्गेवस्त और जमीन के नीचे के पानी को इस्तेमाल करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम तयार करना।
 - 9) विजली की पैदावार बढ़ाना।
 - 10) हथकरघा क्षेत्र का विकास और जनता के इस्तेमाल के सस्त कपड़े की क्वालिटी और उमकी सप्लाई में सुधार।
 - 11) शहरी जमीन और आगे चलकर शहरी वन बनने वाली जमीन के समाजीकरण को लागू करना और छाती जमीन की मिल्वियत और बन्दे पर हदबंदी लगाना।
 - 12) अनाप शनाप खच करनेवाला के मान जायदान की कीमत घाँबन के लिए लाख टुकड़ियों का इन्तजाम और टैक्स चोरी की रोकथाम और आयिक अपराध करने वालों पर भटपट मुकदमा चलाकर उन्हें ऐसी बड़ी सजाएँ देना कि दूसरे लोग जैसे अपराध करने से डरें।
 - 13) स्मगलरों की जायदादें खन करने के लिए खास कानून।
 - 14) पूँजी लगाने के कार्यक्रम-कानून में नरमी और इपोट लाइसेंसों का बेजा इस्तेमाल करनेवाला के खिलाफ कार्रवाई।
 - 15) उद्योगों की व्यवस्था में मजदूरों के भाग लन के लिए नयी योजनाएँ।
 - 16) ट्रकों वसों आदि के लिए राष्ट्रीय परमिट योजनाएँ।
 - 17) मध्यम वर्ग के लोगों के लिए इनकम टैक्स में छूट—8,000 रुपये तक की आयदनी पर कोई टैक्स नहीं।
 - 18) होस्टलों में विद्याथियों के लिए कंट्रोल के दामा पर उनकी जरूरत की चीजें।
 - 19) कंट्रोल के दामों पर कितानें और लिखने पढ़ने का सामान।
 - 20) रोजगार और ट्रेनिंग की सुविधाएँ बढ़ाने के लिए खासतौर पर समाज के कमजोर हिस्सा के लिए नयी अप्रेंटिसशिप योजना।
- इससे कुछ ही महीने पहले दिल्ली से थोड़ी ही दूर पर नरौरा में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा ही तमाशा किया था जब उ होन गरीबों को राहत दिलाने के उपाय करने, जयप्रकाश की सहर को रोकने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों क्विनेट मंत्रियों प्रदेश कांग्रेस कमिटियों के अध्यक्षों को जुटाया था। उस वकत उन्होंने कहा था कि जयप्रकाश के साथ उनके मतभेद असल में 'सामाजिक' याय और आयिक स्वतंत्रता की और हमारे समाज को और ब्यादा आगे बढ़न से रोकने पर तुल हुए पसवाल स्वार्थी वर्गों का और सामाजिक तथा आयिक क्षेत्रों में जा कुछ हासिल किया गया है उसे पक्का करने और अपन चुने हुए रास्तों पर आगे बढ़ते जाने के लिए कमर बाँधे हुए मेहनतकश जनता का टकराव है।
- श्रीमती गांधी अपने राजनीतिक दाय-पेंच के लिए एक आयिक घाट जरूर रखती थी। 1969 में जब कांग्रेस में फूट पड़ी थी तब भी उन्होंने यही किया था, और 1971 में समय से पहले लोकसभा के चुनाव के वकत भी उन्होंने यही किया था और गद्दी कि उनकी लड़ाई अपनी गद्दी को बचाय रखन के लिए नहीं बल्कि देश की आयिक भलाई के लिए है। इस बार भी उनको यकीन था कि सरकार पर अपना बन्दो बनाय रखने की उनकी चाल बीस-सूत्री कार्यक्रम की घाट में छिप जायगी। और उस समय तो उन्हें कामयाबी मिलती दिखायी दे रही थी।

प्रचार प्रसार के सभी माध्यमों में और हर सरकारी और सरकारी वहस में जहाँ देसो वीस सूत्री कार्यक्रम की ही चर्चा थी। हर जगह बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए थे और पोस्टर चिपकाए गए थे जिन पर कार्यक्रम के बीस सूत्र लिखे होते थे और साथ में श्रीमती गांधी की एक बड़ी सी तस्वीर होती थी। बाढ़ जितना ही बड़ा हाता था, लोग पर उसका उतना ही अच्छा धरार पड़ता था। आगिरकार उन्होंने खुद ही इन बोर्डों का हटवा देना का हुक्म दिया क्योंकि उनके करीबी दोस्तों ने उन्हें बताया कि इन बोर्डों की तस्वीरों में आप 'भयानक' लगती हैं।

हर आदमी का कनव्य था कि वह बीस सूत्री कार्यक्रम के अनुसार काम करे, या कम-से-कम जताये तो जरूर कि वह ऐसा कर रहा है। दिल्ली प्रशासन ने सभी व्यापारियों और दुकानदारों को आदेश दे दिये कि वे अपना स्टॉक और कीमती तब्दी पर जिसकर दुकान में लगायें। उन्हें लगभग हर चीज पर दाम की पर्ची लगानी पड़ती थी। इस आदेश का सहारा लेकर अधिकारी बड़ी आसानी से उन दुकानदारों को सजा दे सकते थे जो कांग्रेस की, और बाद में युवक कांग्रेस की तिजोरिया भरने के लिए पैसा नहीं देते थे या जो सरकार के बताए हुए ढंग से सोचने से इकार करते थे।

संजय ने हक्सर से अपना हिमायत चुकाने के लिए दाम की पर्चियां लगाने के हुक्म का सहारा लिया। हक्सर के 80 बरग वूड चाचा, जो नई दिल्ली में बनावटनेस के डिपार्टमेंट स्टोर पंडित ब्रदर्स के मानिक थे, गिरफ्तार कर लिये गए क्योंकि उनकी दुकान में किसी छोटी-सी चीज पर नाम की पर्ची नहीं लगी हुई थी और उहे तीन मिनट तक जेल में रखा गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थानीय नेता अरुणा आसफअली को जाकर श्रीमती गांधी का सम्मानना बुझाना पड़ा कि वह बीच में पड़कर हक्सर के चाचा को छुड़वा दें।

हक्सर की ईमानदारी की दाद देना पड़ती है कि श्रीमती गांधी की सरकार की तरफ उनकी बफादारी में कभी फर्क नहीं आया था। लेकिन यह तो संजय का, और यो तो सरकार का भी, काम करने का तरीका ही था—लोगों के दिल में गहरी छिड़का देना। इतने कुकर्म हो रहे थे कि श्रीमती गांधी ने भी अपना अलग ही एक काम करने का ढंग निकाल लिया था, वह इस तरह की सारी बातों के बारे में अनजान बन जाती थी, हालांकि उहे अपने बेटे और उसके गुर्गों की ज्यादातर हकूत का पहले से पता रहता था।

चीनी और कपड़े की मिला को सरकार के हाथों में लाने के बारे में बरुमा ने जा मुभाव रखा था उसकी चर्चा चारों तरफ हो गयी थी। श्रीमती गांधी ने एक बयान जारी किया कि कारखानों को अपने हाथ में लाने का कोई नया बड़े कंट्रोल लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

श्रीमती गांधी ने कहा कि भीमा का इस्तेमाल रमगलरा को पकड़ने के लिए किया जाएगा। संभवतः उनका कारोबार सारी दुनिया में फैला हुआ था और उनका सबसे बड़ा अट्टा दुर्वाई में था। उका और भीमा कम्पनियां ने रमगलरा के लिए पैसा देने और मान के पकड़े जान या मी जानें के ग्यारे का भीमा करने के लिए वहाँ अपने एगनर खाल किया था। समुद्र के रास्ते मडन के रास्ते और दुर्वाई जहाजों से प्रावाजाही का एक पूरा जान फका लिया गया था। गुजरात से लेकर करल तक समुद्र के किनारे किनारे किननी ही एसी पहचानी हुई जगह थी जहाँ रमगलरा का माल उतारा जाता था और वहाँ से मारे लक्ष में खपत के के द्रा में भेज दिया जाता था। मद्रास रमगलरा का बहुत बड़ा अट्टा था और बंगलौर उनके लिए बिना किसी खतरे के जा छिपने के लिए बहुत अच्छी जगह थी, जहाँ वे एक दूसरे से मिल सकते थे और एक दूसरे से

सलाह मशविरा कर सकते थे। उनके अपने गोदाम थे, अपने बाजार थे, वायरलेस से खबरें भेजने का अपना बंदोबस्त था—और उन लोगों के व्यवहार के कुछ बंधे हुए कायदे कानून थे। स्मगलरा और काले पैसे का धंधा करनेवालों के बीच सीधा सम्पर्क था।

स्मगलरो के खिलाफ जो मुहिम चलायी जा रही थी उसकी सभी तारीफ करत थे। लेकिन श्रीमती गांधी ने खुद ही सितम्बर 1974 में अपने एक मंत्री के० आर० गणेश को, जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, हटा दिया था। गणेश का कहना यह है कि स्पादातर चोटी के स्मगलरो की राजनीति में बड़े-बड़े लोगा तक पहुँच है, और उनमें से कुछ ने तो श्रीमती गांधी और उनके मुख्यमंत्रियों के साथ किसी तरह अपनी तसवीरें भी लिखवा ली थी। गणेश को याद है कि पूरक अनुदान की मजूरी पर बहस के दौरान, सोशलिस्ट सदस्य सदस्य मधुसिमये इस बात पर झट गये कि उ ह चोटी के स्मगलरा के नाम बताये जायें। शाम का वक्त था, काफी देर हो चुकी थी। मुश्किल से गिनती के कुछ सदस्य सदन में मौजूद थे। मैं बोल रहा था। इतने में प्रधानमंत्री सदन में आयी। मैंने अपना जबाब वही रोक दिया।

‘कुछ समय बाद वही सवाल सदन में फिर उठाया गया और एक बार फिर स्मगलरो के नाम बताने की लगातार भाग बी गयी। मैंने तीन नाम झटपट बता दिये—बखिया यूसुफ पटेल और हाजी मस्तान।

“बाद में प्रधानमंत्री के एक खास आदमी ने मुझे बताया कि मुझे इस तरह लोगों के नाम नहीं बताने चाहिए थे। आदाजा लगाइये कि स्मगलर कितने ताकतवर हो गये थे। कुछ दिन बाद, जब स्मगलरो के खिलाफ मुहिम पूरे जोरो पर थी मेरे पास प्रधानमंत्री का एक चार लाइन का खत आया जिसमें मेरा ध्यान अहमदाबाद के किसी आदमी की इस ‘शिकायत’ की तरफ दिलाया गया था कि मंत्री विदेशी सिगरेट साइटर इस्तेमाल करते हैं।

“जिस मुस्तदी के साथ प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के किसी आदमी की यह शिकायत मेरे पास तक पहुँचा दी थी उसके बारे में कम से कम इतना तो कहना ही पड़ेगा कि ऐसा आमतौर पर नहीं होता था। इशारा मैं ममक गया।

“इस बात से इंदिरा गांधी की एक और फटकार मुझे याद आ गयी जब उन्होंने कहा था, ‘हर आदमी यही साबित करना चाहता है कि दूध का धोया और देक्सूर है, बेईमान भकेली मैं हूँ। इस तरह पार्टी कैसे चल सकती है?’

उस वक्त श्रीमती गांधी की मजबूरियाँ कुछ भी रही हो लेकिन स्मगलरा के खिलाफ कारवाई अब बड़ी बेरहमी से की जा रही थी। डेरो वाला पैसा भी निकलवाया गया था और आर्थिक अपराधों के लिए कई व्यापारी भी मीसा में पकड़े गये थे। लेकिन काल पैसे का धंधा करनेवाले सभी लोग नहीं पकड़े गये थे खास तौर पर चोटी के लोग। और यह बात किससे छिपी थी कि किस तरह कई कांग्रेसिया आर्थिक अपराधियों को परोख पर छड़ाने की कोशिश करके और अपमरा की बदली कराके या उनका तरकीबें दिलाकर या व्यापारियों का ठेके दिलाकर डेरा दोलत बटारो थी।

वीम सूत्री कार्यक्रम की बुनियाद पर ग्रासक बग के बड़े-बड़े नेता खुनकर राजनीतिक लपफाजी भी कर सकते थे। वायदो का तो कोई अंत ही नहीं था—अपनी ज़रूरत की हर चीज हम खुद बना करेंगे गरीबा की हालत सुधरगी जमीन का नय सिर स बँटवारा हागा और न जान क्या क्या। हम बाता की बसम हर राजनीतिक पार्टी खाती थी लेकिन उनको पूरा करना दूसरी बात थी। मिसाल के लिए जमीन के बँटवारे के बारे में कानून तो न जान बब का बग चुवा था लेकिन बेरल को छोड़कर,

जहा पहले मानसवादी कम्युनिस्ट पार्टी की और फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मिली जुली सरकार के ज़माने में कुछ किया गया, किसी ने इस कानून को लागू करने की कोशिश भी नहीं की। दस साल के अंदर, 1964 से 1974 के बीच दरिद्रता की सीमा से भी नीचे ज़िंदगी बसर करनेवाले लोगों की संख्या 48 प्रतिशत से बढ़कर 66 प्रतिशत हो गयी थी। देहातो में अब भी ऊँच नीच की वही सीढ़ी बनी हुई थी—जमींदार और कमिया (काम करनेवाले), धनवानों और कगालों के बीच की खाई और चौड़ी हो गयी थी और दिन-ब-दिन चौड़ी होनी जा रही थी।

इस नये कार्यक्रम में कोई बात नयी नहीं थी। एक राज्य ने कहा, 'हमें पैसा बीजिये, सब कुछ ठीक हो जायेगा, खासी बातें करने से क्या फायदा।' और तमिलनाडु का जवाब उनके हमेशा के ढंग का ही था—यह राज्य बीस स्रोतों में से उनीस पहले ही पूरे कर चुका था। दूसरे राज्य भी इसी तरह के दावे करने में पीछे नहीं थे, लेकिन तमिलनाडु के लिए, जहाँ डी० एम० के० की सरकार थी, यह बात कान्ता श्रीमती गांधी की सरकार की नज़रों में न सिर्फ़ डिठाई की बल्कि उसमें भी बदतर बात थी।

यह कार्यक्रम तो लोगों को सालभर देने के लिए था, श्रीमती गांधी के हाथ में डंडा भी था। भारत सरकार ने 4 जुलाई को 26 राजनीतिक संगठनों को गर कानूनी ठहरा लिया, जिनमें से सिर्फ़ चार ही ऐसे थे जिनका कुछ असर था। ये चार संगठन थे हिंदू धर्म का फिर से बालबाना चाहनेवाली लड़ाकू संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (भार० एस० एस०), मुस्लिम धार्मिक संगठन जमाअत इस्लामिए हिंद, हिंदू कट्टर-पण्डितों का एक सम्प्रदाय आनन्द मार्ग और नक्सलवादी (चरम वामपंथी)। उन पर यह आरोप लगाया गया था कि "उनकी हरकतें भीतरी सुरक्षा, सार्वजनिक रक्षा और सार्वजनिक शांति बनाये रखने के रास्ते में बाधा हैं।" बाद में 6 अगस्त को अलग राज्य की मांग करनेवाले भीजो नेशनल फ्रंट को भी इन गर-कानूनी संगठनों की फेहरिस्त में जोड़ दिया गया।

गृहमंत्री ने कहा कि जिन पार्टियों को गर कानूनी ठहराया गया है उनमें से कुछ साम्प्रदायिक पार्टियाँ हैं। लेकिन कुछ ही साल पहले कानून मंत्रालय ने कहा था कि इस तरह की साम्प्रदायिकता की कोई कानूनी परिभाषा नहीं दी जा सकती। उस वक़्त यह सोचा गया था कि साम्प्रदायिकता के खिलाफ़ राजनीतिक लड़ाई लड़ना बेहतर होगा लेकिन ऐसा नगता था कि यह नीति बदल गयी थी। ऐसे लोगों के लिए जो आसानी से साम्प्रदायिकता के आरोप पर यकीन न करते, यह कहा गया कि इन पार्टियों का 'विदेशी ताकतों से सम्बंध है।

इन पार्टियों पर पान्दी लगा देने से सरकार की मनमानी गिरफ्तारियाँ करने का मौका मिल गया। जिन लोगों को भार० एम० एम० या जमाअत से कुछ लेना-देना नहीं था, या जो कई सालों में कोई काम नहीं कर रहे थे, उन्हें भी पकड़ लिया गया।

शेख़ अब्दुल्ला जिन्होंने भारत सरकार से एक समझौते के बाद जम्मू-कश्मीर में अपनी सरकार बनायी थी, इससेही लागू किये जाने के खिलाफ़ थे। मुख्यमंत्री की हेमियत से यह था तो यह कह देते थे कि जम्मू कश्मीर में इसे इसलिए लागू करना पड़ा कि यह राज्य भी भारत का हिस्सा है, या फिर वह यह सफाई देते थे कि सविधान में इससेही लागू करने की गुज़ाईश रखी गयी है।

मेरे साथ 30 सितम्बर को एक इटरगू के दौरान उन्होंने कहा था कि 'जम्मू-रिपब्लिक की फिर सही रास्ते पर लाने के लिए दोनों पक्षों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। लेकिन अगले में वह दिल्ली की 'एक आदमी की सरकार' को बहुत बुरा-

भला कहते थे। वह विपक्ष की भी आलोचना करते थे कि 'बिना किसी तैयारी के वह हृद से आगे निकल गया।

शेख साहब ने गैर-कानूनी सगठनों के नेताओं को गिरफ्तार तो करवाया लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें परोल पर रखा करवा दिया। ये गैर-कानूनी सगठन जो स्कूल बगल चलाते थे उन्हें भी बंद कर दिया गया।

शाम को निकलनेवाले दैनिक अखबार चाँदिए कश्मीर पर भी इमर्जेंसी के दौरान पाबंदी लगा दी गयी। संसद के दूसरी जगहों के मुकाबले कुछ नरमी बरती जाती थी, यहाँ तक कि कभी कभी केन्द्रीय सरकार के संसद को कुछ अखबारों की 'गलतियाँ' राज्य व अधिकारियों की बतानी पड़ती थी।

श्रीमती गांधी के कुछ करीबी लोगों ने शेख साहब पर दबाव डाला कि वह जयप्रकाश की निंदा करें लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। एक बार तो उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में इस बात का जिक्र भी किया लेकिन उनकी तबरी की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के संसद ने छपने ही नहीं दी।

श्रीमती गांधी आर० एस० एस० के मेम्बरो पर शक जता कर कहती थी, लेकिन उस वक़्त तक जो लोग पकड़े गये थे वे तो उनका एक बहुत ही छोटा हिस्सा थे। इस पाबंदी से कोई खास फायदा नहीं हुआ, ज्यादातर कार्यकर्ता अण्डरग्राउण्ड चले गए और उन्होंने जनता की इस उम्मीद का सहारा दिये रहने के लिए एक नए दिन तो इस सरकार का तरफा उलट्टेगा ही, थोड़ा-बहुत जितना भी बन पड़ा धिरो।

अण्डरग्राउण्ड सगठन बनाने में कुछ समय लगा। दो टोलीयाँ थी, एक सोशलिस्ट नता जाज फर्नांडीज की अगुवाई में और दूसरी जनसंघ के नानाजी देशमुख की अगुवाई में। दोनों के बीच थोड़ा बहुत तालमेल भी था लेकिन ज्यादा खोर थोड़ा-बहुत पर था। अपनी तरफ से इन दोनों ही ने उस ताकत के खिलाफ, जिसे 'भारतीय फासिस्टा और रूसिया का गठजोड़' कहा गया था, सत्यग्रह आन्दोलन छेड़ने के लिए हिदायतें जारी कीं। आठ पेज का एक साइक्लोस्टाइल अखबार निकाला गया जिस पर यह हिनायत लिखी रहती थी कि पश्चिम और दूसरी की वे अपने मतभेदों को भुलाकर नास्तिक विचारों के नेताओं से अपील की गयी थी कि वे अपने मतभेदों को भुलाकर 'भारत में फिर से जनतंत्र की स्थापना के संघर्ष के लिए एक हो जायें। इसमें विपक्ष या भी आगे चलकर चेतावनी दी गयी थी कि 'विचारधाराओं पर बहस या नेताओं के झगड़ों का यह समय नहीं है। हमारी एक ही मजल है और वह है फासिस्टों को हाराना और उस जनतंत्र को फिर से कायम करना जिसमें सभी को बुनियादी स्वतंत्रताएँ हासिल रहें और बर्द राजनीतिक सत्ताएँ एक साथ कायम कर सकें। इस अण्डरग्राउण्ड अखबार में रूस के साथ भारत के गहरे सम्बन्धों की बड़ी आलोचना की गयी थी 'रूसिया को जिहान सबम पटले भारत में फासिस्ट व्यवस्था का स्वागत किया था इस बात में भी गहरी दिलचस्पी है कि भारत एक बगल देगा बना रहे जिस नाम को श्रीमती गांधी बड़ी बरहमी और मुस्तदी के साथ पूरा कर रही हैं।'

अण्डरग्राउण्ड सगठन नए एक खुफिया रेडियो स्टेशन भी कायम करने का बचाव किया था और यह भी इतना निया गया था कि उसका ट्रान्स्मीटर 'यूरोप के किसी देश' में पड़ा हुआ है। 'बिना यह रेडियो स्टेशन कभी कायम नहीं हो सगा।

जार्ज फर्नांडीज ने खुफिया तौर पर बाँट गये एक पत्र में यह सुभाव दिया कि खुफिया साहित्य तयार करने बाँटा जाय बानाफूनों की मुनि' चलायी जाय, हृदयाने और 'बंद सगठित किये जायें सरकार के काम काज का ठण्ड कर दिया जायें और

पुलिस और फौज के लोगो के साथ मेल जोल बढ़ाया जाये। जार्ज फर्नांडोज ने कहा कि यह 'सविधान को भयवित्र करने, फासिस्ट डिक्टेटोरशिप कायम करने, देश में कानून का शासन खत्म करने में हाथ बटाना' नहीं चाहते।

नानाजी देगमुख ने अन्दर ही अन्दर विरोध करते रहने की भावना को बढ़ावा देने के लिए पच्चे बाटन के लिए छाटी छोटी टोलियाँ बनाने और नारे लगाने की मुहिम शुरू करने की पैरवी की।

प्रण्डरप्राउण्ड संगठना की भारवाइयाँ बहुत सीमित थीं फिर भी पुलिस को सगातार चौकस रहना पड़ता था और श्रीमती गांधी को चिन्ता लगी रहती थी। इन हलचल में तालमेल बिठाने में जयप्रकाश के मन्त्रेदारी राधाकृष्णन ने हाथ बटाया। जो भलग भलग संगठन सत्याग्रह शुरू करना चाहते थे उन्हें एक लड़ी में पिरोने के लिए उन्होंने कई राज्या का दौरा किया। लेकिन इससे पहले कि बाहर कोई संगठन कायम हो पाता यह गिरफ्तार कर लिये गये। सबसे बड़ा धक्का दक्षिणी दिल्ली की एक बस्ती पर 'भयानक छाप के दौरान नानाजी की गिरफ्तारी से पहुँचा। उनकी मुहिम का नाम 'भौंपरेदान टक घोवर' (सत्ता पर अधिकार) था, लेकिन उनके बाद जब संगठन काग्रेंस के नेता रवीन्द्र वर्मा ने मोर्चा संभाला तो उन्होंने उसका नाम 'भ्राक्ताव' (सूरज) रखा।

इस वकन तक 60 000 लोग गिरफ्तार किये जा चुके थे। गिरफ्तार किये जाने वाला म जयपुर की राजमाता गायत्री देवी और ग्वालियर की राजमाता भी थी। दोनों को दिल्ली के तिहाड़ जेल में जिस बाड़ में मैं था उसी से मिले हुए बाड़ में कैद कर दिया गया। गायत्री देवी के खिलाफ जो इल्जाम था वह विदेशी मुद्रा का झूठा हिसाब देने के बारे में था। दोनों राजमाताओं जनाने बाड़ में रडिया और बार उचक्की औरतो के साथ रगरी गयी थी, जिनके बारे में गायत्री देवी ने बाद में कहा कि 'हर तरफ वही दिखायी देती थी, बिल्कुल ऐसा लगता था कि बीच बाजार में लड़ाका औरतो के बीच रह रहे हैं।' गायत्री देवी ने कहा 'फास से मेरे एक दोस्त ने लिखकर पूछा कि मैं तोहफे में क्या चीज लेना चाहूँगी। जिसके जवाब में मैंने कहा कि कान म ठूसन का जो मोम वहाँ मिलता है वह थोड़ा सा भेज दो।'।

प्रकालिया न पजाब में 9 जुलाई से एक मोर्चा लगाया था जिसकी शुरुआत भमृतसर में पांच प्रकालिया की गिरफ्तारी सह हुई थी। इमर्जेंसी के ऐलान और जनतन्त्र का गला घोटने के खिलाफ यह मोर्चा इमर्जेंसी के अखिर तक चलता रहा। लग-भग 45 000 मिक्ल खुशी खुशी जेल चले गये। प्रकालियो के चोटो के नेता, जिनमें प्रकाशसिंह बादल और गुरचरनसिंह तोहरा भी थे, भीसा में नजरबंद कर दिये गये। श्रीमती गांधी ने, जैसा कि उनका हमेशा का दस्तूर था, इस बार भी यही सोचा कि यह सारा आंदोलन सिर्फ 'बदइन्तजामी' की वजह से जोर पकड़ रहा है। इसकी वजह से वह पजाब के मुख्यमंत्री जैलसिंह से बहुत नाराज थी।

दूसरी जगहों पर भी लोगो को शुरू-शुरू में धक्का लगा था और जो कुछ हो रहा था उस पर उन्हें किसी तरह यकीन नहीं आ रहा था लेकिन अब लोग धीरे धीरे खुलने लगे थे। ज्यादातर अखबार 'सही रास्ते पर आते जा रहे थे। लेकिन साथ ही विरोध की हलचल भी दिखायी देती थी। मुझे 26 जुलाई को गिरफ्तार किया गया।

- 1 गायत्री देवी ने श्रीमती गांधी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अब मुझे राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं बीस-सूखी वायव्य की मानती हूँ, जिसके बावजूद परोल पर रिहा कर दिया गया।

गैर-सरकारी सदस्यों के सवाल, ध्यानावपण प्रस्ताव या उनकी तरफ से सुझाये गये किमी घोर काम के लिए वक्त न दिया जाये।

विपक्ष के सदस्यों ने—उनमे से ज्यादातर तो नजरबंद थे—इस प्रस्ताव की घज्जियाँ उठा दी। माकमवादी सदस्य मोमनाथ चटर्जी ने कहा कि इस तरह सारे-के-सार नियमों को एक साथ उठाकर ताक पर नहीं रखा जा सकता। डी० एम० के० के सदस्य एरा सेजियान ने कहा कि सदन की इम बात का अधिकार तो है कि वह अपने काम काज की व्यवस्था जिस तरह की चाह बना ल लेकिन फिर भी उस कुछ कायदे-कानूनों को तो मानना ही पड़ेगा। मोहन धारिया ने कहा कि सदन का इस तरह काम करने का मौका दिया जाना चाहिए कि उसने काम में कुछ फायदा हो और कायदे कानून भी ऐसे होने चाहिए कि काम में रूकावट पड़ने के बजाय सुविधा हो। एक निदर्शनीय सदस्य रामोमा पी० मिक्वेरा ने कहा कि यह बात समझ में नहीं आयी कि गैर सरकारी सदस्यों की तरफ से पेश किये गये विधेयकों पर विचार करने से क्या इकार कर दिया गया है क्योंकि इन लोगों ने तो सदन के ज़रूरी काम में कभी कोई बाधा नहीं डाली। उन्होंने कहा कि सदन की बैठक बनाना बनाने के लिए नहीं बल्कि देश में जो हालात हैं उन पर बहस करने के लिए हो रही है इमजैसी लागू होने के बाद विपक्ष की हर पार्टी के नेता गिरफ्तार किये गये हैं। सदन के कितने ही सदस्य न सिर्फ गिरफ्तार कर लिये गये थे बल्कि उन्हें धार-धार एक जेल से दूसरे जेल भेजा जा रहा था। सरकार का माथ दने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य सदस्य इन्द्रजीत गुप्ता ने भी कहा कि सरकार का प्रस्ताव तो बस एक खानापूरी है क्योंकि आदेश तो पहले ही जारी किये जा चुके हैं।

संसदीय मामलात के मंत्री के० रघुरमैया ने इसके जवाब में यह दलील दी कि सवाल-जवाब का घटा खत्म कर देने का मतलब किसी भी तरह सदन का अपमान करना नहीं है। यह तो एक तरह की ऐसी पाबंदी है जो सदन खुद अपने ऊपर लगा रहा है।

विपक्ष के विरोध के बावजूद यह प्रस्ताव लौरसभा में 301 के खिलाफ 76 वोटों में और राज्यसभा में 147 के खिलाफ 32 वोटों से पास हो गया। इसके बाद दोनों सदनों में इमजैसी की घोषणा पर सदन की मजूरी लाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया।

श्रीमती गांधी ने जगजीवनराम से यह प्रस्ताव पेश करने को कहा। उनके मन में जो भी सीचालानी चल रही हो पर उनके भाषण में उसकी कोई झलक दिखायी नहीं दी। उन्होंने कहा कि 1967 के बाद में कुछ राजनीतिक पार्टियाँ सरकार की सावक को मिराने के लिए और असंतोष की हालत पैदा करने के लिए लगातार हमले कर रही थी जो जनता के लिए एक खतरा बनत जा रहे थे। 1969 का साल हमारे देश के इतिहास में एक यादगार का साल था। उस साल कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि पूरे देश में तोड़ फोड़ मचाने वाली गतिविधियों के खिलाफ सघन करने के बारे में अदरुनी दुबिधा को खत्म कर देने का फैसला कर लिया। 1971 के आम चुनाव के बाद विपक्ष ने चार पार्टियों का संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश की और उसने बाद कई राज्यों में, खास तौर पर गुजरात और बिहार में लूट भाग और आग लगाने की बहुत सी खबरें आयी। विधानसभाओं के लिए वाक्यावदा चुन गये सदस्यों को उनका राजनीतिक काम काज करने से रोकने के लिए सघन समितियाँ बनायी गयीं। सरकार काम काज ठप्प करके उस न्दोका देने पर मजबूर करने के लिए एक और कोशिश रेलवे हड़ताल के जरिये की गयी। देश की ऐसी शोचनीय और असाधारण स्थिति को देखते हुए इमजैसी का

गैर-सरकारी सदस्यों के सवाल, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों या उनकी तरफ से मुभाये गये किसी घोर काम के लिए वनत न दिया जाये।

विपक्ष के सदस्यों ने—उनमें से ज्यादातर तो नज़रबंद थे—इस प्रस्ताव की पंजियाँ उठा दी। माकमवादी सदस्य मोमनाथ चटर्जी ने कहा कि इस तरह सारे-के-सार नियमों को एक साथ उठाकर ताक पर नहीं रखा जा सकता। डी० एम० के० के सदस्य एरा सेजियान ने कहा कि सदन को इस बात का अधिकार तो है कि वह अपने काम काज की व्यवस्था जिस तरह की चाह बना ल लेकिन फिर भी उसे कुछ कायदे-कानूनों का तो मानना ही पड़ेगा। मोहन धारिया ने कहा कि सदन को इस तरह काम करने का मौका दिया जाना चाहिए कि उसका काम में कुछ फायदा हो और कायदे कानून भी ऐसे होने चाहिए कि काम में रुकावट पड़ने के बजाय सुविधा हो। एक निदलीय सदस्य राधोमो पी० भिक्वेरा ने कहा कि यह बात समझ में नहीं आयी कि गैर सरकारी सदस्यों की तरफ से पक्ष किये गये विधेयकों पर विचार करने से क्या इकार कर दिया गया है क्योंकि इन लोगों ने तो सदन के जरूरी काम में कभी कोई बाधा नहीं डाली। उन्होंने कहा कि सदन की बैठक कानून बनाने के लिए नहीं बल्कि देश में जो हालात हैं उन पर ग़ौर करने के लिए हो रही है। इमर्जेंसी लागू होने के बाद विपक्ष की हर पार्टी के नेता गिरफ्तार किये गये हैं। सदन के कितने ही सदस्य न सिर्फ गिरफ्तार कर लिये गये थे बल्कि उन्हें बार-बार एक जेल में दूसरे जेल भेजा जा रहा था। सरकार का माप देने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य मदस्य इन्द्रजीत गुप्ता ने भी कहा कि सरकार का प्रस्ताव तो बस एक खानापूरी है क्योंकि आदेश तो पहले ही जारी किये जा चुके हैं।

संसदीय मामलों के मंत्री के० रघुरमया ने इसके जवाब में यह दलील दी कि सवाल-जवाब का घंटा खत्म कर देने का मतलब किसी भी तरह सदन का अपमान करना नहीं है। यह तो एक तरह की ऐसी पाव-दी है जो सदन खुद अपने ऊपर लगा रहा है।

विपक्ष के विरोध के बावजूद यह प्रस्ताव लोकसभा में 301 के खिलाफ 76 वोटों से और राज्यसभा में 147 के खिलाफ 32 वोटों में पास हो गया। इसके बाद दोनों सभों में इमर्जेंसी की घोषणा पर सदन की मजूरी लेने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया।

श्रीमती गांधी ने जगजीवनराम से यह प्रस्ताव पेश करने को कहा। उनके मन में जो भी खीचातानी चल रही हो पर उनके भाषण में उसकी कोई झलक दिवायी नहीं दी। उन्होंने कहा कि 1967 के बाद से कुछ राजनीतिक पार्टियाँ सरकार की ताक को गिराने के लिए और असंतोष की हालात पैदा करने के लिए लगातार हमले कर रही थी, जो जात-धर्म के लिए एक खतरा बनत जा रहे थे। 1969 का साल हमारे देश के इतिहास में एक यादगार का साल था। उस साल कांग्रेस नहीं बल्कि पूरे देश में तांड फोड़ मचाने वाली गतिविधियों के खिलाफ सघट्ट करने के बारे में अदरूनी दुविधा को खत्म कर दब के पसना कर लिया। 1971 के ग्राम चुनाव के बाद विपक्ष ने चार पार्टियों का संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिश की और उसने बाद कई राज्यों में, खास तौर पर गुजरात और बिहार में लूट मार और आग लगाने की बहुत मो खबरें आयी। विधानसभाओं के लिए बाकायदा चुन गये सदस्यों को उनका राजनीतिक काम काज करने से रोकने के लिए सघट्ट समितियाँ बनायी गयी। सरकार काम काज ठप्प करके उसे इस्तीफा देने पर मजबूर करने के लिए एक और कोशिश करने के लिए हड़ताल के जरिये की गयी। देश की ऐसी शोचनीय और असाधारण स्थिति को देखते हुए इमर्जेंसी का

ऐलान करना जरूरी हो गया।

कांग्रेसी संसद सदस्यों ने अपने भाषणा में लगभग यही सारी बातें कही। विपक्ष के नेताओं ने भी कुछ भाषण किये। माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ए० के० गोपालन ने कहा

अचानक यह घोषणा इसलिए नहीं की गयी कि भीतरी सुरक्षा के लिए सचमुच कोई खतरा पैदा हो गया था, बल्कि इलाहावाद हाईकोर्ट के फैसले की वजह से और गुजरात के चुनावों में कांग्रेस की हार की वजह से की गयी। मेरी पार्टी ने जो यह चेतावनी दी थी कि पिछले तीन साल से देश एक पार्टी की नादिरशाही डिक्टेटोरशिप की तरफ बढ़ रहा है, वह अचानक इस नयी इमर्जेंसी के ऐलान से सही साबित हो गयी है। इससे संसदीय जनतंत्र को हटा कर एक पार्टी की डिक्टेटोरशिप कायम कर दी गयी है जिसमें सारी ताकत एक ही नतीजे के हाथ में आ गयी है। स्थिति में अचानक मोड़ और जनतंत्र से डिक्टेटोरशिप में यह अचानक परिवर्तन सत्ताशासक पार्टी के ही हाथ में रखने के मकसद से सनट से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए लाया गया है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और धर्मद माग की तरफ जिन्हें अब गैर-कानूनी ठहरा दिया गया था, सरकार का रवैया उसकी सुविधा के हिसाब से समय समय पर बदलता रहा है। 1965 में भारत पाक लड़ाई के दौरान उस समय के प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने शहर की पहरेदारी के लिए सारी दिल्ली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सौंप दी थी।

इमर्जेंसी लागू होने के बाद सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनसे पता चलता है कि हमने का स्वयं जनता के खिलाफ है। जनता को जो जनतांत्रिक अधिकार मिले हुए थे उनका नामोनिशान मिटा दिया गया है। कानून की मजूर में भी अब सभी लोग बराबर नहीं रह गये हैं।

माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हजारों कार्यकर्त्ताओं की अघायुध गिरफ्तारी से अब यह घोषणा की टूटी भी बिल्कुल हट गयी है कि इमर्जेंसी को सिर्फ दक्षिणपंथी प्रतिस्पर्धावादी पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जनता के पीछे पुलिस छोड़ दी गयी है। करल में जेलों के अंदर भी और बाहर भी कितने ही राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्त्ताओं का बुरी तरह पीटा गया है। जनता में दहशत फैलाने की कोशिशों की पूरी तरह निन्दा करना जरूरी है।

जो कोई भी धनवान स्वार्थी वर्गों के खिलाफ या जनतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने की हिम्मत करता है उसके सर पर गिरफ्तारी का खतरा मँडराता रहता है। यह गिरफ्तारियाँ सिर्फ ट्रेड यूनियन और जनवादी आन्दोलन के कुचलने के लिए की जा रही हैं।

जयप्रकाश नारायण की घण्टाई में जो आंदोलन चल रहा है उसने चुनावों में ताकत प्राप्त करने की प्रधानमंत्री की चुनौती स्वीकार कर ली थी। लेकिन गुजरात के चुनावों का नतीजा देखने के बाद प्रधानमंत्री के ही हाथ पाँव फूल गये। सभी राज्यों में गुटबाजी की लड़ाइयों का जो बाजार मग्न था वह बहुत-बहुत अब बे-द्रव्य भी पहुँच गया है और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि इस्लामवाद वाले फ़ैशन और मुस्लिम वोट के आदेश के बाद खुद कांग्रेसी संसदीय दल में इन्दिरा गांधी के नेतृत्व को जबरदस्त चुनौती दी गयी। सत्ता पर कांग्रेस की इज्जतदारी के लिए और पार्टी में तथा सरकार में इन्दिरा

गांधी की स्थिति के लिए जो खतरा पैदा हो गया था, वही जनतंत्र को कुचल देन की फोरी बजह थी।

इंदिरा-नाप्रेस से निकाल दिये गये मोहन धारिया ने कहा

26 जून 1975 का दिन, जिस दिन इमर्जेंसी का ऐलान किया गया था, जिस दिन मेरे साथी, कितने ही राजनीतिक कार्यकर्ता और नेताओं को बड़ी बबरता से जेल के सीखचो के पीछे बंद कर दिया गया था, जिस दिन प्रखबारों की आजादी और नागरिक स्वतंत्रताओं को नौकरशाहों के हवाले कर दिया गया था, भारतीय जनतंत्र के लिए और हमारे देश के इतिहास का सबसे मनहूस दिन माना जायेगा।

सबसे पहले गुरु में ही मैं इस भयानक कारवाई की निंदा करना चाहता हूँ। मुझे इसमें जरा भी शक नहीं है कि इसकी सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और उनके कुछ साथियों पर है। मैं पूरे मंत्रिमंडल को दोषी इसलिए नहीं ठहरा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैबिनेट को भी इसकी खबर कारवाई शुरू कर दिये जाने के बाद दी गयी थी।

बाकायदा यह प्रचार किया जा रहा है कि विपक्ष की पार्टियों की बजह से, दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी ताकतों की बजह से, उपप्रधियों की बजह से आर्थिक कार्यक्रम पूरा नहीं किया जा सका। क्या यह बात सच है? आर्थिक कार्यक्रम को पूरा किया जा सकता था, 1971 के चुनाव के घसत और 1972 में भी हमारे मैनिकेस्टो में जनता से जो वायदे किये गये थे उन्हें पूरा किया जा सकता था।

जनता का इतना भारी समयन पाने के बाद हमें किसने इन्हें पूरा करने से रोका था? हमारे ही पाँव सड़खड़ा गये और हमारे देश में आज जो हालत है वह हमारी ही पदा की हुई है।

जहाँ तक आर्थिक कार्यक्रमों का सवाल है, यह कहा जा रहा है कि वे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हैं। शासन करनेवाली पार्टी के कार्यक्रम, सरकार के कार्यक्रम—यह बात तो मेरी समझ में आती है। लेकिन आखिर किसी आदमी को इस तरह आसमान पर चढ़ा देने का क्या मतलब है? यह भी हमारे देश में डिक्टेटरशिप कायम करने का तरीका है। हमें इस बात का नहीं भूलना चाहिये।

आज हमारे देश की जो हालत है वह बिल्कुल साफ है। शक्ति विपक्ष की पार्टियाँ ज्यादा गठे हुए ढग से एक-दूसरे के निकट आ गयी हैं अब वे सिर्फ पुराना गठजोड़ नहीं रह गयी हैं इसलिए दासक पार्टी का भविष्य अचानक खतरे में पड़ गया है। गुजरात के चुनावों ने यह बात अच्छी तरह साबित कर दी है कि पस ताकत और निजी साख सभा का पूरा जोर लगाने के बाद भी श्रीमती गांधी के लिए अब यह मुमकिन नहीं होगा कि वह जनतांत्रिक चुनावों के जरिये सत्ता हासिल कर सकें या उसे अपने कब्जे में रख सकें। जनता को यह यकीन दिलाने के लिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बना रहना बिल्कुल जरूरी है बड़ी बड़ी मीटिंगें और रैलियाँ जुटाकर वफादारी की शानदार नुमाइशों की गयीं सुप्रीम कोर्ट के फसले की तनिक भी परवाह किये बिना खुले शब्दों में यह एलान किया गया भारत इंदिरा है, और इंदिरा ही भारत है। (India is Indira, and Indira is India)

डी० एम० के० के एरा सेजियान ने कहा

मैं गृहार नहीं हूँ, मैं इसी देश का वासी हूँ। पिछले तरह-बोदह साल से मैं आप ही लोग में स एव रहा हूँ। इस पक्ष के एक मन्बर ने रूप में अपनी सुच्छ हैसियत के मुताबिक मैंने भी सदन की मदद करने की बोणित की है और अपने ससदीय जनतंत्र के काम में मदद दी है। मुमकिन है कि भवसर ऐसा हुआ हो कि हमारी राय बही न रही हो जो आपकी थी लेकिन एक बात के बार में सभी की राय एक थी कि इस दक्ष में और सदन में जनतंत्र का काम चलता रहना चाहिये। उस मातावरण को ग्रब क्या हो गया है? ऐसा क्या हो गया है कि हम लोग एक दूसरे के सामन मोर्चा जमाये हुए हैं, एक-दूसरे से टक्कर ले रहे हैं कि आप हम गृहार कह रहे हैं और हम उन लोगो के पलडे में रख रहे हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं? अध्यक्ष महादय, दो वग बन गये हैं। जो लोग इमजेंसी के पक्ष में हैं उन्हें तो आर्थिक कार्यक्रम का समथन करनेवालो के पलडे में रखा जाता है, जो इमजेंसी के पक्ष में नहीं हैं उन्हें आर्थिक कार्यक्रमो के विरोधियों के पलडे में रखा जाता है। मैं कार्यक्रम के बीस सूत्रो का समथन करता हूँ और अगर आप चाहें तो मैं उनमें एक-दो और जोड़ भी सकता हूँ।

जब बको का कारोबार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था, जब रजवाडो का गुजारा बन्द कर दिया गया था तब हमने पूरी तरह उसका साथ दिया था। उस वक्त आपका बहुमत नहीं था—सगभग 532 मन्बरो में स आपके बल 240 थे—फिर भी हमने आपका तहना नहीं उलटा। हमने इन्दिरा गांधी को गिरा देने की बात सोची भी नहीं। हमने पूरी तरह उनका साथ दिया क्योंकि हम विश्वास करते थे कि बको का कारोबार सरकार के हाथों में ले लिये जाने का कार्यक्रम ठीक है। रजवाडो का गुजारा बन्द कर दिया जाने का कार्यक्रम ठीक है। इस तरह, जब भी कोई अच्छा कार्यक्रम रखा गया, हमने उसका साथ दिया। फिर भी मैं बता दू कि 1971 में जब मौसा का कानून सदन में पेश किया गया तो हमने उसका विरोध किया हालांकि हमारा दोस्ताना एका था।

हो सकता है कि जयप्रकाश ने फौज को भडकाया हो, मुमकिन है कि उन्होंने पुलिस को उबसाया हो और हो सकता है कि उन्होंने जो कुछ कहा उससे देश को नुकसान पहुँचने का खतरा हो। इस बात में मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ कि इस तरह के उबसावा की कड़ी सजा दी जानी चाहिये। आप उन्हें म्दालत के कठपुटे में खड़ा करके यह क्यों नहीं कहते कि उन्होंने राजद्रोह का सबसे गम्भीर अपराध किया है? सारी दुनिया के सामन उनको बेनकाब कीजिये, सबूत पेश कीजिये, यह बात सोलह आने साबित कर दीजिये कि उन्होंने एक भयानक अपराध किया है। वह कितने ही बड़े क्यों न हो अब तक उन्होंने कितने ही खानदार काम किये हैं और वह कितने ही लोकप्रिय क्यों न हो अगर उन्होंने देश के खिलाफ देश की जनता के खिलाफ कुछ किया है तो उन्हें म्दालत के सामने पेश कीजिये उनका अपराध साबित कीजिये और जो भी सजा हो सके उन्हें दीजिये। आज दिन भर हम सब लोग वस यही बात कहते रहे हैं। अगर कुछ सगठन ऐसे हैं जो इस देश की जनता के हितों के खिलाफ काम करते रहे हैं तो उनके खिलाफ बड़ी कारवाई कीजिये, बड़ी से-बड़ी कारवाई कीजिये, लेकिन कानूनी ढंग से, जनतांत्रिक ढंग से। आजादी

हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। अगर वह आपसे छिन जाय, तो उसे दुबारा हासिल करना और भी मुश्किल होता है। डबे के जोर से काम लना कुछ बातों के लिए तो सहूलियत पदा कर सकता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यह मजिल तक पहुँचन का छोटा रास्ता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लाग यहा तक महसूस करते हैं कि पार्लियामेंट की जहरत हो क्या है। जा फंसला एक आदमी कर सकता है उसके लिए क्या जरूरी है कि 500 आदमी यहा आयें? यही हिटलर भी सोचता था। यही कोशिश मुसोलिनी ने भी की थी। लेकिन उनके तरीके चल नहीं पाय क्योकि जात त्र में अगर सरकार कोई गलती करे तो उसकी रोकथाम की जा सकती है, लेकिन अगर डिक्टेटरशिप में सरकार कोई गलती करे तो उसकी कोई रोकथाम नहीं की जा सकती, क्योकि जसा कि कहा जाता है, ससदीय जनतंत्र अब भी सरकार चलाने का सबसे कम असतोषजनक तरीका है।

इसलिए दूसरे पक्ष से मेरी अपील यह है मुमकिन है मैं ऐसी अपील आपसे दुबारा न कर सकूँ। हो सकता है कि हममे से सभी को ऐसे ही अवसर फिर न मिल सकें—इस समय देश में जो वातावरण है उसमें शायद वह न मिले। पहले तो हम लोग जो कुछ यहाँ कहते थे वह लिख लिया जाता था और बाहर लोग उस कम से कम पढ़ तो सकते थे। लेकिन आज मैं जो कुछ यहा कह रहा हूँ वह यहाँ के मेरे मित्रों के लिए ही है। भत के लिए या बुरे के लिए भलाई के लिए या बुराई के लिए हम इस सदन के सदस्य रहे हैं। जनता ने हमें देश में ससदीय जनतंत्र चलाने के लिए चुना है। भल ही हम बहुत थोड़े हैं, आपका बहुमत है। मैं बहुमत के फसले के आगे सर झुकाता हूँ लेकिन अगर वह सभी कायदे कानूनों को पूरा करने के बाद, अच्छी तरह बहस करने के बाद, दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर लिया गया हो। हो सकता है कि सौ बार में से नब्बे बार हम गलत रास्त पर हों लेकिन कम-से कम उन दस मौकों का तो आप फायदा उठाइये जब हमन दंग की भलाई की कोई बात कही हो।

बीसवीं शताब्दी के एक सबसे अच्छे संविधान का, एक सबसे उदार संविधान का, वाइमार रिपब्लिक (जर्मनी) के संविधान का जो हाल हुआ उसके बाद अब जनतंत्र सिर्फ संविधान का, सिर्फ कानून का सबान नहीं रह गया है। हिटलर ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो संविधान के खिलाफ रहा हो। संविधान में जो कायदे-कानून बताये गये थे उन्हें भी उसने नहीं तोड़ा। लेकिन उसी संविधान का सहारा लेकर वहा डिक्टेटरशिप उभर आयी। यह बात कहकर मैं प्रधानमंत्री को और हिटलर को एक ही पलड़े में नहीं रखना चाहता।

इसलिए मेरी अपील यह है अगर ससदीय जनतंत्र में आपका मतलब उसकी बाहरी शक्ल सूरत से, संविधान में बताये गये कायदे कानूना से है, तो उसमें इस देश में जनतंत्र नहीं चल सकता। सिर्फ बाहरी शक्ल सूरत में काम नहीं चलने का, यह भी दखना होगा उसने प्रन्दर प्रसन्नियत क्या है उसकी भावना क्या है। विपक्ष का सिर्फ बदलाव कर लेने की नहीं बल्कि उसके लिए सम्मान की भावना हानी चाहिए, विपक्ष की राय को गवमुच महत्व देने की भावना हानी चाहिए। जब तक हमारे दंग में इस बात का मौका नहीं दिया जायेगा कि बिना किसी ढर के सरकार की आलाचना

की जा सके, बिना हिंसा के सरकार को बदला जा सके—यही जनतंत्र का असली निचोड़ है—तब तक उसकी बाहरी शक्ल सूरत भले ही उनी रहे लेकिन उसका असली सार नहीं मिल सकता। अगर आप समझते हैं कि मैंने हिंसा की कोई कारवाही की है तो बेशक मुझे अदालत के सामने ले जाकर सजा कर दीजिये और मुझे बड़ी-स बड़ी सजा दीजिये।

हमें इस बात पर गव था कि हमारा जनतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा जनतंत्र है। जिन दिना आजादी की नडाई चल रही थी, जब हम लोग कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ते थे, तब हम भी गांधीजी की तरफ से लड़े थे, अंग्रेजों के जमाने में पुलिस ने जो लाठिया चलायी थी उनके निशान अब भी बाकी हैं। मैंने उस जमाने में जो बहुत-सी बातें देखी थी उनमें महात्मा गांधी की लिखी हुई भी एक बात थी। उसमें कहा गया था 'सच्चा स्वराज्य इस तरह नहीं आयेगा कि कुछ लोगों के हाथों में सत्ता आ जाये, बल्कि वह सब आयेगा जब सभी लोग इस लायक हो जायें कि अगर उस सत्ता को बजा तरीके से इस्तमाल किया जाये तो वे उसका इस्तेमाल मुकाबला कर सकें। मतलब यह कि स्वराज्य तभी हानिल होगा जब आम जनता को शिक्षा देकर उनमें यह भरोसा पैदा किया जाये कि वह सत्ता का सही रास्ते पर चला सकती है उसे अपने कानून में रख सकती है। "

हम सभी लोग इसी स्वराज्य के लिए लड़ें थे। हम सभी ने मुसीबतें भेलीं। लेकिन उस दिन की याद कीजिये जब मानव इतिहास के सबसे बहुमूल्य जीवन को, उस आदमी को जिसने इस देश में हमें आजादी का विचार दिया था किसी सिरफिरे ने गोली मारकर खत्म कर दिया। उस सबसे गम्भीर संकट की घड़ी में भी जवाहरलाल नेहरू ने बोलन की आजादी नहीं छीनी थी। जिस आदमी ने पागला की तरह यह मान लिया था कि उसने महात्मा की बजर हत्या की थी उस पर भी खुली अदालत में मुकदमा चलाया गया था।

इसलिए राष्ट्रपिता के नाम पर, उस आजादी के नाम पर जिसके लिए वह लड़े और मुसीबतें भेली वही कानून हर मामले में लागू किया जाना चाहिए। मैं एक एक से अपील करता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो खुशी से आगे बढ़ते रहिये। कानून में जो समझौता है वह गलत है। जब आपने कोई सच्ची गिरफ्तार कर लिए जायें और अगर आपके मन में जरा भी शक हो जैसा कि मेरे मन में है, किसी तरह की आशंका हो जैसी कि मेरे मन में है तो जाकर उनसे पूछिये कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है उन्हें तेल में क्या डाल दिया गया है और उन्होंने स्मगलर के अपराध से भी बड़ा कौन सा अपराध किया है। बहुत से स्मगलर अभी तक आजात घूम रहे हैं। उनमें से बहुत से अभी तक समाज विरोधी हरकतें कर रहे हैं लेकिन फिर भी आजात घूम रहे हैं। कानून का हाथ उन तक नहीं पहुँचा है। लेकिन दाम्नी में आपस एक बार फिर हाथ जोड़कर यही कहेंगे, बार बार यही कहेंगे कि याद रखिये कि अगर किसी आदमी से उसकी आजादी छीन ली जाती है तो वह जिन दूर नहीं है जब हममें से हर आदमी की आजादी छिन जायगी।

महमदाबाद के ससद सदस्य पी० जी० भावलकर ने कहा

मेरी भावना और मेरा आरोप यह है कि यह इमर्जेंसी झूठी है, कि सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है, कि यह सारा खतरा कोरी कल्पना है, और यह संविधान में दिये गये अधिकारों का सरासर बेजा इस्तेमाल है और यह कि यह संविधान से हासिल किये गये अधिकारों के साथ धोखेबाजी है और इसलिए इस सम्मानित सदन को उसे मजबूरी नहीं देनी चाहिये।

संसद का सबसे पहला काम हर आदमी की आजादी का बरकरार रखना है और वह अपने इस काम को इस तरह पूरा करती है या उसे पूरा करना चाहिए कि वह सरनी में इस बात की मांग करे कि जिस सरकार या जिस कैबिनेट को वह बनाती है वह काफी बजहें बताकर यह साबित करे कि जब तक उसे और ज्यादा कानूनी अधिकार नहीं दिये जायेंगे तब तक वह अपना कर्तव्य पूरे नहीं कर सकती। लेकिन मंत्री महोदय ने वन प्रस्ताव पेश करते समय, और प्रधानमंत्री ने आज बहस के दौरान बीच में बोलते हुए हम इस बात की काफी बजहें नहीं बतायी हैं कि उन्हें इतने बहुत से गरमामूली अधिकारों की जरूरत क्या है जिनके खिलाफ कोई दाद-फरियाद भी नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि संविधान की धारा 352 में राष्ट्रपति को जो अधिकार दिया गया है उस अधिकार के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई हैं और उस अधिकार को तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब उस धारा में बतायी गयी परिस्थितियाँ मौजूद हों।

मैं खास तौर पर यह सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ 24 जून को तीसरे पहर और 25 जून की रात के बीच ऐसी कौन-सी बात हुई कि हमारी सरकार को संविधान में इमर्जेंसी का एलान करने की जो गुंजाइश रखी गयी है उसका महाराज नेने को ज़रूरत पड़ गयी। यह भीतरी इमर्जेंसी है या एक आदमी की इमर्जेंसी है ? यह देश की इमर्जेंसी है या शासक पार्टी की इमर्जेंसी है ? यह कानून के शासन के खाली की शुरुआत है। उसी दिन से संविधान की बड़ी चालाकी से और लगातार संविधान की हर उस चीज़ का नष्ट कर देने के लिए इस्तेमाल किया गया है जिसकी हम बद्र कर्त थे, खास तौर पर उसकी मूल अधिकारों की प्रस्तावना का।

सचमुच मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि भारत का पहला गणतन्त्र मर चुका है। संविधान की आड़ लेकर डिक्टेटोरियम कायम कर ली गयी है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे पनपते हुए देश और जनतन्त्र के लिए 26 जून का दिन मात्रम अभागा और सबसे मनहूस दिन है।

अध्यक्ष महोदय, इमर्जेंसी लागू होने के बाद मैं जा सताईम या कितने दिन बिताने हैं, उन्हें न सिर्फ व्यक्ति की आजादी पर अक्रूर गगन और उसमें बतर्क्यात करने के लिए बल्कि उस जड़ से ही गरम कर देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। उन्हें पमान पर गिरफ्तारियाँ दूँ द—नताप्रा की मन्त्र के मन्त्रियों की विधायिका की, नाना हो तरफ के हमारे गाविया की गिरफ्तारियाँ दूँ है सभी पाटिया न योगा की गिरफ्तारियाँ दूँ हैं और इनका हो नहीं शिणपथी प्रतिनिधायिका के गिरफ्तार करने की आड़ में बिनन की वामपथिया, गागनिस्था और दूसरे प्रगतिशील नागा को जेल में डाल दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना हूँ कि इनमें से कौन-से नागों का अपराध क्या था ? यही न कि सच्चाई का उन्होंने जिस तरह दया उभरी तरह बयान

कर दिया। इसलिए मुझे खुशी है कि इन लोगों को जेल भेज दिया गया है। हम सब लोग जेल चने जायें।

स्वतंत्र भारत के गामन हम मभी का जिस क्षमनाक तरीके से अपमान कर रहे हैं उस तरह से तो कभी अंग्रेजा ने भी भारत का नहीं किया था। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस सदन पर इस बात की खास तौर पर जिम्मेदारी आ जाती है कि वह इस बात का पक्का प्रबंध करे कि जिन लोगों को नजरबंद किया गया है उन नताओं को गिरफ्तार किया गया है उनके साथ जेल में ठीक बरताव हो।

इसके बाद मैं अंगवारा की आजादी और मौजूदा सेंसरशिप के सवाल पर आता हूँ। यह सेंसरशिप अनोखी और बे मिसाल है। अंग्रेजों के जमान में भी, उनकी हुकूमत के बदतरीन जमान में भी, जबकि अंग्रेज दूसरा महायुद्ध लड़ रहे थे और एक के बाद एक हार उड़ाई में उनकी हार हो रही थी, उन्होंने कभी पराधीन भारत पर भी ऐसी सेंसरशिप नहीं बापी थी जसी कि स्वतंत्र भारत के शासक हमारे ऊपर बाप रह हैं।

चूँकि मैं सामाजिक नायक में विश्वास करता हूँ, समाजवाद में विश्वास रखता हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि फौरन कुछ आर्थिक कार्यक्रम पूरे किये जायें। हम जानना चाहते हैं कि सरकार को इन कार्यक्रमों को पूरा करने में किससे रोका? अतः मैं जगजीवनराम से पूछना चाहता हूँ, कि आज हम जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ से वापस लौट आने का कोई रास्ता है? या हम एक पार्टी की हुकूमत और उसके बाद एक पार्टी की हुकूमत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या यह खुली डिक्टेटरशिप की शुरुआत नहीं है? क्या जनतंत्र के ढाँचे के टूट हुए टुकड़ा से सरकार ईट ईट जाइकर एक निरंकुश शासन की इमारत नहीं खड़ी कर रही है?

श्रीनगर के शमीम अहमद शमीम न बहा

जनतंत्र आपके लिए बहुत तकलीफदेह तरीका है। लोग आपके खिलाफ बातें करते हैं, लोग आपका विरोध करते हैं लेकिन जनतंत्र की बुनियादी खूबी यही है कि आखिर में जीत बहुमत की ही होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि आजकल जिन लोगों का बहुमत है उन्होंने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है कि अल्पमत का रोड़ा भी रास्ते में क्या रहने दें। यह सदन विपक्ष के कई नाटक देख चुका है। लेकिन यह सदन इस बात का भी गवाह है कि यहाँ से उसी चीज़ का मजूरी ले ली गयी है जिसके साथ बहुमत था। इसकी क्या वजह है कि विपक्ष में जो कुछ किया उसके बावजूद वही कानून आज आपको बाटे की तरह खटकन लगा है? एक बेतुकी दलील यह दी जाती है कि इमर्जेंसी की वजह से लोग ज्यादा मुस्तन्नी से काम करना चाहते हैं सरकारी नौकर 10 वजे पत्तर आने लगे हैं, रस्ते ठीक वक़्त से चलने लगे हैं वगैरह-वगैरह। इसमें यह मतलब छिपा हुआ है कि यह ससदीय रास्ता जिस पर हम पिछले सत्ताईस साल से चलते आये हैं हमारा वक़्त खराब करने के अलावा और कुछ नहीं करता, इसमें यह मतलब भी छिपा हुआ है कि यह जिसमें वे एक बेकार हिस्सा की तरह हैं इसमें यह मतलब भी छिपा हुआ है कि जिस दिन से आपने इमर्जेंसी लागू की है उस दिन से हर चीज़ में बढ़त सुधार हो गया है। इस दलील में तुक क्या है? आप कहते हैं कि हम ससदीय जनतंत्र

का यह दोग नहीं चाहिए, इससे कौम की तरक्की में रुकावट पड़ती है।

घोर फिर भ्रष्टवारी की आजादी का सवाल ले लीजिये। आपने भ्रष्टवारी पर सेंसरशिप लागू कर दी है। वे सूरमा जो भ्रष्टवारी की आजादी और देश की आजादी के लिए लड़ चुके हैं आज सेंसरशिप को सही साबित करने की कोशिश में यह कह रहे हैं कि फलतः भ्रष्टवारी को फलाने दिया गया होता तो मुल्क का पूरा ढाँचा ढह गया होता। इंदिरा गांधी ने कल अपनी तकरीर में कहा था कि उनकी यह बताया गया था कि प्रार० एस० एस० के दफ्तर से जो तलवार बरामद हुई थी वह लकड़ी की थी और इसके बाद उन्होंने कहा था कि या तो आपके पास तलवार है या तलवार नहीं है। यही बात भ्रष्टवारी की आजादी पर भी लागू होती है। या तो भ्रष्टवारी की आजादी होती है या फिर नहीं होती। ऐसा ग़ीबत हाँ सकता कि सिर्फ ऐसे भ्रष्टवार हाँ जो बस वही बातें छापें जो आप चाहते हैं। जनता का असली निचाड़ यह है कि दोनों तरफ की बातें जनता के सामने रख दी जायें और जनता की समझ पर भरोसा रखकर उसे इस बात का फैसला करने का मौका दिया जाये कि क्या सही है और क्या गलत। आप जानते हैं कि 1971 में भ्रष्टवार आपके बारे में क्या लिखते थे, फिर भी जनता ने आपको बोट दिया। भ्रष्टवार जो कुछ लिखते थे उसकी बुनियाद पर उन्होंने फैसला नहीं किया। 'भूठ और सच में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर ऐसा क्या हो गया है कि आज विपक्ष की तरफ से फलायी जान वाली किसी भ्रष्टवारी के महज शब्दों से पूरी सरकार हिल जाती है? अगर इस कानून को, कानून में कुछ हेर-फेर करने के इस सुझाव को मेकनीयती के साथ रखा गया होता तो मैं इसका साथ देता। लेकिन यह बदनीयती के साथ रखा गया है। आपने इस मुल्क की जनता के खिलाफ जग का ऐलान कर दिया है। आप यह कानून महज जवाँ और भ्रष्टाचारियों को बदनाम करने के लिए बनवाना चाहते हैं और सारी दुनिया जानती है कि इसके पीछे असली वजह क्या है। आपको भ्रष्टाचार पर कोई भरोसा नहीं है, आपको जजों पर कोई भरोसा नहीं है।

मेरा मोरारजी देसाई से बहुत सी बातों पर मतभेद है, वह इस सदन में जो कुछ कहते हैं उसका एक लपज भी मुझे अच्छा नहीं लगता, यह सदन गवाह है कि जिस दिन उन्होंने इस सदन में विपक्ष की तरफ से बोलने की जिम्मेदारी सभाली थी उसी दिन मैंने खड़े होकर कहा था, उन्हें मेरी तरफ से बोलने का कोई हक नहीं है।' मैं कह चुका हूँ कि मेरे दिल में जय-प्रकाश के लिए जो भी इज्जत थी, जब उन्होंने जनसभ के इजलास की सद्गति की तो मैंने उनकी इस बात को ठीक नहीं समझा। जिस वक़्त से उन्होंने जनसभ के इजलास में शिरकत की और बिहार की विधानसभा लाइ देने की माँग की उसके बाद से मैंने किसी बात पर उनका साथ नहीं दिया। लेकिन इतना मैं आपको बता दूँ कि मैं इस बात को कभी नहीं मानूँगा कि वह स्मगलर हैं। फिर उन्हें किसलिए गिरफ्तार किया गया है। मोरारजी के बारे में ऐसा लगता है कि उनकी वजह से मुल्क की सलामती के लिए खतरा पैदा हो गया था, वह स्मगलर थे। इसीलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।

आज आपने इमर्जेंसी की आड़ में क्या किया है? इमर्जेंसी के बारे में मैं यह मानता हूँ कि हालात ऐसे थे कि सचमुच कोई सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया था। लेकिन आपने ये कदम उठाये किसके खिलाफ हैं? आपने

ये कदम पूरी कीम के खिलाफ उठाये हैं। आपने मेरे खिलाफ सप्न कदम उठाये हैं। आपने उन लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाये हैं जो आपके साथ हैं। आपने उन लोगों को आजादी की हडप लिया है जो वानून के बताये हुए रास्ते पर चलते हैं। यह वहाँ का इसाफ है कि आप किसी भी आदमी के हक महज इसलिए छीन सें कि उसने कोई ऐसा काम किया है जो आपको पसंद नहीं है। पार्लियामेंट के उन बड़े-बड़े सूरमाओं के सर, जो बड़े-बड़े हमले करते रहते थे, 1971 के चुनाव में कलम कर दिये गये थे। उनके सर जनता ने कलम किये थे। आज भी अगर आपने देश के सामने जाकर कहा होता कि ये लोग पार्लियामेंट की काम नहीं करने देते तो आप देखते कि जनता एक बार फिर आपको बहुमत दिला देती और इन लोगों को ठुकरा देती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।

मुमकिन है कि यह पार्लियामेंट इस मुल्क की आखिरी पार्लियामेंट हो। इसका सबूत श्रीमती गांधी का वह वयान है जिसमें यह कहा गया है कि इमजेंसी से पहले वाले आम हालात भव फिर कभी लौटकर आनेवाले नहीं हैं। उन्होंने उन हालात को आजादी का बैजा इस्तेमाल कहा है। जिस मुल्क में इस बात का फसला एक आदमी के हाथ में हो कि मामूल क्या है और आजादी का बैजा इस्तेमाल क्या है और आजादी क्या है उस मुल्क के फाटक पर समझ लीजिये डिक्टेटरशिप की तस्ती लगी है। श्रीमती गांधी डिक्टेटर नहीं हैं लेकिन उन्होंने डिक्टेटरशिप के रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। डिक्टेटरशिप की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि शुरू शुरू में बहुत सोच-समझकर और बहुत उम्दा उसूल ढाल आने हैं। उन्हें बहुत खूबसूरत झलकाव में ढाला जाता है। धीरे धीरे लोगों को उनमें मजा आने लगता है। उनकी उनमें सुकून मिलता है और सब लोग यह कहने लगते हैं कि यही जम्हूरियत के उसूल हैं। ऐसा यही नहीं होता। इस में जमनी में, उन दूसरे मुल्कों में जहाँ डिक्टेटरशिप है, आम तौर पर लोग जम्हूरियत के गुण गाते हैं और उसके नाम की माला जपत हैं। मैं श्रीमती गांधी को एक बात बताना चाहता हूँ। वह बहुत साफ गो औरत हैं। वह जो कुछ भी कहना चाहती हैं बहुत साफ तौर पर कहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पार्लियामेंटरी तरीके पर से उनका भरोसा उठ गया है। बहुत अच्छा हो अगर वह साफ साफ यह कह दें कि आज इस मुल्क में इस तरीके के लिए कोई जगह नहीं रह गयी है। इसकी वजह कुछ भी हो, मैं उनमें नहीं जाना चाहता।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने श्रीमती इंदिरा गांधी का साथ दिया। उसके ससद सदस्य इन्द्रजीत गुप्ता ने कहा कि इमजेंसी का ऐनान बिलकुल सही था और हर आदमी ने उसका समर्थन किया था। लेकिन सरकार को चाहिये कि वह सारे देश को उन सारी बातों की जानकारी दे जिनकी वजह से उसे यह कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां न जो मोर्चा बनाया था वह जयप्रकाश नारायण की भगुवाई में पिछले डेढ़ साल से कई राज्यों में ऐसे तरीकों से सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था जो पूरी तरह सविधान के अनुकूल नहीं थे। सब तो यह है कि इन सारी घटनाओं का एक अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि के साथ बहुत सीधा सम्बन्ध है। अमरीका अपनी चात चल रहा है।

उन्होंने कहा, प्रस्ताव पेश करनेवाले ने बहुत ठीक कहा था कि कुछ पखवार

सत्ता पर कब्जा करने की इस साजिश में बहुत भागे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। भ्रष्टाचारी के भ्रष्टाचारों को खुली छूट दी गयी हाँ। तो अब तक बीस-पच्चीस दिन के अन्दर उन्होंने देश में तबाही मचा दी होती। संसद के सदस्यों को कमजोर करने और जनता के अधिकारों के हाथ मजबूत करने के लिए लगायी गयी थी।

लोकसभा में बहस के दौरान बीच में बोलते हुए श्रीमती गांधी ने जनसभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर 'कानाफूसी की मुहिम' चलाने का आरोप लगाया और यह शिकायत की कि सरकार के खिलाफ जो 'झूठी बातें' फलायी गयी थी उनके खिलाफ भ्रष्टाचारों ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अब भी इसके बारे में 'कानाफूसी की एक बहुत बड़ी मुहिम' चल रही है कि 'कौन अपने घर में बंद कर दिया गया है जिसने भूल हड़ताल कर रखी है और कौन मर गया है।' इस बात पर जोर देते हुए कि विपक्ष की पार्टियाँ हिंसा के साथ बैठी हुई हैं उन्होंने भ्रष्टाचारों में छपी हुई खबरों का हवाला दिया कि जयप्रकाश ने 1967 में कहा था कि वह 'फौजी डिक्टेटरशिप की बात सोच रहे हैं' और उन्होंने सुझाव दिया था कि उस साल चुनाव की वजह से जो राजनीतिक स्थिरता पैदा हो गयी थी उसे देखते हुए राष्ट्र को चाहिए कि वह इस खाली जगहों को भरने के लिए फौज की मदद का सहारा ले।

भागे चलकर उन्होंने कहा कि गुजरात में विधायकों के बच्चों को मार देने की घमकी देकर उन्हें विधानसभा से इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया और जिस वक्त कांग्रेस का एक विधायक अस्पताल में पड़ा था तो छात्रों ने उसे उठाकर खिड़की के बाहर फेंक देने की घमकी दी थी। 'मानव मांग जैस' अपराधी संगठनों के मुस्टबे' अब भी लोगो की हत्या करने की साजिशें कर रहे थे। जब पश्चिम बंगाल में माकसवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी तब लोग मूर्ख होने के बाद सड़क पर निकल नहीं सकते थे। उन्होंने अपना भाषण जारी रखते हुए कहा, "अब मनमानी आजादी और राजनीति के नाम पर कुछ भी करने की छूट के बिना फिर कभी नहीं लौटने दिये जायेंगे।

'जनतंत्र का तकाड़ा है कि हर आदमी अपने ऊपर काबू रखे। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह विपक्ष को काम करने का पूरा मौका दे, बोलने की आजादी और भीड़ों करने की आजादी दे। लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वह जनतंत्र को नष्ट करने के लिए या सरकार का काम बाज ठप्प कर देने के लिए इसका फायदा न उठाए। 'सरकार का काम-बाज ठप्प कर देने' के शब्द मेरे नहीं हैं ये शब्द यहाँ नहीं दिल्ली की और दूसरी जगहों की भीड़ों में खुलेआम इस्तेमाल किये गये थे। "

श्रीमती गांधी की एक बात के जवाब में भारतीय लोकदल के सदस-सत्य एच० एम० पटेल ने कहा कि जब भ्रष्टाचारों पर पूरी संसद लागू कर दी गयी है तो कानाफूसी की मुहिम और अपवाहों के अलावा और उम्मीद ही क्या की जा सकती है।

राज्यसभा ने 22 जुलाई को 136 के खिलाफ 33 वोटों से इमर्जेंसी के ऐलान को अपनी मजूरी दे दी। वोट से लिये जाने के बाद सोशलिस्ट नेता नारायण गणेश गोरे ने विपक्ष की ओर से एक बयान पढ़ा जिसमें ऐलान किया गया था कि संसद के काम करने के नियमों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिये जाने के बिना और संसद की कार्यवाही की रिपोर्टों पर भी भ्रष्टाचारों में संसद लागू करने के लिए सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए विपक्ष के सदस्य संसद की यात्री बैठक में भाग नहीं लेंगे।

अगले दिन लोकसभा में भी इमर्जेंसी के ऐलान को 336 के विरुद्ध 59

से मजबूरी मिल जाने के बाद विपक्ष के ज्यादातर सदस्य सदन छोड़कर चले गये, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कई छोटी छोटी पार्टियों ने, जिनमें मुस्लिम लीग, रिपब्लिकन पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और अना द्रविड मुन्नेत्र कळगम शामिल थी, बायकाट का साथ नहीं दिया।

दोनों सदना ने सविधान (39वाँ संशोधन) बिल भी पास कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि इमर्जेंसी की घोषणा के लिए राष्ट्रपति के बताये हुए कारणों को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। 28-29 जुलाई को जब पंद्रह राज्यों की विधानसभाओं ने अपनी विशेष बैठकों में इस बिल को मजबूरी द दी, तो उसे 1 अगस्त को राष्ट्रपति की भी स्वीकृति मिल गयी।

इमर्जेंसी के ऐलान की मजबूरी लेना कानूनन जरूरी था। लेकिन श्रीमती गांधी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फसले की वजह से हरेदम परेशान रहती थी।

उनके घर पर जो 'इमर्जेंसी कौन्सिल' बैठती थी वह कई बड़े बड़े वकीलों से सलाह मशविरा करने के बाद इस नतीजे पर पहुँची थी कि कानून की जो शक्ति उस वक्त थी उसमें कोई भी जज उस फसले से असंग कोई फैसला दे ही नहीं सकता था जो जस्टिस सिन्हा ने दिया था।

सबसे पहले तो इस बात का इन्तजाम करना था कि इस फैसले का उनके भविष्य पर कोई बुरा असर न पड़े। श्रीमती गांधी के वकीलों ने, और पैरवी करन स इकार करने से पहले पालकीवाला ने भी उनसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें चुनाव में भ्रष्टाचार का सहारा लेने के इन्तजाम से बरी कर देगा। उन्हें यह भी तसल्ली थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ए० एन० रे थे जिनकी श्रीमती गांधी ने उनकी बारी आने से पहले ही इस पद पर नियुक्त कर दिया था। उनसे पहले जिन तीन जजों की बारी थी उनमें से एक ने जस्टिस हेगड़े ने, उस वक्त कहा था कि श्रीमती गांधी इस बात के लिए रास्ता साफ कर रही हैं कि उनके खिलाफ जो चुनाव याचिका दायर की गयी थी उसमें अगर फैसला उनके खिलाफ हो तो अपील करने का मौका रहे।

फिर भी वह खतरे की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहने देना चाहती थी। गोखले ने इलाहाबाद वाले फैसले को रद्द कर देने के लिए एक बिल तैयार किया और उसका भसविदा सिद्धार्थशंकर र और रजनी पटेल को दिखाया। रजनी पटेल बम्बई के एक प्रगतिशील थे जो सबसे बढ़िया स्काच ह्विस्की रायल मस्मूट के प्रसादा और कुछ नहीं पीत थे। दोनों श्रीमती गांधी के बहुत करीब थे और जब भी उन्हें किसी सलाह मशविरा के लिए उनकी जरूरत पड़ती थी तो वे हवाई जहाज से उड़कर उनके पास पहुँच जाते थे। लेकिन सजय को ये लोग बिलकुल पसंद नहीं थे और वह उनके खिलाफ कारवाई करने के लिए मौने की ताक में था।

एक वकन इस 'प्रगतिशील ग्रुप' ने यह कानून बनवा देा का सुभाव रखा था कि अगर सजा के तौर पर किसी संसद सदस्य की पार्लियामेंट की सम्मति प्राप्त कर दी जाय तो उसके साथ यह भी गत रहनी चाहिए कि उस पर संसद सदस्य न बन सकने की पाबंदी उस संसद की जिदनी तब ही रहे। इरादा यह था कि अगर सुप्रीम कोर्ट श्रीमती गांधी की अपील रद्द कर दे तो प्रधानमंत्री समद को भग बराबर फिर चुनाव करा सकती थी। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं चाहते थे। सजय चुनाव कराने में सहज खिलाफ था। यूनुस का कहना था कि पाँच साल तक चुनाव की बात सोचनी भी नहीं चाहिए।

सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फसले का उसके मुनाय जान की ताराग न ही रद्द कर देने के लिए सोचसभा में 4 जुलाई को एक मिल वेन किया। चुनाव

कानून में कई हेर फेर करने के सुझाव रखे गये थे।

पहला यह कि सरकारी कर्मचारियों पर अपने सरकारी काम के सिलसिले में चुनाव की मुहिम के दौरान राजनीतिक उम्मीदवारों की मदद न करने की पाबन्दी अब नहीं रहेगी। इसका मतलब था कि श्रीमती गांधी को अपनी चुनाव की मीटिंगों के लिए मंच बनवाने और लाउडस्पीकर तथा बिजली लगाने के लिए सरकारी नौकरों की मदद लेने के अपराध से बरी कर दिया जायेगा।

दूसरा यह कि सरकारी गजट में छप जाना के द्वाय सरकार या राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति, इस्तीफे, नौकरी खत्म किये जाने या नौकरी से हटा दिये जाने की तारीख का पक्का सबूत माना जायेगा। इसका मकसद उस दूसरे अपराध को रद्द कर देना था जिसके लिए श्रीमती गांधी को सजा दी गयी थी—यह कि एक सरकारी नौकर यशपाल कपूर ने सरकार को अपना इस्तीफा भेजने से पहले श्रीमती गांधी के चुनाव अभियान के मनेजर की हैसियत से काम किया था।

तीसरा यह कि चुनाव के खर्च का हिसाब लगाने के लिए और 'दूसरे कामों के लिए' नामजदगी की तारीख शुरूआत मानी जायेगी। ऐसा इसलिए किया गया था कि एक ओर तो सुप्रीम कोर्ट यह फैसला न दे सके कि श्रीमती गांधी ने अपने चुनाव के लिए 35,000 रुपये की सीमा से ज्यादा पैसा खर्च किया था और दूसरी तरफ यह कि चुनाव लड़ने का ऐलान करने की तारीख का कोई महत्व नहीं है।

पी० टी० भाई० और यू० एन० भाई० दोनों ही ने पूरा बिल और उसका महत्व समझते हुए खबर भेजी थी। लेकिन सेंसर के दफ्तर के आदेश पर उन्होंने खबर को वापस ले लिया और दूसरी खबर भेजी जिसमें सिर्फ संक्षेप में बिल का निबोड दिया गया था और उसमें श्रीमती गांधी का कोई जिक्र नहीं था।

यह बिल एक संशोधन के साथ 5 अगस्त को लोकसभा में पास हो गया। इसमें यह भी कहा गया था कि चुनाव में भ्रष्टाचार के तरीके अपनाते की बुनियाद पर अगर किसी की सदस्यता खत्म कर दी जाये तो उसका मामला राष्ट्रपति के पास भेजा जाये और राष्ट्रपति चुनाव कमिशनर से सलाह करके यह फैसला करे कि सदस्य न रह सकने की यह पाबन्दी लगायी जाये या नहीं और अगर लगायी जाये तो कितने अरसे के लिए। इसमें एक कसर रह गयी थी। बाद में सरकार ने संविधान में एक संशोधन करवा दिया कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिमण्डल की सलाह को मानना 'लाजिमी' है। उनके लिए और कोई रास्ता ही नहीं था।

सदस्य न रह सकने की पाबन्दी के बारे में तो कानून बनवाना जरूरी था लेकिन इससे भी जरूरी वह कानून था जिसमें प्रधानमंत्री के चुनाव के बारे में किसी झगड़े पर विचार करने का अधिकार चुनाव कमिशन से छीन लिया गया था। यह जताने के लिए कि यह विचार सरकार के दिमाग की उषज नहीं है, श्रीमती गांधी और उनके सलाहकारों ने कांग्रेस के एक मामूली सदस्य सदस्य से यह मसला उठाया। सदस्य न रह सकने की पाबन्दी वाले बिल पर बहस के दौरान उन्होंने कहा कि जिन पदा पर चुनाव जीतकर आनेवाला आदमी ही रह सकता है, उनमें से कुछ घाटलतों के दायरे से बाहर निकाल लिये जाने चाहिए।

गोखले ने इस विचार का स्वागत किया, चौबीस घंटे के अंदर उसे कानूनी शक्ल दे दी, और 7 अगस्त को संविधान (40वाँ संशोधन) बिल पेश किया, जिसमें राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के स्पीकर के चुनाव से सम्बंध रखनेवाले मामले निबटाने के लिए किसी भी अदालत के अधिकार क्षेत्र से नयी सस्था की स्थापना की गयी। इसके पीछे मकसद सिर्फ इस बात का बिलकुल

बन्दोबस्त करना था कि श्रीमती गांधी पर किसी चुनाव याचिका का कोई प्रसरण पड़ने पाये। दूसरों के नाम तो सिर्फ इसलिए जोड़ दिये गये थे कि सीधे-सीधे यह न लगे कि यह बिल सिर्फ श्रीमती गांधी के बचाव के लिए पेश किया गया है। कुछ मुख्यमंत्रियों ने नई दिल्ली टेलीफोन करके यह जानने की कोशिश की कि क्या उनको भी इस मामले में प्रधानमंत्री जैसी छूट मिल सकती है। उनसे मामले में विचार करने का समय नहीं था।

कांग्रेस के ज्यादातर सदस्य हमेशा की तरह निर्दिष्ट बैठे रहे और उन्होंने इस बिल के बारे में कोई एतराज नहीं किया। मन ही मन उन्हें यह बात पसंद भी लग रही हो पर उन्होंने बाहर से ऐसा जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन कुछ लोगो ने इसके खिलाफ आवाज उठायी। बचे चुके विपक्ष की ओर से मोहन धारिया ने ऐलान किया, 'यह कानून इसाहाबाद हाईकोर्ट के फसले से बच निकलने के लिए बनवाया जा रहा है। इसे पास करवाने के लिए भालिखर इतनी हड़बड़ी क्यों की जा रही है? क्या इसलिए कि प्रधानमंत्री के मामले की सुनवाई 11 अगस्त को होने वाली है।'

सबसे पहले यह बिल बहुत हड़बड़ी में 7 अगस्त को 11 बजे लोकसभा में पेश किया गया और सारी आपत्तियों को रद्द करके और यह पावन्दी हटवाकर कि कोई भी बिल सदन में पेश किये जाने से कम से कम एक खास समय पहले सदस्यों के पास भेज दिया जाना चाहिए, सरकार की तरफ से उसे 11 बजेकर 8 मिनट पर विचार के लिए पेश कर दिया गया। अलग-अलग एक एक धारा पर बहस और नियम के अनुसार तीन बार उसके पढ़ दिये जाने के बाद 11 बजेकर 50 मिनट पर यह बिल पास भी हो गया। राज्यसभा ने अगले दिन एक घंटे के अन्दर उसे मजूरी दे दी। उसके खिलाफ कोई धोला ही नहीं।

जिन राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस का बहुमत था उनकी बैठक 8 अगस्त को बुलाई गयी और अगले दिन इस बिल पर उनकी भी मजूरी की मुहर लगवा ली गयी और 10 अगस्त को राष्ट्रपति ने उसे अपनी स्वीकृति दे दी—जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में श्रीमती गांधी की अपील की सुनवाई होने वाली थी उससे एक दिन पहले।

लेकिन इससे पहले कि 40वें संशोधन बिल को (सरकारी हिसाब से वह 39वाँ था) कानून की हैसियत मिल पाती, कांग्रेस के कुछ सदस्य सदस्यों ने एक और कमी पूरी कर दी। उन्हें यह शक हुआ कि विपक्ष का कोई आदमी कहीं इस बिल के खिलाफ स्टे ऑब्जेक्शन न ले ले। इसलिए उन्होंने 9 अगस्त को राज्यसभा की बैठक करायी और संविधान (41वाँ संशोधन) बिल पास करा दिया जिसमें कहा गया था कि जो आदमी राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रह चुका हो उसके खिलाफ किसी अदालत में फौजदारी कानून के तहत कोई मुकदमा नहीं दायर किया जा सकता। राष्ट्रपति का नाम तो यो ही संशोधन जोड़ दिया गया था क्योंकि संविधान की धारा 361 में यह बात पहले ही से मौजूद थी। बिल का मकसद दरअसल प्रधानमंत्री का बचाव करना था। जब सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ दायर की गयी चुनाव याचिका की सुनवाई शुरू हो गयी तो इस बिल को चुपचाप खटाई में डाल दिया गया, मकसद पूरा हो गया था।

अब श्रुति सारे जरूरी कानून बनवाये जा चुके थे, इसलिए सारा ध्यान सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री की अपील की ओर दिया जाने लगा। सबसे पहले तो उसके बारे में 'जहरत से ज्यादा और प्रतिकूल प्रचार को रोकना था। चौक प्रेस सेंसर हैरी डी० पनहा ने छहवारी, समाचार एजेंसियाँ और दूसरे लोगो को खास तौर पर यह आदेश दिया कि वे अदालत की कारवाई की कोई रिपोर्ट पहले उनके दफ्तर से मंजूर करवाये

दिना न छापें। सभी भयभारों ने धु किये बिना ही यह आदेश मान लिया, सिफ एव पेजी दैनिक ईवनिंग घूम नही माना और बाद में उस पर पाबंदी लगा दी गयी।

सुप्रीम कोर्ट की कारवाई की खबर सेंसर करने के आदेश पर चीफ जस्टिस ने भी कोई एतराज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के पूरे इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। सच तो यह है कि यह इस बात के पक्ष में थे कि कार्रवाई में भाग लेना या उसे मुनने के लिए जो वकील आयें उनकी पहले जांच पड़ताल कर ली जाये। इससे खिलाफ इतना जोर भी आवाज उठायी गयी कि—अदालत का बायकाट कर देने तक की धमकी दी गयी—उन्होंने फिर इस लागू नहीं किया।

चीफ जस्टिस की भगुवाई में पाँच जजों की बेंच 11 अगस्त को अपील की सुनवाई करने के लिए बैठी।

शान्तिभूषण ने, जो बहुत चुस्त और मुस्तैद वकील थे और जिन्होंने इलाहाबाद में राजनारायण की तरफ से पैरवी की थी, सुप्रीम कोर्ट में भी यह काम सँभाला। श्रीमती गांधी की पैरवी कर रहे थे अशोक सेन जो पहले कानूनमंत्री रह चुके थे। सेन ने अदालत से सविधान के 39वें संशोधन के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को उलट देने के लिए कहा। लेकिन शान्तिभूषण ने दलील यह दी कि अदालत पहले यह फैसला कर दे कि 39वाँ संशोधन सविधान के मुताबिक ठीक भी है या नहीं। कुछ लोग को कानून से परे रखकर 39वें संशोधन न ऊँचे पद की बुनियाद पर आदमी-आदमी के बीच फाँट पड़ा कर दिया है, उसने शासन के लिए कानून की पाबंदी के विचार को ही नष्ट कर दिया है, और सदन का यह ऐलान कि हाईकोर्ट के फैसले का कोई मतलब नहीं रह गया है सरकार, सदन और अदालतों के अधिकारों को दूसरे से भ्रमण रखने के सिद्धान्त के खिलाफ है। उन्होंने यह दलील भी दी कि सदन की जो बैठक हुई थी उसकी सारी कारवाइयाँ गैर-कानूनी थी, ही मेम्बरों को गैर-कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया था और सचवाई में हिंसा लेने का मौना नहीं दिया गया था।

एटॉर्नी जनरल नीरेन डे ने, जो सरकार का इतना खुला समर्थन करते थे कि सरकार खुद मुश्किल में पड़ जाती थी, यह दलील दी कि चुनाव के भ्रमण पर विचार करना अदालतों का बुनियादी काम नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम के ज्यादातर जनतांत्रिक देशों में चुनाव से सम्बंध रखनेवाले सारे मामले उनकी सदन के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने बहस करते हुए कहा कि 1973 में केशवानन्द भारती बनाम केरल सरकार वाले मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि सदन को सविधान में संशोधन करने या उसे बदलने का अधिकार जरूर है लेकिन इस तरह कि उसका 'बुनियादी ढाँचा या रूपरेखा' बदले या नष्ट न हो जाये।

चीफ जस्टिस ने ने ऐलान किया कि सविधान के संशोधन के बारे में फैसला देने से पहले अदालत श्रीमती गांधी की अपील के मिलसिले में तथ्यों और दलीलों पर जिरह सुनेगी।

सुप्रीम कोर्ट की जिरह के बारे में श्रीमती गांधी को कोई चिन्ता नहीं थी। सविधान के संशोधनों में अगर कोई कसर रह भी गयी होगी तो उनके वकील उसका बन्दोबस्त कर लेंगे।

उहे चिन्ता थी उन बातों की जो पड़ोसी देश बंगलादेश में उस समय हो रही थी। 14 अगस्त को शेख मुजीबुररहमान और उनके परिवार के ज्यादातर लोग को यहाँ बेरहमी से हत्या कर दी गयी थी। न'रों को और न ही किसी दूसरी गुप्त चर सेवा की इसकी रत्ती भर भी भनक मिल सकी थी। एक बार फिर

श्रीमती गांधी को निराश किया था। दरघसल उसी दिन से सजय ने 'रों' को 'समुदायी रिश्तेदारों का सघ' कहना शुरू कर दिया था। 'रों' के छोटी के भफसरो के बहुत-से रिश्तेदार उस सगठन में थे। श्रीमती गांधी ने 'रों' के बर्त्ता घर्त्ता रामजी बाभ्रो से बगलादेश के बारे में पहले से कोई खफिया रिपोट न मिल सकने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्हें परधानी यह थी कि अगर उनके जासूस बगलादेश के बारे में उनके काम नहीं आये तो कल भारत के बारे में भी यही हो सकता है।

सचमुच मुजीब की मौत से श्रीमती गांधी को बहुत गहरा धक्का लगा, खास तौर पर इसलिए कि दाना ही नेता अपना निरकुश शासन कायम करने के एक जसे रास्तों पर चल रहे थे। जब मुजीब ने संविधान की रद्द करके सारी ताकत अपने हाथ में ले ली थी, तो उस वकन जयप्रकाश नारायण ने 11 फरवरी को दिल्ली में बिपक्ष की सभी पार्टियों की एक मीटिंग की थी। उन्होंने कहा था कि शामद यह उस बीज का रिहसल है जिसका सामना कल उन्हें भारत में करना पडना, और उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। प्रशाक महता ने जयप्रकाश नारायण की दलील को यह कहकर रद्द कर दिया था कि भारत में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मोरारजी ने यह नहीं माना कि ऐसा नहीं हो सकता और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं गुजरात में प्रान्दो बन छिड़ दूंगा। चरणसिंह ने कहा 'वह जो भी करना चाहती हैं करें और साथ ही यह भी कहा कि 'वह कर ही क्या सकती हैं?' राजनारायण ने कहा, 'कम-से कम हम दोनों को जेल में तो डाल ही सकती हैं।

जयप्रकाश नारायण ने बहस के बीच में बोलते हुए कहा कि वह लोग इस बात पर गम्भीरता से विचार नहीं कर रहे हैं। उनका पूरी सजीदगी से इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। वह देख रहे थे कि नागरिक स्वतन्त्रताएं खत्म हो जायेंगी, कई पार्टियों वाली व्यवस्था खत्म हो जायेगी। उन्होंने कहा कि बिपक्ष की पार्टियां को बाहरी इमर्जेंसी के जारी रहने के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिये।

हर प्रादमी चाहता था कि 'कुछ किया जाये। क्या किया जाय यह कोई नहीं जानता था लेकिन किसी ने जयप्रकाश की बात पर गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया। बाद में रोहतक जेल में जहाँ इमर्जेंसी के दौरान बिपक्ष के ज्यादातर नेता कैद किये गये थे कुछ लोगों को जयप्रकाश की यह चेतावनी याद आयी। किन्ती सच्ची भविष्य-वाणी थी।

लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिलता था कि श्रीमती गांधी ने मुजीब की हत्या से कोई सबक लिया हो। लाग दबी जबान से इस बात की चर्चा करते थे और भारत की और बगलादेश की घटनाओं में समानता देखत थे। इंगारा यह था कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। वजह कुछ भी गही हो लेकिन श्रीमती गांधी के चारों ओर सुरक्षा का बन्नीबस्त और पतवा कर दिया गया। सफर-रजग रोड के उस हिस्से पर तो, जहाँ उनकी कोठी थी इमर्जेंसी लगने के बाद से ही आवाजाही बन्द कर दी गयी थी लेकिन अब उनकी कोठी से मिले हुए बंगले के सामने से जानेवाली सड़क प्रकवर रोड पर भी आवाजाही बन्द कर दी गयी थी।

बिस्ती ने तो यह सुझाव तब दिया कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय प्रगडा पहराने साल विले श्रीमती गांधी न जायें, जसा कि 1947 में भारत के आजाद होने के बाद से हमेशा होता आया था। लेकिन उन्होंने इस सुझाव को ठुकरा दिया। उन्होंने पब्लिक के सामने आना सगमग बंद हो कर रखा था लेकिन अगर वह 15 अगस्त को नहीं गयीं तो लोगों को यकीन हो जायगा कि वह अपने का सामना करने से डरती हैं—और उनके नाम के साथ यह कमजोरी पहने अभी नही जोड़ी गयी थी।

फिर भी 15 अगस्त को सुबह उनकी कोठी से साल बिले तक के दस किलोमीटर लम्बे रास्ते पर पुलिस का भारी पहरा था। दरियागज में रहनेवालों से सड़क की तरफ खुलनेवाली खिड़कियाँ बन्द रखने को कहा गया था। सड़क के दोनों तरफ के मकानों की छतों पर पुलिस तैनात कर दी गयी थी। बिलकुल वही नक्शा था जैसा व डे ऑफ व अकाल में था, जिसमें यह बयान किया गया था कि पुलिस ने किस तरह जनरल द गाल की हत्या की साजिश को नाकाम किया था। कुछ ही दिन पहले 8 अगस्त को धजाराम सागवान ने, जो पहले फौज में कप्तान रह चुके थे, मुझे जेल में एक साजिश के बारे में बताया था। वह एक टेलिस्कोपिक राइफल लिये हुए पकड़ा गया था।¹

थीमती गांधी जिस समय बन्द मोटर में साल किले जा रही थी, उस समय उन्हें इसका पता नहीं था। उनके दिमाग में मुजीब की हत्या के भलाभा कोई दूसरी बात नहीं थी, जिसकी वजह से उनके बोलने के ढंग पर भी भ्रसर पड़ा। उन्होंने विस्तार के साथ बताया कि उन्होंने इमर्जेंसी क्यों लगायी थी। उन्होंने कहा कि इमर्जेंसी लगाकर उन्हें बहुत खुशी हुई हो, ऐसी बात नहीं थी। वह बहुत दिन तक टालती रही लेकिन बाद में उन्हें हालात में मजबूर कर दिया। एक असाधारण हालत पदा हो गयी थी और देश को फिर से ठीक रास्ते पर लाने के लिए असाधारण कदम उठाना जरूरी हो गया था। उन्होंने अपने बाप अवाहरलाल नेहरू के ये शब्द दोहराये 'भाजादी खतरे में है। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी हिफाजत करो।'

ये शब्द उनको निशाना बनाकर भी कहे जा सकते थे। उन्होंने विपक्ष की पार्टियों को आंदोलन का सहारा लेने के लिए बहुत बुरा भला कहा। केन्द्रीय सरकार ने खिलाफ बिहार और गुजरात जैसा आंदोलन दूसरे राज्यों में भी छेड़ने का नारा दिया गया था, लडको से पढाई छोड़ देने को कहा गया था। कई तरीकों से अनुशासनहीनता फैलायी जा रही थी और कई दल, जिनमें से कुछ तो जनतंत्र और माँहसा में विश्वास भी नहीं रखते थे, इन आंदोलनों को चलाने के लिए मिलकर एक हो गये थे।

मानो यह जानत हुए कि क्यादतियाँ की गयी थी, उन्होंने कहा कि मैंने मुख्य-मंत्रियों को लिख दिया है कि कानूनों को लागू करने में किसी तरह की बेइसाफी और और जबरदस्ती न की जाये। कानून के रास्ते पर चलनेवाले शहरियों की हर तरह से मदद की जाये। पुलिस के और दूसरे अफसरों को जनता के साथ दोस्ती का बरताना चाहिए। अगर कोई गलतियाँ हुई हों तो उन्हें बताया जाना चाहिए कि काम करने का सही तरीका क्या है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी देखभाल अच्छी तरह की जायेगी।

देखभाल वाली बात ठीक नहीं थी। जेल में रहने-सहने की हालत बहुत भयानक थी। सरकार इस बात पर तुली हुई थी कि जो लोग नज़रबन्द किये गये थे उनके साथ आम अपराधियों से भी बदतर सलूक किया जाय। शुरू शुरू के दिनों में जब कदिया से मुलाकात और दूसरी सुविधाओं के बारे में वायदे बनाये जा रहे थे तो मोम महता ने जान-बूझकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा सख्त बनाया था और मह मंत्रालय में अफसरों की एक मीटिंग में यह बात कही भी थी। सबसे पहली बात तो यह कि पुलिस के किसी अफसर की मौजूदगी में दा बिलकुल सगे रिश्तेदारों के साथ महीने में सिर्फ एक बार भाड़े घंटे की मुलाकात की इजाजत थी। हर कंदी को रोज खर्चों के लिए दवाई रुपये मिलत थे। शुरू में नज़रबन्द कदिया को रेडिया भी नहीं दिये गये थे, कुछ को तो

1 इसके पूरे स्पॉरे के लिए मेरी बीछ ही प्रकाशित होनेवाली पुस्तक 'जेल में की प्रतीक्षा'...

सैंसर किये हुए मसबदार तक नहीं दिये जाते थे ।

चूँकि गिरफ्तार किये जानेवालों की तादाद लगभग एक लाख तक पहुँच चुकी थी, इसलिए जेल खचाखच भरे हुए थे । दिल्ली के तिहाड़ जेल में, जहाँ 1,200 कदिया को रखने का इन्तजाम है, 4,000 से ज्यादा बँदी थे । जो थोड़ी-बहुत सुविधाएँ थीं वे इतने लोगों के लिए काफी नहीं थी । कई जेलों में गंदी नाली का पानी ऊपर भाबर चहता रहता था, नल में पानी सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए आता था ।

सन्दन में भारत के हाई कमिश्नर जी० के० नेहरू ने सन्दन के टाइम्स मसबदार में एक छत छपवाया था जिसमें भारत के जेलों की हालत बयान की गयी थी । उसमें कहा गया था 'सरकारी अधिकारी नजरबन्द कैदियों का जितना ध्यान रखते हैं और उनकी जितनी अच्छी देखभाल करते हैं वह बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं अपने बच्चा की करती हूँ । उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह दी जाती है, अच्छा खाना दिया जाता है और उनके साथ अच्छा सलूक किया जाता है ।' बसीमास न कहा कि कैदियों का बज्रन बढ़ गया है ।

जेलों की हालत तो बुरी थी ही, लेकिन अफसरों का रवैया उससे भी बुरा था । उनसे खास तौर पर यह दिया गया था कि वे राजनीतिक कैदियों के साथ धाम धपराधियों से बेहतर सलूक न करें । वही वही यातनाएँ देने के लिए आक्रामकता प्रयोग करते थे । दिल्ली के साल किले में एक बहुत आसीपान कमरे में विदेशों में गंगावर तरह तरह की नयी-से-नयी मशीनें लगायी गयी थी जहाँ लोगों की सच-सच बात बता देने पर 'मजबूर' किया जाता था । बन्नी के चेहरे पर पटो तेज रोगनी पड़ती रहती थी और पीछे से तरह-तरह की आवाजें आती रहती थीं, ताकि कुछ देर में वह हट जाये । मुकिया पुलिस के अफसर बहुत देर तक उससे सवाल-जवाब करते थे और उनकी हर बात और तमाम हरकतें टेप कर ली जाती थीं ।

जेलों में कुछ बँदी भर भी गये जिनमें से एक ट्रेड यूनियन नेता और भारत की थे, जो पहले मध्य प्रान्त विधानसभा के मेम्बर भी रह चुके थे । सभी राजनीतिक पादिया के बौद्ध मेम्बरों ने श्रीमती गांधी की लिखा 'जेल में एक महत्वपूर्ण भाग बर्ता की मौत के बारे में अधिकारियों ने बुराबाप मामले को दबा देने की जो नीति अपना रखी है, उसे देखते हुए हम महसूस करते हैं कि सरकार का उनकी मौत की वजह के बारे में घदासगी जॉय बरबानी चाहिए ।'

जेलों की बुरी हालत और कैदियों के साथ किये जानेवाले बुरे समूह की खबरें विद्वानों के समक्ष आने लगी । समनस्टी इन्टरनैशनल के चेयरमैन ईवान मारिस न कहा 'श्रीमती गांधी की सरकार तो मानव अधिकारों के सिद्धान्त की परवाह किसी, ताइवान, सोवियत संघ और कोरिया जैसे कई दूसरे पुलिस राज्यों से भी कम करती है ।

अप्रत्यापन और दूसरे राजनीतिक मामलों का नाम जारी की गयी घटीत को माटकीय रूप देने के लिए मन्त्र म महात्मा गांधी की मृति के चरणों में एक गजोनि जस्तादी गयी । मन्त्र क टाइम्स मसबदार में 15 अगस्त को एक कोरम का एक विधान 3000 पोंड रूप करके छपाया गया जिसमें लिखा गया था 'मात्र भारत का स्वाधीनता दिवस है । भारतीय जनता की जीवन बुझने में पाद ।' तमाम यूरोप के लगभग 500 मन्त्र-मन्त्रों और बुद्धिजीवियों ने जिसमें कुछ शायद पुस्तक विवेक भी थे, उस पर हस्ताक्षर किये थे । प्रसिद्ध बर्जिन वाक मरी मन्त्र म पर हस्ताक्षर कर रहे थे ।

दोस्तों गांधी बुद्धिजीवियों की दर

२६

नेहरू के स्थापित किये हुए अखबार नेशनल हेराल्ड के सम्पादक चलपति राव से एक जवाब तैयार कराके उन्हें भिजवा दिया। यह अलग बात है कि वह उस पर दस्तखत करने के लिए बहुत बुद्धिजीवियों को नहीं जुटा पायी। बहुत से ऐसे लोगो को, जिन्होंने उस पर दस्तखत करने से इबार किया था, इसके लिए मुसीबतें भेलनी पड़ी। रोमिल्ला थापर, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाती हैं, उन लोगो में से थी जिन्होंने इकार किया था। नतीजा यह हुआ कि उनका पिछले दस साल का इनकम-टैक्स का हिसाब फिर से खुलवाया गया।

सच तो यह है कि इनकम-टैक्स की फिर से जाँच करवाना और सी० बी० आई० की इनकम-टैक्स शाखा की तरफ से व्यापारियों और भ्रष्टारो के घरो पर छापे डलवाना उन लोगो को ठीक करने के लिए, जो उसका हुकम नहीं मानते थे, सरकार का भ्राम तरीका हो गया था। नामी और होनहार इंजीनियर मनमोहन सोधी को, जिहे बोकारो के इस्पात के कारखाने में एक बहुत ऊँचे पद से उद्योग मंत्रालय में लाया गया था, सजय गांधी के कहने पर सी० बी० आई० वालो ने बहुत परेशान किया था। सोधी का कसूर बस इतना था कि ससद में एक सवाल का जवाब तैयार करने के लिए कोई मामूली-सी जानकारी हासिल करने के लिए कुछ भ्रष्टारो को मारुति के कारखाने भेज दिया था। उस जमाने में टी० ए० पई उद्योगमंत्री थे। उन्होंने मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा देने की धमकी दी तब कही जाकर सोधी की जान बची।

वित्त मंत्रालय के दो टुकड़ों में बंट जाने के बाद से इनकम टैक्स के बच्चाये का हीमा खड़ा करके लोगो को सताने की चारदातें और भी बढ़ गयी। इनकम टैक्स, एक्साइज और बकी के कारोबार का एक अलग विभाग बना दिया गया था और प्रणव मुखर्जी के हवाले कर दिया गया था। वह अब सजय के एक दरबारी बन गये थे और उनके हर हुकम को पूरा करने के लिए हरदम तैयार रहते थे।

वित्त मंत्रालय के दो टुकड़े कर दिये जाने से ढीले ढाले वित्तमंत्री सी० सुब्रह्मण्यम की दिल का दौरा पड़ गया। जिस वक्त दक्षिणी भारत के सबसे बड़े कांग्रेसी नेता के० कामराज ने कांग्रेस के पुराने साथ नेताओं का साथ दिया था, जिन्होंने बाद में सगठन कांग्रेस बना ली थी, उस समय सी० सुब्रह्मण्यम ने पूरी तरह श्रीमती गांधी का साथ दिया था। सुब्रह्मण्यम ने श्रीमती गांधी को बताया था कि मारुति के कारखाने की योजना जिस तरह बनायी गयी है उस तरह वह कारखाना कभी नहीं बन पायेगा। उनके सामने ही उन्होंने घटो सजय को यह समझाने की कोशिश की थी कि वह इस योजना में बिडला को अपने साथ ले लें, जिनका खुद अपना मोटर बनाने का कारखाना भी था। सजय को सुब्रह्मण्यम की ये खरी-खरी बातें अच्छी नहीं लगी थी और इस वजह से वह उनसे चिढ़ा चठा था, हालाँकि बहुत बाद में जाकर सजय ने उनकी इसी सलाह पर धमक किया और बिडला को अपने कारखाने में साथ ले लिया।

इमर्जेंसी को लागू हुए अभी दो महीने से कुछ ही ज्यादा वक्त गुजरा था। लेकिन इतने ही दिन में श्रीमती गांधी की देवताओं की तरह पूजा कराने का सिल सिला शुरू हो गया था। सारे देश में जगह-जगह उनकी तस्वीरें लगायी गयी और उनका बीस-भूत्री कामनाम मंत्र की तरह जपा जाने लगा। सभी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों में 'इन्दिरा स्टडी सेंकल' सगठित किये गये और इन्दिरा क्रिगेड में वासुदेवरा की भरती तेज हो गयी।

मराहूर चित्रकार हुसन ने श्रीमती गांधी का दबी के रूप में जो चित्र बनाया था वह सरकारी तौर पर सारे देश में दिखाया जा रहा था। इमर्जेंसी की दबी श्रीमती गांधी को दुर्गा की तरह बाप पर नहीं बल्कि एक बिकरे हुए दहाड़ते घोर पर सवार

दिखाया गया था।

कांग्रेस की सरकारी पत्रिका सोशलिस्ट इण्डिया में श्रीमती गांधी के बारे में पहले से अधिक लेख छपने लगे। एक लेख का शीर्षक था "हमें श्रीमती गांधी पर पूरा भरोसा और विश्वास क्यों रखना चाहिए।" उनकी प्रशस्ति में लेख सभी जगह छपने लगे। विदेशी पत्र पत्रिकाओं में जो लेख छपते थे उनकी नकलें बनवाकर दूसरे पत्र-पत्रिकाओं में छापने के लिए बड़े पैमाने पर भेजी जाती थी। कनाडा की एक पत्रिका में प्रकाशित लेख का शीर्षक था "प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की समझदारी भारत की समझदारी है।"

श्रीमती गांधी ने खुद एक हिंदी पत्रिका के लिए एक लेख लिखा था—मेरी सफलता का रहस्य। इसमें उन्होंने बताया था कि बचपन में एक बार जब उनकी अध्यापिका ने उनसे पूछा था कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहोगी तो उन्होंने जवाब दिया था कि 'मैं जोन ऑफ आर्क बनना चाहती हूँ।' इतिहास यह बात तो लिखेगा ही कि आतिशयवादी वह क्या बन गयी।

उपादातर पत्रिकाएँ, खास तौर पर छोटे प्रकाशन सरकारी विज्ञापन के सहारे चलने की वजह से इसी रास्ते पर लग गये, अखबार भी या बिल्कुल सरकारी गजट बन गये या श्रीमती गांधी की चापलूसी करने लगे। लेकिन इण्डियन एक्सप्रेस जैसे कुछ दैनिक अखबारों ने सेंसरशिप का मुकाबला करने की कोशिश की तो सरकार ने उन पर तरह तरह से दबाव डालना शुरू कर दिया। इस अखबार के मालिक बहादुर मारवाड़ी रामनाथ गोएनका को धमकी दी गयी कि अगर वह चुपचाप घुटने नहीं टेक देंगे तो उनके बेटे और उनकी बहू को मीसा में पकड़वा दिया जायेगा और उनके सारे अखबार नीलाम करवा दिये जायेंगे। गोएनका को भ्रष्ट से बचने के लिए इण्डियन एक्सप्रेस का छोड़ ऑफ डायरेक्टर्स नये सिरे से बनाकर उसमें उपादातर सरकार के लोग रखने पड़े। वे० वे० बिठला जो सजय गांधी के बहुत निकट थे, उसके चैयरमन बना दिये गये।

स्टैंडसमन को इस बात का सजा दी गयी कि वह अपने पहले पेज पर श्रीमती गांधी की काफी तस्वीरें नहीं छापता था। इस अखबार को आदेश दिया गया कि वह अपने सारे पेजों के प्रूफ मजूरी के लिए सेंसर के पास भेजा करे। ये प्रूफ जान-बूझकर सुबह साठ बजे भेजे जाते थे ताकि अखबार वक्त पर न छप सके और उसकी बिक्री गिरती जाये।

बहरहाल, अखबार कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं थे। उनका गला पूरी तरह घोट दिया गया था। सजय का ध्यान गर कानूनी इमारतों को डाने या दिल्ली को 'सुन्दर बनाने' के कार्यक्रम पर लगा हुआ था। राजधानी में फुटपाथों पर दूकानें लगानेवाला पर पाव-दी लगा दी गयी थी। जामा मस्जिद के पास के छोटे छोटे छोखे तक ढा दिये गये थे। इन दूकानदारों से, जो बीसिया बरस से वहाँ अपना कारोबार चला रहे थे कहा गया कि वे शहर के बाहर अपनी दूकानें लगायें—लेकिन वहाँ गाहक कहाँ से पाते।

जामा मस्जिद से हटाये गये दूकानदार इंदर मोहन के पास गये। वह सूचना और प्रसार मंत्रालय में काम करते थे और पहले भी कई बार उनकी मदद कर चुके थे। इंदर को बताया गया कि सारा फसला सजय के हाथ में है। इंदर सजय के पास गया लेकिन उन्होंने टका सा जवाब दे दिया। उसी दिन रात को ग्यान्ह पुलिसवाला इंदर के घर में घुस आये और उन्हें मार पीटकर घसीटत हुए बाहर ले गये। जब इंदर ने अपनी गिरफ्तारी की खबर सूनी तो उनको बताया गया कि इसका हुक्म बहुत से आया है। बाद में उनको फिर बहुत बुरी तरह पीटा गया और तीन दिन बाद

एक वकील ने उ ह छुड़वाया ।

सजय साबित करना चाहता था कि कोई भी उसके रास्ते में न आए और यह बात उसने बहुत कामयाबी के साथ साबित कर दी । मकान और दुकानें ढाय जान का जो थोड़ा बहुत विरोध पहले हो भी रहा था वह भी बंद हो गया । लेकिन जब अप्रैल 1976 में तुकमान गेट के इलाके में घर गिराने का सिलसिला शुरू हुआ तो एक बार फिर बहुत बड़े पमाने पर विरोध शुरू हुआ ।

करनाल, रोहतक, भिवानी और गुडगांव में गरीब लोगों की भुग्गी भोपडियां ढा दी गयीं और उन्हें रहने के लिए कोई दूसरी जगह भी नहीं दी गयी । प्रकेले लखनऊ में कोई दस हजार इमारतें गिरायी गयीं होगी, मदिरा मस्जिद तक को नहीं बचसा गया ।

शायद जामा मस्जिद के आस पास घर और दुकानें गिराये जाने पर जा गुस्सा था उसी के सिलसिले में मस्जिद के इमाम न नमाज के वक्त अपने भुरीदो स कहा कि वे नादिरशाही हुकूमत के फरमानों को न मानें । 15 अगस्त के दिन जब श्रीमती गांधी लाल किले के फाटक पर से भाषण दे रही थी उसी वक्त लाल किले के ठीक सामने मस्जिद के ऊपर लाउडस्पीकर लगवाकर इमाम भी तक्बीर करके उनसे टक्कर ल रहे थे ।

इमजेंसी लागू होने के आठ हफ्त बाद अगस्त के महीने में सजय ने अपनी ताकत आजमाना शुरू किया । उसने सोचा कि अब मुझमें खुद इतनी ताकत है कि लोगो को उसे तस्लीम करना चाहिए और उसने कई बातों के बारे में अपने विचार लोगों के सामने रख देना ही बेहतर समझा ।

नई दिल्ली की एक पत्रिका सज के साथ एक इण्टरव्यू के दौरान उसने कहा कि वह उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ है, अघतंत्र पर किसी तरह के नियंत्रण के खिलाफ है । वह इस बात के पक्ष में था कि टक्का में कमी की जाय (जा बान म हुई) और दंग की आर्थिक हालत मजबूत बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा जिम्मेदारी सौंपी जाय । उसके दक्षिणपथी विचारों को सभी जानते थे और उस कम्युनिस्टा से नफरत थी । उसने कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बुरा भला कहा और गण कम्युनिस्ट पार्टी को जिस तरह काम कर रही थी उसमें भी बहुत-सी खराबियां गिनायी । उसने कहा ' मैं नहीं समझता कि इनसे ज्यादा मालदार और भ्रष्ट लोग आपका बही और मिल सकते हैं ।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ झुकाव रखनेवाले मंत्री चन्द्रजीत यादव ने श्रीमती गांधी से अगले दिन कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी में इस बात पर बहुत तत्परता मची हुई है । ताज्जुब की बात तो यह है कि इसके साथ ही उन्होंने यह मुभाव दिया कि सजय को खूबकर राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए और यह भी कहा कि श्रीमती गांधी का उस पार्टी के अंदर कोई काम सौंप देना चाहिए । श्रीमती गांधी ने कहा कि उसे राजनीति से पार्ई दिलचस्पी नहीं है । उन्होंने उसकी इण्टरव्यू में कही गयी बातों की नफाई दंत हुए कहा कि वह काम करता हूं, मिर्फ सोचता नहीं है ।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बुरा लगा । इस पार्टी का सिर्फ इसलिए श्रीमती गांधी का भरपूर साथ दे रही थी कि उनका झुकाव सोवियत गुट की तरफ था और ऊपर उनका बेटा न सिर्फ दक्षिणपथियों का खयाल अपना रहा था बल्कि कम्युनिस्टा पर भी हमले कर रहा था । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध का श्रीमती गांधी पर पसर हुआ । समाचार न सजय के इण्टरव्यू का जो पूरा स्पीरा प्रकाश को भेजा था वह आपस ले लिया गया । सिर्फ इण्डियन एक्सप्रेस ने उस छपाया था ।

सत्रय ने 28 अगस्त को इण्डियन एक्सप्रेस को अपनी सफाई देते हुए एक बयान भेजा जिसमें कहा गया था, "एक पूरी पार्टी के खिलाफ सभी पर लागू होने वाली ऐसी बात कहने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जाहिर है कि स्वतंत्र पार्टी, जनसम और भारतीय लोकदल में इसमें भी ज्यादा मालदार लोग हैं और उनमें इससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार है। मुझे गुस्सा इसलिए आया कि मैंने सुना है कि कुछ लोग जो अपने का माक्सवादी समझते हैं और यह जताते हैं कि वे दूसरों से बड़कर हैं, वे बहुत पैसवाले हैं और ईमानदार भी नहीं हैं।"

उस दिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सत्रय के बीच ठग गयी। श्रीमती गांधी जानती थी कि सत्रय को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से चिठ है, लेकिन वह भ्रमर उससे कहा करती थी कि अगर वे लोग 'हमारी शर्तों पर हमारे साथ रहना चाहते हैं, तो इसमें हमारा नुकसान ही क्या है?'

उनको अपनी चिन्ता जयप्रकाश की वजह से थी जो भारत की तैत्तिक अंतरात्मा बन चुके थे और महात्मा गांधी के आदर्शों के सच्चे उत्तराधिकारी बन गये थे। उन्हें गांधीजी के आखिरी शिष्य और जयप्रकाश के राजनीतिक गुरु आचार्य विनोबा भावे का ध्यान आया जो उस समय 81 वर्ष के थे। वह 7 सितम्बर को नागपुर के पास पवणार में उनसे मिलने गये। बाबा न जयप्रकाश की गिरफ्तारी पर चिन्ता प्रकट की और कहा कि उन्हें बिना किसी छत के रहना पड़ा। अपना एक साल का मोन-व्रत बीच ही में भंग करके उन्होंने श्रीमती गांधी से कहा कि उनके जीवन की आखिरी इच्छा यही है कि उनके और जयप्रकाश के बीच मेल हो जाये।

आचार्य विनोबा भावे ने खुलेआम इससे झगड़ा कुछ नहीं कहा कि इमजेंसी 'अनुशासन पत्र' है। सरकार ने उनकी इस राय को नारा बना लिया, यहाँ तक कि डाक टिकटो पर लगायी जान वाली मुहर में भी यही नारा लिखा जाने लगा।

वह सरकार की चाल समझ गये और उन्होंने पवणार में आचार्यों की सभी बुनायी। उन्होंने उनसे देश की मौजूदा स्थिति पर निष्पक्ष भाव से सोच विचार करके 'मुक्त भार शांति' स्तान के लिए एक 'अनुशासन' की योजना तयार करने को कहा।

सचमुच बड़े कमाल की बात थी कि भाति भाति के लोगों के इस समुदाय में, जिनमें बाइस वासलर, जज समाजसेवक और लखन सभी थे सबकी राय एक थी। तीन दिन की यातचीत के बाद 1,000 शब्दों का जो बयान जारी किया गया उसमें हर बात साफ-साफ और दोटूक ढंग से कही गयी थी और बीच का रास्ता अपनाया गया था। इसमें अब तक जो कुछ हुआ था उससे लिए किसी को दोष नहीं दिया गया था। एक तरफ तो उसमें इमजेंसी लागू होने के बाद से उद्योग धर्म और शिक्षा के क्षेत्रों में जो कई 'रचनात्मक' सुधार हुए थे उनकी सराहना की गयी थी। दूसरी ओर इसी बयान में यह भी कहा गया था कि अधिशास और सवधम सम्भावना में विश्वास रखनेवाले बहुत से सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्तियों का अनिश्चित काल के लिए नजरबंद कर दिया जाना देश के वर्तमान के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी।

आचार्यों के इस बयान पर श्रीमती गांधी इतना आनंदित थी कि श्रीमन्नारायण को, जो आचार्य विनोबा भावे का सदैव केर दिल्ली आया थे, एक हफ्ते तक मिलने का कोई बख्त ही नहीं दिया गया। विनोबा न श्रीमती गांधी से कोई भगड़ा नहीं किया बल्कि उन्होंने मौजूदा अगड़े का जल्द ही कोई हल निकालने के लिए आचार्यों और बुद्धिजीवियों की जो एक और बड़ी मीटिंग बुनायी थी उसको रद्द कर दिया।

कुछ बुद्धिजीवियों ने विरोध प्रकट करने का एक और रास्ता अपनाया। वे राजपाट में गांधीजी की समाधि पर 2 अक्टूबर को गांधी जयन्ती के दिन जमा हुए

और वहाँ उन्होंने इमर्जेंसी के खिलाफ नारे लगाये। विरोध प्रकट करनेवालों में 85 वर्ष के बूढ़े गांधीवादी जे० बी० कृपलानी भी थे। उन्हें पहले तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। केरल में गांधी जयन्ती के दिन दूर दूर के गाँवों तक में पोस्टर लगाये गये जिनमें जनता से कहा गया था कि 'भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के सामने वह कार्यरता न दिखाये।'।

उस दिन एक घटना ने श्रीमती गांधी को दहला दिया। एक मादमी, जिसके पास चाकू था, मिक्सीरिटी वालों की नज़र से बचकर राजघाट की प्राधाना-सभा में उनके पास आकर बैठ गया। रेल उपमन्त्री हट्टे-कट्टे काफी कुरेशी ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने इसकी जाँच का हुक्म दे दिया लेकिन साथ ही उनकी रक्षा के लिए मिक्सीरिटी के बंदोबस्त में अब 2,000 मादमी तनात कर दिये गये।

गांधी जयन्ती के दिन कामराज की मृत्यु भारत के लिए सबसे बड़ा धक्का था।

इमर्जेंसी से कामराज को सबसे ज्यादा दुःख पहुँचा था। वह कई बार कह चुके थे कि श्रीमती गांधी डिक्टेटर बनने के रास्ते पर भागे बंद रही हैं लेकिन उन्होंने कभी यह सोचा भी नहीं था कि वह सचमुच डिक्टेटर बन जाएँगी। जसा कि मरने से लगभग एक साल पहले उन्होंने मुझसे कहा था, उनकी डर यह था कि अगर प्रायिक और राजनीतिक एकता लाने में देर की गयी तो उत्तर और दक्षिण एक-दूसरे से अलग हो जाएँगे। इमर्जेंसी से यह समस्या टल भले ही गयी हो पर वह हल नहीं हुई थी। दरमिसल, मरने से कुछ ही दिन पहले कामराज ने अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों को बताया था कि इमर्जेंसी के दौरान उनके लिए करने का कुछ रह ही नहीं गया था, जयप्रकाश और श्रीमती गांधी के बीच समझौता कराने का काम भी वह नहीं कर सकते थे क्योंकि श्रीमती गांधी किसी पर भरोसा ही नहीं करती थी।

जयप्रकाश से उन्होंने एक बार कहा था कि उन्हें श्रीमती गांधी पर रती भर भरोसा नहीं रह गया है। जूबि कामराज डी० एम० के० और भन्ना डी० एम० के० दोनों ही के विरोधी थे इसलिए उनके वास्तविक दाँव-पेंच करने की भी ज्यादा गुंजाइश नहीं रह गयी थी। जसा कि जयप्रकाश ने 3 अक्टूबर को अपनी डायरी में लिखा, "वह जानते थे कि श्रीमती गांधी जैसे छल-कपट करनेवाले नेता को भन्ना डी० एम० के० के साथ समझौता कर लेने में कोई सकोच नहीं होगा, और इससे वह बहुत डरते थे। इसलिए, फिलहाल तो उनका रवैया यही था कि भगला चुनाव 'मक्केले' अपने बल पर' लड़ा जाये।'

श्रीमती गांधी को इस बात की बहुत ख़बरत थी कि दक्षिणी भारत उनका साथ दे। वह जानती थीं कि उत्तर में लोग इमर्जेंसी में बहुत नाराज़ हैं। कामराज के मरने के बाद उन्होंने यह 'सावित' करने के लिए एडी चौदी का जोर लगा दिया कि दोनों के बीच जो घनवन थी वह दूर हो गयी थी और दोनों एक-दूसरे के बहुत निकट आ गये थे। यह बात सच नहीं थी लेकिन कामराज से पूछने की नज़र आती थी। श्रीमती गांधी ने कहा कि कामराज तमिलनाडु की संगठन कांग्रेस का उनकी कांग्रेस के साथ मिला देने के लिए तैयार थे। यह सच है कि इमर्जेंसी से पहले कामराज इस बात के लिए राजी थे कि पूरे देश में साठन कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर एक हो जायें, लेकिन इस बात पर कि हर राज्य में संगठन कांग्रेस के नेताओं को बड़ी कांग्रेस में कोई पद दिया जायेगा।

तमिलनाडु में लोगों पर इस बात का गहरा असर पड़ा कि कामराज के दाह-संस्कार में भाग लेने के लिए वह खास तौर पर हवाई जहाज़ से मद्रास गयी थी, और

कुछ लोग यकीन भी करने लगे कि उन्होंने कामराज के बापस में बसे भान की जो बात नहीं थी वह सच थी, और अगर वह कुछ दिन और जिंदा रहत तो ऐसा हो भी जाता। बाद में जब सोवसभा के चुनाव हुए तो लोगो के इस ढंग से सोचन से उन्हें बहुत मदद भी मिली।

दिल्ली के तिहाड़ जेल में उस दिन रात को जेल का सुपरिण्टेण्डेंट तीन सौ अफसरों और कदियों को लेकर दनदनाता हुमा बाढ़ न० 15 में घुस आया और उसने नजरबन्द कदियों को डराने धमकाने की कोशिश की। उसने सोचा कि इन नजरबन्द कदियों की सीधी सादी माँगों का 'जवाब देने के लिए गांधी जयन्ती से अच्छा और कौन दिन हो सकता है। इन लोगो की माँगें बहुत सीधी थी—पाखाने पेशाब के लिए बहतर सुविधाएँ दी जायें इलाज का बेहतर इतजाम हो और खाने, कपड़े और मुलाकात के मामल में जेल के कायदे कानूनों पर अमल किया जायें, और अदालत में या अस्पताल ले जाते वक़्त उनको हथकड़ी न डाली जायें। तिहाड़ जेल के नजरबन्द कदियां न 3 अक्टूबर को भी अपनी भूल हठताल जारी रखी। चरणसिंह राजनारायण और नानाजी देशमुख न इन माँगों में उनका साथ दिया।

सरकार कुछ नरम पड़ी और उसने नजरबन्द कदियों की कुछ माँगें मान ली। लेकिन नजरबंदी के कायदे और भी सख्त कर दिये गये। 18 अक्टूबर को एक बार फिर भीसा के कानून में हेर फेर किया गया और सरकार के लिए अब यह जरूरी नहीं रह गया कि वह इस कानून के तहत की गयी गिरफ्तारियों की वजह किसी को बताये अदालतों को भी नहीं। यह आर्डिनंस पिछली सारीख 29 जून से लागू कर दिया गया ताकि जो लोग इस वक़्त भी जेलों में बन्द थे वे अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अदालतों में कोई करियाद न कर सकें। यह कदम 13 सितम्बर को मेरी रिहाई के बाद उठाया गया था जब दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि सरकार अदालत को इस बात के बारे में संतुष्ट नहीं कर पायी है कि कुलदीप नयर को आतंरिक सुरक्षा कानून के अनुसार कानूनी ढंग से नजरबन्द किया गया है। 'ब्रिटिश समाचार एजेंसी रायटर की खबरें भेजने की लाइन 9 अक्टूबर को काट दी गयी क्योंकि उसने सेंसर के नियमों को तोड़कर यह खबर और कुछ और खबरें भेज दी थी। लाइन दुबारा वापस लगवाने में तीन महीने लग गये।

भीसा में और ज्यादा सख्ती और रायटर की लाइन काट दिये जाने से विदेश में यह भाषना और बढ़ गयी कि भारत तेजी से खुली डिक्टेटोरशिप की तरफ बढ़ रहा है। अमरीका में वाशिंगटन में भारतीय राजदूत टी० एन० कोल की कोठी के पास भारतीय छात्रों ने स्वतंत्रता का माच करके प्रदर्शन किया। कोल ने मौका बमोका इमर्जेंसी के पक्ष में सफाई दी थी और यहाँ तक धमकी दी थी कि भारत ने अपना देश का जा जनतंत्र बनाया है उस में मानने पर अमरीका को एक दिन पछताना पड़गा। उहाँ भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को लिखा कि जो छात्र इमर्जेंसी के गुण नहीं गात थे उनकी छात्रवर्तियां बन्द कर दी जायें। उन्होंने कुछ छात्रों के पासपोर्ट भी रद्द कर दिये क्योंकि वे 'भारत को बदनाम करने पर तुल हुए थे।

शिकागो में जीवन के सभी क्षेत्रों के लगभग सौ लोगो ने जिनम वकील, डाक्टर इंजीनियर व्यापारी और छात्र सभी थे गांधीजी की एक बहुत बड़ी 10 फुट लम्बी और 6 फुट चौड़ी तमबीर लेकर प्रदर्शन किया। तमबीर में गांधीजी जजीरा से जकड़े हुए थे जिसका मतलब यह लिखाना था कि अगर वह जिंदा होत तो वह भी जेल में होते।

चह्वाण 9 अक्टूबर को शिकागो में थे, उन्हें बड़ी मुसीबत का सामना करना

पड़ा। उनके भाषण में रुई बार लोगो न शोर मचाया, 'मुर्दावाद' के नारे लगाये गये। जब यह ऐलान किया गया कि मंत्री महोदय सिर्फ लिखकर पूछे गये सवालो का जवाब देंगे तो दशका ने बहुत हल्ला मचाया। इससे पहले गुवाग की एक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि "भारत में जनतन्त्र न सिर्फ यह कि भरा नहीं है बल्कि अब उसमें पहले से ज्यादा जान और खुस्ती आ गयी है।"

जेनेवा में गिरजाधरो की विश्व परिषद ने 23 अक्टूबर को श्रीमती गांधी से 'जनता का स्वतन्त्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का जनतांत्रिक अधिकार लौटा देने' का अनुरोध किया। परिषद के जनरल सेक्रेटरी ने एक पत्र में इस बात पर भी 'बुद्धि प्रकट किया कि राजनीतिक लोगो को मुकदमा चलाये बिना कद कर रखा गया है और जोर देकर यह दावा कही कि इमर्जेंसी के दौरान सरकार ने जो अधिकार अपने हाथ में ले रखे हैं वे 'मानव अधिकारो में बहुत गम्भीर कटौती का सबूत हैं। श्रीमती गांधी ने इसके जवाब में कहा कि संविधान में जिस तरह बनाया गया है कि 'कौन-सा काम किससे पहले किया जाये उस क्रम से' इमर्जेंसी पूरी तरह मेल खाती है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात पहले कही गयी है और राजनीतिक न्याय की बात बाद में।

यह बात बहुत से लोगो को ठीक नहीं लगी लेकिन अब उनके पाँच भार भी मजबूत हो चुके थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून को चुनाव के दो अपराधों की बुनियाद पर उनके खिलाफ जो फैसला दिया था उस सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून को सभी जजों की एकमत राय से उलट दिया। हाईकोर्ट ने श्रीमती गांधी पर जो यह पाबन्दी लगायी थी कि वह छ साल तक किसी ऐसे पद पर नहीं रह सकती जिसके लिए चुनाव जीतना जरूरी हो वह भी रद्द कर दी गयी।

पाँच जजों की बेंच का यह फैसला मुकदमे के तथ्यों की बुनियाद पर नहीं बल्कि चुनाव कानून में अग्रस्त में संसद में जो हेर फेर किया गया था उसकी बुनियाद पर दिया गया था। इस तरह श्रीमती गांधी दण्ड से बिल्कुल मुक्त हो गयी।

सुप्रीम कोर्ट ने तीन जजों के खिलाफ पाँच जजों की राय में संसद में अग्रस्त के किये गये उस विशेष सशोधन का वह हिस्सा भी रद्द कर दिया जिसमें प्रधानमंत्री के चुनाव के बारे में कोई फैसला देने का अधिकार अदालतों से छीन लिया गया था। इस फैसले से राजनारायण की यह बात सही मान ली गयी कि किसी को इतनी व्यापक छूट का अधिकार देना संविधान की भावना के खिलाफ है।

इन पाँच जजों में से एक जज एम० एच० बग ने जिन्हें उनकी बारी आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया था, इस मुकदमे में दोनों पक्षाओं की ओर से पत्र की गयी बाता की खूबियों और खामियों को छानबीन की, क्योंकि उनका कहना यह था कि मामले का फैसला उस कानून की बुनियाद पर होना चाहिये जो हाईकोर्ट के फैसले के वक्त लागू था। वह इस नतीजे पर पहुँचे कि हाईकोर्ट जिन नतीजों पर पहुँचा था वे बिल्कुल गलत थे। जस्टिस बग ने कहा कि ऐसा लगता है कि 'विद्वान जज महोदय को शायद इस बात का जख्खरत से ज्यादा आभास था कि वह इस देश के प्रधानमंत्री के मुकदमे का फैसला कर रहे हैं।' इसलिए उनकी (जस्टिस बग की), जसा कि उन्होंने अपने फमले में बताया भी इस बात की बड़ी फिन्न थी कि इस बात का असर उनके फैसले पर न पड़ने पाये। फिर भी जब सबूतों को परखने का वक़्त आया तो उन्होंने कहा "मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सबूतों का खरापन परखन के लिए एव जसी कसौटियाँ इस्तेमाल नहीं की, और इस तरह चुनाव याचिका दाखल करनेवाले (राजनारायण) को उस बहुत भारी जिम्मेदारी से छुटकारा दे दिया, जो

उस पक्ष पर होती है जो भ्रष्ट तरीक़े अपनाते का आरोप लगाकर मतदाताओं के फ़सले को चुनौती देता है। "

श्रीमती गांधी की पार्टी न इस जीत पर बड़ी खुशियाँ मनायी और कहा, "जनता के रास्ते की पूरी तरह जीत हुई। यह फैसला जनतांत्रिक ताकतों की जीत है।" लेकिन उनके विरोधियों ने बहुत कटुता के साथ यह कहा कि भ्रष्टालत के फसले की बुनियाद इस बात पर रखी गयी थी कि ससद ने श्रीमती गांधी की पार्टी की माँग पर चुनाव के कानून को बिलकुल नये सिरे से एक नये ही सचि में ढाल दिया था और उन्हें यह नया कानून बनने से बहुत पहले की तारीख से ही बरी कर दिया था।

इस फैसले के कुछ ही समय बाद सरकार ने चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट के उस पिछले फैसले पर भी फिर से विचार किया जाय जिसमें सचि धान के बुनियादी ढाँचे में हेर फेर करने के ससद के अधिकार पर कुछ हदें लगा दी गयी थी। इसमें सलग हाईकोर्टों सरकार के कई कानूनों और अधिनियमों के खिलाफ लगभग 300 रिट इस बुनियाद पर दायर थे कि ये कानून सविधान के बुनियादी ढाँचे से मेल नहीं खाते। नमून के लिए आन्ध्र प्रदेश का एक मुकदमा लिया गया। एटॉर्नी-जनरल नीरेन डे ने यह दलील दी कि 1973 वाले फैसले में यह बात साफ-साफ नहीं बयान की गयी थी कि सविधान की बुनियादी विशेषताएँ क्या हैं और उस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए ताकि ससद को यह मालूम हो सके कि उसकी हैसियत क्या है। पालकीवाला ने आरोप लगाया कि 'किसी भी भारतीय भ्रष्टालत के सबसे ऐतिहासिक फैसले' पर उस फसले के मुनामे जाने के दो ही साल के अन्दर फिर से विचार कराने की बोशिश करके सरकार ने 'भद्दी किस्म की जल्दबाजी' का सबूत दिया है।

सुनवायी के तीसरे दिन के बाद चीफ जस्टिस ने अचानक तरह जजों की बेंच भंग कर दी। उन्हें पता चल गया था कि क्यानाल जज फैसले पर दुबारा विचार करने के पक्ष में नहीं हैं। यह सरकार की हार थी—कई महीने में पहली बार।

घुन के पक्षे वकीलौ न अपने काम का दायरा और बढ़ा दिया। उन्होंने नजर-बंद कदिया की रिहाई के लिए और जेलों की हालत सुधारने के लिए हजारों रिट दायर किए।

आतिभूषण बगसीर में कर्नाटक के हाईकोर्ट में ब्रह्मवाणी, भटलबिहारी बाजपयी, मगठन काग्रेंस के एस० एन० मिश्रा और सोमसिस्ट नेता मधु दण्डवते की पैरवी कर रहे थे। इमजेंसी लागू होने के वक्त ये लोग कर्नाटक में थे। आतिभूषण ने कहा, "हम पूरी इमजेंसी का और सरकार की तरफ से उठाये गये कदमों को चुनौती दे रहे हैं और इस बात को भी कि यसार कानून किस तरह श्रमिकों या श्रमिकों के कदमों के मुताबिक उस गम्भीर खतरनाक साजिश के हिस्से हैं जिसकी वजह से इमजेंसी लागू करने की जरूरत पड़ी।"

श्री और वकील, जिन्होंने नजरबंद कदिया के मुकदमे पीस लिये बिना लठ्ठार वृत्त नाम बमामा व ये वी० एम० तारकुटे, जो पहले बम्बई हाईकोर्ट के जज रह चुके थे और बम्बई के ही साली सोराबजी। तारकुटे ने सिटिजस फार इन्फोनेसी नामक एक मस्यौदा को भी सत्रिय किया। इस मस्यौदा में बुनियादी अधिकार वापस किये जाने की माँग करने के लिए कई नीतियों की। उसने 12 अक्टूबर का अहमदाबाद में एक जनवार्ता किया जिसमें एम० सी० छागला न जो बम्बई के चीफ जस्टिस रह चुके थे सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व चीफ जस्टिस जे० सी० शाह ने, तारकुटे मीनू मसानी और बरु द्रमरे वकीलौ न आपण लिये।

कनवेरान का उदघाटन करते हुए छागला ने कहा, "भाज जो लोग जेल में हैं उनमें से ज्यादातर को यह भी नहीं मान्य है कि वे वहाँ क्यों हैं और वे अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि जहाँ किसी चीज़ को बदला न जा सकता हो वहाँ सफाई देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वे और किसी भद्रालत के सामने भी नहीं जा सकते क्योंकि वे सब चीज़ें तो सब बंद हो गयी हैं।"

उनके इस भाषण की वजह से बड़ीदा के साप्ताहिक भ्रष्टाचार भूमिपुत्र और महात्मा गांधी के कायम किये हुए नवजीवन ट्रस्ट के प्रेस को बर्दा मुसीबत का सामना करना पड़ा। भूमिपुत्र के प्रेस पर ताला डाल दिया गया। मामला हाईकोर्ट तक गया और उसके जजों ने सेंसर के आदेशों के कुछ हिस्सों को गरवानूनी ठहराया। यह फैसला भी सब तक नहीं छपने दिया गया जब तक कि खुद हाईकोर्ट ने इसको छापन की आज्ञा नहीं दे दी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 'किसी नागरिक की आजादी के पक्ष में किसी भद्रालत का कोई भी फैसला किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता।'

नवजीवन ट्रस्ट के प्रेस ने, जहाँ से भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई के दिनों में महात्मा गांधी अपने भ्रष्टाचार यग इण्डिया और हरिजन छपवात थे, भूमिपुत्र के मुकदमे के बारे में एक छोटी-सी किताब छपी। पुलिस ने प्रेस पर छापा मारकर उस पर ताला डाल दिया और उसे छ दिन तक बन्द रखा। प्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट से फरियाद की। एक वक्त ऐसा आया जब नवजीवन ट्रस्ट के प्रेस के सामने यह सुझाव रखा गया कि उस प्रेस में जो कुछ भी छपे अगर पहले सेंसर से उसकी मजूरी ले लेने के लिए प्रेस तैयार हो जाये तो सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। प्रेस के मैनेजर जितेंद्र देसाई ने कहा कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि स्वतंत्र भारत की सरकार ने एक ऐसी सस्था पर ताला डलवा दिया है जिसे गांधीजी ने देश की आजादी हासिल करने के लिए कायम किया था।

कांग्रेस के कुछ वकीलों ने 8-9 नवम्बर को कर्नाटक राज्य वकील सम्मेलन का आयोजन किया। प्रचार यह किया गया था कि यह सम्मेलन गरीबों को कानूनी मदद देने के सिलसिले में किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए 1,00,000 रुपये की मजूरी भी दी थी लेकिन सम्मेलन करनेवालों की असली मशा थी इमर्जेंसी के पक्ष में एक प्रस्ताव पास करना। बहुत से ऐसे वकीलों को, जो खुलेआम कांग्रेस के खिलाफ थे, डेलीगट नहीं बनाया गया। 1,800 में से केवल 600 वकीलों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। फिर भी जब श्रीमती गांधी को सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील में कामयाब होने की बधाई देने का प्रस्ताव सम्मेलन में रखा गया तो पता यह चला कि केवल 10 वोट उसके पक्ष में थे और 590 खिलाफ थे।

यह सच है कि यह कर्नाटक की एक भ्रष्टाचारी घटना थी, लेकिन सारे देश में वकीलों के तबरे बहुत बिफरे हुए थे। वकालतम्यानों में वे इमर्जेंसी की ओर उसमें साथ जुड़ी हुई हर चीज़ की खुलेआम निंदा करते थे।

कुछ वकील इस नतीजे की परवाह किये बिना कानून के शासन के लिए लड़ते रहे। कितन ही जजों ने भी, जिनमें से ज्यादातर हाईकोर्ट के थे, सत्ताधारियों के समझाने-बुझाने की कोई परवाह नहीं की। मिसाल के लिए, श्रीमती पद्मा देसाई ने अपने समुद्र मोरारजी देसाई से मुलाकात के लिए भद्रालत में भर्ती दी, लेकिन मीसा में नजरबंद बंदिया की नजरबंदी की शर्तों के बारे में जो नियम बनाये गये थे वह वही देखो के मिलते ही नहीं थे। दिल्ली के गजट में वे छपे जरूर थे लेकिन उसकी गव 'खतम हो गयी थी'। दो उत्साही जजों, जस्टिस रमराजन और जस्टिस

सामने इस भर्जी की सुनवाई हुई और उन्होंने पूरे घामह के साथ यह बात कही कि सरकार के खुफिया हुकम कानून पर हावी नहीं हो सकते और उन्होंने नजरबंद कैदियों के साथ मुलाकात और पत्र-व्यवहार के बारे में इन नियमों की स्वावट खानन वाली धाराओं को रद्द कर दिया। थोमसी सत्या धर्मा की भर्जी पर, जिनके पति एस० डी० धर्मा ने भी भीमसेन सच्चर की भर्जी पर दस्तखत किये थे, यह कसला दिया गया कि इसजैसी के दौरान भी हर सरकारी कारवाई को किसी कानून की मुनियद पर जायज साबित करना जरूरी है। इलाहाबाद के चीफ जस्टिस के० बी० प्रस्थाना ने, एक प्रोफेसर की नजरबंदी के बारे में धक जाहिर करते हुए कहा कि किसी गिरफ्तारी को जायज साबित करने के लिए सिर्फ सरकार के बठमुत्सापन के ऐलान ही काफी नहीं हैं।

बम्बई में जस्टिस जे० प्रार० विमदलाल और जस्टिस पी० एस० शाह ने महाराष्ट्र के नजरबंदों की शर्तों वाले आदेश में से खुराक मुलाकात और इलाज से सम्बंध रखनेवाली सारी शर्तें रद्द कर दीं। उन्होंने कहा, 'नजरबन्द कदी घाम अपराधी जैसा नहीं होता है और नजरबन्द करने के अधिकार का मतलब दण्ड देने का अधिकार नहीं है।' और यह कि 'किसी भी नजरबन्द कदी पर जो भी पाबंदियाँ लगायी जायें वे कम से कम होनी चाहिये, बस इतनी जितनी कि उसे नजरबन्द रखने के लिए काफी हो।'।

महाराष्ट्र के ऐक्टिंग चीफ जस्टिस बी० डी० तुलजापुरकर न पुलिस के उन हुकम को रद्द कर दिया जिनके जरिये सविधान में नागरिक स्वतन्त्रताओं और कानून के शासन की समस्याओं पर विचार करने के लिए बुलायी गयी बकीला की एक प्राइवेट मीटिंग पर पाबन्दी लगा दी गयी थी। उन्होंने कहा, 'कोई भी सरकार जो खुली बहुसंख्यक इसजैसी की शान्तिपूर्ण और रचनात्मक भावोचना का भी दवा देती हो, कोई भी सरकार जो सिर्फ खुशामदियों और चापलूसों के लिए स्वतन्त्रताएँ बाँकी रखती है और कोई भी सरकार जो अपने पुलिस के सबसे बड़े भ्रष्टरा को इस बात की इजाजत देती है कि वे उनके नागरिकों को अपने उन कामों के लिए भी, जो घाम तौर पर किये जाते हैं, जिनके पीछे कोई छिपा हुआ उद्देश्य नहीं होता है और जिनमें कोई खतरा नहीं होता है, पहले इजाजत लेने पर मजबूर करके अपमानित और बेइज्जत करती है, उसे इस बात का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वह सारी दुनिया के सामने यह ठिठोरा पीटे कि इस देश में जनतन्त्र बाकी है।'।

लेकिन ऐसी मिसालें इक्का-दुक्का ही थीं। कम से कम 400 मुखदमे ऐसे थे, जिनमें मधु निमय का मुखदमा भी शामिल था जिनमें मुद्दे की अपनी बात कहने तक का मौका दिए बिना ही, एकतरफा सुनवाई करके गड़बड़कर सारिज कर दिया गया कि उसे वापस ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट प्रॉडर बड़ी बेरहमी के साथ एन उस वक्त दिये जात थे जब छात्र-कैदियों का परीक्षा देने का मौका निकल चुका था। बम्बई के मयर का चुनाव भी लगभग टल ही गया था।

जाहिर है कि सरकार की कारवाइयों से बकीला न अपना रास्ता नहीं छोड़ा। 7 अप्रैल को, जिस वक्त कि इसजैसी की लहू सबसे ऊंची थी और सयस खतरनाक हो चुकी थी, दिल्ली के हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन ने मजय गांधी के चहुत डी० डी० बावला को हराबर प्राणनाम लेखों को चुना जो उस वक्त तिहाड़ जेल में तनहाई की वद बात रहे थे। जिस बार एसोसिएशन ने भी बायोमी उम्मीदवार के खिलाफ एक और बायो बकील कैबलाल 'गर्मा' को चुना।

यह मजय के लिए खुली चुनौती थी। उसने जिला बाट और सेशन कोर्ट के

वकीलो के, लगभग एक हजार वकीलो के, वकालतखाने तोड़ देने का हुक्म दे दिया। जिस वक्त बुलडोजर इन इमारतों को ढा रहे थे, उस वक्त चारों घोर पुलिस का पहरा था।

चूँकि उस दिन छुट्टी थी इसलिए कोई वकील वहाँ या नहीं। लेकिन खबर फैली तो सारे वकील दोखतावर अपना सामान बचाने के लिए भागे भागे वहाँ पहुँचे। उन्हें बड़ी बेरहमी से खदेड़ दिया गया, और कुछ के पीछे तो पुलिस इतनी बुरी तरह पड़ी कि वे लगभग एक महीने तक छिपे रहे। अगले दिन बार एसोसिएशन के मेम्बरों का एक दल इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए चीफ जस्टिस टी० वी० प्रार० ताताचारी से मिला। तेतालोस वकीला को, जो एक ही बस पर सफर कर रहे थे, फौरन गिरफ्तार कर लिया गया—24 को मीसा में और 19 को डी० आई० प्रार० में। केन्द्रीय सरकार के गृह और आवास राज्यमंत्री एच० के० एल० भगत ने एक और डेलीगेशन से कहा कि शायद डी० डी० ए० के साथ 'किसी रजिस्ट्री की वजह से' ही उनके वकालतखाने ढाये गये हैं। मोम मेहता ने एक तीसरे दल को यह यकीन दिलाया कि अब और कोई तबाही नहीं होगी।

लेकिन अगले ह्दवार को भी डी० डी० ए० ने 200 और वकीलों के कैंबिन तोड़ डाले। बाकी बचे हुए लगभग 500 वकालतखाने छुट्टियों के दौरान बड़ी बेरहमी से वहाँ से हटा दिये गये। शाहदरा और पालियामेंट की फौजदारी की अदालतों में भी सरकार की तरफ से इसी तरह की गुण्डागर्दी की गयी। कुल मिलाकर अठ्ठावन वकील जेल में दस दिये गये। उनमें से सिर्फ एक अशोक सापरा को रिहा किया गया। वह पुलिस के डी० आई० जी० (जेल) का बंटा था और उसे रात के बदन चुपचाप छोड़ दिया गया था।

लेकिन वकीलों की बात और थी। बाकी लोग हमजैसी को कमोबेश जिन्दगी का ठर्रा समझने लगे थे। कुछ तो 'शांति और अनुशासन' के गुण भी गाते थे। कॉलेजो-यूनिवर्सिटियों में छात्र भी, जिनसे जयप्रकाश को बड़ी-बड़ी उम्मीदें थी, कमोबेश चुप हो गये थे।

ऐसा नहीं है कि उन्होंने विरोध किया ही नहीं था। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों ने अगस्त में एक दिन की और सितम्बर में तीन दिन की हड़ताल की। दूसरी यूनिवर्सिटियों की तरह यहाँ भी खुफिया पुलिसवाला की भरमार थी। जब पन्द्रह छात्रों को जो यूनिवर्सिटी में भरती किये जान के लिए हर तरह से योग्य थे दाखिला देने से इन्कार कर दिया गया तो छात्र यूनियन के प्रेसिडेंट ने इसके खिलाफ आवाज उठायी। वाइस चांसलर ने उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 500 अध्यापक और छात्र गिरफ्तार किये गये जिनमें एक युवक नेता अरुण जेटली भी था। दिल्ली के कुछ छात्रों को उनके स्कूला से दो साल के लिए निकाल दिया गया था। हाईकोर्ट ने उन्हें फिर से स्कूल में वापस लेने का हुक्म दिया। कुछ पुलिस इसपेक्टरो ने कॉलेजो और यूनिवर्सिटियाँ भी नाम लिखवा लिया था।

नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में 19 नवम्बर को एक विरोध प्रदर्शन हुआ। इसमें सबसे आगे आगे चौदह से सत्रह वर्ष की उमर तक के चौबोस लड़के थे। उनमें से दो लड़कों ने अफटकर माइक्रोफोन ले लिया और जोर से चिल्लाये, "इंदिरा, हम तारी जेलों को भर देंगे, पर तेरे अत्याचार के आगे कभी सर नहीं झुकायेंगे।"

लेकिन विरोध के इन छुटपुट प्रदर्शनों के बाद छात्र और अध्यापक दोनों ही एक ऐसी जिन्दगी बिताने लगे जो उन्हें पसंद तो नहीं थी लेकिन क्या करते, वह एक नयी हकीकत थी।

उही दिनों अण्डरग्राउण्ड से एक पर्चा बाँटा गया था, जिसमें भारत की दशा बहुत सही सही बयान की गयी थी

सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। ऐसा लगता है कि देश की ऐसी दुदशा इसमें पहले कभी नहीं थी। स्वाध बेहद बढ़ गया है। अब कोई पार्टी नहीं रह गयी है। एक भादमी की हुकूमत है। बाकी सब लोग अब उसके हाथ के सिलोने हैं। आम लोगो और सरकार के छोटे बड़े अफसरों की ज़बान पर ताला लग गया है और उनमें कुछ भी करने की ताकत नहीं रह गयी है। जनता कराह रही है।

लेकिन उसकी बात सुननेवाला और उसे बचानेवाला है कौन ? शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी हासत हो सकती है। लोगो की चेतना हमजैसी के डर के नीचे दबकर रह गयी है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब इंदिरा गांधी को इस बात का एहसास होता जा रहा है कि उन्होंने क्या हालत पैदा कर दी है। रोज नये नये भाडिनेस जारी किये जा रहे हैं। अब वह खुद भी और उनका बेटा सजय गांधी मिलके ही सरकार चला रहे हैं। अब सरकार की बागडोर गुण्डों के हाथ में है। देश इस मुसीबत से कस उबरेगा, यह कोई नहीं जनता।

लोगो लोग नेलों में हैं। उनके परिवारवालों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बहुत से लोगो की नौकरियाँ छिन गयी हैं। कितने ही सबको की पढाई छट गयी है। यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजों के बहुत-से अध्यापक इस समय जलो में बन्द हैं। बूढ़े नौजवाना और बच्चों तक को डराया धमकाया जा रहा है। अब खुभा पुलिस राज है। उनकी बेरहमी और उनकी जुम अब बर्दाश्त के बाहर होत जा रहे हैं।

कोई आर्थिक लाभ भी तो नहीं हुए था। श्रीमती गांधी अभी तक यह नहीं साबित कर पायी थी कि भारत जते गरीब देशों की दरिद्रता की दलदल से बाहर निकलने के लिए रहमदिल निरंकुश शासकों की जरूरत होती है। सब तो यह है कि देश में आर्थिक बदइल्लजामी की शुरुआत 1966 में उनकी सरकार बनते ही हो गयी थी, जब उन्होंने रुपये का भाव घटा दिया था।

अगर हम थोक कीमतों के मामले में बुनियाद 1950-51 के साल की बनायें जिस साल से योजनाओं का दौर शुरू हुआ था और यह मान लें कि उस साल कीमतों का स्तर 100 था, तो उसके बाद के पन्द्रह वर्षों में वह 148 तक पहुँच गया था यानी 48 फीसदी बढ़ गया था। 1966-67 से जिस साल श्रीमती गांधी ने शासन की बाग डोर अपने हाथों में संभाली थी 1974-75 तक थोक कीमतों का स्तर 148 से बढ़कर 351 तक पहुँच गया था। मतलब यह कि उनके शासन के नौ वर्षों के दौरान कीमतें 137 फीसदी से ज्यादा बढ़ी थी।

दूसरी तरफ 1950-51 में देश में 20 अरब 16 करोड़ रुपये के नोट चल रहे थे, 1965-66 में यह रकम बढ़कर 45 अरब 30 करोड़ रुपये तक पहुँच गयी थी यानी लगभग पन्द्रह साल में दुगने से कुछ अधिक। लेकिन 1965-66 और 1974-75 के बीच यह रकम 115 अरब रुपये हो गयी। किसी भी पैमाने से नापन पर यह बहुत तेज रफ्तार की।

जहाँ तक कारखाना की पदावार का सवाल था 1966 में वह 153 प्वाइंट तक

पहुँच चुका था। (इसी पैमाने पर 1951 में यह उत्पादन 55 प्वाइंट पर था।) मतलब यह कि औद्योगिक उत्पादन हर साल लगभग 6.5 फीसदी की रफ्तार से बढ़ रहा था। 1965-66 और 1974-75 के बीच वह 208 प्वाइंट तक पहुँचा, जिससे यह पता चलता है कि हर साल औद्योगिक उत्पादन सिर्फ 4 फीसदी से भी कम की रफ्तार से बढ़ रहा था। और सो भी तब जबकि लगातार फसल अच्छी होने की वजह से काफी राहत मिल गयी थी।

1950-51 में बचत कुल राष्ट्रीय आमदनी की केवल 5.7 फीसदी थी, इतने नीचे स्तर से बढ़कर 1965-66 में वह 13.3 फीसदी तक पहुँच गयी थी। लेकिन 1965-66 और 1974-75 के बीच यह दर लगातार गिरती ही गयी और फिर कभी पहलेवाले स्तर तक नहीं पहुँच सकी। वह 11 से 13 प्रतिशत के बीच घटती-बढ़ती रही। सबसे ज्यादा पूँजी 1966-67 में लगायी गयी जब कुल राष्ट्रीय आमदनी का 15.3 फीसदी फिर पूँजी के रूप में लगा दिया गया था। इसके बाद के वर्षों में यह दर लगातार गिरती ही गयी। 1968-69 में तो वह गिरत गिरते 10.2 फीसदी तक पहुँच गयी और 1974-75 में भी वह इससे बहुत अधिक नहीं थी।

बहुत ही कम बचत, सीमित नयी पूँजी, सुस्त उद्योग, प्रचलित मुद्रा में तेजी से बढ़ती और 1973-75 में सूखे के वर्षों के दौरान खेती की पैदावार में बेहद कमी का नतीजा आर्थिक संकट के भलावा और हो ही क्या सकता था। 1974 और 1975 में देश की आर्थिक संकट का सामना करना ही पड़ा। ऐसा लगता था कि उनकी आर्थिक मजबूरियाँ ऐसी थी कि इमर्जेंसी जैसी कोई चीज लागू किये बिना थीमती गांधी का काम नहीं चल सकता था।

थीमती गांधी को सहारा इस बात से मिला कि 1975-76 में जितनी अच्छी फसल हुई उतनी उससे पहले कभी नहीं हुई थी। उस साल 12 करोड़ 8 लाख टन घनाज पैदा हुआ था जबकि उससे पहलेवाले साल 1974-75 में कुल पैदावार 9 करोड़ 98 लाख टन हुई थी। फिर स्मंगलरो के खिलाफ मुहिम चलायी गयी थी, जिसकी वजह से स्मंगलिंग के घाघे में न सिर्फ जोखिम बढ़ गया था बल्कि वह महंगा भी पड़ने लगा था। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल जैसे चोटी के स्मंगलरा सहित 288 स्मंगलर गिरफ्तार कर लिये गये थे और 177 की जामदारें जन्म कर ली गयी थी। 1 जुलाई को एन ऑर्डनेंस जारी किया गया जिसके अनुसार अब यह जरूरी नहीं रह गया कि जो लोग विदेशी मुद्रा की बचत और स्मंगलिंग की रोकथाम के कानून में पकड़े जायें उन्हें उनकी गिरफ्तारी की वजह बतायी जाये। अगर देश के हित में उन्हें नजरबन्द रखना जरूरी समझा जाय तो उनका मामला सलाहवार बोर्ड के सामने भेजने की भी जरूरत नहीं थी। (गाम्नी देवी इसी कानून में पकड़ी गयी थी।)

सरकार ने रुपये के भाव को किसी विदेशी मुद्रा के भाव के साथ बाँधकर न रखने का भी फैसला किया ताकि विदेशों में रहनेवाले हिंदुस्तानी अपना पैसा सरकारी रास्तों से भेज सकें क्योंकि काले बाजार में भी भाव कुछ बेहतर नहीं था। अब इस तरह हर साल 80 करोड़ रुपये के बजाय 2 अरब रुपये आने लगा।

सीमा के जरूरी वजह से कारखानों में भी शान्ति थी। कोई हड़ताल करने का मोर्चा नहीं दिया जाता था और अगर कोई हड़ताल होती भी थी तो पुलिस बीच में पड़कर उस 'तय' करा देती थी। इसमें ट्रेड यूनियन तो नहीं गुन थे लेकिन मिल मानिव बहुत गुन थे। ट्रेड यूनियनवाले या भी कुछ करने में डरते थे। जिस वस्तु बोनस कानून रह किया गया और मासिका के लिए यह जरूरी नहीं रह गया कि नुक्सान होते हुए भी वे मासिकी तौर पर तनखाह का 8.33 फीसदी बोनस दें, उन

बहुत जरूरी है।

हालाँकि यह पत्र 10 मार्च 1975 को लिखा गया था, लेकिन उसमें 'कतव्य घोर जिम्मेदारी' की बात कही गयी थी—वही बात जो इमर्जेंसी के दौरान श्रीमती गांधी अपने हर भाषण में कहती थी।

उनके इस पत्र से लोग ताज्जुब से चौंक पड़े और लोगो में खलबली मच गयी। कुछ दिन तक सेक्रेटेरियट ने बरामदों में यह भ्रष्टाचार गूँजती रही कि कुछ बुनियादी परिवर्तन और सुधार होनेवाले हैं। प्रधानमंत्री के आदेशों के अनुसार हर विभाग और हर मंत्रालय में इसके बारे में दीर्घ घूँप हाने लगी। कई कबिनेट के मंत्रियों और मुख्य-मंत्रियों ने इसके जवाब में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शासन की समस्याओं के बारे में उनकी 'दूरदर्शिता और गहरी समझ बूझ' के लिए उनकी प्रशंसा करने के बाद—यह रस्म तो उन्हें पूरी करनी ही पड़ती थी—कुछ और विचार और सुझाव अपनी तरफ से रखे।

श्रीमती गांधी ने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया, उन्होंने उनको पढ़ा तक नहीं। सारे खत उनके सेक्रेटेरियट और कबिनेट सेक्रेटरी के पास भेज दिये गये। इसके बाद किसी ने उनके बारे में कुछ भी नहीं सुना।

लेकिन जब उन्होंने 25 अप्रैल को एक दूसरा खत लिखकर उन्हें सभी स्तरों पर प्रशासन को चुस्त करने के बारे में अपने पिछले खत की याद दिलायी तो कबिनेट के सभी मंत्री और मुख्यमंत्री दंग रह गये। उन्होंने इससे साथ 'प्रशासन की काय कुशलता में सुधार' के बारे में एक लम्बा चौड़ा चौदह पन्ने का नोट भी तैयार कर दिया जिसे एत० पी० सिंह और एल० के० भा ने तैयार किया था, जो ऊँचे सरकारी पदा से रिटायर हो चुके थे। उन्होंने एक बार फिर मंत्रियों से प्रशासन को सुधारने और निजी तौर पर ध्यान देने के लिए कहा और प्रशासन को चुस्त और फुर्तीला बनाने के लिए उनसे और सुझाव माँगे। एक बार फिर सेक्रेटेरियट में उनके इस खत की चर्चा होने लगी। हर मंत्री ने अपने बड़े बड़े भ्रष्टारों के साथ कई कई बार मीटिंगों की और हर सेक्रेटरी ने अपने सभी भ्रष्टारों के साथ उन पर पूरा भरोसा करके बातचीत की। हर पंद्रह दिन में एक बार इस सिलसिले में की गयी कारबाई की रिपोर्ट कबिनेट सेक्रेटरी को भेजनी थी। नतीजा वही रहा—सरकार की मशीनरी टस से मस नहीं हुई बाम काज के वही लम्बे चक्करदार तरीके और कमचारियों में वही जात पाँत का भेद-भाव।

लेकिन इमर्जेंसी का सहारा लेकर सरकार ने केन्द्र के 200 भ्रष्टारों को और राज्यों में और भी बहुत सारे भ्रष्टारों को रिटायर कर दिया। 1960 के बाद से यह कानून चला आ रहा था कि पचास साल की उम्र के बाद निरुद्धि कमचारियों की छुट्टी की जा सकती है। जो भ्रष्टार कोई गैर कानूनी काम करने से इन्कार करते थे उनको सजा देने के लिए इस कानून बहुत काम आया।

श्रीमती गांधी अपने घेरे और उसके गुर्गों के साथ मिलकर शासन करके बहुत सतुष्ट थी। एक तरफ तो कीमता में कुछ ठहराव आ गया था और 'ये नोट छापते जाने की जरूरत लगभग विलुप्त' हो गयी थी और दूसरी ओर प्रशासन भी 'बढ़ना मानने लगा था। इन बातों की वजह से श्रीमती गांधी और सजय का अपने ऊपर भरोसा बढ़ गया। अब वे लोग कुछ जोखिम भी मोल ले सकते थे।

यहाँ वह वक़्त था जब श्रीमती गांधी ने कुछ दिन के लिए जयप्रकाश का छोड़ देने की बात सोची। उनके स्वास्थ्य के बारे में जो खबरें आ रही थी वे कुछ अच्छी नहीं थी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो लाग चुप नहीं बैठेंगे। वे श्रीमती गांधी को और उनकी सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे।

वक्त लगभग सभी ट्रेड यूनियन चुप बैठे रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ धोर मचाया लेकिन सिर्फ अखबारों में।

कारखानों में शांति और 'कुछ कर दिखाने' की सरकार की कोशिशों की वजह से कारखानों को अपनी बेकार पड़ी हुई क्षमता को भी इस्तेमाल करने में मदद मिली। इसका एक और नतीजा हुआ—भरमार। ज्यादातर मिल मालिक शिकायत करने लगे कि उनका माल खरीदन के लिए काफी ग्राहक ही नहीं हैं और माल जमा होता जा रहा है। सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया, उसको सिर्फ यह फिक्र थी कि ताला बन्दी या बैठकों न होने पाये। और किसी चीज का कोई महत्व नहीं था।

इसके लिए क्या हमजैसे की जरूरत थी? सब तो यह है कि जो भी काम याची मिली थी उसका ज्यादातर हिस्सा कारोबारी ढंग से सोचनेवाले उद्योग मंत्री टी० ए० पर्ई की उन कोशिशों का नतीजा था जो उन्होंने 1974 में मंत्री बनने के बाद से की थी। हमसलरा के खिलाफ भी 1974 से ही मुहिम चलायी जा रही थी, जब गणेश बिस्म मंत्रालय में राज्यमंत्री थे।

हमजैसे व। नौकरशाही के निवर्त्येपन और सुस्ती पर कोई खास असर नहीं हुआ। श्रीमती गांधी ने केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्यों की सरकारों को कमजोर करके बहुत-सी ताकत अपने सेक्रेटेरियट के हाथों में सौंप दी थी। उनका सेक्रेटेरियट मंत्रियों और मंत्रालयों के साथ लगे हुए स्पेशल असिस्टेंटों, आई० ए० एस० के अफसरों और प्राइवेट सेक्रेटेरियों के जरिये रक्षा मंत्रालय में एस० के० मिश्रा वाणिज्य मंत्रालय में एन० के० सिंह और सूचना मंत्रालय में बी० एस० त्रिपाठी जैसे लोगों के जरिये—सरकार की पूरी मशीनरी को अपनी मुट्ठी में रक्खता था। धीरे धीरे उनके हाथों में असली ताकत आती गयी और वे पालिसियाँ बनाने लगे। सचय उनकी उनका पहला नाम लेकर पुकारता था।

सब पूछा जाये तो श्रीमती गांधी को प्रशासन को सुधारने में कभी सजीदगी से दिलचस्पी थी ही नहीं। पहले तो उन्होंने यह बहाना बनाकर इस काम को टाला कि मोरारजी की अध्यक्षता में प्रशासन सुधार समीशन ने कुछ सिफारिशें की थी, जिनकी छानबीन भारत सरकार के सेक्रेटेरियों ने अभी नहीं की है। जब इस धीमी रफ्तार की आलोचना की गयी तो उन्होंने इन सिफारिशों को अंतिम रूप देने के काम पर तीन मंत्रियों की एक टोली को लगा दिया—मोहन कुमार मगसम डी० पी० घर और टी० ए० पर्ई। कई सम्बन्धी पेपर और सुभाव तयार किये गये लेकिन सबको उठाकर ताक पर रख दिया गया।

यह समझा जाता था कि इस पूरी व्यवस्था को बनाये रखने और चलाने के लिए उनका सेक्रेटेरियट, असल असल मंत्रालयों में काम करनेवाले स्पेशल असिस्टेंट और 'रों' के लोग काफी हैं। लेकिन जनता के सामने अपने भाषणों में और फाइला पर अपनी छुटपुट टिप्पणियों में वह सरकारी काम-काज की धीमी रफ्तार में अपनी दिल चम्पी दिखाती रही और उस पर चिन्ता प्रकट करती रही।

उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों और कबिनेट के मंत्रियों को सभी स्तरों पर प्रशासन का अस्त-व्यस्त के लिए एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा, 'हम बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। कुदरती बात है कि जिन लोगों के हाथ में सरकार का काम-काज चलाने की जिम्मेदारी है उनमें जनता उम्मीद रखती है। आसस, सापरवाही या अनुशासन होना की बात मुझमें नहीं है। हर आत्मी को अपना काम पूरी मुस्तदी से साप करना चाहिये। हर दर्जे के सरकारी नौकरों के अखबार हैं। बिना बतव्य और जिम्मेदारी के बिना अधिकार का सवाम हा पन नहीं हो सकता। कारणर नतृत्व

बहुत जरूरी है।

हालांकि यह पत्र 10 मार्च 1975 को लिखा गया था, लेकिन उसमें 'कृतव्य और जिम्मेदारी' की बात कही गयी थी—वही बात जो इमर्जेंसी के दौरान श्रीमती गांधी अपने हर भाषण में कहती थी।

उनके इस पत्र से लोग ताज्जुब से चौंक पड़े और लोगों में खलबली मच गयी। कुछ दिन तक सेक्रेटेरियट के बरामदे में यह अफवाह गुजती रही कि कुछ बुनियादी परिवर्तन और सुधार होनेवाले हैं। प्रधानमंत्री के आदेशों के अनुसार हर विभाग और हर मंत्रालय में इसके बारे में दौड़ घूम होने लगी। कई कैबिनेट के मंत्रियों और मुख्य-मंत्रियों ने इसके जवाब में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शासन की समस्याओं के बारे में उनकी 'दूरदर्शिता और गहरी समझ वृद्ध' के लिए उनकी प्रशंसा करने के बाद—यह रस्म तो उन्हें पूरी करनी ही पड़ती थी—कुछ और विचार और सुझाव अपनी तरफ से रखे।

श्रीमती गांधी ने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया, उन्होंने उनको पढ़ा तक नहीं। सारे खत उनके सेक्रेटेरियट और कैबिनेट सेक्रेटरी के पास भेज दिये गये। इसके बाद किसी ने उनके बारे में कुछ भी नहीं सुना।

लेकिन जब उन्होंने 25 अप्रैल को एक दूसरा खत लिखकर उन्हें सभी स्तरों पर प्रशासन को चुस्त करने के बारे में अपने पिछले खत की याद दिलायी तो कैबिनेट के सभी मंत्री और मुख्यमंत्री दंग रह गये। उन्होंने इसके साथ 'प्रशासन की काय कुशलता में सुधार' के बारे में एक लम्बा चौड़ा चोट्टा पत्र का नोट भी तैयार कर दिया, जिसे एल० पी० सिंह और एल० के० झा ने तैयार किया था, जो ऊँचे सरकारी पदों से रिटायर हो चुके थे। उन्होंने एक बार फिर मंत्रियों से प्रशासन को सुधारने और निजी तौर पर ध्यान देने के लिए कहा और प्रशासन को चुस्त और पुर्तिला बनाने के लिए उनसे और सुझाव माँगे। एक बार फिर सेक्रेटेरियट में उनके इस खत की चर्चा होने लगी। हर मंत्री ने अपने बड़ बड़े अफसरों के साथ कई-कई बार मीटिंगें की और हर सेक्रेटरी ने अपने सभी अफसरों के साथ उन पर पूरा भरोसा करके बातचीत की। हर पंद्रह दिन में एक बार इस सिलसिले में की गयी कारबाई की रिपोर्ट कैबिनेट सेक्रेटरी को भेजनी थी। नतीजा वही रहा—सरकार की मशीनरी टस से तस नहीं हुई, काम काज के वही लम्बे चक्करदार तरीके और कमचारियों में वही जात पाँत का भेद भाव।

लेकिन इमर्जेंसी का सहारा लेकर सरकार ने केन्द्र के 200 अफसरों को और राज्यों में और भी बहुत सारे अफसरों को रिटायर कर दिया। 1960 के बाद से यह कानून चला आ रहा था कि पचास साल की उम्र के बाद निरक्षर कमचारियों को छेड़नी की जा सकती है। जा अफसर कोई गैर कानूनी काम करने से इस्फार करते थे उनकी सजा देने के लिए इस वक्त यह कानून बहुत काम आया।

श्रीमती गांधी अपने बेटे और उसके मुर्गों के साथ मिलकर शासन करके बहुत सतुष्ट थी। एक तरफ तो कीमतों में कुछ ठहराव आ गया था और नये नोट छापते जान की जरूरत लगभग बिलकुल खत्म हो गयी थी और दूसरी ओर प्रशासन भी 'कहना मानने लगा था। इन बातों की वजह से श्रीमती गांधी और सजय का अपने ऊपर भरोसा बढ गया। अब वे लग कुछ जाखिम भी भोल ले सकत थे।

यही वह वक्त था जब श्रीमती गांधी न कुछ दिन के लिए जयप्रकाश को छोड़ देने की बात सोची। उनके स्वास्थ्य के बारे में जो खबरें आ रही थी वे कुछ अच्छी नहीं थी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो लोग चुप नहीं बैठेंगे। वे श्रीमती गांधी का और उनकी सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे।

एक वक़्त तो जयप्रकाश की हालत इतनी नाजुक हो गयी थी कि उनके अंतिम सस्कार की भी तैयारी कर ली गयी थी। भगवारा ने उनका शोक समाचार भी तैयार कर लिया था। न जाने क्या विद्याचरण शुक्ल ने यह आदेश दिया था कि जयप्रकाश के बारे में जो कुछ लिखा जाये उसमें इस बात का कोई जिक्र न किया जाये कि उनके और नेहरू के बीच दोस्ती थी।

उनका स्वास्थ्य तो खराब था ही, इसके अलावा श्रीमती गांधी को यह भी पता चला था कि जयप्रकाश बहुत निराश हो चुके हैं और जनता के साथ और देश के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके लिए अपने को दोषी समझते थे। उनके नवनीयत सेक्रेटरी पी० एन० धर ने, जिन्होंने हकसर के बाद यह पद संभाला था, सलाह भगवारा करने के बाद गांधी अध्ययन सस्थान (इंस्टीच्यूट ऑफ गांधी स्टडीज) के सुमतदास गुप्ता को जयप्रकाश से मिलकर उनके विचार मालूम करने के लिए भेजा। धर का कहना यह था कि जयप्रकाश और श्रीमती गांधी किसी 'गलतफहमी' की वजह से एक-दूसरे से अलग हटते गये हैं और उस गलतफहमी को 'दूर किया जा सकता है'। दास गुप्ता को ऐसा लगा कि जयप्रकाश पिछली बातों के बारे में सोच विचार करने की मुद्रा में हैं। सच बात तो यह है कि अपनी गिरफ्तारी के बाद पहली बार जयप्रकाश को दास गुप्ता से इस बात की एक पूरी तसवीर मिली कि देश में क्या हुआ था और उससे उन्हें बहुत कुछ हुआ।

जयप्रकाश बाढ़ पीड़िता की मदद करने के लिए पटना भी जाना चाह रहे थे। ऐसा कर सकने के लिए उन्होंने 27 भगस्त को एक महीने के लिए परोल पर छोड़ दिये जाने की प्रार्थना भी की थी। इसके जवाब में श्रीमती गांधी ने कृपि मन्त्रालय के सेक्रेटरी बलबीर चौहान को उन्हें विस्तार के साथ यह बताने के लिए भेजा था कि पटना के लोगो को राहत पहुँचाने के लिए क्या-क्या किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने गाँधी के बारे में कुछ नहीं बताया जिससे जयप्रकाश को बड़ी चिंता हुई।

लेकिन 17 मितम्बर को जो पत्र लिखा, उसमें उन्होंने केवल बाढ़ का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कहा था, 'न सिर्फ यह कि बिहार में बाढ़ की स्थिति विगड़ गयी है, बल्कि देश के दूसरे हिस्सा में भी बाढ़ आयी है। ऐसे वक़्त में किसी के कोई आंदोलन या सभ्य छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर यह मान भी लिया जाये कि राजनीतिक इमर्जेन्सी की कभी कोई जरूरत भी थी तब भी वह तो अब खत्म हो चुकी है और अब उसकी जगह इसाना की मुसीबत की एक इमर्जेन्सी आ गयी है, जिसका मुकाबला करने के लिए सारे देश को मिलकर खोर लगाना चाहिए।'।

श्रीमती गांधी ने इस खत में जितना कहा की कोशिश की गयी थी उससे कहीं ज्यादा उसका मतसब लगाया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जयप्रकाश बहुत निराश थे। लेकिन देश को डिक्टेटरशिप से बचाना का उनका एकमात्र इरादा किसी भी तरह कमजोर नहीं हुआ था। श्रीमती गांधी को उनका भ्रम टूट जाने के बारे में जो खबरें मिलती रही थी उनसे भी उन्होंने खबरत स ज्वाण मतसब निबाला। उन्होंने जयप्रकाश को पहले तीस दिन के परोल पर छोड़कर उनकी हरारत को देखन का फैसला किया।

सजय उनके छोड़े जाने के खिलाफ था लेकिन परोल पर छोड़ दिये जान में उसे कोई ख़ास हज़ दिखायी नहीं दिया क्योंकि उस हालत में जयप्रकाश की राजनीति में दूर रहना पड़ेगा। लेकिन जयप्रकाश ने सरकार को यह बात साफ-साफ बना दी थी कि वह फिर सक्रिय रूप से श्रीमती गांधी का विरोध शुरू करने का इरादा रखते हैं।

जयप्रकाश 12 नवम्बर को रिहा किये गये । सरकार ने इसके बारे में एक छोटी-सी खबर प्रसन्नवारो में छपने की इजाजत दे दी । सरकार ने यह भी नहीं बताया कि उन्हें किन शर्तों पर पैरोल पर छोड़ा गया है । उनके राजनीतिक साथियों का कहना था कि उन्हें इसाज के लिए छोड़ा गया है । डॉक्टरों की राय थी कि वह 'गुदों में खराबी' की वजह से बहुत कमजोर हो गये हैं ।

श्रीमती गांधी देखना चाहती थी कि इसके बाद उनका—और जनता का—क्या रवैया होता है । बहरहाल, इस वक्त पलड़ा तो उनका भारी था ही ।

सुरग का छोर

जयप्रकाश ने जनता के चेहरे पर भय छाया हुआ देखा। चटौगढ में उनका स्वागत करने भी बहुत लोग नहीं पाये थे। दो दिन बाद जब वह इंडियन एयरलाइंस के हवाई जहाज से चटौगढ से दिल्ली पहुँचे तो यहाँ भी हवाई अड्डे पर थोड़े ही स लोग थे और उनके नाम भी खुफिया पुलिसवालों ने दर्ज कर लिये थे। गांधी शांति प्रतिष्ठान पर भी जहाँ वह ठहरे थे, बराबर कड़ी नज़र रखी जा रही थी।

अगर श्रीमती गांधी समझती थी कि वह बदल गये हैं तो यह उनकी भूल थी। वह नाइजेरिया के उस कवि और नाटककार वाले सोयिका की तरह थे जिसने दो साल जेल में काटने के बाद अपने ऊपर उसके असर के बारे में कहा था, 'घाप वहाँ से बाहर निकलत समय भी उही सब चीज़ों पर विश्वास रखते हैं जिन पर वहाँ जाने से पहले रखते थे, लेकिन पहले के मुकाबले में ज्यादा पक्का विश्वास।'।

जयप्रकाश ने सुमत से कहा था कि जो कुछ हुआ है उसके बाद घर मुझसे यह उम्मीद तो नहीं रखते होंगे कि मैं श्रीमती गांधी का साथ दूँगा या उनका हाथ बटाऊँगा। अगर चुनाव कराना का ऐलान कर दिया जाता है तो मैं सरकार के साथ टकराव खत्म कर देने की पैरवी करूँगा। दिल्ली पहुँचने के कुछ ही दिन के अन्दर जयप्रकाश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सिर्फ विदेशी सवाददाता मौजूद थे। भारतीय सवाददाता वहाँ जाते हुए इसलिए डरते थे कि वे नज़र में आ जायेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस मुश्किल से पंद्रह मिनट चली होगी, लेकिन जयप्रकाश ने यह बात बिल्कुल साफ कर दी कि तब्योत कुछ संभलते ही वह फिर नतिक सिद्धांता पर आधारित राजनीति में काम करत रहेंगे।

जयप्रकाश ने सवाददाताओं से कहा, 'श्रीमती गांधी ने इसी चीज़ का तो खत्म कर दिया है। हम लोग अंग्रेज़ों के जमाने से बहुत बदल नहीं हैं। श्रीमती गांधी का विरोध करनेवाली ताकतों को एकता की सड़ी में पिरोन में मैं जो भी मदद द सकूँगा दूँगा। मध्यम वर्ग के लोगो व हौसले पस्त हो चुके हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। विपक्ष के लोग जेल में हैं। अखबारों को जज़ीरा में जकड़ दिया गया है। श्रीमती गांधी के मन में सचमुच डर समा गया होगा, वह बहुत काम डर की वजह से करती हैं।

सरकार को जा जानकारी दी गयी थी उससे यह बात बिल्कुल भिन्न थी। खुफिया विभाग के लोगो ने खबर दी थी कि जयप्रकाश में अब काम करने के लिए बहुत दम नहीं रह गया है। उन दिना भर न मुझे नज़ा था जयप्रकाश बिल्कुल माफूस हो चुके हैं और अब पिछनी बातों का याद करत रहते हैं। लेकिन यह उनकी भूल थी। यह अब भी अपने इरादों पर घटन थे।

जब गहमजी उमांगकर दीक्षित और घर उनसे धानचोत करने गये तो उन्होंने देखा कि वह डरा भी उस में मस हान का तयार नती था। जयप्रकाश अपनी माँग पर

पर लाठीचाज भी किया।

सत्याग्रह सारे देश में हुआ और हर राज्य में कुछ न-कुछ गिरफ्तारियाँ जरूर हुईं। दिल्ली में जयप्रकाश के नारा देने के बाद 29 जून को जो सत्याग्रह हुआ था उसमें और इस सत्याग्रह में फकत यह था कि इस बार बहुत से लोग सत्याग्रह देखने के लिए सड़को पर निकल आये थे। पहले कोई इतनी हिम्मत भी नहीं करता था कि उसे कहीं घास पास देखा भी जाये। सत्याग्रही जो पर्चे बाँट पाते थे उन्हें लोग खुशी खुशी लेते थे। पुलिस का रवैया भी एक तरह से पहले से मलम था—वह अब पहले से भी ज्यादा बेरहम हो गयी थी, जैसे कि उसे अब लाठियाँ बरसाने में या जिसे वह अब तक भीड़ सम्भली थी उसे तितर बितर करने के लिए जोर-जबदस्ती करने में कोई क्लिष्ट, कोई सकोच रह ही न गया हो।

सरकार भी ज्यादा-से-ज्यादा निरकुश होती जा रही थी। हालाँकि इमर्जेंसी के दौरान सभी बुनियादी अधिकार स्थगित कर दिये गये थे लेकिन सरकार ने सविधान की 19वीं धारा में जिन मूल अधिकारों की गारंटी दी गयी है उनमें से सात को स्थगित रखने के लिए खास तौर पर आदेश जारी किये—भाषण की स्वतंत्रता, सम्पूर्ण करने की स्वतंत्रता, संगठन और श्रमिक संघ बनाने की स्वतंत्रता, सारे भारत में बिना किसी रोक टोक के कहीं भी जाने-आने और देश के किसी भी भाग में रहने का अधिकार, सम्पत्ति रखने का अधिकार, कोई भी व्यवसाय व्यापार या कारोबार करने का अधिकार।

राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद के दस्तखत से जारी किये गये आदेश में 19वीं धारा को लागू कराने के लिए अदालतों में अपील करने पर भी पाबंदी लगा दी गयी। सविधान में दिये गये अधिकारों पर यह एक नयी रोक लगाने की कोई वजह भी नहीं बतायी गयी। 26 जून 1975 को इमर्जेंसी लागू होने के बाद से यह चौथी रोक थी।

यह उम्मीद की जाती थी कि श्रीमती गांधी शायद लोगों को रिहा करना शुरू कर दें लेकिन उन्होंने बिलकुल उल्टी ही दिशा अपनायी। सत्याग्रह के बारे में जनता ने जो उत्साह दिखाया था शायद उमी की वजह से सरकार विरोध करनेवालों को बहुत चुन-चुनकर सड़नी के साथ कुचल रही थी।

जयप्रकाश की परोल 4 दिसम्बर को ख़त्म कर दी गयी। हालाँकि उन पर से सारी पाबंदियाँ हटा ली गयी थी फिर भी उन पर नज़र रखी जा रही थी। वह जहाँ भी जाते थे खुफिया विभाग के लोग उनके पीछे परछाई की तरह लगे रहते थे। जो लोग उनसे मिलने आते थे उनका हिसाब रखा जाता था उनके पत्रों की ओर जा कुछ भी वह कहते थे उसकी बड़ी गहरी छानबीन की जाती थी। शायद कोई बात निकल आये।

वरना, जसा कि जयप्रकाश ने मुझसे कहा, इस वक़्त श्रीमती गांधी की गुड़ी खड़ी हुई थी। 'उह' दुर्गा कहा जाता था और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि उन्हें खुद विश्वास हो जाता है कि उनमें वह शक्ति है। वह जानती थी कि किस वक़्त क्या वरन से सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। गांव में वह साधारण धोती पहनती थी और सजीली बहुप्री की तरह सर पर पल्ला डाले रहती थी। कश्मीर में वह कश्मीरिया जस कपड़े पहनती थी। पंजाब में वह कुर्ता-सलवार पहनती थी और यह भी कहती थी कि वह पंजाबी है क्योंकि उनकी छोटी बहन सजय की पत्नी मेनका पंजाब की थी। वह दावा करती थी कि वह गुजरात की बहन हैं क्योंकि उनके पति फीरोज गांधी गुजराती थे। वह जानती थी कि ग्राम लागा पर इन सब बातों का बहुत अच्छा असर पड़ता है। और कुछ समय तक तो पडा भी।

ऐसा लगता था कि 'निर्देशित जनतंत्र' का जो ढाँचा उन्होंने खड़ा किया था वह अब टिका रहगा। ऐसा लगता था कि श्रीमती गांधी न जा राजनीतिव हल पेश किये हैं उन्हे देश में बहुत-से लोग स्वीकार करने को तैयार हैं। बहुत-से लोग, खास तौर पर पढ़े-लिखे स्नाते पीत लोग, बिना किसी शर्तोंहया के कहते थे, "हमसे कोई भी काम कराने के लिए हमेशा हम किसी न किसी मालिक की जरूरत रही है। पहले मुगल थे, फिर अंग्रेज आये और अब श्रीमती गांधी हैं। इसमें आखिर ऐसी बुराई क्या है?"

उनकी कृपादृष्टि की बदौलत सजय ने अपना राजनीतिक असर भी बढा लिया था और अपनी सदिग्ध स्थाति भी। दिल्ली आनेवाला हर मुख्यमन्त्री जब तक सजय से नहीं मिल लेता था तब तक वह अपनी यात्रा का सफल नहीं समझता था। वे सभी एक दूसरे से होठ लगाकर उसे अपने राज्य में आन का यौता देते थे और सरकार की ओर से जुटायी गयी बड़ी-बड़ी मीटिंगों से यह साबित करने की कोशिश करते थे कि वह कितना लोकप्रिय है।

श्रीमती गांधी सचमुच समझनी थी कि वह बहुत लोकप्रिय है। एक बार जब चन्द्रजीत यादव न उनसे सिकायत की कि सजय के स्वागत के लिए जो मीटिंगें होती हैं उनमें से ज्यादातर जुटायी हुई होनी हैं, तो वह बुरा मान गयी और बोली, 'कुछ लोग जलते हैं क्योंकि जनता सचमुच सजय को चाहती है।' यूनुस बार-बार यह कहकर कि लाखों लोग उसकी ओर खिंचे चले आते हैं, श्रीमती गांधी के इस विश्वास को और पक्का कर देते थे। यूनुस ने तो खास तौर पर एक लेख भी लिखा, जो कई अखबारों में छपा भी, जिसमें कहा गया था कि भविष्य सजय के हाथ में है। सच तो यह है कि सजय का स्वागत करने के लिए जो भीड़ें जमा होती थी वे सब भाड़े की होती थीं।

लेकिन जो बात श्रीमती गांधी को कभी-कभी बहुत परेशानी में डाल देती थी वह यह थी कि मुख्यमन्त्रियों ने हवाई अड्डा पर आकर सजय का स्वागत करना शुरू कर दिया था। यह बात सिद्धांतशुद्ध न उनसे कही भी थी। बरम्मा की भाफत उन्होंने उन लोगों को हिदायत भी भिजवा दी थी कि वे उनके बैठे का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन पर न आया करें।

लेकिन मुख्यमन्त्रियों ने इस आदेश की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया क्योंकि जब भी सजय किसी राज्य में जाता था तो उसका स्वागत करने के लिए हमेशा की तरह व 'दोबस्त' करने के बारे में एक गद्दी चिट्ठी गृह-मन्त्रालय की ओर से पहले ही भेज दी जाती थी। मन्त्रालय ने सजय की सुरक्षा के बारे में भी हिदायतें दे रखी थी—जिन मीटिंगों में वह भाषण दे, उनमें पब्लिक की पिस्तौल की मार से बचावा दूरी पर रखा जाये और सब के पीछे ऐसा परदा लगाया जाये जिस गोली न बंध सके, बीच की खाली जगह में पुलिस और सिक्योरिटी के घादमी भर दिये जायें। यह इन्तजाम उन सिक्योरिटी वाला के अनावा था जो चौबीस घंटे उसने साथ लगे रहते थे।

सजय अक्सर इंडियन एयर फ़ोर्स के हवाई जहाज से राज्यों के दोरे पर जाता था। सरकारी तौर पर वह किसी मन्त्री का दोरा होता था लेकिन असली यात्री सजय होता था। आम तौर पर हवाई जहाज भ्रम महता के नाम से लिया जाता था। श्रीमती गांधी के जमाने से पहले यह राज्य-मन्त्री को एयर फ़ोर्स का हवाई जहाज इस्तेमाल करने का कभी अधिकार नहीं था, लेकिन भ्रम महता का यह रिमायत उठोने तौर पर दिलवा रखी थी। धवन, और कभी-कभी दोपन, इस बात का इन्तजाम

ये कि हवाई जहाज किसके नाम स लिया जाये। एव-दो बार ऐसा भी हुआ कि एन थवत पर वह मंत्री नहीं गया और सजय प्रवेला ही चला गया।

ज्यादातर मुख्यमंत्री अपने अनुभव से अब यह जान चुके थे कि श्रीमती गांधी चाहती हैं कि वे सजय स सम्पर्क रखें। राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिद्व जोशी को इस बात के लिए लताड़ा भी गया था कि शुरू शुरू में उन्होंने अपने राज्य के किसी मामले के सिलसिले में सजय स मिलन में आनावानी की थी। बाद में जब सजय एक बार जयपुर आ रहा था तो उन्होंने उसके स्वागत के लिए 200 फाटव बनवाकर इसका प्रायश्चित्त कर लिया था। इन तयारिया पर जा आनाप आनाप पैसा खर्च किया गया था उस पर जनता के गुस्से को देखते हुए श्रीमती गांधी ने उसकी यह यात्रा रद्द करवा दी थी। लेकिन जोशी ने अपनी बफादारी साबित कर दी थी।

हित-द्वेसाईं ने, जो पहले मोरारजी के बहुत करीब थे लेकिन अब कांग्रेस में चले गये थे, श्रीमती गांधी के इस इशारे को कि वह सजय से मिलें या ही टाल दिया था। इसलिए जब तक उन्होंने सजय के दरबार में हाजिरी देना नहीं शुरू कर दिया तब तक उन्हें दिल्ली में श्रीमती गांधी से मिलने के लिए हमेशा कई-कई दिन तक लटवें रहना पड़ता था।

शानी जैलसिंह तो घबन को भी घबनजी कहते थे। एक बार हवाई जहाज पर बैठते वक्त सजय की एक चप्पल नीचे गिर गयी। हवाई घट्टे पर जो बहुत-स लोग जमा थे उनकी तरह ही जैलसिंह भी चप्पल उठाने के लिए लपके।

श्यामाचरण शुक्ला जो सेठी की जगह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गये थे, हरदम सजय के आगे हाथ बाँधे खड़े रहते थे। वह बहुत दिन राजनीति के बनबास में काट चुके थे और यह नहीं चाहते थे कि फिर उनकी वही दुश्वा हो। अगर श्रीमती गांधी श्यामाचरण से यही चाहती थी कि वह सजय के दरबार में हाजिरी दिया करें तो वह यह कीमत देने के लिए हर तरह से तैयार थे।

राजनीतिक जोड़-तोड़ सजय के लिए बायें हाथ का खेल था। उसने युवक कांग्रेस के जरिये अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाना शुरू किया। बहुधा ने कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से उससे युवक कांग्रेस में नयी जान डालने के लिए कहा था और वह 10 दिसम्बर का उसमें भरती हो गया था। उसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर झुकाव रखनेवाले पश्चिम बंगाल के नेता प्रियरजन दास मशी का अध्यक्ष के पद से हटवाकर उसकी जगह एक भरोसवाली पंजाबी लड़की अश्विनी सोनी को अध्यक्ष बनवा दिया।

लेकिन सजय को सबसे बड़ी चिन्ता इस बात की थी कि इमर्जेंसी को एक स्थायी व्यवस्था का रूप कैसे दिया जाये। उसकी माँ प्रकसर उसने कहा करती थी कि इमर्जेंसी हमेशा तो लगी रह नहीं सकती, उसकी जगह कोई ऐसी व्यवस्था लानी होगी जो मजबूत हो, जिस पर भरोसा किया जा सके और जो हमेशा टिकी रह सके। सजय ने फिर घुस्पात अखबारों से की। शुक्ला ने रिपोर्ट दी थी कि कमोबंग सभी अखबार और सभी पत्रकार सीधे हाँ गये हैं और उनसे कोई खतरा नहीं रह गया है। अब खुद अपने सेंसर बन गये हैं।

एक फ्राइडनेम जारी करवाकर आजादी से पहले के दिनों का, आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन की रोकथाम वाला कानून फिर लागू कर दिया गया और एने पाटो, बिहो या अन्य अभिव्यक्तियों के प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी गयी 'जो भारत में या उसके किसी राज्य में कानून के आधार पर स्थापित सरकार के प्रति घणा या निरस्कार या अश्रद्धा उत्पन्न करे और उसने पक्षधर या उपद्रव पदा करे

या उपद्रव पैदा करने की प्रवृत्ति को जन्म दे।" ब्रिटिश राज में इसी कानून के तहत जिस प्रादयी पर 'घापतिजनक सामग्री' लिखने का आरोप लगाया जाता था तो उसे किसी पुराने जज के सामने पेश किया जाता था और उस इस बात का अधिकार होता था कि पत्रकारिता या सावजनिक मामलात से सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्तियों की विशेष जूरी के सामने उसने मुकदमे की सुनवाई हो। लेकिन इस प्राडिनेंस में फैसला करने, सजा देन और पहली अपील की सुनवाई का अधिकार सरकार को ही दिया गया था। उसके बाद ही अभियुक्त हाईकोर्ट में जा सकता था।

सरकार को मुद्रका, प्रकाशना और सम्पादका से नकद जमानत तसब करने का भी अधिकार दिया गया था और उन्हें केवल 'मजूर की गयी' सामग्री छापने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। सरकार 'घापतिजनक' समझी जान वाली सामग्री छापने वाले प्रेस को बन्द भी करवा सकती थी।

सरकार के लिए सुविधाजनक सम्पादकों की एक टोली ने मखबारों के लिए नसिक्ता के मानदण्डों की एक सूची तयार की। यह अनोखी सूची थी। 3,000 शब्दों के इस प्रबचन में एक बार भी 'मखबारों की आजादी' का उल्लेख नहीं किया गया था।

सरकार ने पचासीस से अधिक सवादनताओं की मान्यता भी वापस ले ली। पत्रकारों को अपने अपने मखबारों के प्रतिनिधि बने रहने की तो इजाजत दे दी गयी पर बड़ी बड़ी प्रेस कॉफ़ेसों में और ससद की बठक में जाने की सुविधा उनसे छीन ली गयी। (मरा नाम उन लोगों को फेहरिस्त में था जिनके बारे में कहा गया था कि अगर वे मान्यता के लिए मर्जी दें तो उन्हें मान्यता न दी जाये।)

मखबारों की आजादी की रक्षा करने के लिए पत्रकारों और मखबारों से सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे लोगों की जो सस्था, प्रेस कौंसिल आफ इंडिया, दस वर्ष पहले बनायी गयी थी उस तोड़ दिया गया। इसके लिए कृष्णकुमार बिडला ने दबाव डाला था। भारत की मोटर बनाकर तयार कर देने के सिलसिले में बिडलावाले जो मुफ्त सलाह और दूसरी मदद दे रहे थे उसकी वजह से कृष्णकुमार बिडला सजय के बहुत निकट आ गये थे। बिडला के मखबार हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक श्री० जी० वर्गीज की नौकरी खत्म कर दिये जान के खिलाफ प्रेस कौंसिल के सामने जो शिकायत पेश की गयी थी उसमें के० के० बिडला को इस बात की सफाई देनी थी। शिकायत यह की गयी थी कि वर्गीज के खिलाफ जो कारवाई की गयी थी उसके पीछे 'शासक पार्टी' के कुछ ऐसे लोगों का हाथ था जो मखबारों की आजादी के दुश्मन थे।"

कौंसिल में जा बहस हुई थी उससे के० के० बिडला को पता चल गया था कि फसला उनके खिलाफ होगा। और हुआ भी यही, लेकिन फैसला कभी सुनाया नहीं गया। कौंसिल के सदस्यों के साथ बातचीत की बुनियाद पर उसने अध्यक्ष ने फसले का जो मसविदा तयार किया था उसमें यही इशारा मिलता था कि बिडला और हिन्दुस्तान टाइम्स में उनके एक डायरेक्टर की दोषी ठहराया जाता।

फसले के मसविदा में कहा गया था कि वर्गीज का नौकरी से हटाना मखबारों की आजादी और सम्पादकीय स्वतंत्रता का खूला उल्लंघन था। बिडला और वर्गीज के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ था उसे छपने में रुकवान की बिडला ने जो कोशिश की थी उसकी भी प्रेस कौंसिल ने निन्दा की। फसला इसलिए नहीं सुनाया जा सका कि 31 दिसम्बर 1975 को प्रेस कौंसिल तोड़ दी गयी।

पत्रकारों की ससद की कारवाई की खबरें देने के मामले में जो छूट थी वह भी वापस ले ली गयी। सजय डरता था कि ससद में नागरिकों का ड, इपोट लाइसेंस वाड और भारत वाड के बारे में जो कुछ भी कहा जायेगा उसे

उछालेंगे। यह नहीं चाहता था कि फिर कोई सुफान उठाया जाये। मजा तो यह है कि अखबारवालों को सदन के दोनों सदनों की कारवाइयाँ की सबरें बिना किसी रोक-टोक के देने में मदद देने के लिए सज्जम ने पिता फीरोज गांधी न ही एक बिल सदन में पेश किया था। एक वक्त ऐसा भी आया था, जब श्रीमती गांधी चाहती थीं कि इस बिल को बरकरार रहने दिया जाये, लेकिन सज्जम नहीं माना और उसने अपनी बात मनवा ली। उसने कहा कि सरकार के काम-काज में भावुकता की कोई गुंजाइश नहीं है।

अखबार एक तरह से सरकारी गजट बन गये थे। वे खुद अपने ऊपर इतनी सेंसरशिप लागू करने लगे थे कि सरकार की मजूरी लिये बिना जयप्रकाश के स्वास्थ्य के बारे में जारी किये जानेवाले नुलेटिन भी नहीं छापत थे। फिर भी श्रीमती गांधी और उनके बेटे को सतोष नहीं था। इण्डियन एक्सप्रेस ग्रुप के अखबार अभी तक सीपे रास्ते पर आने को तैयार नहीं थे। इसका एक ही ह्मन था कि उन्हें खरीद लिया जाये। और रामनाथ गोएनका से कहा गया कि वह अपना अखबारों का साम्राज्य बेच दें। लेकिन उनके लिए इतने जमे-जमाये कारोबार से, जिसे उन्होंने धूम से बढ़ाकर यहाँ तक पहुँचाया था, हाथ धो लेना इतना आसान नहीं था। वह फँसला करने के लिए कुछ माहलत लेकर इसे टाले रखना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार धामद अपना इरादा बदल दे। माहलत तो मिल गयी, लेकिन जब गोएनका ने देखा कि सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है तो वह भी कुछ ढीले पड़ गये और एक रात पर अखबारों को बेच देने पर राजी हो गये। रात यह थी कि उन्हें इसकी बाजब कीमत दी जाये और वह भी 'सर्पेंद पैसे' में। वह जानते थे कि यह मुमकिन नहीं होगा।

गोएनका टेढ़ी खीर बनते जा रहे थे। उनको खरीदना बहुत महँगा सौदा हो रहा था। दूसरा रास्ता यह था कि बोट के तेरह डायरेक्टो को किसी तरह काबू में रखा जाये। सज्जम ने सोचा कि बेहतर यही होगा कि बोट को ही बदलवा दिया जाये। के० के० बिडला का चेयरमैन बना दिया गया और कमलनाथ को, जो दून स्कूल के दिनों से सज्जम का दोस्त था, छ में से एक मेंबर बना दिया गया। इस तरह बोट में सरकार का बहुमत हो गया। नये बोट ने पहला काम यह किया कि एडीटर इन चीफ मुलगाँवकर को जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया। कहने का तो इसकी वजह यह बतायी गयी कि वह रिटायर होने की उम्र को पहुँच गये थे, लेकिन असली वजह यह थी कि सरकार अपने आदमी को एडीटर बनाता चाहती थी। दो और पुराने पत्रकार अजित भट्टाचार्य और मैं भी निकाले जाने वाले थे लेकिन गोएनका ने किसी तरह टलवा दिया।

सरकार को इण्डियन एक्सप्रेस के तेवर अब भी पसंद नहीं थे। सरकार ने इस अखबार के सारे सरकारी इस्तहार बंद करवा दिये और सभी सरकारी प्रतिष्ठानों और स्वायत्त संस्थाओं को अपने मंत्रालय की तरफ से एक खुफिया गदनी विट्टी भिजवा दी कि वे एक्सप्रेस ग्रुप के अखबारों को इस्तहार देना बंद कर दें। हर महीने लगभग 15 लाख रुपये का घाटा होने लगा।

अखबारों पर लगभग पूरी तरह अपना शिवजा बस देने के बाद भी मुबला 'पूरे अखबार उद्योग का ढांचा इस तरह नये सिरे से बनाने' की बात करते थे कि 'वह जनता, समाज और पूरे देश के सामने जवाबदेह रहें।' इस सबका मतलब कोई ऐसी पक्की व्यवस्था करना था जो इमर्जेंसी के गौराम मिले हुए भी 191 पर निभर न हो।

इस काम के लिए अंग्रेजी की दो बड़ी 'एजेंसियाँ' और यूनाइटेड यूज ऑफ इण्डिया को दास

हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती को एक में मिला देना जरूरी समझा गया। इस तरह सिर्फ एक जगह कटौत रखने से काम चल जाता। शुक्ला ने भल्लबारी और समाचार एजेंसियों के मालिकों को एक एजेंसी का सुभाव मान लेने पर राजी करने के लिए उनके खिलाफ जोर जबदस्ती और दबाव डालने के अपने वही पुराने हथकण्डे इस्तेमाल किये। बाद में सबको मिलाकर समाचार के नाम से एक एजेंसी बन भी गयी। कुछ डायरेक्टरों और चोटी के कमचारियों की भ्रम्येवाजी को खत्म करने के लिए उन्होंने प्रॉल इण्डिया रेडियो के लिए उनकी खबरें लेना बंद करके जिससे उन्हें काफी आमदनी होती थी, इन एजेंसियों को बिलकुल अपाहिज कर देन की कोशिश की।

जनवरी 1976 के पहले हफ्ते में बताया गया सरकार की योजना यह थी कि एजेंसी की गवर्निंग बॉसिल के बेयरमन और पंद्रह मेम्बरों को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। लेकिन राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दे दिया गया था कि अगर 'उसे पूरा यकीन हो कि एजेंसी कारगर तरीके से काम नहीं कर रही है तो वह गवर्निंग बॉसिल से इसके लिए उचित उपाय करने को कह सकता है।'

सरकार जानती थी कि वह जो कदम उठाने जा रही है उसका मतलब भल्लबारी की भाजादी पर अक्रुश लगाना ही समझा जायेगा। इसलिए उसने यह समझाना शुरू किया कि वह भल्लबारी के साथ जो कुछ भी कर रही है वह सिर्फ इसलिए कि वे 'पूजीपतियों के अंगुल से सचमुच छुटकारा पा सकें।' एजेंसी की वाक्यांश स्थापना 1 फरवरी को हुई।

इधर भल्लबारी को नये सिरे से संगठित करने का काम चल रहा था, उधर सजय ने अपना ध्यान सरकार के ढांचे को नये सिरे से बनाने की अधिक महत्वपूर्ण समस्या पर केन्द्रित किया। वह अपनी माँ से हमेशा कहता रहता था कि अगर मेरा बस चले तो मैं 'पूरी सरकार को बदल दूँ।' इसी सिलसिले में उसने यह मांग भी रखी थी कि मंत्रिमण्डल के 54 मंत्रियों में से एक चौथाई को हटाकर उनकी जगह युवक कांग्रेस के मेम्बरों को दी जाये। केन्द्रीय सरकार में जो लोग ऊँचे-ऊँचे पदों पर तनात थे उनके बारे में उसने छानबीन शुरू भी कर दी थी। अफसरों को 1 सप्तरजग रोड बुलाया जाता था, सजय और भवन उनका इण्टरव्यू लेते थे और इसके बाद या तो उन्हें अपने पदा पर बने रहने दिया जाता था या फिर हटा दिया जाता था।

लेकिन यह काफी नहीं था। सजय चाहता था कि कैबिनेट में और राज्यों में उसके आदमी रहें। इसी तरह से इस बात का पूरा यकीन हो सकता था कि वह जो आदेश देगा उनका पूरी तरह पालन किया जायेगा। उसने बसीलाल को, जो सोलह आने बफादार और उसके अपने आदमी थे, कैबिनेट में पहुँचा दिया। कैबिनेट में उनका काम था सल्ल लाइन अपनाना—बिलकुल वैसे ही जैसी कि घराना चाहता था। बसो साल रक्षामंत्री बनना चाहते थे और बन भी गये। इसकी वजह बिलकुल साफ़ थी।

लेकिन वह यह भी नहीं चाहते थे कि उनकी अपनी जागीर हरियाणा से उनका नाता बिलकुल ही टूट जाय। इसलिए उनसे बाद जब बनारसीदास गुप्ता वहाँ के मुख्य-मंत्री बने (उन्हें भी इसके लिए खुद बसीलाल ने ही चुना था), तो उनसे कह दिया गया कि 'असली मुख्यमंत्री बसीलाल ही रहेंगे और उन्हें उनकी बात सुननी होगी'।

श्रीमती गांधी ने अस्सी बरस के बूढ़े मंत्री उमाशंकर दीक्षित को हटा देने की सजय की इच्छा भी पूरी कर दी। उनके लिए यह बहुत बड़ा फसला था क्योंकि 1971 के चुनाव के वक्त स पार्टी के खड़ाची की हैसियत से दीक्षितजी न श्रीमती गांधी की तरफ़ करोड़ों रुपये जमा किये थे और बाटे थे। इधर कुछ दिनों से श्रीमती गांधी उनमें नाराज थी क्योंकि उनकी वजह सरकार के कामकाज में दखल देने लगी थी।

श्रीमती गांधी ने दीक्षितजी के बैठे की बदली दिल्ली के बाहर करवा दी थी ताकि हर बात में अपनी टांग घसानेवाली उनकी बहू से पीछा छूटे, लेकिन बहू दीक्षितजी का हाथ बंटाने के लिए यही रह गयी। श्रीमती गांधी को ऐसी बहुधो से निबटने का पहले भी अनुभव था। कुछ समय पहले जब कमलापति निपाठी दिल्ली साये गये थे, उनकी 'बहूजी' के पर भी श्रीमती गांधी ने कतर दिये थे।

दीक्षितजी के मंत्रिमण्डल से हटा दिये जाने पर दूसरे मंत्री सहम गये। कुछ ही दिन बाद दीक्षितजी तो कर्नाटक के गवर्नर बनाने भेज दिये गये, लेकिन दूसरे मंत्री सोचने लगे कि अगर आज दीक्षितजी के साथ यह हो सकता है तो कल उनके साथ भी हो सकता है। वे भी भी तावेदार बन गये।

उन्होंने एक और पुराना हिसाब भी खूबा लिया। उन्होंने स्वर्णसिंह को कबिनेट से निकाल दिया। वह हम बात को भूली नहीं थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फसले के बाद उन्होंने पूरे एक दिन टालमटोल करने के बाद उस बयान पर दस्तखत किये थे जिसमें उनके प्रति पूरा विश्वास का ऐलान किया गया था। इस तरह उन्हें दिल्ली को हटाकर उनकी जगह बलिराम भगत को स्पीकर बना देने में बड़ी मदद मिली। विदेश मंत्रालय के राज्यमंत्री के पद से हटा दिये जाने के बावजूद बलिराम भगत उनके स्वामिभक्त सेवक बने रहे थे। सिक्स होने के नाते दिल्ली बड़ी आसानी से स्वर्णसिंह की जगह ले सकते थे।

श्रीमती गांधी पी० सी० सेठी को उबरक तथा रसायन मंत्री बनाकर ले आयीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से वह पराने के बहुत निकट आ गये थे। दीक्षितजी के चले जाने के बाद सेठी से पैसा वसूल करने के लिए किसी को ता पाटी का खजाची बनाना ही या और सेठी ने यह काम बड़ी खूबी से संभाल लिया।

केन्द्र में अपने मोहरे बिठाकर सजय को सत्तोप नहीं हुआ। वह राज्यों में भी अपने ही मुख्यमंत्री चाहता था। उसने सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सफाई करने का बीड़ा उठाया और हैमदतीनन्दन बहुगुणा को वहाँ के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से हटा दिया। इस परिवर्तन के लिए मैं और बेटा दोनों राजी थे। बहुगुणा नजरो से इसलिए उतर गये थे कि उनके होसले बहुत बढ़त जा रहे थे। मैं बेटे को धक्का दे रहा था कि वह अपनी साल एक बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता की हैसियत से जमाने की कोशिश कर रहे थे, जो भागे चलकर प्रधानमंत्री बन सकता था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 1974 वाले चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद (उसे 425 सदस्य के सदन में 216 सीटें मिली थी) उन्होंने मतदाताओं को धमकाव देने के लिए एक पोस्टर छपवाया था जिसमें उनकी तसवीर थी। यह इस बात का काफी सबूत था कि वह अपने को सामने रखने और बड़े बन जाने की तमना रखते थे—श्रीमती गांधी की टक्कर पर, जो खुद भी उत्तर प्रदेश की ही थी। दरअसल उनकी हठान का फैसला जून 1975 में ही कर लिया गया था लेकिन इमर्जेंसी की वजह से यह फसला टल गया था। कुछ लोगों का कहना था कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का असल न अटका होता तो वह पहले ही हटा दिये गये होते। खयाल यह था कि वह अगर डालकर फसला बदलवा सकता है।

उसके बाद तो उन्हें और भी अच्छा बहाना मिल गया था। यूपाला बपूर न, जो श्रीमती गांधी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मामलात की देखभाल करत थे, यह 'खोज की थी कि बहुगुणा न सजय और उसकी माँ को 'नष्ट कर देने के लिए एक 'यन' करने का काम चार तात्रिकों को सौंप रखा है। उनमें से दो ने तो यह बात बतल भी कर ली थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पी० सी० सेठी की मदद से यशपाल बपूर ने उन दोनों का वहाँ पता लगवाकर उन्हें भीसा में गिरफ्तार भी करवा लिया था।

(बहुगुणा ने मुझे बताया कि यह सारा किस्सा 'विलकुल बे बुनियाद' है और 'जिन तांत्रिकों की ये लोग बातें करते हैं' उनका कहीं कोई नाम-निशान नहीं है। मुझ-कि है कि बूढ़े बैद्यजी को, जो कमलापति त्रिपाठी समेत उत्तर प्रदेश के बहुत-से नेताओं का इलाज कर चुके हैं, तांत्रिक समझ लिया गया हो।)

श्रीमती गांधी ने बहुगुणा से इस्तीफा देने को कहा और उन्होंने 29 नवम्बर को इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद बहुगुणा ने श्रीमती गांधी से मिलने की कोशिश की लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने कभी मिलने का वक्त ही नहीं दिया। उन्हें अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया गया क्योंकि उनके हर बयान के लिए पहले सेंसर की मजूरी लेना जरूरी था।

बहुगुणा की जगह सजय ने नारायणदत्त तिवारी को बिठा दिया। कुछ ही दिन में इनको नई दिल्ली तिवारी कहा जाने लगा क्योंकि वह भाग भागकर बार बार दिल्ली जाते रहते थे। केन्द्र में उत्तर प्रदेश के जिनने नेता थे वे सब उनको मुख्यमंत्री बनाने के खिलाफ थे लेकिन सजय वहाँ अपना भादमी चाहता था जिसकी माड में वह उत्तर प्रदेश पर शासन कर सके। जब भी वह लखनऊ आता था या लखनऊ से चलने लगता था तो वहाँ का पूरा मंत्रिमण्डल उसे सलामी देने के लिए हाज़िर रहता था।

श्रीमती गांधी अपनी सरकार के बारे में नयेपन की भावना पैदा करने के लिए प्रायेदिन जो इस तरह के परिवर्तन करती रहती थी उसमें किसी को भी कोई फायदा नहीं होता था। लेकिन इस बार केन्द्र और राज्यो में जो परिवर्तन किये गये थे वह एक मकसद से किये गये थे—जो वफादार थे उन्हें इनाम देने के लिए और जिनकी वफादारी के बारे में शक था उन्हें सजा देने के लिए। बहरहाल, यह तो कामचलाऊ हल था, कोई पक्का बदोबस्त करना जरूरी था।

उनके मन में संविधान को बदलने की धुन समायी हुई थी। संविधान में जो कायदे-कानून बताये गये थे उनकी वजह से 'रोड़ा भटकानेवाले छोटे-छोटे गिरोहों को गडबडी फैलाने और सड़क पड़ा करने के लिए बेहद मौका मिल गया था। श्रीमती गांधी यह महसूस करती थी कि सरकार से तो यह उम्मीद की जाती है कि वह 'यह करे, वह करे,' लेकिन विपक्ष का जो भी जो में आया करने की छूट है। इसीलिए वह इस बात पर जोर देने लगी कि नागरिकों के कर्तव्यों की एक सूची होनी चाहिए, जिनका पालन न करने पर सजा दी जानी चाहिए।

उनके लिए यह बात महत्व तो रखती थी लेकिन बुनियादी नहीं थी। उनका ध्यान इससे भी बड़ी किसी चीज पर केन्द्रित था। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह शासन की राष्ट्रपति प्रणाली अपना लें, कुछ उस तरह की जैसी फ्रांस में है—फ्रांस की वह हमेशा से बहुत बड़ी प्रशंसक थी। ससदीय तरीके से काम बहुत धीमे होता है, और कभी कभी तो उसमें कोई नतीजा नहीं निकलता, और उसमें जो भादमी चोटी पर होता है उसे खलकर अपनी मर्जी से काम करने का कभी मौका नहीं मिलता।

सजय इसी बात को विलकुल दो टूट ढंग से कहता था। उसका कहना था कि राष्ट्रपति प्रणाली सारी ताकत एक भादमी के हाथ में सौंप देती है और उस पर ससद या मंत्रिमण्डल की कोई रोक नहीं होती, और न ही उसके खिलाफ भविष्यवास्त प्रस्ताव पास किया जा सकता है। वह इसमें पक्का था कि संविधान को फिर से बनाने के लिए—उसे विलकुल बदल देने के लिए एक नयी कान्टीच्युएट असेम्बली (संविधान सभा) बनायी जाये।

बीच-बीच में गोखले और कुछ दूसरे लोग कानून की प्रणाली में बुनियादी सुधार की बातें करते रहते थे। लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं बताया था कि उनके मन

मे क्या बात है।

सच तो यह है कि कुछ 'प्रगतिशील लोगों' की राय संविधान को इस तरह बदल देने के पक्ष में थी कि वह समाज की जरूरतों को और ज्यादा हद तक 'पूरा कर सके'। ये लोग नहीं चाहते थे कि सम्पत्ति को मूल अधिकार माना जाये, न ही वे यह चाहते थे कि संविधान की व्याख्या करने की भाँट में अदालतें संसद की सर्वोच्च सत्ता में किसी तरह की कतर ब्यात करें।

लेकिन ये 'प्रगतिशील लोग' भी इस बात के खिलाफ थे कि संविधान में बड़े पैमाने पर कोई बुनियादी परिवर्तन किये जायें और देश की संविधान सभा में भाग लेनेवाले सभी वर्तन के द्वार खोल दिये जायें और देश की संविधान सभा में भाग लेनेवाले सभी राष्ट्रकोणों को ध्यान में रखकर बहुत सोच-समझकर तैयार किये गये इस संविधान को बुनियादी तौर पर बदला जाये।

और वे श्रीमती गांधी को घेरे रहनेवाले लोगों के इस तरह के इशारों के तो कट्टर विरोधी थे कि राष्ट्रपति प्रणाली अपना लेने से देश का शासन बेहतर ढंग से चलाया जा सकता है। सत्ताधारियों के निकट के लोगों की दलीलों में जो यह एक इशारा छिपा रहता था कि इमजेंसी के बदौलत जो 'अनुशासन' और 'शांति' हमें नसीब हुई है उसे 'राष्ट्रपति प्रणाली जैसी किसी चीज' के जरिये ही मजबूत किया जा सकता है।

संविधान के बारे में जो कुछ सोचा जा रहा था उसे ठोस रूप लंदन में भार के हार्ड-कमिशनर बी० के० नेहरू ने दिया, जो श्रीमती गांधी के करीबी रिश्तेदार थे। उन्होंने फ्रांस जैसे संविधान का सुझाव दिया, जिसमें सबसे ऊपर प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति हो। बी० के० नेहरू चाहते थे कि श्रीमती गांधी भारत की 'ग़ाल बन जायें'।

बम्बई से रजनी पटेल ने इस रूपरेखा में और रंग भरा और फिर एक नोट तैयार करके एक सुकिया दस्तावेज की तरह लोगों में बाँटा गया। कोई यह नहीं कहना चाहता था कि ये विचार उसके हैं और किसी को इसकी चिंता भी नहीं थी। लेकिन यह नोट भी बहुत-कुछ 1969 में ए० आई० सी० सी० के बगलौर अधिवेशन के वक्त, जब कांग्रेस के दो टुकड़ों में बंट जाने के तिलसिले की घुरघुरात हुई थी, श्रीमती गांधी के फुटकर विचार जैसा ही था।

इस नोट में कहा गया था, "पिछले पच्चीस वर्षों के दौरान हमारे देश में जा तंत्र के काम करने के अनुभव को देखते हुए" इस बात की जरूरत है कि संविधान का मौजूदा रूप बदला जाये। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, और बातों के प्रस्ताव, इस बात का पक्का बंदोबस्त किया जाना चाहिए कि जब स्वतंत्र और 'मायोजित' चुनाव के बाद जनता एक निश्चित अवधि के लिए किसी सरकार के प्रति अपना विश्वास प्रकट कर दे तो उस सरकार को जनता के हित में बिना किसी रोक टोक के पूरी अवधि तक काम करने का मौका मिले, ताकि राष्ट्र का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी अपनी बुद्धि और अपनी अंतरात्मा के अनुसार, किसी बेजा छूट या बाधा के बिना, किसी से डरे या किसी के साथ पक्षपात किये बिना राष्ट्र की भद्रता के लिए सत्ता का समुचित उपयोग कर सके।"

इस उद्देश्य का पूरा करने के लिए जो ठोस सुझाव दिये गये थे उनमें एक सुझाव यह भी शामिल था कि 'राष्ट्रपति को, जो मुख्य कार्यपालक होगा, सीधे देश व्यापी चुनाव के जरिये छ सत्र के लिए चुना जायगा और संसद की अवधि भी छ साल की होगी। राष्ट्रपति का चुनाव अमरीका की तरह नहीं होगा जहाँ पहले कुछ

प्रतिनिधि चुन लिये जाते हैं और वे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। "चूँकि हमारा राष्ट्र-पति इस तरह जनता के साथे वोट से चुना जायेगा इसलिए इस परिस्थिति में उसकी साख और सत्ता हमराका के राष्ट्रपति से भी बढ़कर होगी," जो बहुत कुछ हद तक दो सदनों के बीच, कांग्रेस और सीनेट के बीच, पिसकर रह जाता है।

राष्ट्रपति प्रणाली का ट्रकान सत्राने की बहुत कोशिश की गयी लेकिन बहुत-से कांग्रेसी इस भाँसे में आने की तयार नहीं थे। हालाँकि उन्होंने इमर्जेंसी के खिलाफ अपनी जवान नहीं खाली थी, लेकिन वे उसकी सहिनयो को तो महसूस कर ही रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि वह हमेशा के लिए कायम रहे। उन्हें डर था कि अगर राष्ट्रपति प्रणाली लागू हो गयी तो यही होगा।

श्रीमती गांधी ने बेहतर यही समझा कि इस मामले को यही छोड़ दिया जाये और इसके बजाय संविधान में बुनियादी परिवर्तन करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया जाये। बाद में चलकर, अगर मुमकिन हुआ तो, राष्ट्रपति प्रणाली का विचार फिर उठाया जा सकता है।

चंडीगढ़ में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में 30 दिसम्बर को जो प्रस्ताव पास किया गया उसमें सिर्फ इतना कहा गया था कि संविधान को इस तरह बदल दिया जाये कि वह 'जनता की मौजूदा जरूरतों को ज्यादा हद तक पूरा कर सके।'

श्रीमती गांधी न सही, पर सजय को इस बात की क्यादा चिंता थी कि इमर्जेंसी और क्यादा दिन तक चलती रहे और मार्च 1976 में जो चुनाव होनेवाले थे उन्हें टाल दिया जाये। इधर कुछ दिनों से 'धराने' ने यह कहना शुरू कर दिया था कि 'इमर्जेंसी से जो कुछ मिला है उसे अभी पुल्ला करना है। यूनुस पूछा करते थे, 'भाखिर चुनाव कराने की ऐसी जल्दी क्या है?' चुनाव तो एक तरह की एग्माशी थे और उन्हें चार-पाँच साल के लिए टाला जा सकता था।

बसीलाल ने सजय की हाँ में हाँ मिलाते हुए चुनाव टाल देने की पैरबी की। वह कांग्रेसी सदसद-सदस्या से कहा करते थे कि लोणा को चुनाव की नहीं अपनी रोखी की फिक्र है। "अगर उन्हें रोटी दे दो, तो बेखटने राज करते रहों। भाखिर भरत ने भगवान राम के छडाऊँ के सहारे देश पर चौदह साल तक राज किया ही था।'

कांग्रेस अधिवेशना ने एक प्रस्ताव पास किया जिने सिद्धायशकर रे ने पेश किया था "भाषिक तथा राजनीतिक स्थिरता लाने में निरन्तरता को सुनिश्चित बनाने के लिए कांग्रेस सदस में कांग्रेसी दल का आवाहन करती है कि वह संविधान की धारा 83¹ के अंतगत बतमान लोकसभा की अवधि को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाये।'

यह वही सिद्धायशकर रे थे जिहोने इमर्जेंसी के विचार को कानूनी रूप दिया था।

इस अधिवेशन ने सरकार को इमर्जेंसी की अवधि भी बढ़ा देने का अधिकार दे दिया। श्रीमती गांधी ने प्रतिनिधियों को बताया कि सरकार का निकट भविष्य में इमर्जेंसी उठाने का कोई इरादा नहीं है। उसे देश की एकता और उसके जिंदा रहने का भी तो ध्यान रखना था।

सच तो यह है कि इंदिरा गांधी का, मुख्यमंत्रियों का, सरकारी मंत्रियों का, सभी का इमर्जेंसी में कुछ निजी फायदा था। कोई बुराई नहीं कर सकता था, कोई विरोध नहीं कर सकता था। जो कुछ वे चाहते थे वही कानून था। उनको बस जुवान

1 धारा 83 में कहा गया है— 'जबकि इमर्जेंसी की घोषणा लागू हो तो संसद कानून के अनुसार लोकसभा की अवधि को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

तो जिससे भी मिलते थे उससे यही पूछते थे कि खुफिया विभाग वाले जो 'शान्ति' की खबरें देते हैं क्या वे सच हैं, लेकिन कोई उन्हें भ्रसलियत नहीं बताता था। हालाँकि भद्र श्रीमती गांधी की यह ध्वादत हो गयी थी कि वह वही बातें सुनती थी जो उनकी भच्छी लगती थी, लेकिन कभी कभी वह भी सोचती थी कि जो खबरें उन्हें दी जाती हैं क्या वे सही और सच्ची हैं। जो कुछ भालूम न हो पाये उसका डर तो लगा ही रहता है।

सरकार ने 5 जनवरी को ससद के सामने इमर्जेंसी को कुछ समय के लिए और बढा देने की और मार्च में होनेवाले चुनावों को कुछ समय के लिए टाल देने की कांग्रेस की सिफारिश पेश की।

विपक्ष के ज्यादातर सदस्यों ने ससद के अधिवेशन के पहले दिन की कारवाई में भाग नहीं लिया, जिस दिन राष्ट्रपति ने वहाँ भाषण दिया था। उनके भाषण के बाद, जिसमें उन्होंने गरीबों को गरीबी सुविधाएँ देने, परिवार नियोजन का काम और तेजी से चलाने और व्यापार पर लगी हुई कुछ पाबंदियों में ढील देने के सरकार के कार्यक्रम की रूपरेखा पेश की गयी थी, सरकार-विरोधी सदस्य सदन में आकर बैठे और उन्होंने इमर्जेंसी पर भरपूर हमला किया। पी० जी० भावलकर ने जोर देकर कहा कि "संसदीय जनतंत्र को तोड़ मरोड़कर उसकी शक्ल बिगाड़ दी गयी है।" एक और सदस्य समर मुखर्जी ने कहा, "संसद की भूमिका की जड़ खोखली कर दी गयी है और खतरा इस बात का है कि उसे और भी खोखला कर दिया जायेगा।"

वृष्णकान्त ने कहा

जो बुनियादी सवाल हमें खुद अपने से पूछना चाहिए वह यह है कि जिन कामयाबियों का दावा किया जा रहा है क्या उन्हें हासिल करने के लिए दमन और भ्रत्याचार के इन सारे उपायों को सचमुच जरूरत है। हमने एक जनतांत्रिक संविधान अपनाया था और यह फसला किया था कि जनतांत्रिक तरीका से राष्ट्रीय जदयों तक पहुँचने के लिए हम एक स्वतंत्र और खुला समाज बनायेंगे। क्या ट्रेनों को ठीक वक्त से चलाने के लिए हमें मुसोलिनी के दार्शनिक विचार से सबक सीखना पड़ेगा? क्या दफतरो में और भ्रष्ट व्यवस्था में भ्रष्टाचार साने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम हिटलरी तरीके अपनायें? क्या हमें चीजों की कीमतें घटाने के लिए भ्रष्ट खर्च और बाह्य खर्च से सबक सीखना होगा? क्या हमारे लिए जरूरी है कि लोगों की नागरिक स्वतंत्रताएँ छीनने के लिए वैसे ही दलीलें दें जैसी कि उगाड़ा में ईदी प्रमोन या फिलीपींस में मार्कोस या यूनान में फौजी जनरल देते हैं। मुसोलिनी की शुरू-शुरू की कामयाबियों से चर्चिल जैसे लोग भले ही घोखे भ घा गये हों और कुछ समय के लिए डिकटेटरों की तारीफ करने लगे हों, लेकिन नेहरू जैसे दूरदर्शी लोग इस तरह के दावों के जाल में नहीं फँसे। उन्होंने इन कार-वाइयों की बाहरी सजावट भी तह में आकर देखा और भ्रसलियत को जान लिया। यही वजह है कि हमने गांधीजी से प्रेरणा लेकर दूसरा ही रास्ता अपनाया।

मैं जिस बुनियादी सवाल की बात कर रहा था, वह यह है कि समाजवाद की मजिल तक पहुँचने के लिए क्या हमें जनतंत्र और जनतांत्रिक तरीकों पर भरोसा है? इमर्जेंसी की कामयाबियों का जो दिबोरा पीटा जा रहा है क्या वह इस बात को मान लेने का और भी जोरदार ऐलान नहीं है कि जनतांत्रिक तरीके नाकामयाब हो गये हैं और उन पर हमारा भरोसा

कुछ दिन बाद काँग्रेस प्रस्ताव पर अपनी धुरी के फैंसला करके कांग्रेस के प्रस्ताव पर अपनी धुरी के खिलाफ भावाज तक नहीं उठायी। मच तो यह है कि बसोलात के रूप में पेश किया चुनाव तो कम से कम पाँच साल के लिए टाल दिये जाने चाहिए। कांग्रेस के इस अग्रिमेशन में सजय को वाक्यांश एक नेता के रूप में बर्तनत। कांग्रेस के इस अग्रिमेशन में सजय को वाक्यांश एक नेता के रूप में बर्तनत। कांग्रेस के इस अग्रिमेशन में सजय को वाक्यांश एक नेता के रूप में बर्तनत।

गया। बहुत छोटा-सा समारोह था जिसमें बंदी की प्रप्यक्ष थी। लगभग बीस साल पहले जब श्रीमती गांधी कांग्रेस महोदया।' ने उनके सामने झुककर कहा था, 'हमारी प्रप्यक्ष यह थे—एक श्रीमती गांधी के लिए, एक कांग्रेस के पड़ताल में कमरे बस तीन ही थे। सबसे ज्यादा जीह उसी के कमरे में था।' गांधी जी की स्त्री थी क्योंकि कांग्रेस में बहुत-से लोग थे।

[illegible][illegible]

कोई प्रखवार था और न वह किसी प्रकार का दुश्मन था।
 बुकिया रिपोर्टों से पता चलता था कि बुकिया
 ने खबरें न छपत से उनमें गुस्सा है और वे बी० बी० सी० और वायस
 के रेडियो कार्यक्रम सुनने लगे हैं।
 जैसा कि सजय अक्सर कहा करता था, उसे बुद्धिजीवियों से नफरत थी। उसने
 काम करने का खुद अपना एक तरीका निकाल लिया था और उससे कामयाबी भी
 मिलती थी। जो मिल मालिक दूकानदार या सरकारी अफसर इनकम टैक्स, एक्साइज
 इन्कार करते थे, उनके घरो पर वह प्रणव मुखर्जी से कहकर लिया था और उससे कामयाबी भी
 और एनफोर्समेंट वालों से छापे डलवा देता था या उनका टैक्स के बकायों का पिछले
 दस माल का हिस्सा खसवा देता था और जो लोग जरा भी अपनी मनमानी करने
 की कोशिश करते थे उन्हें पीछे ब्रूम मेहता से कहकर पुलिस और सी० बी० आई०
 वालों का लगा देता था। इनकम टैक्स एक्साइज या सी० बी० आई० के बिभागों में
 जो सबसे बड़े अफसर थे वे सभी मजबूत के इशारे पर चलते थे क्योंकि वह उनके फायदे
 का पूरा ध्यान रखता था—रिटायर हो जाने के बाद नौकरी बढवा देना, ऊँचा मोहवा
 दिला देना और नौकरी की बेहतर शर्तें दिला देना।
 सजय और श्रीमती गांधी जिस ताकत पर भरोसा करते थे पुलिस पर उसकी
 ताकत पर भरोसा करते थे। सरकारी तौर पर इमर्जेंसी का ऐलान होने से पहले
 सजय और श्रीमती गांधी जिस ताकत पर भरोसा करते थे पुलिस पर उसकी
 ताकत पर भरोसा करते थे। सरकारी तौर पर इमर्जेंसी का ऐलान होने से पहले

लो को लगा देता था। इनके न जाने कौन से दोस्तों ने सोचा कि सबसे बड़े अपराध से वे सभी मजबूत के इशारे पर बचने के लिए पूरा ध्यान रखता था—रिटायर हो जाने के बाद नौकरी बढ़ा देना।

सचय और श्रीमती गांधी जिस ताकत पर भरोसा करते थे पुलिस पर उसकी यह अच्छी तरह देखभाल बरत से। सरकारी तोर पर इमर्जेंसी का ऐलान होने से पहले 25 जून को सुबह गृह मंत्रालय ने सन्नेटरी के दफ्तर में एच० मोदियम से इस बात पर जोर दिया गया कि पुलिस का होमला बनये रखना बहुत जरूरी है और उनकी हर मुश्किल गांधी का ध्यान रखा जाना चाहिए। बाद में उनकी और फौजवालों की तनख्वाहें बढ़ा दी गयीं, फौजवालों की गिटायर हार्न की उम्र भी बढ़ा दी गयी।

गुप्तिया का ध्यान रखा जाना चाहिए। बाद में उनकी और फौजवालों की तनख्वाहें बढ़ा दी गयीं, फौजवालों की गिटायर हार्न की उम्र भी बढ़ा दी गयी।

पुनिमवाना न घोर दूमेरे लोग न अच्छा काम किया था, चारा घोर 'वालि' था। लेकिन पगला गुप्त नहीं था। वही हू वचन यही महामुल किया जाना था कि यह मामला में पहल की मामोनी है। कम-न-कम श्रीमती गांधी के मेन्ट्ररी पो० एन० घर

तो जिससे भी मिलते थे उससे यही पूछते थे कि खुफिया विभाग वाले जो 'शान्ति' की खबरें देते हैं क्या वे सच हैं, लेकिन कोई उन्हें असलियत नहीं बताता था। हालाँकि प्रबुध श्रीमती गांधी की यह आदत हो गयी थी कि वह वही बातें सुनती थी जो उनको अच्छी लगती थी, लेकिन कभी कभी वह भी सोचती थी कि जो खबरें उन्हें दी जाती हैं क्या वे सही और सच्ची हैं। जो कुछ भासूम न हो पाये उसका डर तो लगा ही रहता है।

सरकार ने 5 जनवरी को संसद के सामने इमर्जेंसी को कुछ समय के लिए और बढ़ा देने की और मार्च में होनेवाले चुनावों को कुछ समय के लिए ठाल देने की कांग्रेस की सिफारिश पेश की।

विपक्ष के ज्यादातर सदस्यों ने संसद के अधिवेशन के पहले दिन की कारवाई में भाग नहीं लिया, जिस दिन राष्ट्रपति ने वहाँ भाषण दिया था। उनके भाषण के बाद, जिसमें उन्होंने गरीबों को नयी सुविधाएँ देने, परिवार नियोजन का काम और तेजी से चलाने और व्यापार पर लगी हुई कुछ पाबन्दियों में ढील देने के सरकार के कार्यक्रम की रूपरेखा पेश की गयी थी, सरकार विरोधी सदस्य सदन में आकर बैठे और उन्होंने इमर्जेंसी पर भरपूर हमला किया। पी० जी० भावलकर ने जोर देकर कहा कि "संसदीय जनतन्त्र को तोड़ मरोड़कर उसकी सबल बिगाड़ दी गयी है।" एक और सदस्य समर भुलजी ने कहा, "संसद की भूमिका की जड़ खोखली कर दी गयी है और खतरा इस बात का है कि उसे और भी खोखला कर दिया जायेगा।"

कृष्णकान्त ने कहा

जो बुनियादी सवाल हमें खुद अपने से पूछना चाहिए वह यह है कि जिन कामयाबियों का दावा किया जा रहा है क्या उन्हें हासिल करने के लिए दमन और अत्याचार के इन सारे उपायों की सचमुच जरूरत है। हमने एक जनतांत्रिक संविधान अपनाया था और यह फैसला किया था कि जनतांत्रिक तरीकों से राष्ट्रीय लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए हम एक स्वतन्त्र और खुला समाज बनायेंगे। क्या ट्रेनों को ठीक वक्त से चलाने के लिए हमें मुसोलिनी के दार्शनिक विचार से सबक सीखना पड़ेगा? क्या दफतरो में और भय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम हिटलरी तरीके अपनायें? क्या हमें चीन्ही की कीमतें घटाने के लिए मध्यम खाँ और याह्या खाँ से सबक सीखना होगा? क्या हमारे लिए जरूरी है कि लोगों की नागरिक स्वतन्त्रताएँ छीनने के लिए वसी ही दलों दें जैसी कि उगाढा में ईदी घमीन या फिलोपीस में मार्कोस या यूनान में फौजी जनरल देते हैं। मुसोलिनी की शुरू-शुरू की कामयाबियों से चर्चिल जैसे लोग भले ही धोखे में आ गये हों और कुछ समय के लिए डिक्टेटरो की तारीफ करने लगे हों, लेकिन नेहरू जैसे दूरदर्शी लोग इस तरह के दावों के जाल में नहीं फँसे। उन्होंने इन कार-वाइयों की बाहरी सजावट की तह में जाकर देखा और असलियत को जान लिया। यही सजह है कि हमने गांधीजी से प्रेरणा लेकर दूसरा ही रास्ता अपनाया।

मैं जिस बुनियादी सवाल की बात कर रहा था, वह यह है कि समाजवाद की मजिल तक पहुँचने के लिए क्या हमें जनतन्त्र और जनतांत्रिक तरीकों पर भरोसा है? इमर्जेंसी की कामयाबियों का जो हिंदोरा पीटा जा रहा है क्या यह इस बात को मान लेने का और भी जोरदार ऐलान नहीं है कि जनतांत्रिक तरीके नाकामयाब हो गये हैं और उन पर से हमारा भरोसा

उठ गया है ?

क्या हम यह ऐलान कर रहे हैं कि महात्मा बुद्ध की तरह गांधीजी का भी इस देश के लिए कोई इस्तेमाल नहीं है ? बोद्ध-धर्म चीन, जापान और एशिया के दूसरे देशों में पनपा लेकिन भारत में नहीं पनपा, जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और जहाँ उन्होंने उपदेश दिया था। आज जबकि सारी दुनिया गांधीजी से सीखने की कोशिश कर रही है, जिन्हें प्राथमिक गुण के लिए सबसे काम का आदमी समझा जाने लगा है, हम लोग इस देश में ही उन रवियों को, उन तरीकों को छोड़ते जा रहे हैं जिनका उन्होंने सुझाव दिया था और जिन पर उन्होंने अमल किया था।

शायद हमारे लिए अपने आपको उस बात की याद दिलाना फायदे भव होगा जो प्रधानमंत्री ने 1969 में कही थी "शरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए डिक्टेटरशिप जरूरी नहीं है और न डिक्टेटरशिप से जनता को ताकत ही मिलती है।" अफसस यहोदय, भारतीय समाज में जो असली सफ़ट पैदा हो गया था वह 'राजनीतिक' भ्रष्टाचार था, जिसकी वजह से सावजनिक जीवन के सभी आदर्श कमजोर पड़ गये थे और अधिक तथा सामाजिक सफ़ट ने हमें घेर लिया था। यह सच है कि ऐसी हालत पैदा करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियाँ जिम्मेदार हैं—चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में। लेकिन जाहिर है कि इनके लिए शासक ज्यादा जिम्मेदार हैं। असली समस्या यह है कि राजनीतिक पार्टिमें और राजनीतिक नेताओं पर से लोगों का विश्वास उठ गया है और सावजनिक तथा राजनीतिक जीवन की सारी गन्दगी को दूर करने के लिए हम सबको मिलकर काई फैसला करना होगा।

यह तो पहले ही से मालूम था कि इमर्जेंसी को जारी रखने और चुनावों को टाल देने के सुझावों की ससद की मजूरी मिल जायेगी। कांग्रेसी अब बहुत खुरा दिलायी पड़ रहे थे कि उन्हें अब यह समझने के लिए कि इमर्जेंसी क्यों लागू की गयी मतदाताओं के सामने नहीं जाना पड़ेगा।

लेकिन उनमें से कुछ को सविधान सभा की कारवाई की याद आयी। इमर्जेंसी के बारे में उसमें जो धारा (उस समय 275) थी उसमें पहले यह कहा गया था कि अगर राष्ट्रपति को इस बात का पूरा यकीन हो कि गम्भीर इमर्जेंसी की हालत मौजूद है 'जिससे देश की सुरक्षा को खतरा है चाहे वह युद्ध से हो या घरेलू हिंसा से, तो वह ऐलान जारी करके इस आदेश की घोषणा कर सकते हैं।'

बाद में इस धारा में शब्दों की बदलकर 'चाहे वह युद्ध से हो या घरेलू हिंसा से' की जगह में शब्द रख दिये गये कि 'चाहे वह युद्ध से हो या बाहरी आक्रमण से या भीतरी उपद्रव से', क्योंकि डॉ॰ अवधनर ने, जो उस समय कानूनमंत्री थे, कहा कि 'हो सकता है कि घरेलू हिंसा में बाहरी आक्रमण शामिल न हो।'

राष्ट्रपति को इसत घलापारण अधिकार दिये जाने की सविधान सभा के कुछ सदस्य ने आलोचना की थी। प्रोफसर के० टी० शाह ने 'भीतरी उपद्रव' को शामिल करने पर गहरी चिन्ता प्रकट की और खोर देकर कहा कि इस संशोधन में "राष्ट्रपति को ऐसी सत्ता और अधिकार देने की योगिता की गयी है जो जनतांत्रिक उत्तरदायी सरकार के साथ मेल नहीं खाता।' एच० बी० नयमन ने कहा कि दुनिया के किसी भी जनतांत्रिक देश में सविधान में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने इस विचार की तुलना हिटलर के सत्ता पर अधिकार करने से की जब उत्तान ऐसी ही धारारों का

सहारा लेकर वाइमार सविधान को नष्ट कर दिया था। लेकिन कृष्णमाचारी ने सदन के अधिकांश सदस्यों की भावना को व्यक्त करते हुए कहा कि "इमजेंसी की बात सिर्फ एक उद्देश्य से शामिल की गयी है, इस उद्देश्य से कि इतने वर्षों तक हमने सविधान बनाने के लिए जो कोशिशें की हैं वे व्यर्थ न जाने पायें और हमें चलकर जिन लोगों के हाथ में सत्ता होगी उनके पास सविधान की रक्षा करने के लिए काफी अधिकार हों।"

इस धारा के नये शब्दों को सविधान समा ने बिना किसी परिवर्तन के मान लिया और बाद में उसे सविधान की धारा 352 के रूप में स्वीकार कर लिया गया।

सरकार ने आंतरिक सुरक्षा कानून में भी हेर फेर करके अपने अधिकार और बढ़ा लिये। इस कानून में किसी को भी, अदालतों को भी, कारण बताये बिना राजनीतिक कैदियों को नजरबन्द रखने और जिनकी नजरबन्दी के आदेश की मियाद पूरी हो गयी हो या आदेश रद्द कर दिये गये हों, उनको फिर से गिरफ्तार करने की इजाजत दी गयी थी। लोकसभा ने 22 जनवरी को 27 के खिलाफ 181 वोटों से इस कानून को अपनी मजूरी दे दी।

मास्को का समयन करनेवाली कम्युनिस्ट पार्टी ने, जिसने इमजेंसी के दौरान सरकार को दिये गये अधिकारों का समयन किया था, पहली बार नजरबन्दी की मियाद बढ़ाने के अधिकारों का विरोध किया और विपक्ष का साथ दिया। कम्युनिस्ट सदस्य भी विपक्ष के साथ थोड़ी देर के लिए सदन से बाहर चले गये जब सदन में यह बिल पेश किया गया कि औद्योगिक मजदूरों को हर साल एक महीने की तनख्वाह के बराबर जो बोनस दिया जाता था वह 1976 में सिर्फ आधे महीने की तनख्वाह के बराबर दिया जाये और जिन कंपनियों को मुनाफा न हो वे 1977 में बिल्कुल बोनस न दें।

मीसा कानून के सख्त बनाये जाने के खिलाफ गोखले ने कबिनेट में आवाज उठायी। वह इस बात के पक्ष में थे कि अदालत में नजरबन्दी पर विचार हो। लेकिन जब यह फैसला हो गया कि हर नजरबन्द के मामले पर विचार करने के लिए एक बोर्ड बनाया जायेगा ताकि अगर बोर्ड उसकी रिहाई का हुक्म न दे तो वह अदालत का सहारा ले सकता है गोखले ने अपना ऐतराज वापस ले लिया।

ऐसा लगता है कि मीसा के कानून में यह नया संशोधन तमिलनाडु की स्थिति से निबटने के लिए किया गया था क्योंकि केन्द्र ने 21 जनवरी को वहाँ की परणानिधि की सरकार को बर्खास्त कर दिया था। गवर्नर की रिपोर्ट यह मन्त्रालय में तयार की गयी और तमिलनाडु के गवर्नर के० के० शाह ने उस पर चूँ भी किये बिना दस्त-खत कर दिये। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य की सरकार ने इमजेंसी में दिये गये अधिकारों का दुरुपयोग करने और बड़े पैमाने पर हर तरह भ्रष्टाचार की छूट देने के अलावा बीच-बीच में 'भ्रमण हो जाने की ठकी छिपी घमकियाँ' भी दी थी। सी० एम० के० की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार कुनबापरवरी, प्रशासन और पैसे के मामले में तरह-तरह की गड़बड़ियाँ और सरकारी पद का बेजा फायदा उठाने के जो आरोप लगाये गये थे उनकी जाँच करने के लिए भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जज भार० एम० सरकारिया की निगरानी में एक कमीशन बिठा दिया। परणानिधि को हुक्म न मानने की सजा देना जरूरी था।

तमिलनाडु में सरकार की बागडोर केन्द्र के हाथों में च लिये जान के बाद वहाँ गिरफ्तारियों का बाजार गम हो गया। लगभग 9,000 आदमी गिरफ्तार किये गये। कुछ दिन बाद उनकी सरवा घटते घटते 2,000 रह गयी।

तमिलनाडु की तरह गुजरात में भी केन्द्रीय सरकार के इमजेंसी शासन के

क्रायदे-वानूनो का विरोध किया जा रहा था। हितेन्द्र देसाई ने, जो उस समय तक राज्य कांग्रेस के नेता बन चुके थे, फरवरी में एक रिपोर्ट में कहा कि ग़ैर कांग्रेसी सरकार गुजरात में भ्रमन-चन कायम रखने में नाकामयाब रही है और वहाँ राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है। राष्ट्रपति ने वहाँ का शासन भी 13 मार्च 1976 को अपने हाथों में ले लिया।

तमिलनाडु और गुजरात में ग़ैर-कांग्रेसी सरकारों को जिस तरह हटा दिया गया था उससे विपक्ष की पार्टियों को पहले से भी ज्यादा यह यकीन हो गया कि सिर्फ़ जिंदा रहने के लिए भी उन्हें मिलकर एक हो जाना चाहिए। इमर्जेंसी के दौरान उन्होंने जो मुसीबतें भेली थी उनकी वजह से वह एक दूसरे के साथ बँध रही थी। चार पार्टियों ने—संगठन कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्टो ने—कांग्रेस का और भी प्रभावशाली ढंग से विरोध करने के लिए 26 मार्च को एक ही पार्टी में मिल जाने की अपनी योजना का ऐलान किया। चारों पार्टियों को मिलाकर एक पार्टी बनाने का काम पूरा करने के लिए चार आदमियों की एक स्टीयरिंग कमटी बना दी गयी। एक बयान में यह समझाया गया कि इस तरह मिलकर कारवाही करना इसलिए जरूरी हो गया है कि सरकार “जान-बूझकर हमारे जनतांत्रिक ढाँचे को नष्ट करती रही है और अब उसने एक निरंकुश शासन कायम कर लिया है जिसे वह हमेशा के लिए बनाये रखना चाहती है।” बयान में यह भी कहा गया कि इस मामले में जयप्रकाश ने भी “सलाह दी और मार्ग दिखाया।”

चरणसिंह भक्तेले आदमी थे जो चाहते थे कि चारों पार्टियाँ फौरन मिलकर एक हो जायें। यह बात वह बहुत दिन से कहते आये थे। वह देख चुके थे कि किस तरह संयुक्त मोर्चे ने गुजरात में कांग्रेस के हाथों से सत्ता छीन ली थी। जनसंघ और सोशलिस्ट तैयार थे लेकिन उनके नेता जेल में थे। उनके लिए उनसे मजबूरी लेना जरूरी था। संगठन कांग्रेस ने कहा कि बेहतर यह होगा कि दूसरी राजनीतिक पार्टियाँ उसमें शामिल हो जायें क्योंकि 1969 में कांग्रेस के दो टुकड़े हो जाने के बाद उसके हाथ में इतनी सम्पत्ति आ गयी थी जिससे हर महीने 1,00,000 रुपये किराया आता था। उसका कहना था कि अगर उसने अपना नाम बदल दिया तो यह सारी सम्पत्ति श्रीमती गांधी की कांग्रेस को मिल जायेगी।

एक पार्टी बनाने की बातचीत एक एक कर चलती रही लेकिन कई महीने तक उसका नतीजा नहीं निकला। रास्ते में बहुत-सी रुकावटें थी जिन्हें पार करना था।

जिस वक्त देश के अंदर विपक्ष की पार्टियों ने एकता की बात करना शुरू की, उन्ही दिनों लंदन में 24 अप्रैल को विदेशों में रहनेवाले लगभग 300 हिंदुस्तानियों का एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में पाबन्दियाँ लगानेवाले शासन के खिलाफ़ मुहिम चलाने की योजना बनाने के लिए हुआ। कई प्रतिनिधियों ने कहा कि विदेशों में भारतीय भ्रष्टाचारियों द्वारा प्रचार तथा भारत में सेंसरशिप ने राजनीतिक कदियों तथा उनके साथ बर्ताव को अन्तर्राष्ट्रीय मसला बनने से रोक दिया है। इनमें से बहुतों ने कहा कि 1,75,000 से भी अधिक राजनीतिक विरोधी जेलों में थे तथा कई क़दियों के साथ नृशस व्यवहार किया जा रहा था।

श्रीमती गांधी ने शासन पर हमला करत हुए बोलनेवालों ने कहा, ‘जो चीज़ उनके नेतृत्व की कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनौतियाँ स बचाने के लिए शुरू हुई थी उसने अब बढ़कर एक पार्टी की एकतरफ़ा सत्ता को दी जानेवासी चुनौतियों स बचाव के उपाय या रूप धारण कर लिया है।’

लेकिन भारत में आज़ादी के दीवाना को अभी बोट ने 28 अप्रैल को यह

फसला कर दिया कि सरकार को प्रदालत में मुनवायी के बिना अपने राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल देने का अधिकार है। चार जज इसके पक्ष में थे और एक खिलाफ था। इस फैसले में सरकार के इस दावे का समर्थन किया गया था कि 1975 में लागू की गयी इमर्जेंसी के दौरान राजनीतिक कैंदियों को निचली प्रदालतों में अपील दायर करके अपनी आजादी हासिल करने के लिए 'हेबियस कापस' का अधिकार नहीं है।

इलाहाबाद, बम्बई, दिल्ली, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा और राजस्थान के सात हाईकोर्ट 43 नज़रबंद कैंदियों को 'हेबियस कापस' की प्रार्थना के पक्ष में फैसला दे चुके थे। इन प्रदालतों ने यह ख़ल अपनाया था कि हालाँकि बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन की बुनियाद पर वे नज़रबंदी के आदेश रद्द नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें यह फसला करने का अधिकार तो है ही कि ये आदेश सही हैं या नहीं और स्वाभाविक 'याय और सामान्य कानून के सिद्धान्तों से मेल खाते हैं या नहीं। संविधान की धारा 226 जिसमें हाईकोर्टों को 'हेबियस कापस' का आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है बुनियादी अधिकारों वाले परिच्छेद का हिस्सा नहीं है, और इसलिए उस इमर्जेंसी के अधिकारों के सहारे स्थगित नहीं किया जा सकता।

सरकार की ओर से मोरेन डे ने यह दलील दी कि "इमर्जेंसी के दौरान बुनियादी अधिकारों के मामले में भी राज्यसत्ता के हितों को व्यक्ति के हितों से ऊँचा स्थान दिया जाना चाहिए", नागरिकों पर "इमर्जेंसी के दौरान किसी भी अधिकार के लिए आदेश-स्तन न चलाने की पाबन्दी लगा दी गयी है", और यह कि "इस समय निजी अधिकारों का कोई कानून नहीं है।" दूसरी ओर, शान्तिभूषण नयन दावा किया कि कुछ अधिकार, जिनमें वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, संविधान की देन नहीं बल्कि जनतंत्र का एक बुनियादी अंग है, जिन्हें इमर्जेंसी से भी नहीं छीना जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 27 जून 1975 को जारी किये गये राष्ट्रपति के आदेश को ध्यान में रखते हुए किसी भी आदेशों को नज़रबन्दी के आदेश की कानूनी हैसियत को चुनौती देते हुए रिट की प्रार्थना दायर करने का अधिकार नहीं है और यह कि 29 जून 1975 का प्रॉडिनेंस संविधान की दृष्टि से बिल्कुल वैध है। इस प्रॉडिनेंस के तहत मीसा के कानून में यह हेर फेर कर दिया गया था कि नज़रबंद किये जाने-वाले आदेशों को अब यह बताना जरूरी नहीं रह गया है कि उसे क्यों नज़रबंद किया जा रहा है। जस्टिस ए० एन० रे, एम० एच० बेग, वाई० बी० चंद्रचूड और पी० एन० भगवती ने बहुमत दृष्टिकोण का समर्थन किया और जस्टिस एच० भार० खन्ना ने इसमें विरुद्ध राम ख़ाहिर की।

जस्टिस रे ने यह कहा कि वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार सहित सारे बुनियादी अधिकार संविधान ने ही दिये हैं और संविधान के सहारे उन्हें छीना भी जा सकता है। पहले से सामान्य कानून के तहत 'हेबियस कापस' का कोई सहारा मौजूद नहीं था और सामान्य कानून के तहत कोई भी अधिकार जो बुनियादी अधिकार के समान हो, बुनियादी अधिकार से अलग एक भिन्न अधिकार के रूप में नहीं रह सकता। कानून का शासन स्वतंत्र समाज का पर्याय नहीं है, बुनियादी अधिकारों को लागू करवाने का अधिकार कुछ समय के लिए छीन लिये जाने का मतलब यह है कि इमर्जेंसी के दौरान इमर्जेंसी के क़ायदे कानून ही कानून का शासन हो गये हैं। कानून के नव शासन से अलग कानून का कोई शासन नहीं हो सकता और इमर्जेंसी के संविधान के प्रावधानों को रद्द कराने के लिए कानून के किसी शासन की दी जा सकती।

जस्टिस भगवती ने कहा कि सबट के समय इस सिद्धान्त को ही सबसे बड़ा माना जाना चाहिये कि सामाजिक सुरक्षा ही सर्वोच्च कानून है। यह जरूरी नहीं है कि इमजेंसी का ऐलान करने के लिए युद्ध या बाहरी आक्रमण या भीतरी उपद्रव हो ही, बस इतना ही काफी है कि इस तरह के किसी सकट का खतरा सर पर मंडरा रहा हो। जस्टिस बेग ने कहा कि इस अदालत के सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि सरकार ने अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल किया है।

अपने अल्पमत फैसले में जस्टिस खन्ना ने कहा कि संविधान में किसी भी अधिकारी को यह हक नहीं दिया गया है कि वह हाईकोर्टों से हेबियस कापस का रिट जारी करने का अधिकार छीन ले। इमजेंसी के जमाने में भी सरकार को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वह कानून के सहारे के बिना किसी आदमी की जान या उससे उसकी स्वतन्त्रता ले ले। और जब तक किसी आदमी की जान और उसका स्वतन्त्रता को इतना पवित्र नहीं माना जायेगा तब तक बिना कानून के चलनेवाले समाज और कानून के अनुसार चलनेवाले समाज के अन्तर का कोई मतलब ही नहीं रह जायेगा। अगर सरकार की दलील मान ली जाय तो कोई भी अधिकारी किसी भी आदमी को कानून का सहारा लिये बिना जब तक जी चाहे नजरबंद रख सकता है। सबाल यह नहीं है कि ऐसा हुमा है या नहीं, लेकिन सरकार की दलील मान लेने से यह नतीजा हो सकता है।

इस फैसले पर लोगों को ताज्जुब हुआ और कुछ लोगों को तो निराशा भी हुई क्योंकि यह यकीन किया जाने लगा था कि जस्टिस चन्द्रचूड और जस्टिस भगवती नजरबन्दा का पक्ष लेंगे और हेबियस कापस की अर्जी 2 जजों के खिलाफ 3 जजों की राय से मजूर कर ली जायेगी। बहुमत में से एक जज ने यह भी कहा कि एक के बाद एक कई बकीला ने यह डर जाहिर किया है कि इमजेंसी के दौरान सरकार नजरबन्द कैदियों को नगा करके कोठे लगवा सकती है, उन्हें भूखा मार सकती है, और अगर अदालत ने उसका हक में फैसला दे दिया तो वह उन्हें गोली से भी उड़ा सकती है। लेकिन उन्हें इस बात पर बहुत सतोष था कि स्वतन्त्र भारत का नाम पर इस तरह के किसी कुकर्म का कलक नहीं लगाया जायेगा और उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह की बातें कभी नहीं होगी।

जब लोगों के साथ पानविक मत्स्याचारा की दजनों मिसालें सामने आयीं तो साबित हो गया कि उनकी यह उम्मीद असल में कितनी गलत थी।

लोगों की तरह तरह की यातनाएँ दी गयीं। उनको नगा करके नाल लगे हुए 'फीजी वूट' से रौंदा गया तसुआ पर घुरी तरह मारा गया, पिठलिया की हड्डियों पर पुलिस की लाठियाँ, उस पर एक कास्टेबुल की बिठाकर, बलत की तरह घुमायी गयी, उन्हें घटो एवं ही तरह से झुकाकर बिठाया रखा गया, रोड की हड्डियों पर मारा गया, दोनों कानों पर इतने समाचे मारे गये कि मार खानेवाला बेहोश हो गया। राइफलों के कुदो से मारा गया, शरीर के सूराम्बा में तार लगाकर विजली डोहा दी गयी, सयायहिया का नगा करने बफ को सिला पर लिटाया गया, जलती हुई तिनारेटी और मोमबत्तियों से शरीर को दागा गया उन्हें खाने और पानी के बिना रखा गया और साने नहीं दिया गया और अपना ही पगाव पीन पर मजबूर किया गया, कत्ताई पीछे बाँधकर 'हवाई जहाज' बनाकर लटका दिया गया। (जिस हवाई जहाज बनाना होता था उसके दोनों हाथ पीठ में पीछे रस्सी से बांध दिय जाते थे फिर रस्सी को छत पर लगी हुई एक चर्रों के ऊपर में से जाकर बीच दिया

जाता था। आदमी जमीन से कई फुट ऊपर उठ जाता था और पीठ के पीछे बंधे हुए हाथों से हवा में लटकता रहता था।)

यह सब कुछ बाकायदा योजना बनाकर किया जाता था। दस बारह सिपाही किसी कैदी को घेर लेते थे और चुनकर कोई यातना उस पर आजमाते थे। अगर उसके शरीर पर घाव का कोई निशान दिखायी देता था या उसकी जिस्मानी हालत पर कोई असर हो जाता था तो पुलिस उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करती थी कि कहीं फटकार न पड़े। अगर कैदी को तलाश करने का चारट जारी कर दिया जाता था तो पुलिसवाले उसे एक घाने से दूसरे घाने और दूसरे से तीसरे घाने पहुँचा देती थी। अधिकारियों के लिए भीसा एक बरदान था क्योंकि इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया आदमी किसी अदालत में फरियाद भी नहीं कर सकता था।

जाज फर्नांडीज का भता-पता मालूम करने के लिए उनके भाई लारेंस फर्नांडीज को बगलौर में उनके घर से पुलिस पकड़कर ले गयी।

उनकी कहानी उही की जवानी इस तरह है

6 मई 1976 की रात को मैंने किसी को मेरा नाम लेकर पुकारते सुना। यह सोचकर कि कोई दोस्त होगा मैं फाटक की तरफ बढ़ा। देखता क्या हूँ कि मेरे घर के बाहर ही पुलिस की जीप खड़ी है। आवाज देनेवाला मुफ्ती में पुलिस का एक अफसर था। उसने मुझसे कहा कि अदालत में माइकेल की रिट पिटीशन के सिलसिले में कोई बयान देने के लिए मुझे पुलिस ने बुलाया है। (लारेंस का छोटा भाई माइकेल इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज में इंजीनियर था और वह भी भीसा में गिरफ्तार कर लिया गया था।) यह सोचकर कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मैं अपने बूढ़े माँ बाप को बताये बिना ही घर से निकल पड़ा।

पुलिस ने एक घंटे तक मेरा बयान दज किया और फिर मुझे जासूस विभाग के दफ्तर ले गये। वहाँ किसी ने अचानक मेरे खोर का चप्पड़ मारा। (कई मिनट तक मेरी आँखों के आगे अंधेरा छाया रहा।) जब मुझे होश आया तो मैंने महसूस किया कि उन लोगों ने मेरे सारे कपड़े उतार दिये थे।

वहाँ दस पुलिसवाले थे। उन्होंने मेरी धुनाई शुरू की। मेरे जिस्म के हर हिस्से पर लाठियाँ बरस रही थीं और एक एक करके चार लाठियाँ टूट चुकी थीं। मैं फश पर पड़ा मारे दद के तड़प रहा था। मैंने हाथ जोड़कर उनसे दया की भीख मांगी, घुटनों के बल रेंगकर मैंने एक बार फिर उनसे हाथ जोड़कर बस करने को कहा। मगर वे मुझे फुटबाल की तरह ठोकरें लगाते रहे। इसके बाद वे वहाँ से एक मूसल ले आये और उससे मुझे कई बार मारा। वह भी टूट गया और मैं दद से भीखने लगा।

इसके बाद आखिरी हल्ला हुआ। मैं फश पर पड़ा हुआ था और वे बरगद की जड़ लेकर मेरे ऊपर पिल पड़े। मैं बेहोशी और थोड़े थोड़े होश के बीच मँडरा रहा था।

सुनह के लगभग तीन बजे होये जब मेरी आँख खुली और मैंने पानी माँगा। प्यास के मारे मेरी जान निखली जा रही थी। जब मैंने हाथ जोड़कर पानी माँगा तो एक अफसर ने पुलिसवालों से मेरे मुँह में पेशाब करने का कहा, लेकिन उन्होंने किया नहीं। जब मेरा दम बिलबुल फूलने लगता था तो वे दो एक चम्मच पानी से मेरे होठ तर कर देते थे। वे जानना चाहते थे कि जाज कहाँ है और जाज की बीबी सला और उनका बेटा सितम्बर 1975 में बगलौर क्यों आये थे। वे यह भी मालूम करना चाहते थे कि उनकी वापसी पर मैं उनके साथ भद्रास क्या गया था।

मेरी हालत इतनी नाजुक थी कि उन्हें लगा कि मैं किसी भी क्षण दम तोड़ दूँगा। एक अफसर ने वास्तेबला स जीप तयार करन की कहा। मैंने उस अफसर को अपने आदमियों से कहते सुना "इसे चलती ट्रेन के आगे फेंक दो और वह देना कि इसने आत्महत्या कर ली।" मैं बिल्कुल टूट चुका था। मेरे जिस्म के बाएँ हिस्से की न जाने कितनी हड्डियाँ टूट चुकी थी और मेरी जाँघों में बला का दब हो रहा था। मेरी टाँगें और हाथ बुरी तरह सूज गये थे।

इसने बाद मुझे एक जीप पर ले जाया गया जो मल्लेश्वरम की तरफ जा रही थी। मैंने समझा कि शायद वह अफसर सबमुच अपनी घमकी पर घमस करने जा रहा है। मैं उससे दया की मोख माँगने लगा। जाहिर है उन्होंने अपना इरादा बदल दिया था। मुझे व्यालिकवल की हवालात में ले जाकर बन्द कर दिया गया। अगले दिन मुझे फिर सी० धो० डी० (जामूस विभाग) के दफ्तर लाया गया।

वहाँ मैंने पहली बार एक औरत की जानी पहचानी आवाज सुनी। वह स्नेहमता रेड्डी की आवाज थी। वह बुरी तरह चीख रही थी। पुलिस ने किसी को मेरी मालिश करने के लिए बुलवाया। उसने मेरे हाथ पाव पर तेल लगाया लेकिन थोड़ी ही देर बाद बोला कि मेरी मदद कर सकना उसके बश के बाहर है। उसने अफसरों को मुझे किसी अस्पताल पहुँचा देने की सलाह दी। लेकिन उन लोगों ने सुनी धनसुनी कर दी।

अगले दिन मुझे उस कमरे को पहचानने के लिए जिसमें जाज आकर ठहरा था एक होटल में ले जाया गया। कुछ देर बाद फिर सी० धो० डी० के दफ्तर में चौकने पर मैं भूल से बेहाल लेट गया। जब मैं गिटगिटकर खाना माँगता तो पुलिस वाले मुझ पर गालियों की बौछार कर देते। डाक्टर बुलाया गया। उसने मुझे देख-ढालकर दवाएँ लिख दी। इसके बाद कुछ दिन तक मुझे मल्लेश्वरम के थाने में रखा गया।

पाखाने पेशाब के लिए भी पुलिसवालों को मुझे उठाकर ले जाना पड़ता था। 9 मई को जबदस्ती मेरे बाल काटे गये दाढ़ी बनायी गयी और नहलाया गया, लेकिन रूपड़े वही बदबूदार पहना दिए गये।

कुछ देर बाद दो अफसर सादी पोशाक पहने हुए आये और मुझे मोटर पर बिठाकर ले गये। मेरा धीरज टूट गया और मैं फूट फूटकर रोने लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि जो कुछ हुआ उसके लिए व जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्हें यह काम सौंपा गया था कि वह मेरी गिरफ्तारी चित्रदुग में (वहाँ स कोई 150 किलो मीटर दूर एक छोटे से कस्ब में) दिखायें।

लेकिन मुझे दावनगीर ल जाया गया। वहाँ मुझे बताया गया कि मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायगा और मुझे उससे यह कहना है कि मैं उसी दिन बस के घट्टे पर गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद मुझे एक छोटी सी कौठरी में डकेल दिया गया जहाँ खटमलों और वात्रोंची की भरमार थी। वहाँ के दो इस्पेक्टरों ने आकर मुझसे कहा कि अगर मैं मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस के जुल्मों के बारे में एक बात भी मुह स निवाली तो मेरे चने निगान मिटा दिया जायेगा। व मुझे मजिस्ट्रेट के घर में अपना इरादा बदल दिया और मुझे वा नाम वन उहोने में बात दिया।

बाद में मुझे नग पाँव पॉस मूजकर दून हो गये थे।

प्रदासत

मेरे

११

मजिस्ट्रेट ने मुझसे पूछा कि मैं कब गिरफ्तार किया गया था। मेरी ज़बान लड़खड़ाती लगी क्योंकि मैं भूल चुका था कि पुलिस के अफसरों ने मुझसे कौन-सी तारीख और कौन सा वक़्त बताने को कहा था। मजिस्ट्रेट ने खुद मुझे इशारा दिया और सर हिलाते हुए मुझसे पूछा कि क्या मैं एक दिन पहले बस के अट्ठे पर गिरफ्तार किया गया था। मैं चुप खड़ा रहा और मजिस्ट्रेट ने मुझे 20 मई तक पुलिस की हिरासत में रखने का हुक्म दे दिया।

इसके बाद मुझे हवालात की कुछ बड़ी कोठरी में एक ऐसे आदमी के साथ रखा गया जो 50,000 रु० की चोरी के मामले में पकड़ा गया था। वह पुलिसवालों पर अपना हुक्म चलाता था और जब भी उसका जी चाहता था साना और सिगरेटें मगाना रहता था। उसने मुझे नसलनी दी और वायदा किया कि जिस चीज की भी मुझे जरूरत होगी वह मुझे भगा देगा। काम्पेबल और तारांग उसके एक इशारे पर भाग हुए भ्रातृ थे। उसे सजा हो जाने के बाद जेल में फिर उससे मेरी मुलाकात हुई।

11 मई का मुझे फिर बंगलौर वापस लाया गया और मल्लेश्वरम की हवालात में बदल कर दिया गया। वहाँ मुझे मल्लेश्वरम अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि मेरा एकसर चलना पड़ेगा। पुलिस के अफसरों ने इसकी इजाजत देने में इकार कर दिया। मुझे फिर थाने वापस ले आया गया।

अगले दिन मुझे दूसरे अस्पताल ले जाया गया—कटोनमट के बावर्गिंग अस्पताल में। वहाँ डॉक्टरों ने बहुत सरसरी तौर पर मुझे देखा-खाया और मेरे साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आये।

मुझे फिर मल्लेश्वरम ले जाया गया जहाँ मुझे नशीली दवाएँ दी जाने लगी। नतीजा यह हुआ कि मुझे पेचिश हो गयी और तीन दिन तक मेरा बुरा हाल रहा। इसके लिए उन्होंने मुझे कुछ और दवाएँ दी और मैं अच्छा हो गया। पुलिस को बड़ी फिक्र थी कि मैं किसी तरह 20 तारीख से पहले अच्छा हो जाऊँ। उस दिन मुझे फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना था।

मल्लेश्वरम का थानेदार रोज रात को शराब पीने के लिए मुझ पर जोर डालता रहा था, लेकिन एक काम्पेबल ने मुझे ऐसा करने से मना किया। दूसरे दिन एक बड़ा अफसर आया और मुझसे बोला कि मुझ पर जो कुछ बीती है उसका उसे पूरा पता है। उसने मुझे यकीन दिलाया कि मैं 20 तारीख को छोड़ दिया जाऊँगा। लेकिन अगले दिन जब मुझे मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया तो मुझे वहाँ कोई ऐसा आदमी दिखायी नहीं दिया जो मेरी जमानत कराता। मैंने मजिस्ट्रेट से पुलिस के जुल्म की शिकायत की। उसने कहा कि शिकायत दर्ज कर ली गयी है।

उसके बाद वह मुझे सीधे सेंट्रल जेल ले गया और मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जीप बिलकुल जेल की कोठरी के दरवाजे पर ले जाकर राकी गयी। मेरे दुर्भाग्य से वहाँ का बाडन एक लम्बा चौड़ा तगड़ा सा काले रंग का छ पुटा आदमी था। उस नेखत ही मेरा दम निकल गया। मेरे सब कपड़े उतारे गये मेरी जेब में जो बीडियाँ थी वह छीन ली गयी और मुझे काल कोठरी में डाल दिया गया। कोठरी अंधेरी और बदबूदार थी। मुझे कुछ पता नहीं कि इसके बाद क्या हुआ।

इतने में मैं सुना कि कोई बार-बार मुझे पुकार रहा है। मैं सोचा कि शायद मेरे बान बज रहे होंगे, क्योंकि उनमें से एक आवाज जानी पहचानी थी। वह मधु (दड़वते) की आवाज थी। मैं किसी तरह घिसटता हुआ कोठरी के दरवाजे तक पहुँचा और उसका सीखचा पकड़कर खड़ा हो गया।

मधु ने कहा—तारस, तुम हो? मेरी बात का जवाब दो। क्या पुलिस ने

तुम्हारे साथ जोर-जुल्म किया है ?

मैं न दूबती हुई आवाज में ही कहा। बाहर एक सार मचा हुआ था। बन्दिया के बीच एक भफवाह फैल गयी थी कि बेलगाँव जेल का भागा हुआ एक कदी फिर पकड़कर यहाँ लाया गया है।

थोड़ी ही देर बाद जेलो के इस्पेक्टर जनरल जेल का सुपरिटेंडेंट और डाक्टर लोग वहाँ पहुँचे। वे अपनी पूरी आवाज से चिल्लाते रहे। शायद उनकी सबसे बड़ी कोशिश यह थी कि मुझे पागल बना दें। चूँकि मुझे साँस की तकलीफ थी इसलिए उन्होंने मुझे बाहर सोने की इजाजत दे दी थी। इसके बाद मधु दहवन और सीमा म नज़रबंद दूसरे कैदियों न जेल में भूख-हठताल कर दी। उनकी माँग थी कि मुझे कात काठरी से निकालकर किसी बेहतर जगह रखा जाय।

दूसरे दिन ऐसा लगता है कि शायद मेरा सबसे छाटा भाई और मैं मुझसे मिलने जेल आये थे। मुझे उस मुलाकात की याद नहीं। जेल की अपनी प्रलग ही एक दुनिया है। अगर मैं आज़ाद रहा तो मैं जेलो को सुधारने के लिए लड़ता।

जेल के हाकिम मुझे बिबटारिया अस्पताल ले गये, वहाँ मेरा एक्स रे लिया गया और पलस्तर चढ़ा दिया गया। सीमा का घोंडर मुझे 22 मई को दिया गया। बाद में सुपरिटेंडेंट मुझसे वह घोंडर वापस ले लेना चाहता था लेकिन मैंने देने से इन्कार कर दिया। जब मैं पाखाने गया हुआ था तो उन्होंने मेरी कोठरी की तलाशी भी ली लेकिन उनसे हाथ कुछ न लगा।

कुछ दिन बाद वही सुपरिटेंडेंट अपने पूरे फीज फाटे के साथ फिर आया और मेरी खरिपत पूछने लगा। उसे देखते ही मेरा खून खौल उठा और मैं उससे कहा कि चले जाने को कहा, क्योंकि उसने अपना एक भी बायदा पूरा नहीं किया था। उसने मेरी कोठरी पर ताला डलवा देने की धमकी दी। मैंने उससे कहा "जी चाहता मुझे गाली से उड़वा दो, मुझे परवाह नहीं। मैं जैसी तुम्हारी बेंसी मेरी।

एक और ददनाक कहानी स्नेहलता रेड्डी की है। वह एक बुबली पतली सड़की थी और राजनीतिक शुबह की वजह से 1 मई 1976 को बगलौर सेण्ट्रल जेल में कैद कर दी गयी थी। उसे न यह बताया गया कि उसका जुम क्या है न उससे कोई सबान पूछा गया।

सिनेमा देखनेवालों के लिए स्नेहलता रेड्डी इनाम जीतनेवाली क'नड फिल्म सत्कार की हीरोइन थी (जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उसके पति पट्टाभि थे)। बगलौर के नाट्य और कला जगत में भी उसका बहुत नाम था।

लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी जान पहचान जीवन के सभी धात्रों के लोगों के साथ थी—सांजलिस्ट नेताओं और बुद्धिजीवियों से, भारत के और विदेशों के नाट्यमन के कलाकारों से, लेखकों, चित्रकारों और जादूगरों से, और अपने बड़कर रेड्डी ऐम नोजवान लोग। मे जा अभी तक यह खोजन की कोशिश कर रहे थे कि जीवन का भय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। दिन रात उसके घर के दरवाजे दाम्तो के लिए हमेशा खुले रहते थे।

उसके मित्रों का इनाम बड़ा दाखरा और उसकी दोस्ती में इतनी गमजोगी—इन्ही बातों ने उस जेल में पहुँचा दिया। जात्र फर्नांडोस के साथ उसकी पुरानी दोस्ती थी। बन्स हूंग हालात में इस तरह की दोस्ती का होना ही ददनाक नतीजों की जड़

स्नेहलता की जेल की डायरी पर आधारित।

सुरंग का छोर

वन गया।

पलक भगवते उसकी सुंदर दुनिया बितकर गया और भय और भ्रमजानी आशवाभो की अंधेरी रात शुरू हो गयी। उसकी बेटी नन्दना को दो बार पूछताछ के लिए पकड़ा गया और पूरे परिवार पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी।

वह और उसके पति अपनी नयी फिल्म के लिए लाइटों का बंदोबस्त करने के लिए 27 अप्रैल को मद्रास आनेवाले थे। शाम को 4 बजे नन्दना को पुलिस तीसरी बार पूछताछ के लिए पकड़कर ले गयी।

वह शाम को 7 बजे लौटकर आयी। किसी को बताया भी नहीं गया था इसलिए पूरे परिवार का चिन्ता के भारे बुरा हाल था। उसके इस तरह अचानक गायब हो जाने से सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो गया था। सभी लोग बेहद परेशान थे। आखिरकार वे दोनों अपने बेटे कोणाक को वहीं छोड़कर रात को 9 बजे मद्रास के लिए रवाना हुए।

प्राची रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया और जोर से आवाज दी 'टेलीग्राम'। कोणाक ने दरवाजा खाला और फौरन ही उसकी दोनों बांह जकड़ ली गयी। साथ ही पुलिसवालों का एक झुंड दनदनाता हुमा घर में घुस आया। यह पता लगने पर कि बाकी परिवार मद्रास गया हुआ है, वे लोग उस लड़के को घसीटकर थाने ले गए। ज्यादातर पुलिसवाले सारे घर को उलट पुलटकर तलाशी लेने के लिए और स्नेहलता के 84 वष के बूढ़े माय और नौकरा से पूछताछ के लिए वहीं रह गये। वे लोग दूसरे दिन छ बजे वहाँ से विदा हुए।

मद्रास में स्नेहलता और उसके पति को जो पहली खबर मिली वह यह थी कि उनके बहुत पुराने दोस्त अम्पाराव और उनकी बेटी को उसी दिन सबेरे गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने फौरन टेलीफोन पर बगलौर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन काट दिया गया था। आखिरकार उन्होंने जब पड़ोसी से टेलीफोन मिलाया तो उन्हें पता चला कि रात को क्या हुआ था। उन्होंने बगलौर वापस जाने का फैसला किया और अपना सामान बांधने के लिए होटल लौट आये।

बगलौर पहुँचने पर उन्हें सीधे कालटन हाउस ले जाया गया। वहाँ स्नेहलता और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी लोगों को घर पहुँचा दिया गया। कोणाक का अभी तक कहीं पता नहीं चल सका था। स्नेहलता और पट्टाभि धक्कर खुर हो चुके थे। पिछली रात ब माटर चलाकर मद्रास गये थे और वहाँ जरा भी आराम किए बिना अगल ही दिन वापस आ गये थे।

सारी रात उन्हें एक कमरे में बिठाये रखा गया। पहरे पर जा सतारी या उससे बस इतना ही मालूम हो सका कि 'साइबर ईगा बरतरे' (साहब अभी आते ही होंगे)। उस रात कोई भी नहीं आया।

आखिरकार उस और उसके पति का पूछताछ के लिए अलग अलग कमरों में ले जाया गया। धीरे-धीरे तोड़ देने की तरकीब कारगर हुई। मालूम नहीं कि वह जान बूझकर अपनायी गयी थी या केवल सयोग था। इससे पहले कि कोई एक शब्द भी कहता या कोई सवाल करता, स्नेहलता ने खुद ही कहा, 'मैं वहाँ को वापस ले आओ मेरे पति को छोड़ दो, मेरी बेटी को न सताने का वायदा करो तो मुझे जो कुछ भी मालूम है सब बता दूँगी।

तब तक स्नेहलता और पट्टाभि का इसके अलावा और कोई कसूर नहीं बताया जा सका था कि एक राजनीतिक चरणार्थी के साथ उनकी खुली दोस्ती थी। १९६८ इतनी भोली थी कि जिस नई दुनिया में अचानक उसने अन्त रखा था उसकी

पाना उसने लिए मुश्किल था। धक्का, नींद और अपना बट की चिन्ता से वह इतना निढाल थी कि भनजाने ही उसने एक ऐसी बात कह दी थी जो उसने गले का फाग बन गयी।

उसके परिवार के सब लोग सकुशल हैं, यह साबित करने के लिए वह एक करके उसके कमरे में लाया गया। फिर सबको घर भेज दिया गया, पहले उस ही वहाँ रोक रखा गया। भगले हफ्ते के दौरान जो कुछ हुआ उससे कुछ धीरज बढ़ा।

स्नेहलता से कई बार पूछ-ताछ की गयी लेकिन उसके पास बताने को था ही क्या। परिवार वालों को उसका विस्तार, उसके कपड़े और खाना लाने की इजाजत दे दी गयी। उसके साथ राजनीतिक नजरबन्द इन्हीं जैसा सलूक किया जाने लगा। परिवारवालों को उससे मुलाकात करने की भी इजाजत थी।

7 मई की शाम को जब पट्टरिम पाना लेकर वहाँ पहुँचा तो कार्लटन हाउस में ताला पड़ा हुआ था और चारों ओर सन्नाटा था। यह साबित कि पूछ-ताछ के लिए शायद उसे किसी और जगह ले जाया गया होगा, वह वहीं बैठकर राह देखने लगा। रात का साढ़े दस बजे वह घर लौटा, लेकिन आधी रात के करीब फिर वहाँ गया। अब भी वहाँ कोई नहीं था। घर लौटकर कितनी ही जगह टेलीफोन किया पर कुछ नतीजा नहीं निकला। उस रात घर में कोई भी नहीं सोया। दूसरे दिन सुबह किसी दयालु गुमनाम आदमी ने फोन पर उन्हें बताया कि उसे शक है कि स्नेहलता को जेल पहुँचा दिया गया है।

जिस तरह उस पहली गिरफ्तारी के वक्त चरका दिया गया था, उसी तरह चरका देकर उसे जेल पहुँचा दिया गया। उसके परिवारवालों को कानोबान तब तक नहीं हुई। उस दिन शाम के करीब उसे बताया गया कि उसे छोड़ा जाना है इसलिए अपना सामान बाँधकर तयार रहे। सबसे पहले वे लोग एक मजिस्ट्रेट की भदालत पर चले।

बाकी कार्रवाई तो रस्मी लग रही थी, लेकिन अधिकांश उसने कार्रवाई में ये शब्द पढ़े कि 'तुम्हें नजरबंद करने का हुक्म दिया जाता है।' मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि जैसा ही उसके परिवार वाले जमानत के लिए पसा जुटा लेंगे उसे रिहा कर दिया जायेगा। स्नेहलता ने एक पुलिसवाले से कहा कि वह फोन करके उसके पति को बता दे कि वह इस वक्त कहाँ है। वह फोन तक गया और फोन पर बात करने का नाटक भी किया, लेकिन न कभी फोन मिलाया गया और न ही भगले दिन सुबह तक उसके परिवार वालों का उसका कुछ हाल मालूम हो सका।

इसी बीच कागजात पर दस्तखत हो गये, हुक्म जारी हो गया। स्नेहलता एक बार फिर कार्लटन हाउस पहुँचा दी गयी। तब तक शाम हो चुकी थी। मई के महीने में झुटपुट के वक्त, जब चारों ओर उदासी छा जाती है स्नेहलता को बगलोर मेण्डल जेल की ढरावनी, बेरहम और पथरीली इमारत में पहुँचा दिया गया। वहाँ पहुँचने पर उसे पहले भ्रमभंगजनक अनुभव से गुजरना पड़ा। इसने बाद तो उस इस तरह के न जान कितनी बार अनुभव हुए।

उसके सामान की एक एक चीज की तलाशी ली गयी, त्रिदो के रजिस्टर में उसके दस्तखत और उसके झूठे का निशान लिया गया, और खुद उसके सारे कपड़े उतरवाकर उसकी तलाशी ली गयी।

इसके बाद उसे एक सीली हुई कोठरी में बंद कर दिया गया जो बस इतनी बड़ी थी कि एक आदमी भी उसमें मुश्किल में रह सकता था। कोठरी के सिरे पर पानाने-पेशाब के लिए एक छोटी सी नाली थी और दूसरे सिरे पर साढ़े के सीखवो

का एक दरवाजा था। उसे अपने घरवाला पर इतना गुस्सा आ रहा था कि कि उसका डर और उसकी उदासी भी कुछ दब गयी। उन लोगों से इतना भी न हुआ कि मुझे छुड़ाने की कोशिश करते या मुझसे मिलने ही आ जाते। उसे क्या मालूम था कि उन लोगों ने सारी रात जागकर काटी थी। पुलिसवाला ने कभी फोन करके उहे बताया ही नहीं था कि वह कहाँ है।

अगले दिन सुबह उन्हें मालूम हुआ कि वह जेल में है और वे उसकी जमानत की अर्जी देने मजिस्ट्रेट के घर गये। मजिस्ट्रेट ने उहे यकीन दिलाया कि अगर उनका वकील बाकायदा अर्जी देगा तो जमानत मंजूर कर दी जायेगी। वकील को इस बात का इतना भरोसा नहीं था, फिर भी कोशिश उसने की। उसे निजी तौर पर बता दिया गया कि इस मामले में जमानत नहीं हो सकती। कद की यातना शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे इस पूरे कांड पर से रहस्य का परदा उठने लगा।

पहले स्नेहलता पर भारतीय दण्ड संहिता की दफा 120 और 120 ए के तहत मामला दज किया गया था। आखिरकार जब सरकार कोई भी जुम साबित नहीं कर सकी तो मामला वापस ले लिया गया। लेकिन स्नेहलता अब भी जेल में ही कैद रही इस बार मीसा में। अब बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी।

धीरे धीरे जेल की हकीकत स्नेहलता की समझ में आने लगी। उसकी सेहत इतनी खराब हो चुकी थी कि आखिरकार इसी बुनियाद पर उसे छोड़ दिया गया।

जेल के बाहर आने के कुछ ही दिन बाद दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत हो गयी।

लारेंस और स्नेहलता रेड्डी जस और न जान कितने लोग थे। वे सभी क्यादतियों और यातनाओं के शिकार हुए थे।

भगलौर के बनारा कालेज के छात्र नेता उदयशंकर को उसके घर से बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने ब दर धाने में उसे इतने बेंत मारे और इतनी ठोकरें लगायी कि उसका सारा बदन नीला पड़ गया। उसे न खाना दिया गया न पानी। श्रीकांत देसाई को, जो कानून की आखिरी साल की पढ़ाई कर रहा था और विद्यार्थी परिषद् की कर्नाटक शाखा का ज्वाइंट सेक्रेटरी था, बड़ी दरिन्दगी से पीटा गया और हवाई जहाज बनाया गया।

माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख कामकर्त्ता राबिन कलिता को मीसा में गिरफ्तार किया गया था और वह इलाज के लिए मीहाटी मेडिकल कालिज के अस्पताल में भरती था। उसकी हालत बहुत बिगड़ गयी। उसके घरवालों को उसकी देखभाल करने की इजाजत नहीं दी गयी, बल्कि यहाँ तक कि उससे मिलने भी नहीं दिया गया। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा था फिर भी उसे हफ्ते की पहनाये रखी जाती थी। हफ्ते की पहने-पहने ही उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

हेमन्त कुमार विनोई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह नई दिल्ली के बुद्ध जयन्ती पार्क में पिकनिक पर गया हुआ था। उसे उल्टा लटका दिया गया और नगे तलुबों को जलती हुई भीमबलियों से दागा गया। उसकी नाक में और पालाना करने की जगह पिंसी हुई मिर्चें ठूस दी गयी। इन तमाम यातनाओं के बावजूद उसने यह मानन से इकार कर दिया कि उसने प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई 'पहयन्त्र' रचा था, क्योंकि ऐसा कोई पहयन्त्र था ही नहीं। पुलिस चुप होकर बैठ गयी।

एक समारोह में जहाँ राष्ट्रपति भाषण दे रहे थे, दूसरे सड़कों के साथ बाँटने के जुम में दो सड़के राजेश और अनिल पकड़े गये। एक पाट्रह सास का

दूसरा तेरह साल का। उन्हें बड़ी बेरहमी से पीटा गया और बड़े से धान के पूरे फा पर उनसे भाड़ू लगवायी गयी।

होज खास धाने की पुलिस वहाँ के कुछ कांग्रेसी कामकर्ताओं को तुरा करने के लिए सुनोल और मनोज नामक दो नाबालिग लड़कों का जोड़ीवाड़ा से पकड़कर ले गयी। उन्हें इतना पीटा गया कि आखिरकार उन्होंने वही बयान दे दिया जो पुलिस उनसे चाहती थी।

चंडीगढ़ के चकील सी० एल० लखनपाल का जेल में दिन का महान दौरा पड़ा। उसे पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इन्स्टीट्यूट के अस्पताल ले जाया गया और कुछ ही घंटों के अन्दर वहाँ उसकी मौत हो गयी। वहाँ के डाक्टरों ने उसके इलाज के मामले में लापरवाही बरती थी।

पुलिस ने अपना गुस्सा पड़े लिखे लोगों पर खास तौर पर उतारा। गिल्बी यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा अध्यापक तो 26 जन को तबड़े ही पकड़ लिये गये थे। उनमें से एक प्रो० पी० कोहली, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसीडेंट हैं और कुछ प्रपग भी हैं, को चौबीस घंटे तक लगातार हवा नात में खड़ा रखा गया। पुलिसवाले उन पर गालियाँ और जूता की बौछार करते रहे और उन्हें इधर-से उधर धक्का देते रहे। कितनी ही बार वह गिर पड़े लेकिन उन्हें फिर खड़े हान पर मजबूर किया गया।

कुछ अध्यापकों को तो क्लास में पढ़ाते वक़्त गिरफ्तार किया गया। अदालतों के दृष्टि से जब कुछ अध्यापक छाड़ भी गये तो उन्हें जेल के फाटक ही पर वहीं पहलेवाले जुम लगाकर या कोई जुम लगाय बिना ही दुबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब स्कूली कॉलेजों में सबने मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठायी तब ज़ही जाकर यह दुबारा गिरफ्तार किये जाने का सिलसिला खत्म हुआ।

घोर वामपंथी नक्सलवादियों के खिलाफ ज्यादतियों का सिलसिला तो इमजेंसी के पहले ही से चल रहा था, अब उन्हें बिना किसी बजह के ही पकड़ा जाने लगा। पुलिस और नक्सलवादियों के बीच हथियारबंद मुठभेड़ों के न जाने कितने किस्से बयान किये गये हैं लेकिन इस बात पर किसी भी तरह यकीन नहीं किया जा सकता कि कुछ दर्जनों नक्सलवादी गिनती की पुरानी बंदूकें लेकर हर तरह के हथियारों से लस हज़ारों पुलिसवालों से घंटों घुसी हथियारबंद लड़ाइयों में टक्कर लेते थे।

मिस मेरी टाइलर ने, जिन्हें छ साल तक नजरबंद रखा गया, 6 जुलाई को अपनी रिहाई के बाद बताया कि 'बिहार में छापेमारों का झुंड कायम करने की कोशिश करने' के कूठे आरोप किस तरह गढ़े गये थे। उन्होंने कहा कि यह छापेमारों का गिरोह नहीं था बल्कि कुछ जाशीने नौजवान वामपंथी कार्यकर्ता थे जो बिहार और पश्चिम बंगाल के दूर दूर के देहातों में लोगों की ज़मींदारों और साहूकारों का मुकाबला करने और भूमि-सुधार लाभू करवाने के लिए बड़ावा दे रहे थे। उनमें से बहुत मोठे ही ऐसे हगि जो जेल में मिनने से पहले एक-दूसरों को जानते भी रहे हों। गिरफ्तार करने के बाद मेरी टाइलर को साल भर हज़ारोंबाम जेल में तनहाई में रखा गया और उसके बाद अदालत के सामने हाज़िर करने के लिए जमशेदपुर जल में लाया गया। रिहाई के बाद उन्होंने बताया कि इमजेंसी के एतान के बाद जो अध्यापक गिरफ्तारियों हुई थी उनकी बजह से जिस जेल में सिर्फ 137 बंदियों के लिए इतना कम था, 1,200 आदमी ठूस लिये गये थे।¹

नक्सलवादियों की समस्या कोई नयी नहीं थी। वह 1963 से चली आ रही थी जब धोर वामपंथियों ने चीन भारत सीमा के पास नक्सलवाड़ी (पश्चिम बंगाल) में जमींदारों को निकालकर जमीन पर कब्जा कर लेने के लिए एक हिंसक आन्दोलन शुरू किया था।

सरकार को ज्यादा फिक्र अण्डरग्राउण्ड आन्दोलन की थी। लगभग सात भर हो चुका था और जाज फर्नांडीज को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका था। श्रीमती गांधी ने चोटी के अफसरों की एक मीटिंग करके उन्हें बहुत लताड़ा कि आखिर अब तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका। एक अफसर ने बताया कि वे लोग जाज के संगठन में घुस गये हैं और उनके आदमी अब उस संगठन का हिस्सा बन गये हैं। उसने कुछ ही दिन में जाज की गिरफ्तारी का वायदा किया। और हुआ भी यही। जाज को 10 जून को कलकत्ते में गिरजाघर से मिले हुए एक घर से गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी से अण्डरग्राउण्ड संगठन को बहुत बड़ा धक्का लगा।

अण्डरग्राउण्ड आन्दोलन सजय की आँखों में हरदम खटकता रहता था। नसबन्दी की मुहिम के दौरान उसने जो क्यादतियाँ की थी उनका प्रचार पूरे ब्यौरे के साथ अण्डरग्राउण्ड से किया जा रहा था।

सचमुच, सजय यह मुहिम बड़ी बेरहमी से चला रहा था। उसने हर मुख्यमन्त्री के लिए तय कर दिया था कि किसे कितनी नसबंदियाँ करानी हैं। मुख्यमन्त्रियों ने अपना यह बोझ अफसरों में बाँट दिया था। सजय को खुस करने के लिए सारे मुख्य-मन्त्री नसबन्दी के बारे में उसकी 'इच्छाओं' को पूरा करने के लिए एक-दूसरे से होड़ लगाकर काम कर रहे थे। इसकी परवाह न सजय को थी न श्रीमती गांधी को कि यह काम कौन पूरा किया जाये बस काम पूरा होना चाहिए या कम-से-कम कहा यह जाये कि वह पूरा हो गया है।

सजय की नतीजे से मनलब था, तरीके से नहीं। जबरी नसबन्दी घटले से चलती रही।

दिल्ली में ख़सताना सुल्ताना नाम की एक छबीली लड़की, जो सजय को देवता मानती थी, परिवार नियोजन के काम को बढ़ावा देने के लिए भागे आयी। उसकी कोई सरकारी हैसियत न होते हुए भी जब वह शहरपनाह के अंदर पुरानी दिल्ली की सड़कों पर निकलती थी तो पुलिस की गारद उसके साथ चलती थी, एक जीप उसकी गाड़ी के भागे और एक पीछे। बाद में उसने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उसे इस बात पर बड़ा नाज है कि 'नसबन्दी की मुहिम के साथ—और सजय के साथ—उसका नाम भी जुड़ा हुआ है'।

आवादी की रोकथाम की पॉलिसी के तहत भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को 4 लाख नसबंदियों की ज़िम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन सजय को खुग करने के लिए उत्तर प्रदेश वालों ने 15 लाख नसबंदियाँ कराने का बीड़ा उठा लिया। हर सरकारी विभाग की ज़िम्मेदारी बाँध दी गयी। हर ज़िले को अलग अलग बता दिया गया कि किस कितनी नसबंदियाँ करानी हैं। अध्यापकों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए तो यहाँ तक नुगतना पड़ा कि जो भी आदमी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पायेगा उसे न सरकारी दो जायेंगी, न उसकी तनहाह बढ़ायी जायेगी।

यह मुहिम जुलाई में तेज़ की गयी और महीन भर बाद तो वह तूफानी रफ्तार से चल पड़ी। जय लोग न जबरी नसबन्दी का विरोध किया तो उसकी वजह से हिंसा की 240 घाटाएँ हुई। जन भ राज का मोसत 331 नसबन्तियों का था, जो जुलाई में बढ़कर 1,578 हो गया और अगस्त में जब इसके लिए सास बप लगाये गये तो मोसत

और उहे तरह-तरह से स्तावर उनके दिल मे दहशत बिठा दी ।

हरियाणा मे कितने ही लोगो ने नसबन्दी कराने स इकार कर दिया और जो सरकारी अफसर जबदस्ती उहे पकडकर नसबन्दी के कैपो मे ले जाने के लिए आये उनका सहोने डटकर मुकाबला किया । इन लोगो को अघाघु घ गिरफ्तार किया गया और हर तरह की यातनाएँ दी गयी । गुडगाव जिले के एक नौजवान को वह्श की पुलिस ने अपनी बिरादरीवालो को नसबन्दी के खिलाफ भडकाने के अपराध मे पकडकर एक अघी कोठरी मे बन्द कर दिया । उनस पूछ ताछ के दोरान उसके बाल और नाखून नोच डाले गये और जब उसे छोडा गया तो वह दोनो बानो से बहरा हो चुका था ।

महेन्द्रगढ के एक नौजवान सरकारी भौकर ने जब इस मुनियामे पर नसबन्दी कराने से इकार किया कि उसके कोई बच्चा नही था तो उसे इतना सताया गया कि वह पागल हो गया ।

रोहतक जिले की एक बूढी मास्टरनी को जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश दिया कि जब तक वह दो आदमियो को नसबन्दी के लिए नही लायेगी तब तक उसे तनखाह नही मिलेगी । सफेद बालावाली उस बिधवा को कोई भी न मिला । आखिरकार, कहा जाता है कि वह दो पागल भिलारियो को पकडकर नसबन्दी के कप म लायी तब कही जाकर उसे तनखाह मिली ।

सबने सपादा मुसीबतें इस राज्य के हरिजनो और पिछडे वर्गों के दूसरे लोगो को भेलनी पडी । सरकार को इस बात से कोई मतलब नही था कि नौजवान कुँभारे लडके हो या ऐसे बूढे जिनकी बीवियाँ मर चुकी हैं नपुसक लोग हो या ऐसे लोग जिनकी नसबन्दी पहले हो चुकी है—सभी का नसबन्दी करानी पडती थी । महत्त्व लोगो या उनकी भावनाओं का नही बल्कि इस बात का था कि गिनती पूरी होनी चाहिये ।

बिहार मे सरकारी अफसरों को नसबन्दी की मुहिम के दोरान अपनी 'कार-गुजारी' दिलाने का सबसे आसान मौका मिल गया । नसबन्दी की सबसे गहरी मार शायद आदिवासियों पर पडी । जिस डिप्टी कमिश्नर को सबसे पहले 'अच्छा काम' करने के इनाम मे सोन का मेडल दिया गया वह सिंहभूम जिले मे तैनात था, जो छोटा नागपुर के आदिवासी इलाके का एक हिस्सा है । आदिवासियों का एक और जिला है राँची, वहाँ का सबसे बडा हाकिम भी बहुत पीछे नही था । ज्यादातरियाँ भोजपुर जिले मे भी की गयी, लेकिन वहाँ सबसे ज्यादा मुसीबतें आदिवासियों ने नही भेली, सभी पर बराबर मार पडा ।

पूरबी पटना मे भी गहवड हुई । जबरी नसबन्दी की वजह से बिफरी हुई भीड पर पुलिस ने गोली चलायी, जिसमे एक आदमी मारा गया और कई घायल हुए, लेकिन सेंसर ने अलवारो को हुक्म दे दिया कि वे सिर्फ सरकारी बयान छापें, जिसमे कहा गया था कि फुटपाथ पर रहनेवालो के हटाये जाने पर तिलमिलाये हुए लोगो पर पुलिस ने गोली चलायी । इस घटना के चौबीस घंटे के अंदर युवक बाप्रेस के लोगो ने नसबन्दी का प्रचार करने के लिए बडी-बडी सडकों के किनारे जो तम्बू गाढ़े थे वे सब ग्रायब हो गये । ये फुटपाथ पर रहनेवाले वे लोग नही थे जिन पर गोली चलायी गयी थी ।

राने का मेडल जीतने की होड मे पटना ने लोबसभा के खुनाबो का ऐलान होने के लगभग दो हफ्ते पहल पीछे स आकर सबको पछाड दिया । केन्द्रीय सरकार ने बिहार के हिस्से मे उ लाभ नगबन्दियाँ रखी थी, लेकिन वहाँ हुई सारे छ सास । इस बात से वहाँ के स्वास्थ्यमंत्री बिजेन्दरी दुवे को इतना जोश आया कि उन्होंने अफसरों

राज 5,644 नसबंदी दियो तब पहुँच गया। कई जगह तो यह दखे बिना ही कि किसी उम्र कितनी है, किसी की शादी भी हुई है या नहीं, लोगो को पकड़कर जबरदस्ती नसबन्दी कर दी गयी।

हिंसा की पहली बड़ी घटना 27 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुत्तानपुर जिले में नरकाडीह नामक गाँव में उस वक़्त हुई, जब कमिश्नर साहब न लोगों को 'राखी करने' के लिए जमा किया। लोगो ने इस कार्यक्रम का विरोध किया और भफभरा का गाँव के बाहर खदेड़ दिया। पुलिस न गाली चलायी जिममे तेरह आदमी जान से मारे गए और बीसिया गोलियों से घायल हुए।

जिले के अधिकारियों से हुक्म पाकर पुलिसवाले जबरी नसबन्दी के लिए गाँव वालों को पकड़ पकड़कर लाने के काम में बिलकुल पागलों की तरह जुट गये। गाँवों में घातक छाया हुआ था। सभी लोग अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए भाग भाग कर चेता में जा छिपे। नामी से नामी डाकुओं के जमाने में भी उन्हें कभी अपना घर नहीं छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब खेतों में रहना गाँववासियों के लिए एक घाम बन हो गयी थी। पुलिस के छापो की वजह से उन्हें अपने घरों में रहत डर लगता था।

नसबन्दी की लहर चढ़त चढ़त राज 6,000 आप्रदेशियों तक पहुँच चुकी थी, कि इसने में 18 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर में एक और धमाका हुआ। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नसबन्दी के कप लगवाये और लोगों को बड़ी बड़ी रकमें खर्च दे म देने पर मजबूर किया गया। जो इकार करता था उसे भीमा में या डी० आई० आर० में बंद कर दिये जाने की धमकी दी जाती थी। पुलिसवाले ताक में खड़े रहते थे और लोगो को बस के झुंडों से और रेलवे स्टेशनों से पकड़कर ले जाते थे और जबरदस्ती उनकी नसबन्दी कर दी जाती थी।

एक सास बस्ती से तीन दिन तक बाकायदा लोगों को पकड़कर ले जाया गया और उनकी नसबन्दी कर दी गयी। यह भी नहीं देख पाया कि कौन कुमारा है और किसकी शादी हो चुकी है किसके बच्चे हैं किसके नहीं हैं, कौन जवान है कौन बूढ़ा। एक बार जब इसी तरह भठारह आदमियों को नसबन्दी के प में ले जाया जा रहा था तो लोगो का गुस्सा बामू से बाहर आ गया। बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गयी और उन लोगो को छोड़ देने की माँग करने लगी। फिर पथराव शुरू हुआ। पुलिस ने पहले आसू गैस के गोले छोड़े और जब भगदड़ मची तो उसने उन पर गोली चला दी। पञ्चवीस आदमी मारे गये और आठ लापता हो गये। (उनका आज तक पता नहीं लगा सका है।) इस वारदात को लोग 'छोटा जलियावाला बाग' कहने लगे। कपूरू लगा दिया गया और एक दूसरी बस्ती में चार आदमी कपूरू तोड़ने की वजह से गोलियों के झूट दिये गए।

संसारविश के बावजूद, इन घटनाओं की खबर जबानी ही चारों तरफ फैल गयी और मुजफ्फरनगर से लगभग पचीस किलामीटर दूर इसके जिलाफ़ भाषाज उठाने के लिए एक जुलूस निकाला गया। जब इसाके में कुछ जाने-माने लोगो के कहने पर जुलूस तितर बितर होने लगा तो पुलिस ने सागा का पीछा किया। जब लोगो ने मस्जिद में घुसकर अपनी जान बचाने की कोशिश की तो पुलिस भी नन्दनानी हुई आदर घुस भायी और गोली चलाने लगी। तीन आदमी जान में मारे गये।

बस्ती जिले के एक गाँव में एक बी० डी० ओ०, एक पचासत सक्करी और एक घामसक इस बात का लेला-आला करन गए कि कितन जादे एस है जिन पर नसबन्दी लागू की जा सकती है। गुस्से से बिफरी हुई भीड़ ने उनकी मोटी मोटी बाटकर फेंक दी। पुलिस को जो गुस्सा भाया तो उसने बिना गिनकर वहाँ के लोगो से बदला लिया

घोर उन्हें तरह-तरह से सताकर उनके दिल में दहशत बिठा दी।

हरियाणा में कितने ही लोगो ने नसबंदी कराने से इकार कर दिया और जो सरकारी भ्रष्टाचार उबड़ती उड़ी पकड़कर नसबंदी के कपो में ले जाने के लिए आये उनका उन्होंने डटकर मुकाबला किया। इन लोगो को अघाघु घ गिरफ्तार किया गया और हर तरह की यातनाएं दी गयीं। गुडगांव जिले के एक नौजवान को वहाँ की पुलिस ने अपनी बिरादरीवालों को नसबंदी के खिलाफ मड़काने के अपराध में पकड़कर एक अंधी कोठरी में बंद कर दिया। उससे पूछ-ताछ के दौरान उसके बाल और नाखून नोच डाले गये और जब उसे छोड़ा गया तो वह दोनों कानों से बहरा हो चुका था।

महे द्रगढ़ के एक नौजवान सरकारी नौकर न जब इस बुनियाद पर नसबंदी कराने से इकार किया कि उसके कोई बच्चा नहीं था तो उसे इतना सताया गया कि वह पागल हो गया।

रोहतक जिले की एक बूढ़ी मास्टरनी को जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश दिया कि जब तक वह दो आदिमियाँ को नसबंदी के लिए नहीं लायेगी तब तक उसे तनख्वाह नहीं मिलेगी। सफेद चालावाली उस बिधवा को कोई भी न मिला। अखिर-कार, कहा जाता है कि वह दो पागल भित्तिारियों को पकड़कर नसबंदी के कपो में लायी तब कही जाकर उसे तनख्वाह मिली।

सबसे ज्यादा मुसीबतें इस राज्य के हरिजनो और पिछड़े वर्गों के दूसरे लोगो को झेलनी पड़ी। सरकार का इस बात से कोई मतलब नहीं था कि नौजवान कुमारे लड़के हो या ऐसे बूढ़े जिनकी बीवियाँ मर चुकी हैं नपुंसक लोग हो या ऐसे लोग जिनकी नसबंदी पहले हो चुकी है—सभी को नसबंदी करानी पड़ती थी। महत्व लोगो या उनकी भावनाओं का नहीं बल्कि इस बात का था कि गिनती पूरी होनी चाहिये।

बिहार में सरकारी भ्रष्टाचारों को नसबंदी की मुहिम के दौरान अपनी 'कार गुजारी' दिखाने का सबसे आसान मौका मिल गया। नसबंदी की सबसे गहरी मार आपस आदिवासियों पर पड़ी। जिस डिप्टी कमिश्नर को सबसे पहले 'अच्छा काम' करने के इनाम में सोने का मेडल दिया गया वह सिंहभूम जिले में तनात था, जो छोटा नागपुर के आदिवासी इलाके का एक हिस्सा है। आदिवासियों का एक और जिला है राँची, वहाँ का सबसे बड़ा हाकिम भी बहुत पीछे नहीं था। ज्यादातर भोजपुर जिले में भी की गयी, लेकिन वहाँ सबसे ज्यादा मुसीबतें आदिवासियों ने नहीं झेली, सभी पर बराबर मार पड़ी।

पूरबी पटना में भी गड़बड़ हुई। जवरी नसबंदी की वजह से बिकरी हुई भीड़ पर पुलिस ने गोली चलायी, जिसमें एक आदिमी मारा गया और कई घायल हुए, लेकिन सेंसर ने भ्रष्टाचारों को हुक्म दे दिया कि वे सिर्फ सरकारी बयान छापें, जिसमें कहा गया था कि फुटपाथ पर रहनेवालों के हटाये जाने पर तिलमिलाये हुए लोगो पर पुलिस ने गोली चलायी। इस घटना के चौबीस घंटे के अंदर युवक कांग्रेस के लोगो ने नसबंदी का प्रचार करने के लिए बड़ी-बड़ी सड़कों के किनारे जो तम्बू गाढ़े थे वे सब गायब हो गये। य फुटपाथ पर रहनेवाले वे लोग नहीं थे जिन पर गोली चलायी गयी थी।

सोने का मेडल जीतने की होड़ में पटना ने लोकसभा के चुनावों का ऐलान होने के लगभग दो हफ्ते पहले पीछे से आकर सबको पछाड़ दिया। केन्द्रीय सरकार ने बिहार के हिस्से में 3 लाख नसबन्दियाँ रखी थी, लेकिन वहाँ हुई साढ़े छ लाख। इस बात से वहाँ के स्वास्थ्यमंत्री बिदेश्वरी दुवे को इतना जोश आया कि उन्होंने भ्रष्टाचारों

को सलकारा कि वे 1976 77 का सरकारी साल पूरा होने से पहले ही दस लाख के निशाने तक पहुँच जायें।

बिहार में जो 'अच्छा काम' किया गया या उसकी खुरी में सजय ने चार बार उस राज्य का दौरा किया। चुनाव से पहले जब सजय भाखिरी बार बिहार गया तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीताराम केसरी ने पटना में एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि सजय गांधी राजनीति के सिविज पर उभरता हुआ नया सितारा है, अब कांग्रेस के नेतृत्व को और देश को पचास साल के लिए कोई खतरा नहीं है। सजय का जो शाही स्वागत किया गया उस पर कम से कम दस लाख रुपये खर्च किये गये। इसमें से कम-से-कम गांधी रकम बिहार सरकार ने सुरक्षा के बंदोबस्त और मोटरों की दोढ़ घूप और भीड़ को काबू में रखने के इतना पर खर्च की थी। बाकी गांधी रकम बड़े बड़े सेठों और व्यापारियों ने दी थी। नसबन्दी के लिए खास तौर पर लगाये गये कम्पों में पंजाब की सरकार जितनी इस काम के लिए बितना जोश था। आपरेशन में गड़बड़ी हो जाने की वजह से कुछ लोगो के मर जाने की भी खबरें मिली।

नसबन्दी के सिलसिले में की गयी किसी प्यादती की खबर कोई प्रखबार नहीं छाप सकता था। और न श्रीमती गांधी का 'घराना' उन पर यकीन हो करने को तैयार था, हालाँकि वहाँ सबको मालूम था कि नसबन्दी में और-जबदस्ती की जा रही है। खुफिया विभाग को कुछ प्यादतियों का पता लगा और उसने इनकी रिपोर्ट प्रयानमन्त्री के पास भी भेजी और उनके सकेटरी के पास भी। लेकिन उनके बारे में शायद ही कभी कोई कारवाई की जाती थी। यह कहकर लीपा पोती कर दी जाती थी कि कुछ न कुछ जबदस्ती तो करनी ही पड़ती है। केन्द्रीय सरकार के राज्य-मन्त्री शाहनवाज खाँ ने श्रीमती गांधी को मुजफ्फरनगर की घटना के बारे में एक रिपोर्ट भेजी और उसमें बताया कि किस तरह पुलिस न जान बूझकर ताकत इस्तेमाल की थी और लोग पर जुल्म डाले थे। श्रीमती गांधी ने बस इतना कहा कि बातों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। इस रिपोर्ट की एक कापी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली इल्हमद को भी दी गयी। उन्हें पढ़कर बहुत धक्का लगा। उन्होंने प्रधानमन्त्री से इसकी शिकायत की और अपनी उस डायरी में भी इसे दर्ज किया, जो वह रोज पाबन्दी के साथ लिखते थे।

हाथ पाब की ओर जबदस्ती भवेलता तरीका नहीं था जो इस्तेमाल किया गया। सरकार न सकुलर जारी करके यह आदेश दे दिया कि जो नमचारी या तो खुद अपनी नसबन्दी न कराये या दूसरो की नसबन्दी न कराये उसकी तरफकी रोव दी जाये और तनल्वाह न बढ़ायी जाये। अगले साल के लिए किसी का मोटर चलाने का नया लाइसेंस भी तभी बनाया जाता था जब उसने कम से कम कुछ लोगो की नसबन्दी करापी हो।

दिल्ली प्रशासन ने यह आदेश जारी कर दिया कि उसने जा नमचारी नसबन्दी के साथ हैं उन्हें उनकी तनल्वाह नसबन्दी का सर्टिफिकेट दिसाने पर ही दी जायेगी। कार्पोरेशन के प्राइमरी स्कूलों के 10 000 अध्यापकों को जवानी हुम दे दिया गया कि व कम से-कम पाँच पाँच आदमियाँ को नसबन्दी के लिए राजी करें। स्कूलों की ट्रेड मिस्ट्रेसों को यह अधिभार दे दिया गया कि जब तक किसी विद्यार्थी का बाप या उसकी माँ नसबन्दी न कराये तब तक उस पास न किया जाय। व्यापारियों के कुछ प्रतिनिधियों का दिल्ली के सफिनेट-मन्वर न राजनिवास

पर बुलाकर उनसे कहा कि वे यह तय करें कि हर महीने वे अपने जितने कर्मचारियों और दूसरे लोगों को नसबन्दी के लिए राजी करेंगे।

कई कम्पनियाँ, जहाँ मजदूर रोजनदारी पर या ठेके पर काम करते थे, इसलिए बंद हो गयीं कि मजदूरों ने यह फैसला कर लिया था कि नसबन्दी का खतरा मोल लेने से अच्छा है कि वे अपने गाँव लौट जायें।

सरकार ने आबादी की रोकथाम के बारे में एक राष्ट्रीय पॉलिसी का भी ऐलान किया था। सजय दो बच्चे प्रति परिवार की सीमा बांधना चाहता था लेकिन श्रीमती गांधी और उनका बाकी परिवार तीन के पक्ष में था और मही बात मान ली गयी। राष्ट्रीय पॉलिसी में लक्ष्य यह रखा गया था कि आबादी के हर एक हजार आदमियों के बीच इस वक़्त हर साल 35 बच्चे पैदा होते हैं, इसे घटाकर 1984 तक 25 पर पहुँचा दिया जाये। उम्मीद की जाती थी कि तब तक आबादी बढ़ने की रफ्तार भी 2.4 प्रतिशत से घटकर 1.4 प्रतिशत रह जायेगी। विवाह करने की कम से कम उम्र बढ़ाकर लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल कर दी गयी। नसबन्दी कराने पर रद्दों और शोरतो को नक़द पसा भी दिया जाता था। लेकिन यह फैसला भलग भलग राज्यों के हाथ में छोड़ दिया गया कि अगर वे चाहें तो नसबन्दी को साजिमी बना देने का क़ानून बना सकते हैं। (उस समय हमारी आबादी 61 करोड़ 50 लाख थी।)

नसबन्दी के अलावा सजय को एक धुन थी, दिल्ली की खूबसूरत बनाने की। वह डी० डी० ए० के कर्त्ता घन्टा जगमोहन को रोज़ बताया करता था कि क्या करना है और गंदी बस्तियों को सफ़ाई के सिलसिले में जितना काम होता था उसका लेखा जोखा करता था।

इतने बड़े पैमाने पर, जितना कि पहले कभी नहीं हुआ था घर-कानूनी घरों और भुगी भोपड़ियों के गिरा दिये जाने की वजह से कई बस्तियों से पुराने बसे हुए परिवार छोड़ छोड़कर जाने लगे थे। इसी तरह का एक इलाका वह था जिस मुस्लिम आबादी कहा जाता था। नुक़मान गेट के इलाके में जहाँ बहुत-से गैर मुसलमान भी रहते थे, 13 अप्रैल को जब बस्ती के बाहर बुलडोज़र जमा होने लगे तो लोग बहुत परेशान होकर उठें देखते रहें। वह वैसाही का दिन था और उस इलाके में रहनेवाले पंजाबियों ने अपना यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया था।

वहाँ के रहनेवाले 16 अप्रैल को एच० के० एल० भगत से मिले, जिन्होंने उनको यकीन दिलाया कि उनके घर ढाये नहीं जायेंगे। उन्होंने कहा, यह हो ही कैसे सकता है जबकि ये इमारतें कई पीढ़ियों से वहाँ खड़ी हुई हैं? लेकिन बुलडोज़र फिर भी नहीं हटे।

अप्रैल 19 अप्रैल को बुलडोज़र नुक़मान गेट की तरफ़ बढ़ने लगे। कुछ लोग झुण्ड बनाकर बुलडोज़रों की रोकने के लिए बस्ती के बाहर दरगाहे इलाही के सामने बैठ गये जिस पर अभी हाल ही में सफ़ेदी की गयी थी। कई और मुहल्लेवाले आकर शामिल हो गये और बढ़ते बढ़ते वहाँ कई सौ आदमी जमा हो गये।

दोपहर के करीब ट्रकों में भर भरकर बन्दूक से लैस सी० आर० पी० के सिपाही और दिल्ली के पुलिसवाले वहाँ आने लगे। कुछ ही मिनटों में धक्का मुक्की शुरू हो गयी और शोर गुल मचने लगा। पुलिसवाले रास्ता साफ़ करने की कोशिश कर रहे थे और लोग उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे। इतने में पुलिस की तरफ़ से पत्थरों एक की बोछार हुई। उस वक़्त तक लोग गैर तो मचा रहे थे पर बाकी सब शान्ति थी। भीड़ ने भी पुलिस पर जवाबी पहराव किया।

को ललकारा कि वे 1976 77 का सरकारी साल पूरा होने से पहले ही दस लाख के निशाने तक पहुँच जायें।

बिहार में जो 'भ्रष्टाचार' किया गया था उसकी खुशी में सजय ने चार बार उस राज्य का दौरा किया। चुनाव से पहले जब सजय आखिरी बार बिहार गया तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीताराम केसरी ने पटना में एक पब्लिक मीटिंग में कहा कि सजय गांधी राजनीति के क्षितिज पर उभरता हुआ नया सितारा है, अब कांग्रेस के नेतृत्व को और देग को पचास साल के लिए कोई खतरा नहीं है।

सजय का जो शाही स्वागत किया गया उस पर कम-से कम दस लाख रुपये खर्च किये गए। इससे से कम-से-कम गांधी रकम बिहार सरकार ने सुरक्षा के हथियार और मोटरों की दोड़ धूप और भीड़ को काबू में रखने के इन्तजाम पर खर्च की थी। बाकी गांधी रकम बड़े बड़े सेठा और व्यापारियों ने दी थी।

नसबंदी के लिए खास तौर पर लगाय गए कम्पा में पंजाब की सरकार जितनी बड़ी सड़कें में मर्दों और औरतों को जमा करती थी उससे साफ जाहिर था कि उसमें इस काम के लिए कितना जोश था। ऑपरेशन में गड़बड़ी हो जाने की वजह से कुछ लोगो के मर जाने की भी खबरें मिलीं।

नसबंदी के सिलसिले में की गयी किसी ज्यादती की खबर कोई मखबार नहीं छाप सकता था। और न श्रीमती गांधी का 'घराना' उन पर यकीन ही करने को तैयार था, हालाँकि वहाँ सबको मालूम था कि नसबंदी में जोर-जबदस्ती की जा रही है। खुफिया विभाग को कुछ ज्यादतियों का पता लगा और उसने इनकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री के पास भी भेजी और उनके सनेटरी के पास भी। लेकिन उनके बारे में शायद ही कभी कोई बरखाई की जाती थी। यह कहकर सीपा पोती कर दी जाती थी कि कुछ न कुछ जबदस्ती तो करनी ही पड़ता है। केन्द्रीय सरकार के राज्य मंत्री साहनबाज खाँ ने श्रीमती गांधी को मुजफ्फरनगर की घटना के बारे में एक रिपोर्ट भेजी और उसमें बताया कि किस तरह पुलिस न जान बूझकर ताकत इस्तेमाल की थी और लोगो पर जुल्म डाले थे। श्रीमती गांधी ने बस इतना कहा कि बातों को बहुत बढ़ा-बढ़ाकर पेश किया गया है। इस रिपोर्ट की एक बापी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को भी गयी। उन्हें पढ़कर बहुत धक्का लगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से इसकी शिकायत की और अपनी उस डायरी में भी इसे दर्ज किया जो वह रोज पाबंदी के साथ लिखत थे।

हाथ पाँव की जोर जबदस्ती अबेला तरीका नहीं था जो इस्तेमाल किया गया। सरकार ने सर्कुलर जारी करके यह आदेश दे दिया कि जो कमचारी या तो खुद अपनी नसबन्दी न कराये या दूसरा की नसबन्दी न कराये उसकी तरफ़ से रोक दी जाये और तनखा न बढ़ाया जाये। अगले साल के लिए किसी का मोटर चढ़ाने का नया माइ-सैंस भी तभी बनाया जाना था जब उसने कम से कम कुछ लोगो की नसबन्दी करापी हो।

दिल्ली प्रशासन ने यह आदेश जारी कर दिया कि उसने जो कमचारी नसबन्दी के लायक हैं उन्हें उनकी तनखा नसबन्दी का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही दी जायेगी। कांग्रेस के प्राइमरी स्कूलों के 10,000 अध्यापकों की ख़ास हज़म दे दिया गया कि वे कम से कम पाँच पाँच घण्टियाँ का नसबन्दी के लिए राजी करें। स्कूलों की हज़म दिस्टेंस को यह अधिकार दे दिया गया कि जब तक किसी विद्यार्थी का बाप या उसकी माँ नसबन्दी न कराये तब तक उसे पास न किया जाय।

व्यापारियों के कुछ प्रतिनिधियों का दिल्ली के सेलिब्रिटी-मैन ने राजनिवास

पर घुलाकर उनसे कहा कि वे यह तय करें कि हर महीने वे अपने बितने कमचा और दूसरे लोगों को नसबन्दी के लिए राजी करेंगे।

कई कम्पनियाँ, जहाँ मजदूर रोजनदारी पर या ठेके पर काम करते थे, इस बन्द हो गयी कि मजदूरों ने यह फैसला कर लिया था कि नसब दी का खतरा लेने से अच्छा है कि वे अपने गाँव लौट जायें।

सरकार ने आबादी की रोकथाम के बारे में एक राष्ट्रीय पॉलिसी क ऐलान किया था। सजय दो बच्चे प्रति परिवार की सीमा बाँधना चाहता था लेकिन श्रीमती गांधी और उनका बाकी परिवार तीन के पक्ष में था और यही बात मान गयी। राष्ट्रीय पालिसी में लक्ष्य यह रखा गया था कि आबादी के हर एक 1 आदमियों के बीच इस वक्त हर साल 35 बच्चे पैदा होते हैं, इसे घटाकर 1984 25 पर पहुँचा दिया जाये। उम्मीद की जाती थी कि तब तक आबादी बढ़ने की र भी 2 4 प्रतिशत से घटकर 1 4 प्रतिशत रह जायेगी। विवाह करने की कम से कम बढ़ाकर लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल कर दी गयी। बन्दी करान पर रदों और औरतों को नकद पसा भी दिया जाता था। लेकिन फैसला भलग भलग राज्यों के हाथ में छोड़ दिया गया कि अगर वे चाहता नस को लाजिमी बना देन का कानून बना सकते हैं। (उस समय हमारी आबादी 61 व 50 लाख थी।)

नसबन्दी के अलावा सजय को एक और धुन थी, दिल्ली को खूबसूरत की। वह डी० डी० ए० के कर्ता घंटा जममोहन को रोज बताया करता था कि करना है और गंदी बस्तियों की सफाई के सिलसिले में जितना काम होता था उसे लेखा जोखा करता था।

इतन बड़े पैमाने पर, जितना कि पहले कभी नहीं हुआ था, गैर-कानूनी और भुग्गी भोपड़ियों के गिरा दिये जाने की वजह से कई बस्तियाँ से पुराने बं परिवार छोड़ छोड़कर जाने लगे थे। इसी तरह का एक इलाका वह था जिसे मु आबादी कहा जाता था। नुकमान गेट के इलाके में, जहाँ बहुत से गैर मुसलमान रहते थे, 13 अप्रैल को जब बस्ती के बाहर बुलडोजर जमा होने लगे तो लोग परेशान होकर उठें देखते रहे। वह बसाही का दिन था और उस इलाके में रह पजाबियों ने अपना यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया था।

वहाँ के रहनेवाले 16 अप्रैल को ए० के० एल० भगत से मिले, जिन्होंने यकीन दिलाया कि उनके घर ढाये नहीं जायेंगे। उन्होंने कहा, यह हो ही कैसे है जबकि ये इमारतें कई पीढ़ियों से वहाँ खड़ी हुई हैं? लेकिन बुलडोजर फिर नहीं हटे।

अचानक 19 अप्रैल को बुलडोजर नुकमान गेट की तरफ बढ़ने लगे। लोग भुण्ड बनाकर बुलडोजरों को रोकने के लिए बस्ती के बाहर दरगाह इला सामने बैठ गये, जिस पर अभी हाल ही में सफेदी की गयी थी। कई और मुहल्ले आकर शामिल हो गये और बढ़ते बढ़ते वहाँ कई सौ आदमी जमा हो गये।

दोपहर के करीब दूको में भर भरकर बटूको से लस सी० गार० पं सिपाही और दिल्ली के पुलिसवाले वहाँ आने लगे। कुछ ही मिनटों में धक्का शुरू हो गयी और शोर गुल मचने लगा। पुलिसवाले रास्ता साफ करने की काशि रहे थे और लोग उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे। इतने में पुलिस की तरफ से एक की बोछार हुई। उस वक्त तब लोग गौर तो मचा रहे थे पर बाकी सब की थी। भीड़ में भी पुलिस पर जवाबी पथराव किया।

लगभग डेढ़ बजे दरियागज के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने लाठी चाज वा हुम दिया, इसके बार म तो दो रायों हो ही नहीं सकती कि लाठी चाज बड़ी बेरहमी से किया गया। भीड़ म खलवली मच गयी। लोग इधर-उधर भागन लगे। कुछ जमीन पर गिर पड़े और चोटों तो बहुता की प्रायी। सबडा लोग गिरपतार कर लिए गये, जिनम कई घायल लोग भी शामिल थे। इसके बाद तो वहाँ के लोगो और पुलिस के बीच जमकर लड़ाई शुरू हो गयी। औरतें भी मदों का हाथ बटाने के लिए बसत और बिमटे लेकर अपने घरों से निकल प्रायी, उन्हनि अपन मदों को पुलिस के चंगुल से छुड़ा लिया। लोगो के इस तरह जमकर मुकाबला करन पर पुलिस को ताव प्रा गया। पहले तो उमने आसू गैस के गोले छोड़े और फिर तीसरे पहर लगभग तीन घंटे तक रह-रहकर गोलियों चलाते रहे। जब मामला कानून से बाहर होने लगा तो बर्षू लगा दिया गया। इसी वकन बुलडोजरों ने चढाई की। लगभग 1,000 मकान ढा दिये। 150 लोग जान से मारे गये और 700 गिरपतार कर लिए गये। लेकिन मामला यही पर खत्म नहीं हो गया। बर्षू पतालीस दिन तक लगा रहा। इस दौरान एक एक घर मे घुस-घुसकर लूटमार की गयी। नयी नवली दुल्हनो के जेवर छीन लिए गये। बूढ़ो और बीमारो को भी जानवरो की तरह मारा गया और उनके पास जो कुछ भी था उनसे छीन लिया गया। लोगो को इस घुबड़े म पकड़ लिया गया कि उहोन पुलिस से टक्कर ली थी।

सेंसर ने इसके बारे में एक बखर भी भ्रखबारो म नहीं छपने दिया। लेकिन सारी दिल्ली मे और धीरे धीरे पूरे देश मे तुर्कमान गेट म ढाये गये जुल्मो की खर्च होने लगी। सरकार को मजबूर होकर मानना पडा कि कुछ खोग मारे गये हैं लेकिन उसने भ्रखबारो के लिए जो बयान जारी किया उसमें सच बात कभी नहीं बतायी गयी। जिस वकत तुर्कमान गेट के इलाके मे रहनेवालो को वहाँ से हटाया जा रहा था उस वकन तक डी० डी० ए० वालो को यह नहीं मालूम था कि उस जगह का के क्या करेंगे। तीन महीने बाद वहा दफतरो और ठूकाना के लिए पचास मजिल की एक इमारत बनाने की योजना तैयार की गयी।

जिन लोगो को अबदस्ती उनके घरों से निकाल दिया गया था उहें जमुना के पार एक बजर बियाबान मे ले जाकर छोड़ दिया गया, जहाँ दूसरी सुविधाओ की बात तो दूर रही पीने के पानी तक का इन्तजाम नहीं था। जब कई दिन बाद शेख मन्डुल्ला ने उस कालोनी का मुभाइना किया तो उन्होने तुर्कमान गेट की घटना को कबला बताया। उहे सचमुच बहुत तकलीफ हुई और उन्हनि यह बात अधिकारियो से कही भी। वहाँ के रहनेवाले अपनी करियाद लेकर सजय के पास गये—श्रीमती गांधी को फुरसत नहीं थी—कि उहें बेहतर सुविधाएँ दी जायें तो उसने कहा, 'तुम लोगो ने शेख साहब से झूठी शिकायतें की हैं दुग्द इसका मजा चखवाया जायगा।' उसने कहा कि लोगो को पुलिस पर हमला करने की सजा दी जायेगी।'

गन्दी बस्तियो की सफाई सजय के पाँच-सूत्री कायत्रम म (पहले चार ही थे) शामिल नहीं थी। इस कायत्रम का भी उतना ही प्रचार किया गया था जितना कि श्रीमती गांधी के बीस-सूत्री कायत्रम का। सजय के पाँच सूत्र थे परिवार नियोजन पेड़ लगाना, दहेज पर पाबन्दी, हर आदमी एक आदमी को पढ़ाये और जात पात को दूर करना।

इस कायत्रम मे ऐसी कोई गवत बात नहीं थी लेकिन उमे पूरा करने के लिए जो तरीके अपनाये गये उनसे लोगो म गुस्सा पैदा हुआ। एक और भी बजह थी। वह जो कुछ भी करता था उस पर यह छाप होती थी कि उसके अधिकार मविधान से परे हैं।

उसके हाथ में जितनी ताकत आ गयी थी उस पर लोगो को ऐनराज या और इसलिए वह जो भी कदम उठाता था उसे लोग सुबहे की नजर से देखते थे। हालांकि बहुत-से लोग सीलह आन उसके पक्ष में नहीं थे फिर भी वे उसकी 'काम करने की सूझ बुझ' और 'समझनारी' की तारीफ करते थे। कांग्रेस के अंदर अपना उल्लू सीधा करनेवाले सोचते थे कि चूँकि सारी ताकत उसी के हाथ में है इसलिए उस खुश रखना चाहिए।

सजय रोब तो बहुत जमाता था—और सिर्फ माहति, पाँच सूत्री कार्यक्रम या मुक्क कांग्रेस के मामले में ही नहीं। जो कोई भी उसमें कोई बुराई निकालता था उसे वह धौंस देकर दबा देने या सजा देने की कोशिश करता था। माहति की इमारत का एक हिस्सा बनवात वक्ता वह किसी ठेकेदार में नाराज हो गया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस जमाने में दिल्ली के इस्पेक्टर जनरल भ्रॉफ पुलिस राजगोपालन की बदली यार्डर सिक्वोरिटी फोर्स में सिर्फ इसलिए त्तरवा दी गयी कि उन्होंने सजय की मर्जी का काम करने से इकार कर दिया था।

एयर माशल पी० सी० साल के साथ जो कुछ हुमा उसके पीछे भी सजय का हाथ साफ दिखायी देता था। एयर माशल साल वायु सेना के प्रधान रह चुके थे और इंडियन एयरलाइंस के चेयरमन बनाकर लाये गये थे। इस मामले में तो सजय के भार्द राजीव का भी हाथ था।

एयर माशल साल 31 जुलाई 1976 को रिटायर हानवाले थे। वह इसके सारे कागजात दाखिल करके छुट्टी लेकर चले जाना चाहते थे। लेकिन वह यह भी चाहते थे कि उनकी जगह लेने के लिए किसी को तैयार भी कर दें। उनके बाद डिप्टी मनेजिंग डायरेक्टर सत्यमूर्ति की बारी थी। एयर माशल साल ने अपने मंत्री राजबहादुर और प्रधानमंत्री से इसके बारे में सितम्बर 1975 में बातचीत की और यह सिफारिश की कि उनके रिटायर हो जाने के बाद सत्यमूर्ति को मनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाये। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे लोग चाहे तो वह खुद दिन में कुछ दक्कत काम के लिए दे सकत हैं और चेयरमन बने रह सकते हैं। श्रीमती गांधी और राजबहादुर दोनों ही इस बात के लिए राजी हो गये कि सत्यमूर्ति को उनके बाद उनकी जगह दे दी जाये। लेकिन कहा जाता है कि राजीव सत्यमूर्ति के खिलाफ था।

अक्टूबर में राजबहादुर ने एयर माशल साल से कहा कि प्रधानमंत्री चाहती हैं कि तीन पाइलटो को तरक्की दे दी जाये। उन्होंने जवाब दिया कि तरक्की के लिए जो शर्तें जरूरी हैं, उन पर ये पाइलट खरे नहीं उतरत हैं। एयर माशल साल के इस तरह इकार कर देने से प्रधानमंत्री क्षामद चिढ़ गयी। इसी बीच राजबहादुर ने सत्यमूर्ति के बारे में अपनी राय बदल दी थी और एयर माशल साल का बता दिया था कि सत्यमूर्ति को मनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनाया जायेगा। एयर माशल साल प्रधानमंत्री से मिले—उनके साथ यह उनकी आखिरी मुलाकात थी—और उनसे कहा कि सत्यमूर्ति मनेजिंग डायरेक्टर को हैसियत से बहुत अच्छा काम करेंगे। श्रीमती गांधी ने कहा कि उनकी राय में सत्यमूर्ति 'कुछ खास ईमानदार' नहीं हैं। साथ ही उन्होंने इतना और जोड़ दिया कि 'मुझे सब पता है कि इंडियन एयरलाइंस में क्या होता रहता है।'।

निसम्बर में एयर माशल साल ने कई लागा की बदली कर दी। लेकिन राज बहादुर ने कहा कि उनकी मजदूरी लिये बिना न किसी को नौकरी पर रखा जाय और

1 सितम्बर 1976 में कुछ लोग इंडियन एयरलाइंस के एक बोइंग 737 हवाई जहाज का अपहरण करके ताहीर ले गये थे। जिन कश्मीरियों की यह हरकत थी उन्होंने समझा था कि उस राजाव चला रहा था। राजीव उसी स्ट पर जाता था लेकिन सिर्फ एबरा हवाई जहाज चलाता था।

न किसी की बदली की जाये। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह हुकम ध्वन से मिला है। राजबहादुर ने जनवरी 1976 में यह वायदा किया था कि इण्डियन एयरलाइंस के जो अफसर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं उन्हें बदला नहीं जायगा। लेकिन फरवरी में जब नया बोर्ड बनाया गया तो सत्यमूर्ति¹ का नाम काटकर उनकी जगह उनसे बहुत छोटे एक अफसर को रख दिया गया। एयर माशल लाल ने राजबहादुर के पास जाकर इसका विरोध किया। इस पर राजबहादुर ने लाल से कहा कि आप जिस तरह इण्डियन एयरलाइंस का काम-काज चला रहे हैं उससे प्रधानमंत्री खुश नहीं हैं।

अप्रैल में लाल ने इस्तीफा दे दिया और छुट्टी माँगी। राजबहादुर ने अपने एक ज्वाइट सेनेटरी को भेजकर उनसे कहलवाया कि वह छुट्टी पर न जायें। लाल ने छुट्टी की अर्जी वापस ले ली। लेकिन तब तक राजबहादुर को ध्वन से यह आदेश मिल चुका था कि लाल को छुट्टी पर जाने दिया जाये। लाल ने प्रधानमंत्री से मिलने की नाकामयाब कोशिश की।

13 अप्रैल को लाल ने देखा कि उनके दफ्तर के बाहर सादी पोशाक में कुछ पुलिसवाले तनात हैं और लांबी में पुलिस का एक डी० एस० पी० बैठा है। लाल 19 अप्रैल से छुट्टी पर जाना चाहते थे लेकिन उनके मन्त्रालय से पहले ही एक सर्कुलर भेजा जा चुका था कि एयर माशल लाल 12 अप्रैल से छुट्टी पर हैं। बाद में मन्त्रालय ने एक और चिट्ठी जारी कर दी जिसमें कहा गया था कि एयर माशल लाल की नौकरी खत्म कर दी गयी है।

लाल ने जिन जिन लोगों की बदली की थी उन सबको फिर उनकी पुरानी जगहों पर बहाल कर दिया गया और वह तीन पाइलट जा लाल की राय में 'इस लायक' नहीं थे, उन्हें तरक्की दे दी गयी।

इनकम टैक्स वालों ने लाल और उनके भाई को बहुत तंग किया। बाद में लाल ने एक पिछली घटना का हवाला देते हुए बताया कि एक बार श्रीमती गांधी ने उनसे कहा था कि गुप्ताना जैसे देश में अगर कोई अफसर प्रधानमंत्री का नापसंद हो तो उसे उनके कमरे में घुसने तक नहीं दिया जाता। अब लाल की समस्या में आ रहा था कि उनका क्या मतलब था।

सजय बेकार के बसेड़े खड़े करन लगा था। 11 जनवरी 1976 को वह नौ सेना के किसी समारोह में बसीलाल के साथ बम्बई गया। एम० ई० एस० के शानदार बंगले 'नुक' में मल सेना और वायु सेना के प्रधानों को ठहराने का बंदोबस्त पहले से किया जा चुका था। नौ सेना के अफसरों ने सजय और बसीलाल के ठहरने का इंतजाम दूसरी जगह किया था—होटल में एक पूरा 'सुइट' और एक दो आदमियों के रहने का कमरा। बसीलाल ने 'सुइट' तो सजय को दे दिया और खुद कमरे में ठहर गए। बसीलाल ने नौ-सेना के प्रधान एस० एन० कोहली से कहा कि यह इंतजाम उन्हें पसंद नहीं आया।

फिर जब आलीशान हिनर हुआ तो इस बात पर बड़ी से दे हुई कि कौन कहाँ बैठे। बड़ी मेज पर राष्ट्रपति और उनकी पत्नी, गवर्नर और उनकी पत्नी बसीलाल और उनकी पत्नी और दो बड़े अफसरों के बैठने का इंतजाम किया गया था। फौज के प्रधानों तक के बैठने का प्रबंध दूसरी मेजों पर किया गया था जो उस बड़ी मेज की

1 एयर इण्डिया के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पी० व० जी० शम्भू स्वामी का नाम भी हटा दिया गया थायद इसलिए कि वह कहन को रहे कि दोनों डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टरों के नाम हटा दिये गए हैं।

ही तीन शाखाओं की तरह लगायी गयी थी।

सजय की जगह इस क्रम में कुछ नीचे नौ सेना के अफसरों के साथ थी। बसीलाल चाहते थे कि सजय को बड़ी मेज़ पर जगह दी जाये। कोहली ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है। बसीलाल ने नौ सेना के दूसरे अफसरों के सामने भीत फील बनाना शुरू कर दिया। यह उनकी हमेशा की आदत थी कि जब कोई उनकी बात नहीं मानता था तो वह गाली गलौज पर उतर आता था। कोहली को रिटायर होने में सिर्फ तीन महीने बाकी थे। अचानक उन्होंने कहा कि मैं फौरन इस्तीफा देना चाहता हूँ। बसीलाल को यह आश्चर्य नहीं था कि नौबत यहाँ तक पहुँच जायेगी, उन्होंने फौरन अपना लहजा बदल दिया। चूँकि बसीलाल की पत्नी छिनर में गहरी घायल इसलिए उनकी जगह सजय को दे दी गयी। इस घटना से चारों तरफ एक खल्लो पड़ा हो गयी थी। जल्दी ही इसकी गूँज सारे देश में सुनायी देने लगी। लोग नुकताखोनी करने लगे, दबी जबान से ही सही।

ऐसा नहीं है कि यह बसीलाल के अक्लबलन और घाँघली की पहली मिसाल थी। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने दिल्ली में फौज की ऑपरेशंस ब्रांच के एक कनल सुखजीतसिंह को सस्पेंड कर दिया था। मामला उत्तर प्रदेश में तराई के इलाकों की किसी ज़मीन की कीमत का था। वह ज़मीन बनस साहब ने उसके मालिकों को 'वापस दिलवा दी थी'। बसीलाल के स्पेशल असिस्टेंट आर० सी० मेठानी ने सुखजीतसिंह को अपने दफ्तर में बुलाकर बहुत सताड़ा। जिसको उस ज़मीन से बेदखल किया गया था वह भी उस खन बही मौजूद था। बसीलाल तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गये, उन्होंने उस अफसर को 'सस्पेंड' ही कर दिया। सुखजीत को मिलिटरी ऑपरेशंस ब्रांच से हटाकर दिल्ली छावनी में किसी मामूली जगह भेज दिया गया। न कोई जाँच पड़ताल हुई और न ही दूसरे अफसरों ने ख़बान खोली। बसीलाल के दबाव में आकर ऊपर से नीचे सब सवने धुटने टेक दिये। बाद में इस बिगड़ी हुई हालत को सँभालने के लिए कुछ कदम उठाये गये। सुखजीतसिंह को ब्रिगेडियर बनने की बारी थी, उन्हें यह तरक्की देकर पूर्वी भारत में तनात कर दिया गया।

ताकत का नशा भूकेले बसीलाल को रहा हो, ऐसी बात नहीं थी। शुक्लाजी के भी यही सेवर थे। उनका अपना मैदान फिल्म जगत था। वह डायरेक्टरों प्रोड्यूसरों और फिल्मी सितारों को अपने इशारों पर नवान के लिए तरह-तरह के हथकड़े इस्तेमाल करते थे। किशोर कुमार उनके गुस्से का निशाना इसलिए बना कि उसने दिल्ली में युवक कांग्रेस के एक तमाशे में गाना गाने में आनाकानी की थी। किशोर के सारे गाने रेडियो और टेलीविजन पर बन्द करवा दिये गये। कितनी ही फिल्में सेंसर की मज़ूरी न मिलने की वजह से अटक गयी क्योंकि शुक्लाजी चाहते थे कि प्रोड्यूसर और फिल्म स्टार उनकी 'जी हुजरी' करें। सूचना मंत्रालय में काम करनेवाले एक और पुलिस अफसर इस मदान में उनके खास कारिंदे थे।

ताकत का बेजा इस्तेमाल करने की बीमारी 'घराने' के बड़े और लागो को भी लग चुकी थी। श्रीमती गांधी की बड़ी बहू राजीव की बीबी सोनिया, इटलियन थी। उसने पास अभी तक इटलियन पासपोर्ट ही था लेकिन उसने परदेसिया पर लागू होनवाला कानून के अनुसार अभी तक अपना नाम रजिस्टर नहीं कराया था। इस कानून के अनुसार हर विदेशी आदमी को यहाँ पहुँचने के नब्बे दिन के अंदर अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता था। (मियाद पूरी हो जाने पर हर बार नाम फिर से रजिस्टर करवाना जरूरी था।) किसी ख़माने में वह सरकारी नाइफ इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स की एजेंट थी नकिन अब भारती की सलाह देनेवाली कम्पनी में काम करती थी।

श्रीमती गांधी की दूसरी बहू सजय की बीवी मेनका ने एक पत्रिका निकाली थी सूप, जिसके लिए हर जगह से हर तरीके से इश्तहार जुटाये जाते थे।

फिर युनुस साहब थे जिनका तर्कियाबलाम था 'पकड़ लो'। विदेशी पत्रकारों के सामने उन्होंने कहा था कि पश्चिमी जर्मन 'हिटलर के ढग से सोचते हैं' अंग्रेज 'पागल' हैं और अमरीकी 'बेहूदा' हैं। वह प्रेसीडेंट फोर्ड को कहते थे "भरे, वह पटुवाल का खिलाडी"।

लेकिन अब युनुस अखबारों पर सेंसरशिप कुछ ढीली कर देने के पक्ष में थे, जैसा कि विदेशी पत्रकारों के मामले में पहल ही किया जा चुका था।

बहरहाल, अखबारों पर सेंसर के शिकरे को अब पार्टी के और निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। सेंसरवाने खबरों को और कांग्रेस या युवक कांग्रेस के ब्यापारों तक को छापने से सिफ इसलिए मना कर देते थे कि शुक्लाजी की मर्जी नहीं होती थी, जो हरदम घबन के साथ और घबन की माफत सजय के साथ सम्पक बनाय रखते थे। शुक्लाजी जिस राज्य में भी जाते थे, वहाँ वह सेंसरवाला को और अखबार वालों को तर्कीद कर देते थे कि कांग्रेस के अन्दरनी भगडों के बारे में कोई खबरें न दें। मुगमत्री सेंसर का सहारा लेकर उन खबरों को दबवा देते थे जो उनके या उनके गुट के खिलाफ होती थी। पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष मोहिन्दरसिंह गिल को अपने बयान छपवाने में कठिनाई होती थी क्योंकि जलमिह ने सेंसरवाला को इसके बरखिलाफ हिदायत दे रखी थी। पश्चिम बंगाल के सूचनामंत्री सुब्रत मुखर्जी ने सेंसर के दपतर से कह रखा था कि उनके सापियों के खिलाफ किसी खबर का छपने की मजूरी न दी जाये।

अंग्रेजी की दो पत्रिकाओं को भारत में इमर्जेंसी के कायदे वानूनो की आलोचना करने पर अपना प्रकाशन बन्द कर देने पर मजबूर कर दिया गया था। इनमें से एक था साप्ताहिक ओपीनियन जिसे महाराष्ट्र सरकार ने इसलिए बन्द करवा दिया था कि उसने आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन से सम्बन्धित वानून के सेंसर के नियमों को तोड़ा था।

दूसरी पत्रिका थी मासिक सेमिनार। जब 15 जुलाई को सरकार ने उसे हर चीज पहले सेंसर कराके छापने का आदेश दिया तो उसे मानने से इकार करके उन्होंने खुद ही अखबार छापना बन्द कर दिया। इस पत्रिका के दिलेर सपादक रमेश और उनकी बीवी राज ने सेमिनार में उस आविरी अक म लिखा था कि सेमिनार "अपनी ईमानदारी और आजादी के साथ विचार व्यक्त करने के अधिकार को इस तरह हा छोड़ने की तयार नहीं है।" सेमिनार और ओपीनियन बन्द होने की खबर किसी अखबार में नहीं छपी।

राजनीतिक भक्त्सद स भीसा का इस्तेमाल अब एक आम बात थी जिस सभी जानते थे। जिन लोगों को आत्मा ने गवाही न देने की वजह से किसी काम के करने में एतराज होता था, वे भी एक घमकी से सही रास्ते पर आ जाते थे। गिमाल के लिए, नेरल म विपक्ष के मुस्लिम लीग के कई नेताओं को महज इसलिए नजरबन्द कर दिया गया कि वे शासक गुट से अलग हो गये थे और सरकार के खिलाफ हो गये थे। नजर बंदी के दौरान उन्हें सासब दिया गया कि अगर वे शासक गुट के साथ आ जायें तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।

नेरल कांग्रेस के नेताओं को भी गिरफ्तारी और बंद की घमकी देकर ही भावगवादी मोर्चा छोड़ने और गामक मोर्चे के साथ आ जान के लिए मजबूर किया गया था। सच तो यह है कि नेरल कांग्रेस इमर्जेंसी की आलोचना करने में बहुत मुतार

थी। लेकिन प्रोम मेहता के इशारे पर, खुफिया विभाग के लोगो ने केरल कांग्रेस के वे० एम० जाज और उनके साथियों को दिल्ली जान पर मजबूर किया, जहाँ उनसे दोटूक कह दिया गया कि या तो वे शासक मोर्चे में शामिल हो जायें या जेल जाने को तैयार रहें। उनसे वायदा किया गया कि अगर वे शासक मोर्चे में शामिल हो जायेंगे तो उनके कुछ लोगो को मंत्री बना दिया जायेगा।

हरियाणा में बसीलाल ने मीसा का सहारा लेकर एक फैक्टरी के मजदूर को इसलिए पकड़ा दिया कि उसने बसीलाल के एक आदमी को गबन के जुम में इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। इसकी शिकायत श्रीमती गांधी तक पहुँचायी गयी, पर उन्होंने कुछ किया नहीं। सबको अपने अपने मैदान में खुली छूट थी।

मीसा के बेजा इस्तेमाल के बावजूद जहाँ तहाँ लोग अब भी अपनी गर्जों से गिरपतार हो रहे थे। गुजरात के जनता मोर्चे ने 15 अगस्त 1976 को ग्रहमदावाद से दण्डी तक की पदयात्रा सगठित की। 1930 में जब महात्मा गांधी ने दक्षिणी गुजरात के बलसार जिले में ऐसी ही एक पदयात्रा की थी तो वह भी दण्डी तक गये थे। हालाँकि सरदार पटेल की बहन कुमारी मणिवेन पटेल इस 'यात्रा' की अनुवाह कर रही थी, लेकिन उन्हें गिरपतार नहीं किया गया, उनके बाकी सब साथी गिरपतार कर लिये गये। दिल्ली से खास ताकीद कर दी गयी थी कि उन्हें गिरपतार न किया जायें। बाईस दिन बाद वह दण्डी पहुँचे।

अगस्त के महीने में ही बाबूभाई पटेल भी, जो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे, मीसा में पकड़ लिये गये।

इस तरह की गिरपतारियाँ स विदेशों में लोगो का उम्मीद बँधी कि अब भी कुछ हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो जनतांत्रिक आदर्शों के लिए लड़ सकते हैं। कुछ विदेशी अखबारों ने इन घटनाओं का सहारा लेकर श्रीमती गांधी पर हमला किया। इस आलोचना से उनको बहुत चोट पहुँची। इमर्जेंसी के दौरान कुछ लोग विदेशों में लोगो को यह बताने के लिए भारत छोड़कर चले गये कि इस देश में किस तरह धीरे धीरे आक्रायदा आजादी की जड़ें खोलनी की जा रही हैं।

अमरीका ने 24 अगस्त को भारत की बार कौंसिल के अध्यक्ष राम जेठमलानी को राजनीतिक कारण दी। केरल में सरकार के खिलाफ एक भाषण देने की वजह से जेठमलानी को डर था कि उन्हें गिरपतार कर लिया जायेगा। 28 अप्रैल को वह हवाई जहाज में भारत में बनाइया में माटियल के लिए रवाना हो गये और मई में अमरीका पहुँचे।

जेठमलानी ने वन स्टेट यूनिवर्सिटी में, जहाँ वह तुलनात्मक विधान कानून के अतिथि प्रोफेसर की हैसियत में गये थे बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन को लिखा 'मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारी आत्मा इतनी भर चुबी है कि तुम तानाशाही और घोर भ्रष्टाचार में भी खूबियाँ ढूँढ लगे हो। मुझे यह न बताओ कि तुम्हारे ऊपर उन कामयाबियों का बहुत रीब पड़ा है जिनका कि श्रीमती गांधी दावा करती हैं। मुसोलिनी और हिटलर दोनों ही के पास अपने देशवासियों को दिखाने के लिए उससे कहीं ज्यादा कामयाबियाँ थी जितनी कि श्रीमती गांधी दिखा सकती है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं यहाँ से भारत की आजादी के लिए उससे कहीं ज्यादा काम कर रहा हूँ जितना मैं श्रीमती गांधी की जेलों में बैठकर कर पाता। किसी दिन तुम्हें पूरी सच्चाई का पता चलेगा। मुझे इसमें जरा भी शक नहीं है कि उनका भ्रष्टाचारी शासन हमेशा नहीं रहेगा और जब उसका अन्त होगा तो तुममें से हर एक को, जिसने या तो चुप कर बंदी के भागे सर झुका दिया है या भागे बढ़कर उसका साथ दिया है,

ठहराया जायेगा। हिसाब चुकाने का दिन अब दूर नहीं है।”

राज्यसभा में जनसभा के सदस्य सुब्रह्मण्यम स्वामी पर भी सरकार के खिलाफ काम करने और कानून के चंगुल से और देश से भाग निकलने का आरोप था। उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया था। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। दिल्ली में उनके घरवालों को सताया जा रहा था। राज्यसभा ने 2 सितम्बर को उनके मामले की छानबीन करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया। अगर वह लगातार छ महीने तक सदन से गैरहाजिर रहते तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाती। उसे बरकरार रखने के लिए वह पुलिस की मिलीभगत से भ्रमस्त में सदन में भाये, लेकिन जितने रहस्यमय ढंग से वह भाये उतने ही रहस्यमय ढंग से फिर देश के बाहर भी निकल गये। बाद में उनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म कर दी गयी।

स्वामी के इस तरह गायब हो जाने से श्रीमती गांधी की सरकार की बड़ी वद माभी हुई। लेकिन 24 सितम्बर को भडरपाउड नेता आज फर्नांडीज और चौधौस दूसरे लोगों पर नई दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट की अदालत में सरकार के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाकर उनकी सरकार ने अपनी नाक ऊँची रखने की कोशिश की।

इन लोगों का अपराध यह बताया गया था कि इन्होंने बड़ौदा (गुजरात) से टनी डायनामाइट दूसरी जगहों को भेजा था और वे रेल व्यवस्था में बहुत बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ मचाकर सारे देश में उथल पुथल पैदा कर देना चाहते थे।

असल में बड़ौदा डायनामाइट कांड के लोगों के बारे में श्रीमती गांधी को खबर चिमनभाई ने दी थी जो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे। वह श्रीमती गांधी से समझौता कर लेना चाहते थे क्योंकि 1974 में श्रीमती गांधी ने ही उन्हें मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था।

श्रीमती गांधी को जो खबरें मिली थी उनमें कहा गया था कि गुजरात में पूरा सरकारी ढांचा बहुत ढीला ढाला था और उस पर अभी तक जनता मोर्चे की सरकार का 'नशा' छाया हुआ था। उन्होंने तेल तथा रसायन मनी पी० सी० सेठी को वहाँ से असली खबर साने के लिए भेजा।

अहमदाबाद के हवाई अड्डे पर उतरते ही सेठी ने इस बात का जवाब तलब किया कि उनको सलामी देने का इंतजाम क्यों नहीं किया गया था। पुलिस कमिश्नर ने जल्दी-जल्दी वहाँ पर तैनात कुछ पुलिसवालों को जमा करके जैसी तलबी सलामी का बंदोबस्त करा दिया। सेठी को यह बात पसंद नहीं आयी और उन्होंने पुलिस कमिश्नर को बर्खास्त कर देने का हुक्म दे दिया। उनके घले भ्राने के बाद गुजरात के अधिकारियों ने बर्खास्तगी के इस हुक्म की तामील करने से इकार कर दिया क्योंकि वे जानते थे कि पुलिस कमिश्नर बहुत ही अच्छा अफसर है। अन्दाजा लगाया जाता है दिल्ली के लिए रवाना होन के वक़्त तक सेठीजी ने अहमदाबाद और बड़ौदा में बीसिया पुलिस अफसरों और दूसरे सरकारी अफसरों को बर्खास्त कर दिया था।

अहमदाबाद की एक मजदूर बस्ती में वहाँ के म्युनिसिपल कार्पोरेशन की तरफ से जो एक मीटिंग की गयी उसमें सेठीजी अंग्रेजी में बोलने लगे। एक मुसलमान मजदूर ने बीच में खड़े होकर मुभाव दिया कि मन्नीजी हिन्दी में बोलें। इस पर सेठीजी भड़क उठे और बोले, “इस आदमी को गिरफ्तार क्या नहीं कर लेते? क्या मैं यहाँ अपनी बेइज्जती कराने आया हूँ?” इतना कहकर वह मंच पर से उतर आये और हितेन्द्र देसाई और वहाँ के मेयर वाढीताल कामदार हुक्का-बक्का देखते रह गये। मेयर ने सेठीजी को समझाने की कोशिश की कि किसी का इरादा उनकी बेइज्जती करने का नहीं था। लेकिन सेठीजी ने सबक पर लड़ोवाले लोगो की तरह अहमदाबाद

के प्रथम नागरिक को ढकेल दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से हितेन्द्र देसाई सेठीजी की मोटर में घुसने ही वाले थे कि उन्होंने चिल्लाकर कहा, "आपसे किसने कहा कि मेरे साथ चलिए? चले जाइये यहाँ से।"

दिल्ली लौटकर सेठीजी ने श्रीमती गांधी को बताया कि गुजरात में इमजेंसी का कही नामो निशान नहीं है। इसके बाद घूम मेहता अहमदाबाद भेजे गये और वहाँ गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया। राष्ट्रपति के सलाहकारों की राय में इन गिरफ्तारियों की कोई जरूरत नहीं थी।

गुजरात में गिरफ्तारियों की नयी लहर से ऐसा लगा कि इमजेंसी एक ऐसी सुरंग है जिसका कोई छोर नहीं है। बहुत से लोग साधारण महसूस करते थे और चुपचाप सब-कुछ बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन सर्वोदय आंदोलन के 65 वर्ष बूढ़े कायकर्ता और विनोबा भावे के साथी प्रभाकर शर्मा ने, श्रीमती गांधी के नादिरशाही शासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वर्धा शहर के बाहर सुरगांव में अपने आपका जताकर प्राण दे दिए।

आत्मदाह करने से पहले शर्मा ने श्रीमती गांधी को एक पत्र लिखकर ऐसा करने का कारण बताया। इस पत्र में उन्होंने लिखा था "भगवान् और इंसान को भूलकर और अपने आपको हर तरह की अत्याचारी ताकत से लँस करके सरकार ने अलबारा से उनकी आजादी छीन ली और भारतीय जीवन की हर उस खूबी पर हमला किया जो भली महान और उदात्त हो सकती है। इस साल उसने बड़ी बशर्मा से राष्ट्र की आत्मिक और आर्थिक सम्पत्ता पर हमला किया है।

'आपका मीसा का कानून सरकारी अप्सरा को पिशाच और लोगों को कायर बना देता है। जो निडर होकर अपना काम करता है उस हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाता है।' याय कही नहीं मिलेगा। जब आपके गुर्गे हैं। ऐसी हालत में जेल जाना दमन को स्वीकार कर लेना होगा। मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप मुझे सूझरो की तरह डरा धमकाकर रखें।" गांधीजी के अलबारा पत्र इडिया का हवाला देते हुए पत्र में लिखा गया था 'अगर हम आजाद भव या औरत की तरह न रह सकें तो हमें मरकर सन्तोष पाना चाहिए।' शर्मा ने यह भी लिखा "मैं जानता हूँ कि इस तरह का पत्र लिखना भी अपराध है। इसलिए मैं आपके इस पापी शासन में जीना नहीं चाहता।"

विनोबा ने शर्मा से कहलवाया था कि वह आकर उनसे मिलें, लेकिन वह हो न सका। विनोबा को श्रीमती गांधी से हमदर्दी जरूर थी लेकिन वह खुद बहुत निराश थे। पुलिस ने और खुफिया विभागवालों ने 9 जून को उनके आश्रम पर छापा मारा था और उनकी हिन्दी पत्रिका मन्त्री के उस अंक की 4200 कॉपियाँ जप्त कर ली थी जिसमें यह एलान छपा था कि अगर गो बघ पर पाबंदी न लगायी गयी तो वह 11 सितम्बर से अनशन शुरू कर देंगे। (बाद में सरकार ने यह पाबंदी लगा भी दी थी।)

ज्यादतियों के किस्स सुन-सुनकर और यह महसूस करते कि इस हंगामे का कोई अंत नहीं है व लोग भी, जो कभी इमजेंसी में कुछ अच्छाइयाँ देखते थे, अब उसके खिलाफ हो गये। उन्हें इस निरंकुश शासन से या एक चाडाल चौकड़ी की मनमानी सरकार से छुटकारे का कोई रास्ता नहीं दितायी देता था।

दो बातों की वजह से सरकार और जनता के बीच की दूरी और बढ़ गयी—सविधान में संशोधन और चुनावों का एक बार फिर टल जाना। कांग्रेस ने 27 फरवरी 1976 को स्वर्णसिंह की अध्यक्षता में जो एक बहुत शक्तिशाली कमेटी बनायी थी उसने अपनी रिपोर्ट तयार करके दे दी जिसे सरकार ने लगभग ज्याँ-का-त्यो स्वीकार कर

लिया। स्वर्णसिंह ने मुझे बताया, "अगर मैं न हाता तो इससे भी बदतर हालत होती।" उन्होंने कहा "हम लोग ने राष्ट्रपति प्रणाली को हमेशा के लिए दफन कर दिया।"

सविधान में संशोधनों का जो सुभाव रहा गया था उससे हर तरफ गुस्से की सहर दौड़ गयी। श्रीमती गांधी ने बचन दिया कि संसदीय प्रणाली नष्ट नहीं की जायेगी और यह कि सविधान में बस कुछ 'छाटे-मोटे हेर फेर' किये जायेंगे। लेकिन इससे लोग की आशवाएं दूर नहीं हुई और यह माँग की गयी, तब तो तब कुछ जीवियों की तरफ से, कि नया चुनाव हो जाने से पहले सविधान में कोई संशोधन न किये जायें। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने भी ऐसी ही माँग उठायी।

शिक्षा, कला और साहित्य के क्षेत्रों के लगभग 300 जाने-माने लोगों ने हुस्तामर से श्रीमती गांधी को एक धर्जी दी गयी जिसमें जोर देकर कहा गया कि "भोजपुरा संसद को सविधान में बुनियादी परिवर्तन करने का न कोई राजनीतिक अधिकार है न नैतिक अधिकार। गर कम्युनिस्ट विपक्ष और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सविधान में किये जानेवाले संशोधनों के बारे में कांग्रेस दल की कमेटी के साथ कोई बातचीत करने को तयार नहीं थे और उ हाने इसके बारे में आवश्यक बिल पास करने के लिए 25 अक्टूबर को बुलाये गये संसद के विशेष अधिवेशन का बॉयकाट कर दिया।

संसद ने 2 नवम्बर को 59 धाराओं वाले सविधान (42वाँ संशोधन) बिल को 4 के खिलाफ 366 वोटों से पास कर दिया। आधे राज्यों की विधानसभाओं ने जब इस बिल पर अपनी मुहर लगा दी और 18 दिसम्बर को जब राष्ट्रपति ने भी अपनी मजबूरी दे दी तो यह बिल अधिनियम बन गया। सविधान में बताये गये निर्देशक सिद्धांतों को इसमें मूल अधिकारों से ऊँचा स्थान दिया गया था नागरिका के दस बुनियादी कर्तव्य बताये गये थे, जिनमें अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा का कर्तव्य भी शामिल था, लोकसभा और राज्या की विधानसभाओं की अवधि पाँच साल से बढ़ाकर छ साल कर दी गयी थी, कानून और व्यवस्था में किसी 'संगीत' स्थिति से निबटने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र सेना को किसी भी राज्य में तनात कर देने का अधिकार दे दिया गया था और राष्ट्रपति को मन्त्रिमण्डल की सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था, राष्ट्र विरोधी हस्तगत पर पाबंदी लगा दी गयी थी और राष्ट्रपति को दो साल के लिए इन संशोधनों के रास्ते में आनेवाली किसी भी रुकावट को दूर करने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया था। यह भी तय कर दिया गया था कि सविधान के किसी संशोधन के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई कारवाई नहीं की जा सकती और इसके बाद से केन्द्र या राज्यों के बनाये हुए किसी भी कानून को तब तक असाविधानिक नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि कम-से-कम सात जजों में से दो तिहाई का बहुमत ऐसा फैसला न कर दे। सविधान की प्रस्तावना को बदल दिया गया 'सावभौम लोकतांत्रिक गणराज्य' को बदलकर 'सावभौम समाजवादी गणराज्य' कर दिया गया और 'राष्ट्र की एकता की जगह 'राष्ट्र की एकता और प्रखंडता कर दिया गया।

बरुआ ने कहा कि विचार प्रकट करने की आजादी के साथ उसके दुरुपयोग का दण्ड भी मिलना चाहिए और 'दुरुपयोग' क्या है क्या नहीं, इसका फैसला सरकार करेगी। सविधान में कुछ और संशोधनों का सुभाव ऐन वक्त पर टाल दिया गया। सिद्धाय बाबू चाहते थे कि राष्ट्रपति को कोई सलाह देने से पहले प्रधानमंत्री के लिए मन्त्रिमण्डल से महाविरा करना जरूरी न समझा जाये।

जिन जिन लोगों की श्रीमती गांधी के शासन में फायदा हुआ था उन सभी को इन संशोधनों को उचित साबित करने के काम पर लगा दिया गया। जब भी श्रीमती

गांधी ने सामने कोई समस्या होती थी तब वह ऐसा ही करती थी।

भारत के भूतपूर्व चीफ जस्टिस और लॉ कमीशन के अध्यक्ष पी० बी० गजेन्द्र गडकर ने इन सशोधन की परवी करते हुए कहा, "जब भारतीय जनता नागरिकों की 'यायोचित पर बढ़ती हुई आशाओं और आशाओं को पूरा करने और सामाजिक बराबरी और आर्थिक 'याय के आधार पर एव' नयी समाज-प्रवृत्ति स्थापित करने के अपन ध्येयों को पूरा करने का बीड़ा उठायेगा, तो मुमकिन है कि इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उस समय समय पर मुनासिब कानून बनाने पड़ें।"

विपक्ष के नेता अशोक मेहता ने इस बात की निंदा की कि सरकार "इमजेंसी की स्थिति को (जो जून 1975 में लागू की गयी थी) कानूनी जामा पहना रही है और (प्रधानमंत्री इंदिरा) गांधी के हाथों में सारी शक्ति समेट लेने को कानून का सहारा दे रही है।"

जब सविधान में परिवर्तन करने के सवाल पर विचार करने के लिए 25 अक्टूबर को सदन की बैठक हुई तो विपक्ष के ज्यादातर सदस्यों ने उस बैठक में भाग नहीं लिया। विपक्ष की चार पार्टियों ने मिलकर एक बयान दिया जिसमें कहा गया था कि ये सशोधन 'सविधान में जिन अनुसूचों और अनुसूचियों की व्यवस्था की गयी है उसकी पूरी प्रणाली को नष्ट कर देंगे और नागरिकों के हित के खिलाफ सत्ता के मनमाने उपयोग को ही बाकी रहने देंगे।"

श्रीमती गांधी इस बिल का विरोध करनेवालों पर बरस पड़ी और बहस के दौरान उन्होंने कहा कि 'जो लोग कानून को एक ऐसे शिकजे में फँस देना चाहते हैं जिसे कभी बदला न जा सके, उन्हें नये भारत की सच्ची भावना का कुछ भी पता नहीं है।"

यह आलोचना की गयी कि सरकार ने जो कदम उठाये थे उनका सविधान के बुनियादी ढाँचे पर असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुमत फैसले के अनुसार सदन को ऐसा करने का अधिकार नहीं था। श्रीमती गांधी ने कहा कि सविधान के "बुनियादी ढाँचे के उस जड़ विचार को हम नहीं मानते," जो जजा की गड़ी हुई बात है। सरकार का साथ देनेवाले सविधान के विशेषज्ञों ने कहा कि जजा ने कभी भी साफ साफ शब्दों में यह नहीं बताया कि बुनियादी ढाँचा है क्या। सविधान के बुनियादी लक्षण गिनाना कोई ऐसा कठिन काम नहीं था। इनमें से कुछ तो बिल्कुल बुनियादी थे—स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जनता के सामने सरकार की जवाबदेही, स्वतंत्र जजा के सामने अदालत में विचार कानून का शासन जिसका मतलब यह था कि कानूनी कारवाई पूरी किये बिना किसी भी आदमी से उसकी जान, आजादी या जाय-दाद नहीं छीनी जा सकती, कानून की नज़र में सभी की बराबरी, स्वतंत्र प्रसवार्थ, धर्म निरपेक्षता जिसका मतलब था धर्म की आजादी और धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाना और सामाजिक 'याय।

श्रीमती गांधी को या उनको घेरे रहेवालों को जो चीज परेशान कर रही थी यह सविधान का बुनियादी ढाँचा नहीं था। उनको असली परेशानी इस बात की थी कि बाकी सब लोग तो सीधे रास्ते पर आ गये थे लेकिन जज लोग अभी तक नहीं आये थे। कुछ जज अब भी स्वतंत्र ढंग से काम करते थे और उनके जो फैसले सरकार के खिलाफ होते थे वे प्रणामन के लिए हमेशा एक समस्या खड़ी कर देते थे। वे परेशानी की जड़ थे उन्हें एक जगह से बदलकर दूसरी जगह भेजना पड़ेगा, और यह दूसरी के लिए भी एक सबक होगा।

सालह जजा को बदलकर दूसरी जगहों पर भेज दिया गया एत०

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तक ने इस विचार का विरोध किया। विपक्ष की पार्टियाँ सविधान सभा के तो पक्ष में थीं लेकिन वे चाहती थीं कि उससे सदस्य बालिग मत-धिकार की बुनियाद पर सीधे चुने जायें। उनकी दलील यह थी कि मौजूदा संसद और राज्यों की विधानसभाएँ जितने दिन के लिए चुनी गयी थी उससे ज्यादा वक्त तक वे काम कर चुकी हैं, इसलिए अब वे मतदाताओं की प्रतिनिधि नहीं रह गयी हैं। सविधान सभा के विचार को और आगे नहीं बढ़ाया गया।

लोकसभा ने, जो शुरू में पांच साल के लिए चुनी गयी थी, 5 नवम्बर को अपनी अवधि एक साल के लिए और बढ़ा ली। नतीजा यह हुआ कि जो चुनाव मार्च 1976 में हो जाने चाहिए थे वे अब 1978 तक के लिए टल गये।

अब संसद में कोई मधु लिमये या शरद यादव तो था नहीं जो लोकसभा से इस्तीफा दे देता, जिस तरह इन दोनों ने उस वक्त इस्तीफा दे दिया था जब लोकसभा ने पहले अपनी अवधि बढ़ायी थी। मधु ने स्पीकर को लिखा था 'मेरी राय में मौजूदा लोकसभा की अवधि को बढ़ाना सरासर अनतिथ और बेईमानी की बात है। मेरा पक्का विश्वास है कि इस सरकार को अपने पक्ष में मतदाताओं का फैसला लिये बिना 18 मार्च 1976 के बाद शासन की बागडोर अपने हाथ में रखने का कोई अधिकार नहीं है।' श्रीमती गांधी के नाम एक पत्र में उन्होंने उस वक्त लिखा था "मैं कहता हूँ, लोगों को नज़रबंद करने के बाद आपने अपने हाथ क्यों रोक लिये? जो कुछ आप करना चाहती हैं सब कर देखिये। गणराज्य का यह सारा ढोंग छोड़कर आप राजतंत्र का या साम्राज्यशाही का सविधान क्यों नहीं बनवा लेती ताकि इस बात का पक्का यकीन हो जाये कि आपके बाद आपका बेटा और उसके बाद उसका बेटा राज्य करेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपकी दिली तमन्ना यही है? सायद पश्चिमी देशों के कांसिस्टों को इस बात पर खुशी होगी कि हमारे बारे में उनकी यह पुरानी राय सब निकली कि एशिया और अफ्रीका की 'घटिया नस्लों के हम लोग इस लायक नहीं हैं कि नागरिक स्वतंत्रता और जनतंत्र के बरदानों का सुख भोग सकें।"

सरकार ने लोकसभा की अवधि बढ़ाने को इस बुनियाद पर सही ठहराया कि हमजैसी से जो 'फायदे' हुए हैं उन्हें अभी पक्का करना है। दुबारा अवधि बढ़ाने के बिल का विरोध विपक्ष की लगभग सभी पार्टियों ने किया लेकिन वह 34 के खिलाफ 180 वोटों से पास हो गया। श्रीमती गांधी ने चुनाव टलवाने के पक्ष में यह दलील दी कि "हम भगड़ों से या किसी भी ऐसी चीज़ से परे रहना चाहिए जो गड़बड़ी के हालात पैदा कर सके।"

चुनाव का काँटा रास्ते से हट जाने के बाद अब श्रीमती गांधी को इस बात की फिक्र थी कि सजय ने जितनी बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियाँ सँभालने का बीड़ा उठा लिया है उनके लायक उसे कैसे बनाया जाये। सजय अभी स. कैबिनेट के काफ़ज़ात देखने लगा था, बड़े बड़े अफसर उससे बातचीत करने आते थे, खुफिया रिपोर्टें उसी की भाफ़त प्रधानमंत्री के पास तक पहुँचती थीं। (विद्यारण्य शुक्ला की हरकतों के बारे में जो भी जानकारी होती थी उसे वह अक्सर रोक लेता था क्योंकि श्रीमती गांधी इन मंत्री महोदयों को चेतावनी दे चुकी थीं।) कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री या तो खुद सजय से सलाह लेते थे या इस काम के लिए अपने सेक्रेटरियों को भेजते थे। एक बार पिसा मंत्री नूफल हसन ने किसी सुभाव के सिलसिले में अपने सेक्रेटरी स. सजय की राय मालूम कर लेने को कहा था। राज्यों के मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि चीफ सेनेटरी तथा उसकी मर्जी जानने के लिए उसके दरबार में हाथ बँधे सहे रहते थे।

लेकिन यह सारा सिलसिला तो कामचलाऊ था, किसी वक्त भी टूट

था। श्रीमती गांधी ने सोचा कि इसे बानूनी रूप देना होगा। कुछ लोग ने सुझाव दिया था कि उसे गज्यसभा के रास्ते ससद में ले जाया जाये। लेकिन वह इसके लिए तयार नहीं हुई, यह तो इतना खुला तरीका होगा कि भ्रष्टा भी देख लेगा।

फिलहाल सबसे अच्छा तरीका शायद यही होगा, उन्होंने सोचा, कि युवक कांग्रेस को मजबूत किया जाये और सजय को हमलों से बचाया जाये। अब तो कांग्रेस पार्टी के अन्दर भी लोग खुलेआम उसकी भालोचना करने लगे थे। श्रीमती गांधी ने सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर हमला किया जिसने सजय की भालोचना की थी।

सजय कम्युनिस्टों और उनकी पॉलिसिया स नफरत करता था, यह बात उसने कभी छिपायी नहीं थी। वह कई बार वह चुका था कि दूसरी सजाई के दौरान सोवियत संघ, फ्रेंचों और दूसरी मित्र ताकतों का साथ देकर कम्युनिस्टों ने अगस्त 1942 में राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ गद्दारी की थी। इस भालोचना से चिढ़कर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सैक्रेटरी सी० राजेश्वर राय ने कहा कि कांग्रेस के अन्दर 'एक प्रतिक्रियावादी बाढाल चौकटों' काम कर रही है।

कांग्रेस के लोगों में भी, जिनमें इस वक़्त अपनी वफादारी साबित करने में कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता था, इस बयान पर एक लूफा लडा हो गया और उन लोगों ने कहा कि यह बयान कांग्रेस के अन्दरूनी मामलात में खुला हस्तक्षेप है। श्रीमती गांधी ने भी यही रवया अपनाया।

कई साल में पहली बार 23 दिसम्बर को उन्होंने नाम लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा, 'कम्युनिस्ट कहते हैं कि वे मेरे साथ हैं, लेकिन मेरे लिए इससे बड़े अपमान की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती कि यह कहा जाये कि मैं प्रतिक्रियावादियों के या किसी दूसरे के दबाव में आ सकती हूँ।' अपने बेटे की सफाई दत्त हुए उन्होंने कहा कि 'वह तो बहुत ही मामूली आदमी है बहुत ही छोटा आदमी है, वह न प्रधानमंत्री बननेवाला है न राष्ट्रपति और न ही कुछ और। वह तो बस कांग्रेस का कामकर्ता बन सकता है। इसलिए मैं समझती हूँ कि यह हमला सीधे मेरे ऊपर है।'

गोहाटी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भी 20 नवम्बर को श्रीमती गांधी ने सजय की तरफ से और उसकी युवक कांग्रेस की तरफ से सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि सजय ने जो पाँच सूत्री कार्यक्रम शुरू किया है वह सरकार के बीस सूत्री वार्षिक कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है और उससे देश का आर्थिक नक्शा बदल देने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह विश्वास जाहिर किया कि भारत का भविष्य उसके नीजवानों के हाथ में सुरक्षित है, जिन्होंने कुछ बुरे निताने की भावना के साथ अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है।

गोहाटी अधिवेशन में सब पूछा जाये तो सजय का ही बोलवाला रहा। एक एक करके जो भी प्रतिनिधि बोलने के लिए उठा उसने सजय की ही तारीफ के पुल बांधे। बहरान न तो उसकी तुलना भारत के महान सत्त स्वामी विवेकानन्द से की। केरल प्रदेश कांग्रेस के नीजवान और ईमानदार अध्यक्ष ए० के० एंटोनी ही अकेले ऐसे आदमी थे जिन्होंने इससे हटकर बात कही, और इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेसजनों को अपने आपका 'सुधारना' चाहिये उन्हें अपने ऊपर कोई कलक नदी लगने देना चाहिए और राजनीति की अल्पादेबाजी से दूर रहना चाहिये।

सब लोग मुर म-मुर मिलाकर उनकी और उनके उटे की महिमा का बखान कर रहे थे लेकिन इससे बावजूद गोहाटी अधिवेशन में श्रीमती गांधी कुछ चिंतित हो उठी।

एक तरह का 'मूक असहयोग' उन्होंने वहाँ देखा। उन्होंने देखा कि कांग्रेस के डेलीमेटो में एक तरह की निराशा और अविश्वास है। वही लोग, जिन्होंने अभी एक ही साल पहले चंडीगढ़ में इमर्जेंसी को चुपचाप मान लिया था, उही लोगों के चेहरे अब बुझे-बुझे थे। श्रीमती गांधी अनमने समयको का सहारा नहीं लेना चाहती थी। इससे कहीं अच्छा होगा समयको की नयी पीढ़ तैयार की जाये। उन्हें पूरा विश्वास था कि देश उनके साथ है।

वह अगर नौजवानों का सहारा लेना चाहती थी तो इसकी एक और वजह भी थी। वह चाहती थी कि सजय खुद अपने पाँवों पर मजबूती से खड़ा हो जाये। उसका एहसान माननेवालों में सिर्फ नये और नौजवान लोग होंगे।

आगे चलकर जब कभी वह प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगी, शायद कांग्रेस की अध्यक्ष बन जाने के लिए, तो उस वक्त पार्टी में सजय की इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह उनकी जगह ले सके। ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री तो इस वक्त भी उनके साथ थे— बिहार में मिश्रा, उत्तर प्रदेश में तिवारी, पंजाब में जलसिंह, हरियाणा में बनारसीदास गुप्ता, राजस्थान में हरिदेव जोशी, मध्य प्रदेश में श्यामाचरण शुक्ला, आंध्र प्रदेश में बंगलराव, महाराष्ट्र में एस० बी० चव्हाण और गुजरात में माधवसिंह सोलंकी।

तीन मुख्यमंत्री जो सजय के 'वफादार' नहीं थे, वे थे उड़ीसा की नन्दिनी सत्पथी, पश्चिम बंगाल के सिद्धाचरकर रे और कर्नाटक के देवराज अंस। इनमें से पहले दो के बारे में तो यह समझा जाता था कि उन्हें सजय से बैर है। सजय भी उनको पसन्द नहीं करता था क्योंकि वह उन्हें कम्युनिस्ट समझता था।

श्रीमती गांधी का इशारा इही लोगों की तरफ था जब उन्होंने गौहाटी में कहा था "जिस तरह हर वैद्रीय मंत्री ने अपना भ्रम एक साम्राज्य बना रखा है, उसी तरह हम देखते हैं कि मुख्यमंत्रियों के भी भ्रम भ्रम अपने साम्राज्य हैं और उन्हें दूसरे साम्राज्यों के साथ अपने साम्राज्य के टकराव की भी कोई परवाह नहीं है।"

इन लोगों से इनके साम्राज्य छीनकर उन्हें यह बता देना जरूरी था कि उनकी भौकत क्या है। सबसे पहले नन्दिनी सत्पथी की बारी थी। उड़ीसा के गवर्नर अकबर अली ने, जिन्होंने जयप्रकाश की तारीफ की थी और इस वजह से उन्हें अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था, श्रीमती गांधी को कई खत लिखे थे जिनमें उन्होंने मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार और सरकार के काम-काज में गड़बड़ी के कई आरोप लगाये थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का ध्यान उस भालीशान कोठी की तरफ भी दिलाया था जो नन्दिनी सत्पथी ने भुवनेश्वर में 7,00,000 रुपये की लागत से बनवायी थी। अकबर अली ने यह भी आरोप लगाया था कि कोठी बनवाने का काम पी० डब्ल्यू० डी० के इंजीनियरों की निगरानी में हुआ था और उसके लिए बहुत-सा सरकारी सामान इस्तेमाल किया गया था।

उड़ीसा के एक मंत्री विनायक आचार्य के जरिये सजय ने नन्दिनी सत्पथी का तहता उलटने की सारी तैयारी पहले से कर ली थी। यह भी शिकायतें मिली थी कि सरकारी काम-काज में उनका लड़का हृद से ज्यादा टाँग घड़ाता है और सजय को वह लड़का कभी भी पसन्द नहीं था। इस तरह की शिकायतें भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी कि नन्दिनी सत्पथी सरकार के काम-काज की तरफ और उड़ीसा में भ्रमाल की वजह से जो हालत पैदा हो गयी थी उसकी तरफ पूरा ध्यान नहीं देती हैं।

कुछ लोगों ने नन्दिनी सत्पथी को बताया भी कि श्रीमती गांधी उनके खिलाफ हैं लेकिन उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। देना चाहती भी नहीं थी क्योंकि वह हमेशा श्रीमती गांधी की वफादार रही थी।

ए० भाई० सी० सी० के जनरल सेनैटरी ए० भार० प्रतुले नन्दिनी सत्ययी से इस्तीफा दिलवाने के लिए उड़ीसा भेजे गये थे। उन्होंने वहाँ जाकर कहा, 'हमारी सर्वोच्च नेता श्रीमती गांधी को यह फैसला करने का पूरा पूरा जनतांत्रिक अधिकार है कि कौन उनका वफादार है और कौन नहीं। वफादारों को भलग भलग टुकड़ों में बाँटा नहीं जा सकता।'

श्रीमती गांधी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि जब नन्दिनी सत्ययी अपने राज्य की हालत के बारे में बताने के लिए हवाई जहाज से दिल्ली आयी तो वह उनसे इस्तीफा देने को कहती। जैसा ही नन्दिनी सत्ययी अपने राज्य की राजधानी में वापिस पहुँची और उन्होंने कुछ दिन की छुट्टी ली उसी वक्त उन्हें तार मिला जिसमें उनसे इस्तीफा देने को कहा गया था। हालाँकि सदन में नन्दिनी का बहुमत था, उन्हें मजबूरन 16 दिसम्बर को इस्तीफा दे देना पड़ा।

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सिद्धाथशर्कर ने ने पहले ही किसी व्यापार मण्डल के समारोह में सजय को अपनी वफादारी का बचन दिया था और उस वक्त भी याद दिलाया था कि वह तो उसके परिवार के मित्र हैं, फिर भी उनकी वफादारी पर शक किया जाता था। वह कांग्रेस के एक गुट को दूसरे से लड़वाकर अब तक बाल-बाल बचते आये थे। जिस दिन से वह राज्य के मुख्यमंत्री बने थे तभी से उनकी ताकत का सारा शारोमदार इसी पर रहा था। श्रीमती गांधी और सजय दोनों ही ने उनका नाम उन लोगो की फेहरिस्त में शामिल कर रखा था जिन्हें हटाया जाना था। इस बात का बिंदोरा पीटकर कि वह नई दिल्ली की सरकार से भी टक्कर ले सकते हैं उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपने पाँच मजबूती स जमा लिये थे—इस न्यूनी से बंगाली बहुत खुश होते हैं।

सिद्धाथशर्कर के ग्रुप ने खुलेआम नेहरू परिवार पर यह झुलझाम लगाया कि उसने कभी बंगाल के नेताओं को पनपने का मौका ही नहीं दिया। रे के विरोधी ग्रुप ने सिद्धाथ बाबू पर यह झुलझाम लगाया कि वह बंगाल को भी बंगला देश के रास्ते पर ल जाना चाहते हैं।

सिद्धाथ बाबू आपस के लोगो में यह कहते थे कि केन्द्रीय सरकार उन्हें निकम्मा साबित करने के लिए हिन्दू-मुस्लिम दंग या कोई दूसरे उपद्रव कराने की कोशिश कर सकती है। उनकी दलील यह थी कि हितैह्य देसाई का पत्ता काटने के लिए 1969 में महमदाबाद में हिन्दू मुस्लिम दंगा कराया गया था कमलापति त्रिपाठी को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश में पुलिस की बग़ावत करायी गयी थी, और अब उनकी बारी थी।

श्रीमती गांधी ने सिद्धाथशर्कर के को हटाया नहीं, और न ही वह देवराज प्रसे को हाथ लगाना चाहती थी। इस वक्त तक उनका दिमाग किसी दूसरे ही डर पर काम करन लगा था।

धर सजय को सहारा देकर खड़ा करना था और किसी दिन प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार करना था तो मुख्यमंत्रियों की वफादारी ही इसके लिए काफी नहीं थी। श्रीमती गांधी उन ससद सदस्या की बुनियाद पर सोच रही थी जिनको इमर्जेंसी के बारे में किसी तरह का सवाल नहीं होगा और जिनके लिए जैसी वह भी वसा ही सजय होगा।

खुफिया विभाग और 'रा' दोनों ही का यह भ्रम था कि अगर वह अभी फौरन चुनाव करा लें तो उनको 350 से ज्यादा सीटें मिल जायेंगी। सिक सी० बी० भाई० के डायरेक्टर डी० सेन की राय इससे भलग थी, श्रीमती गांधी उन्हें अपने झालोचको के धरो पर छापे डलवाने के लिए इस्तेमाल करती थी। सेन ने इस बात पर जोर दिया था कि नज़रबन्दों की रिहाई और चुनावों के बीच छ महीने का वक्त

रहना चाहिये ताकि जेल में रहने की वजह से उनकी जो घूम होगी वह कुछ ठंडी पड़ जाये।

श्रीमती गांधी के अपने सेक्रेटरी घर पूरी तरह चुनावों के पक्ष में थे क्योंकि इमर्जेंसी से जो नुकसान थे उन्हें दूर करने का यही एक तरीका था। शेर पर सवार हो जाना भासान होता है पर उस पर से उतरना लगभग नामुमकिन होता है। इसकी क्या तरकीब हो सकती है? घर को यह भी यकीन था कि इमर्जेंसी का असर अब उल्टा पढ़ने लगा है और यह कि आर्थिक समस्याएँ एक बार फिर उभरने लगेंगी।

* बीस-सूत्री कार्यक्रम के कुछ अच्छे नतीजे निकले थे। जुलाई 1975 से दिसम्बर 1975 तक सिर्फ 45 लाख दिहाड़ियों के काम का नुकसान हुआ था जबकि 1974 में यही नुकसान 4 करोड़ 3 लाख दिहाड़ियों का था। पब्लिक सेक्टर में इमर्जेंसी से पहले 16 लाख 20 हजार दिहाड़ियों का नुकसान हुआ था, जबकि इमर्जेंसी के दौरान कुल 1 लाख 20 हजार दिहाड़ियों का नुकसान हुआ। 1975-76 में मुद्रा स्थिति की रफ्तार सिर्फ 33 प्रतिशत थी जबकि 1974-75 में इसकी रफ्तार 234 प्रतिशत थी।

लेकिन जाड़ों की बारिश न होने की वजह से खेती-बाड़ी की हालत बहुत गम्भीर थी, जिसका असर पूरे प्रयत्न पर पड़ता। (इसी वक्त सरकार ने 42 लाख टन अनाज बाहर से मगाने का फैसला किया जिसमें से कुछ तो यूरोप के देशों के साझा बाजार से और अमरीका के 'ग्रान्ति के लिए अन्न' कार्यक्रम के सहित मिला था।) मजदूरों में बेचैनी बढ़ रही थी और पैदावार बढ़ाने का पहलेवाला जोश भी अब कुछ ठंडा पड़ रहा था।

खबर मिली थी कि फौजा छावनियाँ में, खास तौर पर छोटे अफसरों के बीच, खाने के समय इमर्जेंसी के बारे में और सज्ज के सविधान के बाहर के अधिकारों के बारे में खुलेआम चर्चा होती थी। जवानों के बीच नसबंदियों के सिलसिले में की गयी पर्याप्तियों की चर्चा होती थी।

भुट्टो के बारे में बड़ी सारीफ के साथ कहा जाता था कि उन्होंने पाकिस्तान में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया।¹ और अगर श्रीमती गांधी ने चुनाव कराने का ऐलान न किया तो उनके ऊपर यह कहकर हमला किया जायेगा कि वह जनतांत्रिक नहीं हैं।

और फिर अब भी इतना डर बाकी था कि लोग अपना वाट डालने मतदान के द्रो तक जाने से घबरायेंगे। इमर्जेंसी उठायी नहीं जायेगी, उसमें बस थोड़ी-सी ढील दी जायेगी। श्रीमती गांधी ने पक्का इरादा कर लिया था कि विपक्ष की पार्टियों के कार्यक्रमों को सबसे बाद में छोड़ा जायेगा।

विपक्ष की पार्टियों में एकता भी तो अभी नहीं दिखायी देती थी। यह सच है कि उन्होंने 16-17 दिसम्बर को सबको मिलाकर भारतीय जनता कांग्रेस के नाम से एक ही पार्टी बना लेने का फैसला किया था और अपना एक मिला-जुला निशान भी चुन लिया था—चक्र, हल और चर्खा। लेकिन नेता कौन होगा इसका फैसला होना अभी बाकी था। श्रीमती गांधी ने सोचा था कि इसका फैसला कभी हो ही नहीं पायेगा।

दरमसल, विपक्ष की पार्टियाँ श्रीमती गांधी के साथ बातचीत करना चाहती थी। वे कण्ठानिधि के 15 दिसम्बर के इस सुझाव को मान लेने पर तैयार हो गयी थी कि प्रधानमंत्री के साथ बातचीत शुरू की जाये और देश की राजनीतिक स्थिति को

1 जब भारत सरकार ने चुनाव कराने का ऐलान किया तो भुट्टो ने कहा था कि भारत की जनता को उन्हें दुमाएँ देनी चाहियें।

ए० भाई० सो० सी० ने जनरल सेनैटरी ए० भार० भटुले नन्दिनी सत्यपी से इस्तीफा दिलवाने के लिए उठीसा भेजे गये थे। उन्होंने वहाँ जाकर कहा, "हमारी सर्वोच्च नेता श्रीमती गांधी की यह फैसला करने का पूरा पूरा जनतांत्रिक अधिकार है कि कौन उनका बफादार है और कौन नहीं। बफादारी को अलग अलग टुकड़ों में बाँटा नहीं जा सकता।"

श्रीमती गांधी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि जब नन्दिनी सत्यपी अपने राज्य की हालत के बारे में बताने के लिए हवाई जहाज से दिल्ली आयी तो वह उनसे इस्तीफा देने को कहती। जैसे ही नन्दिनी सत्यपी अपने राज्य की राजधानी में वापिस पहुँची और उन्होंने कुछ दिन की छुट्टी ले ली उसी वक्त उन्हें तार मिला जिसमें उनसे इस्तीफा देने का कहा गया था। हानाकि सदन में नन्दिनी का बहुमत था, उन्हें मजबूरन 16 दिसम्बर को इस्तीफा दे देना पड़ा।

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सिद्धाथशर्करा ने ने पहले ही किसी व्यापार-मण्डल के समारोह में सजय का अपनी बफादारी का वचन दिया था और उसे यह भी याद दिलाया था कि वह तो उससे परिवार के मित्र हैं, फिर भी उनकी बफादारी पर शक किया जाता था। वह कांग्रेस के एक गुट को दूसरे से सडवाकर अब तक बाल-बाल बचत आये थे। जिन दिन से वह राज्य के मुख्यमंत्री बने थे तभी से उनकी ताकत का सारा दारोमदार इसी पर रहा था। श्रीमती गांधी और सजय दोनों ही ने उनका नाम उन लागा की फेहरिस्त में शामिल कर रखा था जिन्हें हटाया जाना था। इस बात का डिठोरा पीटकर कि वह नई दिल्ली की सरकार से भी टक्कर ले सकते हैं उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपने पाँच मजबूती से जमा लिये थे—इस खूबी से बंगाली बहुत खुश होते हैं।

सिद्धाथशर्करा के के ग्रुप ने खुलेआम नेहरू परिवार पर यह इलजाम लगाया कि उसने कभी बंगाल के नेताओं को पनपन का मौका ही नहीं दिया। के के विरोधी ग्रुप ने सिद्धाथ बाबू पर यह इलजाम लगाया कि वह बंगाल को भी बंगला देश के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं।

सिद्धार्थ बाबू भापस के लोगो में यह कहत थे कि केन्द्रीय सरकार उन्हें निकम्मा साबित करने के लिए हिन्दू-मुस्लिम दंगे या कोई दूसरे उपद्रव कराने की कोशिश कर सकती है। उनकी दलील यह थी कि हितेन्द्र देसाई का पत्ता काटने के लिए 1969 में अहमदाबाद में हिन्दू मुस्लिम दंगा कराया गया था, कमलाधर त्रिपाठी को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश में पुलिस की बगावत करायी गयी थी, और अब उनकी बारी थी।

श्रीमती गांधी ने सिद्धाथशर्करा के को हटाया नहीं, और न ही वह देवराज भट्ट को हटाने लगाया चाहती थी। इस वक्त तक उनका दिमाग किसी दूसरे ही ढर्रे पर काम करन लगा था।

अगर सजय को सहारा देकर खड़ा करना था और किसी दिन प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार करना था तो मुख्यमंत्रियों की बफादारी ही इसके लिए काफी नहीं थी। श्रीमती गांधी उन ससद सदस्यों की बुनियाद पर सोच रही थी जिनको हमजैसी के बारे में किसी तरह का सकोच नहीं होगा और जिनके लिए जैसी वह थी वसा ही सजय होगा।

बुनियाद विभाग और 'रा' दोनों ही का यह अंदाजा था कि अगर वह अभी फौरन चुनाव करा लें तो उनको 350 से ज्यादा सीटें मिल जायेंगी। सिफ 100 बी० भाई० के शायरेक्टर डी० मेन की राय इससे अलग थी, श्रीमती गांधी उन्हें अपने धातीचक्रों के घरो पर छोड़े बलवान के लिए इस्तेमाल करती थी। मेन ने इस बात पर जोर दिया था कि नजरबन्दों की रिहाई और चुनाव के बीच छ महीने का वक़्त

रहना चाहिये ताकि जिस में रहने की वजह से उनकी जो घूम होगी वह कुछ ठंडी पड़ जाये।

श्रीमती गांधी के अपने सेक्रेटरी घर पूरी तरह चुनाबो के पक्ष में थे क्योंकि इमर्जेंसी से जो नुकसान थे उन्हें दूर करने का यही एक तरीका था। शेर पर सवार हो जाना आसान होता है पर उस पर से उतरना संभव नामुमकिन होता है। इसकी क्या तरकीब हो सकती है? घर को यह भी यकीन था कि इमर्जेंसी का प्रसार अब उल्टा पड़ने लगा है और यह कि आर्थिक समस्याएँ अब बार फिर उभरने लगेंगी।

* बीस-सूत्री कार्यक्रम के कुछ अच्छे नतीजे निकले थे। जुलाई 1975 से दिसम्बर 1975 तक सिर्फ 45 लाख दिहाडियो के बाम का नुकसान हुआ था जबकि 1974 में यही नुकसान 4 करोड़ 3 लाख दिहाडियो का था। पब्लिक सेक्टर में इमर्जेंसी से पहले 16 लाख 20 हजार दिहाडियो का नुकसान हुआ था, जबकि इमर्जेंसी के दौरान कुल 1 लाख 20 हजार दिहाडियो का नुकसान हुआ। 1975-76 में मुद्रा स्फीति की रफ्तार सिर्फ 3.3 प्रतिशत थी जबकि 1974-75 में इसकी रफ्तार 23.4 प्रतिशत थी।

लेकिन जाड़ा की बारिश न होने की वजह से खेती-बाड़ी की हालत बहुत गम्भीर थी, जिसका प्रसार पूरे अखबार पर पड़ता। (इसी वक्त सरकार ने 42 लाख टन अनाज बाहर से मँगाने का फैसला किया जिसमें से कुछ तो यूरोप के देशों के साम्राज्यवादी से और अमरीका के 'शान्ति के लिए अन्न' कार्यक्रम के तहत मिला था।) मजदूरों में बेचनी बढ़ रही थी और पदावार बढ़ाने का पहलवाला जोश भी अब कुछ ठंडा पड़ रहा था।

खबर मिली थी कि फौजा छावनियाँ में, खास तौर पर छोटे अफसरों के बीच, खाने के समय इमर्जेंसी के बारे में और सजय के सविधान के बाहर के अधिकारों के बारे में खुलेआम चर्चा होती थी। जवानों के बीच नक्सबंदियों के सिलसिले में की गयी एमार्शियाँ का चर्चा होती थी।

मुद्दों के बारे में बड़ी तारीफ के साथ कहा जाता था कि उन्होंने पाकिस्तान में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया।¹ और अगर श्रीमती गांधी ने चुनाव कराने का ऐलान न किया तो उनके ऊपर यह कहकर हमला किया जायेगा कि वह जनतांत्रिक नहीं हैं।

और फिर अब जो इतना डर बाकी था कि लोग अपना वोट डालने मतदान के द्रोतक जाने से परवार्येंगे। इमर्जेंसी उठायी नहीं जायेगी, उसमें बस थोड़ी-सी ढील दी जायेगी। श्रीमती गांधी ने पक्का इरादा कर लिया था कि विपक्ष की पार्टियों के कार्यकर्त्ताओं को सबसे बाद में छोड़ा जायेगा।

विपक्ष की पार्टियाँ में एकता भी तो अभी नहीं दिखायी देती थी। यह सच है कि उन्होंने 16-17 दिसम्बर को सबको मिलाकर भारतीय जनता कांग्रेस के नाम से एक ही पार्टी बना लेने का फैसला किया था और अपना एक मिला-जुला निशान भी चुन लिया था—चक्र, हल और खर्खा। लेकिन नेता कौन होगा इसका फैसला होना अभी बाकी था। श्रीमती गांधी ने सोचा था कि इसका फैसला अभी हो ही नहीं पायेगा।

दरमसल, विपक्ष की पार्टियाँ श्रीमती गांधी के साथ बातचीत करना चाहती थीं। वे करुणानिधि के 15 दिसम्बर के इस सुझाव को मान लेने पर तयार हो गयी थी कि प्रधानमंत्री के साथ बातचीत शुरू की जाये और देश की राजनीतिक स्थिति को

1 जब भारत सरकार ने चुनाव कराने का ऐलान किया तो मुद्दों ने कहा था कि भारत की जनता को उन्हें दुमाएँ देनी चाहियें।

सम पर लाने के लिए कोई हल निकाला जाये। विपक्ष की पार्टियों ने एक बयान निकाला था जिसका शीर्षक था 'यह हमारा विश्वास है', इस बयान में उन्होंने अहिंसा, धर्म निरपेक्षता और जनतांत्रिक प्रणाली में अपनी भास्था पर जोर दिया था।

दूसरी ओर विदेशों में होनेवाली आलोचना से भी उन्हें बहुत झुंझलाहट होती थी। पश्चिमवाले उन्हें 'गैर कानूनी' शासक समझते थे। इसकी उन्हें काट करनी थी। इसके लिए उन्होंने फ्रांस को चुना और पश्चिमवालों के साथ एक पश्चिमी देश से 'बात करने' के लिए उन्होंने मई में विदेश यात्रा का बन्दोबस्त किया। उस वक्त तक वह इन लोगों पर यह साबित कर चुकी होगी कि जनता उनके, तथा जो कुछ वह करती हैं उसके, साथ है। सवाल कानूनी या गैर-कानूनी होने का नहीं था, सवाल यह साबित करने का था कि इस बात पर किसी तरह का सदेह नहीं किया जा सकता कि जनता उनकी मुठ्ठी में है।

सजय और बसोलाल दोनों ही की यह राय थी कि कांग्रेस पर तो ये सारी दलीलें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन यह व्यावहारिक राजनीति नहीं थी। वे दोनों चुनाव कराने के सख्त खिलाफ थे। सजय समझता था कि यह 'खून' उसकी माँ के दिमाग में कम्युनिस्टों ने बिठाया है। उसका ऐसा समझना बहुत गलत भी नहीं था क्योंकि ब्रह्मा चुनाव के पक्ष में थे।

श्रीमती गांधी ने सोचा कि सजय, बसोलाल और दूसरे लोग तो बिना बजह परेशान हो रहे हैं। सविधान में इस तरह हेर-फेर कर दिये गये थे कि इमर्जेंसी कमीशन हमेशा की थीज हो गयी थी। कुछ महीने पहले, 2 फरवरी को, सदन ने इमर्जेंसी उठाने के बाद भी अखबारों पर हमेशा सेंसरशिप लगाये रखने की मजूरी दे दी थी। कुछ जजों का तबादला हो जाने के बाद से मजालतों भी हकीकत को समझने लगी थी। और फिर गोलले सविधान में कुछ इस तरह का हेर फेर करने की तैयारी कर रहे थे कि दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत से किसी जज पर महा अभियोग लगाने का प्रस्ताव पास कराने का बजाय सरकार को जजों को बर्खास्त कर देने का अधिकार दे दिया जाये।

सजय के विरोध करने पर श्रीमती गांधी ने एक बार फिर इस बात पर गौर किया। जो मुख्यमंत्री उनसे मिलने आते थे उनसे भी उन्होंने इसके बारे में बातचीत की लेकिन उन लोगों की यह बहने की हिम्मत नहीं होती थी कि वे चुनाव जीत नहीं सकते। अगर इन्हीं दो बातों में से एक को चुनना था कि चुनाव अभी हो या एक साल बाद हो तब तो यही बेहतर था कि चुनाव अभी करा लिये जायें। बाद में शायद उन्हें 'लोगों को काबू में रखने के लिए ज्यादा कोशिश करनी पड़े।

वह यह भी जानती थी कि अण्डरग्राउण्ड संगठन की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके नेता लगभग रोज ही गुप्त भाषा में और फर्जी नामों से आपस में टेलीफोन पर बात करते थे। जब शहरो के भासानी से पकड़ में आ जानेवाले प्रेसों को जन्म कर निभाया गया तो चोरी छिपे साइक्लोस्टाइल अखबार निकाले जाने लगे।

उन्होंने सुफिया विभागवालों से एक बार फिर इस बात की याह लेने के लिए कहा कि जनता के तेवर क्या हैं। पहले की तरह वे इस बार भी उम्मीद नतीजे पर पहुँचे कि यह प्राराम में काफी बड़े बहुमत से जीतेंगे। इस बार इन लोगों ने उन्हें 320 सीटें दी थी पहली बार से 30 कम। सजय अब भी चुनाव कराने के खिलाफ था, लेकिन श्रीमती गांधी चुनाव कराने की ठान चुकी थी।

उन्होंने कई सदस्य-संसदों से भी सलाह मशविरा किया, लेकिन उनमें से कोई

भी अपने इलाके के मतदाताओं के सामने जाने को तैयार नहीं था। इमर्जेंसी ने उनकी सारी साख मिट्टी में मिला दी थी। श्रीमती गांधी पर सबसे ज्यादा असर नई दिल्ली की इस्टीम्यूट प्रॉफ पालिसी रिसर्च (नीति शोध संस्थान) की ओर से करायी गयी एक छानबीन की रिपोर्ट का पड़ा, जिसकी ओर धर ने उनका ध्यान दिलाया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि इस समय श्रीमती गांधी के पक्ष में जनमत अपने शिखर पर है। ऐसा लगता था कि इससे अच्छा मौका उनके हाथ नहीं लगनेवाला है।

वह कितनी गलत साबित हुई। अब तक उन्होंने जो भी कदम उठाया था वह बिल्कुल ठीक वक्त पर उठाया था, लेकिन अब उनका हर हिसाब गड़बड़ होने लगा था क्योंकि जनता के साथ उनका सम्पर्क नहीं रह गया था। उनकी जितनी भी जानकारी थी वह सारी की सारी खुफिया विभागवालों की उन रिपोर्टों से मिली थी जो उन्हें खुश रखने के लिए तैयार की गयी थी। उनके चारों ओर जो खुशामदी और चापलूस जमा थे वे उनसे हरदम यही कहत रहते थे कि इमर्जेंसी ने तो कमाल कर दिया है और जनता अब से पहले कभी इतनी सुखी नहीं थी।

सबसे पहले उन्होंने खुफिया विभागवालों को ही बताया कि वह माच के बाज़ार में या अप्रैल के शुरू में चुनाव करायेंगी और वे इसके लिए 'तैयार' रहे। वह समझती थी कि वह कोई खतरा नहीं मोल ले रही हैं क्योंकि वह जानती थी कि जीत उन्हीं की होगी।

श्रीमती गांधी की मजबूरियाँ कुछ भी नहीं हो, लेकिन चुनाव कराने का फमला करके उन्होंने यह बात मान ली थी कि कोई भी शासन प्रणाली जनता की मर्जी और उसकी मजूरी के बिना नहीं चल सकती। एक तरह से वह जनता के धीरज और उसकी मुसीबतों झेलन की क्षमता का लोहा मान रही थी। क्योंकि बाज़ारकार जीत तो उसी की हुई—जीत उन लोगों की हुई जो अनपढ़ थे, गरीब थे और पिछड़े हुए थे।

फसला

भोरारजी अपनी भादत के अनुसार 18 जनवरी 1977 को भी बहुत सवेरे उठे थे। सुबह उठकर वह टहलने गये। पिछले कई महीना से यही उनका दस्तूर था। वह दिन भी दूसरे दिनो जसा ही लग रहा था।

दिनचर्या गीरस जरूर थी, पर उससे तो मच्छी ही थी जसी कि सोना में थी, जहा वह शुरू शुरू में नजरबंद किये गये थे। उस वक्त तो उह एक छोटी सी मछेरी कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसकी खिडकियाँ हमेशा बन्द रहती थी। बहुत शोर मचाने पर उहे रात होने के बाद बाहर म्हाते में टहलने की इजाजत दे दी गयी थी। म्हाते में साँप बिछू बहुत थे इसलिए उहोने 'यायाम' के लिए अपनी चारपाई के चारो ओर टहलने का फैसला किया। उह मचमुच मछेरे में रखा गया था और उह इसकी कोई खबर नहीं थी कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। उह पढ़ने को म्हाबार तक नहीं दिया जाता था।

जब उहें वहाँ से हटाकर साना के पास ही एक नहर की कोठी में रख दिया गया था तो उहे म्हाबार मेंगाने की और बाद में मुसाकातो की भी इजाजत दे दी गयी थी। उस दिन, 18 जनवरी को उन्होने इण्डियन एक्सप्रेस में एक खबर पढ़ी थी कि लोकसभा के चुनाव माच के अत तक होगे। उन्होने इस खबर पर विस्वास नहीं किया, उह इसके बारे में शक था।

जब उनके कमरे में जहा ठीक से बैठने के लिए भी कुछ न था, पुलिस के कुछ पुराने भफसर आये तो भोरारजी ने उनमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखायी। इन लोगो ने उह बताया कि उह बिना किसी शत के रिहा किया जा रहा है और वे उह झूले रोड पर उनके बैगले ल जाने के लिए आये हैं। वे लोग मोटर भी साथ लाय थे।

तब तक विपक्ष के नेता और ज्यादातर दूसरे लाग छोडे जा चुके थे। नजर बन्ने की सख्या, जो किसी समय 1,00,000 तक पहुँच गयी थी, अब घटकर लगभग 10,000 रह गयी थी।

घर पहुँचकर भोरारजी ने सुना कि श्रीमती गांधी ने लोकमभा बर्खास्त करके नय चुनाव कराने का फसला किया है। उह कोई ताज्जुब नहीं हुआ। उहोने मुझे बाद में बताया 'मैं हमेशा से जानता था कि वह मुझे उसी वकन रिहा करेंगी जब वह चुनाव कराने का फसला करेंगी।'

लेकिन ऐस लोग भी थे जिह ताज्जुब हुआ। इनमें कबिनेट के कई मंत्री भी थे। उनका इस फसन का पता उस दिन तीसरे वक्त तब चला जब उहें जल्दी-जल्दी बुलाकर इसकी मूचना दी गयी। श्रीमती गांधी न उनसे कहा कि जनतांत्रिक प्रणाली में सरकार का थोडे थोडे समय के बाद मतदाताओं का सामना करना ही पडता है। उहोने यह माना कि वह एक जोखिम उठान जा रही हैं।

किसी भी मंत्री न कुछ नहीं कहा। बसोलाल को पहले से इसकी खबर थी और यह परेधान थे, जगजीवनराम और चह्नाण बिनबुल मौन साधे रहे। जिस तरह हमजैसी लागू करने के बारे में उनसे सलाह माँगविरा नहीं किया गया था, उसी तरह चुनावों के बारे में भी उनसे कोई सलाह नहीं ली गयी थी। लेकिन दूसरे मंत्रियों की तरह उनको भी कुछ कुछ शक था कि चुनाव होने वाले हैं, खासतौर पर उसके बाद से जब सजय ने दो ही दिन पहले बम्बई की एक पब्लिक मीटिंग में कहा था कि चुनाव जल्दी ही होनेवाले हैं। इतने दिनों में वे यह मानने लगे थे कि सजय को हर बात का पक्का पता रहता है।

जा बात इन लोगों को नहीं मालूम थी वह यह थी कि उनमें से ज्यादातर का पता साफ कर दिया गया था। श्रीमती गांधी के घर में सब लोग यही कहते थे कि चुनाव के बाद जगजीवनराम को मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। ससद में किसे भेजा जाना चाहिए और किस नहीं इसके बारे में सजय के अपने विचार थे। उस वक़्त तक उसने उन लोगों की फेहरिस्त भी तैयार कर ली थी जिन्हें कांग्रेस का टिकट दिया जाने वाला था—और ससद के ज्यादातर मौजूदा सदस्य उसमें नहीं थे। इन लोगों के लिए बग़ावत करके अपने बल पर खड़ा होना भी बेकार था।

हालाँकि कांग्रेस के हार्ड कमांड ने रस्म पूरी करने के लिए अपनी प्रदेश कमेटियाँ को आदेश दिया कि वे अपने अपने जम्मींदारों की फेहरिस्तें तैयार कर लें, लेकिन ज्यादातर लोग जानते थे कि यह सब महज़ दिखावे के लिए है। सजय ने ज्यादातर नाम पक्के कर रखे थे और श्रीमती गांधी ने हमेशा की तरह उसके फैसले को मजबूती भी दे दी थी।

विपक्ष की पार्टियों को चुनाव होने की तो खुशी थी लेकिन वे जानती थी कि उनके सामने कुछ भयानक कठिनाइयाँ भी हैं। उनके सारे नेता अभी कुछ ही दिन पहले तक जेल में थे और जनता से उनका कोई सम्पर्क नहीं रहा था। उनके बहुत से कामकाज़ अभी तक रिहा नहीं किए गए थे। उनके पास समय भी बहुत कम था।

लेकिन वे अब और अधिक समय नहीं खोना चाहते थे। जिस दिन मोरारजी देसाई रिहा हुए उसी दिन उनके घर पर सगठन कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं की मीटिंग हुई। उस दिन तो बस चाहिए लेने के लिए मोटी मोटी बातों पर बातचीत हुई। अगले दिन ये लोग फिर मिले। इस समय तक श्रीमती गांधी रेडियो पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में चुनावों के बारे में और 'जनता की ताकत का एक बार फिर सबूत देने' के अवसर के बारे में बता चुकी थी।

विपक्ष के नेताओं के सामने जयप्रकाश का एक पत्र था, जिसे सोशलिस्ट नेता एस० एम० जोशी पटना से लाय थे। जयप्रकाश ने कहा था कि अगर उन सबने मिलकर एक ही पार्टी न बना ली तो वह चुनाव से कोई सम्बन्ध नहीं रखेंगे। यही बात वह टेलीफोन पर पहले कह चुके थे।

विपक्ष की पार्टियों के सामने समस्या एक में मिल जान की नहीं थी। उनके नेता जेल में इस समस्या पर एक बार नहीं कई बार बहस कर चुके थे और इसी नतीजे पर पहुँचे थे कि कांग्रेस की विशाल ताकत का मुकाबला करने के लिए एक पार्टी बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अलग अलग और साथ मिलकर विपक्ष के नेताओं में जो बातचीत हुई उसमें भी वे इसी नतीजे पर पहुँचे थे। सच तो यह है कि सभी पार्टियों को एक में मिला देने की बातचीत से चरणसिंह इतनी बुरी तरह निराश थे कि उन्होंने बहुत पहले 14 जुलाई को ही सगठन कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक मेहता को लिख दिया था कि भारतीय लोकदल "अब तब आ चुका है, उसकी

नीयत पर भी चुबहा किया जा रहा है। इसलिए उसने इस सिलसिले में किसी कत्तब के बोझ को अपने मन पर रखे बिना भवेले ही चुनाव लड़ने का फसला किया है—भलावा इस एक कत्तब के कि जब कभी बाकी तीन पार्टियाँ कमोवेश राष्ट्रपिता के बताये हुए कायन्त्रम की रूपरेखा के आधार पर एक सगठन बनाने के लिए अपने आपको भग कर देंगी या भग करने का फंसला कर लेंगी, भारतीय लोकदल फौरन उनके साथ आ जायेगा।"

सारी पार्टियों के मिलकर एक हो जाने में बाधा दरमसल इस सवाल के कारण पड़ रही थी कि नेता कौन हो? 16 दिसम्बर को, जब मोरारजी जेल में थे, विपक्ष के नेताओं की मीटिंग में ऐसा लगता था कि नेता चरणसिंह ही होंगे। मोरारजी जहाँ नजरबन्द थे वहाँ से उन्होंने लिखा था कि उन्हें सब पार्टियों के मिलकर एक हो जाने में दिलचस्पी है, इस बात में नहीं कि नेता कौन होगा।

लेकिन अब, चुनाव का ऐलान हो जाने के बाद विपक्ष के नेताओं की मीटिंग में जिस तरह मोरारजी ने सारी बहस को संभाल रखा था उससे तो अब शक ही नहीं रह गया था कि नेता कौन होगा। सभी पार्टियाँ उन्हें चेयरमैन और चरणसिंह को डिप्टी चेयरमैन बनाने पर राजी हो गयीं।

अपने आपको जिंदा रखने की सहज भावना ने चारों पार्टियों को मजबूर कर दिया था कि वे चुनाव लड़ने के लिए एक ही पार्टी, एक संयुक्त मोर्चा बना लें—जनता पार्टी जिसका एक ही चुनाव का निशान हा और एक ही झंडा हो। सभी पार्टियों की भलग भलग मीटिंगें किये बिना यह मुमकिन नहीं था कि उनकी भलग भलग हैसियत को खत्म कर दिया जाय, लेकिन इसमें वक्त लगता और वक्त उनके पास था नहीं। ये पार्टियाँ जानती थी कि अगर उनकी बुरी तरह हार हुई तो श्रीमती गांधी और उनका बेटा यह समझ लेंगे कि उन्हें डिक्टेटरशिप कायम करने के लिए जनता की तरफ से छूट मिल गयी है। लेकिन अगर उनके काफी लोग जीत जाते हैं और संसद में उनका एक खासा बड़ा ग्रुप बन जाता है तो फिर श्रीमती गांधी यह दावा नहीं कर सकेंगी कि उन्हें जनता का पक्का समर्थन मिल गया है।

एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने से इस बात का तो यकीन हो जायेगा कि विपक्ष के वोट कई टुकड़ा में बटने नहीं पायेंगे। अब तक यही होता आया था कि वोट बंट जान की वजह से ही कांग्रेस जीत जाती थी, हालाँकि उसे कभी भी आधे से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। 1971 तक में जब उसने बाकी सबका सफाया कर दिया था, उस वक्त भी उसे सिर्फ 46.2 प्रतिशत वोट मिले थे।

जयप्रकाश ने पार्टियों के एक में मिल जाने को अपना आशीर्वाद दिया और जनता से कहा कि वह दो चीज़ा में से किसी एक को चुन से जनतंत्र या डिक्टेटरशिप, आज़ादी या गुलामी। उन्होंने कहा कि श्रीमती गांधी की जीत का मतलब होगा डिक्टेटरशिप की जीत। और संयुक्त मोर्चे ने भी आर्थिक समस्याओं के बजाय इसी बात पर जोर दिया।

श्रीमती गांधी ने जनता से कहा कि चुनाव कराने के भरे फमले ही से यह बात गलत साबित हो गयी है कि मैं डिक्टेटर हूँ विपक्ष की जिन पार्टियों ने अब मिलकर दक्षिणानुसी ताकतों की एव पार्टी बनायी है वहीं चुनावों के टलन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं—उन्होंने दश म जो ऊँचम मचा रखा था उसी की वजह से मजबूर होकर उन्हें चुनाव टलवाना पड़ा था।

विपक्ष की पार्टियों ने इस बात पर उनसे कोई भगडा नहीं किया। 23 जनवरी को उन्होंने आजाद जनता पार्टी के बन जान का ऐलान कर दिया। फमले तेनेवाली

सबसे ऊँची मर्यादा के रूप में 27 सदस्यों की एक राष्ट्रीय समिति बनायी गयी। इन अलग अलग पार्टियों का¹ जिनके हिता में और जिनकी विचारधाराओं में टकराव था, एक साथ लाने के लिए जयप्रकाश को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। अलग अलग नेताओं को यह समझाना पड़ा कि राष्ट्र के हित में उन्हें अपने मतभेदों को भुला देना चाहिए।

विपक्ष की पार्टियों को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो यह संदेश जनता तक पहुँचा सकें। लेकिन उनके सबसे सत्रिय नायकता अभी तक जेल में थे। उनके नेता मजरबंदों को जल्द रिहा कराने की माँग पर जोर देने के लिए पहले ग्राम मेहता से और उसके बाद श्रीमती गांधी से मिले। दोनों ही ने वायदा किया कि मजरबंदों को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन राज्या को जो आदेश भेजे गये थे उनमें यह बात साफ कर दी गयी थी कि इस काम में जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है—यह ग्राम रिहाई नहीं है और हर आदमी के मामले पर अलग अलग विचार किया जाना चाहिए, फैसले पर अमल करने में पहले उसे मजबूरी के लिए केन्द्र के पास भेजा जाना चाहिए।

सरकार चाहती यह थी कि जहाँ तक मुमकिन हो विपक्ष के ज्यादा से-ज्यादा वायकताओं को ज्यादा से ज्यादा दिन तक जेल में बन्द रखा जाये और यह भी न मालूम हो कि चुनाव जीतने के लिए किसी वंश हथकड़े का सहारा लिया जा रहा है।

इमर्जेंसी और अखबारों की सेंसरशिप में ढील देने का काम भी बड़े अनमनेपन से किया जा रहा था। सरकार इस बात को साफ कर देना चाहती थी कि तलवार नीची भले ही कर ली गयी हो पर अभी ध्यान में नहीं रखी गयी थी, वह चाहती थी कि लोग उसे देखें और डरते रहें। और कुछ दिन तक तो यह हाल रहा भी कि लोग तलवार को देखते भी थे और डरते भी थे। अभी तक चारों तरफ इतना घातक छाया हुआ था कि जनसमूह न तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इमर्जेंसी फौरन खत्म न की गयी, मजरबंदों को रिहा न किया गया और अखबारों पर से सेंसरशिप पूरी तरह उठा न ली गयी तो उसे मजबूरन चुनाव का बायकाट करना पड़ेगा।

श्रीमती गांधी के घर पर इमर्जेंसी और अखबारों पर सेंसरशिप के सवाल पर एक अतहीन बहस छिड़ी हुई थी। इस पर तो सभी की राय एक थी कि उन्हें बिस्तुल हटा लेने का तो कोई सवाल ही पड़ा नहीं होना। चुनाव के दौरान इनकी वजह से बहुत से लोग वोट देने नहीं जायेंगे जो कांग्रेस के लिए अच्छा ही होगा, और अखबार खुलकर आलोचना भी नहीं कर सकेंगे। और चुनाव हा जान के बाद, जिसमें कांग्रेस का जीतना यकीनी है इमर्जेंसी और सेंसरशिप को फिर से लागू किया जा सकता है। इस वकत उन्हें हटाने का मतलब यह होगा कि दाना सदन में बहस करने, वोट लेने और राष्ट्रपति की मजबूरी लेने का पूरा चक्र फिर से चलाना पड़ेगा, तब कही जाकर इन्हें दुबारा लागू किया जा सकेगा।

अखबारों पर सेंसरशिप में नीच का मतलब यह नहीं था कि अखबारों को जो भी उनका जो चाहे छापने की छुट मिल गयी थी। उनके सिर पर आपत्तिजनक सामग्री छापने में सम्बंधित प्राइवेंस की तलवार लटकती रहती थी। गुवनाजी ने सेंसरशिप का जो जाल फला रखा था उसे अभी समेटा नहीं था। उसके अपसरा से कहा गया कि वे सारे देश का दौरा करके सम्पादकों से जाकर मिलें और उन्हें चेतावनी दे दें कि

1 अलग अलग इलाकों की पार्टियों को मिलाकर चुनाव लड़ने के लिए एक ही पार्टी बनाने का विचार सबसे पहले प्रसिद्ध कांग्रेसी राजदूत पुरी ने पेश किया था। शुरू में वही पार्टी के एक जनरल सचिव बनाये गये थे।

धारापत से रह । ज्यादातर अखबार धारापत के साथ काम करते रहें ।

पटना से दिल्ली आने पर जयप्रकाश नारायण ने मोरारजी के घर पर जा पहलो प्रेस कांफ़ेंस की थी उसमें उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि 'उह' ऐसा लगता है कि जीतेगी ता कांग्रेस ही, इसलिए नहीं कि वह बहुत लोकप्रिय है बल्कि इसलिए कि विपक्ष की पार्टियों को अपने कार्यक्रमों को फिर से संगठित करने के लिए, पसा जमा करने के लिए और जाता को यह बता के लिए कि इस चुनाव में क्या क्या दांव पर लगा हुआ है, बहुत कम समय दिया गया था । इसमें तो शक नहीं कि देश में कांग्रेस की जगह ले सकनेवाली एक दूसरी जानदार पार्टी के बारे में जयप्रकाश का सपना तो ऐसा लगता था कि पूरा हो गया है । लेकिन उह चुनाव में उसकी कामयाबी का इतना भरोसा नहीं था ।

जनता पार्टी ने पंजाब में अकालियों की टोह लेने की कोशिश की और देखा कि वे उसके साथ मिलकर चलने को तैयार हैं । माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि वह नयी पार्टी में शामिल तो नहीं होगी लेकिन उसके साथ चुनाव लड़ने का समझौता ज़रूर कर लेगी क्योंकि नागरिक स्वतंत्रताओं के बिना कोई आर्थिक कामकाज चलाना मुमकिन नहीं है ।

कांग्रेस के लोगों के साथ, जो किसी ज़माने में उनके साथी थे, माक्सवादियों के साथ और दूसरे लोगों के साथ अपनी बातचीत के दौरान चन्द्रशेखर ने यही ख़ास ध्यान दिया था । एक पत्र में उन्होंने लिखा, "हमारे सामने चुनने के लिए जो रास्ते हैं वे बहुत सीमित हैं । या तो हम उसी (कांग्रेस की) भेड़चाल में शामिल हो जायें और छोटी मोटी निजी रिभायर्स हासिल करके अपनी भुलावों की दुनिया में मगन रहे और समाज में जो कुछ हो रहा है उसे हाथ पर हाथ धरे देखते रहें या उन ताकतों के साथ कंधे से-कंधा मिलाकर लड़ने का रास्ता अपनायें, जिन्होंने बुनियादी आजादी और नागरिक अधिकारों को अपना अटल सिद्धान्त बना लिया है ।"

तमिलनाडु में डी० एम० के० न संगठन कांग्रेस के साथ ताल मेल रखने पर अपनी रज़ामंदी जाहिर की । लेकिन चूँकि चुनाव कमीशन ने जनता पार्टी को चुनाव का नया निशान देने से इकार कर दिया था इसलिए सभी पार्टियाँ अपने अपने पुराने निशान रखकर चुनाव लड़ना चाहती थी भारतीय लोकपाल का निशान—एक पहिये के अन्दर कंधे पर हल रहे हुए आदमी वाला निशान—रखकर नहीं ।

कांग्रेस भी साथिया की खोज में थी । उस दा साथी मिले, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरा तमिलनाडु में अपना डी० एम० के० । सचय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कोई सरोकार नहीं रखना चाहता था जिसके खिलाफ उसने कुछ ही दिन पहले 'समाचार' के ज़रिये, जिसके कत्ता घर्तार्थ यूनुस में मज़बूत मे एक जबदस्त मुहिम चलायी थी । लेकिन श्रीमती गांधी ने उसे यकीन दिला दिया कि यह समझौता कांग्रेस की ग़र्ती पर होगा ।

हालाँकि कांग्रेस को किसी की मदद की दरमसल ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसे अपनी जीत का पूरा यकीन था, फिर भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रमों से कुछ तो मदद मिल ही सकती थी । बीस महीने के दौगन लोग के दिलों में जो दहशत बिठा दी गयी थी वह दो तीन महीने में तो दूर नहीं की जा सकती थी । वे उसी को वोट देंगे जिस वोट देने के लिए कहा जायगा, क्योंकि जो लोग उस पार्टी के विनाफ़ सिर उठाने की कोशिश करेंगे जिसके हाथ में सरकार की पूरी मशीन थी, उनको जल्द ही इसका मज़ा चखा दिया जायगा ।

लेकिन जल्द ही इस तरह की ग़बरों आने लगी जिनसे कांग्रेस की परेशानी

होने लगी। लोगो का डर दूर होता जा रहा था, वे इमर्जेंसी के खिलाफ बातें करने लगे थे और उन्हें इस बात का भी डर नहीं था कि उन्हें तबक लिया जायेगा। महात्मा गांधी के बलिदान दिवस 30 जनवरी को जनता पार्टी ने जब अपना चुनाव का प्रचार शुरू किया तो उसका लोगो ने जिस उत्साह से स्वागत किया उससे यह साफ पता चलता था कि हवा कांग्रेस के खिलाफ है। दिल्ली, पटना, जयपुर, कानपुर और कई दूसरी जगहों पर इतनी बड़ी-बड़ी मीटिंगें हुई कि जनता पार्टी के नेताओं को खुद इतनी उम्मीद नहीं थी। आम जनता के इस उत्साह पर अधिकारियों को भी इतना ही ताज्जुब हुआ।

दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें 1,00,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे जबकि सरकारी भण्डारों का आँदाजा था कि 10,000 या हद से हद 20,000 से ज्यादा लोग नहीं आयेंगे। इस मीटिंग में मोरारजी ने भाषण दिया। यह मीटिंग उसी रामलीला मदान में हुई थी जहाँ 25 जून 1975 को नेताओं की गिरफ्तारी और इमर्जेंसी के ऐलान से कुछ ही घंटे पहले, जयप्रकाश ने एक और बहुत बड़ी मीटिंग में भाषण दिया था। वह गमिया के दिनों की बात थी आज जनवरी की ठिठुरती हुई और भीगी हुई गामों में लोग बिलकुल चुपचाप बैठे जनता पार्टी के नेताओं के भाषण सुन रहे थे और बाद में कितनी ही लोग जनता पार्टी के चुनाव फण्ड में पैसे देने के लिए लाइन बाँध कर बड़ी देर तक खड़े रहे।

पटना में जयप्रकाश ने एक बहुत बड़ी भीड़ का शपथ दिलायी कि वे नागरिकों के बुनियादी अधिकारों और उनकी शहरी स्वतन्त्रताओं की रक्षा करने के लिए किसी भी कुयामी को बहुत बड़ा नहीं समझेंगे। दिल्ली में जनवाली मीटिंग के बाद वह पहली बार किसी पब्लिक मीटिंग में भाषण दे रहे थे। यह शपथ लेने के लिए जब हजारों लोगों ने अपने हाथ उठा दिये तो जयप्रकाश की आँखों में खुशी के आँसू छलक आये।

चरणसिंह ने कानपुर में और चन्द्रशेखर ने जयपुर में जनता पार्टी की चुनाव की मुहिम की शुरुआत की। वेहद बड़ी बड़ी भीड़ें जमा हुईं। अगले दिन सुबह जब श्रीमती गांधी के पास खुफिया विभागवालों ने इन मीटिंगों की रिपोर्टें भेजी तो उन्हें पढ़कर वह खुश नहीं हुई। वह बहुत परेशान हो उठी हालाँकि इन रिपोर्टों में इतनी बड़ी-बड़ी भीड़ें जमा होने का कोई आस महत्त्व नहीं था। उनका कहना था कि इमर्जेंसी के भयानक दौर के बाद, जब सिर्फ उन बड़ी मीटिंगों की इजाजत दी जाती थी जो सजय गांधी की जय जयकार करने के लिए की जायें यह स्वाभाविक था कि लोग सर-तकरीरों के इन मौकों का फायदा उठावें। श्रीमती गांधी ने सुझाव दिया कि जवाबी मीटिंगें की जायें।

उन्होंने यह भी साँचा कि उनकी पार्टी में जो 'बूढ़े खसूट' लोग थे उनका घर-घर अपने इलाकों में कम होता जा रहा है। वक्त आ गया है कि उनसे छुटकारा पा लिया जाय, क्योंकि संसद के जितने सदस्यों का वह जानती थी उनमें से ज्यादातर उनके साथ वफादारी से ज्यादा डर की वजह से थे। इस तरह सजय को भी राजनीतिक के मदान में अपने पाव जमान में मदद मिलनी क्योंकि तब उस अपने भरोसे के लोगों का सहारा रहेगा। युवक कांग्रेस ने खुदआम कहा कि उस उम्मीद है कि उसके 150 से 200 तक सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिये जायेंगे। अविभा सीनी ने कहा कि युवक कांग्रेस ही असली कांग्रेस है।

श्रीमती गांधी ने यह इशारा दिया कि उन्हें सारे उम्मीदवारों का चुनने की खुली छूट हानी चाहिए। एक एक करके सभी प्रदेश कांग्रेस कमिटियों ने और उनके

संसदीय बौद्धों ने एकमत होकर प्रस्ताव स्वीकृत कर दिये और प्रधानमंत्री को पूरा अधिकार दे दिया कि उनकी तरफ से वही उम्मीदवार चुन लें।

सजय ने फेहरिस्तें तैयार करना शुरू किया। जितने लोग उसकी चौखट पर था उन लोगों की चौखट पर आने लगे जिनकी उस तक पहुँच थी उतने प्रधानमंत्री की चौखट पर भी नहीं जाते थे। वह हर उम्मीदवार के बारे में यह पता लगाने के लिए कि अपने इलाके में उसका कितना असर है खुफिया विभागवालों से सलाह माँगकर करने लगा। इस तरह इन लोगों पर अपना शिकवा कैसे रखने के लिए उसे बहुत-सा मसाला भी मिल गया। संसद की 542 सीटों में से हर एक के लिए भीसतन दो-दो सौ उम्मीदवार थे।

सजय ने बसोबस की तैयारी की हुई हरियाणा के उम्मीदवारों की फेहरिस्त की छानबीन करके उसे अपनी मजबूरी दे दी। महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया। ऐसा लगता था कि सब-कुछ सजय की योजना के अनुसार ठीक-ठाक चल रहा है।

अचानक सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया। जगजीवनराम ने 2 फरवरी को कांग्रेस से और सरकार से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस में कोई भी इससे लिए तयार नहीं था।

तीन दिन पहले खुफिया विभागवालों ने भ्राम मेहता को इस अपवाह की खबर दी थी कि जगजीवनराम ब्याबस्त करने के मसूबे बना रहे हैं। लेकिन इस पर किसी न गम्भीरता से विचार नहीं किया। अभी एक ही दिन पहले तो जगजीवनराम प्रधानमंत्री से मिले थे और उस वक्त उन्होंने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया था। उन्होंने श्रीमती गांधी को बस इतना बताया था कि वह इमर्जेंसी लागू रखने के खिलाफ हैं। बाद में उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि अगर उन्होंने पार्टी छोड़ने के बारे में उनसे कुछ कहा होता तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। जिस दिन जगजीवनराम ने इस्तीफा दिया था, उसी दिन अपनी गोठी के लम्बे चौड़े लॉन में उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेम काँग्रेस में कहा कि वह चाहते थे कि सभी कांग्रेसी उनके साथ मिलकर इमर्जेंसी को और तानाशाही और निरकुशता की उन प्रवृत्तियों को खत्म करने के लिए उनका साथ दें 'जो इधर-उधर कुछ भ्रष्टे से धीरे धीरे देश की राजनीति में फैल हो गयी है।' उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन के अंदर सभी स्तर पर जनतांत्रिक ढंग से काम करने के तरीके में न सिर्फ अंतर ब्योरा कर दी गयी थी बल्कि उसे लगभग बिमबुल खत्म कर दिया गया था। 'काँग्रेस के संगठन बाल और संसदीय दोनों ही हिस्सों के अन्दर अनुशासनहीनता की न गिफ बंदास्त किया गया है बल्कि उस ऊपर से डकताया गया है और बर्बाद दिया गया है।'

जगजीवनराम के एक तरफ हमबती नन्दन बहुगुणा बैठे थे जिन्हें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया था और दूसरी तरफ नदिनी सरणी बठी थी, जिन्हें उड़ीसा के मुख्यमंत्री के पद से हटाने पर मजबूर कर दिया गया था। इन दोनों ने भी कांग्रेस छोड़ देने का ऐलान किया। नूतनपूर्व मंत्री के० धार० गणग० भी ऐसा ही ऐलान किया। इन सभी ने कहा 'हम नई कांग्रेस नहीं हैं। हम अब भी वही पुरानी कांग्रेस पार्टी हैं।' निसम्बर 1969 में जब श्रीमती गांधी और उनके गांधियों ने अपनी अलग कांग्रेस पार्टी बनायी थी उस बात उन्होंने भी समझना नहीं पाया था।

जब मैं जगजीवनराम से पूछा कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था तो उन्होंने जवाब दिया कि यह बहुत सी बातों का नतीजा था जो मिल-बढ़ गयीं थीं वे लोग

होती रही थी, उन सबका मिलकर यह नतीजा हुआ था। उन्होंने यह भी कहा, "मैं बहुत तनाव का शिकार था।" बहुत दिन से श्रीमती गांधी और उनका बेटा हर वह काम करते प्रायः थे जो उन्हें नापसंद था और वह उनका साथ नहीं देते रह सकते थे।

शायद यह सच हो लेकिन चन्द्रशेखर और बहुगुणा ने उन्हें यह कदम उठान पर राजी करने के लिए कई दिन खच किये थे। ऐसा लगता है कि दिल्ली में चुनाव के सिलसिले में जनता पार्टी की जो पहली मीटिंग हुई थी उससे उनकी यह राय पक्की हो गयी थी कि कई राज्यों में जनता कांग्रेस का तख्ता उलट देगी।

ग्रस्रबारो ने (लेकिन 'वफादार' ग्रस्रबारो ने नहीं) इस खबर को उछालने के लिए सप्लीमेंट निकाले, और कांग्रेसियों ने जगजीवनराम के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जो उनके साथ कांग्रेस छोड़कर चले गये थे, खूब कीचड़ उछाली।

कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने सबसे सम्मति से जगजीवनराम के कांग्रेस छोड़ देने की निंदा करते हुए प्रस्ताव पास किया। बरमा ने इसे 'एक भ्रातृभा' की गद्दारी कहा। श्रीमती गांधी ने कहा कि बड़ी भयानक बात है कि वह इतने महीनों तक चुप क्यों रहे। खबरें देनेवाले सरकारी माध्यमों ने, जिनमें 'समाचार' एजेंसी भी शामिल थी, उनके इस्तीफे को दल बदलने की हरकत कहा।

कांग्रेसी नेताओं ने यह जताने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही न हो। श्रीमती गांधी बहुत परेशान थी। बरसों से उनका यह तरीका रहा था कि ग्रचानक ग्रपों साधियों के सामने कोई फसला लाकर रख देती थी, इस बार जगजीवनराम ने उनको ऐसी चोट पहुँचायी थी कि वह भी उमर भर याद रखता। चुनाव का ऐलान करते वकन उन्हें यह तो भालूम था कि गैर-कम्युनिस्ट पार्टियाँ ग्रापस में गठजोड़ बना सकती हैं, लेकिन जगजीवनराम का इस तरह साथ छोड़कर चले जाना उनके लिए बहुत बड़ा ग्राघात था। उनकी पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी (सी० एफ० डी०) श्रीमती गांधी की पार्टी में से सभी ग्रस्रतुष्ट लोगों को खींचकर ले जा सकती थी और श्रीमती गांधी जानती थी कि उनकी ग्रपनी पार्टी में इस तरह के बहुत-से लोग थे।

उन्हें इस तरह की खबरें मिली थी कि उनकी पार्टी के बहुत-से लोग इमर्जेंसी के नाम पर जो कुछ हो रहा था और उनके बेटे और उनकी युवक कांग्रेस की धाँधली से बहुत नाखुश थे। डर की वजह से और कोई दूसरा मच न होने की वजह से ही वे अब तक कांग्रेस में बने हुए थे। श्रीमती गांधी को डर था कि जगजीवनराम के बाद अब और भी बहुत से लोग कांग्रेस छोड़कर चले जायेंगे। इस वकत जो भी ससद या विधानसभा का मेम्बर है उसे ग्रगर टिकट न दिया गया तो उसके लिए कांग्रेस छोड़ देने का यह काफी ग्रहाना होगा।

वह अब 'बूढ़े खूँसटों' से छुटकारा पाने की हिम्मत नहीं कर सकती थीं। उन्हें अब जाने पहचाने और परखे हुए लोगों का ही सहारा था। सजय गांधी ने ज फेहरिस्ते बनायी थी उन्हें रद्द कर देना पडा। जगजीवनराम के कांग्रेस छोड़ देने का पहला शिकार युवक कांग्रेस हुई। कांग्रेस के जितने लोग उस समय ससद या विधानसभा के मेम्बर थे उनमें से जगदातर को टिकट मिल गया। अब नारा यह बन गया था 'पुराने को पकड़े रहो!', 'एक भ्रातृभा बार-बार दोहराया जा रहा था कि इन सभी लोगों ने ग्रपन घरों पर जगजीवनराम की एब-एक तसबीर लगा ली थी जिसके सामने वे बड़ी ग्रदा से सर झुकते थे।

अब ग्रसरदार मेम्बरों को खुग रखने के लिए पूरा खोर सगाया जा रहा था ताकि वे पार्टी छोड़कर न चले जायें। जिस तरह सिद्धाथ बाबू ने, जो ग्रभी कुछ ही दिन पहले तक दुतकारे हुए लोगों में थे, फिर ग्रपना पासा पसट लिया, वह इसकी एक

कांग्रेस समझती थी कि उसकी लोकप्रियाय में जो कमी हुई है उसकी कसर उसके साधना से पूरी कर ली जायेगी। कांग्रेस खुद देख चुकी थी कि 1971 में किस तरह श्रीमती गांधी के 'गरीबी हटाओ' के नारे के खिलाफ थैलीशाही की एक नही चलने पायी थी। अब कांग्रेस के सामने इसका अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि वह जनता को अपनी ओर लाने के लिए पसा इस्तेमाल करे। पार्टी के खजांची पी० सी० सेठी ने नई दिल्ली में 2 कोशिश रोड पर अपना दफ्तर खोल लिया, जहाँ बदलकर गौहाटी भेजे जाने से पहले जस्टिस रगराजन रहते थे। सेठी ने हर उम्मीदवार को 1,00,000 रुपये के अलावा दो-दो जीपें दी।

उधर जनता पार्टी पैस की तगी की परवाह न करके और पार्टी की ओर से छपवाये गये चुनाव फंड के रूपों का सहारा लेकर चुनाव के मदान में बूढ़ पड़ी। सी० एफ० डी० की आवाज भी जनता पार्टी के साथ थी—जयप्रकाश ने उन दोनों का एक ही झंडे के नीचे और एक ही निशान पर साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए राजी कर लिया था।

जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना सैयद अब्दुल्ला बुखारी ने भी, जो मुसलमानों में बहुत लोकप्रिय थे, अपना पूरा जोर विपक्ष की ओर से लगा दिया।

लेकिन जिस बात से जनता-सी एफ० डी० का हौसला सबसे ज्यादा बड़ा वह 12 फरवरी को हुई जब नहरू की बहन और श्रीमती गांधी की बुम्मा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित भी अपनी भतीजी के खिलाफ जोर लगाने के लिए मैदान में उतर आयी। उन्होंने कहा "आजादी के वर्षों के दौरान हमने जितनी भी जनतांत्रिक समस्याएँ बनायी थी, उन सभी को एक एक करके कुचल दिया गया और नष्ट कर दिया गया। कानून के शासन की जड़ें ब्याखली कर दी गयी और अदालतों की आजादी खरम कर दी गयी। अवधारणों पर संश्लेषण लागू कर दी गयी।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वक्त का बुनियादी तकाजा यह है कि जनता की फिर से पटरी पर लाया जाये। "हमारे विरपोषित आदर्शों को खोखला करत जाने का यह सिलसिला बंद होना चाहिए और हमें एक बार उही आदर्शों पर वापस लौट जाना चाहिये जिनका पालन करने के लिए हम वचनबद्ध हैं।"

सब तो यह है कि इधर कुछ समय से श्रीमती गांधी और श्रीमती पंडित तथा उनके परिवार के सम्बन्ध धीरे धीरे बिगड़ते गये थे। अभी कुछ ही दिन पहले श्रीमती पंडित की बटी तारा ने मुझे बताया था 'कि एक जमाना था जब मामा के घर पर हमारे कुत्ते तक का स्वागत होता था, और अब हम लोगों का भी जाना गवारा नहीं किया जाता।'

श्रीमती गांधी को इन सब बातों से बहुत परेशानी हुई। हालाँकि खुफिया रिपोर्टों में अब भी यही कहा जाता था कि जीन कांग्रेस की ही होगी, लेकिन वह कितनी सीटें जीतती इसका अंदाजा अब बहुत पट गया था। इन रिपोर्टों में यह भी कहा गया था कि बुद्धिजीवी वर्ग इस बात से भी बहुत नाराज हो गया है कि हालाँकि बारी जस्टिस हसराम खन्ना को थी लेकिन उन्हें न बनाकर उनसे जूनियर जज जस्टिस एम० एच० वर्ग को तरक्की देकर भारत का चीफ जस्टिस बना दिया गया था। गोखले ने मुझे बताया कि उन्होंने श्रीमती गांधी को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि जस्टिस खन्ना का हक न मारें लेकिन वह नहीं मानी। जस्टिस खन्ना को इस बात की कीमत चुकानी पड़ी कि गीसा वाले मुकद्दमे में उन्होंने सरकार के खिलाफ अपना फसला दिया था।

चूँकि हवा का रस कांग्रेस के खिलाफ था इसलिए अफवाहें यह उठने

चुनाव टाल दिये जायेंगे। इन अफवाहों ने इतना जोर पकड़ा कि चुनावों की तारीखों का ऐलान करते हुए एक सूचना जारी करनी पड़ी। चुनाव 16 से 20 मार्च तक किये जान का फैसला किया गया था।

श्रीमती गांधी अब भी समझती थी कि कांग्रेस सीव-तानकर 280 सीटें जीत ही जायेगी, खुफिया विभागवालों की भी यही राय थी। लेकिन अब श्रीमती गांधी को खतरा दिखायी देने लगा था। अपने भाषणा में उन्होंने देश के लिए भीतरी और बाहरी खतरों का राय प्रसारण शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष के गिरोह एक बार फिर अस्थिरता की हालत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं—इस बात में एक बहुत ही खतरनाक यूज थी। उन्होंने इमर्जेंसी की घंटी में कहा कि उसकी बदौलत देश ने सभी क्षेत्रों में 'तरक्की की है'। लेकिन आम जनता के बिफरे हुए तेवर और अपनी मोटियों में बहुत थोड़े लोगों को देखकर उन्होंने सफाई देने का रवैया अपनाया "इसमें शक नहीं कि कभी कभी गलतियाँ की गयी हैं और इसके लिए हमने उन अफसरो को मुफ्तिल कर दिया है जो इन ज्यादतियों के लिए जिम्मेदार थे।"

एक गलती नहीं थी, गलतियों का एक पूरा सिलसिला था। अब उन पर से लोगों का भरोसा उठ चुका था। नीचेत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि जब दिस का दौरा पहले से 11 फरवरी, 1977 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मौत हो गयी, तो चारों तरफ यह अफवाह फैल गयी कि श्रीमती गांधी रात को दो बजे राष्ट्रपति भवन गयी थी और उन्होंने राष्ट्रपति पर दबाव डाला था कि वह इस प्रॉब्लिम पर दस्तावेज कर दें कि मौसा के नज़रबन्दों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा और इसी बज़ह से उनको दिन का वह दौरा पड़ा था जिसने उनकी जान ले ली। मैंने इसके बारे में बेगम अहमद से पूछा तो उन्होंने बताया कि उस रात श्रीमती गांधी राष्ट्रपति भवन आयी ही नहीं थीं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए तैनात मिशपोरिटीवालों ने भी यही कहा। लेकिन उस रात श्रीमती गांधी ने राष्ट्रपति अहमद को टेलीफोन उल्लूक किया था। श्रीमती गांधी ने भी किसी तरह के उक्तावे के बिना ही इस बात से इफ़ार किया कि उनके और राष्ट्रपति के बीच कोई मतभेद थे।

उन पर से लोगों का भरोसा उठ जाना तो बुरी बात थी ही, लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि लोगों के मन में यह बात बैठ गयी थी कि वह सत्य को प्रधान-मंत्री बनाना चाहती थी। वह कहती तो यही थी कि उसकी कोई 'राजनीतिक समझना' नहीं है लेकिन लोग कुछ और ही समझते थे। जब उन्होंने रायबरेली में अपनी सीट से मिली हुई घमेठी की मोट से सत्य का वापस का उम्मीदवार बना दिया तो लोगों का यह शक और पक्का हो गया। इस तरह उनके रिक्सा 'डिस्टेंटर' या जनतंत्र के नाम के साथ ही एक गारा और जुड़ गया 'मुनबागाही या जनतंत्र'।

दरअसल, चुनाव की पूरी मूहिम ने दोगन श्रीमती गांधी को निरङ्कुश का घातक का सामना करना पड़ा। पहले तो उन्होंने इस दलजाम को सुनकर भी घबराहट नहीं की, लेकिन जब इसी बात को बार बार दोहराया जाने लगा तो उन्होंने कहा कि "कांग्रेस कभी भी एक घाटी के बल पर अमानवासी पायी नहीं रही है। उन्होंने कहा 'मैं अपने प्रापको जाना की गबन बड़ी तेबिया के मसाला और कुछ भी नहीं समझती हूँ।' लेकिन निरङ्कुश का घातक तो उन पर बिगड़ गया और बिगड़ लगातार इसी एक बात पर घोर देता रहा। वह कहती थी कि बिगड़ के पाम मिस एन्-मूवी कार्य कम है मुझे हज़रत का। यही बात उन्होंने 1971 के चुनाव के वक़्त भी कही थी और लोकगण म दो निहाई बख़्श पा दिया था। लेकिन अब उनकी ग़ाम बिगड़ुम उठ चुकी थी और धार्मिक संघ में भी उफ़ा बाग़नामा कुछ दमगे बेहतर नहीं था।

कांग्रेस के 500 शब्द के मनिफेस्टो में, जिसे श्रीमती गांधी ने खुद जारी किया था, कहा गया था कि कांग्रेस की मजिल समाजवाद है और 'गरीबी, असमानता और सामाजिक भ्रष्टाचार के खिलाफ वह अपनी सहाई और तेज करेगी'।

जनता पार्टी के मनिफेस्टो में खास जोर इस बात पर दिया गया था कि भ्रष्टाचार का डंका नये सिरे से बजाने के लिए वह गांधीवादी सिद्धान्तों और नीतियों का सहारा लेगी ताकि ध्यान खेती-बाड़ी की प्रगति, बेरोजगारी को दूर करने और राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति के एक ही जगह सिमटने न देने पर केन्द्रित रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मनिफेस्टो में कहा गया था कि पार्टी आर्थिक विकास के लिए टिकाऊ परिस्थितियाँ पैदा करने के लिए जनता की रक्षा करेगी और उसे बढ़ायेगी। सी० एफ० डी० ने कहा कि वह पब्लिक सेक्टर को 'सबसे ऊँचा स्थान देने, और इजारेदार घरानों पर प्रभुता सगाने सभी जरूरी चीजों ग्राम आदमी की पहुँच के अन्दर बँधी हुई और स्थिर कीमतों पर दिलाने का प्रयत्न करेगा, उद्योगों की हर समस्या के काम में मजदूरों को उसमें पूरी तरह भाग लेने का अवसर देने और कम से कम समय में भूमि-सुधार लागू करने आदि के पक्ष में है।

लेकिन चुनाव की मोटियों में किसी भी मनिफेस्टो पर विचार ही कम हुआ। पार्टियाँ उनका हवाला भी नहीं-बभार ही देती थी। सिर्फ दो ही नारों की गूँज सुनायी देती थी। विपक्ष कहता था कि हमें दो रास्तों में से एक को चुनना है 'डिक्टेटरशिप या जनतन्त्र', कांग्रेस का भी नारा यही था कि जनतन्त्र या भ्रष्टाकरता।

दोनों पक्ष एक दूसरे पर जाती हमले भी करते थे। श्रीमती गांधी ने कहा कि विपक्ष 'मुझे घेरकर मेरे छुरा भोक्ता चाहता है।' मोरारजी ने जवाब दिया, "छुरा तो हमारे भी भोक्ता गया है।" जगजीवनराम ने कहा कि कांग्रेस में और सरकार में काम करने के जनतांत्रिक ढंग में बतल-ब्योत की गयी। बह्मण ने जवाबी बार किया कि कुछ नेता ऐसे हैं जो ग्राम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते हैं, ऐसे लोग इसी लायक हैं कि उनको नजरबन्दा कर दिया जाये।

भापस की इस तू-तू में मे के बातावरण में आर्थिक समस्याएँ, या सच पूछा जाये तो दूसरी सभी समस्याएँ पीछे ढकेल दी गयी। चुनाव का प्रचार चाहे जिस ढंग का रहा हो लेकिन ऐसा लगता था कि देश में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर दो ही उम्मीदवारों की टक्कर थी—एक कांग्रेस का, दूसरा विपक्ष का। कांग्रेस ने 492 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और बाकी 50 सीटें अपने समयकों के लिए छोड़ दी थी—केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तमिलनाडु में अन्ना डी० एम० के०। जनता पार्टी ने 391 उम्मीदवार अपने खड़े किये थे और 147 सीटें सी० एफ० डी०, माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और पंजाब में भकाली दल तथा तमिलनाडु में डी० एम० के० के लिए छोड़ दी थी।

1967 के चुनाव में कांग्रेस को 40.7 प्रतिशत वोट मिले थे और उसने 283 सीटें जीती थी। 1971 में सिर्फ 3 प्रतिशत बढ़ जाने से, 43.6 प्रतिशत वोटों पर कांग्रेस को 350 सीटें मिल गयी, लोकसभा में दो तिहाई का बहुमत। इस बार विपक्ष को उम्मीद थी कि वह ये वोट अपनी तरफ खींच लायेगा और कांग्रेस का हरा देगा।

सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बार कोई इंदिरा लहर नहीं थी। सच तो यह है कि इस बार लहर उलटी ही थी। जून 1975 में इमर्जेंसी लागू होने के बाद जो दमनचक्र चलाया गया था उसका सरकार बदनाम हो गयी थी। गाँवों में लोग 'रोटी भी और आजादी भी' और 'आजादी से पहले रोटी के बारीक अंतर को भले ही न

चुनाव टाल दिये जायेंगे। इन अपवाहों ने इतना डोर पकड़ा कि चुनावों की तारीखों का ऐलान करते हुए एक सूचना जारी करनी पड़ी। चुनाव 16 से 20 मार्च तक किये जान का फैसला किया गया था।

श्रीमती गांधी अब भी समझती थी कि कांग्रेस खीच-तानकर 280 सीटें जीत ही जायेगी, खुफिया विभागवालों की भी यही राय थी। लेकिन अब श्रीमती गांधी खतरा दिखायी देने लगा था। अपने भाषणों में उन्होंने देश के लिए भीतरी घोर बाहरी खतरों का राग प्रलापना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष के गिरौह एक बार फिर अस्थिरता की हालत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं—इस बात में एक बहुत ही खतरनाक गूँज थी। उन्होंने इमजेंसी की परीची में कहा कि उसकी बदौलत देश ने सभी क्षेत्रों में 'तरक्की की है'। लेकिन ग्राम जनता के बिफरे हुए तैवर और अपनी मीटिंगों में बहुत थोड़े लोगों की देखकर उन्होंने सफाई देने का रवैया अपनाया "इसमें शक नहीं कि कभी कभी गलतियाँ की गयी हैं और इसके लिए हमने उन प्रफसरो को मुआतिर कर दिया है जो इन ज्यादतियों के लिए जिम्मेदार थे।"

एक गलती नहीं थी, गलतियों का एक पूरा सिलसिला था। अब उन पर से लोभों का भरोसा उठ चुका था। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि जब दिल का दौरा पड़ने से 11 फरवरी 1977 को राष्ट्रपति फख्रुद्दीन अली अहमद की मौत हो गयी, तो चारों तरफ यह अपवाह फैल गयी कि श्रीमती गांधी रात को दो बजे राष्ट्रपति भवन गयी थीं और उन्होंने राष्ट्रपति पर दबाव डाला था कि वह इस प्रॉट्रिजेंस पर दस्तखत कर दें कि मीसा के नज़रबन्दी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा और इसी बजह से उनकी दिल का वह दौरा पड़ा था जिसने उनकी जान ले ली। मैंने इसके बारे में बेगम अहमद से पूछा तो उन्होंने बताया कि उस रात श्रीमती गांधी राष्ट्रपति भवन आयी ही नहीं थीं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए सैनिक निक्योरिटीवालों ने भी यही कहा। लेकिन उस रात श्रीमती गांधी ने राष्ट्रपति अहमद को टेसीफोन उद्धर किया था। श्रीमती गांधी ने भी किसी तरह के उबसावे के बिना ही इस बात से इन्कार किया कि उनके और राष्ट्रपति के बीच कोई मतभेद थे।

उन पर से लोभों का भरोसा उठ जाना तो सुरी बात थी ही, लेकिन इससे भी सुरी बात यह थी कि लोगों के मन में यह बात बैठ गयी थी कि वह सज्ज को प्रधान मंत्री बनाना चाहती थी। वह कहती तो यही थी कि उसकी कोई 'राजनीतिक' तमन्ना नहीं है लेकिन लोग कुछ और ही समझते थे। जब उन्होंने रायचरेली में अपनी सीट से मिली हुई घमेठी की गोट से सज्ज को कांग्रेस का उम्मीदवार बना दिया तो लोगों का यह शक और पक्का हो गया। इस तरह उनके खिलाफ 'डिस्टेंटरिण' या जनतन्त्र के नारे के साथ ही एक नारा और जुड़ गया 'हुनबागाही या जनतन्त्र'।

दरमसत, चुनाव की पूरी मुहिम के दौरान श्रीमती गांधी को निरङ्कुशता के आरोप का सामना करना पड़ा। पहले तो उन्होंने इस इन्जाम को सुनकर भी मनमुताबक न किया, लेकिन जब इसी बात को बार बार दोहराया जान लगा तो उन्होंने कहा कि "बापस बभी भी एक आदमी के बल पर चलनेवाली पार्टी नहीं रही है। उन्होंने कहा, 'मैं अपने धायको जनता की सज्ज बभी सेविका के असाडा और कुछ भी नहीं समझती हूँ।' लेकिन निरङ्कुशता का आरोप तो उन पर चिपका गया और बिपण लगातार इसी एव बात पर जोर देता रहा। वह कहती थी कि बिपण के पास मिय एव-मुत्री काय कम है मुझे हटाने का। यही बात उन्होंने 1971 के चुनाव के पक्ष भी करी थी और सोचमभा में का निर्धार बहमन का किया था। लेकिन अब उसी नाम बिमहुम उठ चुकी थी और पारिव लोक में भी उसका बारनामा कुछ इन्तरे बहरन नहीं था।

कांग्रेस के 500 शब्द के मैनफेस्टो में, जिसे श्रीमती गांधी ने खुद जारी किया था, कहा गया था कि कांग्रेस की मजिल समाजवाद है और 'गरीबी, असमानता और सामाजिक अन्धकार के खिलाफ वह अपनी लड़ाई और तेज कर देगी।

जनता पार्टी के मैनफेस्टो में खास जोर इस बात पर दिया गया था कि ग्राम-न-त्र का ढाँचा नये सिरे से बनाने के लिए वह गांधीवादी सिद्धान्तों और नीतियों का सहारा लेगी ताकि ध्यान खेती-बाड़ी की प्रगति, बेरोजगारी को दूर करने और राज-नीतिक तथा आर्थिक शक्ति के एक ही जगह सिमटने न देने पर केंद्रित रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मैनफेस्टो में कहा गया था कि पार्टी आर्थिक विकास के लिए टिकाऊ परिस्थितियाँ पैदा करने के लिए जनता-त्र की रक्षा करेगी और उसे बढ़ायेगी। सी० एफ० डी० ने कहा कि वह पब्लिक सेक्टर को 'सबसे ऊँचा स्थान' देने, और हजारेदार घरानों पर प्रकुश लगाने, सभी जरूरी चीजें ग्राम-भादमी की पहुँच के अन्दर बँधी हुई और स्थिर कीमतों पर दिलाने का प्रबन्ध करने, उद्योगों की हर अवस्था के काम में मजदूरों को उसमें पूरी तरह भाग लेने का अवसर देने और कम से कम समय में भूमि-सुधार लागू करने आदि के पक्ष में है।

लेकिन चुनाव की मीटिंगों में किसी भी मैनफेस्टो पर विचार ही कब हुआ। पार्टियाँ उनका हवाला भी कभी-कभार ही देती थी। सिर्फ दो ही नारों की गूँज सुनायी देती थी। विपक्ष कहता था कि हमें दो रास्तों में से एक को चुनना है 'डिक्टेटरशिप या जनता-त्र', कांग्रेस का भी नारा यही था कि 'जनता-त्र या भ्रारजकता'।

दोनों पक्ष एक-दूसरे पर जाती हमले भी करते थे। श्रीमती गांधी ने कहा कि विपक्ष 'मुझे घेरकर मेरे छुरा भोकना चाहता है।' मोरारजी ने जवाब दिया, "छुरा तो हमारे भी भाँका गया है।" जगजीवनराम ने कहा कि कांग्रेस ने और सरकार ने काम करने के जनता-त्रिब ढग में बत्तर-ब्यात की गयी। चह्णान ने जवाबी वार किया कि कुछ नेता ऐसे हैं जो ग्राम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते हैं, ऐसे लोग इसी लायक हैं कि उनको नजरबन्दा कर दिया जाये।

भापस की इस तू-सू में-में के वातावरण में आर्थिक समस्याएँ या सच पूछा जाये तो दूसरी सभी समस्याएँ पीछे ढकेल दी गयी। चुनाव का प्रचार चाहे जिस ढग का रहा हो, लेकिन ऐसा लगता था कि देश में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर दो ही उम्मीदवारों की टक्कर थी—एक कांग्रेस का, दूसरा विपक्ष का। कांग्रेस ने 492 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और बाकी 50 सीटें अपने समर्थकों के लिए छोड़ दी थी—बैरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और तमिलनाडु में अना डी० एम० के०। जनता पार्टी ने 391 उम्मीदवार अपने खड़े किये थे और 147 सीटें सी० एफ० डी०, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और पंजाब में भकाली दल तथा तमिलनाडु में डी० एम० के० के लिए छोड़ दी थी।

1967 के चुनाव में कांग्रेस को 407 प्रतिशत वोट मिले थे और उसने 283 सीटें जीती थी। 1971 में सिर्फ 3 प्रतिशत बढ़ जाने से, 436 प्रतिशत वोटों पर कांग्रेस को 350 सीटें मिल गयी, लोकसभा में दो तिहाई का बहुमत। इस बार विपक्ष को उम्मीद थी कि वह भी वोट अपनी तरफ खींच लायेगा और कांग्रेस का हरा देगा।

सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बार कोई इन्दिरा सहर नहीं थी। सच तो यह है कि इस बार सहर उलटी ही थी। जून 1975 में इमर्जेंसी लागू होने के बाद जो दमनपत्र चलाया गया था उसमें सरकार बदनाम हो गयी थी। गाँवाँ मालाग 'रोटी भी और भाँजादी भी और भाँजादी से पहले रोटी' के बारीक अंतर को भूल ही न

समझते हो लेकिन जिस तरह से सरकार के कुछ कार्यक्रम, खास तौर पर नसबन्दी का कार्यक्रम, चलाये गये थे उससे वह नाराज थी। देहान्तो में पुलिस ने डण्डे का इस्तेमाल ज़रूरत से ज्यादा बार और ज़रूरत से ज्यादा अघाघुष तरीके से किया था। गृह मंत्रालय में जो ख़ुफ़िया रिपोर्टें आती थीं उनमें कहा गया था कि पुलिस के छोटे आफसर गांववालों को यह धमकी देकर उनसे पैसा ऐंठ रहे थे कि अगर वे पैसा नहीं देंगे तो उन्हें मीसा में पकड़ लिया जायेगा। सैकड़ों गांवों के जिन रहनेवालों ने नसबन्दी करनेवालों से बचने के लिए पुलिस को भी 'खरीद लिया' था। उन्होंने पकड़े जाने से बचने के लिए पुलिस को भी मुहिम शुरू करते वक़्त लोगो के श्रीमती गांधी ने दिल्ली में चुनाव प्रचार की मुहिम शुरू करते वक़्त लोगो के मन से इस गलतफ़हमी को दूर कर देने की कोशिश की थी। उन्होंने यह बात मान ली थी कि उनकी सरकार ने नसबन्दी के कार्यक्रम को पूरा करने और लोगो को गंदी बस्तियों से हटाकर नयी जगहों में ले जाकर बसा देने के सिलसिले में गलतियाँ की थीं। लेकिन इसके जवाब में लोग बड़े तिरस्कार के साथ हंस दिये और और मचाने लगे।

ऐसा लगता था कि अब उनकी बात का कोई मान नहीं रह गया है। यह सच है कि उन्होंने लगभग एक महीने तक एक एक दिन में बीस बीस मीटिंगों में भाषण दिये लेकिन असर बहुत कम हुआ।

मैं इलाहाबाद जिले के फूलपुर इलाके में उनके चुनाव प्रचार की खबरें भेजने के लिए गया था। प्रधानमंत्री हेल्थकोण्टर से प्राणी। 1974 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों के दौरान इसी जगह उन्होंने जिस मीटिंग में भाषण दिया था उसके मुक़ाबले में इस बार सुननेवालों की भीड़ बहुत कम थी। जाहिर है कि मीटिंग का बंदोबस्त करनेवालों का इससे ज्यादा लोगो के ध्यान की उम्मीद थी क्योंकि उन्होंने वहाँ से 40 किलोमीटर दूर इलाहाबाद तरफ़ से और पास पास के इलाकों से लोगो को मीटिंग में लाने के लिए बसों वगैरह का पूरा प्रबंध किया था। लेकिन मैदान के बहुत से हिस्से, जिन्हें चारों ओर बलियाँ लगाकर घेर दिया गया था, खाली पड़े थे और पन्द्रह मीटर ऊँचे भव पर से जो नारे दिये जाते थे उनका जवाब भी बहुत कमजोर आवाज़ में मिलता था।

अपन पन्द्रह मिनट के भाषण में श्रीमती गांधी ने बीच बीच में बहुत सी निजी बातों का हवाला दिया। उन्होंने कहा, 'मेरे परिवार के हम लोगों का कुर्बानियों का इतिहास बहुत सम्बा है। मेरे दादा ने एक मकान बनवाया था स्वराज्य भवन, जो मेरे बाप ने दण्ड को भेंट कर दिया। फिर हम लोगों ने एक और मकान बनवाया, जो भानुद भवन, जिसे मैंने जनता के नाम समर्पित कर दिया। हम लोगों का अर्थन लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ लोग हमारा विरोध भी करें, तब भी हम देश की सेवा करते रहना चाहते हैं। हमारा परिवार आगे भी ऐसा ही करता रहगा।' 'ऐम

श्रीमती गांधी ने जो एक और बात निजी ढंग से कही वह यह थी कि 'ऐम लोगो को मतदम भेजिय जा मेरा साथ दें, न कि मेरी पीठ में छुरा भाँकें।' प्रधानमंत्री ने इस बात का एक बार फिर दोहराया कि उन पर टिकटटर होने का आरोप मज़बूत बर निषानन के लिए लगाया जाना है। क्योंकि अगर मैं टिकटटर होनी तो न मैं चुनाव हार और न विपक्ष के लोगों का भी भीड़ तब तक यही रहती मिमना जाये इन दिनों यह रह है।

श्रीमती गांधी का भाषण गलत हो जान के बाद भी भीड़ तब तक यही रह रही जब तक कि उनका हेल्थकोण्टर उड़ नहीं गया, देश के उन भाग में वह एक मकान

चीज थी।

इससे ज्यादा लोग तो जनता पार्टी के या सी० एफ० डी० के स्थानीय नेताओं का भाषण सुनने के लिए जमा हो जाते थे। लोग उन्हें सुनने के लिए घंटों आधी आधी रात तक इंतजार करते थे। अगर ये नेता देर से भी आते थे तो लोग बुरा नहीं मानते थे, दूसरी ओरिणें चलती रहनी थी और मोटर से, रल से आन-जान में कही न कही देर हो ही जाती थी। विपक्ष का समयन करनेवाले रातों रात न जाने कितने सगठन खड़े हो गये, बालटियरो और चंदे के लिए जो अपीलें की गयी उनका लोगो ने तुरन्त मन मन धन से जवाब दिया। कम से-कम सिधु गंगा के मैदान में तो जो वातावरण था उससे आजादी से पहले के दिनों की याद ताजा हो जाती थी। उन दिनों जो कुछ कांग्रेस कह देती थी उसे जोश के साथ पूरा किया जाता था, अब लोग जनता पार्टी की सलू-कार पर कुछ भी करने को तैयार थे।

कम से कम उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो यह हाल था कि जनता पार्टी ने जिसे भी खड़ा कर दिया उसे जीता हुआ ही समझिये। मजाक में कहा जाता था कि जनता पार्टी अगर खम्भे को भी खड़ा कर दे तो वह भी जीत जायेगा। उम्मीदवार के क्या गुण हैं, वह कितना लोकप्रिय है इससे कोई भ्रतर नहीं पड़ता था, असल सवाल यह होता था कि उम्मीदवार जनता पार्टी और उसके साथियों का है या नहीं।

जनता लहर जब ही जोर पकड़ गयी। उन्नीस महीने के निरंकुश शासन पर आम लोगो में जो गुस्सा था उसकी वजह से उनका हरावा और पक्का हो गया था। सरकार के नेताओं ने कितनी ही बार इस बात का माना कि कुछ गलतियां हो गयी हैं फिर भी लोगो का गुस्सा शांत नहीं हुआ। ऐसा जगता है कि चुनाव का ऐलान होने से पहले ही वे तय कर चुके थे कि वोट किने दना है।

विपक्ष के नेताओं ने जनता को यह बताकर कि जेल में उन लोगो ने असल अलग और पूरे देश ने मिलकर इमर्जेंसी के दौरान क्या-क्या मुसीबतें भेली हैं उनका गुस्सा और भड़का दिया। जबरी नसबन्दी, गंदी वस्तियों की सफाई और जार-जुलम की कितनी ही घटनाएँ रोज सामने आने लगी। जो अखबार आम तौर पर सरकार और इमर्जेंसी की तरफ से बोलने लगे थे अब एक दूसरे से होड़ लगाकर इमर्जेंसी के दौरान की भयानक घटनाओं को उछाल रहे थे। लोग इस बात का पक्का बंदोबस्त कर देना चाहते थे कि 'व भयानक दिन फिर लौटकर न आने पायें और ऐसा कांग्रेस को हराकर ही किया जा सकता था।

खुफिया विभागवाले और सरकारी नौकर पहले विपक्ष से इसलिए कतराते थे कि वह कांग्रेस को हराकर उसकी जगह नहीं ले सकता था लेकिन अब यही लोग सोलह आने कांग्रेस के खिलाफ हो गये। इस दलील में कोई दम नहीं रह गया था कि विपक्ष अब पंचमेल जमघट है। शासक पार्टी ने जा स्थायित्व दिया था उसके मुकाबले में वे अस्थायित्व की भी पसंद करने को तैयार थे। इस घुटन में और आजादी न रह जाने पर केवल मशीनी आदमी ही पदा हो सकते थे। और वे मशीनें बनने को तैयार नहीं थे।

सबसे अधिक कांग्रेस का बहुत बुरा हाल था। महल'स मुख्यमंत्रियों को सन्देश भेजा गया कि वे आम जनता को अपनी ओर लाने के लिए तरह तरह की रिमायतों का ऐलान करें। मुख्यमंत्री तो तिवोरियों का मुह खोले ही बैठे थे, ज्यादातर राज्य भी भी रिजव बन से बज लेकर अपना काम चला रहे थे। राज्यों की सरकारों ने तरह तरह से 2 अरब 50 करोड़ रुपये बाँट दिया—लगान और खेती की आमदनी पर इनकम-

टैक्स कम कर दिया गया, सिंचाई कर घटा दिया गया, बिजली की दर में कटौती हुई, मकान के किराये में छूट दी गयी, और महगाई मत्ता और किराया बढ़ा दिया गया, दवा दारू की बेहतर सुविधाएँ दी गयी।

सगता है कि इन रिआयतों का कोई असर नहीं हुआ। खुफिया रिपोर्टों से पता चलता था कि विपक्ष के हाथ में इमर्जेंसी सबसे बड़ा तुरूप का पता था। चुनाव से कुछ दिन पहले श्रीमती गांधी ने इस बात पर विचार करने के लिए कैबिनेट की मीटिंग की कि अगर इमर्जेंसी उठा ली जाये तो उससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान। ग्राम राम इसके खिलाफ थी। उसे हटाने का मतलब विपक्ष की जीत भी सम्भवी जा सकती थी। बहरहाल, कई लोगों की राय थी अगर उसे उठा भी लिया जाये तो अब इस कदम का फायदा उठाने के लिए समय ही कहा रह गया था।

लोगों को सिर्फ इमर्जेंसी से नफरत रही हो, ऐसी बात नहीं थी, इससे भी ज्यादा नफरत उन्हें सज्ज से थी, बसोबस से थी और कई मामलों में खुद श्रीमती गांधी से थी। वह निराश तो बहुत थी पर अभी हार मानने को तैयार नहीं थी।

ब्यादातर लोग यह समझते थे, और अखबारवाले उनसे भलग नहीं थे, कि चुनाव में बहुत काटे की टक्कर रहेगी, श्रीमती गांधी का पलड़ा विपक्ष के मुकाबले में कुछ भारी रहेगा। यह बात तो कोई सोच भी मुश्किल से ही सकता था कि नेहरू की बेटी, या कांग्रेस हार जायेगी, जिसके हाथ में आजादी के बाद से सत्ता की बागडोर रही थी।

पश्चिमी देशों में यही ग्राम राम थी। स्कडोनेविया के छोटे छोटे देशों को तो अब भी उम्मीद थी कि भारत की जनता एक बार फिर जनतंत्र में अपनी भास्वा का सबूत देगी लेकिन बड़े बड़े देशों श्रीमती गांधी के पक्ष में थे। एक वक्त ऐसा था जब पश्चिमी जर्मनी ने भारत को चेतावनी दी थी कि अगर एक भी जर्मन सबाददाता नई दिल्ली से निकाला गया तो भारत को मदद देना बंद कर दिया जायेगा। अब पश्चिमी जर्मनी का रबैया दूसरा ही था, नई दिल्ली में उसके राजदूत को पूरा यकीन था कि भारत के लिए श्रीमती गांधी से अच्छा नेता कोई दूसरा हो नहीं सकता। आपस की बातचीत में वह दलील यह देते थे कि अगर सभी पश्चिमी देश श्रीमती गांधी के खिलाफ हो जायेंगे तो वह सोवियत संघ की तरफ चली जायेंगी।

श्रीमती गांधी ने जिस दिन से अमरीकी राजदूत विलियम सक्सबी के निजी द्विंदर में अपने का निमंत्रण स्वीकार किया था उस दिन से वह पूरी तरह से उनके पक्ष में हो गये थे। उन्होंने अपनी सरकार को बताया कि भारत को घोर उपलब्ध के रास्ते पर जाने से अगर कोई रोके हुए है तो वह श्रीमती गांधी ही हैं। अमरीकी राजदूत की सज्ज से भी बड़ी दोस्ती थी, जो व्यापार और कारोबार की खुली छूट के पक्ष में था। मार्शल और अमरीकी कम्पनी इंटरोशनल हवाईस्टर के बीच सहयोग की बात सक्सबी ने ही पक्की करायी थी।

बड़े देशों में सोवियत संघ ही भकेला ऐसा देश था जिसे श्रीमती गांधी के जीतने की बहुत उम्मीद नहीं थी। रूसी अफसरों ने मास्को में भारत के दूतावास को बताया था कि हवा का रब उनके पक्ष में नहीं मालूम होता। उन लोगों को इस बात से बड़ी चिन्ता थी।

चुनाव के पूरे प्रचार व दौरान कोई सास घटना नहीं हुई। बस एक दिन समाचार ने राखी रात के बहुत बाद, जब अखबारवाले खबर के बारे में कोई छानबीन भी नहीं कर सकते थे, यह खबर दी कि सज्ज पर उसके मतदान क्षेत्र प्रमेठी में गोली चलायी गयी पर उस चोट नहीं आयी। जयप्रकाश समेत सभी नेताओं ने इस घटना की निन्दा की हालाँकि उनमें से कुछ को यह तब जरूर था कि वहाँ यह वोटों

की हमदर्दी हासिल करने का हथकंडा तो नहीं है।

श्रीमती गांधी 18 मार्च को लौटकर नई दिल्ली आयी। उस वक्त तक ज्यादातर जगह वोट पड चुके थे। आसार अच्छे नहीं दिखायी दे रहे थे। उनके घर पर दो मोटियों हुई—एक 18 को और दूसरी 19 को। इनमें सजय, धवन, बसिलाल और मोम मेहता मौजूद थे। बड़े अफसरा में गढ़ मन्त्रालय के सेनेटरी और दिल्ली के इस्पेक्टर-जनरल पुलिस मौजूद थे। इन लोगों को बताया गया कि प्रधानमंत्री की कोठी की 'हंग कीमत पर हिफाजत' करनी होगी।

उनको यह भी हिदायत दी गयी कि कोठी की रक्षा करने के लिए उधर से गुजरनेवाली सारी सड़कों की नाकेबंदी कर देनी होगी और जरूरत पड़ने पर 'कारवाई करने और हिफाजत करने' के लिए बॉर्डर सिन्धोरिटी फोर्स के जवान तैनात रहेंगे। 'रौ' के पास इस्तेमाल के लिए जो ए० एन० 12 रूसी हवाई जहाज थे उन पर अलग अलग के दो स दस बटालियन (6000 सिपाही) पहले ही लाये जा चुके थे।

इस्पेक्टर जनरल पुलिस न फिर अपने यहाँ के अफसरों को इस हुकम के बारे में बताने के लिए उनकी एक मीटिंग की। एक डी० आई० जी० ने पूछा कि हर कीमत पर हिफाजत करने का क्या मतलब है? आई० जी० ने कहा कि इसका सीधा सादा मतलब है 'हर कीमत पर', जरूरत पड़ी तो लोगों को गोली स उड़ानी देना होगा। डी० आई० जी० ने अपना यह डर उनसे जाहिर किया कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि अगर ऐसी जरूरत पड़ ही गयी तो उनके आदमी जनता पर गोली चलायेंगे।

यह अफवाह भी जारी पर थी कि श्रीमती गांधी यह भी सोच रही थी कि अगर चुनाव में फसला उनके खिलाफ हुआ तो वह मासल लॉ लागू कर देंगी—पहले बॉर्डर सिन्धोरिटी फोर्स की मदद से और फिर तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापतियों की मदद से। कानून मन्त्रालय ने कहा था कि फौज को बुलाय बिना भी मासल ला लागू किया जा सकता है। इस बात का कभी पक्का पता नहीं लग सका और शायद पक्का पता लगना मुमकिन भी नहीं था।

लेकिन यह सच है कि मार्च के शुरू में दिल्ली में सेना के कमांडरो और नौ सेना के सबसे ऊँचे अफसरों की कॉन्फ्रेंस हुई थी। फौज के खुफिया विभाग के सबसे बड़े अफसर मन सिंह की हटाकर उनकी जगह टी० एन० कौल के भाई हृदयनारायण कौल का तैनात कर दिया गया था।

रोटरी क्लब की एक मीटिंग में थल सेना के प्रधान सेनापति जनरल टी० एन० रना ने जब यह बात कही कि सेना का राजनीति से कोई मतलब नहीं है तो इस

1. अमरीकी प्रतिष्ठा नेशन ने अपने कई अफसरों को लिखा था कि 5 और 7 मार्च के बीच गोखले ने अपने मन्त्रालय में चुनावों को टलवा देने के लिए संविधान का सहारा लेने का कोई कानूनी पतरा बूझ निवासन के मिनसिंस में काफी भर खपाया था। नेशन के अनुसार लगभग इसी समय श्रीमती गांधी कुछ मतदान खतों में प्रीज तनात कर देने के बारे में रना के विचार मान्य करों की कोशिश कर रही थीं, इस बुनियाद पर कि उन इलाकों में सावजनिक सुधारवादी बनाये रखन के लिए यह जरूरी था। कहा जाता है कि रना ने ऐसा करने से इकार कर दिया था। इस पर उन्हें कैबिनेट की ओर से हुकम दिया गया कि उनमें जसा कहा गया उससे मुनाबिज अपनी प्रीज तनात करे। रना ने इस हुकम को गुरा करने का दिखावा तो किया लेकिन उदाव जा कुछ किया उसमें श्रीमती गांधी का काम नही बना।

मैन 27 मार्च को गांधीन स पूछा कि चुनाव टलवान के लिए सरकार खान वाली बात कहा तक सच है। उन्होंने कहा इसमें कोई सबां नही है।

अपवाह पर लोगो को और ज्यादा यकीन हो गया कि श्रीमती गांधी ने उनसे कहा था कि वह 'उह शासन करने में मदद दें' लेकिन उ होन इकार कर दिया था।

श्रीमती गांधी को चिंता इस बात की नहीं थी कि चुनाव व नतीजे निकलने के बाद कोई दया या उपद्रव भड़क उठेगा। न उ ह इस बात का डर था कि अगर कांग्रेस हार गयी तो लोग उनकी कोठी के सामन जुलूम लाकर नारे लगायेंगे। उनके दिमाग में कुछ और ही बात थी।

वह समझती थी कि उह 542 में से 200 में 220 तक सीटें मिल जायेंगी और उह उम्मीद थी कि कुछ लोगो को वह खरीद लेंगी। वह समझती थी कि कायवाहक राष्ट्रपति बी० डी० जत्ती की मदद में, जो खुलेआम श्रीमती गांधी का राजनीतिक आभार मानते थे वह सरकार बना लेंगी। शासन की बागडोर उ ही के हाथों में रहनी होगी और अगर सरकार बनाने की उनकी योजना का विरोध किया गया तो शायद साकत का सहारा लेना जरूरी हो जाय।

उनकी योजनाएँ कुछ भी रही हों पर जब उत्तर प्रदेश में रायबरेली के मतदाता-क्षेत्र से, जो इससे पहले वे सभी चुनावों में उनका गढ़ रहा था, उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी राजनारायण न उहें हरा दिया तो सारी योजनाओं पर पानी फिर गया।

जब यह खबर और सजय के हारने की खबर भल्लूबारा के दफ्तरो के बाहर मोटे मोटे प्रक्षरा में लगायी गयी तो हजारों लोग, जिनमें औरतें भी शामिल थी डोकों की ताल पर नाच उठे। एक जगह एक दशक का भी उधर से गुजरता था उसे तबूरी मुर्गे खिला रहा था। एक जमाना था कि यही औरत अपने गौरव के शिखर पर थी और आज 'अनपढ़' जनता ने उसे नीचा दिखा दिया था।

श्रीमती गांधी के चले जाने से एक युग का अंत हो गया, जो न तो पूरी तरह स्वर्ण युग था न पूरी तरह अधकार युग था।

दश को धर्म निरपेक्ष बनाय रखने और एकता के सूत्र में बांधे रखने के सिलसिले में उनकी कोशिशें कोई मामूली योगदान नहीं थी। उन्होंने पाखंड के खिलाफ और लकीर के फकीर बन रहने के खिलाफ साहस का परिचय दिया और राजनीतिक मामला में भी उन्होंने वह रास्ता अपनाया जिस पर चलने पर ज्यादातर दूसरे लोग घबराते।

लेकिन अच्छे कामों या उह पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जानेवाले तरीकों की कमी का साहस से नहीं पूरा किया जा सकता था। ग्यारह साल तक प्रधानमंत्री के पद का भार संभालने के दौरान यही श्रीमती गांधी की सबसे बड़ी ताकत भी थी और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। उनके लिए तरीकों की कोई अहमियत नहीं थी नतीजा की अहमियत थी।

चाह वह 1969 में कांग्रेस के दा टुकड़े कर देने का सवाल रहा हो या जून 1975 में देश में भीतरी इमर्जेंसी लागू करने का, इन बातों ने साबित कर दिया था कि वह अपनी जीत के लिए कोई भी हथियार इस्तेमाल करने का तयार थी। उह बस कामयाबी हासिल करने में मतलब था, इस बात से नहीं कि वह कम हासिल की जाये।

यह मंच है कि वह ऐसे कार्यक्रम में विश्वास रखती थी जिसमें बीच के रास्ते में कुछ कामयाबी को और झुकाव हो लेकिन विचारधारा उनके लिए चुनियाती तौर पर किसी समय को प्राप्त करने का एक माध्यम-मात्र था। 1969 में उन्होंने वकील का कारोबार सरकार के हाथ में ले लेने का जो बूम उठाया था वह एक सराहनीय बूम था लेकिन चुनियाती तौर पर वह मोरारजी का एक रेंजे में हटा देने के लिए उठाया गया था। विचारधारा की दृष्टि से उन पर प्रगतिशील होने की छाप पड़ जाती थी

और आम जनता इसकी अच्छा समझती थी। जितने दिन उन्होंने शासन किया उसके दौरान 16 करोड़ और लोग दरिद्रता की सीमा से भी नीचे पहुँच गये और इस तरह हमारे देश की 68 प्रतिशत आबादी दरिद्रता के रसातल में पहुँच गयी थी।

और जैसे जैसे दिन बीतते गये, उनको यह विश्वास होता गया कि देश के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा यह वही जानती हैं केवल वही। इससे उनके मन में यह भावना जगी कि उनके बिना देश का काम नहीं चल सकता और उन्होंने अपना एक बहुत ताकतवर सेन्ट्रेरियट बनाया जो सरकार के हर विभाग पर अपना शिकजा कसे रखता था, उन्होंने जासूसों का एक जाल फनाया जो उनके असली और फर्जी दोनों ही तरह के विरोधियों पर कड़ी नजर रखता था।

इस तरह उन्हें कोई सलाह देनेवाला नहीं रह गया क्योंकि जो भी जानकारी उनके पास तक पहुँचायी जाती थी वह इस तरह काट छाटकर तैयार की जाती थी कि उनके मन में यह बात और अच्छी तरह बैठ जाये कि उनके बिना काम नहीं चल सकता। अगर कोई उनके सामने दूसरा दृष्टिकोण रखता तो वह अपने मन को यह कहकर बहला लेती कि वह उनकी गद्दी छीनना चाहता है।

कविनेट की मीटिंग में वह ऐसा बरताव करती थी जैसे स्कूल में बच्चा को पढा रही हो। ज्यादातर मंत्री उनकी नाराजगी के डर से उनके सामने जबान भी नहीं खोलते थे। वही सरकार थी। और इसके बारे में उन्होंने किसी के मन में किसी तरह का शक बाकी नहीं रहने दिया।

उन्हें इस बात का कोई डर नहीं था कि इस तरह सारी ताकत एक जगह समेट लेने से उन पर डिक्टेटर बनने का इलजाम लगाया जा सकता है। वह बस इतना जानती थी कि ताकत उनके हाथ में है और वह उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार थी। उनकी नजरो में विपक्ष का एक ही इस्तेमाल था कि उसे कुर्बानी का बकरा बना दिया जाय—उनकी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में जो भी गड़बड़ी हो वह उसके मरये मड बी जाये। वह हर क्षेत्र को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में रखना चाहती थी, चाहे खुलआम चाहे ढके ढिपे ढग से।

हर काम के लिए वह किसी ऐसे आदमी का चुन लेती थी जो उस काम को पूरा करने के सार दाँव पेंच जानता हो। लेकिन काम बन जाने पर उसे धूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाता था। उनका कोई बंधा हुआ सलाहकार नहीं था। वह किसी पर भरोसा ही नहीं करती थी।

ऐसे माहौल में वही आदमी पनप सकता था जिस इस बात से कोई मतलब न हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या सही है या गलत जैम बसीलाल, या फिर वह जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो जिस उनका बेटा सजय। ये लोग कोई गलती नहीं कर सकते थे क्योंकि यही थे लोग ये जिन पर उन्हें भरोसा था। बड़े दुःख की बात थी कि ऐसे साहसी व्यक्ति को ऐसी फटीचर बसाखिया का सहारा लेना पड़ा। लेकिन श्रीमती गांधी को पूरा भरोसा था कि वह जब भी चाहेगी उनसे छूटकारा पा लेंगी। दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया।

और जब उन्होंने चुनाव कराने का आदेश दिया जा उनकी तबाही का कारण बन गये उस वक़्त उन्होंने सोचा कि इन बातों को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है, न उनका बेटा न बसीलाल ये दोनों ही चाहते थे कि चुनाव घान वाले कई बरसा के लिए टाल दिय जायें। उनको ऐसा लगता था कि वह जीत जायेंगी और सबका दिवा देंगी कि वह कुछ भी करें पर जनता उनके साथ है। इसमें एक बार फिर यह साबित हो जायगा कि जनता के साथ उनका सम्पर्क अभी टूटा नहीं है और यह कि उनमें

अभी तब साहस ब्रावी है।

वह यह नहीं समझ पायी कि इतने दिन में सबसे अलग रहते रहते जनता के साथ उनका सम्पर्क टूट चुका है। उन्हें एक सन्तोष तो मिल ही सकता था—जो लोग उनकी तुलना हिटलर और मुसोलिनी से करते हैं वे गलत साबित हो जायेंगे। हिटलर और मुसोलिनी ने कभी स्वतंत्र चुनाव नहीं कराये थे, उन्होंने कम-से-कम यह तो किया।

श्रीमती गांधी को कभी यह डर नहीं था कि वह हार जायेंगी। जिस तरह रायबरेली के रिटनिंग अफसर विनोद मल्होत्रा पर दगाव ढासा गया—दो बार श्रीमती नेहरू ने और तीन बार ध्वन ने दिल्ली से टेलीफोन किया—कि वह दुबारा वाट डलवाने का या कम-से-कम दुबारा वोट गिनवाने का आदेश दे दें, उससे यह तो पता चलता ही है कि वह कम-से-कम यह तो चाहती ही थी कि उनके हारने की खबर का ऐलान जितनी देर में हो सके किया जाये। शायद वह सोचती थी कि अगर कांग्रेस को काफी सीटें मिल गयी तो वह बाद में किसी उप चुनाव में जीतकर आ जायेंगी।

लेकिन उत्तरी भारत के सभी राज्यों में कांग्रेस का यत्ना बिलकुल ही साफ कर दिया। उन्होंने अपनी ताकत के बल पर अपनी निजी आजादी और उनीस महीना में जो कुछ भी खोया वह सब फिर से वापस ले लिया। उनका विद्रोह सिर्फ जबरी नसबन्दी के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ था जिसमें उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया था कि अगर उनके साथ कोई अन्याय हो तो वे उसके खिलाफ कोई फरियाद भी कर सकें—पुलिस उनकी रिपोर्ट दज करने से इन्कार करती थी, मजबूर उनकी शिकायतें नहीं छापते थे अदालतें उनकी अज्ञियों की सुनवाई नहीं करती थी और डर के मारे पड़ोसी तक उनकी मदद को नहीं आते थे।

कांग्रेस की सचमुच बहुत बरागी हार हुई थी। वह जैसे तैसे करके सिर्फ 153 सीटें जीत सकी जबकि 1971 के चुनाव में उसने 350 सीटें जीती थी। जनता पार्टी और उसके साथी सी० एफ० डी० न मिलकर 299 सीटें जीती। उत्तर प्रदेश की 84, बिहार की 54 पंजाब की 13, हरियाणा की 11 और दिल्ली की 7 सीटों में से कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पायी। वह मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1, पश्चिम बंगाल में 3, उड़ीसा में 4 और असम तथा गुजरात में 10-10 सीटें ही जीत पायी।

अलग अलग राज्यों में उसे जितने प्रतिशत वोट मिले उसका ब्योरा इस प्रकार है (ब्रकट में 1971 का प्रतिशत दिया गया है) पश्चिम बंगाल 29.39 (28.23), उत्तर प्रदेश 25.04 (48.56) तमिलनाडु 22.28 (12.51) राजस्थान 30.56 (45.96), पंजाब 35.87 (45.96), उड़ीसा 38.18 (34.46), मणिपुर 45.71 (30.02), महाराष्ट्र 46.93 (63.18), मध्य प्रदेश 32.5 (45.6) करल 29.12 (19.75), कर्नाटक 56.74 (70.87) हिमाचल प्रदेश 38.3 (75.79), हरियाणा 17.95 (52.56), गुजरात 46.92 (44.85), बिहार 22.90 (40.06), असम 50.56 (56.98) और आंध्र प्रदेश 57.36 (55.73)।

उत्तर में तो जनता पार्टी ने पूरा सफाया कर दिया, लेकिन तमिलनाडु में उसका घुरा हाल रहा। वस आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उस एक-एक और तमिलनाडु में दो सीटें मिलीं। जाहिर है कि जनता लहर विन्ध्याचल पर्वत को पार नहीं कर पायी थी। यह भी जाहिर था कि दक्षिण भारत में ज्यादातया भी कम हुई थी और पातना आदि की कहानियाँ अभी सामने नहीं आयी थीं।

जनता पार्टी और सी० एफ० डी० की इतनी गान्धार जीत पर, जो जनता और आजादी के नार पर चुनाव लड़ी थी भाग्य के बुद्धिजीवियों और पश्चिमी दंगी

के लोगो को बहुत ताज्जुब हुआ—दोना ही का जनता से कोई सम्पर्क नहीं था। वे इतनी सी बात नहीं समझते थे कि गरीब को भी अपनी आजादी से उतना ही प्यार होता है जितना किसी धीर को। हो सकता है कि उनके रवध में बहुत बारीकियाँ न रही हो, या वह किसी खास विचारधारा की कसौटी पर खरा न उतरता हो, लेकिन जिस चीज को वे जनता से समझते थे उस पर उनकी आस्था अटिग थी। एक वोट से उनके हाथ में यह ताकत आ गयी थी कि वे अपनी पसन्द के आदमी को चुनें और उन्होंने इस ताकत को यह साबित करने के लिए इस्तेमाल किया कि असली मालिक वही हैं। श्रीमती गांधी और उनकी पार्टी ने यही अधिकार उनसे छीन लिया था। इस मनमानी के खिलाफ यही उनका फसला था।

उन दिनों एक मजाक आम था कि जहाँ जहाँ सजय गया वहाँ-वहाँ कांग्रेस की हार हुई। लेकिन श्रीमती गांधी ऐसा नहीं समझती थी। एक अखबार को दिये गये इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस की हार का दाप सजय के मस्ये में दना बातों को बहुत भतही ढंग से देखना है। उन्होंने कहा कि सजय का पांच सूत्री कार्यक्रम सरकार का कार्यक्रम था, और नहरू के जमाने में 1950 के बाद के वर्षों से चला आ रहा था।

उन्होंने 22 मार्च को कांग्रेस वर्किंग कमिटी की मीटिंग में भी सजय की तरफ से सफाई पत्र की। पहले तो वह इस मीटिंग में आयी नहीं, वह यह जानना चाहती थी कि लोग का अब भी उनकी जरूरत है या नहीं। बाद में उन्होंने इस बात का मौका दिया कि उन्हें मीटिंग में जाने के लिए समझा-बुझाकर राखी कर लिया जाये। जब सिद्धायशकर न बसीलाण को छ साल के लिए कांग्रेस से निकाल देने और सजय की चाडाल चौकड़ी के दूसरे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की माँग की तो वह चीखकर बोली "मुझे निवास दो। मुझे निवास दो।"

श्रीमती गांधी बिना किसी खतरे के इस तरह की बात कह सकती थी। वह जानती थी कि 5 राजेन्द्रप्रसाद रोड पर उनके चारा और जो लोग बैठे हुए थे वे उनके विस्वास कुछ भी नहीं कर सकते थे। इन लोगों में कोई हिम्मत नहीं थी कोई दम नहीं था। ग्यारह साल तक वे चुप भी किये बिना उनका हुकम बजाते आये थे और उनके गुण गाते रहे थे। फिर इसमें ताज्जुब ही क्या है कि कांग्रेस वर्किंग कमिटी ने एक बार फिर उनके मतभेद के बारे में अपना विश्वास प्रकट करके विस्तार के साथ बहस करने का काम 12 अप्रैल के लिए टाल दिया। इस तरह श्रीमती गांधी को अपना वास मतसद पूरा करने के लिए—पार्टी पर अपना कब्जा बनाये रखने और जिन लोगों ने उनका साथ दिया था उन्हें बचाने के लिए—अगली चाल साधने का मौका मिल गया।

इसके बाद अगल कुछ हफ्तों तक पार्टी पर कब्जा करने के लिए जबरदस्त खीचातानी चलती रही, एक तरफ श्रीमती गांधी और उनके लोग थे और दूसरी ओर थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आर भुकाव रखनवाले उनके आलाचका के साथ दक्कान बगला चह्वाण और उनके साथी दम माधे दूर में तमांगा दखत रहे जसा कि मकट के समय में लोग हमेशा में करत आये थे। य लाग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि देखें आखिर में नतीजा क्या होता है और बीच बीच में जब कभी ऐसा

- 1) जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ कब्जा रखनवाली भूतपूष समूह-संस्था श्रीमती सुप्रभा जोशी-श्रीमती गांधी से मिलने गयीं तो वह बड़ा रछाई से मिलीं। श्रीमती गांधी ने कहा कि उनका दगाबाज दोस्ता ने उन्हें धोखा दिया था।

लता था कि हालत और बिगड़ जायेगी और पार्टी में फूट पड़ जाने का खतरा है तो ये लोग भी थोड़ा सा सहारा दे देते थे।

श्रीमती गांधी और उनके साथियों पर जो हमला हो रहा था उसका खूब दूसरी तरफ मोड़ने के लिए उनके समर्थक बरमा के इस्तीफे की मांग करने लगे। उनके खिलाफ इन्जाम यह था कि उन्होंने पार्टी को लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए ठीक से तैयार नहीं किया था। इसकी काट करने के लिए चन्द्रजीत यादव के घर पर मसद के हारे हुए सदस्य और राज्यों के कुछ विधायक जमा हुए और उन्होंने सजय, बसीलाल विद्याचरण शुक्ला और श्रोम मेहता को निकाले जाने की मांग की।

चाली और जवाबी चालों के इस माहौल में सिद्धायश्वर रे, चन्द्रजीत यादव और उनके दोस्तों ने बरमा को कांग्रेस की बकिंग कमेटी और पार्लियामेन्टरी बोर्ड से बसीलाल का इस्तीफा मांगने पर राजी कर लिया। इस पर श्रीमती गांधी आगबबूला हो गयी और उन्होंने यह बात जाहिर कर दी कि वह इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी कि जो लोग उनके करीब थे उनमें से किसी एक को भ्रमण करके पार्टी की हार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाय। उनके ग्रुप ने बरमा के इस्तीफे की मांग तेज करके जवाबी धार बिया। उन्होंने यह भी मांग की कि कांग्रेस बकिंग कमेटी की मीटिंग कुछ दिन के लिए टाल दी जाये और ए० आई० सी० सी० की मीटिंग की जाये जिसमें बरमा की जगह नया अध्यक्ष चुना जाये। सबट गहरा होता गया। पार्टी फूट के रास्त पर आग बत्नी जा रही थी।

एक दिन शाम को श्रीमती गांधी के घर पर एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने अपने बहुतों में बसीलाल के इस्तीफे का खत निवासकर बरमा को नहीं बल्कि चत्तान को दे दिया। लेकिन इससे पहले उन्होंने सबसे इस बात पर हमी भरवा ली थी कि पूरी बकिंग कमेटी एक साथ इस्तीफा दगी और सभी लोग पार्टी की हार के लिए बराबर के जिम्मेदार होंगे।

यह पार्टी पर फिर से बज्जा करने की चाल थी। सबसे पहले चन्द्रजीत यादव ने कहा कि सब लोगो के साथ इस्तीफा देने के सुभाव से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। बावला रहि न भी बरमा को पत्र लिखकर अपने दस्तखत वापस ले लिये और कहा कि यह चाल इसलिए चली गयी है कि बकिंग कमेटी चुनाव के नतीजों के बारे में छान-बीन न कर सके। सिद्धाय वाबू ने भी बलवत्ते से कहलवा भेजा कि सत्र लोगो के एक साथ इस्तीफा देने की बात में अज्र दम नहीं रह गया है। बरमा ने कहा कि बेरल प्रदण कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट ऐंथनी ने भी प्रिवेट्रम में टलीफोन करके उनसे कहा था कि बकिंग कमेटी चुनाव में हार की वजह का पता लगाने की अपनी जिम्मेदारी से बस खतरा सकती है। बरमा ने अध्यक्षतावाता को अपने घर पर बुलाकर यह ऐलान कर दिया कि हम तीन में जो कुछ हुआ है उस दखत हुए उन्होंने हम पूरे मवाल पर त्रिजुल नय सिर में विचार किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का बरारी हार की छात्रान करने के लिए बकिंग कमेटी की मीटिंग पन्न बतायी गयी जागीया का ही हागी।

श्रीमती गांधी ने घमकी दी कि वह बकिंग कमेटी की मीटिंग में नहीं आयेंगी और इस तरह एक बार फिर पार्टी में टूट जाने का खतरा पन्न हा गया। श्रीमती गांधी ने मुग्धप्रिया और प्रणवापेस कमेटियाँ अध्यक्षता का भी वातचीन में हिस्सा नाने का चुनाव दबेर बकिंग कमेटी का दापरा और बढ़ा लिया। बकिंग कमेटी की मीटिंग में एक दिन पन्न श्रीमती गांधी ने एक छोटी चापाकी की पान चनी। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष और बकिंग कमेटी के दूसरे मांगरा को एक पत्र लिखकर

चुनाव में पार्टी की हार की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर थोड़ ली।

अपने इस खत में उन्होंने लिखा था 'सरकार के नेता की हैसियत में मैं बिना किसी सकोच के इस हार की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हूँ। मुझे अपने लिए बहाने या बच निकलने के रास्ते ढूँढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझ में किसी चादल चौकड़ी की तरफ से सफाई पेश करने की और न ही किसी गुप के खिलाफ लड़ना है। मैंने कभी किसी गुप के नेता की हैसियत से काम नहीं किया है।

वकिंग कमेटी की मीटिंग 12 अप्रैल को हुई। चूँकि सारे मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटीयों के अध्यक्ष भी वहाँ मौजूद थे इसलिए वह मीटिंग सिर्फ पिट्टे हुए मोहरो का एक बहुत बड़ा जमाव था जिसे यह मानसूत्र करने के लिए बुलाया गया था कि आखिर गडबन्नी कहीं हुई। लेकिन श्रीमती गांधी का कहीं पता नहीं था।

बिहार के उनके एक चमचे मीताराम केसरी ने पूछा, 'उनके बिना मीटिंग कैसे हो सकती है?' दूसरे लोगो ने भी इसी तरह के सुझाव दिये। कुछ और लोगो ने कहा, 'आइये, हम सब लोग 1 सफरजम रोड चले और इंदिराजी का मनाकर मीटिंग में ले आयें।' कुछ देर तक मीटिंग में गडबन्नी मची रही। आखिरकार बरमा, चह्वाण और कमलापति त्रिपाठी मीटिंग में से उठकर बाहर आये और लपककर एक मोटर पर बैठ गये। तीनों सीधे श्रीमती गांधी की कोठी पर गये और उन्हें अपने साथ मीटिंग में ले आये। सभी ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। वह जानती थी कि उनका जादू अभी खत्म नहीं हुआ है।

वकिंग कमेटी की बहस बहुत तात् भाव से शुरू हुई, लेकिन जब हरियाणा के मीठा बोलनेवाले और नरमी का व्यवहार करनेवाले मुख्यमंत्री बनारसीदास गुप्ता ने अपने पुराने गुरु बसीलाल के खिलाफ तरह-तरह के इतजाम लगाकर अपने मन का बोझ हल्का करना शुरू किया तो लोगों के कान खड़े हुए। बनारसीदास गुप्ता ने कहा कि उनके राज्य की सरकार दिल्ली में बैठकर बसीलाल चलाते थे। उनका अपना काम इतना था कि बसीलाल के लिए, जो तब रक्षामणी थे बड़ी बड़ी मीटिंगों का बन्दोबस्त करायें। उन्हें हुकम था कि जिस मीटिंग में भी बसीलाल बोलें उसके लिए टिकी, बसा और दूसरे तरीका से 1,00,000 आदमी जुटाये जायें। और हर बार जब बसीलाल किसी मीटिंग में बोलते थे तो कांग्रेस के 10,000 वोट कम हो जाते थे। किसी ने पूछा 'गुप्ताजी आप पहले क्यों नहीं बोले?' गुप्ताजी ने जवाब दिया 'मैं बुजदिल था।'

मीटिंग में श्रीमती गांधी ने बसीलाल की तरफ में कोई सफाई पेश नहीं की, लेकिन जब तीसरे पहर मिठावागर रे ने बसीलाल को निकाल देने का सुझाव रखा तो उन्होंने उसके खिलाफ अपनी आवाज उठायी। वकिंग कमेटी में उनके एक दोस्त ने यह सुझाव रखा कि बसीलाल का चौबीस घंटे का अदर इस्तीफा देने का मोक़ा दिया जाय। लेकिन यह मौका नहीं दिया गया। अगले दिन फिर वकिंग कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें बसीलाल की छ सान के लिए पार्टी की बुनियादी मेम्बरी से निकाल दिया गया। श्रीमती गांधी इस मीटिंग में नहीं आयी। दूसरे लोगो पर लगभग कोई आंच नहीं आयी। बिचाचरण गुप्ता को हल्की सी डाट पड़ी और मोम महता के बारे में तो एक शब्द नहीं कहा गया वह बचारे दिन भर दया की भीख माँगते फिरें थे। मजबूत के खिलाफ कोई कारवाई करने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि वह तो कांग्रेस का मेम्बर ही नहीं था। (कहा जाता है कि एक दिन सुबह श्रीमती गांधी बरमा के घर गयी थी और उनसे अपने बेटे के लिए परियान की थी। बरमा ने मे एक मित्र के मामले में यह माना, आखिरकार मैं हूँ तो इसान ही।')

श्रीमती गांधी खुद साफ बच गयी। न सिर्फ यह कि वकिंग कमेटी

‘हमारी सम्मानित नेता’ कहा बल्कि किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि उनकी तरफ उगली तक उठाता।

वर्किंग कमेटी ने बरग्रा का इस्तीफा मजबूर कर लिया—जसा कि पहले ही से तय कर लिया गया था—घोर इस बीच के भ्रम के लिए स्वर्णसिंह को मध्यस्थ चुन लिया। इंदिराजी यह नहीं चाहती थी, वह ब्रह्मानंद रेड्डी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाना चाहती थी। लेकिन बाद में चलकर मई में वह हममें कामयाब हो गयी, लेकिन चुनाव में टक्कर होने के बाद। रेड्डी को 317 वोट मिले और सिद्धायशकर रे को 160। पिछले मंत्रिमण्डल के स्वास्थ्य मंत्री वर्णमिह भी मैदान में थे लेकिन उन्हें बहुत ही थोड़े वोट मिले। मध्य प्रदेश के घाघ कांग्रेसी नेता द्वारकाप्रसाद मिश्रा ने श्रीमती गांधी को जिताने में बहुत मदद की—जसा कि 1969 में वह सिंडीकेट के खिलाफ कर चुके थे।

जनता पार्टी को इस तरह के किसी सबूत का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन चूंकि वह चार पार्टियों का गठजोड़ थी इसलिए वही कड़ी खींचानानी के कुछ आसार ज़रूर दिखायी दिये। उन्हें भ्रमना प्रधानमंत्री चुनना था। इसके लिए तीन दावेदार थे—मोरारजी, जगजीवनराम और चरणसिंह, तब तार पर पहल दो।

जनसंघ और मगटन कांग्रेस व लाग मागगजी के पक्ष में थे और सांगलिसट और ज्यादातर युवा तब जगजीवनराम का चाहते थे। भारतीय लोकसभा अपने नेता चरणसिंह को प्रधानमंत्री बनवाना चाहता था।

बहरहाल, यह मामला जयप्रकाश पर छाड़ दिया गया जो चुनाव के बाद एकछत्र नेता बनकर उभरे थे। बहुत से लोग की शकावा के बावजूद अंत में जीत जन-तंत्र में उनकी अध्यक्षता और जोर तब तक की खिलाफ उनकी अध्यक्षता की ही हुई थी। उनकी सम्पूर्ण क्रांति की कल्पना साकार हो रही थी। वह खुद नेता के चुनाव के फ़ैसले से प्रलग रहना चाहते थे और उन्होंने प्रयोक् मेहता और मधुलिमय को अपनी यह इच्छा जता भी दी थी। लेकिन बाद में उन्हें इस बात के लिए तयार कर लिया गया कि वह सभी लोगों की राय मालम करके फसना बना दें। आचार्य कृपलानी से उनकी मदद करने को कहा गया।

नये चुने गये सप्ताह सम्मेलन से—जनता पार्टी (271), सी० एफ० डी० (28), मावसवादी (22), अक्वाली (8), किमान मजदूर पार्टी (5), रिपब्लिकन पार्टी (2) और लगभग एक दर्जन और सदस्या स—24 मार्च को गांधी शांति प्रतिष्ठान की इमारत में जमा होने को कहा गया। लेकिन सीटिंग शुरू होने से पहले ही राजनारायण न भारतीय लोकदल के नेता चरणसिंह का एक खत लाकर दिया, जो उस समय अस्पताल में थे। इस पत्र में कहा गया था कि प्रधानमंत्री के पद के लिए भारतीय लोकदल मोरारजी देसाई व पक्ष में है। पढ़ने यह समझा जाता था कि शामद चरण सिंह खुद टक्कर लें, लेकिन अंत में वह मैदान में हट गये थे।

मावसवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस बात का पना लगाने में कोई हिस्सा नहीं लिया कि मोरारजी और जगजीवनराम के बीच क्या नाम किन्ने साथ है। पार्टी के कुछ मेम्बरों ने निजी तौर पर कहा कि चूंकि वे लाग इमर्जेंसी के बीच महीना के दौरान पिछली सरकार के कुर्बानों का पदापाग करेंगे इसलिए अगर जगजीवनराम नहीं सरकार के नेता चुन गये तो इस बात में उनको परेशानी होगी क्योंकि उस दौर में वह श्रीमती गांधी की सरकार में शामिल रह चुके थे। लेकिन पार्टी का सरकारों रखना यह था कि वह मोरारजी व मुजाविल जगजीवनराम को अपना पक्ष बदलती।

जब नेता का फँसला करों के लिए इस बुनियादी महत्व की मीटिंग के लिए ससद के सदस्य जमा होने लगे तो हॉल में वोट देने की छपी हुई पर्चियाँ लगायी गयी। लेकिन इससे पहले कि लोगो की राय मालूम करने का सिलसिला शुरू होता, राज नारायण ने सुभाव रखा कि फँसला जयप्रकाश पर छाड़ दिया जाये, मधुलिमये ने इस सुभाव का समर्थन किया। जगजीवनराम और बहुगुणा दोनों हॉल के बाहर इन्तजार कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि लोगो की राय नहीं ली जायेगी तो वे वहाँ से उठकर चले गये। उनको यह बात अच्छी नहीं लगी कि सभी लोगो की राय मालूम करने का जो सुभाव पहले मान लिया गया था उसे भाजमाने से पहले ही छोड़ दिया गया।

जयप्रकाश भय भी राय मालूम कर लेने के पक्ष में थे लेकिन कृपलानी ने कहा कि इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि क्यादा लोग मोरारजी के पक्ष में हैं। इसलिए राय मालूम करने का विचार त्याग दिया गया और कृपलानी ने ऐलान कर दिया कि नेता मोरारजी हैं।

मोरारजी को 24 माच को भारत के चौथे प्रधानमंत्री की शपथ दिलायी गयी, जिस पद के लिए वह पहले भी कम से कम दो बार कोशिश कर चुके थे। भय उनकी बरसो पुरानी साथ पूरी हुई थी।

कुई दिन तक वह अपने मंत्रिमण्डल का ऐलान नहीं कर सके क्योंकि वह सी० एफ० डी० के जनता पार्टी में मिल जाने की राह देख रहे थे। जगजीवनराम इसके लिए इस बात पर तयार थे कि उन्हें उप प्रधानमंत्री बना दिया जाये। लेकिन मोरारजी यह पद चरणसिंह का देने का वायदा कर चुके थे। दो उप प्रधानमंत्री रखना कुछ भ्रष्टाचारा लगता था। मोरारजी बड़े धमसकट में फँस गये थे। चरणसिंह ने मोरारजी को इस दुविधा से छुटकारा दिला दिया और जगजीवनराम के भा जाने के लिए रास्ता खोल दिया। जिस तरह नेता के सवाल का फसला किया गया था वह जगजीवनराम को अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी सरकार में शामिल नहीं होगी।

जब मैंने उनसे पूछा कि आप सरकार में शामिल होना क्यों नहीं चाहते, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उन्होंने कांग्रेस फिर वही मंत्री बनने के लिए नहीं छोड़ी थी। उन्होंने यह भी कहा कि 'कोई भुभन मेरी मंत्री की कुर्सी छीन तो नहीं रहा था।' फिर भी उन्होंने यह बात जरूर माफ कर दी कि उनकी पार्टी सरकार का साथ देने का तो वचन नेगी लेकिन ससद के बाहर वह अपनी असम हैसियत बरकरार रखेगी।

जयप्रकाश ने जगजीवनराम का मंत्रिमण्डल में शामिल हो जाने पर राखी करने की अपनी कोशिशें जारी रखी। दरअसल, जहाँ जयप्रकाश ने सिरा छोड़ा था वहाँ से एक छाटी-सी कमेटी ने उस सँभाल लिया और समझौता करा दिया।

तब यह हुआ कि शासक मोर्चे में जो खास-खास पार्टियाँ शामिल हैं उनमें से हर एक के दो-दो मंत्री मंत्रिमण्डल में होंगे—भारतीय लोकदल के प्रतिनिधि होंगे चरणसिंह और राजनारायण, जिनके मंत्रिमण्डल में शामिल किये जाने पर चरणसिंह अड़ गये थे, जनसम के भटलबिहारी वाजपयी और एल० के० अडवाणी, सी० एफ० डी० के जगजीवनराम और बहुगुणा, सगठन कांग्रेस के रामचंद्र और मिर्चंदर बस्न, सोशलिस्टो के जाज फर्नांडीज और मधु दण्डवते, युवा तुकों और दूसरे लोगो के मोहन धारिया और पुरपोत्तमलाल कौशिक, और अकालिया के प्रकाशसिंह बादल। कुल तेरह नाम थे, जो मनहस गिनती समझी जाती है।

सी० एफ० डी० सरकार में शामिल हो गयी होती लेकिन जब के

नाम का ऐलान किया गया तो जगजीवनराम चिढ़ गये। पिछले दिन जो तरह नामों पर समझौता हुआ था उसके बजाय उन्नीस नामों का ऐलान किया गया। नये नाम थे एच० एम्० पटेल, बीजू पटनायक, प्रतापचन्द्र 'चन्द्र', रवीन्द्र वर्मा, शांतिभूषण और नानाजी देशमुख। 25 मार्च की आधी रात को जगजीवनराम ने मोरारजी को टेलीफोन करके बताया कि वह मन्त्रिमण्डल में शामिल नहीं हो सकेंगे।

जगजीवनराम को इन नये लोगों से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन उन्हें यह बात खुरी लगी थी कि उनकी सलाह क्यों नहीं ली गयी। वह और बहुगुणा दोनों ही शपथ लेने नहीं गये।

फर्नांडीज ने भी, जिनका जगजीवनराम को राजी करने में बुनियादी हाथ रहा था, न जाना ही बहतर समझा। शपथ उन्होंने सोचा कि अगर अभी वह भी मन्त्रिमण्डल के बाहर रहें तो उन्हें जगजीवनराम को अपना इरादा बदलने पर राजी करने में ज्यादा आसानी होगी। नानाजी देशमुख भी जगजीवनराम के बहुत करीब थे, उन्होंने भी यही रवैया अपनाया और अपनी जगह ब्रजलाल वर्मा को मन्त्रिमण्डल में शामिल करने का सुझाव दिया।

इस बार भी जयप्रकाश ने ही इस गुप्तगी को सुलझाया, उनके संदेश से सारा काम बन गया। उन्होंने जगजीवनराम से कहा कि आप एक अकेले भ्रामही नहीं बल्कि पूरी एक ताकत हैं 'जिसके बिना नये भारत का ढाँचा नहीं बनाया जा सकता।' आखिरकार, जगजीवनराम और बहुगुणा भी मन्त्रिमण्डल में शामिल हो गये। उन्होंने अपने लिए कोई खास दर्जा या कोई खास मंत्रालय भी नहीं मांगा। फर्नांडीज ने भी, जो जान बूझकर मन्त्रिमण्डल में शामिल नहीं हुए थे, शपथ ले ली।

मन्त्रिमण्डल बनने के नाटक का यह अंतिम अंक था, लेकिन पर्दा अभी नहीं गिरा था। सी० एफ० डी० को यह मिला था कि उसके साथ 'हर कदम पर विश्वासघात किया गया, जनता पार्टी को यह शिक्का था कि 'दूसरी तरफ से हर बात अपनी मर्जी की करवाने' की काशिश की जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते गये, दोनों के बीच की खाई भी चौड़ी होती गयी।

इस मनमुटाव से सरकार के काम बाज में कोई कठिनाई पदा नहीं हुई। सच तो यह है कि चुनाव के वक्त किये गये कई वायदे तो बड़ी जल्दी पूरे कर दिये गये— नागरिक स्वतंत्रताएँ वापस कर दी गयी, 1971 में बंगला देश की लड़ाई के दिनों में जो बाहरी हमजेंसी लागू की गयी थी वह हटा दी गयी (भीतरी हमजेंसी तो लोकसभा में विपक्ष को पूरा बहुमत मिल जाने पर कांग्रेस ने खुद ही 21 मार्च को हटा दी थी।) प्रॉल इंडिया रेडियो और टेलीविजन के लिए स्वायत्त कॉर्पोरेशन कायम करने का ऐलान कर दिया गया। मीसा में जो लोग अभी तक जेल में बंद थे उन्हें रिहा कर दिया गया। धार्मिक अपराधी भी छोड़ दिये गये। सिपायनलवादियों को यह प्राजादी नहीं दी गयी। (बाद में उन्होंने जयप्रकाश से बीच में पड़ने को कहा और उन्हें कुछ कामयाबी भी मिली।)

फर्नांडीज को, जो बड़ोदा हायनामाइंट केस में मुख्य अभियुक्त थे पहले जमानत पर रिहा किया गया और बाद में जब सी० डी० आई० के हायरैक्टर डी० सेन ने, जो इस मामले को देख रहे थे मारारजी से कहा कि मुकदमे में 'कोई छाम दम नहीं है तो मुकदमा ही वापस ले लिया गया। जाज के साथ बाकी जिन 24 लोगों पर इसजाम लगाया गया था उन्हें भी रिहा कर दिया गया।

लेकिन मुकदमा वापस लिए जाने से पहले फर्नांडीज ने भी अपने निल का सारा गुबार निवास किया। उन्होंने मजिस्ट्रेट से कहा, 'जिस वक्त सरकार के पास म

रहकर काम करनेवाला रेडियो और सेंसर की जजीरो में जकड़े हुए भ्रष्टाचारारी दुनिया का यह बता रहे थे कि किस तरह भारत की जनता ने श्रीमती गांधी की डिक्टेटरशिप और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलनेवाली हुकूमत के आगे सर झुका दिया है, उस वक्त मैं उनकी फासिस्ट सरकार के खिलाफ अडरग्राउंड विरोध संगठित कर रहा था। इस काम में जो धीरतों और मद थे उनमें स्वतंत्रता और आजादी के आदर्श कूट कूटकर भर हुए थे, जो डिक्टेटरशिप के साथ किसी तरह की समझौतेवाजी के लिए तैयार नहीं थे, जो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दाँव पर लगा देने को तैयार थे, जो अपने दृढ़ विश्वास की कीमत चुकाने को तैयार थे।”

यह ती शुरू से ही मालूम था कि इस मुकदमे में कोई दम नहीं था, वह गढ़ा हुआ मुकदमा था।

दस साल में पहली बार विचार व्यक्त करने की पूरी आजादी मिली थी जब भ्रष्टाचारों पर सारी पाबंदियाँ हटा ली गयी थी। सच बात तो यह है कि इमर्जेंसी से पहले भी भ्रष्टाचार ज़रूरत से ज्यादा शरीफ ज़रूरत से ज्यादा भले थे और ऐसी खबरें न छापकर, जिनसे सरकार को कोई परेशानी हो उसे खुश रखने को ज़रूरत से ज्यादा तैयार रहते थे।

भ्रष्टालता पर भी अब कोई दबाव नहीं रह गया था। यह ऐलान कर दिया गया कि इमर्जेंसी के दौरान जिन जजों को बदलकर किसी दूसरी जगह भेज दिया गया था या जिनका मोहदा हटा दिया गया था, उन सबको उनकी पुरानी जगहों पर वापस भेज दिया जायेगा। कायदाबद्ध राष्ट्रपति न 28 पांच को सदन के दोनों सदनों के मिले जुले अधिवेशन में यह ऐलान किया कि जनता सरकार बुनियादी अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं पर लगी हुई बची खुबी पाबंदियाँ भी हटा लेगी कानून का शासन फिर कायम कर देगी भ्रष्टाचारों को अपने विचार आजादी के साथ व्यक्त करने का अधिकार वापस कर देगी और इस बात का पक्का प्रबन्ध करने के लिए कानून बना देगी कि भ्रष्टालतों की ओर से स्वतंत्र रूप से छानबीन कराये बिना किसी भी राजनीतिक या सामाजिक संगठन को गैर कानूनी न ठहराया जाये।

सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमाअते इस्लामी और आनन्द भाग पर से पाबंदी हटा ली।

उसने यह भी वायदा किया कि वह भीसा अप्रतिजनक सामग्री के प्रकाशन से सम्बंधित कानून और जनता के प्रतिनिधियों के चुनाव से सम्बंधित कानून में किये गये उस संशोधन को भी रद्द कर देगी जिसके जरिये कुछ खास लोगों का चुनाव के दौरान किये जातेवाले अपराधों से बरी रखा गया है। तीस साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार शासन करती आयी थी, आज विपक्ष की कुर्सी पर बठी थी, बुझी-भुझी और उदास-सी।

प्रधानमंत्री के सफ्टेरियट को काट छांट दिया गया और उस घब सिर्फ 'दफ्तर' कहा जाने लगा। 'रा' में भी काफी कतर-क्योंत कर दी गयी और परिवार नियोजन कार्यक्रम का बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। जिन अफसरों ने इमर्जेंसी के दौरान खुलेआम सजय का साथ दिया था उन्हें बदलकर दिल्ली में बाहर दूसरी जगहों में भेज दिया गया।

दूसरी ओर इमर्जेंसी लागू करनेवाले भी मुम्वित में फँस गये। पर उन्हें भी अपने किये का पछतावा नहीं था। श्रीमती गांधी ने कहा कि उनकी हार थी यह भी कि उन्होंने चुनाव बनाने के लिए शतत वक्त चुना। एक बार फिर चारों के खिलाफ जहर उगला—जिसका उन्हें मल्ट हो गया था—घोर

पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने ज्यादतियाँ के बिस्से बहुत बढ़ा चढ़ाकर उछाले थे। सजय ने कहा कि वह राजनीति से सपास ले लेगा, लेकिन साथ ही उस इस बात का भी पुरा यकीन था कि सात भर के भदर ही उसका और उसके ग्रुप का पलड़ा फिर भारी हो जायेगा। उसने कहा कि जनता पार्टी को अपने भाग्य को साराहना चाहिए कि मोरारजी प्रधानमंत्री हो गये, वरनाभगर वही जगजीवनराम प्रधानमंत्री बन जात तो और भी बुरा हाल होता। अथिवा सोनी न युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और खुलेआम सजय की आलोचना की।

धवन न अपना इस्तीफा श्रीमती गांधी को उसी जमाने में दे दिया था जब वह नया प्रधानमंत्री चुने जाने के वक्त तक के लिए प्रधानमंत्री का काम-काज देख रही थी। यूनुस न कहा कि जल्द ही वे फिर वापस आ जायेंगे। उन्होंने विलिंगडन ग्रीस्ट में अपना बगला खाली कर दिया और गिल्ली मएक निजी मकान में रहने लगे। उनका बँगला बाग में श्रीमती गांधी को दे दिया गया। बसीलाल को जुनून का दौरा पड़ गया लेकिन कुछ दिन बाद वह ठीक हो गये और उन्होंने कहा कि उनका कांग्रेस से निवाला जाना 'उन लोगों की तिकड़मों' का ही एक हिस्सा था। ग्राम मेहता का रवैया यह था कि जैसे इमर्जेंसी से उनका कभी कुछ लेना देना ही नहीं था। उन्होंने कहा, 'इमर्जेंसी के दौरान जो कुछ हुआ उसका समायन करते हुए मरा एक भी फ़ाँडर दिखा दीजिये।' विद्याचरण शुक्ला ने उसी पुरानी भक्क के साथ कहा कि सारा बसूर तो मछबारी का या सूचना देनवाले माध्यमों का खुद अपना है। उन्होंने अपनी तरफ से ऐसे काम करने का जिम्मा ले लिया जो खुद मुझे नहीं पसन्द थे। सिद्धाथशकर रे को अपने किये पर पछतावा तो नहीं था लेकिन यह साबित करने के लिए कि इमर्जेंसी में और उन उन्नीस महीनों के दौरान जो कुछ हुआ उसमें उनका कोई हाथ नहीं था, उन्होंने श्रीमती गांधी का साथ छोड़ दिया।

जिन भफसरों की सजय, धवन और दूसरे लोगों के साथ मिलीभगत थी उन्होंने साफ़ इकार कर दिया कि इन सब बातों में उनका कोई हाथ था। खैर यह तो सभी कहते थे—और कांग्रेसी उनसे कोई अलग नहीं थे—कि इमर्जेंसी के दौरान जो 'भयानक बातें' हुई उनका उन्हें कभी पता नहीं चला।

श्रीमती गांधी और धवन को छोड़कर ऐसा एक भी आदमी नहीं था जिसने सजय को दोष न दिया हो। जो लोग श्रीमती गांधी के सबसे करीब थे उन्होंने भी कहा, 'सारे भगड़े की जड़ वहीं था।' भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी जिसन इमर्जेंसी का समायन किया था और जिसे लाकसभा में कुल सात सीटें मिली थी, सजय और उसकी आडाल चौकड़ी को दोषी ठहराया।

लेकिन अब ये सब बीती हुई बातें थी। अब हवा में आजादी की गुँज थी। जोश था। खुशी थी। ऐसा लगता था जैसे भँघरे से भवानक उजाले में आ गये हो। एक दूसरी ही तरह की उमंग थी, ऐसी उमंग जो 1947 में, जब देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी उस वक्त भी नहीं दिखायी देती थी। लोग देश के भविष्य के लिए महनत करने और कुर्बानी देने को तयार थे।

जनता सी० एफ० डी० सरकार इस माहौल का पूरा फ़ायदा उठाना चाहती थी और जिन राज्यों में भाव के चुनाव में उसने बाँडे सबका सफ़ाया कर दिया था उनमें वह विधानसभा के नये चुनाव कराना चाहती थी। इसका मतलब था कि सभी उत्तरी राज्यों में नये चुनाव हों—उत्तर प्रदेश पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार में, और इनके अलावा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी। इस समय तक चम्पण विपक्ष की कांग्रेस ससदीय पार्टी के नेता चुने जा चुके थे। इस

काम में उनका सहयोग माँगा गया। यह इसलिए जरूरी समझा गया कि राज्यसभा में बहुमत होने के कारण कांग्रेस संविधान में संशोधन करने और विधानसभाओं की अवधि फिर पहले की तरह ही पाँच साल कर देने की सरकार की योजना पर पानी फेर सकती थी। (संविधान में कोई भी संशोधन दोना सदनों में दो तिहाई बहुमत से ही किया जा सकता है।) चह्दाण सहयोग देन पर राजी हो गये। विधानसभाओं की अवधि छ साल से घटाकर पांच साल कर देन और इस तरह फिर 42वें संशोधन से पहलेवाली स्थिति बहाल कर देने के लिए 7 अप्रैल को संविधान में संशोधन (43वाँ) का प्रस्ताव रखा गया। सरकार इसे इसी बैठक में मंजूर करा लेना चाहती थी। इसका मतलब था कि गुजरात, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में नये चुनाव हो।

चह्दाण शुरू शुरू में तो यह समझ नहीं पाये कि इसने क्या क्या नतीजे होंगे और उन्होंने अपनी पार्टी के मेम्बरों से सलाह माँगविरा भी नहीं किया था। कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने बहुत दिन तक इसका विरोध किया। चह्दाण ने कहा कि उन्होंने सिर्फ इस बात के लिए अपनी राजमन्दी दी है कि यह किस पेश किया जाये, उसको मंजूर करने की नहीं। वह बिहार की विधानसभा भंग करने में पूरी तरह साथ देने को तैयार थे—उस राज्य की विधानसभा जहाँ जयप्रकाश के शान्त्वोलन का सबसे ज्यादा असर पड़ा था। और नहीं नहीं।

जनता पार्टी बड़ी दुविधा में पड़ गयी थी। वह नहीं चाहती थी कि जिंग सहर के सहारे वह विजय की मंजिल तक पहुँची थी वह या ही बिखरकर रह जाये। इसने अलावा 12 अगस्त तक नये राष्ट्रपति का चुनाव भी पूरा हो जाना था। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना था। विधानसभाओं के वोट बहुत काफी थे और उनसे फसले का ख़त बदल सकता था। मन्त्रिमण्डल ने फसला किया कि अगर कांग्रेस ने सहयोग न दिया तो वह नये चुनाव कराने के लिए विधानसभाओं को भंग करने के लिए राष्ट्रपति के अधिकारों का सहारा लेगा—मजे की बात यह थी कि संविधान में ये अधिकार 'भाषा-स्थिति के प्रावधान नामक अध्याय में दिये गये हैं। मन्त्रिमण्डल में इन सवाल पर गरमा गरम बहस हुई और कई मंत्री यह सोचने लगे कि इतने सक्त कदम का नतिज बर्ष से आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। वे जनता पार्टी पर जंगली उठायेंगे कि वह भी बही कर रही है जो कांग्रेस करती थी—एक सरकार की जगह दूसरी तरह की सरकार।

सबसे ससद के चुनावों की बुनियाद पर उन सरकारों का भी बर्खास्त कर देना, जिनकी मिनाद अभी पूरी नहीं हुई थी, भागे के लिए बहुत बुरी मिसाल कायम करना होगा, कुछ भी हो भारत का बाँचा एक सघ-राज्य का बाँचा था, और इससे राज्यों की स्वायत्त-सत्ता का नुकसान पहुँच सकता था।

विधानसभाओं को भंग करने के पक्ष में मन्त्रिमण्डल के फ़सले का ऐलान धरण सिंह ने 18 अप्रैल को एक प्रेस काफ़ेस में कर दिया। उन्होंने कहा कि नौ राज्यों में—बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के—मुख्यमंत्रियों से उन्होंने अपने अपने राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर देने के लिए कह दिया है।

धरणसिंह ने इस कदम को इस बुनियाद पर सही ठहराया कि 199

1 संविधान की धारा 356 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह रिश पर या अन्यथा भी राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर सकता है।

संसद को भंग करन की सलाह मानने का कोई इरादा नहीं था।

फर्नांडीज को उनकी इस याजना की भाव मिल गयी और उन्होंने सरकार के इस्तीफा देने के विचार का भरपूर विरोध किया। उन्होंने खुल्लमखुल्ला कहा कि "अपना बहुमत बनाने के लिए उन्हें (कांग्रेस को) बस इतना करना है कि हममें से कुछ लोगो को गिरफ्तार कर लें।" धीरे धीरे सबकी समझ में आने लगा कि जत्ती ऐलान पर दस्तखत करने से आनाकानी क्यों कर रहे हैं। सभी लोग बहुत भ्रुकलाथ हुए थे। लोगो में गुस्से की सहर दौड़ गयी और उन्होंने जत्ती के बँगले के सामने नारे लगाये।

मन्त्रिमण्डल की बैठक हुई और उसमें एक खत का भसविदा मजूर किया गया जिसमें लिखा था कि अगर वायबाह्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनके मन्त्रिमण्डल की सलाह मानने को तयार नहीं हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बदनाम 42वें सशो घन का हवाला दिया गया, उसमें यह बात साफ-साफ शब्दों में कही गयी थी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मन्त्रिमण्डल की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। जत्ती का घना बनाया रोल बिगड़ गया। कबिनेट के स्रक्रेटरी ने पत्र ले जाकर उन्हें दिया। जत्ती चारों तरफ से घिर गये थे। वह जानते थे कि इसका नतीजा बहुत बुरा होगा और उन्होंने फौरन ऐलान पर दस्तखत कर दिये। एक और स्रक्रेट टल गया। सबने सतोष की साँस ली।

ऐलान 30 अप्रैल को जारी कर दिया गया। नौ राज्यों की विधानसभाएँ भंग कर दी गयी और चुनाव कमिशनर से कहा गया कि वह मानसून शुरू होने से पहले जल्दी-से-जल्दी चुनाव कराने का बन्दोबस्त करें। जनता पार्टी, सी० एफ० डी० और उनके साथियो ने इस ऐलान का स्वागत किया, जबकि कांग्रेस ने उसे एक डिमटेरी हुरकत और देश के सभ राज्य वाले जनतांत्रिक ढाँच पर एक चोट कहा।

दस्तखत करने में जत्ती की टालमटोल से जगजीवनराम का यह विश्वास और पक्का हो गया कि जनता पार्टी और सी० एफ० डी० के नेताओं को अपनी एकता बनाये रखना चाहिए और उन्होंने मोरारजी से कह दिया कि सी० एफ० डी० जनता पार्टी में शामिल हो जायेगी। सी० एफ० डी० के मविष्य का फसला करने के लिए जब उसकी मीटिंग होनेवाली थी, यह उससे लगभग एक हफ्ते पहले की बात है। राजनीति के बहुत समझदार सिलाडी होने के नाते जगजीवनराम जानते थे कि अगर सी० एफ० डी० और जनता पार्टी में कोई समझौता न हो सके तो उत्तर प्रदेश और बिहार उनके लिए एक समस्या बन जायेंगे। लेकिन जनता पार्टी में शामिल होने के पीछे जगजीवनराम का एक और उद्देश्य था। वह उसके अध्यक्ष के चुनाव पर असर डाल सकेंगे। वह नहीं चाहते थे कि भारतीय लोकदल का कोई आदमी जनता पार्टी का अध्यक्ष बन। वामपंथी भ्रुकलाव रखनेवाले चन्द्रसेखर, जिनके नाम पर किसी तरह का कोई धम्का नहीं था, सम्मति से पार्टी के अध्यक्ष चुन लिय गये।

जनता पार्टी और सी० एफ० डी० अब मिलकर एक ही शक्ति बन गये थे। हालाँकि इस मिलसिले को पूरा करने में एक महीने से ज्यादा वक्त लग गया था लेकिन इसकी शुभ मानकर हर तरफ इसका स्वागत किया गया। कुछ लोग इसलिए निराश भी हो गये कि उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी कि जो मोल तोल और सोदेबाजी कांग्रेस के अन्दर होती थी वही उनकी नयी सरकार में भी होने लगी थी।

विधानसभाओं के टिकट जिस तरह बाँटे गये उससे भी वे खुश नहीं थे। दूसरी पाटिया के मगोडो के लिए दरवाजे खोल देना तो बुरा था ही, लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि जनता पार्टी में भी वाले बाजार वाले, गैर कानूनी शराब का घघा करनेवाले, खुशामदी, अपना उल्लू सीधा करनेवाले और कम्युनिस्ट ऊँची-ऊँची जगहों

चुनाव में चूंकि लोगो ने कांग्रेस को विलकुल ठुकरा दिया है इसलिए राज्यों में उसकी सरकारों को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और अपनी इस दलील के पक्ष में उन्होंने संविधान के कुछ अप्रैज विशेषज्ञों के हवाले भी दिये।

इसके अलावा यह एक नैतिक चुनौती भी थी, जिन सरकारों ने अपने अला-वको को मुकदमा चलाये बिना नज़रबंद कर दिया हो, ऐसे जुल्म ढाये हो कि जा बयान भी नहीं किये जा सकते और विपक्ष के सदस्यों को तंग कर-वरके खदेड़ दिया हो, उनके हाथ में शासन की बागडोर नहीं रहने दी जा सकती।

लेकिन गृहमंत्री चरणसिंह ने यह सारा नाम बहुत गलत ढंग से किया था। वह संविधान की पैचीदा गुंथियों में उलझ गये थे। सारा बिस्सा बहुत भोडा रूप धारण कर चुका था और कांग्रेस ने जनता पार्टी के नाम पर बलक लगाने का यह मौका हाथ से नहीं जाने दिया।

जयप्रकाश की राय थी कि जिन राज्यों की विधानसभाओं ने अभी अपने पाँच साल पूरे नहीं किये हैं उन्हें भग्न किया जायें। उनके ध्यान में उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के राज्य थे। जनता सरकार ने एक खरिष्ट मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने (जो अब विदेश मंत्री थे) मोरारजी को पत्र लिखकर विधानसभाओं के भग्न किए जाने पर जो आलोचना हा रही थी उस पर अपनी बिता प्रकट की। वह भी इसी को बेहतर समझते थे कि नौ में से केवल सात राज्यों की विधानसभाओं को भग्न किया जाये।

कुछ राज्यों की कांग्रेसी सरकारों ने सरकार के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल को 'इस कदम को ख़्वा देने और आखिरी फैसला होने तक के लिए कोई आदेश जारी कर देने' की उनकी अर्जी मंजी जजों की राय से खारिज कर दी। लेकिन इससे भी मसला हल नहीं हुआ। श्रीमती गांधी दूर से यह सारा तमाशा देख रही थी। इसी बीच जती ने विधानसभाएं भग्न करने के ऐलान पर दस्तखत करने से इकार कर दिया। जिस दिन उन्होंने इकार किया उससे कई दिन पहले ही उन्हें ऐसा करने के लिए 'राज्य' कर लिया गया था। यह यशपाल कपूर के दिमाग की उपज थी कि कायवाहक राष्ट्रपति विधानसभाओं के भग्न किये जाने के रास्ते में रोड़ा अटका सकता है। श्रीमती गांधी की सलाह लेना जरूरी था और यह यशपाल कपूर ने धन के जरिये किया क्योंकि खुद उन्हें प्रधानमंत्री के घर में घुसने से भना कर दिया गया था। इधर कुछ भरसे स वह एक बेकार का बोझ बन गये थे। हर भादमी फौरन भदान में कूद पड़ा, श्रीमती गांधी भी गौर चह्वाण थी। दोनों ने टेलीफोन पर जती से बात की। कायवाहक राष्ट्रपति अपने बेटे की शादी का न्गोता देने के बहाने गोखले से यह जानने के लिए मिले कि इसमें कानूनी पैचीदगियाँ क्या पैदा हो सकती हैं।

जती अपनी बात पर अड़े रहे, कोई भी दलील उन पर कारगर नहीं हुई। चरणसिंह, शांतिभूषण और कई दूसरे मंत्री उनको समझा-समझाकर हार गये। यह इगारा दिये जाने पर भी कि कायद उन्हें ही अमला राष्ट्रपति बनवा दिया जाय वह सालच में नहीं फँसे। मोरारजी और जगजीवनराम महसूस कर रहे थे कि अब उनके सामने जनता के पास वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया है। उनका बिचार था कि इसी सवाल पर लोकसभा का चुनाव फिर से करा लिया जाय।

उन्हें क्या पता था कि जती ने इसके बारे में पहले ही स सोच रखा था और यह फमला कर लिया था कि अगर जनता पार्टी और सी० एफ० डी० की सरकार ने हस्तीफा दे दिया तो वह चह्वाण में सगवार बनाने को कहेंगे। कायवाहक राष्ट्रपति का

संसद को भंग करने की सलाह मानने का कोई इरादा नहीं था।

फर्नांडीज को उनको इस याचना की भाक मिल गयी और उन्होंने सरकार के इस्तीफा देने के विचार का भरपूर विरोध किया। उन्होंने खुल्लमखुल्ला कहा कि "भ्रपना बहुमत बनाने के लिए उन्हें (कांग्रेस को) बस इतना करना है कि हमसे कुछ लोगो को गिरफ्तार कर लें।" धीरे धीरे सबकी समझ में आने लगा कि जत्ती ऐलान पर दस्तखत करने से आनाकानी क्यों कर रहे हैं। सभी लोग बहुत झुझलाये हुए थे। लोगो में गुस्से की लहर दौड़ गयी और उन्होंने जत्ती के बगले के सामने नारे लगाये।

मन्त्रिमण्डल की बैठक हुई और उसमें एक खत का मसविदा मजूर किया गया जिसमें लिखा था कि अगर वायवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनके मन्त्रिमण्डल की सलाह मानने को तैयार नहीं हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बदनाम 42वें सशो धन का हवाला दिया गया, उसमें यह बात साफ-साफ शब्दों में कही गयी थी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मन्त्रिमण्डल की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। जत्ती का बना बनाया खेल बिगड़ गया। कबिनेट के सफ्टरी ने पत्र ले जाकर उन्हें दिया। जत्ती चारा तरफ से घिर गये थे। वह जानते थे कि इसका नतीजा बहुत बुरा होगा और उन्होंने फौरन ऐलान पर दस्तखत कर दिये। एक और सफट टल गया। सबने सतोष की सांस ली।

ऐलान 30 अप्रैल को जारी कर दिया गया। नौ राज्यों की विधानसभाएँ भंग कर दी गयीं और चुनाव कमिशनर से कहा गया कि वह मानसून शुरू होने से पहले जल्दी से-जल्दी चुनाव कराने का बन्दोबस्त करें। जनता पार्टी, सी० एफ० डी० और उनके साथियो ने इस ऐलान का स्वागत किया, जबकि कांग्रेस ने उसे एक डिक्लेटरी हरकत और देश के 'सब राज्य वाले जनतांत्रिक ढाँच पर एक चोट कहा।

दस्तखत करने में जत्ती की टालमटोल से जगजीवनराम का यह विश्वास और पक्का हो गया कि जनता पार्टी और सी० एफ० डी० के नेताओं को अपनी एक्ता बनाये रखना चाहिए और उन्होंने मोरारजी से कह दिया कि सी० एफ० डी० जनता पार्टी में शामिल हो जायेगी। सी० एफ० डी० ने मविध्य का फसला करने के लिए जब उसकी मीटिंग होनेवाली थी, यह उससे लगभग एक हफ्ते पहले की बात है। राजनीति के बहुत समझदार खिलाडी होने के नाते जगजीवनराम जानते थे कि अगर सी० एफ० डी० और जनता पार्टी में कोई समझौता न हो सके तो उत्तर प्रदेश और बिहार उनके लिए एक समस्या बन जायेंगे। लेकिन जनता पार्टी में शामिल होने के पीछे जगजीवनराम का एक और उद्देश्य था। वह उसके अध्यक्ष के चुनाव पर भरोसा डाल सकेंगे। वह नहीं चाहते थे कि भारतीय लोकदल का कोई भादमी जनता पार्टी का अध्यक्ष बने। मामपयी भुवाव रखनेवाले चन्द्रशेखर, जिनके नाम पर किसी तरह का कोई धमका नहीं था, स्व-सम्मति से पार्टी के अध्यक्ष चुन लिये गये।

जनता पार्टी और सी० एफ० डी० अब मिलकर एक ही शक्ति बन गये थे। हालाँकि इस मिलसिले को पूरा करने में एक महीने से ज्यादा वक्त लग गया था, लेकिन इसको घुम मानकर हर तरफ इसका स्वागत किया गया। कुछ लोग इसलिए निराश भी हो गये कि उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी कि जो मोल-तोल और सोदबाजी कांग्रेस के अन्दर होती थी वही उनकी नयी सरकार में भी होने लगी थी।

विधानसभाओं के टिकट जिस तरह बाँट गये उसमें भी वे खुश नहीं थे। दूसरी पार्टियों के भगोडों के लिए दरवाजे खोल देना तो बुरा था ही, लेकिन इसमें भी बुरी बात यह थी कि जनता पार्टी में भी वाले बाजार वाले, गैर जानूनी घराब का घघा करनेवाले, सुसामदी, भ्रपना उल्लू सीधा करनेवाले और कम्युनिस्ट ऊँची-ऊँची जगहा

पर दिखायी दे रहें थे। इन खबरो से लोगों की निराशा और भी बढ़ गयी कि कांग्रेसी नेताओं की तरह यहाँ भी बड़े बड़े व्यापारिया और सेठा से पैसा जमा किया जा रहा था। ऐसा लगता था कि नौकरशाही भी अपने उसी पुराने आरामतलबी के ढर्रे पर आती जा रही थी। लोग सोचते थे, ऐसा कैसे हो सकता है ?

जयप्रकाश ने तो उनसे वायदा किया था कि गाँव से लेकर नई दिल्ली में वे द्रीय सरकार के स्तर तक चौकसी रखने के लिए जनता की कमेटियाँ बनायी जायेंगी। क्या कोई भी सरकार इतनी गहरी छानबीन की उजाड़त देगी ? आज लोगों के दिमाग में यही सवाल है।

जनता पार्टी ने देश का गतिक स्तर ऊँचा कर दिया है। बरसों बाद अब फिर उन आदर्शों की बात होने लगी है जिन्हें श्रीमती गांधी की सरकार ने बड़ी कोशिश करके सहस्र-महस्र कर दिया था। जनता पार्टी जो कुछ करती है उसकी प्रच्छाद्यों को आम लोग समझते न हो, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जनता पार्टी ने पहले जो नैतिक मानदण्ड कायम किये थे उन्हें वाकी रखना चाहते हैं।

वे इस बात से खुश हैं कि चारों तरफ जो डर छाया हुआ था वह दूर हो गया है—पुलिस का डर दूर दूर तक फैले हुए जामूनों के जाल का डर, भ्रष्टारवाही का डर, दम घोट देनवाले काननों का डर और बिना मुकदमा चलाये नजरबंद कर दिये जान का डर।

वे इस बात से भी खुश थे कि देश के बड़े से बड़े लोगों को भी बहना नहीं जायगा। बैसा में श्रीमती गांधी के खातों की जाँच पड़ताल शुरू कर दी गयी है और अपराधियों को सजा देने के लिए जाँच बमोशन बिठा दिये गये हैं।

आम लोगों का इस बात की भी उतनी ही चिन्ता है कि जो कुछ हुआ घसा फिर न होने पाय। वैसी ही हालत फिर न पैदा होने पाये, इसके लिए हमें कुछ सबक लेना होगा। ऐसा करने का एक तरीका तो यह हो सकता है कि जनतन्त्र में आधिक तत्त्व भर दिया जाये। सबकी बराबरी पर आधारित समाज की स्थापना सम्भव है और हो सकता है कि इस मामले में भारत ही बाकी दुनिया को रास्ता दिखाये।

वे यह भी नहीं चाहते कि जनता पार्टी का भी वही हाल हो जो कांग्रेस का हुआ था उसने नेता भी उनसे पहले वाले नेताओं की रास्ती की हुई कुसियों में इस तरह घस जायें कि वहाँ का एक हिस्सा बन जायें। जन साधारण की दुविधा आदर्शों की दुविधा है। वे जानते हैं कि आदर्शों के पीछे मारे मारे घूमने के मुनाबले में समझौतेबाजी में कहीं ज्यादा फायदा है और उससे कहीं ज्यादा मदद मिलती है। जनता पार्टी के नाम के साथ कुछ प्रच्छादियाँ जुड़ गयी हैं और लोग नहीं चाहते कि उन पर कोई धब्बा लगे।

यह उम्मीद तो कोई भी नहीं करता कि बरसों के दौरान जो एलतियाँ की गयी हैं उन्हें कोई आदमी या कोई पार्टी दो या तीन महीनों में ठीक कर देगी। लेकिन जनता पार्टी न जिस ढंग से और जिस रफ्तार से काम करना शुरू किया है उससे लोग दितुल हताश भले ही न हुए हों, पर कुछ निराश जरूर हुए हैं। लोगों ने कांग्रेस को ठुकरा दिया है, जिस पर अभी तक उसी पुरानी बाहल चौकसी का कब्जा बना हुआ है। अगर जनता पार्टी ने भी वह निराश कर दिया तो वे क्या करेंगे ?

वे इतना डर का तयार हैं। वे समझते हैं कि इतनी जल्दी उम्मीद छाड़ देना ठीक नहीं है और अपना फलसा मुना देना भी अभी बहुत जल्दी है।

परिणिष्ट 1

मारुति

एक सस्ती स्वदेशी 'रत्ना' मोटरकार बनाने का विचार पहले पहल बहुत दिन हुए 1950 के बाद उठा था। छोटी मोटर की योजना। जो मनुभाई गाह की कल्पना की उपज थी, कई उतार चढ़ाव देखे। एक दिन ऐसा आया था जब सरकार ने फ्रांस की 'रत्ना' मोटर बनानेवालों के साथ सम्झौते पर तत्काल हस्ताक्षर कर दिये थे, पाठे कमेटी की सिफारिश यही थी कि हमारी आवश्यकताओं को सबसे अच्छी तरह यही कमेटी की सिफारिश यही थी कि हमारी आवश्यकताओं को सबसे अच्छी तरह यही मोटर पूरा कर सकती है। लेकिन बाद में कृष्णमाचारी के सहज विरोध करने पर यह मोटर पूरा कर सकती है। लेकिन बाद में कृष्णमाचारी के सहज विरोध करने पर यह योजना खटाई में पड़ गयी। इससे धार कई बरस तक इस योजना के शुभाव की चर्चा बार-बार की गयी लेकिन कोई मतीजा नहीं मिलता।

प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कई सम्पनियां न यह मोटर बनाने के लिए टेंडर भेजे और मोटर के अपने अपने नमूने भी तयार कराये। मगूर राज्य के प्री-गिक विकास निगम ने भी अर्जी दी थी, जिसमें यह अर्जा सहाया गया था कि नमूना उद्योग तयार किया था, वही मोटर बाजार में बेचने के पमात्र पर बनाने में लगभग 56 हजार रुपये की लागत आयेगी।

सरकारी क्षेत्रों में इस सवाल पर जो बहस हो रही थी उसमें एक बात थी। एक धारा का माननेवालों का कहना था कि मोटर स्थानीय रूप से बनाने की योजना के साधनों का सहारा लेकर बनायी जाये जबकि दूसरी धारा के लोग कहते थे कि हमारे लिए मोटर बनानेवाली विदेशी कंपनियां के साथ सम्झौता किया जाय। उस समय फोक्सवगन टोयोटा रना, सित्राएन और मागिन्स इत्यादि कंपनियों के नाम योजना में हाथ बंटाने के लिए बहुत उत्सुक थे।

जब यह बहस पूरे जोरों पर थी, उगी मगूर मगूर, इत्यादि न रायस कंपनी के श्रीव बाल कारखाने में अपनी दुर्गि दुर्गि मगूर मगूर यह कहना गलत न होगा कि सजय के इस मगूर में मगूर मगूर अपने आप ही तम हो गया।

ने ही बनायी थी और वही उसका मैनेजिंग डायरेक्टर था हालाँकि इस कम्पनी में उसका सिर्फ एक 100 रु० का शेयर था। जो 'लेटर ऑफ़ इंटेंट' जारी किया गया था उसमें दो लाख शर्तें ये थी। मोटर पूरी तरह यही के साधनों से बनायी जायेगी और उसकी कीमत कम होगी। जैसा कि जाहिर है, जिन हालात में आगे चलकर मासुति लि० काम करनेवाली थी उनमें इन शर्तों के पूरा होने की न कोई उम्मीद थी और न ही उन्हें पूरा किया जा सकता था।

जहाँ तब सजय का सवाल था उसने पहली बड़ी बाधा पार कर ली थी। 'लेटर ऑफ़ इंटेंट' मिल जाने के बाद सजय ज़मीन खरीदने और पैसा जुटाने में लग गया। कितने ही व्यापारी पैसा लगाने को तैयार थे और राजनीति के मदान में भी सम्बे चौड़े होसले रखनेवाले बेईमान लोगों की कोई कमी नहीं थी। इनकी मदद से सजय की ये दोनों समस्याएँ भी हल हो गयीं।

बसौलाल ने अपनी भ्रातृ के मुताबिक खुली पाधली करके महालादा, बुडेर और खेतपुर गाँवों के रहनेवालों को बेदखल करके दिल्ली से गुडगाँव जानेवाली बड़ी सड़क के किनारे 445 एकड़ उपजाऊ ज़मीन हथिया ली। गाँववालों को लगभग 10,000 रु० एकड़ के हिसाब से कुल 45 लाख रुपया मुआवज़ा दिया गया जबकि उससे मिली हुई ज़मीन का भाव 35,000 रु० एकड़ था। इसके अलावा, जो जगह चुनी गयी थी वह इस कानून के भी खिलाफ थी कि किसी भी रक्षा प्रतिष्ठान से 1,000 मीटर की दूरी के अंदर कोई कारखाना न बनाया जाये। सजय का कारखाना फौजी गोला बारूद के एक भण्डार से बिल्कुल मिला हुआ था।

ज़मीन मिल जाने के बाद सजय ने पूँजी जुटाने के सवाल की तरफ ध्यान दिया।

सबसे पहली पूँजी तो उन व्यापारियों से मिली जो इस फेर में थे कि इसके बदले में ज्यादा से ज्यादा रिभायतें हासिल कर लें या अपना कोई काम बनवा लें। सितम्बर 1974 तक मासुति लि० की जमा पूँजी 1,84,60,700 तक पहुँच चुकी थी। इसमें से 22 प्रतिशत शेयर यू० पी० ट्रेडिंग कंपनी के 16 प्रतिशत नेयर दरभंगा मार्केटिंग कंपनी के और 11 प्रतिशत शेयर सारन ट्रेडिंग कंपनी के थे। इनके अलावा मासुति लि० ने 1973-74 के सरकारी साल के दौरान मोटर की बिक्री का अधिकार बेचकर 2,18,91,042 रु० और बढ़ोरे थे। हर डीलरशिप 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का बयाना लेकर बेची गयी थी और वह भी ऐम व्यापारियों के हाथ जिनका इससे पहले मोटरों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा था लेकिन जो समझते थे कि इस काम में पैसा लगाना मुनाफे का सौदा है या जिन्हें इसके लिए मजबूर किया गया था।

शुरू से ही यह योजना सरासर नाकामयाब रही है। पहला जो नमूना बनाया गया था उस क़वाड में डाल दिया गया। दूसरा नमूना बना तो प्राज्ञभाषा के दौरान ही उलट गया। इसके बाद भी जो नमूने बन उनमें भी कोई-न-कोई खराबी ही निकली — किसी का स्टीयरिंग खराब था तो किसी का मस्पैंगन और किसी का रज़न बहुत जल्दी बेहद गरम हो जाता था। एक वक़्त तो ऐसा आया कि सजय ने 'लेटर ऑफ़ इंटेंट' मलगायी गयी शर्तों का ताड़कर विदेशी सामान भी लगाना शुरू कर दिया। अप्सोस फिर भी मासुति लि० ऐसी मोटर नहीं बना पायी जो सड़क पर चल सकती। इस दौरान जब मासुति लखनऊवाली हुई चल रही थी सजय सबके मामूली बड़े भरोसों के साथ धान करता रहा। दिसम्बर 1973 में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में उसने कहा कि बार में हीन में बनकर तयार हो जायेगी। यही बयान उसने अट्ठारह महीने बाद दाहराया और कहा कि 1977 तक पक्करी अपनी पूरी क्षमता में काम करने लगने और राज 200 मोटरें बनाया करेगी। अभी जनवरी 1976 में चंडीगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन के

हालात में, इनमें से कोई भी कंपनी मुनाफा नहीं कमा सकती थी, इसमें न तो ढग का साज सामान ही था और न ढग के काम करनेवाले। लेकिन वह जमाना ग्राम हालात का तो था भी नहीं। श्रीमती गांधी के जबदस्त राजनीतिक संरक्षण का सहारा लेकर सज्ज ने भारत की कंपनियां म बड़ी कामयाबी के साथ ऑर्डरों की भरमार कर दी। जो लोग ग्रामाकानी करते थे या इन फैक्ट्रियों की क्षमता के बारे में शक करते थे उनका पत्ता काट दिया जाता था। और जो लोग कानूनी पहलू से शकएँ उठाते थे उन्हें तग किया जाता था और दबा दिया जाता था। मिसाल के लिए जब अप्रैल 1975 में भारत के साज-सामान के बारे में संसद में सवाल पूछे गये तो औद्योगिक विकास मंत्रालय के डायरेक्टर कृष्णास्वामी ने स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (एस० टी० सी०) के सहित काम करनेवाली कंपनी प्रोजेक्ट्स एण्ड इन्विपमेन्ट कॉर्पोरेशन (पी० ई० सी०) और पूर्वी योरोप के देशों के एजेंट वाटलीबोई से आवश्यक जानकारी देने को कहा। भारत लि० ने मोटर बनाने की मशीनें इन्हीं दो कंपनियों से खरीदी थी। इससे पहले कि कोई जानकारी बाहर जान पाती पी० ई० सी० और एस० टी० सी० के डायरेक्टरों को प्रधानमंत्री के दफ्तर में तलब किया और फटकारा। उनसे जांच पड़ताल बंद कर देने को कहा गया। पी० ई० सी० के जो दो अध्यक्ष, कावल और भटनागर, जांच पड़ताल कर रहे थे उनमें से कावले को बदलकर किसी दूसरी जगह भेज दिया गया और भटनागर को 'सस्पेंड' कर दिया गया। कृष्णास्वामी के घर पर छापा मारा गया और वहाँ से साराब की दो बातें बरामद करके उन्हें एक्सट्राजुड का कानून तोड़ने के जुम में सस्पेंड कर दिया गया।

सरकारी दखलान्दाजी का उजागर करनेवाली एक और मिसाल तेल और प्राकृतिक गैस कमीशन (आ० एन० जी० सी०) का मामला है। जनवरी 1975 में आ० एन० जी० सी० ने सड़क बटनेवाले छ रोलरों के लिए टेण्डर मँगवाये। सरकारी कंपनी गाडन रीच बकशाप (जी० आर० डब्लू०) और दो दूसरी कंपनियों ने टेण्डर भेजे। आ० एच० बी० ने भी एक प्राइवेट कंपनी की माफन टेण्डर भेजा। शुरू में जी० आर० डब्लू० का टेण्डर 1,46,000 रु० का और भारत का 1,60,000 रु० का था। बाद में भारत ने अपना टेण्डर घटाकर 1,41,000 रु० कर दिया। फिर भी ऑर्डर सरकारी कंपनी को ही मिला। यह फैसला दो बानों की बुनियाद पर किया गया था। एक तो यह कि जी० आर० डब्लू० सरकारी कंपनी थी और इसलिए दाम में 11 प्रतिशत तक की छूट पाने की अधिकारी था और दूसरे उसकी साज ब त ऊँची थी।

लेकिन इससे पहले कि जी० आर० डब्लू० के साथ सीना पक्का किया जाता, यह ऑर्डर रद्द कर दिया गया। साज-सामान की खरीदारी में सम्बंध रखनवाले कमीशन के सदस्य लाहिडी न दुबारा एस्टीमेट मँगवाय। भारत ने अपने रोलरों की कीमत घटाकर 1,25,000 रु० कर दी और जी० आर० डब्लू० अपनी पुरानी कीमत पर जमी रही। बाद में ठेका भारत को दे दिया गया। दुबारा टेण्डर मँगवाकर तो लाहिडी ने अपने अधिकारी की सीमा में बाहर जाकर काम किया ही था इसके अलावा उन्होंने एक गलती यह भी की थी कि उन्होंने इस बात का पूरा नहीं किया था कि किसी कंपनी को ठेका देने के कामजात पर हस्तान्तर कराया स पहन उगकी क्षमता का प्रमाण लगाने के लिए उसकी फैक्टरी का मुआयना कर लिया जाना चाहिए। इसके अलावा यह आइर दन की सारी कामगार इतने ऊँचे स्तर पर की गयी थी कि आ० एन० जी० सी० के पुराने बमचारियों का भी पतराज करने का मौका नहीं मिला था।

इमजेंसी लागू हो जाने के बाद तो कानून के अनुसार काम करने का दिखावा भी छोड़ दिया गया था। अब तो टेण्डर मँगाने की भी जरूरत नहीं रह गयी थी। बस सजय के कहने की देर होती थी और कितने ही लोग उसे पूरा करने के लिए तैयार रहते थे। वाशिंगटन पोस्ट ने अपने 10 नवम्बर 1976 के प्रक में लिखा, "ग्राम लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी घोसाघड़ी चल रही है। बड़े-बड़े भफमर कहते हैं कि व कुछ भी नहीं कर सकते। सजय सेक्रेटरियो को बुलाकर बस इतना कह देता है, 'यह ठेका उसको दे दो'।"

इस रवैये का ठोस सबूत यह था कि राज्यों की तरफ से और दूसरी सरकारी सस्थाओं की तरफ से सड़क कूटनेवाले रोलरों की मांग मचाना बढ़ने लगी। इमजेंसी लागू होने के कुछ ही दिन के बाद बाइर रोड्स आर्गनाइजेशन (बी० आर० ओ०) से 100, हरियाणा से 50 पंजाब से 40 और उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी से अनिश्चित संख्या में सड़क कूटनेवाले रोलरों के आर्डर आ चुके थे।

एम० एच० बी० के पास सचमुच नये रोलर बनाने के लिए न तो आवश्यक साज सामान ही था और न तकनीकी जानकारी ही। उसने कुल 2 000 रुपये के हिसाब से फोड और पकिन के सेकिडहैण्ड इजन खरीदकर उन्हें पुराने कबाड रोलरों में फिट कर दिया और उन पर रंग रोगन करके नया बहकर बेच दिया। बाजार में जो दूसरे रोलर मिल रहे थे उनके मुकाबल में इन रोलरों की कीमत (1 40 000 रुपये) चालीस प्रतिशत ज्यादा थी। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि इनमें से ज्यादातर रोलर उन कामों के लिए मुनासिब साबित नहीं हुए जिनके लिए इन्हें खरीदा गया था। बाइर रोड्स आर्गनाइजेशन को यह मालूम होने पर परसानी तो बहुत हुई, लेकिन वह बोल कुछ नहीं सकता था, कि उसे जो रोलर दिए गए थे उनमें से कोई भी बहुत ऊँचाई पर काम नहीं कर सकता था। इसलिए वे पठानकोट में बी० आर० ओ० के डिपो में खड़े रहे।

एम० एच० बी० का एव और काम, जो उन्होंने अभी हाल ही में शुरू किया था बस की बाँड़ी बनाने का था। इस बात के बावजूद कि हर राज्य में बस की बाँड़ियाँ बनाने के लिए अपनी जरूरत भर पूरा इन्तजाम था, एम० एच० बी० को राज्यों की सरकारों की तरफ से ठेरा आर्डर मिलने लगे। मिसाल के लिए मध्य प्रदेश ने एम० एच० बी० को न सिर्फ 100 बसों की बाँड़ी बनाने का आर्डर दिया बल्कि उन्हें 39 000 रुपये की बाँड़ी के हिसाब से बहद ज्यादा भुगतान भी किया। खुद अपने कार्पोरेशन को वे सिर्फ 27 813 रुपये देते थे। इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार को भी सजय की चाडाल चौकड़ी की खुश बरन के लिए जरूरत से 5 लाख रुपया ज्यादा खर्च करना पड़ा। मन्दाजा लगाया गया है कि इमजेंसी उठने तक प्रवेल उत्तर प्रदेश से 499, मध्य प्रदेश से 180 हरियाणा से 307, राजस्थान से 152 और दिल्ली में 52 बसों की बाँड़ी बनाने के आर्डर मिल चुके थे।

सबिन सायद भण्डाचार और कुनवापरवरी की सबसे शमनाक मिसालें विदेशी मल्टीनेशनल कार्पोरेशनों के साथ मासति की मिलीभगत की हैं। इमजेंसी के कुछ ही दिन बाद (मुम्बिन है कुछ पहले में भी हो) मासति बई मल्टीनेशनल कार्पोरेशन का गजट बन बटा—खारा तौर पर भमरीका के इण्टरनेशनल हावैस्टर और पाइपर कम्पनी और पचिम जर्मनी की मन कम्पनी और डिमाग कम्पनी। इन कम्पनियों के बनाये हुए माल के मलाया मासति के पास रसायन, पम्पिंग इजन, चुनडोजर और टचीफोन के मोटे तार सप्लाई करने की भी गजेंसियाँ थी।

मज्ज गोधी न 1976 के बीच में कभी ग्लिमी में पानी सप्लाई करनेवाले और

गन्दे पानी की निकासी का प्रबंध करनेवाले सगठन से यह बात मनवा ली कि शहर में पीने के पानी और गंदे पानी को साफ करने के लिए वह फिटकरी के बजाय विषक प्लाक पालिमिक्स नामक एक रसायन इस्तेमाल किया करे।

यह रसायन एम० टी० एस० वाले सजय गांधी के एक दोस्त आर० सी० सिंह के साथ मिलकर बनाते थे, जो दिल्ली की आई० आई० टी० से छुट्टी लेकर वहाँ काम कर रहा था।

जब पानी सप्लाई के सगठन के कुछ कमिस्टो ने इस रसायन को इस्तेमाल करने के बारे में कुछ आनाकानी की तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। आर० सी० सिंह को म्युनिसिपल कमिशनर बी० आर० टमटा का सक्नीकी सलाहकार बना दिया गया और इस हैसियत से सिंह ने इस रसायन के इस्तेमाल की मजरी दे दी। पानी सप्लाई सगठन रोज 10 000 रुपये का रसायन इस्तेमाल करने लगा। इस सगठन में पालिमिक्स का इस्तेमाल शुरू हो जाने के बहुत दिन बाद इसके लिए टेंडर मंगाये गये ताकि इसका ठेका देने की पूरी बारंबाई फाइलो में ठीक रहे।

शहर में पानी की सप्लाई में कोई भी रसायन इस्तेमाल करने से पहले यह जरूरी है कि कानपुर की नेशनल एनविरानमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीच्यूट से इसकी जांच करवा ली जाये, लेकिन इस रसायन की जांच नहीं करवायी गयी। रसायन की जानकारी रखनेवालों का कहना है कि इस रसायन के इस्तेमाल से पानी में 'मोनोमर' नामक पदार्थ इतनी अधिक मात्रा में जमा हो जाता है कि उससे जहर पदा होने का डर रहता है और उससे खाल और घास की बीमारियाँ फैल सकती हैं। पालिमिक्स के इस्तेमाल से जितना 'मोनोमर' पानी में जमा हो जाता है वह अमरीका के खाने पीने की चीजों से और मादक पदार्थों की तब पड़ जाने से सम्बंधित कानून में बतायी गयी सीमा से कहीं अधिक है। विदेशों में इसे सिर्फ नालियों के पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है पीने के पानी के लिए नहीं।

एजेंट की हैसियत से भारत को हर सोदे की कुल रकम का 20 25 प्रतिशत भाग कमीशन के रूप में मिलता था। सरकारी और प्राइवेट सगठनों को डरा धमका कर उन्हीं कंपनियों को आर्डर भेजने के लिए मजबूर किया जाता था जिनकी एजेंसी भारत के पाम थी। इस सिनसिले में कई चलत हुए ठेके भी रहे कर दिये गये। मिसाल के लिए पालक मक्टर की इंडियन ट्यूब कंपनी को थो० एन० जी० सी० ने ब्रिटिश स्टील कंपनी के बतये हुए मोटे मोटे नल सप्लाई करने का ठेका दे रखा था। भारत के एक प्रतिनिधि भुलभुलवाला न ब्रिटिश स्टील के प्रतिनिधि चार्ल्स गाडन से मिलकर उन्हें यह पट्टी पटायी कि अगर ब्रिटिश स्टीलवाले भारत का अपना एजेंट बना लें तो उन्हें बहुत फायदा रहेगा। ब्रिटिश स्टीलवाले राजी हो गये और इसके फौरन ही बाद इंडियन ट्यूब कंपनी का ठेका खत्म कर दिया गया। इसी तरह जब भारत ने इंटरनेशनल हावर्स्टर की तरफ में पैरवी की तो पोलड के साथ फसल काटने की मशीनें सप्लाई करने का ठेका खत्म कर दिया गया।

एक और मिसाल है जब थो० एन० जी० सी० को चौबीस भारी ट्रकों का आर्डर भारत की भारत देने पर मजबूर किया गया। इनमें में बारह इण्डरनेशनल हावर्स्टर वाले सप्लाई करनेवाले थे और बाकी बारह पश्चिमी जर्मनों की कंपनीमें। भारत का टेंडर 50 लाख रुपये का था, जो उनके बाद वाले सबसे ऊँचे टेंडर से भी दुगुना था। जब थो० एन० जी० सी० ने आठ एसी टका के लिए टेंडर मंगाये जिन पर 40 से 45 टन तक के वैन लगे हों, तो सबसे नीचा टेंडर नई दिल्ली के ग्राम मूविंग एण्ड मशीनरी कारपोरेशन का था। वे अमरीकी हार्वेस्ट ट्रेन 1 करोड़ 58 लाख रुपये

मे दे रहे थे। मारुति ने शुरू में 1 करोड़ 76 लाख रुपये का टेंडर दिया था लेकिन बाद में उसे घटाकर 1 करोड़ 70 लाख रुपये का कर दिया था। ठेका पहली वाली कम्पनी को दिया जानेवाला था लेकिन केशवदेव मासवीय ने खुद बीच में पड़कर उसे मारुति को दिलवा दिया।

इनसोव फ्राटो लि० नामक कम्पनी का कारोबार बिठा देने के पीछे भी मारुति का ही हाथ था। इस कम्पनी का उद्देश्य सोवियत संघ के सहयोग से मोटरगाड़ियाँ बनाना था। दोनो देशों के बीच जो समझौता हुआ था उसमें कहा गया था कि प्रोमोवा एक्सपोर्ट मास्को उत्तर प्रदेश के सहीला शहर में लगाये जानेवाले एक कारखाने में 400 गाड़ियाँ बनाने के लिए आवश्यक विदेशी बल पुर्जें मँगाई करेगा। लेकिन इमर्जेंसी लागू होने के कुछ ही समय बाद उद्योग मंत्रालय ने सोवियत वाली को लिख दिया कि मारुति लि० के पास खुद 'हल्की व्यावसायिक गाड़ियाँ' बनाने की सभी आवश्यक सुविधाएँ मौजूद हैं इसलिए भारत में एक और कारखाना लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय विदेशी बल-पुर्जें मारुति लि० को सप्लाई कर दिये जायें, और जो मोटरगाड़ियाँ बनाने की योजना है उन्हें वहीं बनायेगा। इसके बाद एक और खत भेजा गया जिसमें यह बात साफ कर दी गयी थी कि सरकार एक नया कारखाना लगाने की इजाजत नहीं देगी। नतीजा यह हुआ कि इस योजना को खुपचाप उठाकर साक पर रख दिया गया।

शायद जिस घोटाले के बारे में सबसे ज्यादा दस्तावेज मिलते हैं वह हवाई जहाजों वाला घोटाला है। पाइपर हवाई जहाजों के एजेंट की हैसियत से सजय ने उन्नीस पाइपर हवाई जहाजों के ऑर्डर जुटाये। इनमें से हर हवाई जहाज पर सजय को विदेशी मुद्रा में पांच पाँच लाख रुपये कमीशन मिला। पाइपर से सजय ने मॉल नामक हवाई जहाजों की एजेंसी ले ली—जिस घमरोका ने बड़ी-बड़ी कम्पनियों के अपसरो के लिए बनाया था। यह महसूस करके कि हिंदुस्तान में 'मॉल' हवाई जहाज खरीन्नेवाले गिनती के ही मिल सकेंगे, सजय ने ज़पि मंत्रालय पर दबाव डाला कि वह फसलों पर दबा छिड़कनेवाला 'वसंत' हवाई जहाज बनाना बन्द कर दे और उसकी जगह 'मॉल' इस्तेमाल करे। सौभाग्य से इमर्जेंसी खत्म हो जाने की वजह से इसके बारे में कोई भ्रांतिरी फसना नहीं किया जा सका।

जब जसे हवाई जहाजों में सजय का दखल बढ़ता गया उसने एक नई कम्पनी खड़ी कर दी—मारुति एविएशन कम्पनी। शायद उसका इरादा यह था कि एक तीसरी फीडर एयर लाइन चलायी जाये जिसका कारोबार प्राइवेट लोगो के हाथ में रहे, और इण्डियन एयर लाइंस और दूसरी सरकारी संस्थाएँ उसकी मदद करें। अब यह बात मातूम हो चुकी है कि उसने इण्डियन एयरलाइंस को इसकी छान-बीन करने के लिए राजी कर लिया था कि यह सुभाव किस हद तक सफल हो सकता है। हवाई जहाजों में अपनी बढ़ती हुई निवेशी की वजह से सजय ने सफ़दरजग का हवाई प्रह्ला हथिया लेन की कोशिश की। उसने इण्डियन एयरलाइंस का हुक्म दिया कि वह सारे हैंगर खाली कर दे और अपनी सारी बसों स्टेशन बगन और मोटरों इन्टरप्रस्य एस्टेट में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के डिपो में खड़ी किया करे। वह मारुति एविएशन की बक़चाप सफ़दरजग हवाई प्रह्ला में लगाना चाहता था। किस्मत से इमर्जेंसी खत्म हो जाने वजह से यह हवाई योजना भी खत्म हो गयी।

जब जब सजय और उसके साथी ज्यादा मुनाफ़ा देनेवाले बारबारा में हाथ डालते गये जैसे जैसे बड़े पमाने पर जनता मोटर बनाने की योजना को छोड़ दिया। मारुति लि० के कर्मचारियों को काम पर लगाये रखने के लिए

के कैंप, नार्मा की तस्तिर्याँ, तालों का सामान और दूसरी छोटी-मोटी चीज़ें बनाने का काम दिया जाता रहा। कमी-कमी इस कम्पनी को बिलकुल ही निराले ढंग का ठेका मिल जाता था, जैसे रक्षा मन्त्रालय ने लिए बमों के 'कैंप-चैम्बर' बनाने का ठेका। बीच-बीच में इस तरह के ठेके मिलते रहने के बावजूद मारुति लि० कर्जों की दलदल में धँसती गयी। 1976 के अन्त तक उस पर 2 करोड़ 30 लाख रुपये का कर्जा बढ़ चुका था, जो कि उसकी 2 करोड़ 64 लाख रुपये की बुनियादी जमा पूँजी के लगभग बराबर हो गया।

अगर लोग मारुति को 'माँ रोती' कहने लगे थे तो इसमें गलत क्या था।

परिशिष्ट 2

संसदशक्ति की मार्गदर्शिकाएं

प्रकाशनाय नहीं (गोपनीय)

1 संसदशक्ति का उद्देश्य संसदशक्ति का इस सम्बन्ध में मार्गदर्शन करना तथा उन्हें इसके बारे में सलाह देना है कि वे अनधिकृत, दायित्वहीन अथवा निराशाजनक समाचार, रिपोर्टें, झटकलबाजियाँ या झूठवाहें छापने से कैसे बचें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन मार्गदर्शिकाओं का लक्ष्य यह है कि देश में सार्वजनिक सुव्यवस्था बनाये रखने स्थायित्व तथा आर्थिक प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण बनाये रखने में समाचार पत्र जगत के सभी हिस्सों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त किया जाये।

2 संसदशक्ति की परिधि में हर समाचार, रिपोर्ट, टिप्पणी, वक्तव्य, छद्म अभि-
व्यक्ति, फिल्म, फोटो, चित्र तथा कार्टून आ जाता है।

3 संसदशक्ति संसद, किसी भी विधानसभा या 'पायालय' की कारवाहियों से सम्बन्धित समाचारों, टिप्पणियों अथवा रिपोर्टों के प्रकाशन पर लागू होती है। इन सत्याओं की कारवाहियों को प्रकाशित करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए

(क) संसद तथा विधानसभाओं के प्रसंग में

- 1) सरकार की ओर से दिये गये वक्तव्य पूर्ण रूप में अथवा सक्षिप्त रूप में प्रकाशित किये जायें, पर उसकी अन्तवस्तु संसदशक्ति के नियमों का उल्लंघन न करे।
- 2) किसी विषय पर झूठनेवाले सदस्यों के नाम तथा उनके दलों के नाम दिये जायें तथा यह भी उल्लेख किया जायें कि वे विषय के पक्ष में बोलें या उससे विरुद्ध।
- 3) विधेयकों, सुझावों अथवा प्रस्तावों पर होनेवाले मतदान के परिणाम तथ्य रूप में दिये जायें, और मतदान होने की स्थिति में यह उल्लेख किया जायें कि कितने मत पक्ष में थे और कितने विरुद्ध।
- 4) कोई भी इतर-संसदीय गतिविधि अथवा कोई भी ऐसी चीज जो संसद/विधानसभा की सरकारी कारवाहियों में से निकाल दी गयी हो, प्रकाशित न की जाये।

(ख) 'पायालयों' के प्रसंग में

- 1) जगों के तथा वकीलों के नामों का उल्लेख किया जाये।

- 2) न्यायालय के आदेश का वह भाग, जिसमें यह बताया गया हो कि नया वारवाई की जानी है, प्रकाशित किया जाये परन्तु उपयुक्त भाषा में।
- 3) सेंसरशिप के नियमों का भतिक्रमण करनेवाली कोई सामग्री न छापी जाये।

4 समाचार, टिप्पणियाँ भयवा रिपोर्टें प्रकाशित करत समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जायें

- (क) हर समाचार तथा रिपोर्ट के बारे में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वह तथ्यों की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, और मुनी सुनायी बातों भयवा भयवाहो पर आधारित कोई बात न प्रकाशित की जाये।
- (ख) किसी ऐसी आपत्तिजनक सामग्री को, जो पहले प्रकाशित हो चुकी हो, फिर से ज्यो-का-त्यो छाप देने की अनुमति नहीं है।
- (ग) संचार के आधारभूत साधनों से सम्बन्धित कोई भी अनधिकृत समाचार भयवा विज्ञापन भयवा चित्र प्रकाशित न किया जाये।
- (घ) परिवहन भयवा संचार, आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति तथा वितरण, उद्योग आदि की सुरक्षा से सम्बन्धित व्यवस्थाओं के बारे में कुछ भी प्रकाशित न किया जाये।
- (ङ) किसी भी प्रकाशनाय सामग्री का सम्बन्ध भान्दोमनो तथा हिंसात्मक घटनाओं से नहीं होना चाहिए।
- (च) ऐसे उद्धरण, जो भयने प्रसंग से घलत हो तथा जिनका अभिप्राय गुमराह करना भयवा कोई विकृत भयवा गलत प्रभाव उत्पन्न करना हो, न प्रकाशित किये जायें।
- (छ) प्रकाशित सामग्री में इस बात का कोई संकेत न हो कि उस सेंसर किया गया है।
- (ज) नजरबन्द राजनीतिक व्यक्तियों के नामों का तथा इस बात का कि वे वहाँ नजरबन्द हैं कोई उल्लेख न किया जाय।
- (झ) कोई भी ऐसी सामग्री न प्रकाशित की जाये जिससे इस बात की सम्भावना हो कि
 - 1) विदेशों के साथ भारत के सम्बन्धों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा,
 - 2) जनतांत्रिक संस्थाओं के काम-काज में बाधा पड़ेगी,
 - 3) प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति राज्यपालों और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संस्थाओं की निंदा होगी,
 - 4) आंतरिक सुरक्षा तथा आर्थिक स्थायित्व के लिए खतरा उत्पन्न होगा,
 - 5) सशस्त्र सेना के सदस्यों भयवा सार्वजनिक नमचारियों के बीच भयवृद्धा उत्पन्न होगी,
 - 6) देश में कानून के आधार पर स्थापित सरकार के प्रति घना भयवा तिरस्कार की भावना जागृत होगी,

- 7) भारत के नागरिका के विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य तथा घृणा को भावना को बढ़ावा मिलेगा,
- 8) वह देश के भीतर किसी भी जगह काम रुक जाने तथा धीमा पड जाने का कारण बन जायेगी अथवा इस स्थिति को उत्पन्न कर देगी अथवा उसके लिए उकसावा देगी अथवा उसे उत्तेजित करेगी,
- 9) राष्ट्रीय ऋण के प्रति अथवा किसी भी सरकारी ऋण के प्रति सावजनिक विश्वास को जहें खोलसी होगी,
- 10) किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग को करो का भुगतान करने से इकार करने अथवा उसमें विलम्ब करने का प्रोत्साहन अथवा उकसावा मिलेगा
- 11) सावजनिक कमचारिया के विरुद्ध अपराधपूर्ण बल का प्रयोग करने का उकसावा मिलेगा,
- 12) लोगो को प्रतिव धकारी नियमो को तोडने का प्रोत्साहन मिलेगा ।

5 भाकाशवाणी के प्रसारणो समाचार एजेंसियो की रिपोटों तथा सरकार की ओर स सरकारी तौर पर जारी किये गये बयानो के उद्धरण प्रकाशित करने की अनुमति है, परन्तु हात यह है कि इस प्रकार के उद्धरण म जो कुछ कहा गया हो उसका सच्चा तथा यथाय विवरण प्रस्तुत करें और कोई भी चीज उसके उचित प्रसंग से अलग न की जाये या किसी भी प्रकार विवृत न की जाये ।

6 यदि किसी सवाददाता को कोई खबर किसी ऐसे स्रोत से मिली हो जो सरकारी अथवा प्रामाणिक नहीं है तो उसकी पुष्टि प्रेस सूचना अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है ।

7 यदि किसी अखबार, पत्र पत्रिका अथवा किसी अन्य दस्तावेज मे, केवल सम्पादकीय टिप्पणी को छोडकर, कोई ऐसी रिपोट, टिप्पणी अथवा कोई अन्य सामग्री प्रकाशित हो, जो इन मागदशिकाओ के शब्दा तथा उनके भाषय के प्रतिकूल हो, और यदि यह स्पष्ट हो कि वह केवल स्थानीय सवाददाता की दी हुई सामग्री पर ही आधारित हो सकती है तो उसके लिए स्थानीय सवाददाता को ही उत्तरदायी ठहराया जायेगा जब तक कि यह न सिद्ध कर दिया जाये कि सत्य अन्यथा है ।

8 ऐसी हर प्रमित सामग्री की प्रतिलिपि, जिसे पहले से संसर न कराया गया हो, प्रधान संसर के पास उसकी जानकारी के लिए भेज दी जाये ।

9 किसी समाचार, रिपोट अथवा टिप्पणी को प्रकाशित करना उचित होगा या नहीं, इसके विषय म यदि कोई गवा हा तो मुख्य संसर से परामश किया जाये ।

प्रकाशनार्थ नहीं

ध्याख्या 1—सरकार के किसी कानून या किसी नीति या किसी प्रशासनिक कारवाई को वैध उपायो से बदलवान या उसका निवारण करान के उद्देश्य से व्यक्त की गयी नापसन्दीयगी अथवा आलोचना को, और जिन वाता म भाषा-नाम्यधी भावनामा या प्रादक्षिक जन समुदाया या जातियो या सम्प्रदाया के बीच असमझ

उत्पन्न होता हो या जिनमें इस प्रकार का असामंजस उत्पन्न करने की प्रवृत्ति हो, उनको वैध उपायों से दूर कराने के उद्देश्य से उनकी धोर सकेत करनेवाले शब्दों को इस खण्ड के अभिप्राय की परिधि में आपत्तिजनक सामग्री नहीं माना जायेगा।

ध्याख्या 2—इस बात पर विचार करते समय कि कोई सामग्री विशेष इस अधिनियम के अन्तर्गत आपत्तिजनक है अथवा नहीं, ध्यान इस बात की धोर दिया जायेगा कि उन शब्दों, चिह्नों अथवा दृश्य अभिव्यक्तियों का प्रभाव क्या पड़ता है, न कि यह कि उस समाचार-पत्र अथवा समाचार पत्रों को छापनेवाले प्रेस के रखवाले या प्रकाशक अथवा संपादक का अभिप्राय क्या था।

10 जो कुछ पहले कहा जा चुका है उसे उदाहरणों से स्पष्ट कर देने के लिए यह सलाह दी जाती है कि निम्नलिखित से सम्बंधित कोई समाचार, रिपोर्ट तथा टिप्पणियाँ प्रकाशित न की जायें

- (क) ऐसी बातें जो सरासर भ्रम अथवा झूठी हो या जिनका उद्देश्य दूसरे को डरा धमकाकर अपना काम निकालना हो,
- (ख) इतर ससदीय गतिविधियाँ अथवा कारवाइयाँ, जैसे धरने, बैठकी हड़तालें, मंच की धोर भण्ड पढ़ना चिल्लाना, अध्ययन की भाषा का पालन करने से इकार करना, क्योंकि ये बातें कारवाइयों का भग नहीं हैं,
- (ग) ऐसी बातें जिनमें (प्रदेश, धर्म, नस्ल, भाषा अथवा जाति पर आधारित) विभिन्न जन-समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा अथवा मनमुटाव की भावना को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति हो,
- (घ) समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, प्रकाशनों, पुस्तकों से लिये गये ऐसे उद्धरण जो सेंसरशिप के नियमों का उल्लंघन करते हो,
- (ङ) वे बातें जिन्हें अध्यक्ष ने कारवाई में से निबलवा दिया हो,
- (च) ऐसी बातें जो विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बंधों को बढ़ावा देने में बाधक हो,
- (छ) ऐसी बातें जो देश की सुरक्षा तथा अखण्डता की आवश्यकताओं का प्रतिकूल प्रभाव डालती हो,
- (ज) ऐसी बातें जिनमें जनतांत्रिक संस्थाओं के काम-काज को ध्वस्त करने की प्रवृत्ति हो।

प्रकाशनाय नहीं

8 मार्च 1976 से आरम्भ होनेवाले सत्र के अधिवेशन की कारवाइयों के समाचार देने के सम्बंध में मागदर्शिकाएँ

1 सत्र एक सवसत्ताधारी संस्था है और, इसलिए, उसकी कारवाइयों की अपनी एक पवित्रता है। किसी भी दशा में जनता का स्वयं तथा सवसत्ताधारी संस्था होने का सत्र का स्वरूप बलवत् नहीं होने देना चाहिए। इसलिए कोई भी ऐसा समाचार रिपोर्ट अथवा टिप्पणी प्रकाशित न की जाये जिसमें सत्र की कारवाइयों की पवित्रता को दूषित करने का प्रयत्न किया गया हो या इन कारवाइयों को गलत अथवा विवृत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया हो।

2. सदन की कार्यवाहियों से सम्बन्धित समाचारों, रिपोर्टों तथा टिप्पणियों पर डी० आई० एस० आई० आर० 1971 का नियम 48 और उसके अन्तर्गत जारी किये गये कानूनी आदेश लागू होते हैं। 26 जून 1975 को जारी किये गये कानूनी आदेश 275 (ई), और डी० आई० एस० आई० आर० के नियम 48 के अन्तर्गत 12 अगस्त 1975 तथा 2 फरवरी 1976 को उसमें किये गये संशोधनों के प्रावधान इस प्रसंग में उपयुक्त हैं। इनकी परिधि में वे सभी समाचार, टिप्पणियाँ, अफवाहें तथा अन्य रिपोर्टें आ जाती हैं जिनका सम्बन्ध निम्नलिखित बातों से हो

- (क) उक्त नियमों के, जिनमें उनके अन्तर्गत जारी किये गये आदेश भी शामिल हैं, भाग तीन के नियम 31 तथा 33, भाग चार के नियम 36, 38, 39, 43, 46, 47, 48, 50, 51 तथा 52, भाग पाँच, भाग आठ तथा भाग नौ के प्रावधानों में से किसी का भी उल्लंघन अथवा तथाकथित अथवा निहित उल्लंघन, या
- (ख) इस प्रकार के उल्लंघन के सम्बन्ध में की गयी कोई कारवाई, या
- (ग) आन्तरिक सुरक्षा संरक्षण अधिनियम 1971 (1971 का 26वाँ अधिनियम) के प्रावधानों के अन्तर्गत की गयी कोई कारवाई, या
- (घ) संविधान की धारा 352 के अन्तर्गत 25 जून 1975 को राष्ट्रपति की आपात स्थिति की घोषणा, या
- (ङ) संविधान की धारा 359 के अन्तर्गत 26 जून 1975 को जारी किया गया राष्ट्रपति का आदेश, या
- (च) भारत प्रतिरक्षा अधिनियम 1971 (1971 का 42वाँ अधिनियम) के प्रावधानों के अन्तर्गत, या भारत प्रतिरक्षा (संशोधन) अधिनियम 1975 (1975 का 32वाँ अधिनियम) द्वारा संशोधित रूप में इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, या उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत की गयी कोई कारवाई, या
- (छ) कोई 'प्रतिकूल रिपोर्ट', उस परिभाषा के अनुसार, जो भारत प्रतिरक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के नियम 36 की धारा 7 में दी गयी है, या
- (ज) संविधान की धारा 356 के अन्तर्गत 31 जनवरी 1976 को तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में जारी की गयी राष्ट्रपति की घोषणा।

3. सदन की कार्यवाहियों के समाचार देते समय आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन की रोकथाम से सम्बन्धित अधिनियम 1976 में आपत्तिजनक बताया गयी बातों का भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस अधिनियम में आपत्तिजनक सामग्री की परिभाषा जिम रूप में की गयी है वह इस प्रकार है

आपत्तिजनक सामग्री का अभिप्राय उन सभी शब्दों, चिह्नों अथवा अन्य अभिव्यक्तियों से है

(क) जिसे इस बात की सम्भावना हो कि

- 1) भारत में या उसके किसी राज्य में कानून के आधार पर स्थापित सरकार के प्रति घृणा अथवा तिरस्कार की भावना उत्पन्न होगी या उससे प्रति अश्रद्धा की भावना को उत्साह मिलेगा और उसके

फलस्वरूप सार्वजनिक अव्यवस्था फैलेगी या फैलने की प्रवृत्ति पैदा होगी, या

- 2) किसी व्यक्ति को खाद्य सामग्री अथवा अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति अथवा वितरण में या आवश्यक सेवाओं में हस्तक्षेप करने का उत्साह मिलेगा, या
- 3) सशस्त्र सेनाओं अथवा सार्वजनिक व्यवस्था की बनाये रखने का दायित्व संभालने वाले सशस्त्र दल के किसी सदस्य को अपनी प्रतिबद्धता अथवा अपने कर्तव्य से विमुक्त होने का प्रलोभन मिलेगा, या इस प्रकार के किसी सशस्त्र दल में सेवा करने के लिए लोगों का भरती करने में विघ्न पड़ेगा या इस प्रकार के सशस्त्र दलों के अनुशासन पर कोई प्रभाव आयेगा।
- 4) विभिन्न धार्मिक, नस्ली, भाषाई अथवा प्रादेशिक जनसमुदायों अथवा जातिगत अथवा सम्प्रदायों के बीच शत्रुता, घृणा अथवा मनमुटाव की भावनाओं अथवा असामंजस्य का बढ़ावा मिलेगा, या
- 5) जनसाधारण में या जनसाधारण के किसी भाग में ऐसा भय अथवा घातक उत्पन्न होगा जिससे किसी व्यक्ति को राज्यसत्ता के विरुद्ध अथवा सार्वजनिक शान्ति के विरुद्ध अपराध करने की प्रेरणा मिले, या
- 6) किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी वृग अथवा समुदाय को किसी व्यक्ति की हत्या करने, कोई उपद्रव करने अथवा अन्य कोई अपराध करने का उत्साह मिले,

(ख) जो कि

- 1) भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष अथवा किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निन्दाजनक हो,
- 2) सरासर झूठ हो, अथवा झूठी हो, अथवा जिसका उद्देश्य किसी को बरा धमकाकर अपना काम निश्चालना हो।

एन० डी० एस० 12 यू० एन० आई० के सभी केन्द्रों तथा सभी प्राहकों के लिए भीरचदानी की धोर से

कल बहुत रात गये सेंसर कार्यालय ने हमें मौखिक रूप से निम्नलिखित नयी भागदशिकाओं की सूचना दी। ये आपकी जानकारी के लिए हैं, धोर इन्हें प्रकाशित न किया जाये

निम्नलिखित तीन मामला के बारे में कोई खबर न छापी जाये

- 1 सत्ता के आधामी अधिवेत्ता का काय,
- 2 सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री के चुनाव का मुकद्मा, धोर
- 3 जिन पार्टियों पर प्रतिबंध लगा हुआ है उनमें किसी की प्रतिनिधि का कोई भी बयान।

प्राप्तिकता

डी० ई० एल० 65 जनरल

सपादको के लिए परामश केवल आपकी जानकारी के लिए, प्रकाशनाय नहीं। प्राज सुबह डी० ई० एल० 4 के अन्तगत इससे पहले जारी किये गये परामश से आगे।

मुख्य संसर ने ससद की वारवाइया के बारे मे समाचार देने के सम्बन्ध मे निम्नलिखित भागदशिकाएँ भेजी हैं

- (क) मत्रियो के वक्तव्य पूण रूप मे या सक्षिप्त रूप मे प्रकाशित किये जा सकते हैं, परन्तु उसकी विषय वस्तु से संसरक्षिप के नियमो का अति-क्रमण नही होना चाहिए।
- (ख) किसी बहस मे भाग लेनेवाले ससद सदस्यो के भाषण किसी भी रूप मे या किसी भी ढग से प्रकाशित नही किये जायेंगे, परन्तु उनके नामो का और जिन दलो से उनका सम्बन्ध है उनके नाम प्रकाशित किये जा सकते हैं। बहस मे भाग लेनेवाले सदस्यों के नाम प्रकाशित करते समय इस बात का उल्लेख किया जाये कि उन्होंने किस मुद्दाव का समर्थन किया या विरोध।
- (ग) किसी विधेयक, मुद्दाव, प्रस्ताव आदि पर मतदान के परिणामो का समाचार यथाय रूप मे दिया जाये। मतदान होने की स्थिति मे इस बात का उल्लेख किया जाये कि कितने मत पक्ष में थे और कितने विरुद्ध।

सपादकगण हमसे मुख्य प्रेस सलाहकार की ओर से जारी की गयी निम्नलिखित भागदशिकाएँ आपकी जानकारी के लिए प्रसारित करने को कहा गया है (प्रकाशनाय नहीं)।

मौजूदा इमर्जेंसी मे अखबारो के लिए मार्गदशिकाएँ

आन्तरिक उपद्रव से भारत की सुरक्षा तथा उसके स्थायित्व के लिए उत्पन्न हो जानेवाले खतरे का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय इमर्जेंसी की घोषणा का यह तकाजा है कि खबरो तथा टिप्पणिया की व्यवस्था करने तथा उन्हें भेजने मे अत्यधिक सावधानी तथा सतकता बरती जाये। अखबारो की यह सलाह देना आवश्यक है कि वे अनधिकृत, शर जिम्मेदाराना या निराणाजनक खबरें, अटकन तथा अफवाहें प्रकाशित करने से सावधान रहें, साथ ही अखबारों को जन-साधारण के प्रति अपना दायित्व निभाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। अखबार इमर्जेंसी के दौरान सरकार का तथा जन-साधारण का एक सबसे सशक्त सहारा होते हैं। कोई भी जानकारी जिस ढग से छपी, प्रकाशित तथा प्रसारित की जाती है इसमें उन सागो को बेहद बल मिल सकता है जो देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।

आन्तरिक खतरे का मुकाबला करने के लिए जिस इमर्जेंसी की घोषणा की गयी है उसमें सरकार को मुख्यतः देश के भीतर के उा गुमराह और विध्वंसक तत्वा की ओर से चिन्ता है जो अपनी हरकतो से राष्ट्र की शान्ति तथा उसके स्थायित्व मे विघ्न

डालने की कोशिश कर सकते हैं। एव जनतांत्रिक देश में, जिसमें नागरिक राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों के प्रति पूरी तरह सजग हो, सरकार का उद्देश्य हर मामले में उन व्यापक तथा असाधारण शक्तियों पर निर्भर रहना उतना नहीं होता, जो उसे प्रदान की गयी हो, जितना कि राष्ट्र को इमर्जेंसी के कारणों से छुटकारा दिलाने के बुनियादी काम को पूरा करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाये रखने में देश की आवादी ने सभी हिस्सों का ऐच्छिक सहयोग प्राप्त करना।

सामान्य मार्गदर्शन

1 यदि कोई समाचार स्पष्टतः खतरनाक हो, तो अखबार उसे स्वयं ही न छाप कर मुख्य प्रेस सलाहकार की सहायता करें। यदि कोई शका हो तो उस खबर को निकटतम प्रेस सलाहकार के पास भिजवाया जा सकता है और भिजवा दिया जाना चाहिए।

2 यदि कोई सामग्री प्रकाशित करने से पहले जाँच के लिए भेज दी गयी हो तो प्रेस सलाहकार की सलाह को माना जाये।

3 यदि किसी मामले से सम्बंधित खबरों अथवा टिप्पणियों के प्रकाशन के विरुद्ध सलाह देते हुए मार्गदर्शन किया जा रहा हो, तो उस मामले का कोई उल्लेख तब तक न किया जाये या उसका कोई हवाला तब तक न दिया जाये जब तक कि उसके लिए नये सिरे से मजूरी न प्रप्त कर ली गयी हो, क्योंकि हमेशा समय से काम लिया जाना चाहिए और सनसनीसेज बातें छापने से बचना चाहिए, हम एक बार फिर दोहरा दें, छापने से बचना चाहिए। विशेष रूप से पोस्टर्स के विनो तथा क्षीपकों में इस बात का पालन किया जाना चाहिए।

4 अफवाहों का कोई प्रचार न किया जाये।

5 जब कोई दस्तावेज या फोटो चित्र सरकारी तौर पर जारी किया जाये तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसके साथ जो विवरण अथवा अखबार के लिए हिदायत भेजी जाये उसका आशय बाकी रखा जाये।

6 किसी भारतीय अथवा विदेशी अखबार में यदि कोई आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित हो चुकी हो तो उसे दुबारा प्रकाशित न किया जाये।

7 संचार के आधारभूत साधनों में सम्बंध में कोई भी अनपेक्षित खबर या विज्ञापन या चित्र प्रकाशित न किया जाये।

8 परिवहन अथवा संचार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तथा वितरण आदि की सुरक्षा से सम्बंधित व्यवस्था के बारे में कुछ भी प्रकाशित न किया जाये।

9 कोई भी ऐसी सामग्री प्रकाशित न की जाये जिससे सशस्त्र सेना के सदस्यों या सरकारी नौकरों में भीच अश्रद्धा की भावना पैदा हो सकती हो।

10 कोई भी ऐसी सामग्री प्रकाशित न की जाये जिससे भारत में कानून के आधार पर स्थापित सरकार के प्रति घृणा अथवा तिरस्कार उत्पन्न हो या अश्रद्धा की भावना को उत्साह मिले।

11 कोई भी ऐसी सामग्री प्रकाशित न की जाये जिससे भारत के निवासियों के विभिन्न वर्गों में भीच अश्रद्धा तथा घृणा की भावना को बढ़ावा मिलने की सम्भावना हो।

12 कोई भी ऐसी सामग्री प्रकाशित न की जाये जिसमे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जगह काम बंद हो जाने या इसकी गति धीमी पड़ जाने का कारण बन जाने की या उस स्थिति को वस्तुतः पैदा कर देने की उसके लिए उकसावा देने या उत्तेजना प्रदान करने की सम्भावना निहित हो।

13 कोई भी ऐसी सामग्री प्रकाशित न की जाये जिससे राष्ट्रीय ऋण के प्रति अथवा किसी भी सरकारी ऋण के प्रति सावजनिक विश्वास की जड़ें खोखली हो जाने की सम्भावना हो।

14 कोई भी ऐसी सामग्री प्रकाशित न की जाये जिससे किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के किसी वर्ग को बुरे का भुगतान करने से इकार करने या उसे टाल देने का प्रोत्साहन या उकसावा मिले।

15 कोई भी ऐसी सामग्री प्रकाशित न की जाये जिससे सावजनिक कमचारियों के विरुद्ध अपराधपूर्ण बल का प्रयोग करने के लिए भड़कावा मिलने की सम्भावना हो।

16 प्रतिकूल रिपोर्ट का अभिप्राय किसी भी ऐसी, सच्ची या झूठी रिपोर्ट, वक्तव्य अथवा अन्य रिपोर्ट से है जो या जिसका प्रकाशन, ऊपर बताये गये किसी भी हानिकार काय को करने के लिए उकसावा हो।

प्रलंबारो के लिए सामान्य मागदर्शिकाएँ

प्रलंबारो को सलाह दी जाती है कि संदेश, समाचार, रिपोर्टें तथा टिप्पणियाँ आदि भेजते समय निम्नलिखित मुख्य बातों का ध्यान रखें।

- 1 जनतान्त्रिक संस्थाओं के काम काज में विघ्न डालने की कोई भी कोशिश।
- 2 सदस्यों को इस्तीफा देने पर मजबूर करने की कोई कोशिश।
- 3 आंदोलनों तथा हिंसात्मक घटनाओं से सम्बन्धित कोई भी बात।
- 4 सशस्त्र सेना अथवा पुलिस को भड़काने की कोई कोशिश।
- 5 देश की एकता को खतरे में डालकर विघटन तथा सामुदायिक भावेगों को बढ़ावा देने की कोई कोशिश।
- 6 नेताओं के विरुद्ध झूठे आरोपों की रिपोर्टें।
- 7 प्रधानमंत्री के पद को निंदित करने की कोई कोशिश।
- 8 सामान्य काम काज में विघ्न डालने के लिए कानून तथा व्यवस्था को खतरे में डालने की कोई कोशिश।
- 9 आन्तरिक स्थामित्व, उत्पादन तथा आर्थिक सुधार की सम्भावनाओं को खतरे में डालने की कोई कोशिश।

संसद का फोन

सीरिया के दूतावास पर अरब छात्रों के बमबाद करने के बारे में केवल 'समाचार' की भेजी हुई खबर छपी जाये।

5-6-1976

सैंतर से श्री राघवन

भा.प्र. प्रदेश हाईकोर्ट के जजों के तबादले के बारे में कोई खबर प्रकाशित न की जाये।

8 जुलाई, 1976

5 30 बजे शाम

सैंतर के दफ्तर से

सैंतर से श्री मेहरसिंह ने फोन करके कहा—समझा जाता है कि श्री जयप्रकाश नारायण ने प्रधानमंत्री के कोष से जयप्रकाश के इलाज के लिए हायलिसिस यंत्र खरीदने के लिए प्रधानमंत्री के योगदान के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री को लिखा गया अपना पत्र प्रकाशन के लिए भेजा है। भापसे अनुरोध है कि इस खबर का इस्तेमाल न करें।

सैंतर रूम से आय

इसके (जयप्रकाश के पत्र के) सम्बन्ध में 'समाचार' खबर भेजेगा। उसे प्रकाशन की मजबूरी द दी गयी है।

(ह०)

16-6 1976

समाचार संपादक

सैंतर के दफ्तर से फोन (जे० एन० सिन्हा)

भाज दिल्ली में मित्रो प्रतिनिधिमण्डल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते तथा उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पी० आई० बी० ने सामग्री भेजी है। इस सम्बन्ध में कृपया कोई आलोचनात्मक टिप्पणी न की जाये।

1 जुलाई, 1976

सैंतर का सन्देश

अगर एम० एन० एफ० के नेता लालबेगा कोई बयान जारी करें तो यह सैंतर के पास भेज दिया जाये।

(ह०)

2 7 1976

समाचार संपादक

सैंतर का टेलीफोन

असवार में चांस साबरामा के जाने में, जो एक अंतराष्ट्रीय घोषणा है और दिल्ली में घोषणाही और जहर देने के इलाज में पकड़ा गया है। कोई खबर न छापी जाये। यह टेलीफोन श्री भट्टाचार्य न लिया था।

6 जुलाई, 1976

उप मुख्य सैंतर आय का फोन

मुगहा में इसाइली हमले के बारे में कोई खबर, टिप्पणी या चित्र 14 जुलाई तक न छापा जाये। विशेष रूप से इम्फादली बारबाई की प्रशंसा, बरन और उन उच्चि ठहराने की कोशिश न की जाये।

8 जुलाई 1976

सैंसर का फोन (राघवन)

अगर कोई सवाददाता तटस्थ पूल सम्मेलन से किसी वाक् भाउट के सम्बन्ध में खबर भेजे तो उसे पहले सैंसर करा लिया जाये ।

(ह०)

10 7 1976

समाचार संपादक

सैंसर का सदेश

वाशिंगटन में आनेवाली इस आशय की कोई खबर न छापी जाये कि भ्रम-रीका के धनी व्यापारी श्री कुमार पाट्टार का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है ।

(ह०)

14 जुलाई, 1976

समाचार संपादक

प्रतिलिपि संपादक को

सैंसर का फोन

देश में कीमतों की स्थिति से सम्बन्धित खबरें, टिप्पणियाँ या संपादकीय पहले सैंसर करा लेने के लिए भेजे जायें ।

(ह०)

17 7 1976

समाचार संपादक

यह बात कीमतों गिरने से सम्बन्धित रिपोर्टों पर लागू नहीं होती (सैंसर से श्री ठुकराल) ।

सैंसर का सदेश

जयप्रकाश के बारे में कोई समाचार न छापा जाये ।

20 जुलाई, 1976

सैंसर का फोन (राघवन)

वृषभा उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम और शिक्षा वर के धारकों को बुराई करत हुए कोई खबर या टिप्पणी या संपादकीय न छापाएँ ।

(ह०)

28 7 1976

समाचार संपादक

सैंसर का निर्देश

1 मुख्य सैंसर की एक हिदायत के विरुद्ध निली हार्डवोट में दायर की गयी स्टेटसमन की रिट के बारे में कुछ भी न छापा जाये ।

2 जम्मू व कश्मीर में लागू किये गये अध्यादेशों की बयानों के सम्बन्ध में कोई खबर या टिप्पणी न छापी जाये ।

(ह०)

29 7 1976

19 76

सैंसर से श्री राधवन

भा प्र प्रदेश हाईकोर्ट के जजों के तबादले के बारे में कोई खबर प्रकाशित न की जाये।

8 जुलाई, 1976

5 30 बजे शाम

सैंसर के बदतर हैं

सैंसर से श्री महरसिंह ने फोन करने कहा—समझा जाता है कि श्री जयप्रकाश नारायण ने प्रधानमंत्री के बीच से जयप्रकाश के इलाज के लिए दायनितिस वत्र खरीदने के लिए प्रधानमंत्री के योगदान के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री को लिखा गया अपना पत्र प्रकाशन के लिए भेजा है। आपसे अनुरोध है कि इस खबर का इस्तेमाल न करें।

सैंसर रम से धार्य

इसके (जयप्रकाश के पत्र के) सम्बन्ध में 'समाचार' खबर भेजेगा। उसे प्रकाशन की मजूरी दे दी गयी है।

16-6 1976

(ह०)

समाचार संपादक

सैंसर के बदतर से फोन (जे० एन० सिंह)

आज दिल्ली में मित्रो प्रतिनिधिमण्डल के साथ एक सम्मेलन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस सम्मेलन तथा उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पी० आई० बी० ने सामग्री भेजी है। इस सम्बन्ध में कृपया कोई आलोचनात्मक टिप्पणी न की जाये।

1 जुलाई, 1976

सैंसर का सन्देश

अगर एम० एन० एफ० के नेता सालडेंगा कोई बयान जारी करें तो वह सैंसर के पास भेज दिया जाये।

27 1976

(ह०)

समाचार संपादक

सैंसर का टेलीफोन

अखबार में चार्ल्स सोबराज के बारे में, जो एक भारतीय धोखेबाज है और दिल्ली में घोषाघड़ी और जहर देने के इन्जाम में पकड़ा गया है कोई खबर न छापी जाय। यह टेलीफोन श्री भट्टाचार्य ने लिया था।

6 जुलाई, 1976

उप-मुख्य सैंसर भाव का फोन

मुगादा में इत्यान्ती हमले के बारे में कोई खबर, टिप्पणी या चित्र 14 जुलाई तक न छापा जाये। विरोध रूप से इत्यान्ती बारबाई की प्रणामा करत और उम उचित ठहराने की कोशिश न की जाय।

8 जुलाई 1976

सैंसर का फोन (राघवन)

अगर कोई सवाददाता तटस्थ पूल सम्मेलन से किसी वाक भाउट के सम्बन्ध में खबर भेजे तो उसे पहले सैंसर करा लिया जाये ।

(ह०)

10 7 1976

समाचार संपादक

सैंसर का सन्देश

वाशिंगटन से आनवाली इस आशय की कोई खबर न छापी जाये कि भमरीका के धनी व्यापारी श्री कुमार पोद्दार का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है ।

(ह०)

14 जुलाई, 1976

समाचार संपादक

प्रतिलिपि संपादक को

सैंसर का फोन

देश में कीमतों की स्थिति से सम्बन्धित खबरें, टिप्पणियाँ या संपादकीय पहले सैंसर करा लेने के लिए भेजे जायें ।

(ह०)

17 7 1976

समाचार संपादक

यह बात कीमतें गिरने से सम्बन्धित रिपोर्टों पर लागू नहीं होती (सैंसर से श्री दुकराल) ।

सैंसर का सन्देश

जयप्रकाश के बारे में कोई समाचार न छापा जाये ।

20 जुलाई, 1976

सैंसर का फोन (राघवन)

कृपया उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम और शिक्षा-रक्ष के बारे में उनकी बुराई करते हुए कोई खबर या टिप्पणी या संपादकीय न छापी ।

(ह०)

28 7 1976

समाचार संपादक

सैंसर का निर्देश

1 मुख्य सैंसर की एक हिदायत के विरुद्ध दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गयी स्टेटसमन की रिट के बारे में कुछ भी न छापा जाय ।

2 जम्मू व कश्मीर में लागू किया गया अध्यादेश की बधना के सम्बन्ध में कोई खबर या टिप्पणी न छापी जाये ।

(ह०)

29-7 1976

समाचार संपादक

सर्विस नम्बर 2/8/7/2/1 (बगलौर/विजयवाड़ा/मद्रास/बम्बई/दिल्ली)
हैदराबाद 30 जुलाई

हैदराबाद के श्री भार० श्रीनिवासन की धोर से बगलौर के श्री टी० भार० के नाम और सभी समाचार संपादकों के नाम (सभी केन्द्रों के) प्रतिलिपि।

श्री टी० नागो रेड्डी की प्रत्येष्टि के बारे में समाचार प्रकाशित करने के बारे में सेंसर की धोर से निम्नलिखित हिदायतें दी गयी हैं

"हमें खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि स्व० श्री टी० नागो रेड्डी की प्रत्येष्टि की खबर संक्षिप्त रूप में छापें। उसमें शव के पोस्टमार्टम, उनके प्रण्डरप्राण्ड जीवन और प्रत्येष्टि के समय उपस्थित लोगों की संख्या आदि का उल्लेख न करें।"

सेंसर का फोन (राघवन)

विनोबा भावे से सम्बंधित किसी भी खबर को पहले सेंसर करा लें।
9 अगस्त, 1976

सेंसर के दफ्तर से श्री ठुकराल

राज्यसभा के सदस्य श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी के बारे में इस घातक की कोई खबर या टिप्पणी न छापी जाये कि प्राज्ञ ससद में उन्होंने व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया था, ससद के प्रसंग में उनसे सम्बंधित कोई ग्रन्थ रिपोर्ट भी प्रकाशित न की जाय।
10 8 76

सेंसर का फोन (पारधी)

जेल सुधार के बारे में लोकसभा में उठाये गये प्रश्न के सम्बंध में कुछ न छापे जाये।

11 8-1976

(ह०)

समाचार संपादक

सेंसर का फोन

जमायते-उल्माए हिंद में कुछ प्रस्ताव पास किये हैं। एक प्रस्ताव लेबनान में सीरिया के हस्तक्षेप के बारे में है। इस प्रस्ताव को छापने में पहले सेंसर करा लें।

(ह०)

24 8 1976

समाचार संपादक

श्री राघवन, सेंसर

ससद की प्राज्ञ की कारवां छापने में पहले सेंसर करा लें।

(ह०)

1 सितम्बर, 1976

समाचार संपादक

सेंसर से

भारत की बार कीसिस के अध्यक्ष राम जैठमरानी के बारे में जो दृग समय प्रमरीका में है सभी खबरें छापने में पहले सेंसर करा ली जायें।

(ह०)

6-9 1976

समाचार संपादक

संसदीय कार्य

पञ्जाब के परिवहन राज्य मंत्री श्री दिग्गज सिंह दलेवे ने पञ्जाब हाइवे पर परिवहन विवाद के सम्बन्ध में विधानसभा में एक प्रश्न पेश किया है जिसमें प्रस्तावित पट्टीगढ़ के बीच एक गलियारा का उल्लेख है। इस गलियारे के बारे में सारे उल्लेख बाट दिये जायें।

(१०)

9 सितम्बर, 1976

समाचार संपादक

प्रतिलिपि संपादक को

संसदीय कार्य (भा. रा. प्रश्न)

विमान का अपहरण करनेवालों के नाम, राष्ट्रीयता तथा उनके इरादों के बारे में सही-सही हाल पर आधारित कोई घटकसूचना की संवरण प्रकाशित की जाय।

(१०)

11 सितम्बर, 1976

गिरिजा कक्कार

प्रतिलिपि संपादक को

संसदीय कार्य और सम्बन्ध

संसदीय कार्य के विभिन्न पट्टीगढ़ों में सम्बन्धित सारी खबरें संसदीय के लिए भेजी जायें।

(१०)

15 9 1976

ए. पी. कक्कार

समाचार संपादक

संसदीय कार्य के दफ्तर से श्री ठाकुरदास का फोन

समाचार प्रसार के विषयक स्व. श्री नाथी रंजीत सिंह का समाचार प्रसार के सम्बन्ध में विधानसभा के मानवार्थ के सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध बाट में जो मित्र प्रश्न हैं, उसकी कारवाई प्रकाशित की जाय।

(१०)

20 सितम्बर, 1976

समाचार संपादक

प्रतिलिपि संपादक

समाचार संपादक

नई दिल्ली व्यूरो

देख

सेंसर का फोन (ए० पी० सिंह)

जयगढ़ किले में दफन खजाने की खोज के बारे में कोई खबर सेंसर को दिसाये बिना न छापी जाये।

21 सितम्बर, 1976

प्रतिलिपियाँ संपादक

न्यूरो

सभी चौफ सब

(ह०)

त्रिपाठी

सब-एडिटर

श्री लक्ष्मीचंद सेंसर

कृपया डाक सुदर के बारे में कोई घटकलबाजी की या सनसनीखेज खबर न छापें क्योंकि उससे छानबीन के काम में बाधा पड़ सकती है। इस सम्बंध में आपसे अनुरोध है कि आप वही छापें जो सरकारी तौर पर कहा जाय।

29 9 1976

(ह०)

एस० के० वर्मा

समाचार उप-संपादक

सेंसर का सन्देश

विदेश मंत्रालय भारत पाक वार्ता के बारे में एक बयान जारी कर रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप किसी टिप्पणी या संपादकीय के बिना केवल उसका सरकारी विवरण ही छापें।

7 10 1976

(ह०)

ए० पी० लक्ष्मण

समाचार संपादक

के० बी० शर्मा सेंसर का फोन

कृपया पंजाब की घाटीवाल मिल में हड़ताल के बारे में कोई खबर न छापें।

6-10 1976

एस० के० वर्मा

समाचार उप-संपादक

श्री रतन सेंसर का फोन

उड़ीसा के ३ कांग्रेसी नताग्राम, जिनमें केन्द्रीय मंत्री जे० बी० पटनायक भी शामिल हैं, पार्टी के आमनात के बारे में पुरी में एक बयान दिया है। इस सेंसर करा लिया जाये।

12 10 1976

शिवदास

चौफ सब

सेंसर का फोन

नेल प्रगल्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट छापने से पहले सेंसर को भेजी जाय।

12 10-1976

(ह०)

ए० पी० मकगना

समाचार संपादक

सैंसर ठुकराल का सदेश

लुसाका में, जहाँ रक्षामंत्री बसीलाल ठहरे हुए थे, बम फटने की आशंका के बारे में कोई खबर न छापी जाये।

(ह०)

14 अक्टूबर, 1976

शिवदास
चीफ सब

सहमीचब सैंसर

ईरान की घमरीकी हथियारों की बिक्री के बारे में सारी खबरें और संपादकीय सहित सारी टिप्पणियाँ छापने से पहले सैंसर करा ली जायें।

(ह०)

16 10 1976

समाचार संपादक

सैंसर का फोन

कुछ चुने हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाली नागरिकों पर भारत सरकार की ओर से लगायी गयी पाबंदियों के बारे में कोई खबर और इस विषय में नेपाली सरकार तथा भारतीय राजदूत के बयान छापने से पहले सैंसर कराने के लिए भेजे जायें।

(ह०)

16 10 1976

ए० पी० सबसेना
समाचार संपादक

सैंसर का फोन

फोड़ों से मिलने के लिए नागा शांति परिषद् के प्रतिनिधिमंडल के इंग्लैंड जान के बारे में कोई खबर न छापी जाय।

20 10 1976

ए० पी० सबसेना

उप मुख्य सैंसर, पिस्ले

हैदराबाद में 29 अक्टूबर से 7 नवम्बर तक चौथा एशियन बर्डमिंटन टूर्नामेंट होना जा रहा है। इसमें चीनी टीम के भाग लेने की खबर को बहुत न उछाला जाये (न विवरण के रूप में, न खास फोटो छापकर)।

(ह०)

21 10 1976

ए० पी० सबसेना
समाचार संपादक

सैंसर से जे० एन० सिन्हा

जम्मू कश्मीर के नये मंत्रियों के गणध-ग्रहण के प्रश्न पर जो आज होने वाला था, केवल जम्मू कश्मीर सरकार की प्रस विज्ञप्ति और मुख्यमंत्री का बयान छाप जाय। उसके बारे में कोई टिप्पणी जैसी रिपोर्ट न छापी जाय।

(ह०)

4 11-1976

ए० पी० सबसेना
समाचार संपादक

संसद का सदन (सहमी शहर)

ए० आई० सी० सी० के अधिवेशन में सम्बन्धित सोनी और महेश जोशी के भाषण न छापे जायें ।

प्रधानमंत्री के भाषण के लिए भी 'समाचार' की भेजी हुई खबर को ही नमूना बनायें ।

21 नवम्बर, 1976

(ह०)
गिबदास

संसद के बपतर से श्री राधवन का फोन

राज मध्य प्रदेश की विधानसभा में पेश किये गये पहले बजट की खबर में मे नेशनल हेराल्ड का चप्पा दिये जाने का हवाला काट दिया जाय ।

30-11 1976

(ह०)
एस० बनर्जी

जे० एन० सिन्हा (संसद)

दिल्ली की बजौरपुर जैसी वस्तिवा में औद्योगिक योजनाओं के लिए नवयुवक उद्यमियों के टक्स इन से इकार कर देने के बारे में केवल सरकारी विजिति ही इस्तेमाल की जायें ।

4 12-1976

(ह०)
ए० पी० सक्सेना
समाचार संपादक

संसद का सदन (वारधी)

14 दिसम्बर की श्री सजय गाम्भी का ज मदिरस मनान के बारे में मुख्यमंत्रियों या कांग्रेसी नेताओं का कोई बयान इस्तेमाल न किया जायें ।

9 दिसम्बर, 1976

(ह०)
शिवनाथ

जे० एन० सिन्हा (मुख्य संसद का बपतर)

अमरीका से भारत को 'स्पाईहॉक' जेट फाइटर विमानों की सप्लाई के बारे में कोई खबर न छापें । केवल सरकारी घोषणा ही इस्तेमाल की जायें ।

10 दिसम्बर 1976

प्रतिलिपि संपादक को

सहमीकांत (संसद)

दक्षिण अफ्रीकी भारतीय परिषद के अध्यक्ष श्री ए० एम० मून्ना का रंगभेद के बारे में कोई बयान या भाषण आपके प्रतिष्ठित पत्र में न छपने पायें ।

16 12 1976

(ह०)
समाचार संपादक

संसद से श्री रतन

पार्टी के सदस्य की खींचातानी और भगडो और कांग्रेस तथा युवक कांग्रेस की टक्कर के बारे में कोई खबर न छपी जाये।

(ह०)

19 12 1976

ए० पी० सक्सेना

संसद के दफ्तर से आनन्द पारधी का फोन

पाकिस्तानी दूतावास ने जिन्ना की जन्मशती के अवसर पर किसी समारोह का आयोजन किया है। एक समारोह आज इण्डिया इण्टरनैशनल सेंटर में है। एक और समारोह में हमारे राष्ट्रपति की 25 दिसम्बर की राष्ट्रपति भवन में जिन्ना पदक दिया जायेगा। हो सकता है कुछ और समारोह भी हों। इन समारोहों की खबरें जरा नीचे स्तरों में दी जायें।

(ह०)

23 12 1976

ए० पी० सक्सेना
समाचार संपादक

श्री मेहरसिंह (संसद) का फोन

मैमर की मजूरी लिये बिना उत्तर पूर्वी प्रदेश में विद्रोह के बारे में कोई खबर या लेख न छपा जाये।

(ह०)

23 12 1976

समाचार संपादक

संसद से पारधी

आयनामाइट बाण्ड के सिलसिले में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में दिया गया डा० कुमारी हुसगोल का बयान न छपा जाय।

(ह०)

23 12-1976

समाचार संपादक

के० बी० शर्मा (संसद)

रायपुर में लगाये जानेवाले टेलीविजन टावर के ढह जाने के बारे में कृपया कोई समाचार न छापें।

(ह०)

28 12 1976

ए० डी० जोशी

मुख्य संसद के दफ्तर से

अपीली नेशनल कांग्रेस व श्री एम० भूता व बयानों का जो अपीली जनता की आकांक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरी तरह प्रचार किया जाय। उ होने बल भाषास में एक बयान दिया था और शायद ही एक और बयान देनेवाले हैं।

दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने पिछले मगटन दक्षिण अफ्रीकी भारतीय परिषद के अध्यक्ष श्री ए० एम० मूला के साथ घ में पहले जो हिदायत ली गयी थी, वह अब भी लागू है ।

(१०)

4-1 1977

समाचार मगटन

श्री भाय (उप-मुख्य सेंसर)

नवाग्रा की मीटिंग सहित कांग्रेस तथा युवक कांग्रेस व पार्टी के कार्य के मामलात के बारे में सारी खबरें छापने में पहले छपका सेंसर कराने के लिए भेजी जायें ।

(१०)

8 जनवरी, 1977

एम० के० बर्मा

समाचार उप-सपाक

अनुक्रमणिका

- अप्रधाल, जस्टिस फैसला 99
- अप्रधाल, शेख इमजेंसी पर प्रतिज्ञा 69, जयप्रकाश की निष्ठा करने से इकार 70, श्रीमती गांधी से समझौता 69
- अप्रधाल, पख्ताहीन मली जून 1975 की इमजेंसी का ऐलान 48-49, देहान्त 168, मरने के बारे में अफवाह 168, विपक्ष का धरा और अपील 30, श्रीमती गांधी के इस्तीफे की मांग पर उनके विचार 30, श्रीमती गांधी का प्रभाव 48
- अप्रधाना, के० बी०, जस्टिस फैसला 100
- अप्रधालो का गला घाटा जाना पश्चिमी देशों में प्रतिज्ञा 58-59 बिजली काट देने की तरकीब 50-53, सेंसर-शिप में सख्ती 112-115
- अप्रधालो की सेंसरशिप 62-87 96, 99, अप्रधालो के लिए भागदंडिकाएँ 60, चुस्ती 53, डील 161, दुरुपयोग 144 अप्रधालो का विरोध 60, बिजली का काटा जाना 50, बिहार में 57, लागू होना 50, विदेशी अप्रधालो के आने पर गक 60
- इडिया एक्मप्रेस जयप्रकाश और भार० एस० एस० के खिलाफ प्रस्तावित कारवाई की रिपोर्ट 36-37, दबाव 92, सताया जाना 114
- इदिरा गांधी की चाडाल चौकडी मुख्य सदस्य 18-19
- इदिरा की व्यक्ति पूजा स्थायी बनाने की काशिश 42, 91-92
- इमजेंसी कारण 73, घोषणा के बाद मन्त्रिमण्डल की मजूरी 51, जून 1975 में घोषणा 48-58, बुद्धिजीवियों का 2 अक्षुण्णर वाला विरोध 94-95, विनोबा भावे का बयान 94, श्रीमती गांधी की सफाई 52, ससद से बढाने की मजूरी 122
- इमजेंसी के नदी नज़रबन्दी में मौत 90, बरताव 56-57, 89, यातनाएँ 90, 126-134
- इमजेंसी का धाबा अडरगाउड पत्र 102, गुजरात में नरमी 55, छात्रों का विरोध 101, जम्मू-कश्मीर में नरमी 69-70, तमिलनाडु में विरोध 55-56 पंजाब में 54, 71, पश्चिम बंगाल में 56, राजनीतिक सगठनों पर पाबन्दी 69, राज्यों में 54-57, विदेशी पत्रवाग पर 57-58, विदेशों में पत्रिका 58-59, हरियाणा में 54
- आधिक लाभ भूटे दावे 102-103

इमजेंसी मे गिरपतारियाँ मुर्दे के नाम
वारण्ट 54, सख्या 51, 71

इमजसी डील 161 162, पश्चिमी देशो
के अलबारा मे आलोचना 58, रहस्य
का परदा 45, सुझाव 44

इमाम जामा मस्जिद भूमिका 167,
विरोध 93

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फमला निष्कर्ष
14 श्रीमती गांधी की चिन्ता 13 14,
सशत स्थगन की मजूरी 16, सुप्रीम
कोर्ट मे सशत स्थगन की मजूरी 42,
सुप्रीम कोर्ट मे अपील की सुनवाई
86 87, सुप्रीम कोर्ट मे उसका रद्द
किया जाना 97

श्रीयोगिक शांति स्थापना 103-104

बपूर, धनपान उनकी भूमिका के बारे
मे श्रीमती गांधी की सफाई 31, उनकी
भूमिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का
फमला 15, घबन से सम्बन्ध 20

बहुगुणा का हटवाने मे हाथ 116 117
कांग्रेस पार्टी 1977 के चुनावों के बारे
मे झगड़े 177 180, गौहाटी अधि
वेग 152, पटौगढ अधिवेशन 119
मरीग मे बम्प 66, पसा जमा करन
मे बटिनाई 166 मनिफेस्टो 169

कांग्रेस फार डेमांडेमी, (सी०एफ०डी०)

मनिफेस्टो 160, स्थापना 165

कांग्रेस मे दूज (1969) श्रीमती गांधी
के दीर्घ-चिन्ता 66, टक्कर का भूमिका
26-27

कानिग यक्षिग बम्पा जगजीवनराम के
दुस्ती के पर प्रभाव 165

किशनचन्द दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर
इमजेंसी की घोषणा की पहले से जान
कारी 45, भूमिका 48, सजय का
उन पर प्रभाव 38

फना, हमराज चीफ जस्टिस न बनाया
जाना 167, मीसा वाले मुकदमे में
बहुमत से अलग फसला 125

गांधी, इंदिरा अन्धकार की तरफ रबथा
32-33, आर्थिक 'प्रगतिशीलता 65
66, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फमला
15, इलाहाबाद के फैमल पर प्रति-
क्रिया 15, इमजेंसी की घोषणा की
याजना 44 45, 1977 के चुनाव 166
174, काग्रस ससदीय दल का समयन
38 40, चह्नाण का समयन 25,
चुनाव (1977) मे हार 174, चुनाव
के नतीजो से पहले सुरक्षा का प्रवच
173 चुनाव गठजोड के बारे मे 162,
चुनाव मे भ्रष्ट आचरण 15, जग
जीवनराम के साथ सम्बन्ध 24 25,
जगजीवनराम से टक्कर 29, जग
जीवनराम का इस्तीफा 165, जननत्र
का दिशावा 62, जस्टिस मिनहा से
टक्कर 31, डिक्टेटरिडग 52 डिक्टेटर
चनेने की तमना 49 डिक्टेटर हो
का आगप 160, दुविधा 17 18
गहम मे तुलना 45, पानिमी देगा का
प्रतिनिधता पर मुस्ला 59, चरपन की
तमना 92 चमीनान का सनाह 34,
योग गुन्ना कायनम 60 66 मरिया
का मरुधा पर धरुन 115 116
मार्गनि रति पर राय 24 मुखी

कांग्रेस की करारी हार 176, जनता
सदर 171, जनता-सी० एफ० डी०
की जीत 176-177, जाता सी० एफ०
डी० को ग्राम लोगो का समर्थन 171,
तीजे निकलने से पहले की जीत
तोड़ 173-174, पश्चिमी देशों का
मूल्यांकन 172, टलने की अपवाहें
167-168, सजय की हार 174
श्रीमती गांधी की मुहिम 170-171
चुनाव 1967 के कांग्रेस की हार 19,
कांग्रेस के प्रतिष्ठित बोट 169, चुनाव
(1976) का टलना 119, चुनाव
1971, श्रीमती गांधी के बारे में 66
चौधरी, ए० बी० ए० गनीयाँ (पश्चिम
बंगाल के मंत्री), इमजेंसी का दुह
पयोग 56

जगमोहन डी० डी० ए० के प्रधान,
भूमिका 139

जगजीवनराम भाषावा 53, इनका
टैक्स का बकाया 25, इमजेंसी के बाद
चीकसी 53, इमजेंसी की घोषणा पर
भावचय 51, इस्तीफे के दिन प्रेमबान्केस
164 उत्तराधिकारी नियुक्त करने के
श्रीमती गांधी के अधिकार पर विचार
29, कांग्रेस के नेताओं की नज़र में
26, कांग्रेस पार्टी में चौधराय पर
प्रहार 116, कांग्रेस फार डेमोक्रेसी,
स्थापना 165, कांग्रेस से इस्तीफा
164, भूमिका 31, मुवा तुर्कों की
उनसे निराशा 43, मुवा तुर्कों से भल
जाल 29, लोकसभा के चुनावों के
प्रसंग में 169, लोकसभा में इमजेंसी
का प्रस्ताव रखना 73-74 दक्षिण
हीनता 52-53, श्रीमती गांधी के साथ

सम्बन्ध 24-25, श्रीमती गांधी की
सलाह 24, श्रीमती गांधी से भेंट
164, श्रीमती गांधी से टक्कर 29
'जनसत्ता या डिक्टेटरशिप' का नारा 160,
168

जनता पार्टी अकरालियो और मानसवादी
कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चुनाव लड़ने
का समझौता 162, चुनाव प्रचार की
गुरुप्राप्त 163, पैसे की कमी 167,
मैनिफेस्टो 169, मारारजी का प्रधान
मंत्री चुना जाना 180, 181, स्थापना
160, सांभल कार्यक्रम 160

जयप्रकाश नारायण गुर्दे की बीमारी की
सका 109, गिरफ्तारी और नज़रबंदी
50, गिरफ्तारी के समय कहे गये
शब्द 50, चन्द्रशेखर के यहाँ 24 जून
का भोज 44, जनता पार्टी को छापी
वाद 160, जैन से भागना 64, दिल्ली
में दिलावटी शांति का दिखाया जाना
65, नज़रबन्दी के दौरान सलूब 64
65, नज़रबन्दी की संपादना 47, परोल
रद्द 110, प्रधानमंत्री पद के लिए
जगजीवनराम का समर्थन 25, बिहार
प्रान्तेलन 22 मुजीब के डिक्टेटरी
अधिकारों के बारे में 88, मुहिम 22,
योजना उनकी गिरफ्तारी की 37,
योजना उनके खिलाफ कारवाई की
36-37, रिहाई पर प्रेम काँग्रेस 108,
162, लोक सभा समिति की स्थापना
की घोषणा 46, विपक्ष का देना 22
23, विपक्ष की एकता की ललकार
22, विपक्ष की 25 जून 1975 की
मीटिंग में 46, श्रीमती गांधी का झूठा
प्रचार 66 श्रीमती गांधी के बारे में
राम 64, श्रीमती गांधी के हथकड़ों के
बारे में 110, श्रीमती गांधी की

- नागरवाला बाड 113 114, श्रीमती गांधी का उसमें हाथ 29
- नागरवाला रुस्नम सोहराब रहस्यमय मोत 29
- नय्यर, कुलदीप (लेखक) गिरपतारी 71, नजरबन्दी के बारे में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला 96
- नारग, कुलदीप फिनिपीस के सेंसरशिप के नियम हासिल करना 36, सजय का विश्वासपात्र 36
- नेहरू, जवाहरलाल जनतांत्रिक रख 45, 78, डिक्टेटर बन जाने का खतरा 49 56, विपक्ष की ओर रवया 31
- पत्रकार मान्यता पर पाबंदिया 113
- पाञ्चजन्य बंद किया जाना 54
- प्रशासन-सम्बन्धी सुधार कोरेवादे 104 105
- फर्नांडीज, जॉज अण्डरगाउण्ड संगठन 70, आखिरकार गिरपतारी 135, कानाफूसी की मुहिम की परवी 70, बडौदा डायनामाइट कांड 146, बडौदा डायनामाइट कांड का मुकदमा वापस 182 183
- फर्नांडीज लारेंस यातनाभा की कहानी 127 130
- बसीलाल इद्र गुजराल की निंदा 35
- इमर्जेंसी की घोषणा की योजना की जानकारी 45, इमर्जेंसी कौंसिल में भूमिका 61, पार्टी की उनके रिखाफ कारवाई 179 भूमिका 37, लम्बी चौड़ी डीमें 47, श्रीमती गांधी की चाण्डाल चौकड़ी में 18, श्रीमती गांधी की सलाह 34, सत्ता का दुरुपयोग 143
- वरुणा, देवकात 'इंदिरा ही भारत है' का नारा 20, श्रीमती गांधी की जी हजुरी 39, श्रीमती गांधी के गुर्गों के रूप में 19, इस्तीफा 180, जगजीवन राम के इस्तीफे पर राय 165, प्रगतिशील कदमों के सुझाव 67, फीरोज गांधी और श्रीमती गांधी के भगडों में बीच-बचाव 19, भूमिका 26
- बसु ज्योतिमय इमर्जेंसी की घोषणा का पूर्वाभास 45 46
- बहुगुणा, हेमवती नन्दन 164, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाना 116 117
- बार एसोसिएशन इमर्जेंसी का विरोध 54 55
- बिडला, के० के० 113, सजय का उन पर भरोसा 92
- बी० बी० सी० इमर्जेंसी के बारे में रिपोर्टें 59 120
- बुद्धिजीवी इमर्जेंसी की पैरवी 72, जॉन्स बी० आर० कृष्ण अय्यर, पृष्ठभूमि 38, श्रीमती गांधी के पक्ष में सशक्त फैसला 42, श्रीमती गांधी से विश्व के बुद्धिजीवियों की प्रपील 90
- बेग एम० एच० जस्टिस 125, इनाहाबाद के फैसले के उलटे जाने पर राय 97 98 भारत के चीफ जस्टिस के रूप में 167
- ब्राट, विली पश्चिम जर्मनी के चांसलर जयप्रकाश से मिलने की इजाजत दिय जान से इन्कार 63

विपक्ष का अडरपाउड आंदोलन सगठन
 और गतिविधियाँ 70-71
 विपक्ष की एकता जयप्रकाश की योजना
 22, 23

स्टेटसमैन इमर्जेंसी के बाद की तसवीर
 53 54, तग किया जाना 92
 स्वर्णसिंह श्रीमती गांधी की सलाह 24
 25

सविधान (40वा सशोधन) बिल जल्दी
 जल्दी पास किया जाना 86
 ससद का अधिवेशन (मानसून 1975)
 इमर्जेंसी को राज्यसभा की मजूरी
 83, इमर्जेंसी को लोकसभा की मजूरी
 83 84, इमर्जेंसी पर लोकसभा में
 बहस 73 83, काम काज में बतर-
 व्योत पर प्रस्ताव 72, 73, विपक्ष
 की माँग 40

सादे वारंट दुरुपयोग 48
 सिटिजेंस फार डेमोक्रेसी सम्मेलन में
 छागला का भाषण 98

सिन्हा, जगमोहन लाल, जस्टिस उनके
 खिलाफ आरोप 40, ऐतिहासिक
 फैसला 15, 20, जासूसों की कड़ी
 नजर 14, 'ठीक कर देने' के मसूवे
 53, रिदबत देने की कोशिश 13,
 श्रीमती गांधी की टक्कर 31, सरकार
 का दबाव 13 14, सुनवाई का तरीका
 14

सुरहाण्यम, सी० सजय की उनम
 शिकायत 91
 सुल्ताना, रखसाना भूमिका 135

हक्सर, प्राणनाथ प्रधानमंत्री के क्षेत्र
 टरियट का पुनगठन 33, श्रीमती
 गांधी के साथ सम्बंध 26
 हुसेन, एम० एफ० श्रीमती गांधी का
 प्रतीक चिन्न 91 92
 हेब्रियस कापस रिट अदालत के
 अधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट का
 नहुमत फैसला 124 126

